हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

22 फरवरी, 2023

खण्ड–1, अंक–3

अधिकृत विवरण

विषय सूची

बुधवार, 22 फरवरी, 2023

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए
तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

सदस्यों की अनुपस्थिति के सम्बन्ध में सूचना देना

राजकीय आरोही मॉडल स्कूल, ग्योंग, जिला कैथल, राजकीय आरोही मॉडल स्कूल,
घासो खुर्द, जिला जीन्द एवं राजकीय आरोही मॉडल स्कूल, रामगढ़ पांडवा
के विद्यार्थियों तथा अध्यापकगण का अभिनंदन

हरियाणा विधान सभा सचिवालय में हिन्दी भाषा में कार्य करने के सम्बन्ध में सूचना

अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के राजस्थान की राजधानी जयपुर में
आयोजित 83वें सम्मेलन में पारित किए गए 9 संकल्पों के बारे में सदन
को सूचित करना

शून्यकाल में भाग लेने के लिए सदस्यों के नामों के सम्बन्ध में सूचना

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों/स्थगन प्रस्तावों/गैर सरकारी संकल्पों/अल्पावधि
चर्चा के प्रस्तावों और प्राईवेट मैम्बर बिल के बारे में सूचना

शून्यकाल में विभिन्न मामले/मांगे उठाना

सदन की बैठक का स्थगन

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–

राज्य में स्टिल्ट प्लस चार मंजिला घरों के निर्माण के विरोध से संबंधित

वक्तव्य–

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

पंजाब विधान सभा के सदस्य का अभिनंदन

श्री मनीराम गोदारा राजकीय महाविद्यालय, भोड़िया खेड़ा, जिला फतेहाबाद के अध्यापकगण एवं विद्यार्थियों का अभिनंदन

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा (पुनरारम्भ)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भ तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान

सदन की बैठक का समय बढ़ाना

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भ तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)

सदन की बैठक का समय बढ़ाना

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भ तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण एवं बजट की हार्ड कॉपीज सदस्यों को देने के सम्बन्ध में अनुरोध

नेवा पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2022–23 के लिए अनुपूरक अनुमान (तृतीय किस्त) प्रस्तुत करना

नेवा पोर्टल के माध्यम से प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

वर्ष 2022–23 के लिए अनुपूरक अनुमान (तृतीय किस्त) की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

नियम 121 के अधीन प्रस्ताव (वर्ष 2023–2024 के लिए वित्तीय समितियों के गठन सम्बन्धी)

नेवा पोर्टल के माध्यम से हरियाणा पुलिस संशोधन विधेयक, 2022 पर प्रवर समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

हरियाणा विधान सभा
बुधवार, 22 फरवरी, 2023

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रातः 11:00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री ज्ञान चंद गुप्ता) ने अध्यक्षता की।

———————————

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल शुरू होता है।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

रानियां को उप-मण्डल का दर्जा देना

*21. **श्री शीशपाल सिंह केहरवाला** : क्या उप-मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि-

(क) क्या रानियां का दर्जा बढ़ाकर उपमण्डल तथा रोड़ी एवं बड़ागुढ़ा का दर्जा बढ़ाकर उप-तहसील करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

उप-मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): नहीं, श्रीमान जी, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नही है।

श्री शीशपाल सिंह केहरवाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय उप–मुख्यमंत्री से दो सवाल पूछे थे कि क्या रानियां का दर्जा बढ़ा कर उप–मण्डल तथा रोड़ी एवं बड़ागुढ़ा का दर्जा बढ़ा कर उप–तहसील करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है लेकिन उप–मुख्यमंत्री जी का जवाब नहीं में आया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री जी को अवगत करवाना चाहूंगा कि रानियां सिरसा जिले की एक मात्र नगरपालिका है जो सब–डिविजन नहीं बनी है। उसके बाद की सभी नगरपालिकाएं सब–डिविजन बन चुकी हैं। इसी प्रकार से रोड़ी और बड़ागुढ़ा का भी मामला है। रोड़ी वर्ष 2005 से पहले विधान सभा क्षेत्र भी रहा है और वहां से माननीय श्री ओमप्रकाश चौटाला, श्री रणजीत सिंह तथा श्री जगदीश नेहरा जैसे बड़े नेता विधायक रहे हैं तथा मुख्यमंत्री भी रहे हैं लेकिन अभी तक रोड़ी को उप–तहसील नहीं बनाया गया है। मैं माननीय उप–मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि कम से कम रोड़ी को उप–तहसील का दर्जा देकर उसका मान–सम्मान कायम किया जाये।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है उसके बारे में मेरा कहना है कि आज तक न तो सरकार की तरफ से कोई ऐसी प्रोपोजल चली और न ही जनता की तरफ से तथा उपायुक्त की तरफ से कोई डिमांड आई कि रानियां को सब–डिविजन का दर्जा दिया जाये। अगर हमारे पास कोई डिमांड आती है तो मेरी अध्यक्षता में जो कमेटी बनी हुई है जिसमें श्री कंवरपाल जी तथा डॉ. बनवारी लाल जी सदस्य हैं उस कमेटी में इसको एग्जामिन करेंगे और उसी आधार पर सरकार निर्णय लेगी।

श्री शीशपाल सिंह केहरवालाः अध्यक्ष महोदय, रोड़ी को भी उप–तहसील का दर्जा देकर उसका मान–सम्मान कायम किया जाये। वर्ष 2014 मे कांग्रेस के शासनकाल भी एक बार रोड़ी को उप–तहसील बनाने की घोषणा हुई थी लेकिन वह इम्पलीमैंट नहीं हुई। वहां पर चौधरी रणजीत सिंह जी का भी काफी आना जाना रहता है और लोगों में इस बात की चर्चा भी रहती है कि रोड़ी को उप–तहसील बनाया जाये। मेरा आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि रोड़ी को उप–तहसील का दर्जा देकर उसका मान–सम्मान कायम किया जाये।

श्री नीरज शर्माः अध्यक्ष महोदय, मेरी विधान सभा अकेली ऐसी विधान सभा है जहां पर सब–डिविजन नहीं है।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का कहना है कि कांग्रेस शासन में रोड़ी को उप–तहसील बनाने की घोषणा हुई थी लेकिन ऑन रिकॉर्ड कोई घोषणा नहीं है। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि जिन्होंने घोषणा की थी उनसे पूछ लें कि सिर्फ घोषणा ही हुई थी या कोई कागज भी चला था क्योंकि यह इनकी पार्टी का ही मामला है। आने वाले समय में कमेटी के सामने जो भी प्रोपोजल आयेंगी उनको कमेटी स्क्रूटनाइज करेगी तथा एग्जामिन करेगी

कि किसको सब–डिविजन बनाना है, किसको तहसील या उप–तहसील बनाना है। उस समय जनसंख्या के आधार पर कोई क्राइटेरिया नहीं था लेकिन अब हम इसका क्राइटेरिया रिवाइज कर रहे हैं जिससे जनसंख्या के अनुपात में सब–डिविजन, तहसील और उप–तहसील बनाई जायेंगी। जैसा माननीय सदस्य श्री नीरज शर्मा जी कह रहे हैं कि उनकी विधान सभा क्षेत्र में कोई सब–डिविजन नहीं है लेकिन मैं उनको बताना चाहूंगा कि ऐसे और भी विधान सभा क्षेत्र हैं जहां पर रेवेन्यू का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पाया है। हमारा लक्ष्य यह है कि सभी 140 ब्लॉक्स को पॉपुलेशन के अनुसार बैलेंस करके ऑफिसर्स दिये जायें।

तारांकित प्रश्न संख्या 23

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री जयवीर सिंह सदन में उपस्थित नहीं थे।)

स्वास्थ्य केन्द्रों में सुविधा प्रदान करवाना

***24. श्रीमती नैना सिंह चौटाला :** क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे किः–

(क) दादरी में स्थित नागरिक अस्पताल में अल्ट्रासांउड की सुविधा कब तक आरंभ किये जाने की संभावना है;

(ख) उपरोक्त हस्पताल में बाल चिकित्सक, सर्जन, रेडियालोजिस्ट तथा अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्तियां कब की जाने की संभावना है; तथा

(ग) दादरी नागरिक अस्पताल,सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोपी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र झाझू कलां में एक्स–रे की सुविधा कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है ?

***स्वास्थ्य मं़त्री (श्री अनिल विज) :**

(क) चरखी दादरी में गर्भवती महिलाओं को जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जे0एस0एस0के0) के तहत निःशुल्क अल्ट्रासांउड की सुविधा प्राईवेट एमपैनलमैंट सैंटर द्वारा प्रदान की जा रही है।

(ख) जिला सिविल हस्पताल चरखी दादरी में विशेषज्ञों के रिक्त पदों की भर्ती प्रत्येक मंगलवार को वाक–इन–इन्टरव्यू के माध्यम से एन0एच0एम0 के द्वारा की जा रही है, जब तक रिक्त पद नहीं भर दिये जाते।

(ग) एक्स–रे की सुविधा जिला सिविल हस्पताल, चरखी दादरी में पहले से ही उपलब्ध है, तथा सी0एच0सी0 गोपी व सी0एच0सी0 झोझूकलां में एक्स–रे की सुविधा देने बारे प्रस्ताव विचाराधीन है।

श्रीमती नैना चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो अल्ट्रासाउंड मशीन के बारे में कहा है वैसे तो गवर्नमैंट की तरफ से प्राईवेट होस्पिटल में अल्ट्रासाउंड मशीन है लेकिन मैं महिलाओं के लिए कहना चाहूंगी कि बसों में पहले सिविल होस्पिटल जाना और फिर प्राईवेट सैंटर्स में जाना बहुत मुश्किल है। दादरी सिविल होस्पिटल में अल्ट्रासाउंड मशीन रखी हुई है लेकिन वह मशीन बहुत लम्बे समय से बन्द पड़ी हुई है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह है कि आप वह मशीन ठीक करवा दीजिए। इसी के साथ ही एक जो हड्डी

***सहकारिता मंत्री (डॉ. बनवारी लाल) द्वारा उपरोक्त प्रश्न का उत्तर दिया गया।**

एक्स–रे मशीन है उस पर काम करने का समय सिर्फ शाम दो बजे तक है। उसके लिए भी मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि जब कोई महिला गांव से बसों में चलकर आती है तो एक महिला को काम करके आने मे वैसे ही दो बज जाते हैं। अतः उस हड्डी एक्स–रे मशीन का समय बढ़ाने का काम करें। इसके साथ ही सी.एच.सी. गोपी और सी.एच.सी. झोझू कलां में अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध करवाई जाएं।

डॉ. बनवारी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि अभी जो डॉक्टर्ज की पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं उनके लिए हमने एन.एच.एम. के तहत सात पोस्टें सैंग्शन की हुई हैं। उनके लिए हर मंगलवार को सी.एम.ओ. ऑफिस में इंटरव्यू होता है। जब वे पोस्टें भर जाएंगी तो वह अल्ट्रासाउंड मशीन भी काम करने लग जाएगी। उसके बाद गोपी व झोझू कलां में जो सी.एच.सीज. हैं उनमें एक्स–रे मशीन के लिए ऑर्डर प्लेस कर दिये गये हैं और जल्दी ही उसकी प्रोक्योरमैंट हो जाएगी। सी.एच.सी. लैवल पर अल्ट्रासाउंड मशीन की सुविधा इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि अभी हमारे पास डॉक्टर्ज अवेलेबल नहीं हैं। जैसे दादरी में अल्ट्रासाउंड मशीन तो है लेकिन वहां रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। जब वहां रेडियोलॉजिस्ट अवेलेबल होंगे तो हम वहां अल्ट्रासाउंड मशीन भी उपलब्ध करवा दी जाएगी।

श्रीमती नैना चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने उपरोक्त अस्पताल में जो बाल चिकित्सक सैंटर बनाया है वह लम्बे समय से डॉक्टर्ज न होने की वजह से बंद पड़ा है। उसमें मिट्टी चढ़ रही है। वहां पर एक चाईल्ड स्पैशलिस्ट डॉक्टर की नियुक्ति कर दें ताकि कम से कम बच्चों का तो इलाज हो जाए। दूसरा अस्पताल में जो एक्स–रे मशीन हैं उनमें जितने भी कैसेट्स से एक्स–रे किये जाते हैं वे

सारी की सारी पुरानी कैसेट्स हैं उनसे लोगों की कोई रिपोर्ट सही नहीं आ रही है। अध्यक्ष महोदय, दादरी सिविल होस्पिटल का बहुत ही बुरा हाल है। मैं तो आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि आप अपनी एक टीम दादरी होस्पिटल में भेजकर चैक करवा लें और उसमें जो मशीनें खराब पड़ी हैं उनको बदलवा दीजिए और वहां एक–दो डॉक्टर्ज भेजकर लोगों को सुविधा उपलब्ध करवा दीजिए।

डॉ. बनवारी लाल : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्या ने जो डॉक्टर्ज रखने की बात कही है तो Gynecologist, Radiologists, General Surgeons, Pediatrician, General Physician, ENT Surgeons and Psychiatrist आदि सभी डॉक्टर्ज की पोस्ट सैंग्शन की हुई हैं और उनके लिए हर मंगलवार को इंटरव्यू हो रहा है। जब ये डॉक्टर्ज आ जाएंगे तो वे अवेलेबल करवा दिये जाएंगे और जो एक्स–रे मशीन खराब हैं उनको ठीक करवा दिया जाएगा तथा उनका टाईम भी बढ़वा दिया जाएगा।

श्रीमती नैना चौटाला : धन्यवाद।

तारांकित प्रश्न संख्या–25

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया, क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री गोपाल कांडा सदन में उपस्थित नहीं थे।)

तारांकित प्रश्न संख्या–26

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया, क्योंकि इस समय माननीय सदस्या श्रीमती निर्मल रानी सदन में उपस्थित नहीं थी।)

सड़कों का निर्माण कार्य पूरा करना

*27. **श्री घनश्याम दास :** क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा संख्या 26425 तथा 26426 के अनुसार सड़कों का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है तथा उक्त कार्य के कब तक पूरे किए जाने की संभावना है?

(Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala): Sir, The Estimate for widening and strengthening of Yamuna Nagar Khajuri Jathlana Road upto Gumthala Rao Km. 0.00 to 22.30 (ID 511, 531 & 532) which is CM Announcement bearing code No. 26425 dated 15.05.2022 has been prepared. The estimate is under examination and will be sent to Government for seeking administrative approval. No time frame can be given at this juncture.

The Estimate for strengthening of Jagadhari workshop road Km. 0.27 to 2.00 (ID 428) which is CM Announcement bearing code No. 26426 dated 15.05.2022 has been prepared. The estimate is under examination and will be sent to Government for seeking administrative approval. No time frame can be given at this juncture.

श्री घनश्याम दास अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उप–मुख्यमंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूं कि 15.05.2022 को लगभग सात महीने पहले मुख्यमंत्री जी ने इन उपरोक्त दो सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण और सुधारीकरण करने की घोषणा की थी। निश्चित रूप से घोषणा से यह स्पष्ट है कि इन सड़कों की हालत ठीक नहीं है जिससे प्रायः वहां दुर्घटनाओं का डर रहता है। वहां जो वर्कशॉप रोड है वह शहर के बीचों बीच है और उस पर इतने बड़े–बड़े गड्ढ़े हैं कि उस पर चलना मुश्किल है। वहां एक खजुरी रोड़ है जिस पर प्लाईवुड इंडस्ट्रीज हैं। उस सड़क के माध्यम से बहुत बड़ी संख्या में किसान शुगरमिल को गन्ना सप्लाई करते हैं जिस पर उन किसानों

की गन्ने की ट्रालियां पलटने का डर रहता है और कई बार किसानों की गन्ने की ट्रालियों के पलटने से दुर्घटानाएं भी हो जाती हैं। अतः मैं आपके माध्यम से उप–मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि मामले की सड़कों की जीर्ण–शीर्ण अवस्था को देखते हुए 15.05.2022 को जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी लेकिन अभी सात महीने में भी उसका अनुमान जांच के अधीन है। यह विभाग की कार्यकुशलता को दर्शाता है। अध्यक्ष महोदय, कब उसकी प्रशासनिक स्वीकृति होगी, कब टैक्निकल सैंक्शंन होगी, कब टैंडर लगेगा और उसके बाद कब वर्क ऑर्डर दिया जायेगा? इस सारी प्रक्रिया के चलते हुए बहुत ज्यादा समय लगेगा। सरकार ने जो वहां यातायात की सुविधा दी हुई है, उसके ऊपर कुप्रभाव पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से सदन में यह आश्वासन चाहता हूँ कि उन सड़कों की स्थिति को देखते हुए कोई समय–सीमा तय करें ताकि लोगों को सुगम सड़क उपलब्ध हो सके।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि दिनांक 15.05.2022 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा के अनुसार दोनों सड़कों को लिया गया था। हमने उसके बाद प्रदेश में घोषण की कि हर विधायक अपने–अपने हल्के की इस संबंध में 25 करोड़ रुपये तक के कामों की प्रॉयर्टी लिस्ट दे। उसके अंदर हम कामों को सिलैक्ट करने का काम करेंगे। यमुनानगर निर्वाचन क्षेत्र के माननीय विधायक ने 15 सड़कों के लगभग 24.85 किलोमीटर के 24.53 करोड़ रुपये के नाम अपनी प्रॉयर्टी लिस्ट में दिये हैं। जिसमें ये दोनों संबंधित सड़कें निहित हैं। फिर भी अगले बजट के अंदर एक सड़क की एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रवूल के लिये फाइल संबंधित डिपार्टमैंट में बन चुकी है, उसको हम अगले बजट में इमीजियेट्ली टेकअप करेंगे। माननीय सदस्य ने जो दूसरी सड़क का पैच वर्क 2 किलोमीटर का बताया है, उसका अभी तक नीचे से ही एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रवूल बनकर फाइल नहीं आई है। उसको भी इन फ्यूचर टेकअप करेंगे।

श्री अध्यक्षः उप मुख्यमंत्री जी, इसमें मेरा यह कहना है कि क्या इसके लिये आप कोई समय–सीमा तय नहीं कर सकते कि कितने दिन में अनुमान बनेगा? कितने दिनों में अनुमान बनकर सैंक्शंड होगा, कितने दिनों में एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल हो जायेगी आदि इस प्रकार का कोई एक चार्ट बनाकर विभाग के संबंधित अधिकारियों को नहीं दे सकते? जब संबंधित अधिकारियों के पास फाइल आती है तो तुरंत कार्यवाही होनी चाहिये। राईट टू सर्विस एक्ट के अंदर यह भी मैंशन है कि कितनी देर किस अधिकारी के पास फाइल रहती है। उप मुख्यमंत्री जी, इस प्रोसैस में आपको तेजी लानी होगी।

श्री दुष्यंत चौटालाः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका सुझाव बहुत अच्छा है। कल प्रदेश का बजट पेश होगा।

श्री मेवा सिंहः अध्यक्ष महोदय, सड़कों के काम अलॉट हुए दो साल हो गये हैं।

श्री अध्यक्षः मेवा सिंह जी, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं, प्लीज आप बैठ जाइये।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के बजट से डिपार्टमैंट को बजट अलॉट किया जाता है और उसमें डिपार्टमैंट का प्रैरोगेटिव है कि प्रॉयर्टी किन–किन प्रोजैक्ट्स को देगा।

श्री अध्यक्षः दुष्यंत जी, सरकार ने 25 करोड़ रुपये तक के कामों की प्रॉयर्टी लिस्ट मांगी थी, वो माननीय सदस्यों ने अपनी–अपनी लिस्ट दे दी है। मुझे भी अपने हल्के के कामों की 25 करोड़ रुपये की लिस्ट को दिये हुए लगभग 4 महीने हो गये हैं। चार महीने के अंदर वह लिस्ट कहां है? उस लिस्ट का क्या हुआ? इस प्रकार की बातों का किसी को नहीं पता है।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके निर्वाचन क्षेत्र पंचकुला के बारे में सदन को बता देता हूँ कि हमारे विभाग के पास आपकी तरफ से 6 सड़कों का

26.30 किलोमीटर का लगभग 29 करोड़ रुपये का काम भेजा हुआ है। जो आज हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल पर प्रोसैस के लिये डल चुका है। यदि चेयर चाहती है कि मैं प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र वाईज लिस्ट सदन को बताऊं तो उसके लिये भी मैं तैयार हूँ।

श्री अध्यक्षः माननीय उप मुख्यमंत्री जी, मेरा यह कहना है कि इसके लिये कोई टाइम फ्रेम बना दीजिए।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, एक माननीय विधायक पानीपत और एक माननीय विधायक गुरुग्राम हैं, जिनके निर्वाचन क्षेत्र में हमारी कोई सड़क ही नहीं है। उनकी तरफ से एक भी प्रोजैक्ट बनकर नहीं आया है। अध्यक्ष महोदय, जो बात माननीय सदस्य श्री घनश्याम दास अरोड़ा ने कही है कि ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा है, उसको हम टेकअप करेंगे।

श्री अध्यक्षः उप मुख्यमंत्री जी, मैंने जो बात इस संबंध में कही है, आप उसके ऊपर ध्यान देते हुए इसके लिये कोई टाइम फ्रेम बना दीजिए।

श्री घनश्याम दासः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने सदन को बताया है, मैं उसमें दो बातें आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि जो 25 करोड़ रुपये तक के सड़कों के कामों की बात कही गई है लेकिन जो खजुरी मार्ग है उसका एस्टीमेट्स ही 27 करोड़ रुपये से ऊपर का है, इसलिए वह उसमें कवर नहीं हुई। मैंने वर्क शॉप रोड के लिये अपनी सूची संबंधित एक्सियन के माध्यम से संबंधित हैड ऑफिस चण्डीगढ़ को भेजी थी। विभाग ने अपनी इच्छानुसार एक सड़क का नाम काट दिया, संयोग से वह वर्क शॉप रोड थी, जिसकी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की थी। विभाग ने इस संबंध में अपने आप निर्णय कैसे ले लिया? जब विधायक की सहमति से ही सड़कों के नाम की लिस्ट दी जाती है तो कम से कम उस सड़क का नाम

लिस्ट से हटाना था तो पहले संबंधित विधायक की सहमति भी जरूर लेनी चाहिये थी। यह भी हो सकता था कि मैं अपनी लिस्ट में से दूसरी सड़क का नाम कटवा देता। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिस सड़क की घोषणा की थी और उसकी बहुत जीर्णशीर्ण अवस्था है, जिस सड़क पर चला नहीं जा सकता और दुर्घटनाएं होती रहती हैं। उस सड़क का नाम लिस्ट में रखवा लेता। जब विधायकों को अपनी हल्के में सड़कों से संबंधित 25 करोड़ रुपये तक के काम दिये गये हैं, क्या संबंधित विभागीय अधिकारियों को जो लिस्ट विधायकों द्वारा दी गई हैं उस लिस्ट में से अपने आप कोई भी सड़क का नाम काटने का अधिकार है? यदि इस प्रकार का उनके पास कोई अधिकार है तो कम से कम संबंधित विधायक से उस सड़क के बारे में कोई जानकारी दे और ले सकते थे ताकि जो सड़क माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा के अनुसार बननी थी वह बन सके। इस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा का भी मान–सम्मान हो जाता।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने खुद ही बताया है कि जो सड़क का नाम उन्होंने भिजवाया जिसको खजुरी रोड कहा जाता है उस सड़क का एस्टीमेट्स 25 करोड़ रुपये से ज्यादा है।

श्री अध्यक्ष: उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय सदस्य तो वर्क शॉप रोड की बात कर रहे हैं।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात पर भी आउंगा। यदि मैं माननीय सदस्य की जगह होता और मुझे लगता कि यह सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सड़क है तो मैं अपनी 25 करोड़ रुपये की लिस्ट में केवल इसी सड़क का नाम डालता। मगर इन्होंने अपने क्षेत्रफल को देखते हुए ज्यादा काम दिये। सरकार ने उस काम के अंदर भी तीन प्रोविजन बनाये हैं। जहां पर सिर्फ रि–कारपेटिंग होनी है उसको प्रॉयर्टी लिस्ट–1 में डाला है। जहां पर आर.बी.एम. डाल कर स्ट्रैंग्थनिंग होकर

कारपेटिंग होनी है उसको प्रॉयर्टी लिस्ट–2 में लिया गया है और जहां पर वाइडनिंग, स्ट्रेंग्थनिंग और कारपेटिंग होनी है उसको प्रॉयर्टी लिस्ट–3 में लिया हुआ है। संबंधित विधायक ने अपनी रिकमैंडेशन यह भेजी है कि ये सड़कें बनाई जाये। उस रिकमैंडेशन के हिसाब से डिपार्टमैंट ने प्रॉयर्टी–1, प्रॉयर्टी–2 और प्रॉयर्टी–3 के हिसाब से उठाया है। अध्यक्ष महोदय, विभाग ने सबसे पहले जितनी कारपेटिंग से संबंधित सड़कें थी उनको टेकअप किया। यदि लिस्ट में से कोई सड़क का नाम रहा है तो उसमें विभागीय अधिकारियों की कमी नहीं है क्योंकि प्रॉयर्टी–1, प्रॉयर्टी–2 और प्रॉयर्टी–3 के हिसाब से जो–जो सड़कों के नाम सिस्टम ने उठाया है उसके ऊपर विभाग ने काम किया है।

श्री घनश्याम दासः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से सिर्फ यह निवेदन है कि जो मैंने इस संबंध में सड़कों की सूची भेजी थी उसमें से संबंधित डिपार्टमैंट के अधिकारियों ने कोई सड़क का नाम काटना ही था तो कम से कम नाम काटने से पहले मेरी सहमति तो ले लेते। जो मेरी कम महत्वपूर्ण सड़कों के नाम हैं उनके नाम कटवा देता और जो ज्यादा महत्वपूर्ण सड़क हैं उनको बनवाने के लिये रिक्वैस्ट कर लेता लेकिन विभाग के संबंधित अधिकारियों ने इस प्रकार की कोई बात मेरे से पूछनी उचित नहीं समझी।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने फिर महत्वपूर्ण सड़क की बात कही है। इस बार हमारी प्रॉयर्टी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 25 करोड़ रुपये की थी और फंड्स लिमिटेड थे। मैं माननीय सदस्य को इंश्योर कर रहा हूँ कि अगले बजट के अंदर क्योंकि यह सी.एम. अनाउंसमैंट है, हम जरूर इसको टेकअप करेंगे।

श्री जोगी राम सिहागः अध्यक्ष महोदय, मेरा सिर्फ यह कहना है कि विभाग की प्रॉयर्टी का सिस्टम कौन सा है? जो सड़क सबसे ज्यादा खराब है वह प्रॉयर्टी–1 होनी चाहिये या फिर जो सबसे सड़क कम खराब है वह प्रॉयर्टी–1 होनी चाहिये।

श्री अध्यक्षः यह प्रॉयर्टी तो विधायक को तय करने दो कि वह किसको पहले करवाना चाहता है। सरकार ने तो इस संबंध में राशि फिक्स कर दी है। उसी राशि में विधायक की डिमाण्ड है कि पहले मेरी ये–ये सड़क बन जाये।

बिजली के खम्भों से संबंधित नीति

*28. **श्री वरूण चौधरी** : क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बताएंगे कि:-

(क) क्या राज्य में निजी रिहायशी भूमि के स्वामी को उनकी भूमि पर बिजली के खम्भे लगाने के लिए बिजली विभाग द्वारा अनुमति ली जा रही है;

(ख) क्या भूमि के स्वामी से विभाग द्वारा उनके बिजली के खम्भे हटाने का खर्चा लिया जा रहा है यदि वह इसे हटाना चाहता है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में विभाग की कोई योजना अथवा नियम/विनियम है तथा उसका ब्यौरा क्या है; तथा

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का उसकी अपनी निजी रिहायशी भूमि से बिजली के सरकारी खम्भों को हटाने के लिए स्वामी से खर्च वसूलना न्यायोचित है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री रणजीत सिंह) : श्रीमान,

(क) भारतीय तार अधिनियम के प्रावधानों के तहत, प्राधिकरण के पास किसी भी अचल संपत्ति पर पोस्ट अथवा पोल लगाने और बनाए रखने की पूरी शक्तियां हैं। टावरों के मामले में, सरकार ने 2022 में एक मुआवजा नीति अधिसूचित की है।

(ख) यदि कोई व्यक्ति ओवरहेड लाइन बनने के बाद बिजली लाइनों के नीचे आवासीय भवन का निर्माण करता है, तो उसे तकनीकी फिजीबिलीटी के अधीन ऐसे पोल/लाइन को शिफ्ट करने की लागत जमा करवानी होती है।

(ग) बिजली लाइनों की शिफ्टिंग की लागत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और बिजली आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 के विनियम 63 और एचईआरसी बिजली आपूर्ति कोड विनियम द्वारा विनियमित की जाती है।

(घ) बिंदु (ग) में दी गई प्रतिक्रिया के अनुसार यह मुद्दा नहीं उठता है।

श्री वरूण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि पूरी शक्तियां हैं लेकिन इन शक्तियों को दुरूपयोग विभाग द्वारा किया जा रहा है। विभाग का जे.ई. (कनिष्ठ अभियंता) एक रेखा चित्र बना देते हैं कि यहां से खम्भा और बिजली की लाइन जायेगी। विभाग का कोई भी अधिकारी उसकी कोई जांच नहीं करता है कि यह लाइन किसी के निजी भवन से तो नहीं जा रही है, किसी के जमीन के ऊपर से तो नहीं जा रही है या फिर यह सरकारी जमीन के ऊपर से तो नहीं जा रही है। इस बारे में कोई भी विभागीय अधिकारी ना तो सोचता है और ना ही उसको चैक करता है। यदि उस लाइन को हटाने की बात आती है तो उसकी फाइल एस.ई. तक जाती है और उसकी कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं होती कि कितने समय में उस मैटर को एस.ई. फाइनल करेंगे। अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस संबंधित भू–मालिक से इस संबंध में 'शपथ पत्र' मांगा जाता है कि यदि किसी ने भी रोक दिया तो हम जिम्मेवार नहीं है और हम उस काम को पूरा नहीं करेंगे। जब बिजली की लाइन बिछाई जाती है तब तो संबंधित जे.ई. या एस.ई. से कोई शपथ पत्र नहीं लिया जाता है, इस प्रकार से यह तो जनता के ऊपर एक बोझ डाला जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, पूरी की पूरी नई संरचना का पैसा लिया जाता है। चाहे वह खम्भा दो महीने पहले लगा हो या बिजली की लाइन दो महीने पहले डली हो, पर जनता से नट और बोल्ट से लेकर खंभा, तार, पिन आदि सब चीजों के पैसे लिये जाते हैं। उपभोक्ता को कहा जाता है कि जितना भी पुराना सामान है वह सारा स्टोर में जमा होगा । सर, वह

सामान स्टोर में भी जमा नहीं करवाया जाता है । यह एक जांच का विषय है । मैं चाहूंगा कि लोक उपक्रम समिति इसकी जांच करे कि क्या वह सामान वापिस भी जाता है या नहीं । अध्यक्ष महोदय, वह सामान वापिस भी क्यों जाता है ? अगर किसी खम्भे को 2–4 फुट सरकाना है तो उसी खम्भे को यूज किया जाए लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है । इसके लिए नये सामान का पूरा पैसा लिया जाता है । इसके लिए 20 हजार से लेकर लाखों रुपये तक जनता पर एक्स्ट्रा बोझ डाला जा रहा है । केवल यही नहीं इस पर 10 परसैंट डिपार्टमैंटल चार्जिज, 18 परसैंट जी.एस.टी., लेबर चार्जिज, ट्रांसपोर्टेशन चार्जिज भी लिये जाते हैं । इस तरह से पूरे का पूरा भार उपभोक्ता पर डाल दिया जाता है । अतः अगर किसी व्यक्ति के घर या जमीन के ऊपर से बिजली की कोई तार जा रही है तो उसको वहां से शिफ्ट करवाना उसके लिए टेढ़ी खीर है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस नीति की समीक्षा की जाए और जनहित में इसमें बदलाव किये जाएं । धन्यवाद ।

श्री रणजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, जितना माननीय सदस्य कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है । अगर कहीं पर इस तरह की घटना हुई है और माननीय सदस्य को ऐसा लगता है तो ये उसे मेरे नोटस में ला दें । मैं उसकी जांच करवाता हूं और उनकी मदद करूंगा । सरकार तरीके से काम करती है । ऐसा नहीं है कि अपनी इच्छा से कुछ भी कर लें । उस पर चैक लगा हुआ है । उसको देखा जाता है और मैं भी इसकी मॉनीटरिंग करता हूं । अतः ऐसा कहीं भी नहीं है ।

श्री वरूण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह समस्या किसी एक उपभोक्ता की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम इसकी समीक्षा कर लेंगे लेकिन मैं इस समस्या से व्यक्तिगत रूप से पीड़ित हूं । अगर

किसी व्यक्ति की जमीन पर 20 साल पहले विभाग ने उससे पूछे बगैर और बिना उसकी इजाजत के बिजली का खम्भा लगा दिया तो क्या वह व्यक्ति विभाग से अपनी जमीन यूज करने की एवज में किराया प्राप्त करने का हकदार नहीं है ? ऐसे बहुत–से केसिज हैं जिनमें खम्भा केवल 2 फुट शिफ्ट करना होता है । ऐसे में खम्भा भी वही लगना होता है और तारें भी वही लगनी होती हैं लेकिन उनका ऐस्टीमेट नये सामान का बना दिया जाता है । अतः इसे एक बार देखने की जरूरत है ।

श्री रणजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा कुछ है तो मैं माननीय सदस्य को कहूंगा कि ये उस मामले को मेरे नोटिस में ला दें । मैं उसकी जांच करवाऊंगा ।

श्री वरूण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जैसे आप देख रहे हैं कि यह मांग अकेले मेरे क्षेत्र की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की है । उपभोक्ता पर जो नई संरचना का भार डाला जा रहा है वह गलत है । वहां पर जो तार पहले से लगी हुई होती है विभाग को उसी का पुनः उपयोग करना चाहिए । इसके अलावा उनसे जो 10 परसैंट डिपार्टमैंटल चार्जिज, 18 परसैंट जी.एस.टी., लेबर चार्जिज, ट्रांसपोर्टेशन चार्जिज लिये जाते हैं इन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए । इसमें उपभोक्ता का क्या कसूर है ? इस कार्य को राइट टू सर्विस में शामिल किया जाना चाहिए । इसके अलावा खम्भे के हटने की कोई समय–सीमा भी नहीं है । अगर उपभोक्ता इसके लिए पैसे दे देगा तो उसका खम्भा हट सकता है अदरवाइज उसकी निजी जमीन से वह खम्भा हट ही नहीं सकता । आज इस प्रदेश के ऐसे हालात हैं ।

श्री रणजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः कहना चाहूंगा कि अगर ऐसा कोई मामला माननीय सदस्य के ध्यान में हैं तो ये उस मामले को मेरे नोटिस में ला

दें । मैं उसको ठीक करवाता हूं और आगे इसके लिए हम साफ गाइडलाइंस तय कर देंगे कि ऐसा नहीं होगा ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप गाइडलाइंस की बजाय ऐसी पोलिसी बनाइये कि अगर वह मैटीरियल रियूज हो सकता है तो उसे रियूज करें ।

श्री रणजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार का लाइसैंसी के वर्ष 2003 के रूल 67 और 69 के तहत कार्य–नियम बनाने का इरादा है और हम इस पर ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं ।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है वह कोई हरियाणा स्पैसिफिक बात नहीं है । पूरे देश में जो हमारी पावर युटिलिटी कॉरपोरेशंज हैं उनके एक्ट्स 1800 की सदी में ब्रिटिश राज से बने हुए हैं । माननीय सदस्य ने जो कहा कि उपभोक्ता इससे पीड़ित हैं तो इस पर मेरा कहना है कि पावर डिपार्टमैंट अन्य स्टेट्स का एक बार मंथन करवा लेगा । इसके लिए हम एक कमेटी बना देते हैं । उस कमेटी की जो रिक्मैंडेशंज होंगी इन फ्यूचर हम उनको असैप्ट करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय, कोई भी कानून, कोई भी नियम जनहित के लिए बनता है । अगर नियम–कानून जनहित में नहीं होते तो उनको बदला भी जा सकता है । ऐसा नहीं है कि नियम–कानून बदले ही नहीं जा सकते ।

श्री दुष्यन्त चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए हम एक कमेटी बना देते हैं और वह कमेटी अन्य स्टेट्स का एक बार मंथन कर लेगी कि कौन–सी स्टेट क्या कर रही है । (शोर एवं व्यवधान)

एक आवाजः अध्यक्ष महोदय, आप तो स्पीकर हो। आप भी अपनी बात सदन में रख सकते हो।

श्री अध्यक्षः मैं विधान सभा का अध्यक्ष होने के साथ–साथ जनप्रतिनिधि भी हूं। मुझे अपनी जनता की बात भी तो रखनी है। मैं सुझाव तो दे सकता हूं।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, इस काम के लिए कमेटी बनाएंगे तो मामला गोल–मोल हो जाएगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः प्लीज, सभी माननीय सदस्यगण बैठ जाएं।

———————

हांसी ब्रांच की साइड लाईन को पक्का करना

***29. डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा** : क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे–

(क) क्या हांसी ब्रांच की साइड लाईन आर.डी. –183000 से 198000 तक सीमेंट से पक्का करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उक्त साइड लाईन को कब तक पक्का किए जाने की संभावना है; तथा

(ग) उक्त आर.डी. को पहले किस समय पक्का किया गया था ?

***मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) :** (क) हां श्रीमान जी।

(ख) हांसी ब्रांच की बुर्जी संख्या 183000 से बुर्जी संख्या 198000 में सीमेंट कंक्रीट साइड लाइनिंग का प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है और इस पहुँच में साइड लाइन का कार्य जून 2024 तक पूरा होने की संभावना है।

(ग) हांसी शाखा की बुर्जी संख्या 183000 से बुर्जी संख्या 198000 तक साइड की लाइनिंग वर्ष 1972–73 के दौरान की गई थी और वर्ष 2002 के दौरान कुछ मरम्मत का कार्य किया गया था।

डॉ0 कृष्ण लाल मिड्ढ़ाः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री श्री जय प्रकाश दलाल जी का विशेष

———————————————

***कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) द्वारा उपरोक्त प्रश्न का उत्तर दिया गया**

तौर पर आभार व्यक्त करता हूं। जब भी ये माननीय मुख्यमंत्री जी के बिहाफ पर मेरे प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो मेरा काम हो जाता है। पिछले सैशन के दौरान मैंने जब छठ पूजा के लिए घाट बनाने की मांग रखी थी तो इन्होंने उसको भी मंजूर करने का काम किया था। लेकिन मेरा एक निवेदन और प्रार्थना है कि इस काम के लिए समयावधि को थोड़ा-सा कम किया जाएगा तो बेहतर रहेगा। चूंकि इस वर्ष में दीपावली के आसपास नवरात्रे आएंगे तो उस समय तक इस काम को पूरा करवा दिया जाएगा तो बहुत मेहरबानी होगी। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह नम्र निवेदन है। मैं इसके लिए एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

श्री जय प्रकाश दलाल: माननीय अध्यक्ष महोदय, हम इस कार्य को जल्दी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन समस्या यह है कि संबंधित नहर में पानी लगातार चलता रहता है और पानी कम ही बन्द होता है। जब पानी बन्द होता है तभी इसकी लाइनिंग की जा सकती है। इसीलिए हमने इस कार्य को पूरा करने के लिए थोड़ा-सा ज्यादा टाईम दिया है, लेकिन हम इस काम को जल्दी करवाने की कोशिश करेंगे।

डॉ0 कृष्ण लाल मिड्ढ़ाः माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

सड़कों पर खर्च की गई राशि

***30.श्री भारत भूषण बत्रा:** क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे कि :-

(क) वर्ष 2019 से आज तक नगर निगम, रोहतक सड़कों की मरम्मत पर कितनी राशि खर्च की गई तथा उन सड़कों के नाम क्या हैं जिन पर उपरोक्त राशि खर्च की गई तथा उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2021-22 और 2022-23 में नगर निगम, रोहतक को सरकार द्वारा आबंटित की अनुदान की राशि कितनी है तथा अन्य निधि से निगम को कितनी राशि आबंटित की गई है तथा उसका ब्यौरा क्या है; तथा

(ग) वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 में विधायक की 5 करोड रुपए के अलावा नगर निगम, रोहतक को सरकार द्वारा कितनी राशि आबंटित की गई तथा उसका ब्यौरा क्या है?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डॉ0 कमल गुप्ता) : महोदय,

(क) नगर निगम, रोहतक द्वारा 2019 से अब तक सड़कों की मरम्मत के जो कार्य पूर्ण हो चुकी हैं उन पर 42.81 करोड रुपये की राशि खर्च की गई है। इसके अतिरिक्त 0.83 करोड रुपये के कार्य प्रगति पर हैं और 4.65 करोड रुपये के कार्यों के लिए निविदा प्रकिया में हैं। विवरण अनुलंग्नक 'ए, ए-I से ए-III' पर संलग्न है।

(ख तथा ग) सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 में 162.38 करोड तथा वर्ष 2022-23 (16.02.2023 तक) में 152.88 करोड रुपये की राशि आबंटित की गई है। विवरण अनुलंग्नक 'बी' पर संलग्न है।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान किसी अन्य निधि से नगर निगम, रोहतक को कोई राशि आबंटित नहीं की गई है।

ANNEXURE-A

Municipal Corporation, Rohtak

Details of amount spent for repairing of roads from 2019-20 to 2022-23 (upto 16-02-2023)

Sr. No.	Financial Year	Amount spent on repairing of roads (Rs. in lakhs)	Status	Annexure
1	2019-20	3355.45	Work completed	A-I
2	2020-21	83.65	Work completed	
3	2021-22	543.26	Work completed	
4	2022-23	299.12	Work completed	
Total		**4281.48**		
(to say 42.81 Crores)				

Details of estimated amount for repairing of roads from 01-02-2023 to 16-02-2023

Sr. No.	Period	Estimated expenditure for repairing of roads (Rs. in lakhs)	Status	Annexure
1	01-02-2023 upto 16-02-2023	83.02 **(to say 0.83 Crores)**	Work in progress	A-II
		465.21 **(to say 4.65 Crores)**	Tender in process.	A-III

Annexure-A (I)

Municipal Corporation, Rohtak

Details of amount spent for repairing of roads in the year 2019-20 to 2022-23 (upto 16.02.2023)			
Sr. no.	**Name of Road**	**Amount spent on repairing of roads (Rs.)**	**Remarks**
Year 2019-20			
1	Renovation of Railway Road from Aggarsain Chowk to Bhiwani Stand W-15, Rtk.	22,813,457.00	Work Completed
2	Repair of Roads Streets and G.T. work in W-18, Rtk.	89,095.00	Work Completed
3	Widening of Road by p/L 80mm thick IPB tiles from Kathmandi Flyover to Jhajjar Chungi W-17, Rtk.	557,069.00	Work Completed
4	Const. of Streets from Shop of Sehgal Jewellers to Stationary shop infront of Azad Tent House in Jawahar Nagar W-11, Rtk.	196,780.00	Work Completed
5	P/F IPB from H/o Somnath H/o Kirshan and H/o Kharbanda H/o Suneja, Shop of Rimpi Electric to Jagdish Gandhi Camp W-10, Rtk.	343,665.00	Work Completed
6	P/L of IPB tile in Shori Market, W-15, Rtk.	343,732.00	Work Completed
7	Const. of CC Street from H/o Harish Nagpal in Jagdish Colony W-15, Rtk.	255,048.00	Work Completed
8	Beautification and repair of Road and filling of Pothole and resolving complaint of Harpath, Social Media and C.M window at various locations in W-1 to 22, Rtk.	9,886,661.00	Work Completed
9	Const. of Mastic Road from market and H/o 1457 to 114 towards Sonipat road in Sec-2, W-11, Rtk.	9,988,000.00	Work Completed
10	Maintenance and Misc.Civil works at various places in W-13, Rtk.	755,088.00	Work Completed
11	Const. of Mastic Road from H/o Dr. K.K. Verma H/o 137 to H/o 994, H/o 994 to Shopping Centre towards Main Delhi Road in Sec-1, W-11, Rtk.	9,984,493.00	Work Completed
12	Const. of CC Street Deep wali gali, tomer Satbir Hooda wali gali and Mahabir Ahlawat wali gali in Kailash Colony, W-5, Rtk.	7,168,267.00	Work Completed
13	Const. of Street with IPB infront of Old Police Chowki Chinyot Colony, H/o Sardar Bijli to H/o Janak Juice, Satish (Widening) & Branch street , H/o Dalbir Singh Rathee to H/o Karamraj & approach street H/o	9,369,000.00	Work Completed

Details of amount spent for repairing of roads in the year 2019-20 to 2022-23 (upto 16.02.2023)			
Sr. no.	**Name of Road**	**Amount spent on repairing of roads (Rs.)**	**Remarks**
	Usha to H/o Shakuntala & Shiv Mandir & h/o Karambir Mayna to H/o K.L. Malhotra H/o Kyamuddin to H/o Sukhwant Kaur, Mangal Sain in Chinyot Colony, W-19, Rtk.		
14	Const. of Mastic layer from shop of Ishwar Property to H. No. 1415, Kusum Kunj, H. NO. 1214 to H. No. 1221 in sector-1, in w-11 Rtk.	9,806,755.00	Work Completed
15	Const. of Mastic streets from Amrit Lal Girdhar H/o Sardar Gajender singh H/o Hariom Kumar H/o Yashpal H/o Gaba H/o Maddu, Kanta Sharma, H/o Manoj to Gulshan Dairy H/o Krishan Lal H/o Inder Kumar Saini near Shiv Park H/o Sarvan Kumar Gupta H/o Badri Nath Malhotra and various approaches Streets in W-19, Rtk.	7,590,349.00	Work Completed
16	P/L of Mastic layer in Partap Bazar Road, Kewal Ganj Road and Krishna Bazar Road W-17, Rtk.	9,728,432.00	Work Completed
17	Const. of Street with IPB from Shani Mandir to Naya Johad Jind Road H/o Harish H/o Bamaliya W-5, Rtk.	8,908,799.00	Work Completed
18	Maintenance and Misc. Civil works at various places in W- 6 to 10, Rtk.	4,184,235.00	Work Completed
19	P/l of Mastic layer from Aakashwani Chowk to New Bus Stand road via Prem nagar Chowk W-7, Rtk.	9,020,000.00	Work Completed
20	P/l of Mastic layer from Prem Nagar Chowk to Divya Yog Mandir W-7, Rtk.	7,129,000.00	Work Completed
21	Maintenance and Misc. civil works at various places in W-1 to 5, Rtk.	1,281,383.00	Work Completed
22	Const. of CC and Mastic Road from main road via Tara Hotel wali gali via. H/o Nitu Singhpuria and Side Gali of Nitu SinghPuria in Janta Colony W-18, Rtk.	6,337,849.00	Work Completed
23	P/l of Mastic Layer in road of HUDA Complex W-15, Rtk.	24,053,918.00	Work Completed
24	P/l of Mastic Layer from Bhagat Singh Parking to Jind Road and Standard Sweets to Mata Darwaja Chowk via. M.S. Saraswati School W-17, Rtk.	7,663,277.00	Work Completed
25	Repair of various roads in W- 11 to 15 in M.C. Rtk.	2,488,763.00	Work Completed

Details of amount spent for repairing of roads in the year 2019-20 to 2022-23 (upto 16.02.2023)			
Sr. no.	**Name of Road**	**Amount spent on repairing of roads (Rs.)**	**Remarks**
26	Maintenance & Misc. Civil works at various places in W -16 to 22, Rtk.	998,414.00	Work Completed
27	Const. of Mastic Road from Sonipat stand to via. BalajI Sweets to D.N. School to New Bus Stand in W-13, Rtk.	5,386,000.00	Work Completed
28	P/l of Mastic layer from Charkhamba to Navjeevan Hospital W-13, Rtk.	8,247,947.00	Work Completed
29	Const. of CC Street from ASTA LA VISTA Restaurant to Laxmi Auto Store & branch gali upto Surya Electric near Appu Ghar W-6, RTk.	8,463,070.00	Work Completed
30	Const. of CC Street from h/o Nitu along Park & approaches street of W-7, Rtk.	7,793,181.00	Work Completed
31	Const. of various CC Street from H/o Anuraj Sharma to H/o Vikas Bhatia, Pappu Halwai wali gali near mata Mandir Chowk & Branch Street H/o Jagdish to H/o Madan Sehgal, Chander lal & H/o Bahadurchand to H/o Rinku Nagpal in Tej Colony, Para Mohalla & Gohana Adda in W-17, Rtk.	5,426,075.00	Work Completed
32	Const. of CC Street from H/o Desraj Bahal to H/o Sandeep Sachdeva, Krishna Colony, H/o Shadi Lal vij to H/o Shyam Lal Pahwa, H/o Lal ji Garments, Ganpati Bhujia, Vinod textile (Aryavrat Transport back side street dairy market & H/o Parveen Bhudiraja to H/o Krishan Lal Pahwa Dairy Market near Old Bus Stand in Krishna Colony & Dairy Market in W-17, Rtk.	6,355,968.00	Work Completed
33	Const. of CC Street & laying of Sewer line from Balaji Photostate to H/o Roshan & Fateh Singh to Mahabir Kundu in W-6, Rtk.	2,839,398.00	Work Completed
34	Const. of Street from Lavleen wali gali, Manohar wali Gali & MLA Shakuntla Khatak, Ajit Singh wali gali to Airtel Towers, Anil Hooda wali gali & Hari Mandir Dairy wali gali in Adarsh Nagar, W-14, Rtk.	4,757,041.00	Work Completed
35	Const. of Mastic Layer from H. No. 247 P. Gupta House to Market and H. No. 1457 to H. No. 1586 in Sector-2 in W-11, Rtk.	9,926,186.00	Work Completed

Details of amount spent for repairing of roads in the year 2019-20 to 2022-23 (upto 16.02.2023)			
Sr. no.	**Name of Road**	**Amount spent on repairing of roads (Rs.)**	**Remarks**
36	Const. of CC Street from H/o Man Singh Ex. M.C. wali gali (Nand Colony) Shiv Mandir wali gali (Nand Colony) side street of Shiv Mandir wali gali Indira Chowki to Indira Colony Chowk in Nand Colony & various street in Sanjay Colony W-3, Rtk.	5,701,889.00	Work Completed
37	Const. of street with IPB from infront of Poonam Sweets near railway line Kanheli Road H/o Surender Sarpanch to H/o Lalit Deswal, H/o Sanjay Hooda to H/o Parvesh Contr. H/o Randhir to H/o Anil Contr. H/o Jagdish to H/o Surender Rathi H/o Jagdish to H/o Mahavir, H/o Karan Singh H/o Khan wali gali to H/o teju H/o Satbir to H/o Avdesh Thakur Mata mandir wali gali H/o Anup Singh, Ekta Colony W-20, Rtk.	9,966,874.00	Work Completed
38	Const. of CC Street from H/o Om Parkash Pruthi to H/o Pandit Radheshyam Sharma, shop of Shiv Tent house to H/o Rahul, H/o Somnath Sharma to H/o madan Public Park to H/o Shyam H/o Raju Churi wala to H/o Nikka Ande wala & H/o Ishwar Anand to H/o Vicky Sharma in Gandhi Nagar W-14, Rtk.	3,026,450.00	Work Completed
39	Const. of CC Street from Subji Mandi Chowk to Public Health Disposal, tilak raj M.C. gali in Nand Colony, W-3, Rtk.	5,478,171.00	Work Completed
40	Const. of CC Street from H/o Teju to H/o Ramajor H/o Naresh malik H/o Jagat H/o Vishnu H/o Deepak to H/o Sonu, infront of Chawla Electronics Tony wali Gali H/o Mahender Deepak Suit Centre to H/o Azad Singh H/o Anand Singh to H/o Manoj Pandit etc. Ekta Colony W-20, Rtk.	6,508,357.00	Work Completed
41	Const. of CC Raod from H/o Rinku Kapoor, Sanjay Sehgal H/o Anita Miglani H/o Narender Kapoor to H/o Ashok Maharaj in W-19, Rtk.	5,216,236.00	Work Completed

Details of amount spent for repairing of roads in the year 2019-20 to 2022-23 (upto 16.02.2023)			
Sr. no.	**Name of Road**	**Amount spent on repairing of roads (Rs.)**	**Remarks**
42	Const. of Street from Ashoka road to mahesh Bharti School, Mata Mandir wali gali Sanjay Nijhawan wali gali, Jawa gurudwara & Tony Pandit wali gali, Arya Dharmarh Dispensary wali gali, Dinesh Takkar wali gali, Mange Ram wali Gali, Shekhar Manocha wali Gali near SRS Junior wing & Batra Travel wali gali in Gandhi Camp market area W-14, Rtk.	4,986,003.00	Work Completed
43	Const. of street with IPB tiles from h/o Mangat to H/o Kamal Nayan Chopra and Branch Streets, H/o Mahender to H/o Kawal Nayan Gandhi and branch streets and various streets, H/o Rammehar to H/o Sudhir Batra and Branch Streets, foundation school back side and branch streets and H/o Anand Kiryana Store to Kamla Sadan and Branch Streets in W-19, Rtk.	7,743,558.00	Work Completed
44	P/L of Mastic layer from Mandi to Shiv Mandir, Main street Khanna Coaching Centre, Romi Chawla and Tikona Park street infront of Ramlila park, street along park side, street along ramlila park and street near Tikona Park, Shivaji Colony W-19, Rtk.	2,997,378.00	Work Completed
45	Const. of CC Street from h/o Vashu Dev to H/o Jagdish Kabari wala and Govind Dhingra to H/o Parkash ishpuniyani in Gandhi Nagar W-14, Rtk.	4,888,976.00	Work Completed
46	Const. of streets from h/o Mohit Khanna wali gali, Atta Chakki wali gali infront of Community Centre, H/o Rakesh Khurana wali gali, Pahwa crockery wali gali, Miglani crockery to Sapna Jewellers wali gali, Kamal Kapoor wali gali Ashok dairy wali gali Sitaram Sachdeva wali gali Sant lal Pruthi wali gali, Amrika nand Kutia to H/o Inder Sharma Gandhi nagar, Disposl wali gali and approach gali in jawahar nagarand Gandhi Camp W-14, Rtk.	4,851,271.00	Work Completed
47	P/F of IPB tile H/o Lakpat Hooda H/o Sushil Kumar H/o Dayanand wali gali in Rainakpura W-3, Rtk.	789,120.00	Work Completed

Details of amount spent for repairing of roads in the year 2019-20 to 2022-23 (upto 16.02.2023)			
Sr. no.	**Name of Road**	**Amount spent on repairing of roads (Rs.)**	**Remarks**
48	Const. of CC Street from h/o tarachand Nandal to H/o Pankaj yadav j.E. in Tilak Nagar W-12, Rtk.	1,055,676.00	Work Completed
49	Const. of CC Street from H/o Parveen Narang to H/o yashpal Bhatia and approach street, H/o pawan to H/o Charanjeet Girdhar, Dr. S.K. Khurana and approach street, h/o Sardar Bijli to H/o Janak Juice Satish and Branch Street H/o Arvind to H/o Vinod H/o gulab Singh Ranga H/o Anil Sehgal to H/o Saroj Wadhwa and H/o Sunder to H/o Rajesh in W-19, Rtk.	7,711,178.00	Work Completed
50	Maintenance and Misc. work at various places in W-6 to 8, Rtk.	713,738.00	Work Completed
51	Const. of Street with IPB from Dr. Sunita to Naya johad via Jind Road, H/o Raju Sikka to Krishan Kabir Dharamshala & H/o Suresh to shop of Sanjay W-5, Rtk.	7,943,984.00	Work Completed
52	Const. of Streets near Ramleela Ground, Sharma Auto Works towards Ramleela Ground near Sharma Auto works, Hotel Natraj wali gali near Arjun Park Shardanand wali Gali near Saluja Baggi wala and Hanuman Mandir in Gandhi Camp and Siyarama wali gali in Adarsh Nagar W-14, Rtk.	4,889,302.00	Work Completed
53	Maintenance and Misc. Civil Works at various places in W-20 & 21, Rtk.	775,312.00	Work Completed
54	Maintenance and Misc. Civil Works at various places in W-9 & 10, Rtk.	768,755.00	Work Completed
55	Repair of Road, filling of Pothole, Resolving Complaint of Harpath Social Media & CM Window & beautification of Road at varius locations in W- 1 to 22, Rtk.	4,894,910.00	Work Completed
56	Repair of Roads at various places & resolving of Harpath, Social Media Complaint & P/F of SignBoard, M.C. Rtk.	3,763,406.00	Work Completed
57	Maintenance & Misc. Civil works at various places in W- 16 to 18, Rtk.	1,155,504.00	Work Completed
58	Const. of CC Street from H/o Sher Rathee to Daksh Gym and Dharambir Deshwal wali gali, Janta Colony, W-18, Rtk.	2,490,446.00	Work Completed

Details of amount spent for repairing of roads in the year 2019-20 to 2022-23 (upto 16.02.2023)			
Sr. no.	**Name of Road**	**Amount spent on repairing of roads (Rs.)**	**Remarks**
59	P/L IPB tile from Maya to H/o Bijender, Subhash to Anup Singh Subhash to Rajesh, Krishan Pawaria wali gali, Raju to Dr. Krishan,Bijender to H/o Kishor, Ahlawat Bhawan to Brigmohan, Bijender to Ahlawat Bhwan, Kishor to naresh in Vijay Nagar, W-19, Rtk.	3,961,311.00	Work Completed
60	Const. of CC Street from H/o Brij Nandal to H/o Pardeep Singh Maan, Chhotu Ram Nagar near Power House W-12, Rtk.	733,547.00	Work Completed
61	Maintenance and Misc. Civil Works at various places in W-13 & 14, Rtk.	1,289,149.00	Work Completed
62	Const. of IPB 80mm street from Old police Station to new Police Station near Railway Line in Gandhi Camp W-19, Rtk.	1,041,983.00	Work Completed
63	Const. of Street from H/o Bhim Singh S/o Hari Ram in Surya Nagar Near Gohana Road, W-1, Rtk.	66,778.00	Work Completed
	Total	**335,545,657.00**	
Year 2020-21			
64	Maintenance and Misc. Civil works at various places in W-19 and W-22, Rtk.	783,629.00	Work Completed
65	Repairs of roads and filling of Pothole for Resolving Complaint of Harpath Portal on Various Location in W.No. 1 to 22 Rohtak.	747,363.00	Work Completed
66	Repair and Maintenance of Misc. Civil works at various place w no. 1 to 5 Rohtak	799,023.00	Work Completed
67	Repair of Road at Hooda Complex and old ITI Circular Road Rohtak.	90,979.00	Work Completed
68	Repair and Maintenance of Misc. Civil works at various place w no. 17 to 22 Rohtak	722,537.00	Work Completed
69	Repair of Patch with shelmac in various streets in ward no. 1 to 20 Rohtak	986,614.00	Work Completed
70	Repair and Maintenance of Misc civil works at various place w. no. 6 to 10 Rohtak	798,964.00	Work Completed
71	Const of iron jall for drains , gully chamber and patch for road repair in main bazar Rohtak	96,811.00	Work Completed
72	Const of CC street near shiv mandir in sunaria ward no. 22	1,491,858.00	Work Completed

Details of amount spent for repairing of roads in the year 2019-20 to 2022-23 (upto 16.02.2023)			
Sr. no.	**Name of Road**	**Amount spent on repairing of roads (Rs.)**	**Remarks**
73	Repair and Maintenance of Misc civil works at various place w. no. 11 to 16 rohtak	722,537.00	Work Completed
74	Repair of Maintenance Misc. Civil Works at various place in w. no. 14	294,220.00	Work Completed
75	Repair of Maintenance Misc. Civil Works at various place in w. no. 17	320,414.00	Work Completed
76	Repair of Sabji Mandi Street at gandhi camp w. no. 14	410,443.00	Work Completed
77	Supply for repair for patches with green bituminous compound material for MC area	99,633.00	Work Completed
	Total	**8,365,025.00**	
Year 2021-22			
78	Const. of street in Village Garhi Majra w.no. 10, Rohtak	1,059,739.00	Work Completed
79	Const of CC road from prem nagar chawla to city park jail road w. no. 5 Rohtak	10,041,630.00	Work Completed
80	P/L of Various IPB Streets in Sukhpura & Uttam Vihar ward no. 7, Rohtak.	315,060.00	Work Completed
81	Const. of IPB Street from Nonand Mor to H/o Kawar with approaches in village Baliyana, ward no, 10 Rohtak.	623,279.00	Work Completed
82	Const. of Street (B.I. no. 542/13361 and B.I. no. 903/13311, 904/13312) in Bohar Village, Ward no. 09, Rohtak	1,499,211.00	Work Completed
83	Const. of IPB back side of Mandir and Foji wali Gali Sunaria, ward no. 22, Rohtak.	1,956,480.00	Work Completed
84	Repair and Maitenance of Misc. Civil Works at various places in ward no. 18, Rohtak.	80,312.00	Work Completed
85	Repair and Maitenance of Misc. Civil Works at various places in ward no. 19, Rohtak.	80,100.00	Work Completed
86	Repair and Maitenance of Misc. Civil Works at various places in ward no. 20, Rohtak.	90,616.00	Work Completed
87	Repair of Roads by Pothole filling and patch work in ward no. 22, rohtak.	95,217.00	Work Completed
88	Repair of Roads by Pothole filling and patch work in ward no. 19, rohtak.	82,768.00	Work Completed
89	Repair of Roads by Pothole filling and patch work in ward no. 21, rohtak.	96,884.00	Work Completed

Details of amount spent for repairing of roads in the year 2019-20 to 2022-23 (upto 16.02.2023)			
Sr. no.	**Name of Road**	**Amount spent on repairing of roads (Rs.)**	**Remarks**
90	Const of CC street Press Kmani via H/o Vishal to H/O Ratanlal gurunanak gali w.no. 3, Rohtak	741,303.00	Work Completed
91	Repair and Maintenance of Misc. Civil Works of various place at w.no. 6, Rohtak	375,584.00	Work Completed
92	Repair and Maintenance of Misc. Civil Works of various place at w.no. 15, Rohtak	376,157.00	Work Completed
93	Repair of DLF road near main sbi bank w.no.14, Rohtak	60,503.00	Work Completed
94	Repair and Maintenance of Misc. Civil Works of various place at w.no. 12, Rohtak	376,814.00	Work Completed
95	Const of street from sohna niwas House No. 1309/19 Suresh Chand Jain, House of Rajender House no. 1301/19 Shant Nagar w.no. 16, Rohtak	724,410.00	Work Completed
96	Repair and Maintenance of Misc. Civil Works of various place at w.no. 21, Rohtak	330,715.00	Work Completed
97	Repair and Maintenance of Misc. Civil Works of various place at w.no. 9, Rohtak	379,068.00	Work Completed
98	Repair and Maintenance of Misc. Civil Works of various place at w.no. 10, Rohtak	363,216.00	Work Completed
99	Repair and Maintenance of Misc. Civil Works of various place at w.no. 22, Rohtak	356,136.00	Work Completed
100	Repair and Maintenance of Misc. Civil Works of various place at w.no. 19, Rohtak	272,036.00	Work Completed
101	Repair and Maintenance of Misc. Civil Works of various place at w.no. 8, Rohtak	368,072.00	Work Completed
102	Repair and Maintenance of Misc. Civil Works of various place at w.no. 11, Rohtak	376,121.00	Work Completed
103	P&L of IPB Street in Tej colony in w. no. 6, Rohtak	1,686,433.00	Work Completed
104	P&L of IPB Street in Rainkepura in w.no. 5	1,677,374.00	Work Completed
105	Repair and Maintenance of Misc. Civil Works of various place at w.no. 13, Rohtak	375,644.00	Work Completed
106	Upgradation of street from H/o Tarun Chawla near hans kiryana store via foundation school shivaji colony w.no. 19	1,755,896.00	Work Completed

Details of amount spent for repairing of roads in the year 2019-20 to 2022-23 (upto 16.02.2023)			
Sr. no.	**Name of Road**	**Amount spent on repairing of roads (Rs.)**	**Remarks**
107	Const of various IPB street repair and maintenance of misc civil work at various place at w.no. 14	1,695,991.00	Work Completed
108	Repair and Maintenance of Misc. Civil Works of various place at w.no. 16, Rohtak	97,503.00	Work Completed
109	Repair and Maintenance of Misc. Civil Works of various place at w.no. 1, Rohtak	374,497.00	Work Completed
110	Repair and Maintenance of Misc. Civil Works of various place at w.no. 15, Rohtak	98,000.00	Work Completed
111	P&L of IPB in Kuaa Mohalla, ward no. 3, Rohtak	1,180,612.00	Work Completed
112	Const. of IPB Street in Parvesh Nagar, ward No. 8, Rohtak	1,500,632.00	Work Completed
113	P&L of IPB in various street and other Misc. Repair civil works in ward no. 15, Rohtak	546,450.00	Work Completed
114	Repair of Maintenance of Misc. Civil Works at Various places in Ward No. 18, Rohtak	375,877.00	Work Completed
115	P/L IPB Street from Bhavya Graphica to chaudhary gyan singh, Dev Colony and backside of krishan honda showroom and repair and htc of misc. civil works at various rtk	1,735,579.00	Work Completed
116	P/L of IPB Stret in Laxmi Colony back side Saraswati School w.no. 4 Rohtak	1,695,692.00	Work Completed
117	Const. of CC Street in Gali No.5, Arya Nagar W.No. 15, Rohtak	902,609.00	Work Completed
118	Repair of Maintenance of Misc. Civil Works at Various places in Ward No. 16, Rohtak	368,960.00	Work Completed
119	Repair and Maintenance of Misc. Civil Works at Various Places in Ward no. 7, Rohtak	96,728.00	Work Completed
120	Repair and Maintenance of Misc. Civil Works at Various Places in Ward no. 8, Rohtak	97,289.00	Work Completed
121	Const. of C.C Street in Pech Kapoor Chand near Railway Road ward no. 16, Rohtak	1,336,114.00	Work Completed
122	Repair of Roads by Pothole Filling and Patchwork in ward no. 5 Rohtak.	96,754.00	Work Completed
123	Const. of IPB Street Near Sant Kabir Park, Tej Colony Ward no. 6, Rohtak.	255,527.00	Work Completed

Details of amount spent for repairing of roads in the year 2019-20 to 2022-23 (upto 16.02.2023)			
Sr. no.	**Name of Road**	**Amount spent on repairing of roads (Rs.)**	**Remarks**
124	Repair of Maintenance of Misc. Civil Works at various places In ward no. 20, Rohtak	285,152.00	Work Completed
125	Const. of IPB Street in Gali No. 4&5, Ward no. 12, Rohtak.	1,130,032.00	Work Completed
126	Repair with Ready Mix Bitu minous Material like Shalmac (go green patches) for Harpath Portal Complaints in Ward no. 1 to 11, Rohtak	568,812.00	Work Completed
127	Repair with Ready Mix Bitu minous Material like Shalmac (go green patches) for Harpath Portal Complaints in Ward no. 12 to 22, Rohtak	569,365.00	Work Completed
128	Repair of Roads by Pothole Filling and Patchwork in ward no. 3 Rohtak.	96,068.00	Work Completed
129	Repair and Maintenance of Misc. Civil Works at various places in Ward no. 15. Rohtak	87,931.00	Work Completed
130	Repair of Roads by Pothole Filling and Patchwork in ward no. 15 Rohtak.	87,286.00	Work Completed
131	Repair of Roads by Pothole Filling and Patchwork in ward no. 1 Rohtak.	96,604.00	Work Completed
132	Repair of Roads by Pothole Filling and Patchwork in ward no. 8 Rohtak.	96,554.00	Work Completed
133	Repair of Roads by Pothole Filling and Patchwork in ward no. 7 Rohtak.	96,461.00	Work Completed
134	Repair of Roads by Pothole Filling and Patchwork in ward no. 2 Rohtak.	96,678.00	Work Completed
135	Repair of Roads by Pothole Filling and Patchwork in ward no. 6 Rohtak.	97,372.00	Work Completed
136	Repair and Maintenance of Misc. Civil Works at various places in Ward no. 9 Rohtak	93,866.00	Work Completed
137	Repair of Roads by Pothole Filling and Patchwork in ward no. 4 Rohtak.	96,938.00	Work Completed
138	Repair and Maintenance of Misc. Civil Works at various places in Ward no. 10 Rohtak	89,295.00	Work Completed
139	Repair of Roads by Pothole Filling and Patchwork in ward no. 10 Rohtak.	91,726.00	Work Completed
140	Repair of Roads by Pothole Filling and Patchwork in ward no. 9 Rohtak.	92,725.00	Work Completed

Details of amount spent for repairing of roads in the year 2019-20 to 2022-23 (upto 16.02.2023)			
Sr. no.	**Name of Road**	**Amount spent on repairing of roads (Rs.)**	**Remarks**
141	Repair and Maintenance of Misc. Civil Works at various places in Ward no. 4 Rohtak	97,316.00	Work Completed
142	Repair and Maintenance of Misc. Civil Works at various places in Ward no. 16 Rohtak	87,612.00	Work Completed
143	Repair of Roads by Pothole Filling and Patchwork in ward no. 16 Rohtak.	95,491.00	Work Completed
144	Repair of Road Patches in ward no. 1 to 22, Rohtak	52,197.00	Work Completed
145	Repair and Maintenance of Misc. Civil Works at various places in Ward no. 04 Rohtak	97,789.00	Work Completed
146	Repair of Raods by Pothole filling and Patchwork in w.no. 17, Rohtak.	88,876.00	Work Completed
147	Repair and Maintenance of Misc. Civil Works at various places in Ward no. 17 Rohtak	86,209.00	Work Completed
148	Repair and Maintenance of Misc. Civil Works at various places in Ward no. 14 Rohtak	81,904.00	Work Completed
149	Repair of Raods by Pothole filling and Patchwork in w.no. 12, Rohtak.	96,011.00	Work Completed
150	Repair of Raods by Pothole filling and Patchwork in w.no. 20, Rohtak.	92,278.00	Work Completed
151	Repair of Raods by Pothole filling and Patchwork in w.no. 11, Rohtak.	98,377.00	Work Completed
152	Repair of Raods by Pothole filling and Patchwork in w.no. 14, Rohtak.	83,299.00	Work Completed
153	Repair of Raods by Pothole filling and Patchwork in w.no. 18, Rohtak.	97,570.00	Work Completed
154	Repair of Raods by Pothole filling and Patchwork in w.no. 18, Rohtak.	83,000.00	Work Completed
155	Repair and Maintenance of Misc. Civil Works at various places in Ward no. 13 Rohtak	88,208.00	Work Completed
156	Repair and Maintenance of Misc. Civil Works at various places in Ward no. 3 Rohtak	94,939.00	Work Completed
157	Providing and Laying of IPB Street in front of Ashram main road jind chowk to hisar Bypass ward no. 2, Rtk.	1,559,081.00	Work Completed
158	Repair and Maintenance of Misc. Civil Works at various places in Ward no. 5 Rohtak	94,071.00	Work Completed

Details of amount spent for repairing of roads in the year 2019-20 to 2022-23 (upto 16.02.2023)			
Sr. no.	**Name of Road**	**Amount spent on repairing of roads (Rs.)**	**Remarks**
159	Repair and Maintenance of Misc. Civil Works at various places in Ward no. 7 Rohtak	97,867.00	Work Completed
160	Repair and Maintenance of Misc. Civil Works at various places in Ward no. 1 Rohtak	97,296.00	Work Completed
161	Const. of CC Street From H/o Manjeet to H/o Dharmbir in Janta Colony W.no. 18, Rohtak	1,958,470.00	Work Completed
162	Const. of Street from H/o Rajiv Sharma to H/o Narender Kundu, Surya Nagar, Ward no. 1, Rohtak.	500,000.00	Work Completed
163	Const. of IPB Streets H/o Snjay, H/o Sandeep, H/o Sombir and H/o Rajender Budhwar, Sunaria Kalan, ward no. 22, Rohtak.	976,634.00	Work Completed
164	Const. of IPB stret H/o Phol Singh, Rajender Singh to Amit Kumar ward no. 2, Rohtak.	170,755.00	Work Completed
165	Construction of IPB Streets from Jagriti High School to Gaukaran Park Ward No. 04, Rohtak.	593,869.00	Work Completed
166	Const. of IPB Street from H/o Hoshiyari devi PG H/o Jai Kishan H/o Santra devi to Shiv madir wali Gali, ward no. 08, Azaadgarh, Rohtak.	204,980.00	Work Completed
167	Construction of Street of Surender Batra Ex. Parshad, Shivaji Colony, ward no. 19, Rohtak	390,681.00	Work Completed
168	Const. of IPB Streets Gautam Electricals Near peepal wala chowk to Deepak Kumar 34/14A Sai Dass Colony, ward no. 6, Rohtak	177,993.00	Work Completed
169	Const. of Street from H.no. 50 to H.no. 100 in Housing Board ward no. 19, Rohtak	335,311.00	Work Completed
170	Const. of Street from H/o Miglani to Ashok Pani Wala Tak, Patel Nagar, Ward no. 19, Rohtak.	414,159.00	Work Completed
171	Const. of Street from Main street to H/o kuldeep to baba mast nath B/W ward no. 10, Rohtak.	421,830.00	Work Completed
172	Const. of Street H/o Jagbir Singh B.E.O. to Sandeep kumar Prajapati W.no. 12 Rohtak	390,961.00	Work Completed
173	Const. of IPB street from front of Mr. Raj Kumar 166/14 to Bhutani Medicos near Gohana Adda ward no. 6, Rohtak.	269,270.00	Work Completed

Details of amount spent for repairing of roads in the year 2019-20 to 2022-23 (upto 16.02.2023)			
Sr. no.	**Name of Road**	**Amount spent on repairing of roads (Rs.)**	**Remarks**
174	Const. of Street from SAPERO Wali Gali to Valmiki Basti, Patel Nagar, Ward No. 19, Rohtak.	251,323.00	Work Completed
175	Const. of Balmiki Wali Gali, New Janta Colony, Ward no. 18, Rohtak.	982,000.00	Work Completed
176	Pavement of IPB Near Revenue Colony, Rohtak	174,518.00	Work Completed
	Total	**54,326,602.00**	
Year 2022-23 (Upto 16-02-2023)			
177	Misc Civil works in Jasbir Colony ward No. 8, Rohtak	64,677.00	Work Completed
178	Repair of street in Jasbir Colony Pear H/o RK Phogat, ward No. 8, Rohtak	94,860.00	Work Completed
179	Repair of Street Near Balaji Hair Dressar, Jasbir Colony, Ward no. 8, Rohtak	89,984.00	Work Completed
180	Misc Civil Works Near Chinyot Colony Rohtak.	57,952.00	Work Completed
181	Const of Streets from H/o Ritesh Baldeva, H/o Ajit S/o Shyamlal B.I No. 1228/19389, H/o Anjali W/o Ashok, B.I No. 1203/119364, H/o Manoj S/o Hari Parkash B.l.No. 1191/19352, H/o Jitender S/o Phool Singh B.l. No. 1180/19341, Sunarian, Ward No. 22, Rohtak	1,421,261.00	Work Completed
182	Const of Streets from H/o Rambir S/o Jaipal B.I No. 1152/19316, Karambir B.I No. 1152/19311, H/o Mehar Singh S/o Kedar B.l.No. 190, H/o Devender S/o Ram Kumar, Sunarian, Ward No. 22, Rohtak	1,699,535.00	Work Completed
183	Const. of Street from H/o Dhanpati W/o Umed B.l No. 551/15679 Sunaria, Ward No. 22, Rohtak	1,508,233.00	Work Completed
184	Const. of street from H/o Mahender S/o Kapoor B.l. No. 1314 H/o Sopal S/o Ramkumar, B.L 1268/19429 H/o Ramphal S/o Hansu and H/o Mahabir B.L. No. 309/15330, Sunarian, Rohtak	1,214,841.00	Work Completed
185	Filling of Pothole and laying of GSB at Sec-01 & 02 Road in M.C Rohtak	38,525.00	Work Completed
186	Const. of Street (B.I No. 1291/13714, B.l.No. 1294/13717, B.l. no 1304/13728, B.l. no.1314/13738, B.l. no. 171/11535 and B.l. no.1333/13758, B.l. no.	1,281,924.00	Work Completed

Details of amount spent for repairing of roads in the year 2019-20 to 2022-23 (upto 16.02.2023)			
Sr. no.	**Name of Road**	**Amount spent on repairing of roads (Rs.)**	**Remarks**
	1326/13750) Bohar village, Ward no. 09, Rohtak		
187	Repair of streets infornt of Holy heart hospital, Ward no. 11, Rohtak	97,006.00	Work Completed
188	Filling of pothole and laying of GSB on road , Ward no. 8 in M.C Rohtak,	20,335.00	Work Completed
189	Repair of maintenance of Misc. Civil works Palika Colony in ward no. 18, rohtak	98,058.00	Work Completed
190	Repair and maintenance of Misc. Civil Works at Various places in ward no. 12, Rohtak.	96,250.00	Work Completed
191	Repair and maintenance of Misc. Civil works at various places in ward no. 6, Rohtak	88,939.00	Work Completed
192	Repair and maintenance of Misc. Civil works at various places in ward no. 22, Rohtak	118,107.00	Work Completed
193	Const. of IPB street of gali no. 4, sheetal nagar, ward no. 21, Rothak	1,564,864.00	Work Completed
194	Const. of CC street of gali no. 2, Ambedkar colony, ward no. 20, Rohtak	1,623,804.00	Work Completed
195	MTC of potholes with misc. civil works in ward no. 9,10,11,12, and 13, Rohtak	1,174,096.00	Work Completed
196	Const. of various CC Street and other misc. Repair on civil works in ward no. 17, Rothak	1,615,152.00	Work Completed
197	Maintenance of potheles with misc. civil works in ward no. 1 to 8 and 10, Rohtak	499,393.00	Work Completed
198	P/L IPB in various streets in Shastri Nagar and shiv nagar ward no. 2, rohtak	1,615,906.00	Work Completed
199	Maintenance of potholes with misc. civil work in ward. No. 14 to 22, Rohtak	1,639,933.00	Work Completed
200	Repair and maintenance of Misc. civil works at various places in ward no. 21, Rohtak	97,048.00	Work Completed
201	Const. of CC street in front of Rama Ashram Chinyot colony ward No. 19, MC. Rohtak	541,302.00	Work Completed
202	Const. of street from shop of Deepak Halwai to Bhupi Sharma, w.no. 18, Rohtak.	1,047,938.00	Work Completed

Details of amount spent for repairing of roads in the year 2019-20 to 2022-23 (upto 16.02.2023)			
Sr. no.	**Name of Road**	**Amount spent on repairing of roads (Rs.)**	**Remarks**
203	Const. of sytreet Natraj Hotel wali gai, ramnath gridhar wali gali, sunder lal kulra wali gali and vadilal wali gali, gandhi nagar ward. No. 14, Rohtak	484,122.00	Work Completed
204	Const. of CC Street near H/o Sachdeva H/o Gupta, Hari Nagar Colony and other misc civil work in wn. No. 15, rohtak	765,151.00	Work Completed
205	Const. of IPB street Jaat Dharamshala to Master Hukam Chand H. nO. 354, Uttam Vihar , ward No . 7, rohtak	1,349,551.00	Work Completed
206	P/L of IPB from corner of Govt. school up to Ritu ladies suit collection & boutique in Bohar Village Ward No. 9 MC Fund rohtak.	172,123.00	Work Completed
207	Const. of IPB Street from Delhi road to lighness hazel bonquet hall garhi bohar Village Ward No. 10, MC Fund Rohtak.	916,035.00	Work Completed
208	Const. of Street infront of Hanuman Handir H/o Dharpul slyh H/o Shyam Slyh Ekta Colony Ward No. 20 Rohtak.	1,043,273.00	Work Completed
209	Const. of C.C Street in Ward no. 15 Rohtak. 1. Verma Sunaro Guchi Gali Ghampura. 2 Shonty kabadi Wali gali Jagdish Colony. 3 Bakmiki Wali gali Ram nagar.	434,384.00	Work Completed
210	Const. of C.C. Street near H/o H.D. Fashion H/o laxmi nayare shyla to H/o vinod diwan (tul wali Gali) arya nagar and dhanno mandi Street jhajar Road ward 16 Rohtak,	651,900.00	Work Completed
211	MTC of potholes with Bituminous Compond materials ward no. 17 Rohtak.	95,161.00	Work Completed
212	Const. of IPB street shiv mandir wali gali Sant Santosh Bayan wlai gali Ward no. 1 Rohtak.	1,097,765.00	Work Completed
213	Const. of IPB Street Form K. N Interpriese to H/o Deepak Kaushik Gali no 8 Uttam vihar Ward no. 7 M.C. Rohtak	880,296.00	Work Completed
214	Const. of C.C. Street near Pizza bean wali Gali, Durga Colony, Deepak hooda wali gali, Prem Nagar & Gulshan Bhojnalya Backside Street, Ward no. 13 M.C. Rohtak	1,339,387.00	Work Completed

Details of amount spent for repairing of roads in the year 2019-20 to 2022-23 (upto 16.02.2023)			
Sr. no.	**Name of Road**	**Amount spent on repairing of roads (Rs.)**	**Remarks**
215	Const. of Street in Nehra Cable wali New Vijay nagar ward no. 21 Rohtak	1,273,727.00	Work Completed
	Total	**29,912,798.00**	
	Grand Total	**428,150,082.00**	

Annexure-A (II)

Municipal Corporation, Rohtak

Details of estimated amount for repairing of roads from 01-02-2023 to 16-02-2023			
Sr. no.	**Name of Road**	**Estimated expenditure for repairing of roads (Rs. in Lakh)**	**Status**
1.	Repair of Potholes with Jet Patcher Mechanism in Ward No. 09, M.C. Rohtak.	10.00	Work in progress
2.	Estimate for Patch Work of Bitumen Roads in Sector 1, 2 and 14 in Ward-11, M.C. Rohtak.	24.91	Work in progress
3.	Estimate for Patch Work of Bitumen Roads in Sector 2, 3 Part in Ward-12, M.C. Rohtak.	17.94	Work in progress
4.	Repair of Potholes with Jet Patcher Mechanism in Ward No. 14, M.C. Rohtak.	1.61	Work in progress
5.	Repair of Potholes with Jet Patcher Mechanism in Ward No. 17, M.C. Rohtak.	2.36	Work in progress
6.	Repair of Potholes with Jet Patcher Mechanism in Ward No. 19, M.C. Rohtak.	1.69	Work in progress
7.	Repair of Potholes with Jet PatcherMechainism in Ward No. 13, M.C. Rohtak.	12.00	Work in progress
8.	Repair of Potholes with Jet PatcherMechainism in Ward No. 15, M.C. Rohtak.	3.00	Work in progress

9.	Repair of Potholes with Jet PatcherMechainism in Ward No. 16, M.C. Rohtak.	4.00	Work in progress
10.	Repair of Potholes with Jet PatcherMechainism in Ward No. 18, M.C. Rohtak.	3.35	Work in progress
11.	Repair of Potholes with Jet PatcherMechainism in Ward No. 20, M.C. Rohtak.	2.16	Work in progress
Total		**83.02**	

Annexure- A (III)
Municipal Corporation, Rohtak

Details of estimated amount for repairing of roads from 01-02-2023 to 16-02-2023			
Sr. no.	**Name of Road**	**Estimated expenditure for repairing of roads (Rs. in Lakh)**	**Status**
1	Repair, Maintenance of Potholes and Misc. Civil Works in Ward No. 1, M.C. Rohtak.	24.98	Tender received and under process for approval
2	Repair, Maintenance of Potholes and Misc. Civil Works in Ward No. 2, M.C. Rohtak.	24.99	Tender received and under process for approval
3	Repair, Maintenance of Potholes and Misc. Civil Works in Ward No. 3, M.C. Rohtak.	25.00	Tender called for 22-02-2023
4	Repair, Maintenance of Potholes and Misc. Civil Works in Ward No. 4, M.C. Rohtak.	25.00	Tender called for 22-02-2023
5	Repair, Maintenance of Potholes, Street Renovation and Misc. Civil Works in Ward No. 5, M.C. Rohtak.	24.99	Tender received and under process for approval
6	Repair, Maintenance of Potholes, Street Renovation and Misc. Civil Works in Ward No. 6, M.C. Rohtak.	24.97	Tender under process
7	Repair, Maintenance of Potholes and Misc. Civil Works in Ward No. 7, M.C. Rohtak.	24.98	Tender called for 22-02-2023
8	Repair, Maintenance of Potholes and Misc. Civil Works in Ward No. 8, M.C. Rohtak.	24.97	Tender called for 22-02-2023

Details of estimated amount for repairing of roads from 01-02-2023 to 16-02-2023			
Sr. no.	**Name of Road**	**Estimated expenditure for repairing of roads (Rs. in Lakh)**	**Status**
9	Estimate for Repair Work of Streets, Replacement of Damaged Manhole Cover, Construction of G.T. at Various in Ward No. 9, M.C. Rohtak.	15.00	Tender to be re-called
10	Estimate for Repair Work of Streets, Replacement of Damaged Manhole Cover, Construction of G.T. at Various in Ward No. 10, M.C. Rohtak.	24.96	Tender received and under process for approval
11	Estimate for Repair Work of Streets, Replacement of Damaged Manhole Cover, Construction of G.T. at Various in Ward No. 12, M.C. Rohtak.	7.16	Tender received and under process for approval
12	Upgradation of Streets, Repair of Potholes and Misc. Civil Works in Ward No. 13, M.C. Rohtak.	13.00	Tender received and under process for approval
13	Const. of Streets and Misc. Civil Repair Works in Ward No. 14, M.C. Rohtak.	23.39	Tender called for 22-02-2023
14	Upgradation of Streets by Repair and Potholes and Misc. Civil Works in Ward No. 15, M.C. Rohtak.	22.00	Tender called for 22-02-2023
15	Upgradation of Streets and Repair and Patches and Misc. Civil Works in Ward No. 16, M.C. Rohtak.	21.00	Tender called for 22-02-2023
16	Const. of Streets and Misc. Civil Repair Works in Ward No. 17, M.C. Rohtak.	22.64	Tender called for 22-02-2023
17	Repair, Maintenance of Pothole and Misc. Civil Works in Ward No. 18, M.C. Rohtak.	21.65	Tender called for 22-02-2023
18	Const. of Streets and Misc. Civil Repair Works in Ward No. 19, M.C. Rohtak.	23.31	Tender called for 22-02-2023
19	Repair, Maintenance of Pothole and Misc. Civil Works in Ward No. 20, M.C. Rohtak.	22.84	Tender called for 22-02-2023
20	Const. of Streets and Misc. Civil Repair Works in Ward No. 21, M.C. Rohtak.	23.39	Tender called for 22-02-2023
21	Estimate for Repair Work of Streets, Replacement of Damaged Manhole Cover, Construction of G.T. at Various in Ward No. 22, M.C. Rohtak.	24.99	Tender called for 22-02-2023
	Total	**465.21**	

Annexure -B

Fund Released to Municipal Corporation Rohtak for the year 2021-22 and 2022-23 (As on 16.02.2023)			
			(Rs.in Lakh)
Sr.No.	**Name of the Scheme**	**Fund Released 2021-22**	**Fund Released 2022-23 (As on 16.02.2023)**
1	State Finance Commission (SFC)	5755.17	7694.23
2	Central Finance Commission (CFC)	940.52	961.22
3	Scheme for compensation of loss of commercial property of small shopkeepers because of natural disasters	0.00	1170.09
4	Mukhyamantri Samagra Shahri Vikas Yojna	2869.23	0.00
5	Stamp Duty	1332.00	0.00
6	SBM	578.07	1540.00
7	AMRUT	4762.62	3922.66
	Total (Rs.in Lakh)	**16237.61**	**15288.20**
	Total (Rs.in Crore)	**162.38**	**152.88**

Note:- (i) An amount of Rs. 29.66 Crores was granted as loan to Municipal Corporation, Rohtak on 11.09.2019 on account of rehabilitation of displaced people due to construction of Elevated Railway Track on Rohtak-Gohana Railway Track. An amount of Rs. 16.18 crores during F.Y. 2021-22 and Rs. 15.88 crores during F.Y. 2022-23 (totalling Rs. 32.06 Crores including interest) were recouped out of SFC Grant from Municipal Corporation, Rohtak.

(ii) The above recouped amount of Rs. 32.06 Crores has been included in the SFC amount shown in the above table at Sr. No. 1 i.e,. Rs. 16.18 crores was of F.Y. 2021-22 and Rs. 15.88 crores was of F.Y. 2022-23.

श्री भारत भूषण बत्तरा: माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि डिपार्टमैंट्स में आपस में कॉआर्डिनेशन नाम की कोई चीज नहीं है। मैंने पिछले दिनों विधान सभा सचिवालय के थ्रू एक क्वैरी लगायी थी जिसका रिप्लाई यह आया है कि रोहतक को कोई भी ग्रान्ट नहीं दी गयी है। यह रिप्लाई मेरे पास है और आप कहें तो मैं

इसको सदन के पटल पर रख दूंगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस सरकार ने रोहतक को गढ्डों का शहर बना दिया है। इन्होंने रिप्लाई में माना है कि वहां पर 24 सड़कें टूटी हुई हैं। इन्होंने मेरी क्वैरी के संबंध में दिये गये रिप्लाई में माना है कि सैक्टर–1, सैक्टर–2, सैक्टर–3 और सैक्टर–4 की सड़के टूटी पड़ी हैं और इनके लिए सिर्फ 2 करोड़ रुपये दिये गये हैं। मुझे पता नहीं ये किस हिसाब से अमाउंट दे रहे हैं? मैंने इनके लिए बजट के एस्टीमेट्स के अलावा कुछ दूसरी चीजें भी मांगी हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि मेरे पास अखबार (Tribune) की कटिंग है, उसमें लिखा हुआ है कि–

> The Rohtak Municipal Corporation has failed to address the pressing concerns of the city residents, with even the top authorities citing lack of funds and expressing helplessness in fulfilling their mandate.

इन्हीं की पार्टी के मेयर ने भी इसी अखबार में स्टेटमैंट दी है जोकि इस प्रकार है –

> "I have tried to do my best, but have not been able to ensure the provision of good roads, parks, sewerage and other civic amenities ………"

अध्यक्ष महोदय, इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में नहीं बैठे हुए हैं। मैंने इनसे ब्यौरा मांगा था कि वर्ष 2019–20, वर्ष 2020–21 और वर्ष 2021–22 में म्युनिसिपल कमेटी ने कितना कैपिटल एक्सपैंडीचर खर्च किया है ? इस पर विभाग का रिप्लाई 000 में आया है। ये कहां से संबंधित आंकड़ें दिखा रहे हैं? 'Roads' is capital expenditure. इसमें मेरा कहना यह है कि या तो आज

सदन में दिया गया रिप्लाई गलत है या पहले दिया गया रिप्लाई गलत है। यह बात ठीक है कि सरकार करनाल पर मेहरबान है, वहां पर थोड़ा– सा ज्यादा कैपिटल एक्सपैंडीचर ज्यादा है। माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री जी हिसार के हैं, लेकिन वे इस वक्त सदन में नहीं हैं। वहां पर भी कैपिटल एक्सपैंडीचर है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जाट कॉलेज में 4 मई, 2022 को सम्मेलन में एक घोषणा की थी। उस समय उन्होंने कहा था कि मैं रोहतक के लिए 120 करोड़ रुपये की ग्रांट की घोषणा करता हूं, वह 120 करोड़ रुपये कहां गये? It is the announcement made by the Chief Minister. अभी सदन में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बैठे हैं हालांकि इन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं देना है। मैंने दिल्ली रोड को बनाने के लिए शोर मचाया था लेकिन वह रोड तो बना दी गई परन्तु दिल्ली रोड की कंडीशन अच्छी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, बाबा मस्तनाथ के साथ सड़क बोहर को जाती है। वहां पर सड़क इतनी टूटी हुई है कि वहां पर कोई आदमी किसी भी हालत में जा नहीं सकता है। सोनीपत रोड से नीचे नांदल भवन की तरफ आओ तो वहां पर सड़क टूटी पड़ी है। सारे शहर में सब जगहों से सड़कें टूटी पड़ी हैं। तिलयार के सामने सड़क की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है और सरकार का हाल तो बुरा है ही। मैं पिछले दिनों समाचार पत्र पढ़ रहा था कि पंचकूला जिले में भी सड़कों का बुरा हाल है वहां पर गड्ढे बने हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, आप तो सत्ता के अंदर शक्तिशाली आदमी हैं। आपसे डरकर सब कुछ कर देते होंगे। आप इनको कहो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गड्ढों की सरकार मत बनाओ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, आप अपना सैप्लीमैंट्री पूछिये।

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह सवाल नहीं है। क्वैश्चन आवर में भाषणबाजी नहीं होनी चाहिए।

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा। अभी डॉ. कमल गुप्ता जी सदन में उपस्थित नहीं है क्योंकि माननीय मंत्री श्री दलाल साहब उनके बिहाफ पर जवाब दे रहे हैं। आप मुझे यह बतायें कि रोहतक शहर की सड़कें अच्छी कंडीशन में मुक्कमल कितने दिनों में या कितने महीनों में कर देंगे? क्या रोहतक म्युनिसिपल कारपोरेशन को आप कोई स्पैशल ग्रांट देंगे या नहीं? गुरूग्राम के अंदर 38% mishaps due to the path holes. गुरूग्राम का यह हाल है। माननीय मुख्यमंत्री जी हर रोज गुरूग्राम पहुंचे होते हैं और वहां की सड़कों का यह हाल है कुछ और मत करो, कम से कम वहां पर सड़कें, पानी और सीवरेज की व्यवस्था का इंतजाम तो कर दो। हम खुश हो जायेंगे तथा हमें सरकार से और उम्मीद भी नहीं है।

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, रोहतक शहर को वर्ष 2021–22 में स्टेट फाइनैंस कमीशन से 57.55 करोड़ रुपये दिये गये और वर्ष 2022–23 में 76.94 करोड़ रुपये दिये गये। सैंट्रल फाइनैंस कमीशन से 9.44 करोड़ रुपये दिये गये और Scheme for Compensation of loss of Commerical Property के 11. 70 करोड़ रुपये दिये गये। मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के तहत वर्ष 2021–22 में 28.72 करोड़ रुपये दिये गये। स्टाम्प ड्यूटी के 13.32 करोड़ रुपये दिये गये। अमृत योजना के तहत 47.62 करोड़ रुपये दिये गये। वर्ष 2021–22 में कुल 162. 38 करोड़ रुपये दिये गये। वर्ष 2022–23 में 152.88 करोड़ रुपये दिये गये। इसके अलावा 29.66 करोड़ रुपये की लोन के रूप में ग्रांट भी दी गई थी। इसको हमने वापिस रिकवर भी कर लिया था। हमने वहां पर पैसा दिया है।

श्रीमती शकुंतला खटक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि वह पैसा कहां लगाया?

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, उस पैसे को रोहतक शहर में ही लगाया है। उस पैसे से आगे लोकल बॉडीज में जो वहां की चुनी हुई सरकार है वह काम करवाती है। सरकार के द्वारा रोहतक शहर का जो हक बनता है उसको दिया जायेगा। जिस तरह से हरियाणा के बाकी जिलों को पैसा दिया जाता है उसी तरह से रोहतक शहर को भी पैसा दिया जायेगा।

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, मेरी एक सप्लीमैंट्री है। इन्होंने पिछले 3 सालों का 284 करोड़ रुपये की एक्चुवल इन्कम का ब्यौरा दिया है जबकि एक्चुवल रेवेन्यू एक्सपैंडीचर 325 करोड़ रुपये है। जब इनका रेवेन्यू एक्सपैंडीचर ही पूरा नहीं होता तो फिर सरकार ग्रांटों के पैसे में रेवेन्यू एक्सपैंडीचर का पैसा डालती होगी? मेरे कहने का मतलब यही है कि सरकार उस पैसे को कहां पर ले जाती होगी? अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए आपसे रिक्वैस्ट करूंगा कि आधे घंटे की डिबेट इस सदन के अंदर हो कि म्युनिसिपल कारपोरेशन और म्युनिसिपल कमेटी को स्ट्रैंग्थन करने के लिए कोई न कोई बात करनी चाहिए कि चाहे इसके लिए स्टेट फाइनैंस कमीशन से पैसे आये, चाहे गवर्नमैंट ग्रांट दे। अगर म्युनिसिपल कमेटीज को अपने पर डिवैल्पमैंट के लिए छोड़ेंगे तो कैसे बात बनेगी? मेरे ख्याल से माननीय सदस्य श्री असीम गोयल जी भी मेरी इस बात से एग्री करेंगे क्योंकि तनख्वाह ही मुश्किल से पूरी होती है। जैसे सरकार गांव के विकास कार्यों के लिए पंचायतों को पैसे देती है, उसी तरह से शहरों में भी म्युनिसिपल कमेटीज को ग्रांट क्यों नहीं दी जाती है? यह चिंतन का विषय है।

अटेली को उप-मंडल के रूप में घोषित करना

*** 31. श्री सीता राम यादवः** क्या उप-मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि-

(क) क्या यह तथ्य है कि अटेली को उप-मंडल के रूप में घोषित करने के लिए सरकार द्वारा एक समिति को गठित किया गया है; यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट क्या है; तथा

(ख) अटेली को कब तक उप मंडल घोषित किए जाने की संभावना

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant chautala) : Yes, Sir, there is a proposal to establish a Sub-division in Ateli. Since the matter is still under consideration, it is not possible to specify a time frame in this regard. अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि कमेटी के पास अटेली तहसील को उप मंडल बनाने का प्रपोजल आया हुआ है जो सरकार के अंडर कन्सीड्रेशन है, लेकिन इसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन नहीं दी जा सकती क्योंकि बारी–बारी से सैंट्रल गवर्नमैंट सैंसस की बाउंड्री के नोटिसज प्रदेश सरकार को भेजती रहती है। हम नए सैंसस का भी इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ–साथ एक एरिया पॉपुलेशन का रिव्यू कर रहे हैं कि सब डिविजन में, तहसील में और डिस्ट्रिक्ट में कितना होना चाहिए ? विभाग उसके लिए काम कर रहा है और जब उसकी रिपोर्ट सब्मिट होगी, उसके बाद ही संबंधित प्रपोजल कंसीडर होगी।

श्री सीताराम यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि दिनांक 10.10.2017 के पत्र क्रमांक 2730 और दिनांक 13.02.2020 के पत्र क्रमांक 3490 के द्वारा उपायुक्त महोदय नारनौल ने रिपोर्ट पेश की है। जिसमें अटेली तहसील को उप मंडल बनाने के लिए सरकार द्वारा जो नार्म्स निर्धारित किए गए हैं, वे सभी नार्म्स अटेली तहसील पूरा करती है। जिसमें 16 पटवार हल्के व 60 गांव सम्मिलित किए जाने प्रस्तावित हैं, जिनमें उपरोक्त प्रारूप के क्रमांक 1 से 14 पटवार हल्का व 52 गांव तहसील अटेली में स्थित हैं तथा 1 पटवार हल्का मुण्डिया खेड़ा व 4 गांव तहसील कनीना में स्थित हैं तथा 1 पटवार हल्का गुवानी व 4 गांव तहसील नारनौल में स्थित हैं। उपरोक्त

60 गांवों का कुल क्षेत्रफल 25415 हैक्टेयर है तथा 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 129019 है। प्रस्तावित उप मण्डल की जिला मुख्यालय से दूरी 17 किलोमीटर है। प्रस्तावित उप मण्डल में एक अटेली व एक पंचायत खण्ड अटेली है। इस प्रकार हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित उप मण्डल बनने के सभी मापदण्ड पूरे होते हैं। अतः तहसील अटेली को उन्नत करके उप मण्डल बनाया जाना उचित होगा। ऐसी रिपोर्ट माननीय उपायुक्त महोदय नारनौल द्वारा सरकार को भेजी गई है जिसे लगभग 6 साल हो गए। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वे अटेली को उप मण्डल घोषित करने का मुझे आश्वासन दें।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि मैंने खुद माना है कि रिपोर्ट आयी हुई है। मगर जैसे माननीय सदस्य ने बताया कि इतने सब डिविजन से इतने गांव निकाले जाए तो क्या आने वाले समय में उन सब डिविजन के अन्दर जो पॉपुलेशन क्राइटेरिया और विलेज के नम्बर्स का क्राइटेरिया फुलफिल हो पाएगा। इसके ऊपर हम जल्द ही एक कमेटी एफ.सी.आर. की अध्यक्षता में बनाएंगे जो इस पूरे सिलैक्शन मैथड को रिव्यू करके सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी उसके बाद ही सरकार द्वारा कोई निर्णय लिया जाएगा।

लघु सचिवालय का निर्माण करना

***32. श्री संजय सिंह :** क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे किः-

(क) सोहना लघु सचिवालय तथा तावडू लघु सचिवालय के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है; तथा

(ख) उक्त सचिवालयों का निर्माण कार्य कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala) :

(a) The architectural drawings have been issued by Department of Architecture forconstruction of Mini Secretariats at Sohna and Tauru. The estimates are being prepared for seeking administrative approval for the works.

(b) Since the administrative approval is yet to be sought, therefore, no timeline can be given at this stage.

श्री संजय सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हमारी सोहना विधान सभा के अन्दर तावडू और सोहना दो सब डिविजन लगते हैं लेकिन इन दोनों सब डिविजन में से किसी में भी लघु सचिवालय नहीं हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कि यह स्टार्टिंग की घोषणा है। इस संबंध में मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इसका काम कितनी जल्दी स्टार्ट कर दिया जाएगा ?

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि दिनांक 26.12.2022 को रेवेन्यू डिपार्टमैंट से हमारे पास पत्र आया था कि लैण्ड अवेलिबिलिटी हो चुकी है। आर्किटैक्चर विभाग को नक्शे बनाने के लिए फाइल भेज दी गई है। जैसे ही अनुमान आ जाएगा कि लागत कितनी होगी उसका टैंडर करके उसका काम शुरू करेंगे क्योंकि सरकार की भी प्रायरिटी है कि जहां पर ऑफिसर्स डिप्लॉय हो चुके हैं वहां पर जल्द से जल्द इंफ्रास्ट्रक्चर देकर आम जनता को भी उसका लाभ दिया जाए।

....

तालाबों का गन्दा पानी निकालना

***33. श्री बिशन लाल सैनीः** क्या विकास एवं पंचायत मंत्री कृपया बताएंगे किः—

(क) तालाबों की कुल संख्या कितनी है जिनमें पौंड अथॉरिटी, हरियाणा द्वारा अब तक कार्य निष्पादित किए गए हैं; तथा

(ख) यदि नहीं, तो क्या रादौर विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र के गांवों के तालाबों के गंदे पानी को निकालने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा उसका ब्यौरा क्या है?

***विकास एवं पंचायत मंत्री (श्री देवेंद्र सिंह बबली) :** श्रीमान जी,

(क) 223 तालाबों (ग्रामीणः 204, प्रति अनुलग्नक F/A व शहरीः 19, प्रति अनुलग्नक F/B) का जीर्णोद्धार पूरा हो गया है एवं 494 तालाबों (ग्रामीणः 489, प्रति अनुलग्नक F/C व शहरीः 05, प्रति अनुलग्नक F/D) तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य विभिन्न चरणों में प्रगति पर है।

(ख) रादौर विधानसभा क्षेत्र के 37 तालाबों (प्रति अनुलग्नक F/E) के जीर्णोद्धार का कार्य अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत शुरू किया गया था जिनमें से 3 तालाबों का कार्य पूरा हो चुका है, 23 तालाबों का काम प्रगति पर है एवं बाकी 11 तालाबों का काम टैंडर स्टेज पर है।

***कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) द्वारा उपरोक्त प्रश्न का उत्तर दिया गया**

ANNEXURE-F/A

Amrit Sarovar Ponds List (Rural Ponds) - Completed						
Sr No	**District Name**	**Block Name**	**Village**	**Pond Name**	**UID**	**Department**
1	AMBALA	SAHA	TEPLA(133)	Near Mandir	01HRAMBSHA0133TEPL001	PR-PW
2	AMBALA	AMBALA-I	KALERAN(307)	Near Govt School	01HRAMBAM10307KALE001	PR-PW
3	AMBALA	AMBALA-I	MOHRI(253)	Near BPL Plot	01HRAMBAM10253MOHR001	PR-PW
4	AMBALA	AMBALA-I	DORANA(271)	Near Govt. School	01HRAMBAM10271DURA001	PR-PW
5	AMBALA	AMBALA-II	PANJOKHARA(29)	NAhan singhwala pond	01HRAMBAM20029PANJ003	PR-PW
6	AMBALA	BARARA	SUBHRI(232)	Near Shiv Mandir	01HRAMBBRR0232SUBH001	PR-PW
7	AMBALA	NARAINGARH	DERA(190)	Village Pond 1	01HRAMBNRG0190DERA001	PR-PW
8	AMBALA	SAHA	GHASEETPUR(195)	Near house of Sarpanch Surinder Kumar	01HRAMBSHA0195GHIS001	PR-PW
9	AMBALA	NARAINGARH	MAWAKHERI(113)	Village Pond	01HRAMBNRG0113MAWA001	PR-PW
10	AMBALA	NARAINGARH	OKHAL(295)	Village Pond	01HRAMBNRG0295OKHA001	PR-PW
11	AMBALA	NARAINGARH	BAKARPUR(297)	Village Pond	01HRAMBNRG0297BAKA001	PR-PW
12	AMBALA	AMBALA-I	DHANORI(186)	Near pwd Road	01HRAMBAM10186DHAN001	PR-PW
13	AMBALA	AMBALA-I	MARDON(252)	Near Gugamadi	01HRAMBAM10252MARD001	PR-PW
14	AMBALA	AMBALA-II	PANJOKHARA(29)	telijohar	01HRAMBAM20029PANJ002	PR-PW
15	AMBALA	BARARA	ZAFARPUR(8)	IN FRONT # OF TONI BLOCK SAMITI MAMBER	01HRAMBBRR0008ZAFF001	PR-PW
16	AMBALA	AMBALA-I	KONKPUR(273)	Near peer baba as jansui road	01HRAMBAM10273KONK001	PR-PW
17	AMBALA	AMBALA-II	BARNALA(PART)(48)	Langar hall pond	01HRAMBAM20048BARN001	PR-PW
18	AMBALA	AMBALA-I	BEGOMAJRA(181)	Near Shamshan ghat	01HRAMBAM10181BEGO001	PR-PW
19	AMBALA	BARARA	MILAKSHEKHAN(205)	Near Baba Khera	01HRAMBBRR0205MILK001	PR-PW
20	AMBALA	BARARA	ABDULGARH(247)	near peer baba	01HRAMBBRR0247ABDU003	PR-PW
21	AMBALA	SAHA	UPLANA(14)	near khera	01HRAMBSHA0014UPLA002	PR-PW
22	AMBALA	BARARA	ABDULGARH(247)	near road	01HRAMBBRR0247ABDU001	PR-PW
23	AMBALA	NARAINGARH	BARSUMAJRA(300)	Village Pond	01HRAMBNRG0097BARS002	PR-PW
24	AMBALA	SHAHZADPUR	BURJSHAHID(63)	Outside Firni	01HRAMBSZP0063BURJ001	PR-PW
25	AMBALA	SHAHZADPUR	BURJSHAHID(63)	Near Abadi	01HRAMBSZP0063BURJ002	PR-PW
26	AMBALA	SAHA	HAMIDPUR(137)	Nearest Panch Rakesh Kumar	01HRAMBSHA0137HAMI001	PR-PW
27	AMBALA	NARAINGARH	LAUTAN(91)	Pond Near Samshan ghat	01HRAMBNRG0LAUT085	PR-PW

28	AMBALA	AMBALA-II	RAWLAN(65)	Village Pond	01HRAMBAM20145ROLL001	PR-PW
29	BHIWANI	BAWANIKHERA	BALIYALI(44)	Kamana Pond	01HRBHWBWK0044BALI002	PR-PW
30	BHIWANI	BHIWANI	BAMLA(15)	BAGICHI POND	01HRBHWBHW0186BAML005	PR-PW
31	BHIWANI	BEHAL	BEHAL(106)	CATTLE POND	01HRBHWBHL0015BEHA002	PR-PW
32	BHIWANI	BHIWANI	DINOD(26)	Mandir wala pond	01HRBHWBHW0120DINO002	PR-PW
33	BHIWANI	BAWANIKHERA	BARSI(133)	KANDU WALA POND	01HRBHWBWK0133BARS005	PR-PW
34	BHIWANI	BEHAL	SURPURAKALAN(105)	Jhogi Wala	01HRBHWBHL0105SURP001	PR-PW
35	BHIWANI	BEHAL	BEHAL(106)	Khadi Wali Johri	01HRBHWBHL0015BEHA001	PR-PW
36	BHIWANI	KAIRU	JITWANABAS(61)	Gande Pani Wala Johad	01HRBHWKRU0087JEET001	PR-PW
37	BHIWANI	BEHAL	CHEHARKALAN(13)	Ranisar Wala Pond	01HRBHWSWI0013CHAH003	PR-PW
38	BHIWANI	BAWANIKHERA	BALIYALI(44)	Bukrana Pond	01HRBHWBWK0044BALI003	PR-PW
39	BHIWANI	BHIWANI	DEVSAR(25)	Pahadi Wala	01HRBHWBHW0025DEVS007	PR-PW
40	BHIWANI	TOSHAM	TOSHAM(RURAL)(33)	annewala	01HRBHWTSM0033TOSH001	PR-PW
41	CHARKHIDADRI	BOND	RANILA(130)	Kamwlaa johad	01HRCHDDDR0130RANI006	PR-PW
42	CHARKHIDADRI	DADRI	BHAGVI(163)	pipalwala pond	01HRCHDDDR0001BHAG270	PR-PW
43	CHARKHIDADRI	BADHRA	JEWALI(37)	Sameachat wala Johar	01HRCHDBDR0037JEWA001	PR-PW
44	CHARKHIDADRI	BADHRA	DOHKAHARYA(7)	Dohka hariya Pond	01HRCHDBDR0007DOHK002	PR-PW
45	FARIDABAD	BALLABGARH	GARKHERA(67)	shamshan ghaat wali	01HRFRDBLG0123GARK089	PR-PW
46	FARIDABAD	BALLABGARH	MOHLA(46)	Govt School Ke Pass Johad	01HRFRDFRD0123MAHL032	PR-PW
47	FARIDABAD	BALLABGARH	ATALI(89)	GAON WALI	01HRFRDBLG0123ATAL030	PR-PW
48	FATEHABAD	NAGPUR	HIZRAWANKHURD(40)	NEAR BUS STAND POND	01HRFTBNGP0040HIZR001	PR-PW
49	FATEHABAD	TOHANA	SAMAIN(80)	Krishana Pond	01HRFTBTHN0080SAMA001	PR-PW
50	FATEHABAD	FATEHABAD	BIGHAR(44)	BIGHAR MODEL POND Near Shamshan Ghat	01HRFTBFTB0044BIGH002	PR-PW
51	FATEHABAD	FATEHABAD	BHIRDANA(139)	GAU SALA ROAD MODEL POND	01HRFTBFTB0139BIRD009	PR-PW
52	FATEHABAD	FATEHABAD	HIZRAWANKALAN(41)	HIZRAWAN KALAN MODEL POND	01HRFTBFTB0041HIZR003	PR-PW
53	FATEHABAD	BHATTUKALAN	BHATTUKALAN(16)	HANUMAN MANDIR MODEL POND	01HRFTBBTK0016BHAT002	PR-PW
54	FATEHABAD	BHUNA	BHUNDRA(79)	Harijan Basti pond	01HRFTBTHN0137BHUN001	PR-PW
55	GURUGRAM	SOHNA	GARHIBAZIDPUR(175)	pond 1	01HRGGMSHN0175GARH002	PR-PW
56	GURUGRAM	FARRUKHNAGAR	BUDHERA(43)	Badli Road	01HRGGMFRN0130BUDH001	PR-PW
57	GURUGRAM	PATAUDI	BOHARAKALAN(134)	BAGICHI POND	01HRGGMGGM0134BHOR001	PR-PW
58	GURUGRAM	SOHNA	HARIAHERA(183)	pond 1	01HRGGMSHN0183HARI001	PR-PW
59	GURUGRAM	FARRUKHNAGAR	KHETAWAS(118)	Phirni	01HRGGMFRN0118KHAI001	PR-PW

60	GURUGRA M	PATAUDI	PRASAULI(138)	NEAR BPL COLONY	01HRGGMGGM01 38PLAS001	PR-PW
61	GURUGRA M	FARRUKHNAG AR	TAJNAGAR(30)	MGGBY COLONY	01HRGGMFRN003 00TAJ002	PR-PW
62	GURUGRA M	PATAUDI	CHANDLADUNGE RWAS(148)	POND	01HRGGMPTD014 8CHAN002	PR-PW
63	GURUGRA M	PATAUDI	MAUJABAD(21)	Mozamabad	01HRGGMPTD002 1MAUJ364	PR-PW
64	GURUGRA M	GURUGRAM	DAULTABAD(53)O G	waste water pond	01HRGGMGGM00 53DAUL408	PR-PW
65	GURUGRA M	SOHNA	DAULA(197)	pond 1	01HRGGMSHN01 97DAUL001	PR-PW
66	GURUGRA M	SOHNA	HARCHANDPUR(1 99)	baba somnath pond	01HRGGMSHN01 99HARC002	PR-PW
67	GURUGRA M	FARRUKHNAG AR	IQBALPUR(40)	Rain Water POND	01HRGGMFRN004 0IQBA363	PR-PW
68	GURUGRA M	PATAUDI	BILASPUR(146)	POND	01HRGGMPTD014 6BILA003	PR-PW
69	HISAR	NARNAUND	RAKHIKHAS(76)	AAZISHAR II	01HRHSRNRD007 6RAKH005	PR-PW
70	HISAR	ADAMPUR	SADELPUR(20)	Aathuna bass ka johad	01HRHSRADM002 0SADA001	PR-PW
71	HISAR	ADAMPUR	ADAMPUR(CT)	gandapani	01HRHSRADM003 4ADAM001	PR-PW
72	HISAR	ADAMPUR	SISWAL(174)	sahid mandir johad	01HRHSRADM017 4DHAN003	PR-PW
73	HISAR	HISAR-I	GANGWA(166)(CT)	Gindhiya pond	01HRHSRHR1016 6GANG005	PR-PW
74	HISAR	NARNAUND	PETWAR(92)	DIGGI WALA	01HRHSRNRD009 2PETW007	PR-PW
75	HISAR	UKLANA	PABRA(65)	dahb wala johad	01HRHSRUKL0065 PABR009	PR-PW
76	HISAR	HISAR-I	MANGALIAKALAN (161)	Brahama wala Johad	01HRHSRHR1016 6MANG001	PR-PW
77	HISAR	HISAR-I	MANGALIJHARA(1 60)	Piruwali johar	01HRHSRHR1016 0MANG001	PR-PW
78	HISAR	NARNAUND	MAJRA(104)	MAKNA WALA	01HRHSRNRD010 4MAJR002	PR-PW
79	HISAR	HISAR-I	BADONRANGRAN (7)	desewala johar	01HRHSRHR1000 7BADY003	PR-PW
80	HISAR	AGROHA	NANGTHALA(138)	Brahmano Wala	01HRHSRAGR013 8NANG001	PR-PW
81	HISAR	NARNAUND	MAJRA(104)	GLLI JOHD	01HRHSRNRD010 4MAJR003	PR-PW
82	HISAR	HISAR-II	BALSMAND(22)	Kumhar Khanda Johar	01HRHSRHR2002 2BALS002	PR-PW
83	JHAJJAR	BAHADURGAR H	JAKHAUDA(41)	Sawari	01HRJJRBDG0041 JAKH002	PR-PW
84	JHAJJAR	BADLI	BAHAMNOLA(270)	Rambha Vala Jhod	01HRJJRDDL0270 BAMN003	PR-PW
85	JIND	UJHANA	DHANAURI(6)	Tirth	01HRJNDNRW000 6DHAN004	PR-PW
86	JIND	ALEWA	NAGURAN(81)	TEERTH	01HRJNDALW008 1NAGU006	PR-PW
87	JIND	UJHANA	BELARKHA(39)	Tirth Wala Pond	01HRJNDNRW003 9BELA001	PR-PW
88	JIND	JIND	AHIRKA(83)	Mandirwala	01HRJNDJND0081 AHIR002	PR-PW
89	JIND	JIND	AHIRKA(83)	schoolwala	01HRJNDJND0081 AHIR001	PR-PW
90	JIND	JULANA	GATAULI(49)	sabuwala	01HRJNDJLN0049 GATO006	PR-PW
91	JIND	NARWANA	KAHNAKHERA(69)	BHUTWALI	01HRJNDNRW006 9KANH001	PR-PW
92	JIND	NARWANA	GURTHALI(37)	Kalra Wala Pond	01HRJNDNRW003 7GURT001	PR-PW
93	JIND	NARWANA	GURTHALI(37)	PIRWALA POND	01HRJNDNRW003 7GURT002	PR-PW

94	JIND	NARWANA	JULEHRA(62)	KUNDIWALA	01HRJNDNRW0062JULE001	PR-PW
95	JIND	NARWANA	GORUSAR(42)	Mandirwala pond	01HRJNDNRW0042GURU001	PR-PW
96	JIND	UCHANA	DAROLIKHERA(97)	Daka wali	01HRJNDUCN0097DARO001	PR-PW
97	JIND	UCHANA	BADANPUR(93)	baghwala	01HRJNDUCN0093BADA002	PR-PW
98	JIND	UCHANA	DURJANPUR(101)	ragdiwala	01HRJNDUCN0101DURJ005	PR-PW
99	JIND	UCHANA	DHANKHARI(133)	daru wali	01HRJNDUCN0133DHAN004	PR-PW
100	JIND	UCHANA	SURBRAH(99)	ghosaniya wala	01HRJNDUCN0099SURB002	PR-PW
101	JIND	SAFIDON	BAGRUKALAN(31)	Bagru Kalan Johad-4	01HRJNDSFD0031BAGR004	PR-PW
102	KAITHAL	KALAYAT	BATTA(15)	UTTMAN (Model Pond)	01HRKTLKLT0015BATT004	PR-PW
103	KAITHAL	PUNDRI	KARORA(46)	Satiwala (Model Pond)	01HRKTLPNR0046KARO002	PR-PW
104	KAITHAL	KAITHAL	SAJOOMA(14)	Tirth (Religious/Historical)	01HRKTLKLT0014SAJU005	PR-PW
105	KAITHAL	KAITHAL	KEORAK(33)	Koti Kuteshwer Tirth	01HRKTLKTL0033KEOR003	PR-PW
106	KAITHAL	DHAND	DHAND(9)	behind police station (Model Pond)	01HRKTLDND0009DHAN002	PR-PW
107	KAITHAL	DHAND	PABNAWA(20)	Daaber wala (Model Pond)	01HRKTLDND0011PABN008	PR-PW
108	KAITHAL	GUHLA	BHAGAL(1)	farmana bhagal(Model Pond)	01HRKTLGHL0001BHAG027	PR-PW
109	KAITHAL	KALAYAT	MATOR(26)	Markandeswhwar Tirth (Model Pond)	01HRKTLKLT0026MATO005	PR-PW
110	KAITHAL	PUNDRI	HABRI(31)_	Church Wala (Model Pond)	01HRKTLPNR0031HABR001	PR-PW
111	KAITHAL	DHAND	PHARAL(12)	Chappar Pond	01HRKTLDND0012PHAR002	PR-PW
112	KAITHAL	KAITHAL	SAJOOMA(14)	GHARAOWA	01HRKTLKLT0014SAJU001	PR-PW
113	KAITHAL	GUHLA	BHAGAL(1)	basanti mata ala(bhagal)	01HRKTLGHL0001BHAG031	PR-PW
114	KAITHAL	GUHLA	BHAGAL(1)	kund(guga mari vala)	01HRKTLGHL0001BHAG028	PR-PW
115	KAITHAL	KALAYAT	CHUSALA(28)	Dhobi Tirth	01HRKTLKLT0028CHOU004	PR-PW
116	KAITHAL	KALAYAT	CHUSALA(28)	kanthari	01HRKTLKLT0028CHOU001	PR-PW
117	KAITHAL	GUHLA	ARNOLI(32)	arnoli(unknown)	01HRKTLGHL0032ARNO001	PR-PW
118	KAITHAL	GUHLA	BHUNSLAN(134)	near tample(bhusla)	01HRKTLGHL0001BHUN023	PR-PW
119	KAITHAL	KAITHAL	BUDHAKHERA(87)	GALYA WALA	01HRKTLKTL0087BUDH001	PR-PW
120	KAITHAL	KAITHAL	BHANPURA(14)	Bhanpura Johar 1	01HRKTLKTL0014BHAN001	PR-PW
121	KAITHAL	KAITHAL	BUDHAKHERA(87)	SULTAN wala pond	01HRKTLKTL0087BUDH002	PR-PW
122	KAITHAL	DHAND	BEGPUR(1)	on Pobala road	01HRKTLDND0002BEGP004	PR-PW
123	KAITHAL	DHAND	BEGPUR(1)	On rasulpur road	01HRKTLDND0002BEGP005	PR-PW
124	KAITHAL	GUHLA	BUDHANPURGUJRAN(137)	unknown(budanpur)	01HRKTLGHL0137BUDA001	PR-PW

125	KAITHAL	KAITHAL	PADLA(9)	JOHAR (Mandir wala)	01HRKTLKTL0009 PADL002	PR-PW
126	KAITHAL	PUNDRI	BAKAL(74)	Near School	01HRKTLPNR0074 BAKA001	PR-PW
127	KAITHAL	KAITHAL	BHENIMAJRA(36)	Johar 40	01HRKTLKTL0036 BHAI001	PR-PW
128	KARNAL	KARNAL	KACHHWA(11)	Gurudwara wala pond	01HRKNLKNL0011 KACH002	PR-PW
129	KARNAL	NILOKHERI	SAGA(58)	vishnu path tirth pond	01HRKNLNLK0058 SAGG004	PR-PW
130	KARNAL	MUNAK	PADHA(68)	Panchdev Trith (Main Pond -A)	01HRKNLMNK006 8PADH004	PR-PW
131	KARNAL	NISSING	GONDAR(35)	Gautam Rishi Pond	01HRKNLNSR0035 GOND002	PR-PW
132	KARNAL	MUNAK	PADHA(68)	dandu wala -B	01HRKNLMNK006 8PADH003	PR-PW
133	KARNAL	NILOKHERI	BUTANA(PART)(34)	Jile singh wala pond	01HRKNLNLK0034 BUTA004	PR-PW
134	KARNAL	ASSANDH	SALWAN(95)	nova pond	01HRKNLASD0095 SALW003	PR-PW
135	KARNAL	MUNAK	BALLA(30)	Assandh road	01HRKNLMNK003 0BALL002	PR-PW
136	KURUKSHETRA	THANESAR	DAYALPUR(PART)(383)	Bhishma Kund	01HRKKRTNS0383 DIYA001	PR-PW
137	KURUKSHETRA	PIPLI	JIRBARI(371)	on NH44	01HRKKRPPL0371 JIRB001	PR-PW
138	KURUKSHETRA	PEHOWA	ARNAICHA	Renuka Dham	01HRKKRPHW001 4ARNE001	PR-PW
139	KURUKSHETRA	THANESAR	KIRMACH(6)	Near SYL	01HRKKRTNS0006 KIRM002	PR-PW
140	KURUKSHETRA	PEHOWA	BIBIPURKALAN(50)	W.W.P	01HRKKRPHW005 0BIBI001	PR-PW
141	KURUKSHETRA	THANESAR	KHIZARPURA(28)	Khijarpur 1	01HRKKRTNS0028 KHIJ002	PR-PW
142	KURUKSHETRA	ISMAILABAD	NAISI(323)	Pond 1	01HRKKRIML0323 NAIS001	PR-PW
143	KURUKSHETRA	BABAIN	NAKHROJPUR(164)	In village pond	01HRKKRBBN016 4NAKH001	PR-PW
144	KURUKSHETRA	PEHOWA	RATTANGARHKAKRALI(8)	village pond	01HRKKRPHW000 8RATT001	PR-PW
145	KURUKSHETRA	ISMAILABAD	SALPANIKALAN(300)	Salpani kalan big pond	01HRKKRIML0300 SALP001	PR-PW
146	MAHENDERGARH	SATNALI	SATNALI(7)	sherawali	01HRNRLSTN0007 SATN002	PR-PW
147	NUH	FEROZEPURJHIRKA	BIWAN(148)	Rajabal Kua Wala	01HRNUHFZJ0148 BIWA003	PR-PW
148	NUH	NUH	MALAB(122)	Baa Johad	01HRNUHNUH01 22MALA001	PR-PW
149	NUH	PUNAHANA	BICHHOR(243)	Khuta	01HRNUHPNH024 3BICC002	PR-PW
150	NUH	PINGWAN	MAMLIKA(130)	badi johad	01HRNUHPNH012 3MAML043	PR-PW
151	PALWAL	HODAL	AURANGABAD(83)	Bada talab	01HRPWLHDL002 1AURA001	PR-PW
152	PALWAL	BADOLI	KUSHAK(111)	primary school Johad	01HRPWLBDL011 1KUSH001	PR-PW
153	PALWAL	HODAL	SUNDHAD(89)	Laldas jhodar	01HRPWLHDL008 9SUND092	PR-PW
154	PALWAL	HODAL	BHIDUKI(99)	Bayi wali Pond	01HRPWLHDL009 9BHID048	PR-PW
155	PALWAL	HATHIN	CHHAINSA(211)	Chanisa	01HRPWLHTN021 1CHAN004	PR-PW
156	PALWAL	HATHIN	RUPRAKA(246)	Roopraka 4	01HRPWLHTN024 6ROOP004	PR-PW
157	PALWAL	HATHIN	UTAWAR(278)	Uttawar 1	01HRPWLHTN027 8UTTA001	PR-PW

158	PALWAL	HATHIN	KOT(280)	Kot 3	01HRPWLHTN028 00KOT003	PR-PW
159	PALWAL	HATHIN	ALIMEO(284)	Alimeo 1	01HRPWLHTN028 4ALIM001	PR-PW
160	PALWAL	BADOLI	CHANDHAT(172)	Kirpa wali Pond	01HRPWLBDL017 2CHAN001	PR-PW
161	PALWAL	HODAL	BANCHARI(124)	Mahadev Mandir	01HRPWLHDL012 8BANC089	PR-PW
162	PANCHKUL A	PINJORE	NANAKPUR(91)	Sotwala Pond2	01HRPKLPJR0000 NANA380	PR-PW
163	PANCHKUL A	BARWALA	BARWALA(246)	NEAR PAKKA TALAB	01HRPKLBRL0246 BARW001	PR-PW
164	PANCHKUL A	BARWALA	NAWAGAONURFK HADER(24)	Basanti Mala Johad near Goga Madi	01HRPKLBRL0020 NAYA268	PR-PW
165	PANCHKUL A	BARWALA	BHARELI(249)	Sardar wala johad	01HRPKLBRL0249 BHAR005	PR-PW
166	PANCHKUL A	PINJORE	NANAKPUR(91)	Johad	01HRPKLPJR0091 NANA003	PR-PW
167	PANCHKUL A	BARWALA	BHARELI(249)	Saini wala johad near Jaat Dharamshala	01HRPKLBRL0249 BHAR006	PR-PW
168	PANCHKUL A	MORNI	BHOJJABYAL(324)	Sherla	01HRPKLMRN0BH OJ006	PR-PW
169	PANIPAT	PANIPAT	SEWAH(32)	Bilphala Talab	01HRPPTPPT0032 SIWA002	PR-PW
170	PANIPAT	SAMALKHA	CHULKANA(118)	Dhokhar Wala	01HRPPTSML0118 CHUL001	PR-PW
171	PANIPAT	BAPOLI	DHADOLA(46)	Shimla Gujran wala pond	01HRPPTBPL0046 DADO001	PR-PW
172	PANIPAT	PANIPAT	SEWAH(32)	Pandit Wala Talab	01HRPPTPPT0032 SIWA001	PR-PW
173	REWARI	DHARUHERA	BALIARKHURD(20 0)	Shamshan Ghat wala Pond	01HRRWRRWR02 00BALI001	PR-PW
174	ROHTAK	KALANAUR	BANIYANI(123)	Dudhiya Aala / Thakur wala	01HRRTKKLN0123 BANY001	PR-PW
175	ROHTAK	KALANAUR	BHALIANANDPUR (98)	BARA TALAB	01HRRTKKLN0098 BHAL002	PR-PW
176	ROHTAK	KALANAUR	BHALIANANDPUR (98)	GUHI POND	01HRRTKKLN0098 BHAL001	PR-PW
177	ROHTAK	MEHAM	NINDANAKHAS	Kalser Pond(Nindana Khas)	01HRRTKMHM01 07NIND002	PR-PW
178	ROHTAK	ROHTAK	BAHUAKBERPUR(94)	BORAS	01HRRTKRTK0094 BAHU001	PR-PW
179	ROHTAK	MEHAM	BEHRANSEKHPUR TITRI	baniya wala	01HRRTKMHM01 06BHAR002	PR-PW
180	ROHTAK	KALANAUR	BANIYANI(123)	Buddha	01HRRTKKLN0123 BANY002	PR-PW
181	ROHTAK	ROHTAK	LADHOT(65)	SUNEHARA POND	01HRRTKRTK0065 LADH002	PR-PW
182	ROHTAK	MEHAM	FARMANAKHAS(1 13)	Jitodi	01HRRTKMHM0F ARM059	PR-PW
183	SIRSA	SIRSA	HANDIKHERA(75)	Handi khera-1	01HRSRSSRS0075 HAND001	PR-PW
184	SIRSA	SIRSA	KUSUMBI(50)	Near School	01HRSRSSRS0KUS U061	PR-PW
185	SIRSA	SIRSA	KUSUMBI(50)	Main Jorh	01HRSRSSRS0063 KUSU083	PR-PW
186	SIRSA	NATHUSARICH OPTA	RUPAWAS(26)	Near Goga Medi	01HRSRSNTS0026 RUPA004	PR-PW
187	SONIPAT	GOHANA	KASANDI(59)	Mata Wala	01HRSPTGHN005 9KASA003	PR-PW
188	SONIPAT	GOHANA	KASANDA(58)	Near Gaushala	01HRSPTGHN005 8KASA003	PR-PW
189	SONIPAT	RAI	NAHRA(227)	GANGESHAR	01HRSPTRAI0227 NAHR004	PR-PW

190	SONIPAT	GOHANA	KASANDI(59)	Tributary Drain No 4	01HRSPTGHN0059KASA090	PR-PW
191	SONIPAT	MUNDLANA	MUNDLANA(45)	Naya Pond	01HRSPTMDN0045MUND004	PR-PW
192	SONIPAT	MUNDLANA	SIWANKA(26)	Hanoi wala pond	01HRSPTMDN0026SIWA003	PR-PW
193	SONIPAT	MUNDLANA	SIWANKA(26)	bojhariwali Johri Pond -1 sawanka	01HRSPTMDN0026SIWA004	PR-PW
194	SONIPAT	MUNDLANA	HASSANGARH(30)	Talab	01HRSPTMDN0030HASA001	PR-PW
195	YAMUNANAGAR	SADAURA	NAUSHAHRA(162)	naushera	01HRYNRSDR0162NAUS001	PR-PW
196	YAMUNANAGAR	BILASPUR	MILKARA(258)	Milkara	01HRYNRBLP0MILK019	PR-PW
197	YAMUNANAGAR	RADAUR	BAKANA(40)	SC pond	01HRYNRRDR0040BAKA002	PR-PW
198	YAMUNANAGAR	SARASWATINAGAR	BALCHHAPAR(365)	Bal Chhapper	01HRYNRSWN03650BAL001	PR-PW
199	YAMUNANAGAR	PARTAPNAGAR	BAKKARWALA(177)	bakkarwala	01HRYNRKJB0177BAKK001	PR-PW
200	YAMUNANAGAR	JAGADHRI	SUDHAIL(425)	shamshan ghat pond	01HRYNRJGD0425SUDH001	PR-PW
201	YAMUNANAGAR	RADAUR	JHINWARHERI(172)	NEAR SHAMSHAN GHAT	01HRYNRRDR0JHIN051	PR-PW
202	YAMUNANAGAR	CHHACHHRAULI	BALACHAUR(312)	gadiriyo wala pond	01HRYNRCCR0BALA011	PR-PW
203	YAMUNANAGAR	JAGADHRI	KAIL(378)	kail pond	01HRYNRJGD0378KAIL001	PR-PW
204	YAMUNANAGAR	JAGADHRI	NAIGAWAN(122)	Near Govt. school pond	01HRYNRJGD0NAI066	PR-PW

ANNEXURE-F/B

Amrit Sarovar Ponds List - Completed (Urban)

Sr No	District Name	Block Name	Village	Pond Name	UID	Department
1	GURUGRAM	GURUGRAM (CORPORATION)	SAMASPUR(91)	SAMASPUR POND	02HRGGMGUR0029SAMA001	ULBD
2	GURUGRAM	GURUGRAM (CORPORATION)	BADSHAHPUR (87)	BADSHAHPUR POND	02HRGGMGUR0025BDHA001	ULBD
3	GURUGRAM	GURUGRAM (CORPORATION)	BASAI(50)	BASAI POND	02HRGGMGUR0012BRSI001	ULBD
4	GURUGRAM	GURUGRAM (CORPORATION)	BEGUMPURKHATOLA(101)	BEGUMPUR KHATOLA POND	02HRGGMGUR0026BKTL001	ULBD
5	GURUGRAM	GURUGRAM (CORPORATION)	BEHRAMPUR(100)	Pond	02HRGGMGUR0025BEHR001	ULBD
6	GURUGRAM	GURUGRAM (CORPORATION)	DAULTABAD(28)	NEAR GPS	01HRGGMPTD0028DAUL002	ULBD
7	GURUGRAM	GURUGRAM (CORPORATION)	DHANWAPUR(51)	Dhanwapur	02HRGGMGUR0012DPUR001	ULBD

8	GURUGRAM	GURUGRAM (CORPORATION)	DHANWAPUR(51)	DHANWAPUR	02HRGGMGUR0012DPUR002	ULBD
9	GURUGRAM	GURUGRAM (CORPORATION)	TIGRA(91)	TIGRA POND	02HRGGMGUR0026TGRA001	ULBD
10	GURUGRAM	GURUGRAM (CORPORATION)	SUKHRALI(71)	SUKHRALI POND	02HRGGMGUR0006SHRI001	ULBD
11	GURUGRAM	GURUGRAM (CORPORATION)	KASAN(129)	MACHI WALA	01HRGGMGGM0129KASA002	ULBD
12	GURUGRAM	GURUGRAM (CORPORATION)	BASAI(50)	DADA BHAIYA MANDIR	02HRGGMGUR0012BRSI002	ULBD
13	GURUGRAM	GURUGRAM (CORPORATION)	KADIPUR(105)	KADIPUR POND	02HRGGMGUR0013KPUR001	ULBD
14	GURUGRAM	GURUGRAM (CORPORATION)	PANWALAKHUSROPUR	khatu shyam mandir	02HRGGMGUR0001PWLA001	ULBD
15	GURUGRAM	GURUGRAM (CORPORATION)	SARHAUL(70)	SARHAUL POND	02HRGGMGUR0005SHUL001	ULBD
16	GURUGRAM	GURUGRAM (CORPORATION)	BANDHWARI(79)	badhi chopal jhor	02HRGGMWAZ0000BAND002	ULBD
17	GURUGRAM	GURUGRAM (CORPORATION)	NURPURJHARSA(165)	radha krishan	02HRGGMGUR0000NURP001	ULBD
18	GURUGRAM	GURUGRAM (CORPORATION)	DARBARIPUR(162)	Baba harbaksha mandir pond	02HRGGMGUR0025DARB002	ULBD
19	GURUGRAM	GURUGRAM (CORPORATION)	PALRA(164)	palra pond	01HRGGMSHN0164PALR379	ULBD

ANNEXURE-F/C

Amrit Sarovar Ponds List - In-Progress (Rural)

Sr No	District Name	Block Name	Village	Pond Name	UID	Department
1	AMBALA	AMBALA-I	MOHRI(253)	Near Govt.School	01HRAMBAM10253MOHR002	PR-PW
2	AMBALA	SAHA	GANGANHERI(12)	Mata wala Pond	01HRAMBSHA0012GAGN001	PR-PW
3	AMBALA	SAHA	GANGANHERI(12)	Near shiv Mandir	01HRAMBSHA0GANG138	PR-PW
4	AMBALA	SAHA	CHHANNI(192)	Near PH Tubewell	01HRAMBSHA0192CHHA001	PR-PW
5	AMBALA	BARARA	RAJAULI(200)	near gurudwara	01HRAMBBRR0200RAJO001	PR-PW
6	BHIWANI	BHIWANI	DINOD(26)	NEAR CHAUPAL	01HRBHWBHW0045DINO002	PR-PW
7	BHIWANI	BHIWANI	KELANGA(130)	Dhobhi	01HRBHWBHW0130KALI001	PR-PW
8	BHIWANI	BHIWANI	DEVSAR(25)	Mandir Wala Johad	01HRBHWBHW0025DEVS006	PR-PW

9	BHIWANI	BHIWANI	DHANANA(52)	Tirtha Pond	01HRBHWBHW 0203DHAN001	PR-PW
10	BHIWANI	BHIWANI	REWARIKHERA(4)	Feeru Wala Johad near Shiv Mandir	01HRBHWBHW 0004REWA001	PR-PW
11	BHIWANI	BHIWANI	BAMLA(15)	MANDIR WALA GORWA POND	01HRBHWBHW 0186BAML004	PR-PW
12	BHIWANI	BAWANIKHERA	BALIYALI(44)	Salam Kund	01HRBHWBWK0 044BALI001	PR-PW
13	BHIWANI	BHIWANI	CHANG(5)	Near ashram Model Pond	01HRBHWBHW 0114CHAN001	PR-PW
14	BHIWANI	BHIWANI	TIGRANA(10)	BIDSAR	01HRBHWBHW 0010TIGR001	PR-PW
15	BHIWANI	BHIWANI	KHARAKKALAN(131)	Baniya Wala Johd	01HRBHWBHW 0131KHAR005	PR-PW
16	BHIWANI	BEHAL	CHEHARKALAN(13)	BALWANA POND	01HRBHWSWI0 013CHAH001	PR-PW
17	BHIWANI	BEHAL	BEHAL(106)	waste water pond	01HRBHWBHL0 017BEHA003	PR-PW
18	BHIWANI	BAWANIKHERA	BHAINIJATTAN(131)	SATI WALA POND	01HRBHWBWK0 131BHAI007	PR-PW
19	BHIWANI	BAWANIKHERA	BHAINIJATTAN(131)	NANDA WALA POND	01HRBHWBWK0 131BHAI005	PR-PW
20	BHIWANI	TOSHAM	CHHAPARJOGIAN(85)	CHATRRI WALA POND	01HRBHWTSM0 125CHAP057	PR-PW
21	BHIWANI	SIWANI	DHANIDARIYAPUR	Khanda	01HRBHWTSM0 087DHAN006	PR-PW
22	BHIWANI	SIWANI	DHANIDARIYAPUR	NEAR SCHOOL	01HRBHWSWI0 163DHAN004	PR-PW
23	BHIWANI	TOSHAM	KHAWA(94)	Khadi Johar	01HRBHWTSM0 094KHAW006	PR-PW
24	BHIWANI	BAWANIKHERA	LOHARIJATU(47)	Tilsar Pond	01HRBHWBWK0 023JATT003	PR-PW
25	BHIWANI	BAWANIKHERA	LOHARIJATU(47)	Singhrana Pond	01HRBHWBWK0 065JATT001	PR-PW
26	BHIWANI	BHIWANI	PALUWAS(12)	Bukan Hjariwala johad	01HRBHWBHW 0012PALU005	PR-PW
27	BHIWANI	BHIWANI	PALUWAS(12)	Naya Jogiwala Johad	01HRBHWBHW 0012PALU007	PR-PW
28	CHARKHIDA DRI	BOND	BONDKALAN(127)	Kilsar	01HRCHDBND0 127BOND001	PR-PW
29	CHARKHIDA DRI	BADHRA	BADHRA(40)	Khadi Ganda Pani Johar	01HRCHDBDR00 40BADH001	PR-PW
30	CHARKHIDA DRI	DADRI	GHIKARA(141)	Mandir wala Pond	01HRCHDDDR01 86GHIK003	PR-PW
31	CHARKHIDA DRI	DADRI	MORWALA(157)	Baba Takadi Wala	01HRCHDDDR01 57MORW001	PR-PW
32	CHARKHIDA DRI	BOND	BASMUTSILRANILA(154)	Gaanv wala johad	01HRCHDDDR01 54BASS002	PR-PW
33	CHARKHIDA DRI	BOND	SANJHARWAS(131)	Brahaman wala johad	01HRCHDDDR01 31SANJ005	PR-PW
34	CHARKHIDA DRI	DADRI	CHARKHI(143)	Navva Pond Charkhi	01HRCHDDDR01 43CHAR002	PR-PW

35	CHARKHIDA DRI	DADRI	BIGOWA(155)	jal sisar	01HRCHDDDR0155BIGO002	PR-PW
36	CHARKHIDA DRI	BOND	RANILA(130)	Rajwala johad	01HRCHDDDR0130RANI004	PR-PW
37	FARIDABAD	BALLABGARH	CHHAINSA(202)	dhani wali pond	01HRFRDFRD0202CHHA001	PR-PW
38	FARIDABAD	BALLABGARH	SIKRI(48)	maswasi	01HRFRDFRD0123SIKR028	PR-PW
39	FARIDABAD	FARIDABAD	DHOUJ(17)	Goiyli Pond	01HRFRDFRD0879DHAU001	PR-PW
40	FARIDABAD	BALLABGARH	ATALI(89)	GULAR WALI	01HRFRDBLG0123ATAL039	PR-PW
41	FARIDABAD	BALLABGARH	BHANAKPUR(45)	sekhli pond	01HRFRDFRD0123BHAN055	PR-PW
42	FARIDABAD	BALLABGARH	FATEHPURBILOCH (58)	giliyawali	01HRFRDBLG0123FATE065	PR-PW
43	FARIDABAD	FARIDABAD	PALI(13)	pali pond 1	01HRFRDFRD0123PALI036	PR-PW
44	FARIDABAD	BALLABGARH	SIKRI(48)	badatalab	01HRFRDFRD0123SIKR030	PR-PW
45	FARIDABAD	BALLABGARH	LADOLI(70)	khaeesh wali johar	01HRFRDBLG0123LADH082	PR-PW
46	FARIDABAD	BALLABGARH	ATALI(89)	GUHILI	01HRFRDBLG0123ATAL038	PR-PW
47	FARIDABAD	BALLABGARH	ATALI(89)	KHANA WALI	01HRFRDBLG0123ATAL037	PR-PW
48	FARIDABAD	BALLABGARH	ATALI(89)	BAKORA	01HRFRDBLG0123ATAL031	PR-PW
49	FATEHABAD	FATEHABAD	BHIRDANA(139)	BHIRDANA WASTE POND-2	01HRFTBFTB0139BHIR010	PR-PW
50	FATEHABAD	FATEHABAD	BHIRDANA(139)	BHIRDANA CATTLE POND-2	01HRFTBFTB0139BHIR002	PR-PW
51	FATEHABAD	RATIA	BADALGARH(152)	balmiki basti pond	01HRFTBJKL0152BADA002	PR-PW
52	FATEHABAD	BHATTUKALAN	BANAWALI(27)	NEAR STADIUM	01HRFTBBTK0027BANA004	PR-PW
53	FATEHABAD	BHATTUKALAN	BANAWALI(27)	NEAR MANDIR	01HRFTBBTK0027BANA002	PR-PW
54	FATEHABAD	FATEHABAD	BIGHARII	BIGHAR-II	01HRFTBFTB0000BIGH336	PR-PW
55	FATEHABAD	BHATTUKALAN	DHABIKHURD(3)	DHABI KHURD POND-1	01HRFTBBTK0003DHAB087	PR-PW
56	FATEHABAD	BHATTUKALAN	DHABIKHURD(3)	DHABI KHURD POND-2	01HRFTBBTK0003DHAB088	PR-PW
57	FATEHABAD	BHATTUKALAN	DHABIKHURD(3)	panchayti land near by vkc back side near mggby	01HRFTBBTK0DHAB080	PR-PW
58	FATEHABAD	BHUNA	DHANIGOPAL	School wala pond	01HRFTBTHN0218DHAN002	PR-PW
59	FATEHABAD	BHUNA	DULT(76)	NEAR GOVT SCHOOL	01HRFTBBHN0076DULT003	PR-PW

60	FATEHABAD	RATIA	HASSINGA(83)	ON HASSANGA MP SOTTER ROAD	01HRFTBRTI0166HASS042	PR-PW
61	FATEHABAD	RATIA	HASSINGA(83)	NEAR PRIMARY SCHOOL	01HRFTBRTI0166HASS044	PR-PW
62	FATEHABAD	BHUNA	JANDLIKHURD(89)	bajewala pond	01HRFTBBHN0089JAND004	PR-PW
63	FATEHABAD	FATEHABAD	JHALANIA(49)	JHALANIA CATTLE POND	01HRFTBFTB0139JHAL006	PR-PW
64	FATEHABAD	FATEHABAD	JHALANIA(49)	JHALANIA WASTE POND	01HRFTBFTB0139JHAL007	PR-PW
65	FATEHABAD	BHUNA	KHASAPATHANA(64)	Khasa pathana to Dhani Gopal road	01HRFTBBHN0064KHAS310	PR-PW
66	FATEHABAD	RATIA	LAMBA(155)	Near gurudwara pond , SCHOOL DHANI	01HRFTBRTI0155LAMB325	PR-PW
67	FATEHABAD	NAGPUR	MADH(108)	MUDH WASTE WATER	01HRFTBNGP0108MUDH002	PR-PW
68	FATEHABAD	RATIA	RATTANGARH(163)	Piladakh near govt hospital	01HRFTBRTI0163RATT001	PR-PW
69	FATEHABAD	RATIA	RATTANGARH(163)	Near Gurughar	01HRFTBRTI0163RATT002	PR-PW
70	GURUGRAM	FARRUKHNAGAR	BASONDA(18)	Mandir waala	01HRGGMFRN0018BASO360	PR-PW
71	GURUGRAM	PATAUDI	BOHARAKALAN(134)	GARHI WALA POND	01HRGGMGGM0134BHOR002	PR-PW
72	GURUGRAM	FARRUKHNAGAR	BASONDA(18)	KHUDANA WALA	01HRGGMFRN0018BASU001	PR-PW
73	GURUGRAM	PATAUDI	BAPAS(266)	POND	01HRGGMPTD0266BAPA001	PR-PW
74	GURUGRAM	FARRUKHNAGAR	FAZALPURBADLI(31)	NEAR SAMSHAN BHUMI	01HRGGMFRN0031FAZI002	PR-PW
75	GURUGRAM	FARRUKHNAGAR	MAHCHANA(16)	DHANI POND	01HRGGMFRN0016MEHC003	PR-PW
76	GURUGRAM	PATAUDI	NURGARH(12)	village pond	01HRGGMPTD0012NOOR003	PR-PW
77	GURUGRAM	FARRUKHNAGAR	MAHCHANA(16)	village pond	01HRGGMFRN0016MEHC002	PR-PW
78	GURUGRAM	FARRUKHNAGAR	MAHCHANA(16)	IWMP(panch peer)	01HRGGMFRN0016MEHC004	PR-PW
79	GURUGRAM	GURUGRAM	TIKLI(167)	pond 2	01HRGGMSHN0166TEEK001	PR-PW
80	HISAR	UKLANA	BITHMARA(85)	Pathar Wala Pond	01HRHSRUKL0085BITH006	PR-PW
81	HISAR	AGROHA	NANGTHALA(138)	Gaaw Wala Johhd	01HRHSRAGR0138NANG002	PR-PW
82	HISAR	ADAMPUR	SISWAL(174)	near road/Near	01HRHSRADM0174DHAN002	PR-PW

				hanuman mandir		
83	HISAR	HISAR-I	GANGWA(166)(CT)	Ramdev mandir wala pond	01HRHSRHR10166GANG004	PR-PW
84	HISAR	HISAR-II	BALSMAND(22)	Mohabbat wala Johar	01HRHSRHR20022BALS003	PR-PW
85	HISAR	HISAR-II	BALSMAND(22)	Saadhewali Johar	01HRHSRHR20022BALS006	PR-PW
86	HISAR	UKLANA	PABRA(65)	guli	01HRHSRUKL0065PABR010	PR-PW
87	HISAR	HANSI-I	GARHI(139)	FRANSIYA POND	01HRHSRHS10139GARH006	PR-PW
88	HISAR	AGROHA	KULERI(56)	Gandi Johdi	01HRHSRAGR0056KULE007	PR-PW
89	HISAR	HANSI-I	SORKHI(130)	GOKAL GADI WALA POND	01HRHSRHS10130SORK003	PR-PW
90	HISAR	HANSI-I	MAZADPUR(31)	BRHAMAN WALA POND	01HRHSRHS10031MUJA001	PR-PW
91	HISAR	HANSI-I	KHARKHARA(127)	Kumbha Road wala Johr	01HRHSRHS10127KHAR001	PR-PW
92	HISAR	HANSI-I	SORKHI(130)	RAHU WALA POND	01HRHSRHS10130SORK001	PR-PW
93	HISAR	AGROHA	KULERI(56)	Bhaker Wala Johad	01HRHSRAGR0056KULE003	PR-PW
94	HISAR	HANSI-II	BHAKLANA(94)	BOJAA WALA JOHD	01HRHSRHS20094BHAK011	PR-PW
95	HISAR	ADAMPUR	CHULIKHURD(6)	CHULI KHURD WASTE WATER POND/Baba chand giri johad	01HRHSRADM0006CHUL002	PR-PW
96	HISAR	HISAR-I	HARIKOT(220)	near harijan chopal	01HRHSRHR10220HARI002	PR-PW
97	HISAR	HANSI-I	KULANA(114)	Bodia Pond	01HRHSRHS10114KULA003	PR-PW
98	HISAR	HISAR-I	MANGALIMOHBAT(158)	Shani Mandir johad	01HRHSRHR10158MANG002	PR-PW
99	HISAR	BARWALA	SARERA(73)	Ganda Pani Johari	01HRHSRBRW0054SARE075	PR-PW
100	JHAJJAR	BAHADURGARH	CHHARA(17)	RAMKUND	01HRJJRBDG0017CHHA003	PR-PW
101	JHAJJAR	BERI	DIGHAL(2)	devsar	01HRJJRRRI0002DIGH011	PR-PW
102	JHAJJAR	JHAJJAR	KHATIWAS(113)	siraj wala pond	01HRJJRJJR0113KHAT005	PR-PW
103	JHAJJAR	MATANHAIL	ISLAMGARH(117)	BODIYA	01HRJJRMTL0117ISHL002	PR-PW
104	JIND	UCHANA	DUMARKHAKALAN(119)	Jogi Wala pond	01HRJNDUCN0119DUMA001	PR-PW
105	JIND	UCHANA	DUMARKHAKALAN(119)	Goban Pond	01HRJNDUCN0119DUMA003	PR-PW
106	JIND	UCHANA	DUMARKHAKALAN(119)	Kund Pond	01HRJNDUCN0119DUMA002	PR-PW

107	JIND	UCHANA	UDEPUR(102)	samanya 1	01HRJNDUCN0102UDAY001	PR-PW
108	JIND	NARWANA	SHINGHWA(33)	panda	01HRJNDNRW0033SING002	PR-PW
109	JIND	NARWANA	SHINGHWA(33)	kundi	01HRJNDNRW0033SING006	PR-PW
110	JIND	NARWANA	KALODAKHURD(83)	old samanya pond	01HRJNDNRW0083KALO002	PR-PW
111	JIND	NARWANA	KALODAKALAN(84)	samanya pond	01HRJNDNRW0084KALO003	PR-PW
112	JIND	NARWANA	MOHALKHERA(38)	late pond	01HRJNDNRW0038MOHA001	PR-PW
113	JIND	NARWANA	FRAINKALAN(78)	harijan basti pond	01HRJNDNRW0078FRAI004	PR-PW
114	JIND	NARWANA	FRAINKALAN(78)	Khima wala pond	01HRJNDNRW0078FRAI002	PR-PW
115	JIND	NARWANA	KHANPUR(71)	HARIJAN JODI	01HRJNDNRW0071KHAN001	PR-PW
116	JIND	NARWANA	KARAMGARH(70)	BADAJOD	01HRJNDNRW0070KARA003	PR-PW
117	JIND	NARWANA	FULIANKHURD(68)	BADAJOD	01HRJNDNRW0068PHUL001	PR-PW
118	JIND	ALEWA	ALEWA(86)	model pond lokan	01HRJNDALW0086ALEW005	PR-PW
119	JIND	NARWANA	SULEHRA(63)	Baba dere wala pond	01HRJNDNRW0065SULH005	PR-PW
120	JIND	ALEWA	KATWAL(54)	buchawala	01HRJNDALW0054KATW002	PR-PW
121	JIND	ALEWA	SHAMDO(68)	kalwa	01HRJNDALW0068SHAM002	PR-PW
122	JIND	ALEWA	DAUHLA(80)	chikana	01HRJNDALW0080DAHO001	PR-PW
123	JIND	SAFIDON	MUANA(63)	Firni wala johad	01HRJNDSFD0063MUAN006	PR-PW
124	JIND	UCHANA	CHHATTAR(76)	mirja wala	01HRJNDUCN0076CHAT002	PR-PW
125	JIND	UJHANA	DHAMTANSAHIB(60)	KUND	01HRJNDNRW0060DHAM001	PR-PW
126	JIND	UCHANA	KABARCHHA(124)	Mani Teerath Pond	01HRJNDNRW0124KABE001	PR-PW
127	JIND	NARWANA	SURAJAKHERAURFSHEOGARH(40)	Bada pond /Kundi	01HRJNDNRW0040SURJ001	PR-PW
128	JIND	NARWANA	DHARODI(72)	DHABWALA	01HRJNDNRW0072DHAR001	PR-PW
129	JIND	NARWANA	DABLAIN(76)	dabwala	01HRJNDNRW0076DABL003	PR-PW
130	JIND	NARWANA	BHANABARAHMNAN(41)	Shivrali Pond	01HRJNDNRW0027BHAN001	PR-PW
131	JIND	NARWANA	BHANABARAHMNAN(41)	Bholu Wala	01HRJNDNRW0041BHAN001	PR-PW
132	JIND	NARWANA	BHIKHEWALA(91)	kalapani	01HRJNDNRW0091BIKH002	PR-PW
133	JIND	NARWANA	BIDRANA(35)	Dhabwali pond	01HRJNDNRW0035BIDR003	PR-PW

134	JIND	NARWANA	DHARODI(72)	Dheni wala	01HRJNDNRW0072DHAR006	PR-PW
135	JIND	UCHANA	MAKHAND(105)	Matawala	01HRJNDUCN0105MAKH001	PR-PW
136	JIND	UCHANA	KAKROD(104)	Dedsar	01HRJNDUCN0104KAKR001	PR-PW
137	JIND	JIND	KHARAKRAMJI(68)	Gurban Johad	01HRJNDJND0068KHAR004	PR-PW
138	JIND	UCHANA	BHAGWANPURA(96)	Mandirwala main pond	01HRJNDUCN0096BHAG002	PR-PW
139	JIND	UCHANA	BHONSLA(132)	naya johd	01HRJNDUCN0132BHON003	PR-PW
140	JIND	JIND	BRAHKALAN(100)	peer khan	01HRJNDJND0160BRAH002	PR-PW
141	JIND	JULANA	BUWANA(19)	Bura wala	01HRJNDJLN0064BUWA002	PR-PW
142	JIND	JULANA	BUWANA(19)	Daab/ Kund Wala Pond	01HRJNDJLN0064BUWA001	PR-PW
143	JIND	JIND	JALALPURKALAN(13)	Let wala	01HRJNDJND0013JALA002	PR-PW
144	JIND	JIND	LALITKHERA(7)	waste water pond 2	01HRJNDJND0007LALI004	PR-PW
145	JIND	JIND	LALITKHERA(7)	Sindhoda wala	01HRJNDJND0007LALI003	PR-PW
146	JIND	JIND	NIDANA(66)	Waste water pond 1	01HRJNDJND0036NIDA002	PR-PW
147	JIND	JIND	PONKARKHERI(10)	bad	01HRJNDJND0010POKR004	PR-PW
148	JIND	JIND	PONKARKHERI(10)	kalawala	01HRJNDJND0010POUN001	PR-PW
149	JIND	UJHANA	RASIDAN(56)	Rasidan	01HRJNDNRW0056RASI001	PR-PW
150	JIND	NARWANA	SAINTHLY(88)	samanya 2 sardar wala	01HRJNDUCN0086SAIN003	PR-PW
151	JIND	SAFIDON	SINGHANA(43)	baba Wala	01HRJNDSFD0043SING001	PR-PW
152	KAITHAL	DHAND	PHARAL(12)	Near Falgu Tirth	01HRKTLDND0012PHAR001	PR-PW
153	KAITHAL	DHAND	AHUN(19)	Pale Wala	01HRKTLDND0019AHUN002	PR-PW
154	KAITHAL	DHAND	KAUL(16/1)	JEET WALA (Model Pond)	01HRKTLDND0016KAUL003	PR-PW
155	KAITHAL	PUNDRI	PAI(48)	Dhaab Wala(Model Pond)	01HRKTLPNR00480PAI003	PR-PW
156	KAITHAL	DHAND	KAUL(16/1)	GAAD WALA	01HRKTLDND0016KAUL004	PR-PW
157	KAITHAL	KALAYAT	BADSIKRIKALAN(24)	dobi pond	01HRKTLKLT0024BADS002	PR-PW
158	KAITHAL	KAITHAL	BUDHAKHERA(87)	PADA WALA	01HRKTLKTL0087BUDH003	PR-PW
159	KAITHAL	KAITHAL	BALWANTI(32)	Johar	01HRKTLKTL0032BALW001	PR-PW
160	KARNAL	GHARAUNDA	KOHAND(30)	budi mata pond	01HRKNLGRD0001KOHA020	PR-PW

161	KARNAL	NILOKHERI	NIGDHU(14)	ganga pond	01HRKNLNLK0040NIGH005	PR-PW
162	KARNAL	INDRI	SMORA(55)	Karu Talab	01HRKNLIND0055SAMO001	PR-PW
163	KARNAL	ASSANDH	PANGALA	Goye Wala Pond	01HRKNLASD0075PANG001	PR-PW
164	KARNAL	NILOKHERI	DADUPUR(83)	Ror Pond (Bathewala)	01HRKNLNLK0083DADU005	PR-PW
165	KARNAL	NILOKHERI	SAMANABHAU(30)	Near NH1	01HRKNLNLK0030SAMA001	PR-PW
166	KARNAL	ASSANDH	KHIZARABAD(85)	Gurudwara wala	01HRKNLASD0085KHIJ001	PR-PW
167	KARNAL	ASSANDH	SALWAN(95)	chalni wala	01HRKNLASD0095SALW006	PR-PW
168	KARNAL	GHARAUNDA	FARIDPUR(39)	outer faridpur pond	01HRKNLGRD0039FARI008	PR-PW
169	KARNAL	ASSANDH	DOPEDI(93)	Power House Wala Pond	01HRKNLASD0093DUPD003	PR-PW
170	KARNAL	ASSANDH	DOPEDI(93)	Malikpur Wala Pond	01HRKNLASD0093DUPD001	PR-PW
171	KARNAL	NILOKHERI	TIKHANA(PART)(46)	kalu baba	01HRKNLNLK0046TAKH001	PR-PW
172	KARNAL	KARNAL	RAMBA(62)	Near Govt. School	01HRKNLIND0062RAMB003	PR-PW
173	KARNAL	ASSANDH	GANGATHERI(56)	dase Wala pond	01HRKNLASD0056GANG005	PR-PW
174	KARNAL	ASSANDH	RATTAK(76)	Aara Wala Pond	01HRKNLASD0076RATT001	PR-PW
175	KARNAL	ASSANDH	JAISINGHPURA(82)	Kund wala pond	01HRKNLASD00820JAI004	PR-PW
176	KARNAL	ASSANDH	UPLANA(78)	Dhab Vala	01HRKNLASD0078UPLA002	PR-PW
177	KARNAL	ASSANDH	JALMANA(64)	Delsar Pond	01HRKNLASD0064JALA001	PR-PW
178	KARNAL	INDRI	SMORA(55)	PANDIT WALA	01HRKNLIND0055SAMO003	PR-PW
179	KARNAL	MUNAK	MUNAK(28)	MakhuWala	01HRKNLMNK0028MUNA001	PR-PW
180	KARNAL	MUNAK	MUNAK(28)	Lodhi Wala	01HRKNLMNK0028MUNA002	PR-PW
181	KARNAL	MUNAK	BALLA(30)	Devi mandir	01HRKNLMNK0030BALL003	PR-PW
182	KARNAL	MUNAK	BALLA(30)	Goli road	01HRKNLMNK0030BALL006	PR-PW
183	KARNAL	NILOKHERI	SONKERA(51)	Near school pond	01HRKNLNLK0000SON041	PR-PW
184	KARNAL	NILOKHERI	NIGDHU(14)	stadium wala	01HRKNLNLK0040NIGD006	PR-PW
185	KARNAL	NILOKHERI	RAIPURRORAN(44)	near IAY COLONY	01HRKNLNLK0044RAIP001	PR-PW
186	KARNAL	NILOKHERI	SHAMGARH(77)	SHAMGARH POND NEAR SHIV MANDIR	01HRKNLNLK0077SHAM003	PR-PW
187	KARNAL	NILOKHERI	DADUPUR(83)	CHUREWALA	01HRKNLNLK0083DADU004	PR-PW

188	KARNAL	ASSANDH	SALWAN(95)	mata wala pond	01HRKNLASD0095SALW004	PR-PW
189	KARNAL	ASSANDH	SALWAN(95)	MALAKSHER	01HRKNLASD0095SALW005	PR-PW
190	KARNAL	ASSANDH	SALWAN(95)	tirath desamadhe	01HRKNLASD0095SALW007	PR-PW
191	KARNAL	ASSANDH	SALWAN(95)	bamno wala	01HRKNLASD0095SALW008	PR-PW
192	KARNAL	ASSANDH	SALWAN(95)	chmaro wala	01HRKNLASD0095SALW009	PR-PW
193	KARNAL	GHARAUNDA	KAIMLA(25)	kaimla pond1	01HRKNLGRD0001KAIM006	PR-PW
194	KARNAL	ASSANDH	RATTAK(76)	Harijan Near Basti Wala Pond (Dada Khera Wala)	01HRKNLASD0076RATT002	PR-PW
195	KARNAL	ASSANDH	UPLANA(78)	Mochan Vala	01HRKNLASD0078UPLA003	PR-PW
196	KARNAL	ASSANDH	UPLANA(78)	Sincer Vala	01HRKNLASD0078UPLA001	PR-PW
197	KARNAL	KUNJPURA	BARAGAON(69)	MULLAN WALA POND	01HRKNLKJP0BARA072	PR-PW
198	KARNAL	GHARAUNDA	FARIDPUR(39)	Sultan shab	01HRKNLGRD0001FARI224	PR-PW
199	KARNAL	GHARAUNDA	FARIDPUR(39)	balmiki pond	01HRKNLGRD0001FARI231	PR-PW
200	KARNAL	GHARAUNDA	FARIDPUR(39)	malkhana pond	01HRKNLGRD0001FARI227	PR-PW
201	KARNAL	KUNJPURA	BARAGAON(69)	gulhe wala	01HRKNLKJP0041BARA002	PR-PW
202	KARNAL	GHARAUNDA	PHURLAK(21)	mai mndir pond	01HRKNLGRD0001PHUR011	PR-PW
203	KARNAL	KUNJPURA	BARAGAON(69)	Chaku wala	01HRKNLKJP0069BARA001	PR-PW
204	KARNAL	GHARAUNDA	FARIDPUR(39)	pathera pond	01HRKNLGRD0001FARI225	PR-PW
205	KARNAL	GHARAUNDA	PHURLAK(21)	mandir wala pond	01HRKNLGRD0001PHUR014	PR-PW
206	KARNAL	GHARAUNDA	FARIDPUR(39)	butli pond	01HRKNLGRD0001FARI229	PR-PW
207	KARNAL	NILOKHERI	SAGA(58)	100gajj palatiawala pond	01HRKNLNLK0058SAGG008	PR-PW
208	KARNAL	NILOKHERI	SAGA(58)	badiya walan pond	01HRKNLNLK0058SAGG007	PR-PW
209	KARNAL	NILOKHERI	SAGA(58)	kapuria wala pond	01HRKNLNLK0058SAGG006	PR-PW
210	KARNAL	NILOKHERI	BARANI(34)	near bramanad mandir	01HRKNLNLK0034BARA002	PR-PW
211	KARNAL	INDRI	BUTANKHER(24)	NEAR MAIN PWD ROAD	01HRKNLIND0024BUTT003	PR-PW
212	KARNAL	INDRI	BUTANKHER(24)	Near phirni	01HRKNLIND0023BUTT003	PR-PW
213	KARNAL	KUNJPURA	CHAUNRA(13)	chaura 2	01HRKNLKNL0054CHAU002	PR-PW

214	KARNAL	INDRI	GANDHINAGAR	NEAR PHIRNI	01HRKNLIND0046GAND001	PR-PW
215	KARNAL	INDRI	GARHIJATTAN(9)	NEAR SHAMSAHN	01HRKNLIND0009GARH002	PR-PW
216	KARNAL	INDRI	HAIBATPURA(17)	School wala pond	01HRKNLIND0017HABI003	PR-PW
217	KARNAL	GHARAUNDA	JAMALPUR(22)	jamalpur pond	01HRKNLGRD0022JAMA001	PR-PW
218	KARNAL	MUNAK	MORMAJRA(31)	Johar Majra	01HRKNLASD00310MOR001	PR-PW
219	KARNAL	INDRI	SARWANMAJRA(20)	colony rampura road	01HRKNLIND0020SARW002	PR-PW
220	KARNAL	INDRI	SARWANMAJRA(20)	Near phirni	01HRKNLIND0054SARW003	PR-PW
221	KARNAL	INDRI	PUNJOKHERA(23)	NEAR BUTTAN KHERI ROAD	01HRKNLIND0023PENJ002	PR-PW
222	KURUKSHETRA	THANESAR	SANWLA	Near NH44	01HRKKRTNS0044SANW104	PR-PW
223	KURUKSHETRA	ISMAILABAD	AJRANAKHURD(276)	on phirni	01HRKKRTNS0276AJRA001	PR-PW
224	KURUKSHETRA	LADWA	JAINPURJATTAN(78)	Near General Choupal	01HRKKRLDW0078JAIN002	PR-PW
225	KURUKSHETRA	LADWA	SURA(50)	In village pond	01HRKKRLDW0050SURA001	PR-PW
226	KURUKSHETRA	LADWA	CHHALAUNDI(67)	SC Basti	01HRKKRLDW0067CHHA003	PR-PW
227	KURUKSHETRA	LADWA	DHANORAJATTAN(59)	Shamshan ghat pond	01HRKKRLDW0059DHAN001	PR-PW
228	KURUKSHETRA	LADWA	SAMALKHA(63)	On Main Road	01HRKKRLDW0063SAMB001	PR-PW
229	KURUKSHETRA	PIPLI	SAMANI(29)	Near NH44	01HRKKRPPL0029SAMA002	PR-PW
230	KURUKSHETRA	LADWA	KHERIDABDALAN(64)	Near place of community centre	01HRKKRLDW0064KHER002	PR-PW
231	KURUKSHETRA	PIPLI	MASANA(96)	Near PWD Road	01HRKKRPPL0096MASA001	PR-PW
232	KURUKSHETRA	LADWA	BUDHA(61)	Near Mandir	01HRKKRLDW0061BODH001	PR-PW
233	KURUKSHETRA	PEHOWA	BAKHLI(11)	Near Guga Madi	01HRKKRPHW0011BAKH001	PR-PW
234	KURUKSHETRA	PEHOWA	BAKHLI(11)	Near Panchayat Ghar	01HRKKRPHW0011BAKH002	PR-PW
235	KURUKSHETRA	PEHOWA	ARNAICHA	Arnecha 1	01HRKKRPHW0014ARNE002	PR-PW
236	KURUKSHETRA	PIPLI	DHIRPUR(408)	pond 2	01HRKKRTNS0408DHIR001	PR-PW
237	KURUKSHETRA	PIPLI	SHADIPURLADWA(367)	Near Lalla Wala Peer	01HRKKRPPL0367SHAD002	PR-PW
238	KURUKSHETRA	PIPLI	KANIPLA(104)	Near Shamshan Ghat	01HRKKRPPL0104KANI002	PR-PW
239	KURUKSHETRA	PIPLI	GOBINDMAJRA(407)	Near Phirni	01HRKKRPPL0407GOVB001	PR-PW

240	KURUKSHETRA	PIPLI	KHAIRA(345)	Near shiv mandir	01HRKKRPPL0345KHAI001	PR-PW
241	KURUKSHETRA	THANESAR	BHAINSIMAJRA(18)	Bhansi Majra 1	01HRKKRTNS0018BHAN001	PR-PW
242	KURUKSHETRA	THANESAR	KIRMACH(6)	Near Govt. School	01HRKKRTNS0006KIRM001	PR-PW
243	KURUKSHETRA	THANESAR	CHANDERBHANPUR(372)	CHANDER BHANPUR 1	01HRKKRTNS0372CHAN002	PR-PW
244	KURUKSHETRA	THANESAR	AMIN(33)	Ambawala Pond	01HRKKRTNS0033AMIN001	PR-PW
245	KURUKSHETRA	THANESAR	AMIN(33)	Susmali wala Pond	01HRKKRTNS0033AMIN002	PR-PW
246	KURUKSHETRA	THANESAR	DAYALPUR(PART)(383)	MirjaPur Road wala Pond	01HRKKRTNS0DAYA004	PR-PW
247	KURUKSHETRA	SHAHBAD	TEORA(243)	Teora 1	01HRKKRSHB0243TEOR001	PR-PW
248	KURUKSHETRA	THANESAR	KIRMACH(6)	kesar mali pond	01HRKKRTNS0006KIRM005	PR-PW
249	KURUKSHETRA	THANESAR	KIRMACH(6)	Phirni 2	01HRKKRTNS0006KIRM006	PR-PW
250	KURUKSHETRA	THANESAR	BAHARI(PART)(389)	Nabhar Temple	01HRKKRTNS0BAHA001	PR-PW
251	KURUKSHETRA	THANESAR	DHURALA(404)	Gujjar Pond	01HRKKRTNS0404DHUR002	PR-PW
252	KURUKSHETRA	THANESAR	ISHAQPUR(29)	Ishaqpur 1	01HRKKRTNS0029ISHA001	PR-PW
253	KURUKSHETRA	PIPLI	ISHARGARH(356)	In village pond	01HRKKRPPL0356ISHA001	PR-PW
254	KURUKSHETRA	BABAIN	MANGAOLIRANGRAN(130)	In village pond	01HRKKRBBN0130MANG001	PR-PW
255	KURUKSHETRA	PIPLI	MATHANA(364)	Bada Pond	01HRKKRPPL0364MATH001	PR-PW
256	KURUKSHETRA	PEHOWA	NIMBWALA(9)	On Main Road	01HRKKRPHW0009NEEM001	PR-PW
257	KURUKSHETRA	ISMAILABAD	ROHTI(312)	Rohti 1	01HRKKRIML0312ROHT001	PR-PW
258	KURUKSHETRA	ISMAILABAD	SALPANIKALAN(300)	salpani kalan small	01HRKKRIML0300SALP002	PR-PW
259	KURUKSHETRA	BABAIN	SANGHOR(163)	On Mahauwa Kheri Road	01HRKKRBBN0163SANG003	PR-PW
260	KURUKSHETRA	PIPLI	SIRSALA(397)	Near Panchayat Ghar	01HRKKRTNS0397SIRS002	PR-PW
261	KURUKSHETRA	PIPLI	SODHI(369)	Near Peer Baba	01HRKKRPPL0369SODH002	PR-PW
262	MAHENDERGARH	NARNAUL	GEHLI(137)	Mandir ke pass	01HRNRLNRL0137GAHL002	PR-PW
263	MAHENDERGARH	KANINA	BEWAL(30)	Pirag wala Pond	01HRNRLKNN0030BEWA004	PR-PW
264	MAHENDERGARH	KANINA	BEWAL(30)	Dirty Water pond Bewal	01HRNRLKNN0030BEWA005	PR-PW
265	MAHENDERGARH	MAHENDRAGARH	MALRASARAI(57)	Khada Wala Johad	01HRNRLMDG0057MALR002	PR-PW
266	MAHENDERGARH	KANINA	DHANAUNDA(12)	Aashram Wala	01HRNRLKNN0012DHAN007	PR-PW

267	MAHENDER GARH	KANINA	SEHLANG(9)	Nappa wala johad	01HRNRLKNN0009SEHL003	PR-PW
268	MAHENDER GARH	KANINA	SEHLANG(9)	Annasir Johad	01HRNRLKNN0009SEHL004	PR-PW
269	MAHENDER GARH	SATNALI	JARWA(4)	jarwa ki dhani	01HRNRLSTN0007JARW004	PR-PW
270	MAHENDER GARH	KANINA	BAGHOT(6)	bab ala pond	01HRNRLKNN0006BHAG001	PR-PW
271	MAHENDER GARH	MAHENDRAGARH	BASSAI(47)	Adda Johad	01HRNRLKNN0047BASS001	PR-PW
272	MAHENDER GARH	MAHENDRAGARH	BASSAI(47)	Goga wala Johad	01HRNRLMDG0047BASS002	PR-PW
273	MAHENDER GARH	ATELI	ATELI(RURAL)(21)	Nanak Wala	01HRNRLATL0021ATEL001	PR-PW
274	MAHENDER GARH	ATELI	CHANDPURA(25/1)	Chandpura (Guga Mandir Pond)	01HRNRLATL0CHAN038	PR-PW
275	MAHENDER GARH	ATELI	SUJAPUR(25/2)	Sujapur 1st (Guga Mandir)	01HRNRLATL0025SUJA002	PR-PW
276	MAHENDER GARH	ATELI	GANIYAR(23)	Ganiyar (Hanuman Mandir)	01HRNRLATL0023GANI001	PR-PW
277	MAHENDER GARH	ATELI	BAJAR(24)	Bazad (Hanuman Temple)	01HRNRLATL0024BAZA002	PR-PW
278	MAHENDER GARH	ATELI	GHARIRUTHAL(41)	Johadi Wala Pond	01HRNRLATL0041GHAR103	PR-PW
279	MAHENDER GARH	NARNAUL	BALAHKHURD(147)	nangalia johd	01HRNRLNRL0147BALA001	PR-PW
280	MAHENDER GARH	SATNALI	BARDA(18)	indokala	01HRNRLSTN0015BARR001	PR-PW
281	MAHENDER GARH	MAHENDRAGARH	JASAWAS(81)	Waste water pond	01HRNRLMDG0081JASA001	PR-PW
282	MAHENDER GARH	SIHMA	KALWARI(34)	Khana wala Johad	01HRNRLSHM0034KALW003	PR-PW
283	NUH	NAGINA	NAGINA(51)(CT)	SC Johar	01HRNUHNGN0051NAGI003	PR-PW
284	NUH	INDRI	REWASAN(168)	Road wala Johad	01HRNUHINR0168REWA001	PR-PW
285	NUH	PUNAHANA	NAI(229)	Bada Johad	01HRNUHPNH02290NAI004	PR-PW
286	NUH	PUNAHANA	NEEMKA(242)	Bada Johad	01HRNUHPNH0242NEEM001	PR-PW
287	NUH	PUNAHANA	JHAROKARI(239)	Bada Johad	01HRNUHPNH0239JHAR001	PR-PW
288	NUH	TAURU	BHAJLAKA(63)	chota johad	01HRNUHTRU0063BHAJ001	PR-PW
289	NUH	INDRI	MANUWAS(186)	Mandir wala Johad	01HRNUHINR0186MANU003	PR-PW
290	NUH	TAURU	BHOGIPUR(53)	Gram panchayat pond	01HRNUHTRU0053BHOG093	PR-PW
291	NUH	PUNAHANA	KHERLAPUNAHANA(169)	takiya johad	01HRNUHPNH0123KHED037	PR-PW
292	NUH	FEROZEPURJHIRKA	PATKHORI(90)	chain pur	01HRNUHFZJ0090PATH002	PR-PW

293	NUH	FEROZEPURJHIRKA	SAKRAS(64)	eidgaon wali pond	01HRNUHFZJ0064SAKR002	PR-PW
294	NUH	NUH	GHASERA(161)	Taali wala Pond	01HRNUHNUH0GHAS032	PR-PW
295	NUH	PINGWAN	PINAGWAN(127)(CT)	patla	01HRNUHPGW0127PINA002	PR-PW
296	NUH	PUNAHANA	BISRU(199)	Khuta Johad	01HRNUHPNH0199BISR001	PR-PW
297	NUH	PUNAHANA	SINGAR(238)	Chandaal	01HRNUHPNH0238SING007	PR-PW
298	NUH	PUNAHANA	KHERLAPUNAHANA(169)	chayri johad	01HRNUHPNH0123KHED036	PR-PW
299	NUH	FEROZEPURJHIRKA	BIWAN(148)	Kabristan Wala	01HRNUHFZJ0148BIWA001	PR-PW
300	NUH	FEROZEPURJHIRKA	BIWAN(148)	Dargah wala	01HRNUHFZJ0148BIWA002	PR-PW
301	NUH	NUH	MALAB(122)	badhi wala johad	01HRNUHNUH0123MALA018	PR-PW
302	NUH	NUH	GHASERA(161)	Shashan wala Johar	01HRNUHNUH0161GHAS003	PR-PW
303	NUH	PUNAHANA	SINGAR(238)	pokhar	01HRNUHPNH0238SING002	PR-PW
304	NUH	NUH	ALAWALPUR(133)	mujiya pati	01HRNUHNUH0123ALWA009	PR-PW
305	NUH	NUH	ALAWALPUR(133)	Sawtiya Pati	01HRNUHNUH0123ALWA010	PR-PW
306	NUH	PINGWAN	MOHAMMADPURTER(187)	badi johad	01HRNUHPNH0187MOHA001	PR-PW
307	NUH	PINGWAN	FEROJPURMEO(203)	bijli wala	01HRNUHPNH0203FIRO001	PR-PW
308	NUH	TAURU	DHULAWAT(81)	aam wala band	01HRNUHTRU0081DHUL001	PR-PW
309	NUH	NAGINA	ATERNASHAMSHABAD(47)	Bohra wala Johar	01HRNUHNGN0047ATER001	PR-PW
310	NUH	NAGINA	KULTAJPURKALAN(62)	Bada Johar	01HRNUHNGN0062KULT001	PR-PW
311	NUH	NAGINA	HASANPURNUH(16)	Chota Johad	01HRNUHNGN0016HASA115	PR-PW
312	PALWAL	HODAL	DEEGHOT(135)	Gula Pond	01HRPWLHDL0135DEEG056	PR-PW
313	PALWAL	PRITHLA	ALAWALPUR(62)	Sayed Wali / Bhajan Wali	01HRPWLPTL0062ALAW084	PR-PW
314	PALWAL	HASANPUR	GULAWAD(113)	Gulabad Pond	01HRPWLHSP0113GULA001	PR-PW
315	PALWAL	HATHIN	MANDKOLA(217)	johri baba pond 28	01HRPWLHTN0217MAND028	PR-PW
316	PALWAL	PRITHLA	DUDOLA(40)	Pavasi vali Pond	01HRPWLPTL0040DUDO107	PR-PW
317	PANCHKULA	RAIPURRANI	GANAULI(200)	near abadi	01HRPKLRPR0200GANA001	PR-PW
318	PANCHKULA	PINJORE	KARANPUR(88)	KARANPUR	01HRPKLPJR0088KARA005	PR-PW
319	PANCHKULA	BARWALA	SHAMTOO(241)	Village pond	01HRPKLBRL0241SHAM001	PR-PW
320	PANCHKULA	BARWALA	BATAUR(247)	SAINIYO WALA POND	01HRPKLBRL0247BATO002	PR-PW

321	PANIPAT	BAPOLI	BAPOLI(54)	Sani wala pond	01HRPPTBPL0054BAPO008	PR-PW
322	PANIPAT	BAPOLI	PASINAKHURD(49)	Khadana wala jhod	01HRPPTBPL0049PASI001	PR-PW
323	PANIPAT	MADLAUDA	MADLAUDA(7)	Lalu Wala 1	01HRPPTMDD0007MADL001	PR-PW
324	PANIPAT	BAPOLI	BEHRAMPUR(40)	Bhumiya 56-57	01HRPPTBPL0040BEHR002	PR-PW
325	PANIPAT	SANOLIKHURD	JALALPUR(38)	Dhabb Vala Jhod	01HRPPTBPL0038JALA002	PR-PW
326	PANIPAT	BAPOLI	DHADOLA(46)	Masjid Wala	01HRPPTBPL0046DADO003	PR-PW
327	PANIPAT	BAPOLI	BEHRAMPUR(40)	Dabri Pond	01HRPPTBPL0040BEHR001	PR-PW
328	PANIPAT	SANOLIKHURD	JALALPUR(38)	Janyala wala jhod	01HRPPTBPL0038JALA003	PR-PW
329	PANIPAT	BAPOLI	PASINAKHURD(49)	Chamar Gadda jhod	01HRPPTBPL0049PASI002	PR-PW
330	PANIPAT	BAPOLI	PASINAKHURD(49)	School Wala Pond	01HRPPTBPL0049PASI003	PR-PW
331	PANIPAT	ISRANA	JONDHANKHURD(69)	Chota pond	01HRPPTISR0001JOND006	PR-PW
332	PANIPAT	SAMALKHA	RAKSEHRA(91)	Goli wala	01HRPPTSML0091RAKE001	PR-PW
333	PANIPAT	SAMALKHA	RAKSEHRA(91)	Dada Khera Pond	01HRPPTSML0091RAKE004	PR-PW
334	PANIPAT	SAMALKHA	KARHANS(69)	Peer wala	01HRPPTSML0069KARH001	PR-PW
335	PANIPAT	SAMALKHA	GARHITAYAGIAN	MANDIR WALA	01HRPPTSML0086GARH011	PR-PW
336	PANIPAT	BAPOLI	GOELAKHURD(61)	Pachawa Wala Pond	01HRPPTBPL0061GOYL001	PR-PW
337	PANIPAT	SAMALKHA	BODHWALMAJRI(87)	DRAIN WALA POND	01HRPPTSML0087BHOD001	PR-PW
338	PANIPAT	SAMALKHA	ATTA(80)	Chichan Pana (Lehne School Near)	01HRPPTSML0080ATTA001	PR-PW
339	PANIPAT	MADLAUDA	NAUHRA(20)	Gheeya Wala Pond	01HRPPTMDD0020NOHR001	PR-PW
340	PANIPAT	MADLAUDA	NAUHRA(20)	Nuria wala Pond	01HRPPTMDD0020NOHR002	PR-PW
341	PANIPAT	MADLAUDA	NAUHRA(20)	Badd wala jhod	01HRPPTMDD0020NOHR003	PR-PW
342	PANIPAT	SANOLIKHURD	SANOLIKALAN(30)	Power house wala	01HRPPTSNK0030SANO001	PR-PW
343	PANIPAT	PANIPAT	SIMLAMOLANA(2)	Mandir wala	01HRPPTPPT0002SIML001	PR-PW
344	REWARI	REWARI	JADRA(87)	Sukh Das Wala Johad	01HRRWRRWR0087JADR005	PR-PW
345	REWARI	NAHAR	KOSLI(172)	Balkhandi Mandir pond	01HRRWRNHR0172KOSL005	PR-PW
346	REWARI	REWARI	JATUWAS(148)	Jatuwas Temple	01HRRWRRWR0148JATU002	PR-PW
347	REWARI	NAHAR	KOSLI(172)	Gussai pond	01HRRWRNHR0172KOSL003	PR-PW

348	REWARI	JATUSANA	ROJHUWAS(231)	BHAIYA vala pond	01HRRWRJTS02 31ROJH003	PR-PW
349	REWARI	JATUSANA	ROJHUWAS(231)	BANI vala pond	01HRRWRJTS02 31ROJH001	PR-PW
350	REWARI	NAHAR	KOSLI(172)	Hardeva pond	01HRRWRNHR0 172KOSL004	PR-PW
351	REWARI	BAWAL	SHAHPUR(33)	Mandir Wala (Main Village Wala)	01HRRWRBWL0 033SHAP001	PR-PW
352	REWARI	KHOL	KHALETA(17)	kankar wala-1	01HRRWRDHN0 017KHAL001	PR-PW
353	REWARI	BAWAL	SUTHANA(42)	suthana 3	01HRRWRBWL0 042SUTH001	PR-PW
354	REWARI	DAHINA	JAINABAD(13)	gangla-1	01HRRWRDHN0 013ZAIN002	PR-PW
355	REWARI	DAHINA	JAINABAD(13)	guhila-1	01HRRWRDHN0 013ZAIN003	PR-PW
356	REWARI	REWARI	KAKORIA(214)	Kherawala 1	01HRRWRRWR0 214KAKO001	PR-PW
357	REWARI	REWARI	BHURTHALJAT(216)	Jarphala 1	01HRRWRRWR0 2160JAT001	PR-PW
358	REWARI	DAHINA	DEHLAWAS(89)	Ganda Pani	01HRRWRDHN0 089DEHL001	PR-PW
359	REWARI	NAHAR	BAWWA(22-N)	Mata wala pond	01HRRWRNHR0 022BAWW003	PR-PW
360	REWARI	NAHAR	NAYAGAON(21-N)	Pehi Wala Pond	01HRRWRNHR0 021NAYA004	PR-PW
361	REWARI	NAHAR	KHURSHIDNAGAR (27-N)	School Wala Pond	01HRRWRNHR0 174KHUR001	PR-PW
362	REWARI	DAHINA	DAROLI(3)	Dirty water Pond	01HRRWRDHN0 003DARO001	PR-PW
363	REWARI	DAHINA	BHOTWASAHIR(85)	Bohatwas Ahir-2	01HRRWRKOL0 085BAHO001	PR-PW
364	REWARI	DAHINA	BHATHERA(79)	Ganda Pani Johad	01HRRWRDHN0 111BHAT001	PR-PW
365	REWARI	DAHINA	BHATHERA(79)	Shiv Mandir Johad	01HRRWRDHN0 111BHAT003	PR-PW
366	REWARI	BAWAL	JAISINGHPURKHERA(22)	Pahadi Wala Pond	01HRRWRBWL0 022JAI0122	PR-PW
367	REWARI	KHOL	KUNDAL(44)	Peer Baba Wala Pond	01HRRWRKOL0 044KUND094	PR-PW
368	REWARI	BAWAL	JAISINGHPURKHERA(22)	Banni Wala Pond	01HRRWRBWL0 022JAI128	PR-PW
369	REWARI	NAHAR	SHAMNAGAR(168_)	PIPLI POND	01HRRWRNHR0 008SHYA001	PR-PW
370	REWARI	BAWAL	JALALPUR(43)	Baba Johri Wala Pond	01HRRWRBWL0 043JALA072	PR-PW
371	REWARI	BAWAL	SABAN(17)	Sanjarpur Rasta Wala Pond	01HRRWRBWL0 017SABA127	PR-PW
372	REWARI	BAWAL	TANKRI(48)	khata wala	01HRRWRBWL0 048TANK001	PR-PW
373	REWARI	DAHINA	BASS(75)	Dharadhar 2	01HRRWRKOL0 075BASS005	PR-PW
374	REWARI	JATUSANA	DOHKIA(107)	Taal Wala Pond	01HRRWRJTS01 07DHOK001	PR-PW

375	REWARI	KHOL	CHIMNAWAS(69)	Waste Water Pond	01HRRWRKOL0069CHIM073	PR-PW
376	REWARI	KHOL	MANETHI(28)(CT)	Bada Pond	01HRRWRKOL0028MANE115	PR-PW
377	ROHTAK	MEHAM	MADINAKAURSAN (105)	Jakhali Pond	01HRRTKMHM0105MADI002	PR-PW
378	ROHTAK	LAKHANMAJRA	TITOLI(88)	malskar	01HRRTKLMR0088TITO002	PR-PW
379	ROHTAK	MEHAM	MOKHRAKHAS(101)	Mandali Wala	01HRRTKMHM0100MOKH004	PR-PW
380	ROHTAK	MEHAM	BAHLBA(103)	Malsar Pond	01HRRTKMHM0103BEHL005	PR-PW
381	ROHTAK	MEHAM	NINDANATIGRI	Sanser pond(Nindana Tigiri)	01HRRTKMHM0107NIND004	PR-PW
382	ROHTAK	MEHAM	NIDANA(98)	PAJAWE WALA POND(Nidana)	01HRRTKMHM0098NIDA002	PR-PW
383	ROHTAK	MEHAM	NIDANA(98)	Jato wala Pond(Nidana)	01HRRTKMHM0098NIDA003	PR-PW
384	ROHTAK	MEHAM	MOKHRAKHAS(101)	Dobhi	01HRRTKMHM0100MOKH006	PR-PW
385	ROHTAK	MEHAM	BEHRANSEKHPUR TITRI	Gugana pond/ Bani wala	01HRRTKMHM0106BHAR004	PR-PW
386	ROHTAK	MEHAM	BEHRANJINDRAN	sadansar	01HRRTKMHM0126BHAR001	PR-PW
387	ROHTAK	ROHTAK	BAHUAKBERPUR(94)	SUIWALA	01HRRTKRTK0094BAHU002	PR-PW
388	ROHTAK	ROHTAK	BAHUAKBERPUR(94)	RITORI	01HRRTKRTK0094BAHU003	PR-PW
389	ROHTAK	ROHTAK	BAHUAKBERPUR(94)	BADWALA POND	01HRRTKRTK0094BAHU004	PR-PW
390	ROHTAK	LAKHANMAJRA	NANDAL(94)	khadde aala	01HRRTKLMR0094NAND001	PR-PW
391	ROHTAK	LAKHANMAJRA	NANDAL(94)	gaam aala	01HRRTKLMR0094NAND004	PR-PW
392	ROHTAK	MEHAM	SISARKHAS(123)	Gulla Pond	01HRRTKMHM0012SISA001	PR-PW
393	ROHTAK	ROHTAK	KILOIKHAS(60)	FACTORY WALA	01HRRTKRTK0123KILO037	PR-PW
394	ROHTAK	ROHTAK	KILOIKHAS(60)	Dada Meda ala	01HRRTKRTK0KILO084	PR-PW
395	ROHTAK	ROHTAK	KILOIKHAS(60)	Dobh wala	01HRRTKRTK0KILO085	PR-PW
396	ROHTAK	MEHAM	AJAIB(108)	Gond wala pond	01HRRTKMHM0108AJAI005	PR-PW
397	ROHTAK	MEHAM	AJAIB(108)	Gula	01HRRTKMHM0AJAI085	PR-PW
398	ROHTAK	MEHAM	AJAIB(108)	gilhala	01HRRTKMHM0AJAI086	PR-PW
399	ROHTAK	MEHAM	AJAIB(108)	ramsar	01HRRTKMHM0AJAI087	PR-PW
400	ROHTAK	MEHAM	FARMANAKHAS(113)	dhamawala	01HRRTKMHM0113FARM006	PR-PW

401	ROHTAK	MEHAM	FARMANAKHAS(113)	parshid	01HRRTKMHM0112FARM002	PR-PW
402	ROHTAK	LAKHANMAJRA	KHARAKJATAN(110)	Rasal Wala Pond	01HRRTKLMR0110KHAR002	PR-PW
403	ROHTAK	LAKHANMAJRA	KHARAKJATAN(110)	Baniya Wala Pond	01HRRTKLMR0110KHAR003	PR-PW
404	ROHTAK	LAKHANMAJRA	KHARAKJATAN(110)	Naya Pond	01HRRTKLMR0110KHAR004	PR-PW
405	ROHTAK	LAKHANMAJRA	KHARAKJATAN(110)	Bucha Wala Pond	01HRRTKLMR0110KHAR001	PR-PW
406	SIRSA	BARAGUDHA	RORI(167)	Near Gurughar	01HRSRSBGD0167RORI008	PR-PW
407	SIRSA	BARAGUDHA	RORI(167)	Near Hanuman Mandir	01HRSRSBGD0167RORI001	PR-PW
408	SIRSA	RANIA	BANI(121)	Near Anaj Mandi	01HRSRSRNI0121BANI005	PR-PW
409	SIRSA	SIRSA	BARUWALI-I(67)	Pond-1	01HRSRSSRS0067BARU002	PR-PW
410	SIRSA	SIRSA	SANGHARSARISHTA(66)	pond 2	01HRSRSSRS0066SANG002	PR-PW
411	SIRSA	SIRSA	SHAHPURBEGU(86)	Pashuo ka Talaab	01HRSRSSRS0086SHAH002	PR-PW
412	SIRSA	DABWALI	RAMGARH(245)	NEAR STADIUM	01HRSRSBBW0245RAMG001	PR-PW
413	SIRSA	RANIA	KEHARWALA(260)	Indra colony	01HRSRSRNI0260KEHA003	PR-PW
414	SIRSA	BARAGUDHA	ALIKAN(176)	Near Gurughar	01HRSRSBGD0176ALIK003	PR-PW
415	SIRSA	BARAGUDHA	ALIKAN(176)	Near Gaushala	01HRSRSBGD0176ALIK002	PR-PW
416	SIRSA	SIRSA	BHAMBOOR(90)	Firni Pond	01HRSRSSRS0090BHAM001	PR-PW
417	SIRSA	SIRSA	DARBI(69)	Darbi pond 1	01HRSRSSRS0069DARB001	PR-PW
418	SIRSA	SIRSA	DARBI(69)	Darbi Pond2	01HRSRSSRS0069DARB002	PR-PW
419	SIRSA	BARAGUDHA	FATEHPURNIAMATKHAN(194)	Near Gugamari	01HRSRSBGD0194FATE001	PR-PW
420	SIRSA	SIRSA	FATEHPURVAIDWALA(76)	Pond 3	01HRSRSSRS0074VAID002	PR-PW
421	SIRSA	SIRSA	FATEHPURVAIDWALA(76)	Pond 4	01HRSRSSRS0074VAID003	PR-PW
422	SIRSA	ODHAN	JANDWALAJATTAN(253)	NEAR GURU GHAR	01HRSRSODN0253JAND003	PR-PW
423	SIRSA	ODHAN	LAKARANWALI(200)	Behind Gurudwara	01HRSRSODN0200LAKA032	PR-PW
424	SIRSA	NATHUSARICHOPTA	NEZIAKHERA(44)	Pashuo ka Talaab 1	01HRSRSNTS0044NEJI002	PR-PW
425	SIRSA	NATHUSARICHOPTA	NEZIAKHERA(44)	Near Water Works	01HRSRSNTS0044NEJI001	PR-PW
426	SIRSA	DABWALI	PANIWALARALDU(303)	GURUGHAR WALA POND	01HRSRSBBW0303PANI001	PR-PW
427	SIRSA	ODHAN	PIPLI(308)	Harijan wala jodh	01HRSRSODN0308PIPL005	PR-PW

428	SIRSA	ODHAN	PIPLI(308)	In front of Shamshan Ghat	01HRSRSODN0000PIPL062	PR-PW
429	SIRSA	DABWALI	RAMPURABISHNOIAN(254)	NEAR PANCHAYAT BHAVAN	01HRSRSBBW0254RAMP003	PR-PW
430	SIRSA	DABWALI	RISALIAKHERA(246)	NEAR VETENERY HOSPITAL	01HRSRSBBW0246RISA005	PR-PW
431	SIRSA	SIRSA	SIKANDERPUR(73)	Pond-2	01HRSRSSRS0073SIKA002	PR-PW
432	SIRSA	SIRSA	SIKANDERPUR(73)	Pond-3	01HRSRSSRS0073SIKA003	PR-PW
433	SIRSA	DABWALI	CHAUTALA(267)	Stadium Pond	01HRSRSBBW0267CHAU001	PR-PW
434	SONIPAT	KHARKHODA	KHANDA(9R)	NAGO WALA	01HRSPTKKD0009KHAN002	PR-PW
435	SONIPAT	RAI	PABSRA(36)	PANCHPEER WALA	01HRSPTRAI0036PABS001	PR-PW
436	SONIPAT	KHARKHODA	KANWALI(216)	MUNNI WALA	01HRSPTKKD0216KANW002	PR-PW
437	YAMUNANAGAR	JAGADHRI	MAHLANWALI(380)	shamshanghat wala pond	01HRYNRJGD0380MAHI001	PR-PW
438	YAMUNANAGAR	RADAUR	BAKANA(40)	Dhoba	01HRYNRRDR0040BAKA005	PR-PW
439	YAMUNANAGAR	RADAUR	TOPRA(193)	Topra pond	01HRYNRRDR0193TOPR003	PR-PW
440	YAMUNANAGAR	RADAUR	JHAGURI(195)	jhaguri	01HRYNRRDR0195JHAG001	PR-PW
441	YAMUNANAGAR	RADAUR	UNHERI(38)	phed tubewell	01HRYNRRDR0038UNHE001	PR-PW
442	YAMUNANAGAR	RADAUR	KANDRAULI(19)	Kandroli	01HRYNRRDR0019KAND001	PR-PW
443	YAMUNANAGAR	SARASWATINAGAR	BHAMBHOLI(435)	shiv temple	01HRYNRSWN0435BHAM002	PR-PW
444	YAMUNANAGAR	BILASPUR	PABNIKHURD(334)	pabni khurd	01HRYNRBLP0334PABN001	PR-PW
445	YAMUNANAGAR	CHHACHHRAULI	DHARAMKOT(270)	dharmkot	01HRYNRCCR0270DHAR001	PR-PW
446	YAMUNANAGAR	SARASWATINAGAR	JANDHERA(433)	Koluwala	01HRYNRSWN0433JHAN002	PR-PW
447	YAMUNANAGAR	SARASWATINAGAR	JAGDHAULI(343)	Shetla Mata	01HRYNRSWN0343JAGD003	PR-PW
448	YAMUNANAGAR	SARASWATINAGAR	KALAWAR(351)	Googa Madi	01HRYNRSWN0351KALA001	PR-PW
449	YAMUNANAGAR	RADAUR	SADHAURA(51)	Sadhura	01HRYNRRDR0051SADH001	PR-PW
450	YAMUNANAGAR	SARASWATINAGAR	KALAWAR(351)	Klawad	01HRYNRSWN0351KLAW003	PR-PW
451	YAMUNANAGAR	CHHACHHRAULI	MANDKHERI(319)	mand kheri1	01HRYNRCCR0319MAND001	PR-PW
452	YAMUNANAGAR	CHHACHHRAULI	TUGALPUR(192)	tugalpur	01HRYNRCCR0192TUGA001	PR-PW
453	YAMUNANAGAR	JAGADHRI	RATTANGARH(487)	sc ka majra pond	01HRYNRJGD0487RATT001	PR-PW
454	YAMUNANAGAR	JAGADHRI	GALOLI(429)	galoli johr pond	01HRYNRJGD0429GALO001	PR-PW

455	YAMUNANAGAR	JAGADHRI	JHINJRON(479)	chauran pond	01HRYNRJGD0479JHIN001	PR-PW
456	YAMUNANAGAR	JAGADHRI	KHAJURI(159)	panchtirthi pond	01HRYNRJGD0159KHAJ001	PR-PW
457	YAMUNANAGAR	SARASWATINAGAR	SARAN(449)	Dabbar wala	01HRYNRSWN0449SARA001	PR-PW
458	YAMUNANAGAR	SARASWATINAGAR	SARASWATINAGAR	HANGOLI ROAD	01HRYNRSWN0444SARA004	PR-PW
459	YAMUNANAGAR	SARASWATINAGAR	SARASWATINAGAR	SAINI MOHALLA	01HRYNRSWN0444SARA006	PR-PW
460	YAMUNANAGAR	SARASWATINAGAR	BADANPURI(481)	MAHILA CHOPAL	01HRYNRSWN0486BADA001	PR-PW
461	YAMUNANAGAR	RADAUR	KHURDBAN(17)	Khurdban	01HRYNRRDR0017KHUR001	PR-PW
462	YAMUNANAGAR	RADAUR	GUMTHALARAO(21)	Gumthala	01HRYNRRDR0021GUMT003	PR-PW
463	YAMUNANAGAR	PARTAPNAGAR	BHANGERI	bhangeri	01HRYNRKJB0009BHAN114	PR-PW
464	YAMUNANAGAR	RADAUR	DOHLI(203)	Dohli	01HRYNRRDR0203DOHL001	PR-PW
465	YAMUNANAGAR	BILASPUR	MUSIMBALHINDWAN(371)	Baba Sadh	01HRYNRBLP0371MUSS001	PR-PW
466	YAMUNANAGAR	SARASWATINAGAR	KALAWAR(351)	Model Town Klawad	01HRYNRSWN0351MODE004	PR-PW
467	YAMUNANAGAR	SARASWATINAGAR	JAGDHAULI(343)	Govt. school	01HRYNRSWN0343JAGD002	PR-PW
468	YAMUNANAGAR	RADAUR	GUMTHALARAO(21)	Gumthala	01HRYNRRDR0021GUMT002	PR-PW
469	YAMUNANAGAR	RADAUR	GUMTHALARAO(21)	Kamleh pond	01HRYNRRDR0021GUMT004	PR-PW
470	YAMUNANAGAR	SARASWATINAGAR	RAMGARH(37)	jato wala	01HRYNRSWN0187RAMG003	PR-PW
471	YAMUNANAGAR	SARASWATINAGAR	BUREKAMAJRA	Shamshan Ghat Wala	01HRYNRSWN0177BHUR003	PR-PW
472	YAMUNANAGAR	SARASWATINAGAR	BALCHHAPAR(365)	gurudwara	01HRYNRSWN03650BAL002	PR-PW
473	YAMUNANAGAR	SARASWATINAGAR	KALANPUR(461)	Desh Raj	01HRYNRSWN0461KALA001	PR-PW
474	YAMUNANAGAR	JAGADHRI	KHUNDEWALA(370)	khundewala pond	01HRYNRJGD0370KHUN001	PR-PW
475	YAMUNANAGAR	JAGADHRI	RUHLAKHERI(424)	rohla khedi pond	01HRYNRJGD0424ROHL001	PR-PW
476	YAMUNANAGAR	RADAUR	JHINWARHERI(172)	Jhinverheri 2	01HRYNRRDR0JHIN048	PR-PW
477	YAMUNANAGAR	CHHACHHRAULI	CHAOWALA(328)	chauwala	01HRYNRCCR0328CHAU001	PR-PW
478	YAMUNANAGAR	SARASWATINAGAR	GARHISIKANDARAH(186)	MIDDLE SCHOOL	01HRYNRSWN0186GARH001	PR-PW
479	YAMUNANAGAR	JAGADHRI	HARIPURJATAN(379)	balmiki basti pond	01HRYNRJGD0379HARI001	PR-PW
480	YAMUNANAGAR	CHHACHHRAULI	JATHERI(307)	jatehri	01HRYNRCCR0307JATE001	PR-PW
481	YAMUNANAGAR	JAGADHRI	KARERAKHURD(148)	karera kurd-1 pond	01HRYNRJGD0148KARE002	PR-PW
482	YAMUNANAGAR	PARTAPNAGAR	KARKAULI(171)	karkuli2	01HRYNRKJB0171KARK246	PR-PW

483	YAMUNANAGAR	JAGADHRI	KATHWALA(377)	Near School	01HRYNRJGD0377KATH001	PR-PW
484	YAMUNANAGAR	SARASWATINAGAR	NAMDARPUR(455)	Govt. school	01HRYNRSWN0455NAMD001	PR-PW
485	YAMUNANAGAR	RADAUR	SANDHALI(25)	Sandhali	01HRYNRRDR0025SAND003	PR-PW
486	YAMUNANAGAR	RADAUR	SANDHALI(25)	Sandhali 1	01HRYNRRDR0025SAND001	PR-PW
487	YAMUNANAGAR	PARTAPNAGAR	SHAHZADWALA(16)	shahzadwala	01HRYNRKJB0016SHAH001	PR-PW
488	YAMUNANAGAR	CHHACHHRAULI	TAHARPURKALAN(28)	taharkalan1	01HRYNRCCR0028TAHA001	PR-PW
489	YAMUNANAGAR	JAGADHRI	DASANI(128)	dusani	01HRYNRJGD0128DUSA001	PR-PW

ANNEXURE-F/D

Amrit Sarovar Ponds List - In-Progress (Urban)

Sr No	District Name	Block Name	Village	Pond Name	UID	Department
1	AMBALA	AMBALA (CORPORATION)	GHELKHURD	Machipalan pond	01HRAMBAM20129GHEL001	ULBD
2	AMBALA	AMBALA (CORPORATION)	LIHARSA(54)	Liharsha 2	01HRAMBAM20054LIHA002	ULBD
3	FARIDABAD	FARIDABAD (CORPORATION)	BUDENA	Budena 46	02HRFDBBAL0328BUNA002	ULBD
4	FARIDABAD	FARIDABAD (CORPORATION)	SIHI	Sihi 163	02HRFDBBAL0334SIHI003	ULBD
5	FATEHABAD	FATEHABAD (COUNCIL)	FATEHABAD(RURAL)(134)	Chilli Lake	02HRFTBROH0000PHWR002	ULBD

ANNEXURE-F/E

List of Ponds in Radaur Assembly Constituency Amrit Sarovar

Sr. No.	District	Name of Constituency	Block	Village	Name of Pond	UID	Status of Pond
1	YAMUNANAGAR	RADAUR	JAGADHRI	SUDHAIL (425)	shamshan ghat pond	01HRYNRJGD0425SUDH001	Completed
2	YAMUNANAGAR	RADAUR	RADAUR	BAKANA(40)	SC pond	01HRYNRRDR0040BAKA002	Completed
3	YAMUNANAGAR	RADAUR	RADAUR	JHINWARHERI(172)	NEAR SHAMSHAN GHAT	01HRYNRRDR0JHIN051	Completed

4	YAMUNANAGAR	RADAUR	JAGADHRI	DASANI(128)	dusani	01HRYNRJGD0128DUSA001	Works Awarded
5	YAMUNANAGAR	RADAUR	JAGADHRI	JHINJRON(479)	chauran pond	01HRYNRJGD0479JHIN001	Works Awarded
6	YAMUNANAGAR	RADAUR	JAGADHRI	KARERA KHURD(148)	karera kurd-1 pond	01HRYNRJGD0148KARE002	Works Awarded
7	YAMUNANAGAR	RADAUR	JAGADHRI	KHAJURI (159)	panchtirthi pond	01HRYNRJGD0159KHAJ001	Works Awarded
8	YAMUNANAGAR	RADAUR	JAGADHRI	RATTANGARH(487)	sc ka majra pond	01HRYNRJGD0487RATT001	Works Awarded
9	YAMUNANAGAR	RADAUR	RADAUR	BAKANA(40)	Dhoba	01HRYNRRDR0040BAKA005	Works Awarded
10	YAMUNANAGAR	RADAUR	RADAUR	DOHLI(203)	Dohli	01HRYNRRDR0203DOHL001	Works Awarded
11	YAMUNANAGAR	RADAUR	RADAUR	GUMTHALARAO(21)	Gumthala	01HRYNRRDR0021GUMT002	Works Awarded
12	YAMUNANAGAR	RADAUR	RADAUR	GUMTHALARAO(21)	Kamleh pond	01HRYNRRDR0021GUMT004	Works Awarded
13	YAMUNANAGAR	RADAUR	RADAUR	GUMTHALARAO(21)	Gumthala	01HRYNRRDR0021GUMT003	Works Awarded
14	YAMUNANAGAR	RADAUR	RADAUR	JHAGURI (195)	jhaguri	01HRYNRRDR0195JHAG001	Works Awarded
15	YAMUNANAGAR	RADAUR	RADAUR	JHINWARHERI(172)	Jhinverheri 2	01HRYNRRDR0JHIN048	Works Awarded
16	YAMUNANAGAR	RADAUR	RADAUR	KANDRAULI(19)	Kandroli	01HRYNRRDR0019KAND001	Works Awarded
17	YAMUNANAGAR	RADAUR	RADAUR	KHURDBAN(17)	Khurdban	01HRYNRRDR0017KHUR001	Works Awarded
18	YAMUNANAGAR	RADAUR	RADAUR	SADHAURA(51)	Sadhura	01HRYNRRDR0051SADH001	Works Awarded
19	YAMUNANAGAR	RADAUR	RADAUR	SANDHALI(25)	Sandhali	01HRYNRRDR0025SAND003	Works Awarded
20	YAMUNANAGAR	RADAUR	RADAUR	SANDHALI(25)	Sandhali 1	01HRYNRRDR0025SAND001	Works Awarded
21	YAMUNANAGAR	RADAUR	RADAUR	TOPRA(193)	Topra pond	01HRYNRRDR0193TOPR003	Works Awarded
22	YAMUNANAGAR	RADAUR	RADAUR	UNHERI(38)	phed tubewell	01HRYNRRDR0038UNHE001	Works Awarded
23	YAMUNANAGAR	RADAUR	SARASWATINAGAR	BADANPURI(481)	MAHILA CHOPAL	01HRYNRSWN0486BADA001	Works Awarded

24	YAMUNANAGAR	RADAUR	SARASWATINAGAR	GARHISIKANDARAH(186)	MIDDLE SCHOOL	01HRYNRSWN0186GARH001	Works Awarded
25	YAMUNANAGAR	RADAUR	SARASWATINAGAR	RAMGARH(37)	jato wala	01HRYNRSWN0187RAMG003	Works Awarded
26	YAMUNANAGAR	RADAUR	SARASWATINAGAR	SARAN(449)	Dabbar wala	01HRYNRSWN0449SARA001	Works Awarded
27	YAMUNANAGAR	RADAUR	JAGADHRI	HARNAUL(465)	harnol pond	01HRYNRJGD0465HARN001	Under Tender Stage
28	YAMUNANAGAR	RADAUR	RADAUR	GHILOUR MAJRI	Ghilour Majri	01HRYNRRDR0GHIL028	Under Tender Stage
29	YAMUNANAGAR	RADAUR	RADAUR	KHERILAKHASINGH(190)	Kheri Lakha Singh	01HRYNRRDR0190KHER001	Under Tender Stage
30	YAMUNANAGAR	RADAUR	RADAUR	PALAKA(198)	Palaka Pond	01HRYNRRDR0198PALA001	Under Tender Stage
31	YAMUNANAGAR	RADAUR	RADAUR	PALAKA(198)	Palaka Pond	01HRYNRRDR0108PALA001	Under Tender Stage
32	YAMUNANAGAR	RADAUR	RADAUR	UNHERI(38)	Near knowledge center	01HRYNRRDR0038UNHE002	Under Tender Stage
33	YAMUNANAGAR	RADAUR	SARASWATINAGAR	HUDIA(173)	samshan ghat	01HRYNRSWN0173HUDI001	Under Tender Stage
34	YAMUNANAGAR	RADAUR	SARASWATINAGAR	HUDIA(173)	Balmiki	01HRYNRSWN0173HUDI002	Under Tender Stage
35	YAMUNANAGAR	RADAUR	SARASWATINAGAR	MASANAJATAN(184)	Panchyati	01HRYNRSWN0184MASA001	Under Tender Stage
36	YAMUNANAGAR	RADAUR	SARASWATINAGAR	SARAN(449)	Mallpani	01HRYNRSWN0449SARA002	Under Tender Stage
37	YAMUNANAGAR	RADAUR	SARASWATINAGAR	SARAN(449)	Baniwala	01HRYNRSWN0449SARA004	Under Tender Stage

श्री बिशन लाल : अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि गांवों के अंदर जितने भी तालाब हैं जो गंदे पानी के भरे खड़े हैं उनके बारे में बता दें। अगर ये पूरे हरियाणा के बारे में जानकारी नहीं देना चाहते तो कम से कम रादौर के बारे में तो बता दें कि वहां पर कितने तालाबों को संवारा गया और उनका क्या इंतजाम किया गया। करोगे या नहीं करोगे। कुल मिलाकर मैं यह जानना चाहता हूं कि रादौर हल्के

के जितने भी तालाब गांव के अंदर हैं जिनमें गंदा पानी भरा पड़ा है वे उबड़–खाबड़ हो रहे हैं। पानी बाहर निकल रहा है। उनमें से पौंड अथॉरिटी ने कोई एक–आधा जोहड़ ठीक किया है या नहीं किया है?

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, हमने पौंड अथॉरिटी ऑफ हरियाणा के द्वारा पूरे प्रांत में 1615 तालाबों की एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल दे दी है। जिसमें 1047.67 करोड़ रूपये की योजना बना दी गई है। पौंड अथॉरिटी ऑफ हरियाणा के द्वारा रादौर हल्के के अंदर 37 तालाबों की 29 करोड़ रूपये की एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल दे दी है। अगर एवरेज निकाला जाये तो यह पूरे प्रदेश से तीन गुणा ज्यादा है। रूरल डिवैल्पमैंट डिपार्टमैंट के द्वारा मनरेगा की 86 लाख की स्कीम्ज है। कुल 48 केस इनके क्षेत्र के हैं। इन पर 29.86 करोड़ रूपये की लागत से काम अभी चल रहा है।

श्री बिशन लाल : स्पीकर सर, मैं सिर्फ यह जानना चाह रहा था कि रादौर के अंदर किसी एक–आधे तालाब पर काम हुआ भी है या अभी सिर्फ योजनायें ही बन रही हैं। मुझे उनके नाम बता दिये जायें।

श्री अध्यक्ष : इसमें लिखा तो है कि तीन का काम पूरा हो चुका है।

श्री जय प्रकाश दलाल : स्पीकर सर, किसी भी काम को करने के लिए पहले एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल होती है। उसके बाद उसका टैण्डर होता है। उसके बाद आगे का काम होता है। यह सारी की सारी प्रक्रिया निर्धारित है। इनके क्षेत्र के 37 तालाबों के कामों की हमने 29 करोड़

रूपये की एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल देकर टैण्डर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

श्री बिशन लाल : स्पीकर सर, मंत्री जी मुझे सिर्फ इतना बता दें कि कौन–कौन से गांवों के तालाबों पर पौंड अथॉरिटी ऑफ हरियाणा द्वारा काम किया जाना प्रस्तावित है। मुझे सम्बंधित गांवों के नामों की लिस्ट दे दी जाये।

श्री जय प्रकाश दलाल : स्पीकर सर, रादौर हल्के के 37 तालाबों पर काम किया जाना प्रस्तावित है उनकी लिस्ट जवाब के साथ लगी है। माननीय सदस्य उसको जवाब में देख सकते हैं।

टोल प्लाजा की कुल संख्या

***34. श्री लक्ष्मण सिंह यादव :** क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि:-

(क) हरियाणा राज्य में राज्य राजमार्गों तथा जिला राजमार्गों पर स्थित वाणिज्य टोल प्लाजा की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह तथ्य है कि कमर्शियल टोल प्लाजा जो गांव गुज्जरवास में राज्य राजमार्ग पर तथा गांव चौकी न0 1 में जिला राजमार्ग पर स्थापित किए गए हैं जिनसे सरकार को नाममात्र का राजस्व मिल रहा है तथा उक्त क्षेत्र के लोगों के बीच रोष व्याप्त है; तथा

(ग) क्या उपरोक्त टोल प्लाजा को हटाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala) :

a) Sir, there are total 12 number of commercial toll plazas situated on the State Highways, Major District Highways and Other District Highways in Haryana State. The category wise detail of Toll Plazas is as under:-

(i) State Highways = 07
(ii) MDR = 03
(iii) ODR = 02
} 12 No.

b) Sir, there are two commercial toll plazas set up in the said area namely;

(i) **TP-53** installed on Subana-Kosli-Nahar-Kanina road (SH-22) near village Gujarwas at km 69.00 in Rewari District. Presently, this toll plaza is generating average revenue of approximately Rs. 141.00 lacs annually to the Government. There is resentment prevailing amongst the people of said area for installing this toll.

(ii) **TP-54** installed on Jewra Gudana road (Hailly Mandi Palhawas road) at km 9.500 in Rewari District. Presently, this toll plaza is generating average revenue of approximately Rs. 40.00 lacs annually to the Government. There is resentment prevailing amongst the people of said area for installing this toll.

(c) No, sir.

श्री लक्ष्मण यादव : अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से डिप्टी सी.एम. साहब का धन्यवाद करना चाहूंगा कि पिछली बार मैंने सदन में एक पुल का क्वैश्चन उठाया था आज उसकी प्रशासनिक स्वीकृति भी जारी हो चुकी है और उसका पैसा भी सैंक्शन हो गया है। मैं डिप्टी सी. एम. साहब का धन्यवाद भी करता हूं और साथ में एक निवेदन भी करता हूं कि मेरे यहां एक छोटे से एरिया में ही रोड्ज पर तीन टोल टैक्स बैरियर लगा रखे हैं। इन रोड्ज में एक रोड तो एक तहसील से दूसरी तहसील तक है और दूसरी एक जिले से दूसरे जिले तक है और तीसरी रोड नैशनल हाईवे है। इन तीनों रोड्ज पर टोल टैक्स बैरियर लगे हुए हैं। नैशनल हाईवे की मैं चर्चा नहीं करना चाहता बल्कि मैं तो स्टेट के रोड्ज पर जो इस तरह से टोल लगा रखे हैं उनके बारे में बात करना चाहता हूं। इनसे मेरे इलाके की जनता में रोष व्याप्त है। इनके विरोध

में लोग वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा और भी बहुत से टोल टैक्स लगे होते हैं जो नहीं होने चाहिएं। स्कूल बसों पर कोई टोल टैक्स नहीं होता लेकिन वहां पर स्कूल बसों पर भी टोल वसूला जा रहा है। अगर कोई किसी शोक सभा में शामिल होने जा रहा है तो उनको भी टोल देना पड़ता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के जो छोटे–मोटे कमर्शियल व्हीकल्स हैं उन पर भी टोल लग रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे हरियाणा में राज्य मार्गों, जिला मार्गों तथा अन्य जिला मार्गों पर सिर्फ 12 कमर्शियल टोल प्लाजा हैं जिसमें से 2 मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या पूरे हरियाणा में केवल 12 कमर्शियल टोल प्लाजा हैं और कहीं पर क्या कोई कनैक्टिविटी है ही नहीं? मेरे निर्वाचन क्षेत्र के साथ यह अन्याय क्यों हो रहा है? इस बात को लेकर वहां की जनता में आक्रोश है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि–

गैरों पर कर्म अपनों पर सितम, ऐ जाने वफा ये जुल्म न कर,
हम चाहने वाले हैं तेरे यूं हमको सताना ठीक नहीं।

मैं तो यही कहना चाहूंगा कि या तो पूरे हरियाणा में कमर्शियल टोल प्लाजा लागू कर दिये जायें या मेरे निर्वाचन क्षेत्र के दो कमर्शियल टोल प्लाजा को भी हटा दिया जाये।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह कहना सही है। स्टेट हाईवेज, एम.डी.आर. और ओ.डी.आर. पर हरियाणा प्रदेश में पी.डब्ल्यू.डी. के केवल 12 कमर्शियल टोल प्लाजा हैं जहां पर प्राइवेट व्हीकल्स से टोल कलैक्शन नहीं होता है। जहां तक स्कूल बसिज की बात है तो स्कूल बसिज कमर्शियल व्हीकल्स

में आती हैं इसलिए उनसे टोल वसूला जाता है। इन टोल प्लाजा से जब भी कोई कमर्शियल नम्बर प्लेट का व्हीकल निकलेगा तो उसको टोल चुकाना होता है। माननीय सदस्य कुछ समय पहले एक डैलिगेशन लेकर मुझसे मिल कर गये थे और हमने टोल प्लाजा नं. 54 को एग्जामिन करवाया था और मैं इस महान् सदन में यह घोषणा करना चहूंगा कि 1 मार्च, 2023 से हम उसको बंद करने जा रहे हैं क्योंकि वहां पर कमर्शियल व्हीकल्स की संख्या बहुत कम है और लोकल लेवल पर पब्लिक के लिए हिंड्रेंस पैदा कर रहा है। माननीय सदस्य का जो दूसरा टोल प्लाजा है उसकी भी हम समीक्षा करवा लेंगे और अगर कमर्शियल व्हीकल्स कम हैं और कमर्शियल एक्टिविटीज वायबल नहीं होंगी तथा पब्लिक को भी उससे दिक्कत है तो भविष्य में उस पर भी विचार कर लेंगे।

श्री लक्ष्मण सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि उस टोल प्लाजा की लगभग 1 करोड़ 41 लाख रुपये कलैक्शन है और इतनी तो कर्मचारियों की सैलरी भी हो जाती है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि सिर्फ वहीं पर यह कमर्शियल टोल प्लाजा क्यों जरूरी है? राज्य राजमार्गों पर 7 कमर्शियल टोल प्लाजा हैं, मुख्य जिला मार्गों पर 3 तथा अन्य जिला मार्गों पर 2 कमर्शियल टोल प्लाजा लगे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में ही इस प्रकार के टोल प्लाजा क्यों लगे हुए हैं? वहां पर लोग धरने पर बैठे हुए हैं। लोग मेरे पास आ कर कहते हैं कि इस टोल को हटवाओ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि 1 करोड़ 41 लाख रुपये कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है इसलिए टोल प्लाजा नं. 53 को भी हटाने की कृपा करें। वहां पर सकूल बसों की लाइनें लग जाती हैं। अगर मेरे विधान सभा क्षेत्र से यह कमर्शियल टोल प्लाजा नहीं हटता है तो पूरे राज्य में इस तरह के कमर्शियल टोल प्लाजा लगा दिये

जायें। मैं बताऊंगा कि कहां पर स्टेट की स्टेट से कनैक्टिविटी है, कहां पर जिला से जिला तथा तहसील से तहसील की कनैक्टिविटी है? आप सभी पर इस तरह के कमर्शियल टोल प्लाजा लगा दीजिए। मेरे साथ ही ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? मैं उस रोड से निकल भी नहीं पाता हूं क्योंकि लोग मुझसे कहते हैं।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिस टी.पी. 53 की बात कर रहे हैं उसकी कलैक्शन लगभग 1.5 करोड़ रुपये है। हम उसको रिव्यू करवा लेते हैं तथा उसके अनुसार सरकार निर्णय ले लेगी। सत्र अवकाश के बाद जब दोबारा से विधान सभा का सत्र शुरू होगा तब इसके बारे में स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। इसके अतिरिक्त टी.पी. 54 को हम 1 मार्च, 2023 से बंद कर रहे हैं।

श्री शमशेर सिंह गोगी: अध्यक्ष महोदय, असंध और करनाल के बीच में भी एक टोल प्लाजा लगा हुआ है तथा लोगों को हर रोज जिला मुख्यालय करनाल जाना पड़ता है तो टोल टैक्स देना पड़ता है। यह मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोगों के लिए एक तरह का जजिया कर है। अगर माननीय सदस्य श्री लक्ष्मण यादव जी के क्षेत्र का टोल हटाया जा रहा है तो मेरे असंध का टोल प्लाजा भी हटाने की कृपा की जाये।

....

सड़क चौड़ी करना

***35. श्री सुभाष गांगोली -** क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे किः-

(क**)** क्या यह तथ्य है कि लगभग **56** करोड़ रुपये की लागत से जींद-सफीदों सड़क को **10** मीटर तक चौड़ा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा **3** अप्रैल**, 2021** को घोषणा की गई थी**;**

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त सड़क को 10 मीटर तक चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा उक्त कार्य को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; तथा

(ग) क्या सफीदों विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले लोक निर्माण विभाग की 22 सड़कों की मरम्मत करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 3 अप्रैल, 2021 को घोषणा की गई थी?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala) :

(a) Yes Sir, the above said road is proposed under CM Announcement (CMA No. 25943) (for widening from 7 mtr. to 10 mtr.). However, the date of announcement is 03.04.2022 instead of 03.04.2021

(b) The length of this road is 36.73 km. The rough cost estimate has been uploaded on HEW portal amounting to Rs. 7901.11 lacs, which is under examination and will be submitted for approval to Government. The time frame cannot be given at this stage.

(c) The CM Announcement was to repair the 21 nos. roads (instead of 22 nos. roads) and all these are proposed to be repaired.

श्री सुभाष गांगोली : अध्यक्ष महोदय, 03 अप्रैल, 2022 को मुख्यमंत्री जी ने जीन्द–सफीदों रोड के चौड़ीकरण की घोषणा की थी और 03 फरवरी, 2023 को मैंने अधिकारियों से पूछा कि इस रोड का क्या स्टेटस है ताकि मैं विधान सभा में इसका प्रश्न लगा सकूं। उन्होंने मुझे बताया कि अभी तक इस रोड के लिए ऐस्टीमेट्स बनाने की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है। जब मैंने यह प्रश्न विधान सभा में लगाया तो उसके बाद इसकी प्रक्रिया शुरू की गई है। इस प्रक्रिया की शुरूआत एक्सियन ऑफिस से होती है लेकिन आज तक एक्सियन ऑफिस से इस रोड का ऐस्टिमेट्स बनकर नहीं गया है। जब मैंने इस रोड को बनाने की समय सीमा की बात की तो माननीय उप–मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके माध्यम से उप–मुख्यमंत्री जी

से रिक्वैस्ट करूंगा कि इस रोड का चौड़ीकरण कब तक कर दिया जाएगा? इसकी समय सीमा जरूर तय की जाए कि इस पर काम कब तक शुरू हो जाएगा? इसी के साथ ही मेरी विधान सभा की 21 सड़कों की मरम्मत व चौड़ीकरण की घोषणा भी की गई थी लेकिन एक्सियन ऑफिस से उन 21 सड़कों का ऐस्टीमेट्स भी अभी तक नहीं बना है। उनमें से तीन–चार सड़कें मैंने अपने 25 करोड़ रुपये के कामों में दी हैं क्योंकि मुझे लोकल ऑफिसर्ज ने कहा कि पहले आप हमें मुख्यमंत्री जी की घोषणा में से कुछ सड़कें दे दो तो उनमें से जो ज्यादा महत्वपूर्ण सड़कें थी वह मैंने अपने 25 करोड़ रुपये वाले कामों में दे दी। उनके ऐस्टिमेट्स हैड क्वार्टर पर आए हुए हैं लेकिन मेरे हल्के की बाकी जो 17–18 सड़कें बची हैं जिनकी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी उन पर भी ध्यान दिया जाए और जो जीन्द–सफीदों रोड के चौड़ीकरण का काम था उसकी समय सीमा जरूर से जरूर निर्धारित की जाए। यह मेरा आपके माध्यम से उप–मुख्यमंत्री जी से निवेदन है।

श्री दुष्यंत चौटाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो ऐस्टिमेट्स के बारे में बात कही है कि अभी तक ऐस्टिमेट्स नहीं बना है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारे पास डी.पी.आर. से इस सड़क का ऐस्टिमेट 79 करोड रुपये का आया है। इसके लिए फोरैस्ट क्लीयरैंस और बाकी एप्रूवल चाहिए होती हैं उसके लिए ऑलरेडी फाईल पुटअप कर दी गई है। आने वाले समय में जैसे ही फोरैस्ट से इसकी एप्रूवल आती है तो हम इस सड़क की वाइडनिंग भी करेंगे। यह सरकार की अनाउंसमैंट है उसको पूरा किया जाएगा। जहां बाकी सड़कों की बात आई है इनके 25 करोड़ रुपये के कामों में से मेरे पास इनकी तरफ से अभी तक 15 करोड़ रुपये की ही डिमांड आई है। मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य जिन

21 सड़कों की बात कर रहे हैं उनमें से ये 10 करोड़ रुपये के काम जल्दी से जल्दी भिजवाएं उनको हम इसी फाईनैंशियल इयर में टेकअप करेंगे।

श्री सुभाष गांगोली : अध्यक्ष महोदय, जो मैंने काम दिये हुए थे वे लगभग तेईस–साढ़े तेईस करोड़ रुपये के थे उनमें से भी लगभग 10 करोड़ रुपये के काम अकेले मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं में से हैं। वह भी इसलिए कि हमारे एस.ई. और एक्सियन ने यह कहा कि अगर ये दोनों अर्थात सी.एम. साहब की घोषणा और आपके 25 करोड़ के काम इक्ट्ठे हो जाएंगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। इन सड़कों में से हाट से रामनगर तक की सड़क बहुत ही जर्जर हालत में है जिसके कारण लोगों ने अल्टरनेट रास्तों से जाना शुरू कर दिया है। यह सड़क सी.एम. साहब की घोषणा में भी है और मेरे 25 करोड़ रुपये के कामों में भी है लेकिन इनमें जो जीन्द–सफीदों रोड के चौड़ीकरण का काम है उसको टाईम बाउंड जरूर करवाया जाए क्योंकि 10 महीने बाद जब मेरा प्रश्न एक्सियन ऑफिस या इंजीनियर सैल में गया उसके बाद इस पर काम शुरू हुआ है लेकिन 10 महीने तक इस पर कोई भी काम शुरू नहीं हुआ था। 10 महीने पहले कम से कम इसका ऐस्टिमेट बनाने का काम भी शुरू नहीं हुआ था। मैं पूछना चाहता हूं कि अब इस रोड पर काम कब तक शुरू हो जाएगा, इसका टाईम बाउंड जरूर किया जाए।

डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा : अध्यक्ष महोदय, मेरे जीन्द का भी इसी प्रश्न से संबंधित एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : मिड्ढा साहब, प्लीज आप बैठ जाइये। इस तरह से तो पूरे हरियाणा की सड़कें हो जाएंगी। इस तरह तो सारे हरियाणा में सड़कें ही सड़कें हैं। आप इस तरह से नहीं पूछ सकते।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का कहना कि इस रोड के काम को टाईम बाउंड किया जाए। मैं उनको बताना चाहूंगा कि फोरैस्ट की क्लीयरैंस के बाद ही इसका अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरा माननीय सदस्य ने जो हाट गांव की सड़क की बात कही है उसके लिए मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य भी खुद देख सकते हैं कि उस सड़क की एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल पर डल चुका है। उसके टैंडर प्रक्रिया में जितना समय लगेगा उस अवधि को हम शॉर्ट लाईन भी नहीं कर सकते लेकिन उसके बाद कंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

श्री सुभाष गांगोली : अध्यक्ष महोदय, मेरी जो 17 सड़कें बची हुई हैं उनमें से 5–6 सड़कें तो मैंने अपने 25 करोड़ रुपये के कामों में दे दी हैं। अतः मेरी जो 17 सड़कें बची हैं कम से कम उनका तो टाईम बाउंड करवाया जाए।

....

राजकीय महिला महाविद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण करना

***36. श्री हरविंदर कल्याण** : क्या उपमुख्यमंत्री कृपया बताएंगें किः

(क) क्या यह तथ्य है कि घरौंडा विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र (करनाल) में राजकीय महिला महाविद्यालय, बसताड़ा का निर्माण कार्य उच्च शिक्षा विभाग के अनुरोध पर आरम्भ किया गया था;

(ख) उपरोक्त महाविद्यालय का निर्माण कार्य किस तिथि को आरम्भ किया गया था;

(ग) क्या यह भी तथ्य है कि लगभग गत् तीन वर्षो से इस महाविद्यालय का निर्माण कार्य रोक दिया गया है; तथा

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त महाविद्यालय के निर्माण कार्य को कब तक पुनः आरम्भ /पूरा किया जाने की संभावना है ?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala) :

a) Yes, Sir.

b) The work of construction of Govt. College for Women at Bastara in Gharaunda Assembly Constituency (Karnal) was started on 26.02.2019 as per agreement.

c) Yes, presently the work has been stopped by the contractual agency since March, 2022.

d) At present, no time frame can be given as the matter is sub-judice. The Hon'ble High court has restrained the department from taking any coercive action against the contractual agency.

श्री हरविन्द्र कल्याणः स्पीकर सर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में गर्ल्स कालेज का कार्य रूका हुआ है और मैंने इस संदर्भ में जो जानकारी मांगी थी, उसके जवाब में मुझे माननीय उप मुख्यमंत्री जी से जवाब मिला है कि इस संदर्भ में वर्तमान में कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती क्योंकि मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और माननीय उच्च न्यायलय ने संविधा एजेंसी के खिलाफ बलपूर्वक कार्यवाही करने की रोक लगा दी है। यह सही है कि मामला सब ज्युडिश है मगर मैं इसमें यह कहना चाहूंगा कि यह भी तो सही है कि उस एजेंसी ने फ्राड किया हुआ है और यह सारा कुछ जग जाहिर भी हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक एन.सी.सी. एकेडमी भी है, इसका काम भी इसी एजेंसी के पास है और वह काम भी रूका हुआ है। स्पीकर सर, यह कहना है कि बलपूर्वक कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है, यह कोई विषय नहीं है। वास्तव में विभाग को इसमें एक क्लीयर स्टैंड लेना चाहिए क्योंकि इस एजेंसी की अभी पिछले दिनों विजिलेंस ने हैफेड के एक मामले में इंक्वायरी भी की है। जब आर्बिट्रेशन संभव नहीं है तो विभाग को कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल करना चाहिए और नियमों के अनुसार आगे से इस एजेंसी के कांट्रैक्ट को खारिज करके

रिटैंडरिंग करने का काम करते हुए प्रोजेक्ट्स के काम को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, इस संस्था का काम 65 परसेंट पूर्ण हो चुका था और उसके बाद इंक्वायरी की गई। इसके प्रोजेक्ट के अंदर बजट अनुमान से ज्यादा लागत लगाई गई थी। इसके उपर हाई कोर्ट ने कोरेसिव एक्शन के लिए मना करते हुए, कंसंर्ड ए.सी.एस. को आदेश दिए हैं कि एक कमेटी इस सारे विषय को एग्जाामिन करते हुए आगे का निर्णय ले और इस प्रकार कमेटी ने प्रोजेक्ट–बाई–प्रोजेक्ट मेजरमैंट कराते हुए, इस एजेंसी के लिए कई जगहों पर कैंसिलेशन प्रक्रिया एडाप्ट की है और कई जगह आर्बिट्रेशन के तहत काम को नगोशियेट करने का भी काम किया गया है। माननीय सदस्य को मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आज के दिन कुछ ज्यादा कहना संभव नहीं है लेकिन जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी है, इसका अगला एजेंडा जब भी आयेगा तो उसमें इस प्रोजेक्ट के संदर्भ में फाइनल निर्णय लिया जायेगा और उस रिपोर्ट को हाई कोर्ट में सबमिट करने का काम भी करेंगे।

....

मुख्यमंत्री की घोषणाएं लागू करना

*__37. श्री असीम गोयल :__ क्या मुख्यमंत्री बताएंगे कि अंबाला शहर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में दिनांक 01.01.2015 से 31.12.2019 तक माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाएं लागू की गई हैं, यदि हाँ तो उसका ब्योरा क्या है?

****मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) :** महोदय, अंबाला शहर विधानसभा क्षेत्र में दिनांक 01.01.2015 से 31.12.2019 तक की गई मुख्यमंत्री घोषणाओं का वार्षिक ब्यौरा निम्न प्रकार है:–

———————————————————————

****शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) द्वारा उपरोक्त प्रश्न का उत्तर दिया गया ।**

वर्ष–वार ब्यौरा					
वर्ष	कुल	कार्यान्वित / पूर्ण	कार्यरत	संभावित नहीं	लम्बित
2015	5	3	2	0	0
2016	16	9	5	1	1
2017	16	12	3	0	1
2018	49	42	4	2	1
2019	2	2	0	0	0
कुल	**88**	**68**	**14**	**3**	**3**

श्री असीम गोयलः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले बजट सत्र में भी इन घोषणाओं को लेकर एक स्पेसिफिक डिपार्टमैंट अर्थात यू.एल.बी. को लेकर सदन में एक सवाल लगाया था और आज मैंने मेरे विधान सभा क्षेत्र की जो पूरी सी. एम. अनाउंसमैंट् हैं, को लेकर सदन में सवाल लगाया है। पिछली बार आदरणीय यू.एल.बी. मिनिस्टर जी ने मुझे सदन में दो घोषणाओं के उपर जवाब देते हुए कहा था कि एक घोषणा का काम तो 92 प्रतिशत पूरा हो चुका है और दूसरी घोषणा का काम 80 परसैंट पूरा हो चुका है और बहुत जल्दी इसको कंप्लीट करा देंगे लेकिन उन्होंने इसके लिए डेट नहीं बताई थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि उसके उपर अभी तक भी कोई रिवाज्ड एस्टिमेट्स की प्रक्रिया तक भी शुरू नहीं हुई है जबकि अप्रैल माह में हमने रिवाइज्ड एस्टिमेट्स भेज दिए थे। इसी प्रकार कुछ घोषणायें जो लगभग 6 साल पुरानी हैं, उसकी कंम्पलीशन डेट सदन में 30.5.2022, 4.7.2022 तथा 31.12.2022 बताई गई थी और और एक घोषणा की तिथि फरवरी 2023 बताई गई थी लेकिन मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि इनकी तो अभी तक रिवाइज्ड एस्टिमेट्स की प्रक्रिया तक भी एसैप्ट करने की कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। इसके अलावा जिस बात का मेरे साथी हरविन्द्र कल्याण जी ने जिक्र किया है, के संदर्भ में कहना चाहूंगा कि हमारे यहां की पी.डब्ल्यू.डी. की चार

घोषणायें में से तीन घोषणायें उसी एजेंसी की वजह से रूकी हुई पड़ी हैं। इसमें विभाग का बहुत पैसा लगा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, एक घोषणा 28.5.2016 की है, दूसरी 12.2.2017 की है तथा तीसरी घोषणा 31.7.2017 की है। अध्यक्ष महोदय, विडंबना देखिए कि हमारे यहां जो वूमन कालेज है, वह सारा का सारा सरकारी स्कूल के अंदर ही चल रहा है जिसकी वजह से स्कूल की बच्चियां तो परेशान हो ही रही हैं और उसके साथ–साथ कालेज के विद्यार्थी भी परेशान हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, गुरू गोबिंद सिंह का ननिहाल मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर आता है। माता गुजरी कौर के नाम से एक वी.एल.डी.ए. कॉलेज बनना था, जिसकी घोषणा वर्ष 2017 में हुई थी, वह भी पैंडिंग है। मिनी सचिवालय की घोषणा हुए लगभग 7 साल हो गये हैं, इस प्रकार लगभग सभी घोषणाएं अन–कम्पलीट हैं। इन घोषणाओं में सबसे बड़ी दिक्कत सब–ज्युडिश को लेकर आ रही है। जैसे अभी माननीय विधायक श्री हरविन्द्र कल्याण जी ने कहा कि जब तक डिपार्टमैंट एक एफिडेविट फाइल करके टैंडर का प्रोसैस नहीं चलायेंगे तब तक काम कम्पलीट नहीं होंगे। सब–ज्युडिश मैटर को चलते हुए तो लगभग 6–7 साल हो गये हैं, इस बात का पता नहीं कि यह मैटर कितने साल और आगे तक जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, एक हमारी घोषणा 200 बेडिड के अस्पताल को 300 बेडिड करने की थी, उस घोषणा को हुए लगभग 8 साल हो गये हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि घोषणाएं लम्बित हैं और कार्यरत हैं, इस बात का तो मुझे भी पता है। मेरी इस प्रकार की हमारी कई घोषणाएं हुए लगभग 7–8 साल हो गये हैं और वे हमारे इलाके के लिये बहुत ही जरूरी घोषणाएं हैं, इसलिए मेरा निवेदन है कि इनके ऊपर कार्य करते हुए जल्दी से जल्दी कम्पलीट करवाया जाये। मेरा माननीय संसदीय मंत्री जी से अनुरोध है कि मुझे कम से कम सदन में आश्वासन तो जरूर दे।

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की तीन घोषणाएं पैंडिंग हैं। एक घोषणा सेंट्रल जेल अम्बाला के पीछे सिटी फॉरेस्ट का निर्माण करने की थी। अभी सेंट्रल जेल अम्बाला नए स्थान पर ट्रांसफर नहीं हुई, इसलिए काम रूका हुआ है। दूसरी घोषणा अम्बाला ब्लॉक–1 में जनसुई हैड पर बस स्टैण्ड का निर्माण करने की थी। इसका माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उद्घाटन कर दिया है और इस पर काम शुरू होने वाला है। माननीय सदस्य की तीसरी घोषणा नगर निगम कार्यालय द्वारा अम्बाला शहर में ऑडिटोरियम, मार्किट तथा मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण करने की थी। अध्यक्ष महोदय, यू.एल.बी. द्वारा दिनांक 10.02.2023 को अम्बाला शहर में इस कार्य बारे मौके का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान यह निर्णय लिया गया कि इस घोषणा को सरकार की दिव्य नगर योजना के अन्तर्गत पूरा किया जा सकता है। जिसमें लागत का 50 प्रतिशत राज्य सरकार तथा 50 प्रतिशत नगर निगम, अम्बाला वहन करेगा। तदानुसार विभाग द्वारा दिनांक 15.02.2023 को कमिश्नर, नगर निगम, अम्बाला को विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने बारे कहा गया है ताकि इस कार्य में आगे की कार्यवाही की जा सके। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की तीन घोषणाएं नोट फिजिबल हैं, उनमें से एक ग्राम नग्गल में वॉटर ट्रीटमैंट प्लांट का निर्माण, दूसरी अम्बाला शहर में वॉटर वर्क्स के पास गैस्ट हाउस का निर्माण और तीसरी अम्बाला शहर में बस स्टैण्ड के पास रेहड़ी बाजार की स्थापना की है। अध्यक्ष महोदय, कुछ घोषणाओं का बजट एस्टीमेट्स बढ़ गया है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा हुआ है कि जितने और ज्यादा रूपयों की आवश्यकता पड़ेगी वे उपलब्ध करवा देंगे।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

विज्ञापन शुल्कों से संबधित ब्यौरा

38. **श्री राकेश दौलताबाद:** क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे कि :-

(क) विज्ञापन **शुल्कों** तथा प्रभारों की श्रेणी में आज तक नगर निगम, गुरूग्राम की वसूली योग्य कुल राषि कितनी है;

(ख) नगर निगम गुरूग्राम में सभी विज्ञापन स्थानों, प्रत्येक स्थान के पते तथा प्रत्येक स्थान के **शुल्कों** तथा प्रभारों का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ग) उन इकाईयों का ब्यौरा क्या है जिनकी और नगर निगम, गुरूग्राम द्वारा विज्ञापन **शुल्कों** तथा प्रभारों के संबंध में की वसूली लंबित है;

(घ) नगर निगम गुरूग्राम द्वारा विज्ञापन **शुल्कों** तथा प्रभारों की वसूली लंबित होने के कारण क्या है;

(ङ) वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 से आज तक के लिए विज्ञापन **शुल्कों** तथा प्रभारों की श्रेणी में नगर निगम गुरूग्राम का वास्तविक **वार्षिक** राजस्व क्या है;

(च) क्या नगर निगम गुरूग्राम ने कोई अग्रिम, पूर्व अदायगी की कार्यप्रणाली या कोई अन्य सुदृढ़ अदायगी अवसंरचना वर्तमान तथा भविश्य के विज्ञापन अनुबंधो के लिए लागू की गई या की जानी प्रस्तावित है?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (**डॉ० कमल गुप्ता**) : श्री मान जी,

(क) नगर निगम, गुरूग्राम (एमसीजी) के पास उपलब्ध जानकारी अनुसार विज्ञापन शुल्क और शुल्क की श्रेणी में अब तक की कुल वसूली योग्य राशि 321.433 करोड़ रूपये है।

(ख) नगर निगम, गुरूग्राम क्षेत्र में सभी विज्ञापन स्थानों की विस्तृत सूची, प्रत्येक स्थान के सटीक स्थान और पते के साथ-साथ प्रत्येक स्थान की फीस और शुल्क अनुबंध-I पर है।

(ग) उन संस्थाओं का विवरण जिनसे वसूली शुरू की जानी है, अनुबंध-II में है।

(घ) प्रत्येक लंबित विज्ञापन शुल्क के कारणों का उल्लेख अनुबंध-II की सूची में किया गया है।

(ङ) विज्ञापन शुल्क से नगर निगम गुरूग्राम का वर्षवार वार्षिक राजस्व नीचे दिया गया है: -

क्रम संख्या	**वितिय वर्ष**	**नगर निगम गुरूग्राम का वर्षवार वास्तविक वार्षिक राजस्व (करोड़ों में)**
1	2019-20	15.45
2	2020-21	9.44
3	2021-22	14.65
4	2022-23	17.50 अब तक

(च) सरकार ने हरियाणा नगर निगम विज्ञापन उपनियम 2022 को अधिसूचित किया है और विज्ञापन अनुमति/अधिकार प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया है जिसके द्वारा नगर निगम गुरूग्राम और अन्य सरकारी विभाग की सभी साइट केवल खुली ई-नीलामी के माध्यम से दी जा सकती है। इसके अलावा, भुगतान में चूक को रोकने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

क) आवेदक को सभी तिमाही भुगतान अग्रिम रूप से करने होंगे।

ख) आवेदक को अनुमति के समय तिमाही भुगतान के समतुल्य जमानत राशि जमा करनी होगी, भुगतान में चूक की स्थिति में जमानत राशि से अनुमति फीस काटी जाएगी।

ग) जमानत राशि के अनुमति फीस होने पर अनुमति स्वतः निरस्त हो जाएगी।

अनुबंध-I

हरियाणा नगर निगम विज्ञापन उपनियम *2018* के तहत वैध अनुमति

क्रम संख्या	ओएमडी संख्या	एजेंसी	जगह	शुल्क (रुपये में) प्रति माह
1	485	आदित्य बिड़ला फैशन	ओमेक्स सेलिब्रेशन मॉल	3283234
2	503	आदित्य बिड़ला फैशन	ड्रीम्ज मॉल	4182626
3	909	आदित्य बिड़ला फैशन	एम्बिएंस मॉल, एम्बिएंस आइलैंड, डीएलएफ फेज 3, सेक्टर 24, गुरुग्राम, दिल्ली 122010, भारत	2066805
4	498-499	एडग्रोथ मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	नेक्सा, सेक्टर 48, गुरुग्राम	1927670
5	500	एडग्रोथ मीडिया	अगस्ता प्वाइंट गोल्फ कोर्स रोड	1216600
6	565-566	एडग्रोथ मीडिया	श्री श्याम फर्निचर मार्केट सेक्टर 24, गुरुग्राम	1553026
7	623	एडग्रोथ मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	डीएलएफ फेज 2 सेक्टर 25	2120948
8	992	एडग्रोथ मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	एफ3पीवी+क्यूडब्लयूजे, यू ब्लॉक, नाथूपुर, सेक्टर 24, गुरुग्राम, हरियाणा 122022, भारत	3931068
9	1080	एडग्रोथ मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	1002, हैमिल्टन सीटी रोड, डीएलएफ सिटी IV, सेक्टर 28, गुरुग्राम, हरियाणा 122009, भारत	2641147
10	1089	एडग्रोथ मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	117 चोधरी जल आपूर्ति के पास, विश्वकर्मा रोड, ब्लॉक एन, डीएलएफ सिटी फेस 2 गुरुग्राम 122002	5392828
11	963	एडिडास	डीएलएफ साइबर हब, शॉप नंबर-यूजीएफ /ए, यूनिट 2डी, ग्राउंड फ्लोर, गुड़गांव -122002	92151
12	960	एकेजेएस एंटरप्राइजेज	203-208, डीएलएफ गैलेरिया रोड, एयरटेल स्टोर के पास, गैलेरिया मार्केट, डीएलएफ चरण IV, सेक्टर 28, गुरुग्राम, हरियाणा 122009, भारत	4662431

13	1104	एकेजेएस एंटरप्राइजेज	सेवा कॉर्पोरेट, डीएलएफ फेस 2, सेक्टर 25, गुरुग्राम, हरियाणा 122022, भारत	6102084
14	858	आउटडोर प्राइवेट लिमिटेड के बारे में	आउटडोर प्राइवेट लिमिटेड के बारे में	716380
15	990	आउटडोर प्राइवेट लिमिटेड के बारे में	एरिक्सन बिल्डिंग, डीएलएफ साइबरसिटी, सेक्टर 25, डीएलएफ साइबर सिटी, डीएलएफ फेस 2, डीएलएफ साइबर ग्रीन, गुरुग्राम, हरियाणा 122002, भारत	15336
16	1031	आउटडोर प्राइवेट लिमिटेड के बारे में	साइबर सिटी टॉवर ए, डीएलएफ टॉवर 8 वीं रोड, डीएलएफ साइबर सिटी, डीएलएफ फेस 2, सेक्टर 24, गुरुग्राम, हरियाणा 122002, भारत	2162619
17	1034	आउटडोर प्राइवेट लिमिटेड के बारे में	21, डीएलएफ टॉवर 10वीं रोड, डीएलएफ साइबर सिटी, डीएलएफ फेज 2, सेक्टर 24, गुरुग्राम, हरियाणा 122022, भारत	77903
18	1035	आउटडोर प्राइवेट लिमिटेड के बारे में	8बी, बिल्डिंग 6, डीएलएफ साइबर सिटी आरडी, डीएलएफ साइबर सिटी, डीएलएफ फेज 3, सेक्टर 24, गुरुग्राम, हरियाणा 122010, भारत	52725
19	1036	आउटडोर प्राइवेट लिमिटेड के बारे में	8बी, बिल्डिंग 6, डीएलएफ साइबर सिटी आरडी, डीएलएफ साइबर सिटी, डीएलएफ फेज 3, सेक्टर 24, गुरुग्राम, हरियाणा 122010, भारत	726709
20	1038	आउटडोर प्राइवेट लिमिटेड के बारे में	8-ए, डीएलएफ साइबर सिटी, डीएलएफ चरण 3, सेक्टर 24, गुरुग्राम, हरियाणा 122010, भारत	170490
21	1060	आउटडोर प्राइवेट लिमिटेड के बारे में	गुड़गांव फरीदाबाद टोल प्लाजा	2607696
22		आउटडोर प्राइवेट लिमिटेड के बारे में	गुड़गांव फरीदाबाद टोल प्लाजा	2607696
23		आउटडोर प्राइवेट लिमिटेड के बारे में	फरीदाबाद गुड़गांव टोल प्लाजा	2607696
24		आउटडोर प्राइवेट लिमिटेड के बारे में	फरीदाबाद गुड़गांव टोल प्लाजा	2607696
25		आउटडोर प्राइवेट लिमिटेड के बारे में(8800398420)	लेबर चौक फेज 1 के बाद	2607696

26		आउटडोर प्राइवेट लिमिटेड के बारे में(8800398420)	लेबर चौक के बाद	2607696
27		आउटडोर प्राइवेट लिमिटेड के बारे में(8800398420)	लेबर चौक के बाद	2607696
28		आउटडोर प्राइवेट लिमिटेड के बारे में(8800398420)	चरण 1 लाल बत्ती	2607696
29		आउटडोर प्राइवेट लिमिटेड के बारे में(8800398420)	खुशबू चौक	2607696
30		आउटडोर प्राइवेट लिमिटेड के बारे मे(8800398420)	खुशबू चौक	2607696
31		आउटडोर प्राइवेट लिमिटेड के बारे में(8800398420)	खुशबू चौक के पास	2607696
32		आउटडोर प्राइवेट लिमिटेड के बारे में(8800398420)	खुशबू चौक के पास	2607696
33		आउटडोर प्राइवेट लिमिटेड के बारे में (8800398420)	ग्वाल पहाड़ी सनसेट पॉइंट	2607696
34		आउटडोर प्राइवेट लिमिटेड के बारे में (8800398420)	ऊपर पारस चौकड़ी	2607696
35		आउटडोर प्राइवेट लिमिटेड के बारे में (8800398420)	खुशबू चौक के बाद	2607696
36		आउटडोर प्राइवेट लिमिटेड के बारे में (8800398420)	खुशबू चौक के बाद	2607696
37		आउटडोर प्राइवेट लिमिटेड के बारे में (8800398420)	खुशबू चौक के बाद	2607696
38		आउटडोर प्राइवेट लिमिटेड के बारे में (8800398420)	खुशबू चौक के बाद	2607696
39		आउटडोर प्राइवेट लिमिटेड के बारे में (8800398420)	खुशबू चौक के बाद	2607696
40		आउटडोर प्राइवेट लिमिटेड के बारे में (8800398420)	घाट चौक के बाद	2607696

41		आउटडोर प्राइवेट लिमिटेड के बारे में (8800398420)	घाट चौक के बाद	2607696
42		आउटडोर प्राइवेट लिमिटेड के बारे में (8800398420)	घाट चौक के बाद	2607696
43		आउटडोर प्राइवेट लिमिटेड के बारे में (8800398420)	उत्साही तेरी	2607696
44	928	अमेय कमर्शियल प्रोजेक्ट्स प्रा. लिमिटेड (9911938383)	सी3एचएफ+जेवीएम, ब्लॉक एच, सेक्टर 57, गुरुग्राम, हरियाणा 122003, भारत	1470729
45	768	ब्लूमून रिटेल प्रा. लिमिटेड (9818389858)	295/1/2, अनामिका एन्क्लेव, सेक्टर-14, गुरुग्राम	302750
46	785	कनॉट प्लाजा रेस्तरां	सेक्टर 29 गुरुग्राम	63053
47	786	कनॉट प्लाजा रेस्तरां	सेक्टर 29 गुरुग्राम	63053
48	823	कनॉट प्लाजा रेस्तरां	डीएलएफ साइबर हब।	236473
49	824	कनॉट प्लाजा रेस्तरां	डीएलएफ साइबर हब।	236473
50	826	कनॉट प्लाजा रेस्तरां	डीएलएफ साइबर हब।	236473
51	827	कनॉट प्लाजा रेस्तरां	डीएलएफ साइबर हब।	236473
52	600	देखभाल स्वास्थ्य बीमा	विपुल टेक स्क्वायर गोल्फ कोर्स रोड	353663
53	937	क्रॉसवर्ड बुकस्टोर लिमिटेड	10 डीएलएफ साइबर सिटी, डीएलएफ फेज 2, सेक्टर 24, गुरुग्राम	89479
54	744	डेकाथलॉन स्पोर्ट्स इंडिया प्रा0 लिमिटेड (9654247699)	सुभाष चौक सेक्टर 48	778745
55	745.46	डेकाथलॉन स्पोर्ट्स इंडिया प्रा0 लिमिटेड (9654247699)	8-बी, ग्राउंड फ्लोर 5, टावर बी शॉपिंग मॉल फेज-प्/746, एलईडी, टावर-बी, शॉपिंग मॉल डीएलएफ फेज-I	322249
56	837	डेकाथलॉन स्पोर्ट्स इंडिया प्रा0 लिमिटेड (9654247699)	यूनिट 8-बी, जीएफ-5, बिल्डिंग 8 टावर-बी, शॉपिंग मॉल, डीएलएफ फेज-1, गुरुग्राम	1016504
57	711	ईआईएच लिमिटेड	साइबर हब भूतल पार्किंग	343505
58	717	ईआईएच लिमिटेड	साइबर हब भूतल पार्किंग	515457
59	727	ईआईएच लिमिटेड	साइबर हब भूतल पार्किंग	142953
60	585	एक्सपाईडेट हेल्थकेयर	उद्योग विहार फेज 3	687854
61	965	एक्सप्रेस हाउसकीपर प्राइवेट लिमिटेड (7840006434)	ग्लोबल फोयर, गोल्फ कोर्स रोड, सेक्टर 43, गुरुग्राम, हरियाणा 122002, भारत	575752

62	894	फेयरपोर्टल इंडिया प्रा. लिमिटेड (9810500683)	विपुल टेक स्क्वायर, गोल्फ कोर्स रोड, सेक्टर 42, गुरुग्राम	670606
63	788	फ़ुटेक डिजिटल	एंबियंस मॉल	241984
64	966	फ़ुटेक डिजिटल	एम्बिएंस मॉल, एम्बिएंस आइलैंड, डीएलएफ फेज 3, सेक्टर 24, गुरुग्राम, दिल्ली 122010, भारत	1124524
65	666	जीआईआईआर संचार	एंबियंस मॉल	1012377
66	1023	जीआईआईआर कम्युनिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (9818983311)	209ए, एंबियंस आइलैंड, डीएलएफ फेज 3, एंबियंस मॉल, गुरुग्राम, हरियाणा 122002, भारत	882432
67	993	गो लाईव (9650881111)	मोनिका नुरेसारी नाथूपुर	789384
68	1098	गो लाईव (9650881111)	दि वेयरहाउस, नियर एंबिएंस आइलैंड, डीएलएफ फेज 3, सेक्टर 24, गुरुग्राम, हरियाणा 122010	830931
69	857	गोदराज एंड बॉयस एमएफजी कंपनी लिमिटेड	जेएमडी आर्केड मॉल, ए-ब्लॉक, डीएलएफ फेज-1, सेक्टर- 28, गुरुग्राम	610296
70	36	हाईट प्रमोशन	गैलेरीया बाजार	1700800
71	36	हाईट प्रमोशन	गैलेरीया बाजार	1700800
72	962	हाईट प्रमोशन कंपनी (9810470007)	डीएलएफ फेज 4	2083886
73	812	हाई ईम्प्रेशन	एनएच8 चोपड़ा स्टील	619085
74	1113	हाई ईम्प्रेशन (9811022202)	बेस्टेक बिजनेस टावर के पास, वाटिका टावर के पास, सोहना रोड, सेक्टर-48, गुरुग्राम	1578758
75	954	हाउस अॉफ ब्यूटी प्राइवेट लिमिटेड	56, एंबियंस आइलैंड, डीएलएफ चरण 3, सेक्टर 24, गुरुग्राम, दिल्ली 122002, भारत	415815
76	651	हुंडई मोटर्स	एनएच 8 गुरुग्राम	2757649
77	567	लैकस इन्टेग्रेटड	साइबर हब	14329539
78	667	लैकस इन्टेग्रेटड	डीएलएफ साइबर हब	1735633
79	735	लैकस इन्टेग्रेटड	होराइजन सेंटर गुरुग्राम	8601197
80	747	लैकस इन्टेग्रेटड	एंबियंस मॉल	1765094
81	748	लैकस इन्टेग्रेटड	आरके फोर स्क्वायर	9683874
82	749	लैकस इन्टेग्रेटड	आरके फोर स्क्वायर	9683874
83	750	लैकस इन्टेग्रेटड	आरके फोर स्क्वायर	9683874
84	751	लैकस इन्टेग्रेटड	बिल्डिंग नंबर 9बी साइबर हब	6486284

85	752	लैकस इन्टेग्रेटड	डीएलएफ साइबर हब	1627829
86	791	लैकस इन्टेग्रेटड	बिल्डिंग नंबर 5 के पास, साइबर हब	15885849
87	792	लैकस इन्टेग्रेटड	हम फोरम बिल्डिंग का काम करते हैं	15885849
88	793	लैकस इन्टेग्रेटड	हम फोरम बिल्डिंग का काम करते हैं	15885849
89	794	लैकस इन्टेग्रेटड	गेटवे टॉवर	15885849
90	795	लैकस इन्टेग्रेटड	गेटवे टॉवर	15885849
91	796	लैकस इन्टेग्रेटड	डाउनटाउन मॉल	15885849
92	797	लैकस इन्टेग्रेटड	इंडसइंड बैंक मेट्रो स्टेशन	15885849
93	798	लैकस इन्टेग्रेटड	साइबर हब भूतल पार्किंग	15885849
94	799	लैकस इन्टेग्रेटड	साइबर हब भूतल पार्किंग	15885849
95	863	लैकस इन्टेग्रेटड	एंबियंस मॉल गुरुग्राम	6089735
96	864	लैकस इन्टेग्रेटड	एंबियंस मॉल गुरुग्राम	1873038
97	865	लैकस इन्टेग्रेटड	एंबियंस मॉल गुरुग्राम	1779751
98	886	लैकस इन्टेग्रेटड	डीएलएफ साइबर हब।	2691420
99	887	लैकस इन्टेग्रेटड	डीएलएफ साइबर हब।	220239
100	932	लैकस इन्टेग्रेटड	एम्बिएंस मॉल, एम्बिएंस आइलैंड, डीएलएफ फेज 3, सेक्टर 24, गुरुग्राम, दिल्ली 122010, भारत	1786912
101	1116	लैकस इंटिग्रेटेड	एफ3एकसडब्लयू + जीपी, डीएलएफ फेज-3, सेक्टर-24, गुरुग्राम	14338096
102	1118	लैकस इंटिग्रेटेड	डाउन टाउन, डीएलएफ फेज 3, सेक्टर 24, गुरुग्राम	1823781
103	991	लेमन ट्री लैंड एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	टाटा लाविडा, जी2एम9 + वीएच7, सेक्टर 113, बजघेरा, गुरुग्राम, दिल्ली 122017, भारत	1816259
104	903	मार्क एंड स्पेंसर	आरडी मॉल सेक्टर 52	863649
105	919	मार्क एंड स्पेंसर	टावर-ए, डीएलएफ सिटी फेज 2, गुरुग्राम	118099
106	920	मार्क एंड स्पेंसर	एयरिया मॉल बादशाहपुर	91538
107	930	मार्क एंड स्पेंसर	एम्बिएंस मॉल, एम्बिएंस आइलैंड, डीएलएफ फेज 3, सेक्टर 24, गुरुग्राम, दिल्ली 122010, भारत	308450
108	931	मार्क एंड स्पेंसर	गैलेरिया मार्केट	20411
109	684	मैक्स मीडिया	वाटिका चौक के पास	2630350
110	733	मैक्स मीडिया	वाटिका चौक गुरुग्राम।	804184
111	878	मीडिया जंक्शन	इफको चौक गुरुग्राम	621678
112	964	मीडिया जंक्शन (9910004448)	मेट्रो स्तंभ संख्या 180 के पिछे, वाटिका टॉवर के पास रैपिड मेट्रो, गोल्फ कोर्स	667831

			रोड, सनसिटी, सेक्टर 54, गुरुग्राम, हरियाणा 122002, भारत	
113	971	मीडिया जंक्शन (9910004448)	1442, दिल्ली - जयपुर एक्सपाइ, ब्लॉक सी, सुखराली, सेक्टर 17, गुरुग्राम, हरियाणा 122022, भारत	662411
114	1015	मीडिया जंक्शन (9910004448)	सी33वी +5एमएफ, बहरामपुर नया, सेक्टर 61, गुरुग्राम, हरियाणा 122102, भारत	667718
115	1016	मीडिया जंक्शन (9910004448)	93एक्सएफ+4पी8, सेक्टर 65, गुरुग्राम, हरियाणा 122102, भारत	667718
116	1019	मीडिया जंक्शन (9910004448)	एम62-ए, अदानी सम्सारा, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, होटल लेमन ट्री के पास, सेक्टर 60, गुरुग्राम, हरियाणा 122001, भारत	667718
117	1021	मीडिया जंक्शन (9910004448)	पुलिस स्टेशन सेक्टर- 65 कट (पिकअप), बहरामपुर नया, सेक्टर 61, गुरुग्राम, हरियाणा 122102, भारत	667718
118	1022	मीडिया जंक्शन (9910004448)	सी2जे5+एकस4जी, ब्लॉक बी, सेक्टर 34, गुरुग्राम, हरियाणा 122001, भारत	667718
119	755	एमजी ग्रुप की कंपनियां	इफको चौक, एबीडब्ल्यू टावर	49490432
120	1082	मिकाडो रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड (9899790205)	सी478+4एकस मिकादो रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड सैज, गांव बेहरामपुर और बलोला जिला गुरुग्राम, हरियाणा, भारत	1698663
121	888	माउंटेन वैली	डीएलएफ साइबर हब।	21044
122	889	माउंटेन वैली	डीएलएफ साइबर हब।	11871
123	890	माउंटेन वैली	डीएलएफ साइबर हब।	23849
124	891	माउंटेन वैली	डीएलएफ साइबर हब।	122173
125	910	माउंटेन वैली	एंबियंस मॉल, डीएलएफ फेज 3, सेक्टर 24, गुरुग्राम,	33154
126	911	माउंटेन वैली	एंबियंस मॉल, डीएलएफ फेज 3, सेक्टर 24, गुरुग्राम,	33154
127	912	माउंटेन वैली	एंबियंस मॉल, डीएलएफ फेज 3, सेक्टर 24, गुरुग्राम,	33154
128	913	माउंटेन वैली	एंबियंस मॉल, डीएलएफ फेज 3, सेक्टर 24, गुरुग्राम,	33154
129	914	माउंटेन वैली	एंबियंस मॉल, डीएलएफ फेज 3, सेक्टर 24, गुरुग्राम,	33154

130	915	माउंटेन वैली स्प्रिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (99685823403)	गैलेरिया शॉपिंग मॉल	19295
131	916	माउंटेन वैली स्प्रिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (99685823403)	गैलेरिया शॉपिंग मॉल	19295
132	918	माउंटेन वैली स्प्रिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (99685823403)	गैलेरिया शॉपिंग मॉल	19295
133	989	माउंटेन वैली स्प्रिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (99685823403)	शॉप नंबर - 24 ग्राउंड फ्लोर, वर्ल्डमार्क गुड़गांव, मैडवास रोड, सेक्टर - 65, गुड़गांव, हरियाणा -122001	68784
134	1109	पीपी डिजिटल इंडिया प्रा0 लिमिटेड (9829180966)	सिकंदरपुर मार्केट, एम्मार के सामने, डीएलएफ फेज-1, सेक्टर-26, गुरुग्राम	792633
135	1110	पीपी डिजिटल इंडिया प्रा0 लिमिटेड (9829180966)	सिकंदरपुर मार्केट, एम्मार के सामने, डीएलएफ फेज-1, सेक्टर-26, गुरुग्राम	792633
136	740	पीपी डिजिटल	विपुल टेक सीक्वेर गोल्फ कोर्स रोड	3515897
137	741	पीपी डिजिटल	विपुल टेक सीक्वेर गोल्फ कोर्स रोड	
138	765	पीपी डिजिटल इंडिया प्रा0 लिमिटेड (9829180966)	विपुल अगोरा मॉल एनएच 148 ए ।	1779750
139	830	पीपी डिजिटल इंडिया प्रा0 लिमिटेड (9829180966)	एचआर 26 ढाबा सोहना रोड	1779386
140	885	पीपी डिजिटल इंडिया प्रा0 लिमिटेड (9829180966)	एंबियंस मॉल गुरुग्राम	183986
141	925	पीपी डिजिटल इंडिया प्रा0 लिमिटेड (9829180966)	एमजी रोड डीएलएफ फेज 1 गुरुग्राम	1801229
142	927	पीपी डिजिटल इंडिया प्रा0 लिमिटेड (9829180966)	जेएमडी गैलेरिया, सोहना रोड, गुरुग्राम	1793770
143	977	पीपी डिजिटल इंडिया प्रा0 लिमिटेड (9829180966)	201, दूसरी मंजिल डीएलएफ ग्रैंड मॉल, महरौली-गुड़गांव रोड, ए ब्लॉक,	1800892

			डीएलएफ फेज 1, सेक्टर 28, गुरुग्राम, हरियाणा 122002, भारत	
144	1002	पीपी डिजिटल इंडिया प्रा0 लिमिटेड (9829180966)	जेएमडी मेगापोलिस, सेक्टर 48, सोहना रोड, गुरुग्राम, हरियाणा	1903949
145	1119	पीपी डिजिटल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	खसरा नंबर 155-156/3, नाथूपुर, डीएलएफ फेज 2, सेक्टर 25, गुरुग्राम	834350
146	1120	पीपी डिजिटल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	खसरा नंबर 155-156/3, नाथूपुर, डीएलएफ फेज 2, सेक्टर 25	1927900
147	1139	पीपी डिजिटल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	ग्लोबल फोयर के पास, गोल्फ कोर्स रोड, सेक्टर-43,	1935595
148	1140	पीपी डिजिटल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	ग्लोबल फोयर के पास, गोल्फ कोर्स रोड, सेक्टर-43,	1935595
149	956	एम/एस प्यूमा स्पोर्ट्स	डीएलएफ साइबर हब, शॉप नंबर-यूजीएफ /ए, यूनिट 2डी, ग्राउंड फ्लोर, गुड़गांव -122002	365738
150	976	रेडियंस विज्ञापन (9811094568)	एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन मॉल, डीएलएफ सिटी फेज IIमहरौली-गुड़गांव रोड, हेरिटेज सिटी, सेक्टर 25, गुरुग्राम, हरियाणा 122002, भारत	150909
151	728	आर एस विज्ञापन एजेंसी	एंबियंस मॉल	3855365
152	731	आर एस विज्ञापन एजेंसी	एंबियंस मॉल	3855365
153	613	साईं मीडिया	साइबर सिटी गुरुग्राम	
154	702	एसबीडी ग्रीन एनर्जी	व्यापर केंद्र गुरुग्राम	341818
155	1093	एसबीडी ग्रीन एनर्जी एंड इंफ्रा इंडिया प्रा0 लिमिटेड (9599088510)	5832, मचान के पास, वाइन शॉप और इंडियन अॉयल फ्यूल स्टेशन, अपोजिट। व्यापार केंद्र बाजार, व्यापार केंद्र रोड, गुरुग्राम, हरियाणा 122009, भारत	2122892
156	1094	एसबीडी ग्रीन एनर्जी एंड इंफ्रा इंडिया प्रा0 लिमिटेड (9599088510)	एफ39पी+5जीएच, वीपीओ 13, चकरपुर, हेमिल्टन कोर्ट के सामने, डीएलएफ फेज IV, गुरुग्राम, हरियाणा 122022, भारत	2122892
157	452	श्लोरवे मीडिया	सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के बगल में एमजी रोड	2019955
158	615	श्लोरवे मीडिया	यूनीपोल गुरुद्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन	2344212
159	647	श्लोरवे मीडिया	सेक्टर 29 गुरुग्राम	1794067

160	1088	श्लोरवे मीडिया (9818148090)	एसबी मार्केट, सिकंदरपुर, गुरुग्राम-122002 (हरियाणा)	1648223
161	1107	श्री श्याम आइस पब्लिसिटी (9910004448)	गोदरेज 106, द्वारका एक्सपायरी, बाबूपुर गांव, गुरुग्राम, हरियाणा 122002, भारत	639397
162	852-849	स्केचर्स साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड	आर्केड 48 रहेजा मॉल सोहना रोड गुरुग्राम के पास	738205
163	1083	स्मार्ट इवेंट्स (9711450416)	-	29172
164	1108	सोशल टॉक	खसरा नंबर 5/1 मैदावास सेक्टर 63	676155
165	872	सेन्को गोल्ड लिमिटेड (7605004761)	एफएफ-102, जेएमडी रीजेंट आर्केड मॉल, ए-ब्लॉक, डीएलएफ फेज-1, सेक्टर-28, गुरुग्राम	1206989
166	951	सेन्को गोल्ड लिमिटेड (7605004761)	गोल्ड सूक, सेक्टर 43 गुड़गांव, हरियाणा, व्यापार केंद्र रोड, ब्लॉक सी, सुशांत लोक चरण I, सेक्टर 43, गुरुग्राम, हरियाणा 122003, भारत	52733
167	1046	शरद गोयल (9899000005)	420, वीरेंद्र ग्राम के पास, सिकंदरपुर घोसी, गुरुग्राम, दिल्ली 122002, भारत	637076
168	1029	मैसर्स एसआईएस लिमिटेड (सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड) (9811667296)	72, चरण IV, उद्योग विहार, सेक्टर 18, गुरुग्राम, हरियाणा 122002, भारत	307139
169	1026	सुपर मार्ट (9990480120)	13 से 30, स्पैजेज, ग्राउंड फ्लोर, टावर-बी, सोहना एक्सप्रेसवे, सेक्टर-47, बादशाहपुर, गुरुग्राम, हरियाणा-122018	100844
170	1066	टाटा स्टारबक्स प्राइवेट लिमिटेड (9711505115)	जी 27, एंबियंस मॉल, एनएच8, गुरुग्राम, हरियाणा - 122002	21535
171	1068	टाटा स्टारबक्स प्राइवेट लिमिटेड (9711505115)	स्टारबक्स यूनिट नंबर 028, ग्राउंड फ्लोर, वर्ल्डमार्क सेक्टर 65, गुरुग्राम, हरियाणा - 122018	51681
172	734	टेन सीक्योर मीडिया	13 सेक्टर 42, गुरुग्राम	1927682
173	781	टेन सीक्योर मीडिया	55-56, एमजी रोड डीएलएफ फेज 3, सेक्टर 24 गुरुग्राम	1850472
174	829	टेन स्क्वायर मीडिया एंड प्रोडक्शन प्रा0 लिमिटेड	गोल्फ कोर्स रोड सन सिटी सेक्टर 54	1857994

		(9808908989)		
175	883	टेन स्क्वायर मीडिया एंड प्रोडक्शन प्रा0 लिमिटेड (9808908989)	11, क्यू-2, डीएलएफ सिटी फेज-II, सेक्टर-25, गुरुग्राम	1801223
176	884	टेन स्क्वायर मीडिया एंड प्रोडक्शन प्रा0 लिमिटेड (9808908989)	जेएमडी रीजेंट प्लाजा एमजी रोड	1873038
177	622	ट्रेंट लिमिटेड	सेक्टर 29 और 68 आरिया मॉल गुरुग्राम	3415041
178	650	टेन स्क्वायर मीडिया एंड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड 9808908989		1786907
179	668	टेन स्क्वायर मीडिया एंड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड 9808908989	दुकान नंबर 02 ब्रिस्टल होटल के पास	1927682
180	680	टेन स्क्वायर मीडिया एंड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड 9808908989	आरिया मॉल सेक्टर 68	870050
181	933	टेन स्क्वायर मीडिया एंड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड 9808908989	मेट्रो पिलर नंबर 60 एमजी रोड के पास	820650
182	1111	टेन स्क्वायर मीडिया एंड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड 9808908989	प्लॉट नंबर 05, बिल्डिंग नंबर 05 के सामने, सेक्टर रोड, चौधरी मार्केट, डीएलएफ फेज-III, नाथूपुर, सेक्टर- 24, गुरुग्राम	1943510
183	1071	टेन स्क्वायर मीडिया एंड प्रोडक्शन प्रा. लिमिटेड (9808908989)	शॉप न- जीएच, 1, हैमिल्टन सीटी रोड, चक्करपुर, सेक्टर 28, गुरुग्राम, हरियाणा 122022, भारत	786131
184	1072	टेन स्क्वायर मीडिया एंड प्रोडक्शन प्रा. लिमिटेड (9808908989)	1002, हैमिल्टन सीटी रोड, डीएलएफ सिटी IV, सेक्टर 28, गुरुग्राम, हरियाणा 122009, भारत	786131
185	1073	टेन स्क्वायर मीडिया एंड प्रोडक्शन प्रा. लिमिटेड (9808908989)	कार्यालय संख्या- 901, गैलेरिया टॉवर, डीएलएफ चरण IV, सेक्टर 28, गुरुग्राम, हरियाणा 122009, भारत	786131
186	901	ट्यूलिप इंफ्राटेक	गोल्फ कोर्स रोड	2605680
187	922	वाटिका सॉवरेन पार्क प्रा0 लिमिटेड (9911344741)	ब्लॉक-एम, 202 वाटिका सॉवरिन पार्क, सेक्टर-99 गुरुग्राम	10288

188	923	वाटिका सॉवरेन पार्क प्रा0 लिमिटेड (9911344741)	टावर-ए, वाटिका सॉवरेजिन पार्क, सेक्टर-99, गुरुग्राम	746807
189	1074	वाईट कि कन्सलटेंट (9910004448)	सी27वी+32जे, ओमैक्स लिमिटेड, ओमैक्स सिटी सेंटर, सोहना रोड, सेक्टर 49, गुरुग्राम, हरियाणा 122018, भारत	637076
190	1075	वाईट कि कन्सलटेंट (9910004448)	ओमैक्स सेलिब्रेशन मॉल, सोहना रोड, सेक्टर 48, गुरुग्राम, हरियाणा 122001, भारत	637076
191	1076	वाईट कि कन्सलटेंट (9910004448)	राव कॉम्प्लेक्स, कॉन्सिएंट वन के पास, सेक्टर 109, गुरुग्राम, हरियाणा 122017, भारत	639713
192	1079	वाईट कि कन्सलटेंट (9910004448)	118, दिल्ली - जयपुर प्रदर्शनी, एलआईजी कॉलोनी, सेक्टर 31, गुरुग्राम, हरियाणा 122001, भारत	634439
193	670	युआव ट्रेडिंग (9650733012)	हीरो होंडा चौक	742425
194	732	युआव ट्रेडिंग (9650733012)	वाटिका सिटी, सोहना रोड, सेक्टर- 66, गुरुग्राम	789384
195	941	युआव ट्रेडिंग (9650733012)	ग्वाल पहाड़ी, गुड़गांव फरीदाबाद रोड	786131
196	1135	युआव ट्रेडिंग	यूनिवर्सल ट्रेड टॉवर, सोहना रोड, सेक्टर 49, गुड़गांव	2652000
197	884	टेन स्क्वायर मीडिया एंड प्रोडक्शन प्रा. लिमिटेड (9808908989)	जेएमडी रीजेंट प्लाजा एमजी रोड	1873038
198	622	ट्रेंट लिमिटेड	सेक्टर 29 और 68 आरिया मॉल गुरुग्राम	3415041
199	650	टेन स्क्वायर मीडिया एंड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड 9808908989		1786907
200	668	टेन स्क्वायर मीडिया एंड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड 9808908989	दुकान नंबर 02 ब्रिस्टल होटल के पास	1927682
201	680	टेन स्क्वायर मीडिया एंड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड 9808908989	आरिया मॉल सेक्टर 68	870050

202	933	टेन स्क्वायर मीडिया एंड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड 9808908989	मेट्रो पिलर नंबर 60 एमजी रोड के पास	820650
203	1111	टेन स्क्वायर मीडिया एंड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड 9808908989	प्लॉट नंबर 05, बिल्डिंग नंबर 05 के सामने, सेक्टर रोड, चौधरी मार्केट, डीएलएफ फेज-III, नाथूपुर, सेक्टर- 24, गुरुग्राम	1943510
204	1071	टेन स्क्वायर मीडिया एंड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड 9808908989	शॉप न0- जीएच 1, हैमिल्टन सीटी रोड, चक्करपुर, सेक्टर 28, गुरुग्राम, हरियाणा 122022, भारत	786131
205	1072	टेन स्क्वायर मीडिया एंड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड 9808908989	1002, हैमिल्टन सीटी रोड, डीएलएफ सिटी IV, सेक्टर 28, गुरुग्राम, हरियाणा 122009, भारत	786131
206	1073	टेन स्क्वायर मीडिया एंड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड 9808908989	कार्यालय संख्या- 901, गैलेरिया टॉवर, डीएलएफ चरण IV, सेक्टर 28, गुरुग्राम, हरियाणा 122009, भारत	786131
207	901	ट्यूलिप इंफ्राटेक	गोल्फ कोर्स रोड	2605680
208	922	वाटिका सॉवरेन पार्क प्रा0 लिमिटेड (9911344741)	ब्लॉक-एम, 202 वाटिका सॉवरिन पार्क, सेक्टर-99 गुरुग्राम	10288
209	923	वाटिका सॉवरेन पार्क प्रा0 लिमिटेड (9911344741)	टावर-ए, वाटिका सॉवरेजिन पार्क, सेक्टर-99, गुरुग्राम	746807
210	1074	वाईट कि कन्सलटेंट (9910004448)	सी27वी+32जे, ओमैक्स लिमिटेड, ओमैक्स सिटी सेंटर, सोहना रोड, सेक्टर 49, गुरुग्राम, हरियाणा 122018, भारत	637076
211	1075	वाईट कि कन्सलटेंट (9910004448)	ओमैक्स सेलिब्रेशन मॉल, सोहना रोड, सेक्टर 48, गुरुग्राम, हरियाणा 122001, भारत	637076
212	1076	वाईट कि कन्सलटेंट (9910004448)	राव कॉम्प्लेक्स, कॉन्सिएंट वन के पास, सेक्टर 109, गुरुग्राम, हरियाणा 122017, भारत	639713
213	1079	वाईट कि कन्सलटेंट (9910004448)	118, दिल्ली - जयपुर प्रदर्शनी, एलआईजी कॉलोनी, सेक्टर 31, गुरुग्राम, हरियाणा 122001, भारत	634439
214	670	युआव ट्रेडिंग	हीरो होंडा चौक	742425
215	732	युआव ट्रेडिंग (9650733012)	वाटिका सिटी, सोहना रोड, सेक्टर- 66, गुरुग्राम	789384

216	941	युआव ट्रेडिंग (9650733012)	ग्वाल पहाड़ी, गुड़गांव फरीदाबाद रोड	786131
217	1135	युआव ट्रेडिंग	यूनिवर्सल ट्रेड टॉवर, सोहना रोड, सेक्टर 49, गुड़गांव	2652000
218	668	टेन स्क्वायर मीडिया एंड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड 9808908989	दुकान नंबर 02 ब्रिस्टल होटल के पास	1927682
219	680	टेन स्क्वायर मीडिया एंड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड 9808908989	आरिया मॉल सेक्टर 68	870050
220	933	टेन स्क्वायर मीडिया एंड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड 9808908989	मेट्रो पिलर नंबर 60 एमजी रोड के पास	820650
221	1111	टेन स्क्वायर मीडिया एंड प्रोडक्शन प्रा. लिमिटेड (9808908989)	प्लॉट नंबर 05, बिल्डिंग नंबर 05 के सामने, सेक्टर रोड, चौधरी मार्केट, डीएलएफ फेज-III, नाथूपुर, सेक्टर- 24, गुरुग्राम	1943510
222	1071	टेन स्क्वायर मीडिया एंड प्रोडक्शन प्रा. लिमिटेड (9808908989)	शाप न0-जीएच 1, हैमिल्टन सीटी रोड, चक्करपुर, सेक्टर 28, गुरुग्राम, हरियाणा 122022, भारत	786131
223	1072	टेन स्क्वायर मीडिया एंड प्रोडक्शन प्रा. लिमिटेड (9808908989)	1002, हैमिल्टन सीटी रोड, डीएलएफ सिटी IV, सेक्टर 28, गुरुग्राम, हरियाणा 122009, भारत	786131
224	1073	टेन स्क्वायर मीडिया एंड प्रोडक्शन प्रा. लिमिटेड (9808908989)	कार्यालय संख्या- 901, गैलेरिया टॉवर, डीएलएफ चरण IV, सेक्टर 28, गुरुग्राम, हरियाणा 122009, भारत	786131
225	901	ट्यूलिप इंफ्राटेक	गोल्फ कोर्स रोड	2605680
227	922	वाटिका सॉवरेन पार्क प्रा. लिमिटेड (9911344741)	ब्लॉक-एम, 202 वाटिका सॉवरिन पार्क, सेक्टर-99 गुरुग्राम	10288
228	923	वाटिका सॉवरेन पार्क प्रा. लिमिटेड (9911344741)	टावर-ए, वाटिका सॉवरेजिन पार्क, सेक्टर-99, गुरुग्राम	746807
229	1074	वाईट कि कन्सलटेंट (9910004448)	सी27वी+32जे, ओमैक्स लिमिटेड, ओमैक्स सिटी सेंटर, सोहना रोड, सेक्टर 49, गुरुग्राम, हरियाणा 122018, भारत	637076
230	1075	वाईट कि कन्सलटेंट (9910004448)	ओमैक्स सेलिब्रेशन मॉल, सोहना रोड, सेक्टर 48, गुरुग्राम, हरियाणा 122001, भारत	637076

231	1076	वाईट कि कन्सलटेंट (9910004448)	राव कॉम्प्लेक्स, कॉन्सिएंट वन के पास, सेक्टर 109, गुरुग्राम, हरियाणा 122017, भारत	639713
232	1079	वाईट कि कन्सलटेंट (9910004448)	118, दिल्ली - जयपुर प्रदर्शनी, एलआईजी कॉलोनी, सेक्टर 31, गुरुग्राम, हरियाणा 122001, भारत	634439
233	670	युआव ट्रेडिंग	हीरो होंडा चौक	742425
234	732	युआव ट्रेडिंग (9650733012)	वाटिका सिटी, सोहना रोड, सेक्टर- 66, गुरुग्राम	789384
235	941	युआव ट्रेडिंग (9650733012)	ग्वाल पहाड़ी, गुड़गांव फरीदाबाद रोड	786131
236	1135	युआव ट्रेडिंग	यूनिवर्सल ट्रेड टॉवर, सोहना रोड, सेक्टर 49, गुड़गांव	2652000

हरियाणा नगर निगम विज्ञापन उपनियम *2022* के तहत वैध अनुमति

क्रम संख्या	**ओएमडी संख्या**	**एजेंसी**	**जगह**	**शुल्क (रुपये में) प्रति वर्ग मीटर प्रति माह**
1	1591	इवेंटलेस डिज़ाइन्स प्राइवेट लिमिटेड	वर्ल्डमार्क सैक्टर 65	5645
2	1365	सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया लिमिटेड	सिग्नेचर टावर, टावर ए, साउथ सिटी-1, गुरुग्राम, हरियाणा- 122001	5801
3	1364	शांति इन्फोरमेटिकस	डीएलएफ साइबर पार्क, गुड़गांव	6604
4	1312	कल्याण ज्वैलर्स	दुकान नं। 15, ग्राउंड फ्लोर, गोल्डसौक मॉल, सी-ब्लॉक, सुशांत लोक 1, सेक्टर 43, गुरुग्राम	2541
5	1224	हाइट्स प्रमोशन कंपनी	डीएलएफ गैलेरिया मार्केट, फेज IVडीएलएफ फेज IV	7613
6	1223	हाइट्स प्रमोशन कंपनी	डीएलएफ गैलेरिया मार्केट, फेज IVडीएलएफ फेज I	7613
7	1199	माउंटेन वैली स्प्रिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	फॉरेस्ट एसेंशियल्स, डीएलएफ साइबरहब, यूजीएफ/बी/यूनिट 1डी, ग्राउंड फ्लोर, बिल्डिंग नंबर 10ए, डीएलएफ साइबर	3303

			सिटी, फेज 2, गुड़गांव 122002	
8	1070	डेकाथलॉन स्पोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	ग्राउंड फ्लोर, 8बी/जीएफ/3 और 8बी/जीएफ/4, बिल्डिंग 8, टावर बी, साइबरहब, डीएलएफ साइबर सिटी, डीएलएफ फेज 2, गुरुग्राम हरियाणा-122002	5801
9	1066	टाटा स्टारबक्स	ग्राउंड फ्लोर, वाटिका बिजनेस पार्क, सेक्टर 49, सोहना रोड, गुड़गांव, हरियाणा में स्थित है	5081
10	1004	शांति इन्फोरमेटिकस	साइबरहब, डीएलएफ साइबर सिटी, चरण 2, गुड़गांव 122002	6605
11	989	करोनीकलसर	मैदावास रोड, सेक्टर 65, गुरुग्राम, हरियाणा 122001	5645
12	892	तुमुल भारद्वाज	डीएलएफ गैलेरिया फेस-4 सेक्टर 28.	7613
13	891	फ्लॉक कॉलिविंग एलएलपी	ए-14/29, डीएलएफ सिटी फेज 1, गुरुग्राम	5081
14	879	फुजीफिल्म डीकेएच एलएलपी	प्लॉट नंबर 4पी, सेक्टर 43, अर्बन एस्टेट, गुरुग्राम	2541
15	873	हाइट्स प्रमोशन कंपनी	डीएलएफ गैलेरिया मार्केट, फेज IVडीएलएफ फेज IV	7614
16	870	हाइट्स प्रमोशन कंपनी	डीएलएफ गैलेरिया मार्केट, फेज IVडीएलएफ फेज IV	7614
17	869	हाइट्स प्रमोशन कंपनी	डीएलएफ गैलेरिया मार्केट, फेज IVडीएलएफ फेज IV	7614
18	846	शेफ्ता नंदा	नंबर जी-43, ग्राउंड फ्लोर, एंबियंस मॉल, एंबियंस आइलैंड, एनएच-8 गुड़गांव हरियाणा-122010	3303
19	845	शेफ्ता नंदा	नंबर जी-43, ग्राउंड फ्लोर, एंबियंस मॉल, एंबियंस आइलैंड, एनएच-8 गुड़गांव हरियाणा-122010	3303

20	782	प्यूमा स्पोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	जीएफ18-ए, विलेज मैडवास, सेक्टर 65, वर्ल्डमार्क गुरुग्राम हरियाणा	2823
21	718	प्यूमा स्पोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	स्पैज बुलेवार्ड, सेक्टर-47, सोहना रोड गुड़गांव - 122018 गुड़गांव	2541
22	679	शेफ्ता नंदा	प्लॉट नंबर 53 सेक्टर 32 इंस्टीट्यूशनल एरिया गुरुग्राम गुड़गांव	2823
23	648	जोआलुक्कास	16,17,18 ग्राउंड फ्लोर, गोल्ड सूक मॉल, सुशांत लोक, सेक्टर 43	2541
24	620	हाइट्स प्रमोशन कंपनी	डीएलएफ गैलेरिया मार्केट, फेज IVडीएलएफ फेज IV	6452
25	619	हाइट्स प्रमोशन कंपनी	डीएलएफ गैलेरिया मार्केट, फेज IVडीएलएफ फेज IV	5592
26	604	अंकुश मारवाहा	स्पेज़ बुलेवार्ड II, भूतल, बुलेवार्ड II, सेक्टर 47, सोहना रोड	2541
27	575	रीच प्रमोटर्स प्रा. लिमिटेड	सेक्टर 68, गुरुग्राम एचआर 122103	2841
28	556	हाइट्स प्रमोशन कंपनी	डीएलएफ गैलेरिया मार्केट, फेज IVडीएलएफ फेज IV	5592
29	492	हरलीन सिंह ओबेरॉय	किला नंबर 12/2। 13/1। 13/2। 14/1, सेक्टर 72, गांव फाजिलपुर झरसा, गुड़गांव	5646
30	390	हरलीन सिंह ओबेरॉय	खेत नंबर 221/274, गांव बेहरामपुर, तहसील सोहना, गुड़गांव, हरियाणा 122004	1920
31	337	डीके वेंचर	पालडा (एमसीजी के स्वामित्व वाली साइट)	12293
32	341	असटयूट मीडिया	दौलताबाद (एमसीजी के स्वामित्व वाली साइट)	19516
33	342	दीपक कुमार	दौलताबाद (एमसीजी के स्वामित्व वाली साइट)	9116
34	358	दीपक कुमार	बाबूपुर (एमसीजी के स्वामित्व वाली साइट)	21375

35	334	डीके वेंचर	झारसा (एमसीजी के स्वामित्व वाली साइट)	8201
36	339	दीपक कुमार	खेरकी माजरा (एमसीजी के स्वामित्व वाली साइट)	2663
37	340	दीपक कुमार	खेरकी माजरा (एमसीजी के स्वामित्व वाली साइट)	9863
38	344	नीरज मंगला	बायो विविधता पार्क नाथूपुर (एमसीजी के स्वामित्व वाली साइट)	18788
39	345	ऐड ग्रोथ	बायो विविधता पार्क नाथूपुर (एमसीजी के स्वामित्व वाली साइट)	20388
40	346	ऐड ग्रोथ	बायो विविधता पार्क नाथूपुर (एमसीजी के स्वामित्व वाली साइट)	20788
41	347	गो लाईव	सामने बायो विविधता पार्क नाथूपुर (एमसीजी के स्वामित्व वाली साइट)	21788
42	348	ऐड ग्रोथ	सिकंदरपुर (एमसीजी के स्वामित्व वाली साइट)	21188
43	349	गो लाईव	सामने बायो विविधता पार्क नाथूपुर (एमसीजी के स्वामित्व वाली साइट)	19388
44	338	असटयूट मीडिया	भोंडसी (एमसीजी के स्वामित्व वाली साइट)	8912
45	1216	असटयूट मीडिया	बाशापुर (एमसीजी के स्वामित्व वाली साइट)	13790
46	350	डीके वेंचर	बेगमपुर खतोला (एमसीजी के स्वामित्व वाली साइट)	21792
47	351	डीके वेंचर	बेगमपुर खतोला (एमसीजी के स्वामित्व वाली साइट)	20192
48	353	हिंदुस्तान पब्लिसिटी	बाशापुर (एमसीजी के स्वामित्व वाली साइट)	6390
49	361	ऐड ग्रोथ	उल्हावास (एमसीजी के स्वामित्व वाली साइट)	20878
50	395	एसएस उद्‌यम	उल्हावास (एमसीजी के स्वामित्व वाली साइट)	20478

51	396	ऐड ग्रोथ	उल्हावास (एमसीजी के स्वामित्व वाली साइट)	22478
52	397	डीके वेंचर	कन्हाई (एमसीजी के स्वामित्व वाली साइट)	20821
53	398	असटयूट मीडिया	बादशाहपुर (एमसीजी के स्वामित्व वाली साइट)	24190
54	399	दीपक कुमार	भोंडसी (एमसीजी के स्वामित्व वाली साइट)	5712
55	519	दक्ष	छत घाट पार्क, न्यू पालम विहार (एमसीजी के स्वामित्व वाली साइट)	4884
56	548	ऐड ग्रोथ	ज्वाला मिल पार्क, सैक्टर 22ए (एमसीजी के स्वामित्व वाली साइट)	6842
57	543	ऐड ग्रोथ	दुंदाहेड़ा बूस्टर पार्क (एमसीजी के स्वामित्व वाली साइट)	4772
58	545	नीरज मंगला	धुंधाधेरा बूस्टर पार्क (एमसीजी के स्वामित्व वाली साइट)	4872
59	549	ऐड ग्रोथ	एच के पास मकान सं. 630 सैक्टर 5 (एमसीजी के स्वामित्व वाली साइट)	6588
60	551	ऐड ग्रोथ	छठ पूजा घाट, सेक्टर 5 (एमसीजी के स्वामित्व वाली साइट)	6718
61	552	ऐड ग्रोथ	कमला नेहरू पार्क (एमसीजी के स्वामित्व वाली साइट)	4772
62	554	ऐड ग्रोथ	रोज गार्डन, सैक्टर 15 (एमसीजी के स्वामित्व वाली साइट)	18426
63	608	आल अबाउट आउटडोर	स्मृति वाटिका पार्क, सैक्टर 55 (एमसीजी के स्वामित्व वाली साइट)	26774
64	632	आल अबाउट आउटडोर	एफ 462, विनायक गुण (एमसीजी के स्वामित्व वाली साइट)	8054
65	647	दक्ष	सुभाष चोक (एमसीजी के स्वामित्व वाली साइट)	8374

66	336	ऐड ग्रोथ	खेरकी ढोला (एमसीजी के स्वामित्व वाली साइट)	2779
67	331	ऐड ग्रोथ	भादशापुर (एमसीजी के स्वामित्व वाली साइट)	3290
68	332	आल अबाउट आउटडोर	बंधवारी (एमसीजी के स्वामित्व वाली साइट)	2416
69	333	आल अबाउट आउटडोर	बलोला (एमसीजी के स्वामित्व वाली साइट)	2416
70	355	झंघू	पवालापुर खुसरो (एमसीजी के स्वामित्व वाली साइट)	9105
71	356	झंगू	पवालापुर खुसरो (एमसीजी के स्वामित्व वाली साइट)	2205
72	352	मैक्स मीडिया सर्विसेज	वाटिका कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के सामने, सिही (एमसीजी के स्वामित्व वाली साइट)	1679
73	426	मैक्स मीडिया इंडस।	सार्वजनिक शौचालय, गौशाला मैदान (2.16 वर्ग मीटर) (एमसीजी के स्वामित्व वाली साइट)	2722
74	431	मैक्स मीडिया इंडस।	सार्वजनिक शौचालय, महावीर चोक (2.16 वर्ग मीटर) (एमसीजी के स्वामित्व वाली साइट)	4772
75	434	एसएस उद्यम	सार्वजनिक शौचालय राजीव चोक (2.16 वर्ग मीटर) (एमसीजी के स्वामित्व वाली साइट)	13972

अनुबंध-*II*

क्रम सं.	एजेंसी का नाम	देय राशि (रुपए करोड़ में)	वसूली
1	मैसर्स स्काईकॉम	32.04	सीडब्ल्यूपी 15216 आफ 2018 में मुकदमेबाजी के तहत मैसस एसोसिएशन अॉफ गुड़गांव आउटडोर विज्ञापनदाता बनाम हरियाणा राज्य और जुड़े मामले सीडब्ल्यूपी 30480/2018, सीडब्ल्यूपी 3761/2019, सीडब्ल्यूपी 37690/2019। **<u>संक्षिप्त</u>** याचिकाकर्ताओं ने उक्त सीडब्ल्यूपी में हरियाणा नगर निगम विज्ञापन उपनियम 2018 को चुनौती दी है। 2018 के सीडब्ल्यूपी नंबर 15216 में दिनांक 04.06.2018 के आदेश के तहत, माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ वसूली की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। 2018 की सीडब्ल्यूपी संख्या 30480, 2019 की सीडब्ल्यूपी संख्या 3761 और 2019 की सीडब्ल्यूपी संख्या 37690 को 2018 की सीडब्ल्यूपी संख्या 15216 के साथ जोड़ा गया है।
	मैसर्स स्काईएड्स डिजिटल	0.12	
	मैसर्स कुशा विज्ञापन	0.61	
	मैसर्स टाइकून	10.95	
	मैसर्सएमजीएफ इवेंट्स	7.02	
2	रैपिड मेट्रो रेल गुरुग्राम लिमिटेड	180.00	सीडब्ल्यूपी 1870/2015 में मुकदमेबाजी के तहत मैसर्स रैपिड मेट्रो बनाम हरियाणा राज्य और अन्य। **<u>संक्षिप्त</u>** एचएसवीपी और रैपिड मेट्रो के बीच समझौता दिनांक 09.12.2009 के समझौते के तहत बीओटी आधार पर निष्पादित किया गया है। वीडी क्लॉज नं 7.1.1 ऐसे समझौते का जिसे एचएसवीपी ने कानून के अनुसार अनुमति और एनओसी लेने के अधीन मैसर्स रैपिड मेट्रो को विज्ञापन के अधिकार दिए हैं। एचएसवीपी ने अनुमति शुल्क से छूट के लिए हरियाणा सरकार से अनुरोध किया। माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर आयोजित एक बैठक

			जिसमें माननीय मुख्य मंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया है कि एसीएस, यूएलबी रैपिड मेट्रो के विज्ञापन शुल्क से छूट प्रदान करते हुए तदानुसार विज्ञापन के लिए नीति में संशोधन करेगा। बैठक की कार्यवाही दिनांक 11.03.2013। इसके बाद ऐसे प्रस्ताव के आधार पर नगर निगम गुरूग्राम ने मैसर्स रैपिड मेट्रो को पत्र दिनांक 24.10.2013 द्वारा अनुमति प्रदान की है। माननीय ए.सी.एस, यूएलबी ने पत्र पीएस/पीएसयूएलबी/2014/1339 दिनांक 24.12.2014 के माध्यम से नगर निगम, गुरुग्राम को कारण बताओ नोटिस जारी किया है; एचएसवीपी और मैसर्स रैपिड मेट्रो यह बताएं कि एमसीजी द्वारा जारी अनुमति वापस क्यों नहीं ली जाती है और रुपये का जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाता है। मैसर्स रैपिड मेट्रो के खिलाफ हर साल 30 करोड़ रुपये नहीं लगाए जाएं। मैसर्स रैपिड मेट्रो ने 2015 के सीडब्ल्यूपी 1870 के माध्यम से उक्त कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी है। मामले में अगली सुनवाई तारीख 27.09.2023 है। नगर निगम गुरूग्राम ने 09.08.2021 को पत्र जारी किया है; 24.08.2021 और 06.09.2022 एचएसवीपी को मेसर्स रैपिड मेट्रो द्वारा विज्ञापन शुल्क के भुगतान के बारे में हस्तक्षेप करने और रिपोर्ट करने के लिए। एचएसवीपी की ओर से आज तक कोई जवाब नहीं मिला है। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि मैसर्स रैपिड मेट्रो से 2013 से 2018 की अवधि के लिए 180 करोड रुपये की वसूली की गई है सीडब्लयूपी 1870 आफ 2015 के प्रश्न में है। वर्तमान में हरियाणा नगर निगम विज्ञापन उपनियम 2022 के तहत सरकार द्वारा शुरू किए गए पोर्टल पर एचएमआरटीसी की 72 साइटें नीलामी के लिए चालु हैं।

3	मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डेवलपर्स	14.46	आरएसए नंबर 10 में मुकदमेबाजी के तहत। आरएसए 2360/2018 आरएसए 1383/2018 आरएसए 2398/2018 आरएसए 2359/2018 आरएसए 2392/2018 आरएसए 2358/2018 आरएसए 2695/2018 आरएसए 2296/2018 आरएसए 2399/2018 आरएसए 2400/2018 **<u>संक्षिप्त</u>** संकल्प दिनांक 02.12.20210 तत्कालीन आयुक्त, एमसीजी ने विज्ञापन शुल्क के लिए रु. 100, 115 और 125 प्रति वर्ग फीट। ओ.एम.डी वॉलव्रैप के लिए प्रति माह 2013 में विभिन्न एजेंसियों को रिकवरी नोटिस जारी किए गए थे, जिन्हें एजेंसियों ने अलग-अलग सिविल सूट द्वारा सिविल कोर्ट, गुरुग्राम के समक्ष चुनौती दी थी। 2015 में सिविल कोर्ट, गुरुग्राम ने दिनांक 12.05.2015 के आदेश द्वारा इस तरह के कानूनी मामलों का निपटारा किया है, जिसमें एमसीजी को निर्देश दिया गया है कि सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकारी होने के नाते एजेंसियों से उक्त राशि की वसूली न की जाए। नगर निगम गुरूग्राम ने माननीय (एडीजे) की अदालत के समक्ष फैसले को चुनौती दी है, गुरुग्राम ने अलग-अलग अपील की। माननीय (एडीजे), गुरुग्राम के न्यायालय ने दिनांक 08.10.2015 के आदेश द्वारा उक्त 10 अपीलों का निस्तारण सरकार से सक्षम प्राधिकारी होने के नाते दरों का निर्धारण करने के बाद ही वसूली शुरू करने के निर्देश के साथ किया।
	मैसर्स डीएलएफ कार्यालय डेवलपर्स, नई दिल्ली	1.2	
	मैसर्स रेनकॉन पार्टनर्स, नई दिल्ली	1.73	
	मैसर्स डीएलएफ कमर्शियल एंटरप्राइजेज	0.06	
	मेसर्स डीएलएफ लिमिटेड गुरुग्राम, शॉपिंग मॉल	5.76	
	मेसर्स डीएलएफ साउथ प्वाइंट 1 ई, नई दिल्ली	0.03	
	मैसर्स डीएलएफ एसेट प्रा. 1ई नई दिल्ली (भवन संख्या-14)	0.32	
	मेसर्स डीएलएफ लिमिटेड शॉपिंग मॉल, अर्जुन मार्ग, डीएलएफ सिटी फेज-1, गुड़गांव (डीटी मेगा मॉल)	1.92	
	एम/एस डीएलएफ लिमिटेड शॉपिंग मॉल, अर्जुन मार्ग, डीएलएफ सिटी फेज -1, गुड़गांव (ग्रैंड मॉल)	5.30	
	मेसर्स डीएलएफ लिमिटेड शॉपिंग मॉल, अर्जुन मार्ग, डीएलएफ सिटी फेज-1, गुड़गांव (सिटी कोर्ट)	0.40	

			एमसीजी ने माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष उपरोक्त आरएसए दायर किया है जिसमें आगामी सुनवाई तिथि 19.07.2023 है। पत्र दिनांक 09.02.2012, 23.02.2021 और 18.08.2021 के माध्यम से एमसीजी ने सरकार से विज्ञापन के लिए दरें निर्धारित करने का अनुरोध किया है।
4	मैसर्स एंबियंस मॉल:	11.08	वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है वसूली प्रमाण पत्र एजेंसियों के खिलाफ उपायुक्त, गुरुग्राम द्वारा जारी किए गए हैं। एचएमसी अधिनियम 1994 की धारा 130 के तहत अंचल कराधान अधिकारी, -III, एमसीजी द्वारा इसका निष्पादन किया जा रहा है।
	मैसर्स एनएसआर फार्म (एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन)	2.91	
	मैसर्स एमजीएफ मेगासिटी मॉल गुड़गांव	3.89	
	मैसर्स आर.डी. विज्ञापनदाता, 6ई, सैनिक फार्म नई दिल्ली	0.43	
	मैसर्स डीएलएफ बिल्डिंग नंबर 05	3.57	
	मैसर्स रीजेंट प्लाजा मॉल गुरुग्राम	1.51	
	मैसर्स जेएमडी रीजेंट आर्केड मॉल गुरुग्राम	2.31	
	मैसर्स श्याम विज्ञापनदाता ग्राम जादरा जिला रेवाडी	0.0073	
	पाथवे स्कूल बलियावास अॉफ गुरुग्राम फरीदाबाद रोड गुरुग्राम	0.0046	
	मैसर्स 24 सेवन फाइलिंग स्टेशन के सामने, निर्वाण देश, गोल्फ कोर्स, गुरुग्राम	0.03	
	मैसर्स रीजेंट प्लाजा मॉल गुरुग्राम	1.51	
	मैसर्स जनता फाइलिंग स्टेशन सिकंदरपुर महरौली-गुरुग्राम रोड, गुरुग्राम	0.01	
	मैसर्स जेएमवीडी ग्रुप ए-8 पुलिस स्टेशन कापसहेड़ा के सामने, नई दिल्ली	0.10	

	मैसर्स लैंकोइन्फ्राटेक लिमिटेड लैंको हाउस, प्लॉट - 397, उद्योगविहार, फेज-3, गुरुग्राम	0.33	
	मैसर्स अर्श पब्लिसिटी प्रा. लिमिटेड सिकंदरपुर, गुरुग्राम	0.14	
	मैसर्स सर्ज मीडिया प्रा. लिमिटेड डब्लयूजैड 320 8सी, पहली मंजिल, महिंद्रा पार्क, रानी बाग, नई दिल्ली	0.04	
	मैसर्स लांसर्स इंटरनेशनल स्कूल डीएलएफ, फेज- V, सेक्टर-53, गुरुग्राम	0.0011	
	मैसर्स आइकॉन इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन सर्विस (आई) प्रा0 लिमिटेड, एन-214, एलजीएफ, ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली-110048	0.04	
	मैसर्स एंवॉयस इलेक्ट्रॉनिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड 482, उद्योगविहार, फेज- V, गुरुग्राम	0.95	
	मैसर्स ऐडर्वट कम्यूनिकेशन प्रा0 लिमिटेड	16.95	
	महाराजाऐडर्वटाईजर	4.53	
	मैसर्स एडवेल ऐडर्वटाईजमैन्ट सर्विस	9.17	
कुल		**321.433**	

महाविद्यालय के भवन का निर्माण करना

***39. श्री ईश्वर सिंह :** क्या उच्चतर शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे किः-

(क) क्या यह तथ्य है कि गुहला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के गांव चाक्कू लदाना में मुख्यमंत्री द्वारा घोषित राजकीय महाविद्यालय स्कूल के कमरों में चलाया जा रहा है; तथा

(ख) यदि हां, तो उक्त महाविद्यालय का भवन कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है तथा इसका निर्माण कब तक आरंभ किए जाने कि संभावना है क्योंकि ग्राम पंचायत द्वारा शिक्षा विभाग को जमीन भी उपलब्ध करा दी गयी है?

उच्चतर शिक्षा मंत्री (श्री मूल चंद शर्मा): (क) हां, श्रीमान जी। (ख) राजकीय महाविद्यालय, लदाना चाक्कू के निर्माण हेतु ले-आउट प्लान, ड्राईंग एवं सिविल कार्यों के लिए अनुमानित लागत बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ले-आउट प्लान, ड्राईंग एवं रफ कॉस्ट एस्टीमेट प्राप्त होने के बाद भवन निर्माण के लिए राशि जारी करने के संबंध में कार्यवाही की जाएगी।

गरीब परिवारों के लिए घर उपलब्ध करवाना

***40 श्री बलबीर सिंह :–** क्या हाउसिंग फॉर ऑल मंत्री कृपया बताएगें कि :–

(क) राज्य में वर्ष 2014 से 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बी.पी.एल. परिवारों के लिये निर्मित घरों की कुल संख्या कितनी है तथा घरों के निर्माण के लिए किये गये सर्वेक्षणों की संख्या कितनी है तथा उनका जिलावार ब्यौरा क्या है ?

(ख) क्या सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार वर्ष 2024 तक सभी जरुरतमंद गरीब परिवारों को निर्माण के पश्चात घर उपलब्ध करवाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

हाउसिंग फॉर ऑल मंत्री (डॉ. कमल गुप्ता) : श्रीमान् जी, विवरण सहित जवाब सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जाता है।

विवरण

म

प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी तथा प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अंतर्गत जिलावार लाभार्थियों की संख्या तथा वितरित की गई वित्तिय सहायता।

		पी.एम.ए.वाई –शहरी		पी.एम.ए.वाई –ग्रामीण		कुल	
क्रम सख्या	जिला	शहरी तथा ग्रामीण लाभार्थियों की संख्या	वितरित की गई कुल वित्तिय सहायता (करोड़ में)	शहरी तथा ग्रामीण लाभार्थियों की संख्या	वितरित की गई कुल वित्तिय सहायता (करोड़ में)	शहरी तथा ग्रामीण लाभार्थियों की संख्या	वितरित की गई कुल वित्तिय सहायता (करोड़ में)
1	2	3	4	5	6	7 (3+5)	8 (4+6)
1	अम्बाला	1000	12.695	506	5.04	1506	17.74
2	भिवानी	1784	31.742	826	13.17	2610	44.92
3	चरखी–दादरी	305	1.959	284	1.82	589	3.77
4	फरीदाबाद	30	0.69	166	2.28	196	2.97
5	फतेहाबाद	2154	33.258	1205	15.89	3359	49.15
6	गुरूग्राम	567	11.348	51	0.64	618	11.99
7	हिसार	4442	70.233	2334	28.38	6776	98.61
8	झज्जर	671	13.803	570	7.12	1241	20.93
9	जींद	3068	50.333	1181	14.79	4249	65.13
10	कैथल	2824	53.646	2053	21.56	4877	75.20
11	करनाल	1903	35.061	2688	30.97	4591	66.03
12	कुरूक्षेत्र	1146	24.065	2213	27.41	3359	51.48
13	महेन्द्रगढ़	402	6.757	593	7.61	995	14.37
14	मेवात (नूँह)	1384	12.13	4401	50.80	5785	62.93
15	पलवल	824	9	583	7.84	1407	16.84
16	पंचकुला	19	0.42	181	2.07	200	2.49
17	पानीपत	378	7.321	1075	12.83	1453	20.16
18	रेवाड़ी	221	3.054	106	1.43	327	4.49

19	रोहतक	1412	26.971	1221	16.28	2633	43.25
20	सिरसा	632	12.552	2945	33.03	3577	45.58
21	सोनीपत	688	16.801	1190	14.45	1878	31.25
22	यमुनानगर	2101	40.66	1974	25.43	4075	66.09
कुल		**27955**	**474.499**	**28346**	**340.8393**	**56301**	**815.34**

....

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट का निर्माण करना

41. डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कृपया बताएंगे कि –

(क) क्या जींद शहर की बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए 5 एम.एल.डी. सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसके कब तक निर्मित किये जाने की संभावना है ? तथा

(ख) क्या निर्माणाधीन 15 एम.एल.डी. के सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट में टैंक फटने पर एजेंसी तथा विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (डॉ. बनवारी लाल) :

(क) अमृत 2.0 के तहत जींद शहर के लिए सीवेज ट्रीटमैंट प्लांट के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है । प्रस्ताव के प्रशासनिक अनुमोदन के उपरान्त 2 वर्ष के अंदर इस कार्य के पूर्ण होने की संभावना है ।

(ख) जींद शहर के मौजूदा 15 एम.एल.डी. सीवेज ट्रीटमैंट प्लांट के उन्नयन का कार्य प्रगति पर है व साइट पर इस कार्य के निष्पादन के दौरान, टैंक (निर्माणाधीन) की दीवारें कुछ खराबी के कारण टूट गई थी । उक्त स्ट्रक्चर का पुनर्निर्माण एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर करवाया जा रहा है । इस कार्य के 31.03.2023 तक पूर्ण होने की संभावना है ।

....

एच.एस.ए.एम.बी. द्वारा निर्मित सड़कों का ब्यौरा

42. डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा : क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कृपया बताएंगे कि:-

(क) वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, जींद द्वारा बनाई गई सड़कों की कुल संख्या कितनी है तथा खर्च का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उच्च स्तरीय ऐजेंसी के माध्यम से उपरोक्त निर्मित सड़कों की गुणवत्ता की जांच करवाई गई है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; तथा

(ग) क्या सरकार राज्य विजिलेंस/ सतर्कता के माध्यम से उपरोक्त सड़कों की जांच करेगी; यदि हां, तो यह जांच कब तक कराए जाने की संभावना है ?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल): (क) वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, जींद द्वारा 992.92 करोड़ रूपये की लागत से 9 नई सड़कों का निर्माण किया गया;

(ख) पालवां से खेड़ी मसानिया सड़क की जांच उप मण्डल विजिलेंस कमेटी द्वारा की गई है तथा जांच रिपोर्ट अभी अपेक्षित है; तथा

(ग) समय-समय पर 1.00 करोड़ रूपये से अधिक लागत वाले कार्यो की सूची राज्य विजिलेंस/ सतर्कता ब्यूरो को भेजी जाती है तथा उनके द्वारा इन कार्यो की जांच क्रमरहित आधार पर की जाती है, इसलिए कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती ।

आर्ट ब्लॉक का निर्माण करना

43. डॉ. कृष्ण लाल मिडडा : क्या उच्चतर शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे कि:–

(क) क्या यह तथ्य है कि राजकीय स्नातकोतर महाविद्यालय, जीन्द मे अपर्याप्त इमारत के कारण छात्रों को खुले क्षेत्र में कक्षाओं में भाग लेना पड़ता है या तथा

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त महाविद्यालय में आर्ट ब्लॉक का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो इसके कब तक निर्मित किए जाने की संभावना है?

उच्चतर शिक्षा मंत्री (श्री मूल चंद शर्मा) : (क) हां, श्रीमान जी।

(ख) हां, श्रीमान जी, उपायुक्त, जींद से प्रस्ताव प्राप्त हो गया है तथा कला खण्ड के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

मनरेगा स्कीम के अंतर्गत कार्यों की कुल संख्या

44. डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा : क्या विकास एवं पंचायत मंत्री कृपया बताएंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान मनरेगा योजना के अंतर्गत जींद जिले में निष्पादित कार्यों की कुल संख्या कितनी है; तथा

(ख) प्रत्येक कार्य (कच्चा तथा पक्का कार्य) पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

****विकास एवं पंचायत मंत्री (श्री देवेन्द्र सिंह बबली)** श्रीमान,

(क) वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान मनरेगा योजना के तहत जिला जींद में कुल 2456 कार्य करवाये गए।

(ख) इन 2456 कार्यों पर 5261.61 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रत्येक कार्य (कच्चा और पक्का कार्य) का विवरण अनुलग्नक "क" पर है और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विवरण अनुलग्नक "ख" पर है ।

....

पशु चिकित्सकों की ड्यूटियां

45. श्री बिशन लाल सैनी : क्या पशुपालन एवं डेयरी मंत्री कृपया बताएंगे किः-

(क) पशु चिकित्सकों तथा कंपांउडरों के कर्तव्यों की प्रकृति क्या है;

(ख) क्या इनके कर्तव्य की प्रकृति में यह भी सम्मिलित है कि उपरोक्त कर्मचारी पशुओं की देखभाल तथा इलाज के लिए पशुओं के मालिक के घर जाना होगा; यदि

नहीं, तो क्या यह उनके लिए न्यायसंगत है कि फीस लेने के बाद पशुओं के इलाज के लिए गांवों में जाते हैं?

****उपरोक्त अतारांकित प्रश्न के उत्तर के जवाब के एनैक्श्चर्स 56 पेजिज का होने के कारण चेयर के आदेशानुसार इन एनैक्श्चर्स को पूर्व प्रथानुसार हरियाणा विधान सभा के पुस्तकालय में रखवाया गया।**

पशु पालन एवं डेयरी मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) : (क) पशु चिकित्सक और

पशु चिकित्सा विकास सहायक (वी.एल.डी.ए.) का जॉब चार्ट क्रमशः अनुलग्नक - I व II पर संलग्न है।

(ख) नहीं श्रीमान् जी, फीस लेकर पशुओं के इलाज के लिए गांवों में जाना उनके लिए न्यायसंगत नहीं है।

अनुलग्नक-I

पशु चिकित्सक (वी.एस.) पद के कर्तव्य

1. पशु चिकित्सालय में आने वाले आंतरिक एवं बाह्य मामलों का उपचार।
2. नगर पालिका समिति के पास आवश्यक स्टाफ की कमी होने पर स्थानीय बूचड़खाने में वध किए गए पशुओं का मृत्यु पूर्व और मृत्यु उपरांत परीक्षण।
3. पशुओं के संक्रामक रोगों की रोकथाम।
4. क्षेत्र में अनुपयुक्त नर पशुओं का बधियाकरण।
5. पशु प्रजनन।
6. पशु प्रजनन, आहार तथा प्रबंधन से संबंधित प्रचार कार्य।
7. पशुओं के बीमा संबंधी कार्य।
8. उच्च दूध उत्पादन वाली मुर्राह भैंसों और उनके कटड़ों की पहचान करना।
9. स्वास्थ्य देखभाल शिविरों, बांझपन शिविरों और कृमिनाशक शिविरों का आयोजन करना।
10. सरकार द्वारा समय-समय पर पशुपालकों तथा लोगों के कल्याण हेतु शुरू की गईं विभिन्न राष्ट्रीय एवं राजकीय कार्यक्रमों / स्कीमों को लागू करना।
11. पशुओं के उपचार / टीकाकरण शिविरों से सम्बन्धित विभिन्न चिकित्सीय / रोग निरोधी / प्रचार कार्यक्रमों का आयोजन और पर्यवेक्षण।

अनुलग्नक-II

पशु चिकित्सा विकास सहायक (वी.एल.डी.ए.) पद के कर्तव्य

1. ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 (1940 का 23) के अन्तर्गत ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स नियम, 1945 की "अनुसूची एच" में निर्दिष्ट दवाओं का, पंजीकृत पशु चिकित्सक द्वारा नियत अनुसार प्रयोग और क्रियान्वयन।
2. चिकित्सीय दवाओं का संयोजन और वितरण।

3. दर्दनाशक, ज्वरनाशक दवाओं और अन्य मुँह द्वारा दी जा सकने वाली दवाओं के माध्यम से प्रारंभिक पशु चिकित्सा सहायता प्रदान करना।

4. बधियाकरण, डी- हॉर्निंग, डिस-बडिंग और डी-बीकिंग करना।

5. सर्जिकल/प्रसूति रोग संबंधी मामलों के उपचार में पंजीकृत पशु चिकित्सक की सहायता करना।

6. पशुओं का रोग निरोधी टीकाकरण।

7. घावों, बाहरी/सतही रक्तस्त्राव, फोड़ा, सतही जलन आदि जैसी बीमारियों का निपटान करना।

8. मुँह व खुर, थनैला तथा स्टॉमाटाइटिस आदि बीमारियों में रोगाणुरोधक/औषधी से मुंह, खुर, पैर, थन आदि को धोना।

9. प्रयोगशाला परीक्षण हेतु रक्त, सीरम, मल, मूत्र, वीर्य, दूध और अन्य नमूने एकत्र करना और प्रयोगशाला भेजना।

10. संक्रामक रोगों की निगरानी, प्रयोगशाला जांच और प्रकोप नियंत्रण उपायों सहित अन्य संबंधित तकनीकी कार्यों में सहायता करना।

11. रोग संबंधी आंकड़े एकत्र करना, संकलित करना, अनुरक्षण करना और रिपोर्ट करना।

12. आपात स्थिति सहित विभिन्न बीमारियों के मामलों में प्राथमिक तौर पर पशुचिकित्सा प्रदान करना, जैसेः

    क) आसमानी बिजली का आघात
    ख) लू लगना / शीत दंश
    ग) बिजली का झटका
    घ) जहर के मामले
    ड़) सांप का काटना
    च) डूबना
    छ) योनि/गर्भाशय का आगे बढ़ना
    ज) गर्भनाल का प्रतिधारण
    झ) कठिन प्रसव
    ञ) नवजात पशु की नाभि रज्जु की मरमह पट्टी करना
    ट) साधारण फ्रैक्चर
    ठ) चोट/संक्रमण के मामले में पूंछ काटना।
    ड) बदहजमी
    ढ) भूख ना लगना
    ण) टिम्पनी/अफारा
    त) सींग की चोट

थ) जंगली जानवरों का हमला

द) प्राकृतिक आपदा

ध) दुर्घटना आदि

13. गायों और भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान करना, उसका अनुश्रवण एवं रिकार्ड का रख-रखाव करना।

14. विभाग की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत दूध उत्पादन हेतु गाय / भैंसों का पंजीकरण एवं दूध रिकार्डिंग / प्रदर्शन रिकार्डिंग के आयोजन में पशु चिकित्सकों की सहायता करना।

15. पशुपालकों के लिए पशु आहार एवं चारा प्रबंधन, विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के संबंध में विस्तार गतिविधियों में सहायता करना।

16. पशु चिकित्सक के पर्यवेक्षण में पशु चिकित्सा संस्थाओं के भण्डार एवं उसके रिकार्ड का संग्रहण, वितरण, अनुरक्षण करना।

17. संस्थाओं के उपकरणों का सामान्य रखरखाव एवं साफ-सफाई सुनिश्चित करना।

18. पशु चिकित्सकों की देख-रेख में क्षेत्रीय पशु चिकित्सा संस्थानों के सभी रिकार्ड बनाए रखना।

19. विभागीय स्कीमों एवं निर्देशों अनुसार पशुधन इकाईयों की स्थापना में पशु चिकित्सकों की सहायता एवं पशुओं की टैगिंग करना।

20. पशुओं के उपचार/टीकाकरण शिविरों से सम्बन्धित विभिन्न चिकित्सीय / रोग निरोधी / प्रचार कार्यक्रमों के आयोजन और पर्यवेक्षण में पशुचिकित्सकों की सहायता करना।

21. सरकार द्वारा पशुपालकों और जनता के कल्याण हेतु समय-समय पर शुरू किए गए राष्ट्रीय / राजकीय कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन में पशु चिकित्सकों की सहायता करना।

22. प्रभारी पशु चिकित्सक एवं उच्चाधिकारियों द्वारा विभाग के हित में सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

एन.जी.टी योजना द्वारा तलाबों का नवीनीकरण

46. श्री बिशन लाल सैनी : क्या विकास एवं पंचायत मंत्री कृपया बताएंगे कि–

(क) 25 फरवरी, 2021 से अब तक एन.जी.टी या किसी अन्य योजना के द्वारा रादौर खण्ड में नवनिर्मित किए गए जलाशयों की संख्या कितनी है तथा उसका ब्यौरा क्या है; तथा

(ख) क्या सरकार जांच करेगी यदि इस सम्बन्ध मे कोई अनियमितता हुई है?

विकास एवं पंचायत मंत्री (श्री देवेन्द्र सिंह बबली) : (क) खण्ड रादौर में 16 तालाबों के नवीनीकरण का कार्य स्वीकृत है । इनमें से 11 तालाब एनजीटी कार्य योजना यमुना नदी के अंतर्गत स्वीकृत हैं । यह सभी कार्य पूर्ण हैं । 3 तालाब हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आदर्श तालाब योजना के अंतर्गत स्वीकृत हैं जोकि प्रगतिधीन है । 2 तालाब धूसर जल प्रबंधन (स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण चरण–II) के अंतर्गत स्वीकृत है जोकि प्रगतिधीन हैं ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

....

नई बसें खरीदना

47. श्री बिशन लाल सैनी : क्या परिवहन मंत्री कृपया बताएंगे–

(क) क्या नई बसें खरीदने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; तथा

(ख) क्या सरकार इन बसों पर उन व्यक्तियो में से कंडक्टरों को नियुक्त करेगी जिन्होने वर्ष 2018 में हड़ताल के समय पर सरकार की सहायता की थी, यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मन्त्री (श्री मूल चन्द शर्मा) : (क) हां, श्रीमान्, सरकार द्वारा 1000 पूर्ण रूप से निर्मित सामान्य गैर ए0सी0 बसें, 150 एच0वी0ए0एसी0 बसें तथा 125 मिनी बसें खरीदने का फैसला लिया गया है।

(ख) हां, श्रीमान्, जिन परिचालकों ने वर्ष 2018 में हड़ताल के दौरान काम किया है जब कभी एच0के0आर0एन0 के माध्यम से परिचालको की नियुक्ति की जायेगी तब उन्हें नियुक्ति में प्राथमिकता दी जायेगी।

....

भूमि की रजिस्ट्री खोलना

48. श्री बिशन लाल सैनी : क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि-

(क) क्या यह तथ्य है कि नगर समिति, रादौर के अन्तर्गत भूमि की रजिस्ट्री बन्द की गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उपरोक्त रजिस्ट्री को कब तक खोले जाने की संभावना है; तथा

(ग) रजिस्ट्री न होने के कारण कुल कितने राजस्व का नुकसान हुआ तथा इसका ब्यौरा क्या है?

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : (क) नहीं श्रीमान्।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 और पंजीकरण अधिनियम, 1908 के प्रावधानों के अनुसार दस्तावेजों के पंजीकरण के समय लागू स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क के रूप में राजस्व की कोई हानि नहीं हुई है।

....

एकत्रित गंदे पानी की समस्या का समाधान करना

49. **श्री भारत भूषण बत्रा :** क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कृपया बताएंगे कि-

(क) क्या यह तथ्य है कि रोहतक शहर की अधिकतर कॉलोनियों में गंदे एवं बदबूदार पानी की आपूर्ति की जा रही है तथा उक्त समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाए गए हैं तथा उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) सर छोटूराम चौक पर एकत्रित हुए बरसाती पानी की निकासी करने के लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाए गए हैं तथा उसका ब्यौरा क्या है; तथा

(ग) सर छोटूराम चौक के साथ लगते तालाब में बरसाती पानी का जलाश्य निर्मित करने के लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाए गए हैं तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (डॉ. बनवारी लाल) : (क) रोहतक शहर की कॉलोनियों में पीने योग्य पानी की आपूर्ति की जा रही है। जब भी कोई गंदे एवं बदबूदार पानी की शिकायत प्राप्त होती है उसको तत्काल सुधारा/ठीक कर दिया जाता है।

(ख) सर छोटूराम चौक व उसके आस-पास के क्षेत्र में एकत्रित होने वाले बरसाती पानी को अप्पू घर स्थित मौजूदा बरसाती पानी निकासी के डिस्पोजल के माध्यम से निकाला जाता है। अप्पू घर स्थित बरसाती पानी निकासी के डिस्पोजल की क्षमता 49.4 क्यूसेक की है व इसका जलग्रहण क्षेत्र 160 हेक्टेयर का है।

(ग) मुख्यंमत्री घोषणा क्रमांक 12639 दिनांक 19.05.2016 के तहत रोहतक शहर में सर छोटूराम चौक के साथ लगते तालाब में बरसाती पानी का जलाश्य निर्मित करने का कार्य 671.46 लाख रूपये के अनुमान **"अप्पू घर झील का पुनर्विकास जिला रोहतक"** के अन्तर्गत 17.07.2017 को आवंटित किया गया। एजेंसी द्वारा साइट पर कार्य आरंम्भ किया गया था व 499.73 लाख रूपये की राशि का कार्य पूर्ण किया गया था व वर्तमान में साइट पर कार्य पिछले दो वर्षो से निलंबित पड़ा है। एजेंसी के विरुद्ध अनुच्छेद-।। और अनुच्छेद-।।। की पहल की गई है।

....

नशीली दवाओं के दुरुपयोग के कारण हुई मौतों की संख्या

50. श्री अमित सिहागः क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) डबवाली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र तथा सिरसा जिला में नशीली दवाओं के दुरूपयोग में नशीली दवाओं/अत्यधिक डोज के कारण वर्ष 2022 में दर्ज हुई मौतों की संख्या कितनी है ?

(ख) नशा तस्करों के खिलाफ पंजीकृत आपराधिक मामलों की संख्या कितनी है? जिला सिरसा में वर्ष 2019, 2020, 2021 और 2022 में पंजीकृत अपराधियों के मामलों की संख्या कितनी है तथा इसका वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

(ग) जिला सिरसा विशेषकर डबवाली तथा कालांवाली विधान सभा क्षेत्र में नशे की तस्करी को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्री (श्री अनिल विज): महोदय, एक वक्तव्य सदन के पटल पर रख दिया गया है।

वक्तव्य

(क) वर्ष 2022 में डबवाली विधानसभा क्षेत्र एवं जिला सिरसा में नशीले पदार्थों के सेवन व अत्यधिक मात्रा के सेवन से हुई मौतों की संख्या इस प्रकार हैः

जिला सिरसा में कुल	डबवाली विधानसभा क्षेत्र में कुल	
18	डबवाली = 7	कालांवाली = 3

(ख) जिला सिरसा में वर्ष 2019,2020,2021 एवं 2022 में नशा तस्करों के विरुद्ध दर्ज अपराधिक मामलों की संख्या एवं अभियोजित अपराधियों की संख्या का वर्षवार विवरण निम्नानुसार हैः-

जिला सिरसा में वर्षवार नशा तस्करों के विरुद्ध दर्ज अपराधिक मामलों की संख्या				जिला सिरसा में वर्षवार अभियोजित अपराधियों की संख्या			
2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
587	722	446	624	837	1333	787	1088

(ग) जिला सिरसा, विशेष रुप से डबवाली और कालांवाली विधानसभा क्षेत्रों में नशीले पदार्थों के खतरे को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं?

हरियाणा सरकार ने राज्य स्तर पर हरियाणा राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो बनाया है। एच.एस.एन.सी.बी ने नशीले पदार्थों के खतरे को नियंत्रित करने के लिए एक राज्य कार्य योजना प्रस्तुत की है जिसका माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा ने दिनांक 26.06.2022 को उद्धघाटन किया है।

- स्टेट एक्शन प्लान के तहत हरियाणा के हर गांव, वार्ड, पीएचसी, उपमण्डल और जिलों मे मिशन टीमों का गठन किया गया है, जो देश में पहली बार हुआ है। पुरे हरियाणा में कुल 8876 मिशन टीमों का गठन किया गया है, जिनमें से जिला सिरसा में 480 मिशन टीमों का गठन किया गया है । स्टेट एक्शन प्लान के अन्तर्गत जनता एवं पुलिस के 85000 से ज्यादा टीम सदस्य लगातार नशाखोरी के विरुद्ध कार्य करेंगे। ये टीमें जल्द ही

पुरे हरियाणा राज्य में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति का एक सर्वेक्षण करेंगी, जिसका उद्धेश्य पीड़ितों को इलाज और पुनर्वास में मदद करना है।ये सभी टीमें एच.एस.एन.सी.बी. के 'हॉंक सॉफ्टवेयर' से जुड़ी हुई है, जिसमें तस्करों के ड्रग ट्रेल की पुरी मैपिंग के लिए उन्नत सुविधा उपलब्ध है ।

- टोल फ्री नम्बर 9050891508 और छात्रो को जोड़ने के लिये 'धाकड़' कार्यक्रम पहले ही आरम्भ किया जा चुका है ।
- सिरसा पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन 'क्लीन' शुरु किया है । कई मामले दर्ज किए गए हैं और अपराधियों को गिरफतार किया गया है।
- 8330 घरों की छानबीन (कोम्बिंग) की जा चुकी है। राज्य के बाहर 268 छापेमारी की गई है और 236 अभियुक्तों को गिरफतार किया गया है।
- 20 मेडिकल दुकानों को सील किया गया है और 14 मेडिकल दुकानों के लाईसेंस रद्द किए गए हैं। मेडिकल की दुकानों से प्रतिबंधित दवाओं की चोरी को रोकने के लिए एच.एस.एन.सी.बी. द्वारा "साथी एप" विकसित किया गया है और जल्द ही इसे हरियाणा में चालू किया जाएगा ।
- 12 नशा तस्करों से सम्बंधित गैर कानुनी रुप से अतिक्रमण करके या स्थानीय उपनियमों का उल्लंघन करके निर्माण की गई लगभग 31,64,325 रुपये कीमत की संपतियाँ तोड़ी गई हैं। पी.आई.टी एन.डी.पी.एस. अधिनियम, के तहत 3 मामले प्रक्रियाधीन है। लगभग 3 करोड़ रुपये की सम्पत्ति को अटैच किया गया है ।
- सिरसा पुलिस ने नशामुक्त करने के लिए 12 गांवों को गोद लिया है।

- 292 व्यक्तियों को नशामुक्ति के लिए सहायता प्रदान की गई है और 708 जागरुकता शिविर आयोजित किए गए हैं। एच.एस.एन.सी.बी. ने सिरसा में भी कई अभियान चलाए हैं और डॉग स्क्वायड के साथ सिरसा में अपनी इकाई स्थापित की है।
- राज्य सरकार ने नये नशामुक्ति केन्द्र स्थापित किये हैं तथा प्रत्येक मण्डल स्तर पर भी राज्य स्तरीय पुनर्वास केन्द्रो को स्थापित करने का विचार किया जा रहा है।
- वर्तमान में जिला सिरसा में 3 सरकारी एवं 13 निजी नशामुक्ति केन्द्र चल रहे हैं।
- सिरसा के जिला नागरिक अस्पताल में 10 बिस्तर का नशामुक्ति केन्द्र चल रहा है।
- उपमण्डलीय अस्पताल मंडी डबवाली व कालांवाली में एक नशामुक्ति केन्द्र भी स्थापित किया गया है तथा जिला बाल कल्याण कार्यालय, सिरसा द्वारा एक नशामुक्ति केन्द्र चलाया जा रहा है ।
- हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाईटी द्वारा सिविल अस्पताल, सिरसा में एक ओपिओइड सबस्टीट्यूशन थेरेपी (ओ.एस.टी.) केन्द्र भी स्थापित किया गया है। यह केन्द्र अंतःशिरा ड्रग उपयोगकर्ताओं को मौखिक ओपिओइड विकल्पों पर बदलने और पुर्ण नशामुक्ति की दिशा में आगे बढने में मदद करता है।
- सिविल अस्पताल सिरसा की जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम टीम साप्ताहिक रुप से सिरसा जेल का दौरा करती है और 2022-23 में 442 जेल बंदियों की काउंसलिंग की गई है।

बन्दरों के आतंक को रोकना

51.श्री अमित सिहाग : क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे कि डबवाली तथा पंचकुला में बन्दरों के आतंक को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाए जा रहे हैं ?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डा० कमल गुप्ता): श्रीमान् जी, नगर परिषद, डबवाली तथा नगर निगम, पंचकुला में बन्दरों के आतंक को रोकने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित पग उठाए जा रहे हैं :–

क्र.सं.	एम.सी. का नाम	पकड़े गए बंदरों की संख्या	टिप्पणी
1	नगर परिषद, डबवाली	418	वर्ष 2020 से 31.01.2023 तक कुल 418 बंदरों को पकड़ा गया है। उनमें से 382 बंदरों को यमुनानगर के कालेसर वन में भेज दिया गया है और शेष 36 बंदरों को मेडिकल जांच के बाद भेजा जाएगा।
2	नगर निगम, पंचकुला	88	वर्ष 2022 से 31.01.2023 तक कुल 88 बंदरों को पकड़ा गया है और निकटतम वन में छोड़ा गया है। सेक्टर–12ए, पंचकुला में शिकायतें प्राप्त करने के लिए एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है।

....

52. श्री अमित सिहाग : क्या विकास एवं पंचायत मंत्री कृपया बताएंगे किः–

(क) बेसहारा पशुओं की समस्या के समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाए जा रहे हैं; तथा

(ख) क्या सरकार का गौशालाओं/नंदीशालाओं में छोड़ी गई गायों तथा बैलों की बढ़ती हुई संख्या तथा गायों/पशुओं को दिए जाने वाले फीड़ की कीमत में बढोतरी को ध्यान में रखते हुए गौशालाओं/नंदीशालाओं में प्रति पशु प्रति दिन अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का इरादा है?

विकास एवं पंचायत मंत्री (श्री देवेन्द्र सिंह बबली) श्रीमान जी,

(क) हरियाणा पंचायती राज एक्ट,1994 के अधिनियम की धारा 21 (XXVI), जोकि ग्राम पंचायतों पर लागू होती है, के अनुसार ग्राम पंचायत का दायित्व है कि वे पशु शेड और पशुबाड़ा का निर्माण और रखरखाव करेगीं। तदानुसार, सभी उपायुक्तों (उपायुक्त सिरसा सहित) को ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध संसाधनों/स्त्रोतों की सीमा के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।

(ख) नहीं, महोदय पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार गौशालाओं/नंदीशालाओं को प्रति दिन प्रति पशु के हिसाब से अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने बारे कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा डबवाली विधानसभा क्षेत्र की गौशालाओं को दिए गए अनुदान का विवरण अनुबंध अनुसार साथ संलग्न है।

विवरण

Detail of grant provided by Animal Husbandary & Dairying Department During Year 2022- 23 as First installment to Gaushalas of Dabwali constituency.

S. No.	Name of Gaushalas	No. of Gauvansh	Amount (Rs)
1	Shri Krishan Bhagwan Gaushala Samiti, Abushahar	526	157800
2	Shri Krishan Gaushala, Sakta Khera	223	66900
3	Sant Bab Kishan Singh Ji Maharaj Masmorial Gaushal Samiti, Masitan	484	145200
4	Shree Krishan Paranami Gaushala, Moujgarh	282	84600
5	Bhagwan Shri Krishan Goshala Sewa Samiti	1572	471600
6	Shree Ram Gaushala Sewa Saadan, Asakhera	202	80800
7	Baba Bala Samadha Wala Gaushala Samiti, Ganga	1062	318600
8	Shree Krishan Gaushala, Jandwala Bishnoian	643	192900
9	Shri Radha Krishan Gaushala, Goriwala	228	68400
10	Shri Baba Krishan Nath Gaushala Samiti, Ramgarh	365	109500
11	Shri Gaushala, Risalia Khera	935	280500
12	Shree Krishan Parnami Gaushala, Rampur Bishnoian	247	74100
13	Shri Krishan Parnami Gaushala, Ratta Khera-Rajpur	365	108600
14	Shri Ram Gopal GoshalaSamiti, Kaluana	703	210900
15	Shri Radha Krishan Gaushala, Ahmedpur Darewalal	467	140100
16	Shri Krishan Gopal Gaushala Bijjuwali	369	110700
17	Shri Krishan Parnami Gaushala Godikan	478	143400
18	Shri Krishan Gaushala, Khuiyan Malkana	185	55500
19	Shri Krishan Parnami Gramin Go Sewa Kendra, Sawant Khera	254	76200
20	Sant Baba Kalu Das Giri Ji Gaushala, Matdadu	264	79200
21	Shri Gaushala Mandi Dabwali	1212	363600
22	Nandishala Mandi Dabwali	513	153900
23	Bhagat Kabir Gaushala Sewa Samiti, Dabwali	106	31800
24	Shri Sant Baba Labh Singh Gosewa Samiti, Desu Jodha	153	45900
Total		**11,838**	**35,70,700**

....

समान काम के लिए समान वेतन

53 श्री नीरज शर्मा : क्या मुख्यमन्त्री यह बताएंगे कि :–

(क) क्या यह तथ्य है कि हरियाणा राज्य में आऊटसोर्सिंग भाग–II के अन्तर्गत कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन दिया जा रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त वेतन कब से दिया जा रहा है। यदि नही, तो उस के कारण हैं; तथा

(ग) क्या समान काम के लिए समान वेतन के लागू होने के बाद भाग–2 कर्मचारियों को वार्षिक इंक्रीमैंट (वेतन वृद्धि) दी जा रही है; यदि हाँ, तो उन विभागो के नाम क्या हैं जिनमें ये दी जा रह है; यदि नहीं, तो क्या वेतन वृद्धि न देना न्यायोचित है ?

मुख्यमन्त्री (श्री मनोहर लाल) :श्रीमान् जी,

(क) 'समान काम के लिए समान' वेतन हरियाणा में आऊटसोर्सिंग नीति भाग–II के तहत कार्यरत कर्मचारियों को सरकार की हिदायतें क्रमांक 16/36/2016–3जी0एस0–II दिनांक 03.11.2017 के तहत दिया जा रहा है।

(ख) दिनांक 01.11.2017 से आऊटसोर्सिंग नीति भाग–II के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को 'समान काम के लिए समान' दिया जा रहा है।

(ग) भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 26 अक्तूबर, 2016 द्वारा न्यूनतम वेतनमान प्रदान करने के निर्देश दिये है और इसे हरियाणा सरकार द्वारा हिदायते दिनांक 03.11.2017 के तहत लागू किया गया है। उक्त निर्देश में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वार्षिक वेतन वृद्धि का कोई सन्दर्भ नही दिया गया है। सरकार की हिदायतें क्रमांक 16/7/2015–3जी0एस0–II दिनांक 28.09.2021 द्वारा आऊटसोर्सिंग नीति के तहत नियुक्ति को बन्द किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने अधिसूचना क्रमांक16/91/2021–3जी0एस0–II, दिनांक 30.06.2022 द्वारा ग्रुप ग एवं घ की रोजगार सूची के विरूद्ध हरियाणा कौशल रोजगार निगम (ह0कौ0रो0नि0) के माध्यम से अनुबंधित व्यक्तियों को तैनात करने के लिये एक नई नीति अर्थात् ''अनुबंधित व्यक्तियों की तैनाती नीति, 2022'' को अधिसूचित किया है।

....

औद्यौगिक क्षेत्र नियमित करना

54 **श्री नीरज शर्मा :** क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि :-

(क) क्या यह तथ्य है कि फरीदाबाद में गांव सरूरपुर तथा गांव नंगला औद्यौगिक क्षेत्र है;

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त क्षेत्र को नियमित करने को कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा उक्त क्षेत्र को कब तक नियमित किए जाने की सभांवना है;

(ग) गांव सरूरपुर तथा गांव नंगला औद्यौगिक क्षेत्र की मुख्य सड़को तथा गलियों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या उक्त क्षेत्र बुरी अवस्था में है; तथा

(ङ) यदि हां, तो उपरोक्त क्षेत्र की सड़को तथा गलियों को कब तक निर्मित/मरम्मत किए जाने की सभांवना है?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डॉ0 कमल गुप्ता) : श्रीमान् जी,

(क) उद्योग और वाणिज्य विभाग, हरियाणा द्वारा मैसर्स आर.एस.आई. सॉफटेक के माध्यम से किए गए एक सर्वेक्षण में गांव सरूरपुर और गांव नंगला के राजस्व क्षेत्र में कई उद्योग है।

(ख) उपरोक्त क्षेत्रों को नियमित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। हालांकि सीडब्ल्यूपी संख्या 11226 ऑफ 2013 में माननीय उच्च न्यायालय के आदेष के तहत "औद्योगिक इकाईयों को स्थानांतरित करने की नीति" तैयार की गई है, दिनांक 20.07.2016 के तहत औद्योगिक इकाई को स्थानांतरित करने या वर्तमान स्थान पर अनुमति देने का प्रस्ताव तैयार है, जोकि प्रगति पर है। इसके अलावा, अवैध औद्योगिक क्षेत्रों/कॉलोनियों को हरियाणा नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले नगरपालिका क्षेत्र (विषेश प्रावधान), अधिनियम, 2016 के तहत नियमित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अधिनियम केवल आवासीय कॉलोनियों को अधिसूचित करने पर विचार करता है।

(ग) गांव सरूरपुर की मुख्य सड़क नगर निगम फरीदाबाद के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ग्राम नंगला की मुख्य सड़क का निर्माण हो चुका है, परन्तु ग्राम नंगला की औद्योगिक इकाईयों की आंतरिक गलियां निर्मित नहीं और यह क्षेत्र अनाधिकृत है।

(घ) गांव नंगला की औद्योगिक इकाइयों की गलियों की हालत खराब है, लेकिन अनाधिकृत क्षेत्र होने के कारण विकास कार्य नहीं हो पा रहे है। गांव सरूरपुर का क्षेत्र नगर निगम फरीदाबाद क्षेत्र के बाहर पड़ता है।

(ड़) क्योंकि, गांव सरूरपुर नगर निगम फरीदाबाद की सीमा के बाहर आता है और औद्योगिक क्षेत्र नंगला गांव की राजस्व संपदा अनाधिकृत क्षेत्र में स्थित है, इसलिए विकास कार्य नहीं हो सकते। इसके अलावा, वर्तमान में नगर निगम फरीदाबाद के पास गांव नंगला तक मुख्य सड़क के निर्माण/मरम्मत की कोई योजना नहीं है।

सड़कों का निर्माण करना

55. श्री नीरज शर्मा : क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री बताएंगे कि :–

(क) क्या फरीदाबाद विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र के वार्ड न. 5 के जीवन नगर पार्ट –1 तथा पार्ट –2 की मुख्य सड़कें तथा गलियां चलने योग्य हैं तथा उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उपरोक्त क्षेत्र की सड़कों तथा गलियो का निमार्ण कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है;

(ग) फरीदाबाद वार्ड न. 5, वैध रोड़ पर्वतीय कॉलोनी की मुख्य सड़कें तथा गलियां बुरी अवस्था में है;

(घ) यदि हाँ, तो उक्त सड़कों तथा गलियो का निमार्ण कार्य कब तक किए जाने की संभावना है; तथा

(ड़) क्या फरीदाबाद के वार्ड न. 5, जलधर पार्क पूरी तरह विकसित है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; यदि नहीं, तो उक्त पार्क को कब तक पूरा विकसित किए जाने की संभावना है ?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डा0 कमल गुप्ता) : (क) श्रीमान जी, जीवन नगर पार्ट–1 की सड़कें चलने योग्य हैं और इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक लगाकर बनाई गई हैं।

जीवन नगर पार्ट–2 की सड़कें कच्ची हैं। हालांकि नगर निगम फरीदाबाद ने समय–समय पर इन कच्ची सड़कों का समतलीकरण कर चलने योग्य बनाया है।

(ख) (क) भाग के उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह उपयुक्त नहीं हैं।

(ग) श्रीमान जी, नगर निगम फरीदाबाद के वार्ड नंबर–5, वैध रोड़ पर्वतीय कॉलोनी की कुछ सड़कों व गलियों की हालत ठीक नहीं है।

(घ) वर्तमान में नगर निगम फरीदाबाद के पास वार्ड संख्या–5, वैध रोड़ पर्वतीय कॉलोनी में सड़कों एवं गलियों के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ड) नगर निगम फरीदाबाद ने फरीदाबाद एन आई टी निर्वाचन क्षेत्र के जलधर पार्क को पूरी तरह से विकसित नहीं किया है। वर्तमान में इस परिसर में दो भूमिगत पानी की टंकी, एक ओवरहेड पानी की टंकी और एक सरकारी स्कूल मौजूद है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के नियमों के अनुसार इस क्षेत्र को सुरक्षा कारणों से आम जनता के लिए नहीं खोला जा सकता है क्योंकि यह परिसर पेयजल आपूर्ति के लिए उपयोग किया जाता है। इसलिए इस जलधर पार्क (बूस्टिंग कैंपस) को आम जनता के लिए पार्क के रूप में विकसित नहीं किया जा सकता है।

....

स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत विकास कार्य

56. श्री नीरज शर्मा : क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे कि:-

(क) क्या फरीदाबाद एन.आई.टी विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र के 60 फीट सड़क पर स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत किसी प्रकार के विकास कार्य निष्पादित किए जाने हैं;

(ख) यदि हाँ, तो निष्पादित किए जाने वाले कार्यों का ब्यौरा क्या है तथा उनकी लागत क्या है; तथा

(ग) उक्त कार्यों के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डॉ0 कमल गुप्ता) : हाँ, श्रीमान जी ।

(क) इस सड़क पर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई0सी0टी0) कार्यों में सम्मिलित सिविल और विद्युत कार्यों को पैन सिटी आई0सी0टी0 परियोजना के प्रस्ताव के एक भाग के रूप में लिया गया है, यह कार्य स्मार्ट सिटी परियोजना का हिस्सा है।

(ख) पैन सिटी आई0सी0टी0 परियोजना (जोकि स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का हिस्सा है) के तहत फरीदाबाद एन0आई0टी0 विधानसभा क्षेत्र की 60 फुट सड़क पर किए जाने वाले कार्यों में आई0सी0टी0 प्रणाली, स्ट्रीट लाइट, विद्युतकार्य और स्टॉर्म वाटर सुधार शामिल हैं, जिसके लिए 6.3 करोड़ रुपये की राशि खर्च होने की संभावना है, जो फरीदाबाद स्मार्ट सिटी की 26.28 करोड़ रुपये राशि से किए जाने वाले कार्य पैन सिटी आई0सी0टी0 परियोजना का हिस्सा है।

(ग) परियोजना की निविदा फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा जारी की गई थी, लेकिन दरें काफी अधिक थीं, इसलिए इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। अब, स्मार्ट सिटी मिशन दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजना को डिपॉजिट कार्य के रूप में नगर निगम फरीदाबाद को हस्तांतरित कर दिया गया है। नगर निगम फरीदाबाद द्वारा परियोजना की निविदा जारी कर दी गई है और कार्य के आवंटन की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए नियत समय में इसे पूरा किया जाएगा।

उप-मंडल बनाने के लिए मानदंड

57 श्री राकेश दौलताबाद : क्या उप-मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि -

(क) विनियमन क्या है जिनके अन्तगत जिले के उप-मण्डल बनाए गए हैं;
(ख) मौजूदा उप- को अधिक उप- मण्डलों में विभाजित या पुनः आरेखन (रिड्राइंग) करने के लिए मापदण्ड क्या है?
(ग) हरियाणा में नए उप - मण्डलों को बनाने या पुनः आरेखन (रिड्राइंग) करने की प्रक्रिया क्या है; तथा
(घ) हरियाणा में एक उप-मण्डल की औसतन जनसंख्या कितनी है?

उप-मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चैटाला) : हां, श्रीमान जी

(क) हरियाणा के राज्यपाल द्वारा पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय के परामर्श से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केंद्रीय अधिनियम) की धारा 7 की उपधारा (3) के तहत राज्य में नया उप-मण्डल बनाया जाता है।

(ख) उप-मण्डल के मापदण्ड

गांव	तहसील/उप-तहसील	पटवार सर्कल	जनसंख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	दूरी
40 व अधिक	01 व अधिक	15 व अधिक	1,00,000 व अधिक	15,000 व अधिक	जिले से 10 किलोमीटर व अधिक

(ग) सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा भेजे गये प्रस्ताव प्राप्त होने पर एवं सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर वित्त विभाग की सहमति एवं मन्त्री परिषद् की बैठक के अनुमोदन के बाद मामले को प्रेषित किया जाता है। दंड प्रक्रिया संहिता,1973 (1974 का केंद्रीय अधिनियम) की धारा 7 की उपधारा (3) के तहत माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की सहमति और विधि एवं विधायी विभाग द्वारा उचित पुननिरीक्षण के बाद गृह विभाग द्वारा नये उप-मण्डल का निर्माण बारे अधिसूचना जारी की जाती है।

(घ) जैसा उपरोक्त बिदुं न. (ख)

मौजूदा सडकों पर साईकिल लेन विकसित करना

58. श्री राकेश दौलताबाद : क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बतायेंगे कि–

(क) पैदल चालकों तथा साइकिल चालकों की अनुकूलता के लिए जिला गुरूग्राम को विकसित करने के लिए क्या पग उठाए जा रहे हैः

(ख)क्या गुरूग्राम जिले में पैदल तथा साइकिल पर यातायात प्रोत्साहन के लिए कोई कार्यक्रम सक्रिय है

(ग) क्या गुरूग्राम जिले में सडकों तथा उपरि पूलों को साइकिल चालकों के लिए अलग लेन के साथ विकसित किया जा रहा है, औरः

(घ) क्या गुरूग्राम की मौजूदा सडकों पर साइकिल लेन विकसित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): महोदय, प्रश्नों के बिन्दुवार उत्तर इस प्रकार हैं :

(क) जी0एम0डी0ए0 द्वारा बनाए जा रहे मास्टर सैक्टर डिवाईडिंग सडकों पर पैदल यात्रियों की सुविधाओं को विकसित करने के लिए 79.31 किलोमीटर फुटपाथ पर काम या तो प्रगति पर है या पूरा हो गया है। इसके अतिरिक्त, फुटपाथ कार्य की 25.30 किमी लंबाई कार्यचरण की निविदा/आवंटन में है।

(ख) पैदल और साईकिल पर परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए जी0एम0डी0ए0 में कोई कार्यक्रम नहीं है परन्तु जी0एम0डी0ए0 मैट्रोपॉलिटन एरिया के जी0एम0डी0ए0 व्यापक गतिशीलता प्रबन्धन योजना (सीएमएमपी) के अनुसार 7वीं जी0एम0डी0ए0 प्राधिकरण की बैठक में एजेंडा मद संख्या 7.13 पैदल यात्री के साथ–साथ साईकलिंग सुविधा के रूप में अनुमोदित किया गया है, जी0एम0डी0ए0 द्वारा बनाए जा रहे सभी मास्टर सडकों के साथ प्रस्तावित है।

(ग) जी0एम0डी0ए0 द्वारा बनाए जा रहे मास्टर सैक्टर डिवाईडिंग सडकों पर साईकिलिंग सुविधाओं को विकसित करने के लिए, 16.02 किलोमीटर साईकिल ट्रैक पर काम या तो प्रगति पर है या पूरा हो चुका है । इसके अलावा, 24.01 किमी लंबी साईकिल ट्रैक का काम निविदा/कार्यचरण के आवंटन में है।

(घ) जी0एम0डी0ए0 के अनुसार, गुरूग्राम मैट्रोपॉलिटन एरिया की व्यापक गतिशीलता प्रबन्धन योजना (सीएमएमपी) जी0एम0डी0ए0 प्राधिकरण की 7वीं बैठक में एजेंडा मद संख्या

7.13 पैदल चलने वालों के साथ–साथ साईकिल चलाने की सुविधा के रूप में अनुमोदित है, जी0एम0डी0ए0 द्वारा बनाए जा रहे सभी मास्टर सडकों के साथ प्रस्तावित है।

....

जल शक्ति अभियान के तहत लाभार्थी

59 श्री राकेश दौलताबाद : क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे किः–

(क) राज्य में योजना के प्रारंभ होने की तारीख से अब तक जल शक्ति अभियान के तहत लाभार्थियों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य में जल शक्ति अभियान के अंतर्गत आज तक आवंटित निधियों एवं व्ययों का ब्यौरा क्या है;

(ग) जल शक्ति अभियान की योजना के अंतर्गत पुनः उपयोग तथा रिचार्ज संरचना की कुल संख्या कितनी है तथा गुरूग्राम जिले में योजना के आरंभ होने से आज तक के अन्य ब्यौरे क्या हैं; तथा

(घ) जल शक्ति अभियान के अन्तर्गत किए गए पारंपरिक नवीनीकरण तथा अन्य जल निकायों/टैंकों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है तथा जिला गुरूग्राम में योजना के आरम्भ करने की तिथि से आज तक का ब्यौरा क्या है?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): (क) श्रीमान जी, राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत स्थानीय समुदायों को जल शक्ति अभियान के लॉन्च की तारीख से उपरोक्त हस्तक्षेपों/केंद्रित क्षेत्रों के माध्यम से लाभान्वित किया गया है।

(ख) श्रीमान जी, जल शक्ति अभियान के प्रस्तावित हस्तक्षेपों के तहत गतिविधियों को निष्पादित करने के लिए हरियाणा राज्य को जल शक्ति अभियान में अलग से कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई थी।

(ग) श्रीमान जी, गुरुग्राम जिले में जल शक्ति अभियान योजना के तहत पुनः उपयोग और पुनर्भरण संरचनाओं का योजना के शुभारंभ की तारीख से लेकर आज तक का विवरण इस प्रकार है, अधिक जानकारी Annexure – I में संलग्न हैः–

Soak Pit	1870
Other reuse/recharge structure	71
Total	1941

(घ) श्रीमान जी, गुरुग्राम जिले में जल शक्ति अभियान के तहत योजना के शुभारंभ की तारीख से अब तक कुल 35 पारंपरिक और अन्य जल निकायों/टैंकों के जीर्णोद्धार का विवरण Annexure – II में संलग्न है।

Annexure -I

Jal Shakti Abhiyan:Catch the Rain

National Water Mission, Ministry of Jal Shakti

S.NO.	Activity Name	Works Completed
Reuse and Recharge Structures		
1	Soak Pit (Urban)	500
2	Soak Pit (Rural)	1370
3	Other Reuse / Recharge Structure	71
		1941

Annexure – II

Total No. of Traditonal water bodies restored during year 2021 and 2022

Sr. No.	TRADITIONAL WATER BODIES RESTORED
S.No.	**Name of Village**
1	Mojabad
2	Iqbalpur
3	Harchandpur
4	Daula
5	Palasoli
6	Budhera
7	Garhi Wazidpur
8	Kaliawas
9	Bilaspur
10	Hariyahera
11	Bas Padamka -1
12	Taj Nagar
13	Chandla Dungarwas
14	Daultabad
15	Badshahpur
16	Dhanwapur
17	Begampur Khatola
18	Sarai Alawardi
19	Tigra

20	Sukhrali
21	Basai
22	Jhajgarh
23	Kasan
24	Rampura
25	Birhera
26	Daboda
27	Jarrau
28	Sunderpur
29	Haqdarpur
30	Jarrau-II
31	Mandawar
32	Rahaka
33	Sarhol
34	Kadipur
35	Gariatpur Bas

स्पोर्टस स्टेडियम विकसित करना

60. श्री राकेश दौलताबाद: क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि:-

(क) विनियम क्या है जिनके अन्तर्गत राज्य में खेल स्टेडियम तथा इंडोर स्टेडियम विकसित किए जाते हैं;

(ख) क्या कोई विनियमन या अध्ययन है जो यह वर्गीकृत करता है कि एक खेल को किस क्षेत्रीय तथा जनसंख्या सीमा तक पर्याप्त माना जाता है;

(ग) एक क्षेत्र में एक खेल स्टेडियम या इंडोर खेल सुविधा के विकास के लिए योग्यता क्या है; तथा

(घ) क्या जिला गुरूग्राम और बादशाहपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में विशिष्ट खेलों जैसे गोल्फ, स्केट बोर्डिंग, जिम्नास्टिक और स्क्वैश इत्यादि के लिए सरकारी सुविधाएं प्रदान की जा रही है?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : (क) व (ग) खेल स्टेडियम/ इन्डोर स्टेडियम बनाने का निर्णय स्थानीय जनता की मांग, भूमि की उपलब्धता, स्थानीय खिलाडियों की क्षमता और उपलब्धियां आसपास

के क्षेत्र में उपलब्ध खेल बुनियादी ढांचे जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

(ख) खेल विभाग ने खेल अवसंरचना बनाने का निर्णय लेने हेतु उपलब्ध खेल अवसंरचनाओं व सम्भावनाओं की जियो-मैपिंग करवाई है।

(घ) बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में गोल्फ, स्केट बोर्डिंग, जिम्नास्टिक और स्क्वैश के लिए कोई सरकारी सुविधाएं नहीं है। हालांकि, गुरूग्राम जिला में क्रिकेट, एथलैटिक्स, जुडो, कबडडी, मुक्केबाजी, तीरंदाजी, बास्केटबाल, वालीबाल, कुश्ती, टेबल-टेनिस, जिम्नास्टिक, ताईक्वाडो, भारोत्तोलन, लॉन-टैनिस और योग जैसे विभिन्न खेलों की सुविधाएं प्रदान की गई है।

गोदाम का निर्माण

61. श्रीमती नैना सिंह चौटाला: क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कृपया बताएंगे कि-

(क) क्या **बाढड़ा** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में फसल भंडारण के लिए किसी गोदान के निर्मित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, तथा

(ख) यदि हां, तो उन गांवों के नाम क्या हैं जिनके उक्त गोदाम निर्मित किए जाने की संभावना है ?

कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री (जय प्रकाश दलाल) (क) और (ख) नहीं श्रीमान, बाढड़ा विधानसभा क्षेत्र में गोदाम के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव हरियाणा राज्य भंडारण निगम के विचाराधीन नहीं है।

वातानुकूलित कुश्ती हाल का रखरखाव

62. श्रीमती नैना सिंह **चौटाला** : क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि क्या बाढड़ा विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र के गांव कलाली में खेल विभाग द्वारा वातानुकूलित कुश्ती हाल के प्रबन्ध तथा मरम्मत के लिए सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गई है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : महोदय, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग द्वारा ग्राम बलाली (ना कि ग्राम कलाली) में एक वातानुकूलित कुश्ती हाल का निर्माण किया गया है। यह हाल खेल विभाग को हैण्ड ओवर नहीं किया गया है। लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग से इसे टेक ओवर करने उपरांत खेल विभाग द्वारा इसका रखरखाव करेगा।

एच.एस.आई.आई.डी.सी. क्षेत्र को क्रशर जोन घोषित करना

63 श्रीमती नैना सिंह चौटाला: क्या उप मुख्यमन्त्री कृपया बताएंगे कि क्या जिला दादरी में क्रशर जोन को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है क्योंकि एच.एस.आई.आई.डी.सी. क्षेत्र राज्य सरकार की नीति के अनुरूप है; यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): नहीं मैडम जी, इस समय जिले दादरी में औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित क्रशर जोन की राज्य सरकार की पॉलिसी के अनुसार एच.एस.आई.आई.डी.सी. क्षेत्र के रूप में घोषित करने का कोई भी ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

....

फिरनियों का निर्माण

64. श्रीमती नैना सिंह चौटाला : क्या विकास एवं पंचायत मंत्री कृपया बताएंगे कि:–

(क) बाढ़डा विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र में गांवों की संख्या कितनी है जिनमें फिरनियां कच्ची तथा क्षतिग्रस्त हैं; तथा

(ख) क्या गांवों की उपरोक्त कच्ची तथा क्षतिग्रस्त फिरनियों को निर्मित करने की कोई योजना सरकार द्वारा बनाई जा रही है तथा इनके कब तक निर्मित किए जाने की संभावना है?

विकास एवं पंचायत मंत्री (श्री देवेन्द्र सिंह बबली) : (क) बाढड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के 43 गांवों में फिरनियां आंशिक रूप से कच्ची हैं तथा 11 गांवों की फिरनियां आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं; तथा

(ख) हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा फिरनियों पर पक्की/metalled सड़क बनाई जाती हैं। इस बारे विकास एवं पंचायत विभाग के विचाराधीन कोई योजना नहीं है।

....

पात्रता के मापदण्ड को परिवर्तित करना

65. श्री प्रदीप चौधरी: क्या स्कूल शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे कि:–

(क) क्या यह तथ्य है कि राज्य में गणित अध्यापक के लिए आवेदन करने के लिए वे व्यक्ति योग्य नहीं हैं जिन्होंने गणित के साथ स्नातक तथा गणित शिक्षण के रूप में गणित के साथ बी0एड0 की है;

(ख) क्या लोकहित में योग्यता मापदण्ड परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ताकि वे व्यक्ति जिन्होंने गणित के साथ स्नातक तथा गणित षिक्षण के रूप में गणित के साथ बी.एड. की है गणित अध्यापक के लिए आवेदन करने के लिए योग्य हो सके; यदि हां, तो उपरोक्त प्रस्ताव के कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

शिक्षा मंत्री, (श्री कंवर पाल) : (क) व (ख) नहीं, श्रीमान् जी।

....

तेंदुए द्वारा मारे गए पालतू पशुओं की कुल संख्या

66. श्री प्रदीप चौधरी : क्या पशुपालन एवं डेयरी मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या गत् चार वर्षों के दौरान पंचकूला जिले में तेंदुए द्वारा मारे गए पालतू पशुओं की कुल संख्या कितनी है तथा उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्हें मुआवजे का भुगतान किया गया है तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव, मंत्री (श्री कंवर पाल)) :श्रीमान, पंचकूला जिले में गत् चार वर्षों के दौरान तेंदुए द्वारा 55 पालतू पशुओं को मारने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें से निम्नलिखित 19 लोगों को उनके मारे हुए पालतू पशुओं का मुआवजा दिया जा चुका है व शेष 36 शिकायतें प्रक्रिया में हैं-

क्र सं	नाम और पता	मृत पशुओं का नाम	मुआवजा
1	श्री सोमनाथ पुत्र श्री दीपराम गांव नोलटा, पंचकूला	गाय की बछडी	6000
2	श्री तरसेम सिंह पुत्र श्री लाल सिंह गांव अमबुआ, मोरनी, पंचकूला	गाय	12000
3	श्री जगतराम पुत्र श्री परशुराम गांव खण्यो भोजकोटी, पंचकूला	कटडी	7000
4	श्री श्यामप्रकाश पुत्र श्री मस्तराम गांव मदहेडी, ठंठोग, पंचकूला	बकरी	3500
5	श्री प्रदीप सिंह पुत्र श्री नानकचंद गांव भूडी, मोरनी, पचंकूला	कटडा	7000
6	श्री हैप्पी पुत्र श्री जगदीश गांव बरूण, मोरनी, पंचकूला	गाय	12000
7	श्री नरंजन पुत्र श्री देशराज गांव उतरों, मोरनी, पंचकूला	कटडा	7000
8	श्री जयपाल सिंह पुत्र श्री बस्तीराम	कटडा	7000

	गांव कुण्डल, मोरनी, पंचकूला		
9	श्री दलबीर सिंह पुत्र श्री हेमराम गांव सेहत कूना, भोज नग्गल, मोरनी पंचकूला	बकरी	3500
10	श्री जीत सिंह पुत्र श्री हीरा सिंह गांव चपलाना भोजकोटी, पंचकूला	गाय	12000
11	श्री नानकचंद पुत्र श्री केशोराम गांव ढाकवाला, पंचकूला	बछडा	6000
12	श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री चरण कुमार गांव बरोटीवाला, टिक्करहिल्स, पचंकूला	गाय	12000
13	श्री राजपाल पुत्र श्री तुलसीराम गांव उतरों भोजनग्गल, पंचकूला	गाय	12000
14	श्री दीपक कुमार पुत्र श्री जोगीन्दर सिंह गांव भूडी, पंचकूला	बैल	12000
15	श्री प्रीतम सिंह पुत्र श्री तुलाराम गांव बयूला भोजनग्गल, पंचकूला	बकरी	3500
16	श्री कमल सिंह पुत्र श्री रमेश गांव चाखली भोजकोटी, पंचकूला	बैल	12000
17	श्री पवन कुमार पुत्र श्री सुन्दर सिंह गांव चपलाना, मोरनी, पंचकूला	गाय	12000
18	श्री देशराज पुत्र श्री धुलीचंद गांव जोनपुर मटोर, पंचकूला	भैंस	30000
19	श्री सतीश कुमार पुत्र श्री बाला राम गांव ठाठर, मोरनी, पंचकूला	गाय	12000

मानदेय बढ़ाना

67. श्री प्रदीप चौधरी : क्या विकास एवं पंचायत मंत्री कृपया बताएंगे कि पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने तथा उन्हें टोल फ्री की सुविधाएं देने का भी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा उसका ब्यौरा क्या है?

विकास एवं पंचायत मंत्री (श्री देवेन्द्र सिंह बबली) नहीं, श्रीमान।

....

एक्सप्रैस–वे पर आउटलैट कट

68. चौ॰ आफताब अहमद: क्या उप-मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे -

(क) दिल्ली मुम्बई ग्रीन **एक्सप्रैस**–वे पर नूंह तथा पलवल के लोगों के लिए निर्धारित योजना तथा सरकारी आश्वासन के पश्चात भी खेड़ा-खलीलपुर-मंडकोला के.एम.पी जंक्शन तथा फरीदाबाद, **एक्सप्रैस**–वे जंक्शन पर आउटलैट कट उपलब्ध न कराए जाने के कारण क्या हैं; तथा

(ख) उक्त **एक्सप्रैस**–वे पर मरोडा - खानपुर घाटी - नगीना पर सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद आउटलैट कट निर्मित न किए जाने के कारण क्या हैं तथा उसका ब्यौरा क्या है?

उप मुख्यमंत्री (श्री **दुष्यंत चौटाला**)**:** (क) के.एम.पी., **एक्सप्रैस**–वे और डी.एन.डी.-फरीदाबाद-बल्लभगढ़-के.एम.पी. लिंक के साथ दिल्ली-मुंबई ग्रीनफील्ड , **एक्सप्रैस**–वे का इंटरसेक्शन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई) के अधिकार क्षेत्र में आता है। एन.एच.ए.आई ने आउटलैट कट प्रदान करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है क्योंकि यह इंटरचेंज की जटिलता के कारण संभव नहीं है, जिसे तीन , **एक्सप्रैस**–वे के साथ-साथ वे साइड सुविधाओं की कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हालांकि, मंडकोला-सिलानी रोड और के.एम.पी. , **एक्सप्रैस**–वे के इंटरचेंज के निर्माण की व्यवहार्यता का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) एन.एच.ए.आई ने उक्त **एक्सप्रैस**–वे पर मरोडा - खानपुर घाटी - नगीना सड़क के लिए आउटलैट कट प्रदान करने के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है क्योंकि इसे व्यवहार्य नहीं माना गया था।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जल आपूर्ति

69. चौ. आफताब अहमद : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कृपया बताएंगे कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत नूंह जिले में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को कितनी मात्रा में जल उपलब्ध करवाया जा रहा है तथा गत् तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (डॉ. बनवारी लाल) : श्रीमान जी, वर्तमान वर्ष 2022-23 में 50 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की औसत दर से ग्रामीण क्षेत्र में जल आपूर्ति की जा रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान औसत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल आपूर्ति का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

I.	वर्ष 2019-20	- 45 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
II.	वर्ष 2020-21	- 46 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
III.	वर्ष 2021-22	- 48 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन

प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय का निर्माण

70. चौ0 आफताब अहमद : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे कि:–

(क) क्या यह तथ्य है कि वर्ष 2014 में नूंह शहर में हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड द्वारा शिक्षा विभाग को भूमि स्थानांतारित की गई थी जिस पर प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय का निर्माण होना था; तथा

(ख) यदि हां, तो गत 8 वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा निष्पादित कार्यों का ब्यौरा क्या है तथा 8 वर्षों की देरी के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों के नाम क्या हैं तथा सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाही की गई ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कंवर पाल):

(क) हां, श्रीमान् जी ।

(ख) विभाग द्वारा दिनांक 19–01–2022 को जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, नूंह से नूंह शहर में राजकीय प्राथमिक विद्यालय/राजकीय माध्यमिक विद्यालय के निर्माण कार्य हेतु अनुमान प्राप्त होने के उपरान्त दिंनाक 20–01–2022 को 146.10 लाख रुपये की धन राषि की स्वीकृति की गई व हरियाणा विद्यालय शिक्षा परियोजना परिषद (एच0एस0एस0पी0पी0) को यह धन राषि हस्तांनतरित कर दी गई। इसका निर्माण कार्य अप्रैल, 2023 में आरम्भ होने की सम्भावना है। राज्य सरकार के निर्णय अनुसार सभी निविदाएं पोर्टल के माध्यम से जारी की जानी हैं, किन्तु हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल में तकनीकी कारणों

के चलते हरियाणा विद्यालय शिक्षा परियोजना परिषद (एच0एस0एस0पी0पी0) द्वारा निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हो सका । भवन के निर्माण कार्य में विलम्ब जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, नूंह के स्तर पर हुआ है, क्योंकि वर्ष 2015 से 2021 तक इस सम्बन्ध में उन द्वारा कोई पत्राचार नही किया गया। श्री वजीर चन्द म़जोका, श्रीमती ज्ञानवती और श्री कपिल कुमार पुनिया इस विलम्ब के लिए जिम्मेदार हैं जो वर्ष 2015 से 2021 तक कार्यरत रहे। सरकार द्वारा इन सभी दोशी अधिकारियों के विरूद्ध आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाही की जायेगी।

यूनानी महाविद्यालय के निर्माण में विलम्ब

71. चौ. आफताब अहमद: क्या आयुष मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या नूंह जिले के गांव अकेड़ा में निर्माणाधीन यूनानी महाविद्यालय के कार्य में के क्या कारण हैं तथा कितने समय से लंबित है तथा उक्त महाविद्यालय में कक्षाएं कब से आरम्भ किए जाने की संभावना है ?

आयुष मंत्री (श्री अनिल विज): श्रीमान जी, राजकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, अकेड़ा का निर्माण कार्य कार्यकारी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें), नूंह द्वारा संचालित किया जा रहा है। अब तक 52 फीसदी निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। जैसे ही भवन पी0डब्ल्यू0डी0 (बी0एंडआर0) द्वारा सौंप दिया जाएगा, कक्षाएं शुरू करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाएगी।

....

नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलना

72. श्री सीता राम यादव : क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या अटेली विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र के खंड अटेली के गांव चन्दपुरा एवं गढ़ी रुथल तथा खंड कनीना में गांव नांगल एवं रामबास में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो इन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के कब तक खोले जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज): नहीं, श्रीमान जी।

....

ग्राम ज्ञान केंद्रों की संख्या

73. श्री सीता राम यादव :: क्या विकास एवं पंचायत मंत्री कृपया बताएंगे कि अटेली विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र की 95 पंचायतों में अब तक कितने ग्राम ज्ञान केंद्र खोले गए हैं तथा शेष गांवों में ग्राम ज्ञान केन्द्र कब तक खोले जाने की संभावना है?

विकास एवं पंचायत मंत्री (श्री देवेन्द्र सिंह बबली) : अटेली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की 95 पंचायतों में से 9 ग्राम ज्ञान केन्द्रों का निर्माण हरियाणा दीन बन्धु ग्राम उदय योजना (नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित) के अन्तर्गत करवाया गया है। जैसे ही अटेली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के गांवों में ग्राम ज्ञान केन्द्र खोलने हेतु प्रस्ताव/मांग प्राप्त होगी, उनका निर्माण राशि की उपलब्धता तथा योजना के दिशानिर्देशों के आधार पर करवा दिया जाएगा।

सामुदायिक केंद्र की कुल संख्या

74. श्री सीता राम यादव: क्या विकास एवं पंचायत मंत्री कृपया बताएंगे कि अटेली विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र की 95 पंचायतों में अब तक कुल कितने सामुदायिक केंन्द्रों का निर्माण किया गया है तथा शेष गांवों में सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है?

विकास एवं पंचायत मंत्री (श्री देवेन्द्र सिंह बबली) : अटेली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की 95 पंचायतों में किसी भी सामुदायिक केन्द्र का निर्माण नहीं हुआ है। जैसे ही सामुदायिक केन्द्र के निर्माण हेतु कोई मांग प्राप्त होगी, तो उसकी जाँच उपरान्त, बजट की उपलब्धता तथा योजना के दिशानिर्देशों अनुसार कार्यवाही कर ली जाएगी।

....

शराब घोटाले की जांच

75. श्री अभय सिंह चौटाला : क्या गृह मंत्री कृपया बताएंगे कि –

(क) क्या यह तथ्य है कि वर्ष 2020 में शराब घोटाले की जांच के लिए सरकार द्वारा विशेष जांच दल का गठन किया गया है, यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है, तथा

(ख) क्या उक्त रिपोर्ट में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा कोई कार्रवाही की गई है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या है?

गृह मंत्री (अनिल विज) : नहीं श्रीमान् जी

(क) कोरोना काल में लाक डाउन के दौरान खरखौदा में शराब तस्करी की जांच के लिए सरकार ने एस.आई.टी. का गठन नहीं किया है।

वास्तव में आदेश संख्या 6/2/2020-2एच.सी. दिनांक 11.05.2020 के तहत, गृह विभाग, हरियाणा ने खरखौदा-मटिंडू रोड, सोनीपत, हरियाणा में अस्थायी गोदाम में बरामद शराब के स्टॉक से चोरी के मामले की जांच करने के लिए श्री टी.सी. गुप्ता, आईएएस, अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, विद्युत, अधिकारिता, नवीकरणीय ऊर्जा एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (एस.ई.टी.) का गठन किया। दिनांक 30.07.2020 को, विशेष जांच दल (एस.ई.टी.) ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी जिसमें रिपोर्ट में उल्लिखित चूकों के लिए व्यक्तिगत अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की सिफारिशें और आबकारी विभाग के कामकाज में व्यवस्थित सुधार के लिए सुझाव/अनुशंसित उपाय भी शामिल हैं।

पत्र क्रमांक 20/64/2020-3एस.1) दिनांक 25.08.2020 के माध्यम से मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार (कार्मिक विभाग) ने अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग और प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी और कराधान विभाग को विशेष जांच दल की रिपोर्ट की प्रति सहित एस.ई.टी की सिफारिशों पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतू भेजने के

साथ-साथ सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि पूरे मामले की जांच राज्य सतर्कता ब्यूरो द्वारा की जाए। तदनुसार, मुख्य सचिव हरियाणा सरकार (कार्मिक विभाग) ने सतर्कता विभाग को राज्य सतर्कता ब्यूरो द्वारा उपरोक्त मामले की जांच करने का निर्देश दिया।

इसके अतिरिक्त, श्री संजीव कौशल, आईएएस, मुख्य सचिव हरियाणा सरकार की एक सदस्यीय समिति बनाई गई जो कि निम्नलिखित टीमों/समितियों की रिपोर्ट और सिफारिशों का अध्ययन करेगा और विभिन्न विभागों द्वारा किए जाने वाले आवश्यक सुधारात्मक उपायों की पहचान करेगा और चूककर्ताओं के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई शुरू करेगा:-

1. श्री टी.सी. गुप्ता, आईएएस के नेतृत्व में गठित एस.ई.टी।
2. सुश्री कलारामचंद्रन, आईपीएस की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट ।
3. श्री श्रीकांत जाधव, आईपीएस की अध्यक्षता में गठित एस.आई.टी.।
4. राज्य सतर्कता ब्यूरो द्वारा की जा रही जांच ।

मामला अभी विचाराधीन है।

(ख) पुलिस महानिदेशक, हरियाणा द्वारा श्रीमति कला रामचन्द्रन, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया कि विशेष जांच दल द्वारा दी गई रिपोर्ट जिसमें पुलिस विभाग के स्तर पर पाई गई अनियमितता की जांच करे तथा सुनिश्चित करे कि शराब की उत्पत्ति/स्त्रोत के मामलों में जांच अधिकारियों द्वारा की गई विफलता की जिम्मेदारी तय करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करे। श्रीमति कला रामचन्द्रन, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर 14 मामलों में 27 पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई है।

<u>आगे, आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा की गई कार्यवाही निम्न प्रकार से है:-</u>

हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड एवं अपील) नियम, 2016 के नियम 7 के तहत सात ए.ई.टी.ओ. तथा 01 ए.ई.टी.ओ. को हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड एवं अपील) नियम, 2016 के नियम 8 के तहत आरोप पत्र जारी किया गया जिन्होंने 27.03.2020 से 31.03.2020 की अवधि के दौरान परमिट स्वीकृत किए थे, जबकि शराब की दुकानों को कोविड़-19 महामारी लॉकडाउन के कारण बंद होने के लिए आदेश दिया गया था। इनमें से एक मामले में सक्षम प्राधिकारी ने यथोचित निर्णय लेते हुए 01 ए.ई.टी.ओ जिसे नियम 7 के तहत चार्जशीट किया गया था का निपटान कर दिया है। शेष 07 मामलों में विभागीय कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्त के अलावा, उपरोक्त अवधि के दौरान परमिट और पास जारी करने के लिए 16 आबकारी निरीक्षकों को हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड एवं अपील) नियम, 2016 के नियम 7 के तहत चार्जशीट किया गया है। उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

कुल बकाया ऋण तथा ब्याज की राशि

76. श्री वरुण चौधरी: क्या सहकारिता मंत्री कृपया बताएंगे कि 31 मार्च 2017 **तथा** 31 मार्च 2022 **तक** हरियाणा राज्य के किसानो **की** कुल बकाया ऋण तथा ब्याज कितना है ?

सहकारिता मंत्री (डॉ० बनवारी लाल) : श्रीमान जी, 31 मार्च 2017 व 31 मार्च 2022 में की स्थिति के अनुसार हरियाणा राज्य के किसानों पर कुल ऋण और ब्याज निम्मानुसार हैं :-

हरको बैंक

राशि लाखों में

क्रम संख्या	वर्ष	कुल कृषि ऋण	बकाया ब्याज	कुल
1	31.03.2017 के अनुसार	870741.52	205746.78	1076488.30
2	31.03.2022 के अनुसार	1205925.65	258775.62	1464701.27

एच.एस.सी.ए.आर.डी.बी.

राशि लाखों में

क्रम संख्या	वर्ष	कुल कृषि ऋण	बकाया ब्याज	कुल
1	31.03.2017 के अनुसार	151923.06	104193.38	256116.44
2	31.03.2022 के अनुसार	109414.64	141322.97	250737.61

हरको बैंक व एच.एस.सी.ए.आर.डी.बी. की कुल अतिदेय ऋण एवं ब्याज की राशि:

राशि लाखों में

क्रम संख्या	वर्ष	कुल कृषि ऋण	बकाया ब्याज	कुल
1	31.03.2017 के अनुसार	1022664.58	309940.16	1332604.74
2	31.03.2022 के अनुसार	1315340.29	400098.59	1715438.88

....

पंजीकृत होम स्टे की संख्या

77. श्री वरूण चौधरी: क्या विरासत एवं पर्यटन मंत्री कृपया बताएंगे कि राज्य में होम स्टे योजना 2021 के अर्न्तगत पंजीकृत होम स्टे की जिलावार संख्या कितनी है तथा इसकी क्या प्रतिक्रिया रही अर्थात क्या परिणाम मिला ?

विरासत एवं पर्यटन मंत्री (श्री कंवर पाल) पंजीकृत होम/फार्म हाउस स्टे का जिलेवार विवरण निम्न अनुसार है :–

क्रम संख्या	जिले का नाम	पंजीकृत होम स्टे	पंजीकृत फार्म स्टे	जोड़
1	गुरूग्राम	––	17	17
2	फरीदाबाद	––	2	2
3	सोनीपत	––	2	2
4	झज्जर	––	2	2
5	हिसार	––	1	1
6	करनाल	––	2	2

7	मेवात	--	2	2
8	पंचकूला	2	2	4
	कुल	2	30	32

प्रदेश में होम स्टे एवं फार्म टूरिज्म योजना लागू होने से ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिला है । घर/खेत के मालिक की आय में अतिरिक्त वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं । आगंतुकों को ग्रामीण संस्कृति, रीति–रिवाजों, खान–पान और गतिविधियों के बारे में जानकारी/अनुभव प्राप्त होता है। यह योजना प्रतिस्पर्धी मूल्य–बिंदुओं पर विभिन्न ग्रामीण स्थानों पर आवास के बहुत सारे विकल्प प्रदान करेगी । इस योजना से पर्यटन और आत्म–विकास में स्थानीय समुदायों की भागीदारी भी बढेगी ।

खेल नर्सरियों की संख्या

78. श्री वरूण चौधरी : क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि क्या राज्य में युवा खेल प्रतिभाओं की पहचान करने के लिए जिलावार कितनी खेल नर्सरियां खोली गई तथा राज्य सरकार द्वारा तथा सार्वजनिक क्षेत्र इकाईयों/निजी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा चलाई जा रही खेल नर्सरियों की संख्या कितनी है?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) :श्रीमान, जिलावार खेल नर्सरियों का विवरण निम्न प्रकार से है -:

विवरण

संख्या	जिला	विभागीय प्रशिक्षकों द्वारा संचालित नर्सरियों की संख्या	सरकारी/निजी संस्थानों में संचालित नर्सरियों की संख्या
1.	अम्बाला	19	08
2.	भिवानी	35	34
3.	चरखी दादरी	18	09
4.	फरीदाबाद	12	15
5.	फतेहाबाद	12	21
6.	गुरूग्राम	16	12
7.	हिसार	27	40
8.	झज्जर	32	36
9.	जीन्द	24	39
10.	कैथल	19	38

11.	करनाल	25	33
12.	कुरूक्षेत्र	28	23
13.	महेन्द्रगढ़	02	16
14.	नूंह	06	14
15.	पलवल	06	12
16.	पंचकूला	22	13
17.	पानीपत	19	21
18.	रेवाड़ी	20	22
19.	रोहतक	36	32
20.	सिरसा	17	20
21.	सोनीपत	29	42
22.	यमुनानगर	08	16
	कुल	**432**	**516**

वृक्ष गणना एवं जियो टैगिंग

79. श्री वरूण चौधरी: क्या वन मंत्री बताएंगे कि क्या हरियाणा राज्य में वृक्ष की गणना पर तथा प्रत्येक वृक्ष की जियोटैगिंग पर क्या कार्यवाई की गई है?

वन मंत्री (श्री कंवर पाल): हां, वृक्षों की गणना एवं जियोटैगिंग का कार्य सितम्बर, 2022 में शुरू कर दिया गया था तथा वनों के बाहर खड़े वृक्षों की गणना तथा जियोटैगिंग का कार्य प्रत्येक गांव, कस्बा तथा शहर में पूर्ण कर लिया गया है। गणना किए गए वृक्षों से संबंधित विश्लेषण का कार्य प्रगति पर है।

नौकरियों के बैकलॉग का ब्यौरा

80. श्रीमती गीता भुक्कल: क्या मुख्यमंत्री कृप्या बताएंगे किः–

(क) राज्य में अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए रिक्त पड़े आरक्षित पदों का वर्गवार/कैडरवार ब्यौरा क्या है, तथा

(ख) क्या अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों के बैकलॉग को भरने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): महोदय जी, स्थिति पूर्ण विवरण सहित विधान सभा के पटल पर रखी है।

(क) राज्य में अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए बैकलॉग सम्बंधी आरक्षित रिक्त पदों का वर्गवार विवरण दिनांक 31.03.2022 के अनुसार निम्न प्रकार से हैः–

अनुसूचित जाति

	ग्रुप 'क'	ग्रुप 'ख'	ग्रुप 'ग'	ग्रुप 'घ'
सरकारी विभाग, जिसमें आयुक्त एवं उपायुक्त सम्मिलित हैं (85)	01	126	3821	1143
सार्वजनिक उपक्रम (61)	86	29	440	329
कुल	**87**	**155**	**4261**	**1472**

पिछड़ा वर्ग 'ए'

	ग्रुप 'क'	ग्रुप 'ख'	ग्रुप 'ग'	ग्रुप 'घ'
स्रकारी विभाग, जिसमें आयुक्त एवं उपायुक्त सम्मिलित हैं (85)	02	172	2326	1137
सार्वजनिक उपक्रम (61)	16	14	341	242
कुल	**18**	**186**	**2667**	**1379**

पिछड़ा वर्ग 'बी'

	ग्रुप 'क'	ग्रुप 'ख'	ग्रुप 'ग'	ग्रुप 'घ'
सरकारी विभाग, जिसमें आयुक्त एवं उपायुक्त सम्मिलित हैं (85)	02	42	2493	818
सार्वजनिक उपक्रम (61)	07	05	229	185
कुल	**09**	**47**	**2722**	**1003**

(ख) मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के द्वारा अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए पहले से ही हिदायतें दिनांक 24.09.2013, 27.05.2014, 11.09.2015 और 04.05.2018 सभी सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों को पहले से ही जारी की हुई हैं। सभी सरकारी विभाग/सार्वजनिक उपक्रम तदानुसार अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों से संबंधित बैकलॉग को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं।

सदस्यों की अनुपस्थिति के संबंध में सूचना देना

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री भव्य बिश्नोई, विधायक ने मुझे पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि वे निजी व्यस्थतता के चलते दिनांक 22 एवं 23 फरवरी, 2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकेंगे।

इसी प्रकार से श्री सुरेन्द्र पंवार, विधायक ने ई–मेल के माध्यम से मुझे सूचित किया है कि वे अस्वस्थ होने के कारण आज दिनांक 22 फरवरी, 2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

इसी प्रकार से श्री संदीप सिंह, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, राज्य मंत्री ने ई–मेल के माध्यम से मुझे सूचित किया है कि वे बीमार होने के कारण आज दिनांक 22 फरवरी, 2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

....

राजकीय आरोही मॉडल स्कूल, ग्योंग, जिला कैथल, राजकीय आरोही मॉडल स्कूल, घासो खुर्द, जिला जीन्द एवं राजकीय आरोही मॉडल स्कूल, रामगढ़ पांडवा के विद्यार्थियों तथा अध्यापकगण का अभिनंदन

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि राजकीय आरोही मॉडल स्कूल, ग्योंग, जिला कैथल, राजकीय आरोही मॉडल स्कूल, घासो खुर्द, जिला जीन्द एवं राजकीय आरोही मॉडल स्कूल, रामगढ़ पांडवा के विद्यार्थी तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूँ।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, आज सदन की कार्यवाही देखने के लिये आरोही मॉडल स्कूल्ज के विधार्थी एवं अध्यापकगण आये हुए हैं, इसलिए मेरा

आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, जो प्रदेश के वित्त मंत्री भी हैं, उनसे अनुरोध है कि आरोही मॉडल स्कूल्ज की जितनी भी टीचर्ज, बच्चों आदि से संबंधित समस्याएं हैं उनको भी दूर करने का प्रयास किया जाए।

श्री अध्यक्षः बहन गीता जी, आपका यह राजनीतिक भाषण ठीक नहीं है। आप हर जगह राजनीतिक बातें करती हैं। बहन गीता जी, आप कोई समय तो छोड़ दिया करो। बहन जी, यदि आपको आरोही स्कूल के बारे में कुछ कहना ही है तो इस संबंध में आप अपना प्रश्न लगा सकती थी।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, हाउस में इससे संबंधित मेरा प्रश्न लगा था और उसका जवाब दिया गया था, इसीलिए मैंने यह प्रश्न किया है ।

श्री अध्यक्ष : गीता जी, अब बच्चों के सामने इस प्रश्न को उठाने की क्या जरूरत है?

....

हरियाणा विधान सभा सचिवालय में हिन्दी भाषा में कार्य कराने के सम्बन्ध में सूचना

माननीय सदस्यगण, मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि हरियाणा विधान सभा सचिवालय में प्रायः ऐसा देखने में आ रहा था कि हरियाणा विधान सभा सचिवालय का अधिकतर कार्य मुख्यतः अंग्रेजी में किया जा रहा था जबकि हरियाणा प्रदेश में मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषा हिन्दी है । राज्य के लोगों की भाषा के रूप में हिन्दी भाषा का प्रयोग हमारे दिन–प्रतिदिन के काम–काज में किया जाए । विभिन्न राज्यों में उनकी क्षेत्रीय भाषाएं अधिकारिक कार्यों एवं निर्देशों के लिए अंग्रेजी भाषा की जगह ले रही है । भारतीय संविधान के अनुच्छेद–343 के अनुसार हिन्दी राज्य की अधिकारिक भाषा है । भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सभी राज्यों को क्षेत्रीय भाषाओं का प्रावधान किया गया है । वर्ष 1969

में हरियाणा राजभाषा अधिनियम की धारा–3 के प्रावधान के अनुसार हिन्दी को हरियाणा की अधिकारिक भाषा घोषित किया गया, इसलिए मैंने दिनांक 3 फरवरी, 2023 को हरियाणा विधान सभा सचिवालय में अधिकारिक कार्य/निर्देशों, परिपत्र, अधिसूचना, नोटिंग (टिप्पणी–लेखन), सत्र का कार्य हिन्दी में तत्काल प्रभाव से किये जाने के आदेश दिये । मैंने यह भी आदेश दिए कि कार्यालय में जो पत्र हिन्दी भाषा में आते हैं, उनका जवाब केवल हिन्दी भाषा में ही दिया जाए और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग मात्र दूसरे राज्यों से पत्राचार एवं कुछ कानूनी दस्तावेजों के संबंध में करना स्वीकार्य होगा । इन आदेशों की एक प्रति मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा के प्रधान सचिव को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सूचनार्थ हेतू भेज दी गई थी ।

....

अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के राजस्थान के जयपुर में आयोजित 83वें सम्मेलन में पारित किए गए 9 संकल्पों के बारे में सदन को सूचित करना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं सदन को सूचित करना चाहता हूँ कि अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 83वां सम्मेलन 10 जनवरी से 12 जनवरी, 2023 तक जयपुर में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में मैंने, उपाध्यक्ष, श्री रणबीर गंगवा जी ने एवं सचिव, हरियाणा विधान सभा ने भी भाग लिया। उपरोक्त सम्मेलन में नौ संकल्प पारित किए गए। जिसकी प्रति सभी माननीय सदस्यों के पठन के लिए नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन के पटल पर रख दी गई है।

सम्मेलन के संकल्प 1 में भारत सरकार और भारत की संसद को जी–20 राष्ट्रों के समूह और संसद–20 (पार्लियामेंट–20) की अध्यक्षता ग्रहण करने पर अभिनंदन किया गया और भारत को 'लोकतंत्र की जननी' के रूप में प्रस्तुत करने

और समता, समावेशिता, बंधुत्व, शांति और संवहनीय जीवनशैली के लिए वैश्विक नेतृत्व को पूर्ण समर्थन देने का संकल्प किया गया।

यह सदन भी भारत की संसद को जी–20 राष्ट्रों के समूह की अध्यक्षता ग्रहण करने पर गौरवान्वित है और भारत को मिले वैश्विक नेतृत्व को पूर्ण समर्थन देने का संकल्प करता है।

संकल्प 2 में राष्ट्र के विधायी निकायों के माध्यम से कानून बनाने में भारत की जनता की प्रधानता में अपना पूर्ण विश्वास व्यक्त किया गया और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए राज्य के सभी अंगों को हमारे संविधान में निर्दिष्ट संवैधानिक सीमाओं का सम्मान करने का आहवान किया गया।

यह सदन भी कानून बनाने में भारत की जनता की प्रधानता में अपना विश्वास व्यक्त करता है। संविधान में विधायिका/कार्यपालिका/न्यायपालिका के बीच शक्तियों का जो विभाजन किया गया है उसका हम सभी सम्मान करते हैं और यह आशा करता है कि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका भी संविधान में निर्दिष्ट शक्तियों के पृथ्ककरण के सिद्धांत का पालन करे ।

संकल्प 3 में नव स्वतंत्र राष्ट्र के समक्ष ज्वलंत विषयों के समाधान के संदर्भ में संविधान सभा के सदस्यों के अनुकरणीय आचरण को ध्यान में रखते हुए तथा सहयोग, सामंजस्य एवं विभिन्न विचारधाराओं के समन्वय की भावना के अनुरूप यह संकल्प किया गया कि विधायी निकायों की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों की व्यापक रूप से समीक्षा की जाएगी और सदस्यों की अधिक भागीदारी तथा विधानमंडलों की सभाओं के सार्थक कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करते हुए आदर्श समरूप नियम प्रक्रियाएं बनाई जाएं;

और यह कि अमर्यादित तथा असंसदीय आचरण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु नियम प्रक्रियाओं में सदस्यों के लिए आचार संहिता को शामिल किया जाए।

यह सदन भी इस बात को स्वीकार करता है कि विधायी निकायों के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों की विस्तृत रूप से समीक्षा की जानी चाहिए ताकि सदस्यों की अधिक से अधिक भागेदारी हो सके।

संकल्प 4 में हमारे विधायी निकायों में कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सदस्यों द्वारा सरकार से प्रश्न पूछे जाने के समयसिद्ध साधन के महत्व को स्वीकार करते हुए सभी राजनैतिक दलों को आहवान किया गया कि वे आम सहमति से यह निर्णय लें कि विधानमंडलों की सभाओं में, विशेष रूप से प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उत्पन्न न किया जाए।

यह सदन भी मानता है कि कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए इसलिए इस विधान सभा ने हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 45 ए के अंतर्गत यह प्रावधान किया है कि प्रत्येक सदस्य प्रति माह तीन सवाल पूछ सकते है। सभी राजनैतिक दलों का यह कर्त्तव्य है कि प्रश्नकाल के दौरान सदन में व्यवधान उत्पन्न ना हो क्योंकि अगर प्रश्नकाल में व्यवधान उत्पन्न हुआ तो सदस्य अपने सभी प्रश्न का जवाब सरकार से प्राप्त नहीं कर पायेंगे।

संकल्प 5 में हमारे विधानमण्डल के संचालकों के रूप में समितियों की भूमिका को पहचानते हुए, समिति प्रणाली को सशक्त करने और कार्यपालिका के कार्य की समीक्षा की सीमा और दायरे को बढ़ाने के लिए भारत में सभी विधायी निकायों से सार्थक कदम उठाने का आहवान किया गया।

यह सदन भी मानता है कि समिति प्रणाली को ज्यादा से ज्यादा सशक्त किया जाना चाहिए। साथ ही कार्यपालिका के कार्य की समीक्षा भी समय–समय

पर होती रहनी चाहिए। समिति प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से पिछले वर्ष आठ तदर्थ समिति गठित करने का फैसला लिया गया था। सदन ने अब बजट की समीक्षा के लिए अलग–अलग मांगों पर आठ स्थायी समिति गठित की जा चुकी है।

संकल्प–6 में संघ और राज्य विधानमंडलों के कार्य प्रबंधन में वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त करने के लिए बैठक में संकल्प लिया गया कि अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के अध्यक्ष को राज्य सरकारों से विस्तृत विचार–विमर्श हेतु अधिकृत किया जाए।

80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन में केवड़िया गुजरात में हुए (25 और 26 नवम्बर, 2020) को राज्यों के विधानमंडलो ने अपनी वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त करने के लिए संकल्प किया था तथा शताब्दी सत्र के अवसर पर 17 से 19 दिसंबर, 2021 को शिमला में आयोजित हुए सम्मेलन में यह फैसला लिया गया था कि सभी राज्य विधानसभाओं में वित्तीय अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए और इसी के तहत महासचिव, लोकसभा ने मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के उनके पत्र दिनांक 31 दिसंबर, 2021 द्वारा हरियाणा सरकार से अनुरोध किया था कि हरियाणा विधान सभा के साथ परामर्श के साथ वित्तीय स्वतायत्ता पर विचार किया जाए। यहां यह भी बताना उचित है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने विधान सभा को वित्तीय स्वायत्ता देने की घोषणा सम्मेलन के दौरान कर दी थी।

संकल्प–7 में यह संकल्प लिया गया कि भारत में सभी विधायी निकाय अधिक दक्षता, पारदर्शिता और परस्पर संपर्क की दृष्टि से विधायी निकायों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल ग्रिड में भाग लेने हेतु सभी कदम उठाएंगे।

हरियाणा विधान सभा भी इस दिशा में प्रयासरत है और इसी के तहत अगस्त, 2022 से नेवा पोर्टल पर कार्य करना शुरू कर दिया गया है हम चाहते

है कि पर्यावरण की दृष्टि से कागज का प्रयोग कम से कम किया जाए तथा सभी कार्य डिजिटल माध्यम से हो ताकि विधान सभा के सभी कार्य पारदर्शिता से और परस्पर संपर्क प्रभावी रूप से हो सके।

संकल्प 8 में सदस्यों की प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण भागीदारी को बढ़ावा देने और विधायिका के कार्यकरण की कार्योत्पादकता बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों को मान्यता देने के उद्देश्य से इस संकल्प को दोहराया गया है कि एक निष्पक्ष प्रणाली के माध्यम से चुने गए विधायी निकायों हेतु वार्षिक आधार पर एक उत्कृष्ट विधायिका पुरस्कार की शुरूआत की जाये।

यह सदन हर वर्ष उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार की शुरूवात बहुत पहले कर चुका है। इसका उद्देश्य यह है कि सदस्यगण विधानसभा के कार्यों में अपनी अत्याधिक रूचि लें ताकि समाज के ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। यह सदन उत्कृष्ट विधायिका एवं विधायी निकायों हेतु वार्षिक पुरस्कार की शुरूआत का स्वागत करता है। निश्चय ही इस पुरस्कार से विधायिका की कार्योत्पादकता बढ़ेगी।

संकल्प 9 में यह संकल्प लिया गया कि समाज के सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं और युवाओं को संवैधानिक प्रावधानों तथा विधायी नियमों और प्रक्रियाओं की जानकारी देने के सभी संभव प्रयास किए जाएं।

इस संदर्भ में हमारा यह प्रयास है कि विधान सभा के नियमों/प्रक्रियाओं की जानकारी विद्यार्थियों, महिलाओं तथा समाज के सभी वर्गों को दी जाएं। इसी के तहत हम ज्यादा से ज्यादा स्कूलों/विश्वविद्यालयों के बच्चों को, अध्यापकों को सदन की कार्यवाही दिखाने के लिए निरंतर बुलाते रहते है ताकि हमारी युवापीढ़ी भी इस बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो सके। हमने विधान सभा सत्रों की

कार्यवाही का लाईव प्रसारण भी शुरू कर दिया है ताकि समाज के ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। यह आपके सूचनार्थ था ।

....

शून्यकाल में भाग लेने के लिए सदस्यों के नामों के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब शून्यकाल शुरू होता है। जो माननीय सदस्य शून्यकाल पर बोलेंगे मैं एक बार उनकी सूची पढ़ देता हूं। श्री सुभाष गांगोली जी, श्री बलबीर सिंह, श्री सत्य प्रकाश जरावता जी, श्री जगदीश नायर जी, श्री मोहम्मद इलियास जी, श्री शमशेर सिंह गोगी जी, श्री मामन खान जी, श्री भारत भूषण बतरा जी, श्री चिरंजीव राव जी, श्री नयन पाल रावत जी, श्री सोमवीर सांगवान जी, श्री कुलदीप वत्स जी, श्री असीम गोयल जी, श्री ईश्वर सिंह जी, श्री बिशम्बर सिंह जी, श्रीमती निर्मल रानी जी, श्रीमती किरण चौधरी जी, श्रीमती गीता भुक्कल जी, श्री घनश्याम सर्राफ जी, राव दान सिंह जी, श्री लीला राम जी, श्री नरेन्द्र गुप्ता जी, श्री बलराज कुंडू जी, श्री अमित सिहाग जी, श्री प्रमोद विज जी, श्री प्रदीप चौधरी जी, श्री रामनिवास जी, श्री राकेश दौलताबाद जी, श्री घनश्याम दास अरोड़ा जी, श्री राम कुमार कश्यप जी, श्री अमरजीत ढांडा जी और श्री दीपक मंगला जी आदि। (शोर एवं व्यवधान) मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जो माननीय सदस्य कल बोल चुके हैं, उनको आज की सूची में शामिल नहीं किया जायेगा इसलिए जो माननीय सदस्य कल नहीं बोल पाये थे, उनमें श्री मोहन लाल बड़ौली जी हैं क्योंकि वे बीमार थे, इसलिए नहीं बोल पाये थे।

श्री राकेश दौलताबाद : अध्यक्ष महोदय, मुझे कल भी शून्यकाल पर बोलने के लिए समय नहीं दिया गया था। कल दिनांक 23.02.2023 को शून्यकाल होगा या नहीं।

श्री अध्यक्ष : दौलताबाद जी, कल शून्यकाल नहीं है कल सिर्फ बजट है। आज 12 माननीय सदस्यों को बोलने के लिए 5–5 मिनट का समय दिया जायेगा। अब श्री मोहन लाल बड़ौली जी बोलेंगे।

श्री मोहन लाल बड़ौली : अध्यक्ष महोदय, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं आज बोलना नहीं चाहता हूं।

....

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों/स्थगन प्रस्तावों/गैर सरकारी संकल्पों/अल्पावधि चर्चा के प्रस्तावों और प्राइवेट मैम्बर बिल के बारे में सूचना

श्री वरुण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमने जो कॉलिंग अटैंशन मोशन और शॉर्ट ड्यूरेशन मोशन दिए हैं उनका क्या फैट है?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे कॉलिंग अटैंशन मोशंज 68 प्राप्त हुए हैं। इनमें से ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 13 के साथ ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 57 संलग्न है जो कि दिनांक 21.2.2023 के लिए स्वीकृत थी, इसको अन्य तिथि के लिए स्थगित कर दिया गया है। मुझे श्री वरुण चौधरी विधायक, श्री भारत भूषण बतरा विधायक और श्री आफताब अहमद विधायक द्वारा प्रदेश में हरियाणा बिल्डिंग कोड को बार–बार संशोधित कर स्टिल्ट जमा चार मंजिला घरों को बनाने की अनुमति देने के विरोध बारे अल्प अवधि चर्चा संख्या–1 प्राप्त हुई है, जिसे मैंने ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 50 में परिवर्तित कर दिया है। मुझे श्री नीरज शर्मा, विधायक द्वारा ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 42 प्राप्त हुई है जो कि समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 50 के साथ संलग्न कर दिया है और जिसे मैंने दिनांक 22.2.2023 के लिए स्वीकृत भी कर लिया है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि ऐसी 63 ध्यानाकर्षण सूचनाएं अभी विचाराधीन हैं और एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए सरकार से कमैंट्स मांग लिये हैं। मुझे दो

एडजर्नमैंट मोशंज भी प्राप्त हुए हैं, जो अभी विचाराधीन है। दो नॉन ऑफिशियल रैजोल्यूशंज प्राप्त हुए हैं जो अभी विचाराधीन हैं। इसके अतिरिक्त मुझे अल्प अवधि चर्चा के लिए दो सूचनाएं प्राप्त हुईं हैं जिनमें से एक विचाराधीन है और एक अल्प अवधि चर्चा को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में कन्वर्ट कर दिया गया है। एक प्राइवैट मेम्बर बिल आया था लेकिन विधेयक में कुछ कमियां होने के कारण उसे संबंधित विधायक को वापस भेज दिया गया है। इसके अलावा सरकार की तरफ से हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक, 2023 का बिल आया है।

....

शून्य काल में विभिन्न मामले/मांगे उठाना

श्री अध्यक्ष: अब श्री सुभाष गांगोली जी जीरो आवर में अपनी बात रखेंगे।

श्री सुभाष गांगोली: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सफीदों के अन्दर एक नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज से 4 साल पहले किया था और इसकी जमीन भी ट्रांसफर हो चुकी है। मिट्टी और पानी का भी टैस्ट हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, इस कॉलेज के साथ ही 6 और भी नर्सिंग कॉलेज बनाने की घोषणा हुई थी वे सभी लगभग बन चुके हैं परन्तु सफीदों के नर्सिंग कॉलेज का जिन सौ ईंटों की दीवार बनाकर शिलान्यास किया गया था वहां पर अब वे सौ ईंट भी नहीं हैं। सफीदों के इस कॉलेज बनाने की घोषणा पर कोई भी अमल नहीं हुआ। इसे फरवरी, 2019 में बनाने की घोषणा हुई थी, आज इस घोषणा को पूरे 4 साल हो चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, इस नर्सिंग कॉलेज की बच्चियों की क्लासिज गर्ल्स कॉलेज के अन्दर लगती हैं क्योंकि इस कॉलेज का निर्माण आज तक भी शुरू नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, कॉलेज के निर्माण और बसों के संचालन के लिए बच्चियां डायरेक्टर मैडिकल एजुकेशन के ऑफिस में गई थीं तब उनके सामने

किसी ने अनअथॉराइज रूप से शंका जताई कि आपके इस नर्सिंग कॉलेज को सफीदों से दूसरी जगह भी ले जाया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पैरा मैडिकल कॉलेज की घोषणा की थी और उसकी भी कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर की बात है जबकि वहां तो जमीन भी ट्रांसफर हो चुकी है और क्लासिज भी लगती हैं। सफीदों के नर्सिंग कॉलेज की 650 के लगभग बच्चियों की क्लासिज गवर्नमैंट कॉलेज में लगती हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि इस नर्सिंग कॉलेज की बिल्डिंग का निर्माण जल्दी से जल्दी करवाया जाए ताकि यहां पढ़ने वाली बच्चियां अपनी क्लासिज सुचारू रूप से ले सकें। **(इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्या श्रीमती सीमा त्रिखा पदासीन हुई।)** सभापति महोदया, इसी प्रकार से दिनांक 20.02.2023 को जीन्द जिले के 8 ब्लॉक के सरपंच डी.सी. साहब, को एक ज्ञापन देना चाहते थे और उनका इरादा सिर्फ ज्ञापन देने का था। जब सरपंच डी.सी. साहब को ज्ञापन देने ऑफिस में गये तो उनके सामने तहसीलदार और नायब तहसीलदार को भेज दिया गया और उन्हें कहा गया कि डी.सी. साहब व्यस्त हैं। सरपंचों ने इस बात पर जोर दिया कि हम ज्ञापन सिर्फ डी.सी. साहब को ही देंगे लेकिन इसकी एवज में सरपंचों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। सभापति महोदया, सरकार ने एक व्यवस्था तो महिलाओं को पंचायतों में 50 प्रतिशत आरक्षण देकर कर दी लेकिन सरकार को एक व्यवस्था और भी करनी चाहिए थी कि यदि कोई महिला सरपंच प्रदर्शन करे तो उस प्रदर्शन में उनके साथ केवल महिला पुलिसकर्मी ही व्यवस्था संभाले और अगर लाठीचार्ज करना पड़े तो वह महिला पुलिसकर्मियों द्वारा ही किया जाए। इस प्रदर्शन में जो महिला सरपंच थीं उनको पुरुष पुलिसकर्मियों ने लाठियों से पीटा जो कि निंदनीय है,

अलोकतांत्रिक है और किसी भी तरह से सहन करने योग्य नहीं है। सभापति महोदया, लाठीचार्ज करने के बाद डी.सी. साहब ने कल ज्ञापन लिया है, जबकि वह ज्ञापन परसों भी लिया जा सकता था। जबकि सरपंच सिर्फ और सिर्फ ज्ञापन देना चाहते थे। अध्यक्ष महोदय, ज्ञापन देना और प्रदर्शन करना सबका अधिकार है। इस प्रकार की अलोकतांत्रिक प्रक्रिया को सरकार को नहीं अपनाना चाहिए और इस घटना की निन्दा इस पूरी सदन को करनी चाहिए। सभापति महोदया, इसी प्रकार से हमारी सफीदो की नगर पालिका में खुद की इन्कम बहुत कम है इसलिए इसको विशेष अनुदान दिया जाए ताकि यहां के विकास कार्य हो सके। इसी प्रकार से मैं गर्ल्ज कॉलेज, पिल्लूखेड़ा की बात करना चाहता हूं। उसकी जमीन भी ट्रांसफर हो चुकी है। पिछले साल से उसकी क्लॉसिज पिल्लूखेड़ा के गवर्नमैंट स्कूल में लग रही हैं। मेरी यह मांग है कि उस बिल्डिंग को भी जल्दी से जल्दी बनाया जाये। इसी प्रकार से मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे जींद–पानीपत जिले का जो एरिया एन.सी.आर. के अंदर आते हैं उसमें पोल्ट्री का बहुत बड़ा व्यवसाय है। उसमें ऐसी व्यवस्था करनी होती है जिसके लिए 24 घंटे बिजली की निरंतर जरूरत रहती है। जो पॉल्यूशन बोर्ड ऑफ इंडिया है उसने वहां पर जैनरेटर सैट्स को प्रतिबंधित किया हुआ है। मेरी सरकार से मांग है कि पोल्ट्री को असैंशियल चीजों की श्रेणी में लाकर उनको जैनरेटर सैट यूज करने की इजाजत दी जाये ताकि वे अपना काम सुचारू रूप से कर सकें। वहां पर एक काम और बड़ा जोर शोर से चला हुआ है जिसमें पॉल्यूशन बोर्ड ऑफ इंडिया के अधिकारी आते हैं और हमारी यूनिटों का बिजली का कनैक्शन कटवाकर जाते रहते हैं और उस कनैक्शन को जुड़वाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है उसका हमें ही पता है। 20–20 दिन तक हमारा वह कनैक्शन वापिस नहीं जुड़ पाता। मैंने इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को

भी ज्ञापन दिया था। मैं तो यही निवेदन करता हूं कि मुख्यमंत्री जी को मैंने जो ज्ञापन दिया है उस बारे में भारत सरकार से बात करके हमें इसकी इजाजत दिलवाई जाये। इसी प्रकार से मैं यह बताना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में डॉक्टरों की बहुत ज्यादा भारी कमी है। जहां पर 12 डॉक्टर्ज की जरूरत है वहां पर एक भी डॉक्टर नहीं है। ऐसे ही मेरे हल्के के डाथल गांव की सी.एच.सी. की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। उसका निर्माण कार्य भी जल्दी से जल्दी करवाया जाये। रजाना कला में जमीन स्वास्थ्य विभाग को ट्रांसफर हो चुकी है इसलिए वहां पर भी पी.एच.सी. का निर्माण करवाया जाये।

श्री बलबीर सिंह (इसराना) : धन्यवाद सभापति महोदया जी। मेरे हल्का इसराना में ग्राम मोहदीनपुर–थिराना की पंचायत ने एक प्रस्ताव ग्राम सभा के माध्यम से पास किया है। उनकी मांग है कि इस गांव का नाम थिराना किया जाये। मैं बताना चाहता हूं कि मेरे हल्का इसराना में एक गांव खुखराना है। जोकि एक नरक की जिन्दगी जी रहा था। उसको शिफ्ट करने का काम 2012–13 में चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने सी.एम. रहते हुए किया था। उसी समय उन मकानों की मुआवजा राशि तय की गई थी परन्तु उनका काम आज तक शुरू नहीं हुआ। तब से आज तक मकान बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत है उनका भाव लगभग तीन गुणा बढ़ गया है इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि आज के भाव के हिसाब से उन मकान मालिकों को मुआवजा बढ़ाकर दिया जाये। एक बात मैं यह बताना चाहता हूं कि क्लर्क वैल्फेयर एसोसिएशन हरियाणा ने भी एक मांग पत्र सभी विधायकों, मंत्रियों और सभी जिला उपायुक्तों को दिया कि क्लर्क बहुत काम करते हैं काम के हिसाब से वेतन बहुत कम है इसलिए सी.ए.डब्ल्यू.एस. चाहती है कि उनका वेतन बढ़ाया जाये। यदि सरकार द्वारा वेतन नहीं बढ़ाया जाता है तो सी.ए.डब्ल्यू.एस. भविष्य में कोई भी कदम उठाने के लिए मजबूर

होगी। इसी प्रकार से एक ज्ञापन आई.टी.आई. अनुदेशक संघ, भारतीय मजदूर संघ ने भी दिया है कि आई.टी.आई. विभाग द्वारा एच.पी.एस.सी. की एडवरटाईजमैंट नम्बर 12/2019 के तहत अनुदेशकों की नियमित आधार पर भर्ती पूर्ण करने के उपरांत नवचयनित स्थायी अनुदेशकों को ज्वाईनिंग स्टेशन देने हेतू लगभग 11 वर्षों से स्वीकृत पदों पर पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत लगे अनुबंध आधार के अनुदेशकों को सरप्लस बताकर नौकरी से निकालने का काम किया गया। 526 अनुदेश्कों को 13.02.2023 को हटाने का नोटिस दिया गया वर्तमान में खाली पदों की संख्या बहुत ज्यादा है इसलिए इन 526 परिवारों के पालन पोषण व उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए इनको रोजगार से न हटाया जाये। इन अनुदेशकों की सरकार के अधिकारियों से 3 बार मीटिंग हुई है। उन्होंने इन अनुदेशकों को यह आश्वासन दिया है कि उनको नहीं हटाया जायेगा। उनके विश्वास दिलाने के बावजूद भी इनको हटाने का काम सरकार ने किया है सभापति महोदया, हमारे जो भाई बहन सरकारी कर्मचारी लगे हुए हैं वे ओल्ड पैन्शन स्कीम (ओ.पी.एस.) की मांग को लेकर लगातार शांतिपूर्ण तरीके से धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रजातंत्र में हर किसी को धरना प्रदर्शन करने का हक है और अपनी मांगें रखने का हक है। जब वे शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो पंचकूला में पुलिस द्वारा उनको बेरहमी से लाठी और डंडों से पीटा गया, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गये और उन पर पानी की बौछारें की गई। उन पर बहुत अधिक अत्याचार हुआ है। मैं उसकी कड़े शब्दों में निन्दा करता हूं और आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि ओ.पी.एस. लागू करने की उनकी जो मांग है सरकार उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उनकी मांग को पूरा करे। अब मैं इसराना और मतलौडा के बस स्टैंड के बारे में अपनी बात रखना चाहता हूं। मैंने सदन में 3 बार अपना प्रश्न लगाया था कि इसराना और मतलौडा ब्लॉक में बस स्टैंड नहीं

हैं और इसके कारण दोनों जगह बहुत दिक्कत है। वहां पर 35–36 गांव हर ब्लॉक में लगते हैं। मुझे तीनों बार सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री, उप–मुख्यमंत्री तथा मंत्री जी द्वारा विश्वास दिलाया गया था कि मार्च, 2022 तक उक्त दोनों बस स्टैंड बना दिये जायेंगे लेकिन आज तक वहां पर एक ईंट भी नहीं लगी है। जब मुझे दिसम्बर, 2021 के सत्र में विश्वास दिलाया गया था कि मार्च, 2022 में उक्त बस स्टैंड बनवा दिये जायेंगे तब मैंने कहा था कि जब वहां पर आज तक कुछ भी काम नहीं हुआ है तो आप किस प्रकार से मार्च, 2022 तक काम पूरा कर देंगे। उस समय मैंने मतलौडा बस स्टैंड के शौचालय की बात उठाई थी कि जब तक नया बस स्टैंड नहीं बन जाता तब तक पुराने बस स्टैंड पर एक महिला शौचालय की व्यवस्था की जाये। तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे सदन में यह विश्वास दिलाया था कि मार्च, 2022 तक आपको नया बस स्टैंड बना कर दे देंगे लेकिन आज तक इसराना और मतलौडा में नया बस स्टैंड नहीं बना है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि उक्त दोनों जगह पर नये बस स्टैंड यथाशीघ्र बनाए जायें। धन्यवाद।

(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)

श्री सत्य प्रकाश जरावता (पटौदी): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और हरियाणा सरकार का आभार व्यक्त करता हूं कि इस बजट सत्र में माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में एक तरफ जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डिवैल्पमैंट के लिए नये–नये प्रोजैक्ट्स हैं वहीं दूसरी तरफ समाज कल्याण के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए और किसानों के कल्याण के लिए बहुत सारे काम किये गये हैं। सभी नागरिकों के प्रति करूणा और मैत्री का भाव रखते हुए सबको एक समान रखते हुए हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे को

आगे बढ़ाते हुए प्रदेश की आधी आबादी को चिरायु योजना से जोड़ कर उनके स्वास्थ्य की चिन्ता और उनके परिवार के लिए प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री अन्न वितरण योजना के तहत उनके परिवार के लिए अन्न की चिन्ता की है। उपाध्यक्ष महोदय, चाहे महिलाओं की बात हो या महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की बात हो, चाहे एम.एस.एम.ई. की नई योजनाओं से बेरोजगारों को आत्मनिर्भर बना कर उद्योग स्थापित करने की बात हो, चाहे मैरिट के आधार पर नौकरियों की बात हो, हर विषय पर प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में नये आयाम स्थापित किये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने संत रविदास जयंती पर पदोन्नति में आरक्षण देकर अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के लिए ऑक्सीजन का काम किया है। वर्ष 2001 में जब देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बने थे, उन्होंने 85 वां संविधान संशोधन किया और पूरे देश के अन्दर वह संशोधन लागू हुआ परन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि 22 वर्ष बाद अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी घोषणा की है। इसकी घोषणा वर्ष 2015 में भी की गई थी लेकिन कुछ तकनीकी रूकावटों की वजह से वह लागू नहीं हो सका। अब सभी तकनीकी रूकावटों को दूर करते हुए अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने का काम किया गया है। शायद पूरे देश के अन्दर हरियाणा एक पहला राज्य है जहां क्लास–1 और क्लास–2 की पदोन्नति में आरक्षण नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि या तो रोस्टर के अनुसार सिनयोरिटी देकर पदोन्नति में आरक्षण किया जाए या रिजर्वेशन देकर एस.सी., एस.टी. के कर्मचारियों को क्लास–1 और क्लास–2 में रिजर्वेशन में प्रमोशन देकर उनको बराबरी का हक दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि 27.5.2015 का प्रदेश सरकार का प्रमोशन में रिजर्वेशन को रोकने

का ऑर्डर है उसको विद्ड्रा किया जाए और 01.01.2020 का जो ऑफिस मैमोरैंडम है जिससे रोस्टर बैन किया गया था उसको भी प्रदेश सरकार विद्ड्रा करे क्योंकि तमाम कोर्ट के केस खत्म हो चुके हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इलाके में जमीन की बन्दर बांट और जो लूट–खसोट हुई है उसका परिणाम हम आज तक भुगत रहे हैं। उसमें 912 एकड़ मानेसर की, 5200 एकड़ कासन की, खो की, पचगांव की और 162 एकड़ अली अरढ़ाना की जमीन है। इस प्रकार से करीब–करीब 8000 एकड़ जमीन पिछली सरकार के समय में ओणे–पोणे दामों में किसानों को डरा धमका कर छीनी गई थी।

श्री उपाध्यक्ष : सत्य प्रकाश जी, आपका समय हो गया है।

श्री सत्य प्रकाश जरावता : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अभी समय रह रहा है क्योंकि मैंने माननीय मोहन लाल बड़ौली जी उनकी पांच मिनट ली हुई हैं इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि मुझे अपना पूरा समय बोलने दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : मोहन लाल बड़ौली जी का समय आपका समय थोड़ी है।

श्री सत्य प्रकाश जरावता : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की हुई है। उन्होंने मुझे अपनी पांच मिनट बोलने के लिए कहा है। माननीय मुख्यमंत्री ने अब गांव कासन के किसानों को 92 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ 67 लाख रुपये देने का जो निर्णय लिया है उससे हमारे किसानों को फायदा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : सत्य प्रकाश जी, आपका समय हो गया है।

श्री सत्य प्रकाश जरावता : उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो मेरे इलाके की सारी डिमांड्स पर बोलना रह रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : सतयप्रकाश जी, बाकी आप लिखकर दे दें उसको प्रोसिडिंग का पार्ट बना दिया जाएगा। आप बजट पर बोल लेना।

***श्री सत्य प्रकाश जरावता** : उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से 2200 एकड़ जमीन जो किसानों के दबाव में रिलीज की उसको एग्रीकल्चर जोन बनाकर छोड़ दिया और मास्टर प्लान 2025 बदल दिया गया। मेरा अनुरोध है कि गुरूग्राम–मनेसर मास्टर प्लान 2025 को पुनः बहाल किया जाए। इसी तरह से मोकलवास–श्वरखड़ी–ततारपुर बास लाम्बी के गांवों की 2200 एकड़ जमीन को पुनः औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जाए। इसी तरह से हरियाणा स्कूल शिक्षा परिषद परियोजना के तहत नियुक्त एजुकेशन वॉलंटियर को मिनिमम वेजिज दिये जाएं। इसी तरह से वी.एल.डी.ए. से पदोन्नत बी.एल.इ.ओ. को राज पत्रित पद घोषित किया जाए और इसमें पदोन्नति में अनुसूचित जाति की सीटें आरक्षित की जाएं। इसी के साथ स्कूलों व कार्यालयों में जो सफाई कर्मचारी पार्ट टाईम कार्यरत हैं उनको मिनिमम वेजिज दिये जाएं और इन्हें नियमित किया जाए। इसी के साथ अनुसूचित जाति का सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में सभी ग्रुपों में बैक लॉग पूरा किया जाए। इसी के साथ शिक्षा विभाग में कार्यरत मिनिस्ट्रियल स्टाफ की समस्याओं का समाधान किया जाए। इसी के साथ ग्राम पंचायतों की बिना ई–टैंडरिंग की राशी की सीमा बढ़ाई जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ प्रतिनिधि मंडल कर्मचारियों/अधिकारियों के ज्ञापन मिले हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि आई.टी.आई. विभाग जिसका अब नाम बदलकर युवा अधिकारिता और उद्यमिता विभाग कर दिया गया है। पिछले 10 वर्षों से डी.सी. रेट पर कार्यरत विभिन्न ट्रेडों के अनुदेशक जिनकी जगह नये स्थाई अनुदेशक आ गये हैं को विभाग में रिक्त अन्य पदों पर स्थानान्तरित किया जाए और नई ट्रेड्स आरम्भ की जाएं तथा कौशल विकास केन्द्र आरम्भ कर इनको समायोजित क्योंकि

***चेयर के आदेशानुसार उपरोक्त स्पीच को प्रोसिडिंग्ज का पार्ट बनाया गया।**

इनमें ज्यादाती अनुदेशक ओवरऐज भी हो चुके हैं। इसी के साथ नगरपालिका, नगरपरिषद और नगरनिगम में सम्मिलत हुए गांव में लाल डोरा के अन्दर निर्माण के लिए नक्शे पास और विकास शुल्क, ग्रह शुल्क से मुक्त रखा जाए। इसी के साथ पटोदी विधान सभा के लगभग 46 स्कूलों की बिल्डिंग्ज जर्जर हैं उनमें कुछ नई बननी हैं और कुछ में पुराने कमरों की मुरम्मत होनी है तथा उनमें शौचालयों व चार दीवारी का कार्य होना है उसको शीघ्र करवाने का कष्ट करें। इसके साथ ही कृषि भूमि को व्यक्तिगत ऋण, व्यापार एवं उद्योग, गृहनिर्माण, शादी–विवाह के लिए लिये गये ऋण के बदले मार्केट रेट या सर्कल रेट के 50 प्रतिशत तक ऋण की एवज में मोर्गेज करने का नियम बनाकर मंजूरी देने का कार्य करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी कुछ महत्वपूर्ण मांगे मेरे विधान सभा क्षेत्र पटोदी की हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि मरे क्षेत्र में हरियाणा राज्य परिवहन की बसों की बहुत कमी है। वहां कुछ रूटों से बसें बंद कर दी गई हैं। आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 100 बसें हरियाणा राज्य परिवहन रेवाड़ी–गुरूग्राम–चण्डीगढ़–हरिद्वार–मथुरा–आगरा–हिसार–भिवानी–जयपुर और लोकल बसों पर चलाई जाए तथा के.एम.पी. पंचगांव, मानेसर में नये बस स्टैंड का निर्माण किया जाए। इसी के साथ नगर निगम मानेसर में भवनों के रिहायशी और व्यवसायिक तथा औद्योगिक भवनों के नये नक्शे पास करवाने आरम्भ किये जाएं। इसी क साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार 64 हजार नौकरियां देगी और चालु वित्त वर्ष में 13 हजार 275 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। ग्रुप सी एवं डी के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा लोकसेवा आयोग 1862 नौकरियां चिरायु योजना के तहत एक लाख अस्सी हजार वाले 29 लाख परिवारों के 46 लाख 7 हजार चिरायु कार्ड बनाए गए।

श्री जगदीश नायर : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जीरो हावर पर बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। आज हमारी मनोहर लाल जी के नेतृत्व की सरकार ने आई.एम.टी. की घोषणा, मैडिकल कॉलेज की घोषणा, रेलवे लाईनें बिछाने की घोषणा, राष्ट्रीय राज मार्ग बनाने की घोषणा, जल जीवन मिशन और 24 घंटे बिजली देने पर काम करने की घोषणा की है। हमारी सरकार गरीब कल्याण का लक्ष्य रखकर चलने वाली, अन्त्योदय पर चलने वाली, किसान कल्याणकारी नीति बनाकर किसान का भला करने वाली, एस.सी., बी.सी. को ऊपर उठाने वाली योजना बनाने वाली सरकार है। मैं इन योजनाओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। पिछले 20 साल की तुलना में आज हरियाणा की तस्वीर में नया हरियाणा दिखाई देता है। उपाध्यक्ष महोदय, आप बिजली के क्षेत्र में देखें तो बिजली के क्षेत्र में चारों तरफ गावों में बिजली की लाईनें बिछाई जा रही हैं, बिजली के खम्बे लगाए जा रहे हैं। अगर पानी के क्षेत्र को देखें तो गांवों में पानी की पाईप लाईन बिछाई जा रही हैं, बुस्टर स्टेशन बनाए जा रहे हैं। ये सभी जनहित के कार्य हैं। अगर लॉ एण्ड ऑर्डर की बात करें तो कोई भी व्यक्ति 112 नम्बर पर कॉल करता है तो केवल 8 मिनट में उसकी सुरक्षा के लिए टीम पहुंचने का काम करती है। यह जनहित की सरकार है जिसका श्रेय माननीय मनोहर लाल जी को जाता है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही यह कल्याणकारी सरकार, गरीब लोगों के लिए अनेक योजनायें लेकर आई है। गरीब के कल्याण करने की दिशा में गरीब की लड़की को शगुन देने की योजना शुरू की गई है। श्रम लोन देने की योजना के तहत अढ़ाई लाख रूपये से चार लाख रूपये तक का लोन देने का काम किया जाता है जोकि निश्चित तौर पर काबिले–ए–तारीफ है। महिला श्रमिक उधमित योजना के तहत 5 लाख रूपये तक का लोन देने का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत यदि

महिलायें अपना कोई समूह बनाकर काम करना चाहती हैं तो यह योजना उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए बहुत मददगार साबित होगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने गरीबों का उद्धार कैसे हो, अंतिम व्यक्ति का भला कैसे हो, इस तरह की योजनाएं लाकर, ऐसे लोगों को एक बहुत बड़ा लाभ देने का काम किया है। 10 रूपये की थाली योजना बनाई गई है। हमारे प्रदेश में बहुत से लोग भूखे ही सो जाते हैं लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के दिशा–निर्देशन में 10 रूपये की थाली योजना शुरू करने का फैसला लिया गया है जिसकी वजह से 10 रूपये में भरपेट खाना मिलेगा। हमारे जिलों में और हर कस्बे में यह योजना अब चल भी रही है। यह कोई छोटी योजना नहीं है। पहले की सरकारों ने तो इस बारे में कभी सोचा तक नहीं था कि गरीब का पेट कौन भरेगा और गरीब लोग कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। पशुपालन के लिए लोन देने की योजना शुरू की गई है। मुफ्त राशन योजना शुरू की गई है। आवास योजना के लिए 482 करोड़ रूपये खर्च करने का काम किया गया है। यह कोई छोटी बात नहीं है। गरीब व्यक्ति जिनके पास मकान नहीं होता है, उनको सरकार इस योजना के तहत मकान बनाकर देने का काम कर रही है। आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रूपये तक मुफ्त इलाज का प्रावधान किया गया है। चिरायु योजना ताकि हरियाणा का आदमी लंबी आयु जिए, यह योजना भी शुरू की गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी का यह करिश्मा ही है कि आज अस्पतालों में लाइनें लगी रहती है। लोग निःशुल्क जांच कराने का काम करते हैं। सारी बीमारियों की फ्री में जांच करवाकर, गरीब आदमी बड़ा अच्छा महसूस करता है। आज लगता है कि प्रदेश में वास्तव में ही सरकार नाम की कोई चीज है। पहले की सरकारों ने कभी भी इस तरह की योजनाओं पर ध्यान देने का काम नहीं किया था। आज

हर गरीब आदमी को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अपना पानी–अपनी विरासत, प्रधानमंत्री बीमा योजना शुरू की गई है। जिसका उद्देश्य यही है कि किस तरह से किसान का भला किया जा सकता है। कैसे किसान उन्नति कर सकता है और कैसे किसान को बर्बादी से रोका जा सकेगा तथा किस प्रकार से किसान के जोखिम का मुआवजा दिया जा सकेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री बीमा योजना लाकर ऐसे जोखिमों के समाधान का प्रावधान करने का काम किया गया है। निरोगी हरियाण योजना के तहत हरियाणा में कोई भी निरोगी न रहे, इसके लिए डाक्टरों की भर्ती करना तथा डाक्टरों का स्टॉफ बढ़ाने का काम किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, बातें बहुत हैं आखिर किस किस का मैं जिक्र करूं। गरीब के इलाज के 14 नए 100 बैड के सी.एस.आई. अस्पताल खोलने का काम किया गया है। कृषि कल्याण के लिए 33.79 करोड़ रूपये खर्च करने का काम किया गया है। बागवानी पर 10.26 करोड़ रूपये खर्च करने का काम किया गया है। नहरी तंत्र को सुधारने के लिए 500 करोड़ रूपये खर्च करके किसान को मजबूत करने का काम किया गया है। (घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं शॉर्ट में अपनी बात कहूंगा क्योंकि आपकी घंटी बज चुकी है। अब मैं अपने होडल विधान सभा क्षेत्र की तस्वीर प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कुछ साथी शोर मचा रहे थे। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः नायर जी, आपका बोलने का समय पूरा हो चुका है। आप प्लीज बैठिए। आपको जो बात रखनी है, इसके बारे में बजट पर चर्चा के दौरान बोल सकते हैं।

मोहम्मद इलियास (पुन्हाना): सबसे पहले नायब सदर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने मुझे जीरो आवर पर बोलने का समय दिया। नायब सदर साहब पूरे सदन को मालूम है और यही नहीं पूरा देश और प्रदेश इस घटना के

बारे में जानता है जोकि अभी राजस्थान के घाटमिका गांव में घटी है। हरियाणा के कुछ गलत अनासिर, यहां से गए और गोतस्करी के आरोप में दो भाइयों को किडनैप करके हरियाणा प्रदेश में लेकर आए। किडनैप तो हो जाया करते हैं लेकिन सबसे बड़े अफसोस की बात तो यह है कि हरियाणा प्रदेश के सी.आई.ए. के लोगों ने इन गलत अनासिर लोगों के साथ मिलकर किडनैप करने का काम किया। मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा अत्याचार, माइनोरिटी के साथ और दूसरा नहीं हो सकता है। मैं सदन के माध्यम से हरियाणा सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या पुलिस, किडनैप जैसे कृत्यों को करने के लिए बनाई गई है। अगर यह बात मान भी ली जाये कि गऊ रक्षकों की सहायता के लिए यह लोग ऐसा काम करते हैं तो मैं यह बात साफ कर देना चाहूंगा कि मेवात क्षेत्र का कोई भी आम और खास गऊ हत्या नहीं करना चाहता है और न ही कोई इस काम को शह देता है। आज तक इस बात की तफ्तीश नहीं हो पाई कि उनको गऊ रक्षक पकड़ कर लाई है या फिर पुलिस पकड़ कर लाई है।***

श्री महीपाल ढाण्डा: उपाध्यक्ष महोदय, RSS वाले ऐसा काम नहीं करते हैं। माननीय सदस्य को सोच–समझ कर ही सदन में बोलना चाहिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, ने जो RSS से संबंधित बात कही है, उसे रिकॉर्ड न किया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कंवर पाल: उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य इस प्रकार के 50 बार आरोप लगा चुके हैं लेकिन आज तक कोई सिद्ध नहीं कर पाये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

***चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।**

श्री महीपाल ढाण्डाः उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह के काम कांग्रेस पार्टी वाले ही कर सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

मोहम्मद इलियासः उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात पूरी तो हो जाने दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कंवर पालः उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यगण ही इस प्रकार के काम करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

मोहम्मद इलियासः उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरा टाइम जरूर नोट कर लेना। (शोर एवं व्यवधान)

श्री महीपाल ढाण्डाः उपाध्यक्ष महोदय, आप माननीय सदस्य को सदन से बाहर करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री शीशपाल सिंह केहरवालाः उपाध्यक्ष महोदय, ढाण्डा साहब की भाषा ठीक नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला खटकः उपाध्यक्ष महोदय, श्री महीपाल जी ऐसा कहने वाले कौन होते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

राव चिरंजीवः उपाध्यक्ष महोदय, महीपाल जी को सदन में ठीक ढंग से बोलना चाहिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः सभी माननीय सदस्यगण, अपनी–अपनी सीटों पर बैठ जाईये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री महीपाल ढाण्डाः उपाध्यक्ष महोदय, पहले उनको कहिए कि वे अपनी–अपनी सीटों पर बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः सभी माननीय सदस्यगण, अपनी–अपनी सीटों पर बैठ जाइये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री महीपाल ढाण्डाः उपाध्यक्ष महोदय, पहले वे शब्द प्रोसीडिंग में से निकलवाए जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः मैं सभी माननीय सदस्यों से अपील करता हूँ कि यदि आप लोगों को कोई बात कहनी है तो चेयर को एड्रैस करके ही कहिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कंवर पालः उपाध्यक्ष महोदय, RSS दुनिया की सबसे बड़ी स्वयं सेवी संस्था है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी माननीय सदस्य को शोभा नहीं देती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आफताब अहमदः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि ढाण्डा जी को सदन में इस तरह नहीं बोलना चाहिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः इलियास जी, आप किसी का भी नाम नहीं ले सकते। (शोर एवं व्यवधान)

मोहम्मद इलियासः उपाध्यक्ष महोदय, क्यों नहीं ले सकते, जब उन्होंने ऐसा काम किया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः उपाध्यक्ष महोदय, क्या श्री महीपाल ढाण्डा जी को इस तरह बोलना शोभा देता है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः बहन जी, ढाण्डा साहब की इस बारे प्रतिक्रिया बाद में आई है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कंवर पालः उपाध्यक्ष महोदय, RSS दुनिया की सबसे बड़ी स्वयं सेवी संस्था है। इस तरह के काम तो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लोग ही कर सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान) माननीय सदस्य द्वारा इस तरह के गलत आरोप लगाये जा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः प्लीज, आप सभी माननीय सदस्यगण अपनी–अपनी सीटों पर बैठ जायें। इलियास जी, आप जो भी स्टेटमैंट सदन में दे रहे हों वो बिना किसी तथ्य

और सबूत के ना दे। जो शब्द RSS से संबंधित हैं वे प्रोसीडिंग से निकाल दिये गए हैं।

मोहम्मद इलियासः उपाध्यक्ष महोदय, चार–पांच महीने पहले एक घटना हमारे मेवात के रवा गांव में हुई थी। चाहे आप उस घटना की इंक्वॉयरी करवा लें। उस समय भी यह कहा गया था कि वहां पर बजरंग दल के लोग गये हैं। वो लोग हथियारों सहित गये थे और उनके साथ सी.आई.ए. की पुलिस भी थी। आप इसकी इंक्वॉयरी करवा लें। यदि यह बात सच नहीं हुई तो मैं हाउस में कह रहा हूँ कि इसके लिये मैं कोई भी सजा पाने का हकदार हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि उनको रास्ते में ही मार दिया गया था और उनको फिरोजपुर झिरका या थाने में लाते समय यह काम किया गया था। अगर हरियाणा पुलिस इसके प्रति सचेत होती तो शायद उनकी जान बच सकती थी। हरियाणा पुलिस का यह काम था कि वे उनको अपनी कस्टडी में रखते और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करते लेकिन ऐसा हरियाणा पुलिस ने नहीं किया। चाहे वह नूंह की पुलिस थी या वह फिरोजपुर झिरका की पुलिस थी। उनको एक मौका मिल गया और उनसे हरियाणा पुलिस मिली हुई थी। भिवानी में ले जाकर उनको मार देने का काम किया। सिर्फ मार देने से उनका पेट नहीं भरा बल्कि उनके निशान और सबूत मिटाने के लिए उनको जलाने का काम किया। स्पीकर महोदय, इससे घिनौना काम और क्या हो सकता है? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आज हरियाणा प्रदेश के अल्पसंख्यक अपने आपको बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं । मेरी सरकार से मांग है कि इन घटनाओं पर अंकुश लगाने का काम किया जाए । सरकार की ओर से उनके खिलाफ अवश्य कार्यवाही की जाए और जो मुलजिम पाये जाएं उनको कड़ी–से–कड़ी सजा दी जाए । उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं पंचायतों की बात करना चाहूंगा । प्रदेश में अभी–अभी पंचायतों के चुनाव

हुए हैं । सरकार ने जो ई–टैंडरिंग पोलिसी लागू की है उसके बारे में मेरा कहना है कि उस पोलिसी को वापिस लिया जाए । सरपंचों को पंचायतों के कार्य करने के लिए कम–से–कम 20–20 लाख रुपये दिए जाएं । उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने हल्के की मांगें उठाना चाहूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : इलियास जी, आपका समय पूरा हो गया है, इसलिए अब आप अपनी सीट पर बैठ जाइये । अगर आपने कुछ और कहना है तो आप महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के समय बोल लेना । अब माननीय सदस्य श्री शमशेर सिंह गोगी बोलेंगे ।

श्री शमशेर सिंह गोगी (असंध) : उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत चुनावों के द्वारा एक छोटी सरकार बनी थी । मुझे यह कहते हुए बड़ा दुःख होता है कि पंचायतों को जिस तरह से क्लर्क, जे.ई., प्रशासन और ऊपर बैठे आकाओं के द्वारा खाया जाता है उनका तो सरकार ने हिसाब नहीं किया लेकिन जो व्यक्ति चुनकर आये हैं उनको कह दिया है कि आप क्लर्कों की नौकरी करो । अगर उनसे यही काम करवाना था तो फिर उनके चुनाव करवाने की आवश्यकता ही क्या थी ? मेरा कहना है कि सरकार को अगर ई–टैंडरिंग भी करवानी है तो उसको सरपंच के द्वारा या ब्लॉक समिति के द्वारा या जिला परिषद के द्वारा करवाना चाहिए । क्या यहां पर बैठे हुए सभी लोग ईमानदार हैं और वहां पर बैठे हुए सभी लोग बेईमान हैं ? यह गलत परिपाटी डाली जा रही है । लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया जा रहा है । आप सरपंचों को अधिकार दो क्योंकि वे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं । असंध नगर पालिका में 13 अनअथॉराइज्ड कॉलोनियां हैं । पिछली बार भी यह कहा गया कि वे अप्रूव हो गई हैं । मुझे किसी ने बताया कि उनमें से 11 कॉलोनियां अप्रूव हो गई हैं । इसी तरह दो साल पहले 10 करोड़ रुपये का फंड देने की बात कही गई थी लेकिन वह फंड आज तक नहीं दिया गया । जुंडला

को सब–तहसील बनाने के लिए मैंने माननीय मुख्य मंत्री महोदय को पत्र दिया था लेकिन आज तक मुझे उस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया गया । निसिंग को ब्लॉक बना दिया गया जबकि ब्लॉक का नाम जुंडला रखना था । जुंडला को ब्लॉक नहीं बनाया गया । असंध में एक सब्जी मण्डी है । उसको 2 साल से शिफ्ट कर रहे हैं लेकिन पता नहीं वह शिफ्ट कब होगी जबकि जगह उपलब्ध है । इससे पब्लिक के साथ–साथ सरकार का भी नुकसान हो रहा है । बला एक बड़ा गांव है । उसके स्कूल की बिल्डिंग गिर गई लेकिन उसको बनाने का कोई काम नहीं किया जा रहा है । बिजली के कनैक्शन 18 दिसम्बर तक दिए गए थे लेकिन उसके बाद आज नये कनैक्शन नहीं दिए जा रहे हैं । मैंने 2 साल पहले करप्शन की जांच करवाने के लिए डी.सी., करनाल को एक लैटर लिखा था । उन डी.सी. की तो वहां से ट्रांसफर हो गई लेकिन उनके साथ वह जांच भी गुड़गांव ही चली गई । उसकी आज तक जांच नहीं हुई । फिर मेरे पास एक दिन एस.डी.एम. साहब का फोन आया कि साहब, आप दो प्वॉयंट की जांच करवा लो, करप्शन थोड़ी ज्यादा है । इस पर मैंने कहा कि आप व्यायामशाला और 5 पोंड सिस्टम की जांच करवा दो लेकिन उसकी जांच भी नहीं हो रही है । उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सरकार यह बताए कि जो करप्शन पर जीरो टॉलरैंस पॉलिसी है वह किस– किस के लिए है? क्या वह सिर्फ सत्ता पक्ष वालों के लिए है कि जीरो कहकर साथ में कुछ भी लिख लें? जैसे कि 5 ट्रिलियन लिखते हैं, लेकिन उसमें इनको पता नहीं कि कितनी जीरो लगेंगी? ऐसे ही इनको कहें कि ठगी का काम बन्द कर दें और उसका हिसाब मेरे को दिलवा दें। मैं पिछले 2 सालों में सदन में लगातार बोल रहा हूं। मैंने संबंधित डी.सी. का नाम लेकर कहा है कि वह जांच नहीं करवा रहा है। सरकार ने डी.सी. तो प्रमोट करके गुरुग्राम भेज दिया है, लेकिन मुझे संबंधित जांच का नतीजा नहीं मिला है। उपाध्यक्ष

महोदय, फिर भी सरकार कहती है कि हमारा करप्शन पर बहुत कंट्रोल है। अगर मैं सरकार के बारे में कुछ कहूंगा तो ये हंगामा करने लग जाएंगे। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि चौकीदार और नम्बरदार की वजह से गांव की व्यवस्था चलती थी, वे भी रोने लग रहे हैं। अब वे पता नहीं कि किसको रो रहे हैं ? अगर मैं इनके बारे में कहूंगा तो माननीय मंत्री जी कहेंगे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं? जिनकी सरकार है, उनका नाम तो लेना ही पड़ेगा। यह तो वही बात है कि अगर किसी के बाप का नाम ले लिया जाए तो वह कहे कि उसके बाप का नाम क्यों ले रहे हैं? अगर मेरा कोई बाप है तो उसका नाम लिया जाएगा। अगर मैं आर.एस.एस. का नाम लेता हूं तो बी.जे.पी. वाले कहते हैं कि आर.एस.एस. का नाम क्यों ले रहे हैं? इनका तो वही मां–बाप है और सारी गड़बड़ वहीं से आती है।

श्री कंवर पालः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि हमें तो इस बात का गर्व है कि हम आर.एस.एस. से जुड़े हुए हैं।

श्री महीपाल ढांडाः उपाध्यक्ष महोदय, हम यही कह रहे हैं कि माननीय सदस्य को इज्जत से उसका नाम लेना चाहिए।

श्री उपाध्यक्षः गोगी जी, इनका कहना यह है कि इसका नाम लेने से आपकी वाणी शुद्ध होगी।

श्री शमशेर सिंह गोगीः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मेरे हल्के की एक रफतक से लेकर सिरसल चौक तक 10 मीटर की सड़क बननी थी। इस समय माननीय उप मुख्यमंत्री जी सदन में नहीं बैठे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगा कि पिछले साल के बजट से मेरे हल्के में एक भी नयी सड़क नहीं बनी है। इस संबंध में यह कहा जाता है कि सी.आर.एफ. में दिल्ली भेज रखी है और पता नहीं कब आएगी ? अगर यह इनके बस की बात नहीं है तो माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी को एक दिन

यही पर बुला लेंगे तो हम यही पर उनसे डिमांड कर लेंगे। इसके अतिरिक्त कैथल से सफीदों रोड पर बहुत गढ्डे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: गोगी जी, आपके बोलने का समय पूरा हो चुका है। प्लीज, अब आप बैठ जाएं। अब माननीय सदस्य श्री मामन खान जी अपनी बात रखेंगे।

श्री मामन खान (फिरोजपुर झिरका): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हरियाणा प्रदेश की कानून एवं व्यवस्था के बारे बताना चाहूंगा। मेरे से पहले भी कई माननीय सदस्यों ने हाउस में इस बारे में बात की है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी और माननीय गृहमंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि आपने गौ रक्षा के नाम पर मेवात में गुंडे भेज रखे हैं और उनको बहुत बडे.–बड़े हथियार दे रखे हैं। मैं इसके बारे में सदन में भी जानकारी टेबल करूंगा। सरकार ने उनको किस आधार पर हथियार दे रखे हैं? क्या उनको ये हथियार मुसलमानों को मारने के लिए दे रखे हैं? क्या आपने जो कानून बना रखे हैं, उनके अनुसार गौ हत्या करने वालों को पुलिस कड़ी से कड़ी सजा नहीं करवा सकती? इसके पीछे क्या कारण है? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि इन गुंडों ने मेवात जिले के तीन नौजवानों की गौ रक्षा के नाम पर जान ली है। इसके लिए हरियाणा सरकार जिम्मेवार है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी जिम्मेवार हैं, माननीय गृहमंत्री जी जिम्मेवार हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी जिम्मेवार हैं और माननीय मंत्री जी जिम्मेवार हैं। ये वहां पर जाकर ऐसे लोगों पर लगाम क्यों नहीं लगाते? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि उन लोगों ने अभी 4 घटनाओं को अंजाम दिया है। इनकी टीम दिनांक 23.04.2022 को शेखपुरा गांव में गयी थी। इसमें कुछ लोग मेवात से हैं, कुछ लोग जींद से आते हैं और कुछ लोग रोहतक से आते हैं। ये लोग गांव शेखपुरा में जाते हैं और वहां पर अपने

हथियारों को लहराते हैं। इनके पास डिवैल्पमैंट एंड पंचायत विभाग की एक गाड़ी होती है जिसका नम्बर एच.आर.–70 डी, 4177 है। इस गाड़ी में वहां से जबरन लोगों को उठाकर गौशाला में ले जाते हैं और उनको मारते हैं। इसके बाद फिर पुलिस को हैंडओवर कर देते हैं। एस.पी. साहब, इनके परिजनों की एप्लीकेशन भी नहीं ले सकते। इसके बाद इसी टीम ने दिनांक 15.08.2022 को दूसरी घटना रावा गांव में की थी। यही टीम गांव में जाती है और जंगलों में घूमती है और वहां पर कोई गौकशी नहीं होती है। ये वहां पर जो हमारी बहन–बेटियां जंगल में जाती हैं, उनके साथ अश्लील हरकतें करते हैं और गांव वाले विरोध करते हैं तो वे गोलियां चलाते हैं। फिर पुलिस भी उन्हीं के खिलाफ जबरदस्ती करती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाशः उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय पर अपनी बात रखना चाहूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मामन खानः उपाध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य बीच में बोल रहे हैं तो मेरा टाईम बन्द कर दें ताकि मुझे अपनी बात रखने का पूरा मौका मिल सके।

श्री उपाध्यक्षः सत्य प्रकाश जी, प्लीज, आप बैठ जाएं। माननीय सदस्य श्री मामन खान जी अपनी बात रख रहे हैं।

श्री सत्य प्रकाशः उपाध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः सत्य प्रकाश जी, प्लीज, आप बैठ जाएं। माननीय सदस्य श्री मामन खान जी अपनी बात रख रहे हैं।

श्री मामन खानः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को उनके बोलने के टाईम पर ही अपनी बात रखनी चाहिए। मैं भी उनके बराबर का ही माननीय विधायक हूं।

श्री सत्य प्रकाशः उपाध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः सत्य प्रकाश जी, प्लीज, अब आप बैठ जाएं।

*13:00 बजे

श्री सत्य प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं। *******(शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सत्य प्रकाश जी, आप प्लीज बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं। *******(शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सत्य प्रकाश जी, आपकी कोई बात रिकॉर्ड नहीं हो रही है इसलिए आप प्लीज बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, जब माननीय सदस्य आपकी ही बात नहीं मानते हैं तो इनको नेम करो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सत्य प्रकाश जी, आपकी कोई बात रिकॉर्ड नहीं हो रही है इसलिए आप प्लीज बैठ जायें। आप ऐसे बीच में सदन की कार्यवाही को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मामन खान : उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर बहन बेटियों के साथ अश्लील हरकतें की जाती हैं और जब इसका गांव वाले विरोध करते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमें दर्ज करा दिये जाते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सत्य प्रकाश जी, आप फिर खड़े हो गये। आपको बोलने के लिए किसने अलाउ किया है। आप प्लीज बैठ जायें। मेरी सभी माननीय सदस्यों से गुजारिश है कि इस समय जीरो ऑवर चल रहा है। कोई भी मैम्बर जब अपनी बात कह रहा होता है तो बीच में कोई भी माननीय सदस्य डिस्टर्ब न करे और

***चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।**

बोलने वाले माननीय सदस्यों से भी मेरा निवेदन है कि कोई इस टाइप की बात न की जाये जो बिना मतलब की दूसरे माननीय सदस्यों के ऊपर टिप्पणी हो (शोर एवं व्यवधान)

श्री मामन खान : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। जो बात हकीकत है, मैं वही बात बता रहा हूं। जब वहां पर उन्होंने बहन बेटियों के साथ अश्लील हरकतें की और गांव वालों ने इस बात का विरोध किया तो उन लोगों के ऊपर पुलिस ने 307 और 379–बी जैसी संगीन धाराएं लगाकर उनको भी अंदर करने का काम किया। उसके खिलाफ गांव वालों ने दरख्वास्त दी लेकिन गौ–रक्षक के नाम पर जो गुंडागर्दी कर रहे थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उपाध्यक्ष महोदय, इस बात की हद तो तब हो गई जब दिनांक 28.1.2023 को वारिस पुत्र फौज मोहम्मद, गांव हुसनपुर, नूंह का रहने वाला जो भिवाड़ी में गाड़ी रिपेयरिंग करने के लिए गया था। उसको मोनू मानेसर टीम ने सुबह 4 बजकर 56 मिनट पर उठाया। उसको खोरी चौकी तावडू के पास रखा और अढाई घंटे तक उसको वहां पर पीटा गया। उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर दो बार पुलिस वाले गये लेकिन उसको किसी ने नहीं बचाया। वहां पर दो बार पी.सी.आर. भी गई थी जिसकी वीडियो फुटेज अवेलेबल है। उसके बाद उसको वहां से सुबह 7:30 बजे उठाकर ले जाते हैं। बकायदा तौर पर उसकी वीडियो भी बनाई गई है जो मैं आपको दे दूंगा। जिसमें वह जान की भीख मांगता है कि मुझे छोड़ दो। उसके 2 घंटे बाद उसका एक्सीडैंट दिखा दिया जाता है और कह दिया जाता है कि उसकी एक्सीडैंट होने के कारण मौत हुई है। जब उनके पास यह लड़का था तो फिर एक्सीडैंट वाली बात कहां से आ गई? मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि एक कमेटी बनाकर उनके खिलाफ धारा 302 के तहत केस दर्ज किया जाये। यह मोनू मानेसर कभी श्री अमित शाह के साथ फोटो खिंचवा रहा है और कभी श्री

अरूण जेटली के साथ फोटो खिंचवा रहा है। क्या ऐसा करके वह मेवातियों को डराना चाहता है कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं। अबकी बार माननीय मंत्री जी याद रखना, अगर यह मेवात आ गया तो कहीं इसकी प्याज सी न फोड़ दी तो मेवात का हमें कौन कहेगा क्योंकि वहां पर लोग पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान है। इसने मेवात में बहुत आतंक फैला दिया है। हमारे मेवात के इसने तीन लड़कों की जान ले ली है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नयन पाल रावत : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मामन खान : उपाध्यक्ष महोदय, ये आदमी हमारे बच्चों को कैसे मार रहा है? नयन पाल रावत जी, जब इसने हमारे तीन आदमियों को मारा था तब आप इस पर बोलते। (शोर एवं व्यवधान) सरकार के बस का काम नहीं रहा है क्योंकि सरकार ने इनको हथियार दे रखे हैं कि मेवातियों को मारो।

श्री नयन पाल रावत : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य धमकी दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : रावत जी, प्लीज आप बैठ जायें।

उपमुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही कि कोई वीडियो एवीडेंस इनके पास है जिसके अंदर वह लाइव था और कार एक्सीडेंट में उसकी डैथ दिखाई गई तो हम आई.जी. रेवाड़ी की अध्यक्षता में एक कमेटी बना देंगे। जो आप हमें तथ्य देंगे, उसकी इन्क्वायरी करवायेंगे।

श्री मामन खान : उपाध्यक्ष महोदय, हम सरकार को इसका तथ्य भी देंगे। इसके बाद इन्होंने फिर एक काम और किया। मेरे हरियाणा के साथ लगता हुआ एक गांव घाटमीका है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि फर्जी गौ–रक्षक हरियाणा पुलिस की मिलीभगत से आये दिन बेगुनाह मुसलमान जवानों को मेवात से अगवा कर लेते हैं और बाद में उनको बेरहमी से मौत के घाट उतार देते हैं।

कुछ दिन पहले गाय के नाम पर पहलू खान, जुनैद खान, रकबर व वारिस खान और जुनैद को सड़क पर मार गिराया गया था। अब नासिर और जुनैद को बोलेरो कार की सीट की बैल्ट से बांधकर पैट्रोल छिड़ककर भिवानी के जंगलों में लाकर मार गिराया । यह कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बात है कि मेवातवासियों को किस तरह से ले जाकर कहां–कहां इनको जिंदा जलाने का काम किया जा रहा है। मैंने जिन तथ्यों के बारे में बताया है उनसे संबंधित कागजात सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। आप इनको प्रोसीडिंग्ज का पार्ट बनवा दें।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, आप इन कागजात को सदन के पटल पर रख दें, इनको प्रोसीडिंग्ज का पार्ट बनवा दिया जाएगा।

***श्री मामन खान :** ठीक है उपाध्यक्ष महोदय।

***चेयर के आदेशानुसार उपरोक्त लिखित स्पीच को कार्यवाही का हिस्सा बनाया गया।**

Gi. Mamman Khan — Hon'ble Spk

सेवा में, 22-2-23 — 223 Received — No- 334-SD 26-4-22

श्रीमान थाना प्रबन्धक महोदय,

थाना फिरोजपुर झिरका जिला नूंह

विषय:— दरखास्त बाबत नाजायज हथियारों के बल पर घर से अपहरण करने, लूटपाट व जान से मारने की नीयत से फायर करने बारे मुकदमा दर्ज करने बारे दरखास्त 1. श्रीकान्त पुत्र बालकिशन, 2. अनिल पुत्र किटटू निवासीयान गाव मरोडा थाना नगीना, 3. मन्नू पुत्र कैलाश, 4. मौनू पुत्र नामालूम, 5. सन्नी पुत्र नामालूम सर्व निवासीयान गाव पिनंगवाव 10—12 अन्य

श्रीमान जी,

प्रार्थी होशियार पुत्र प्यारे खान निवासी गाव शेखपुर थाना फिरोजपुर झिरका जिला नूह का स्थाई निवासी हूं जमीदारे का काम करता हूं दिनांक 23.04.2022 को मैं, मेरा लडका साहिब अपने पूरे परिवार के साथ घर पर मौजूद थे कि समय करीब 6 बजे AM [redacted] को हमारे घर के सामने एक दम तीन गाडियां आकर रूकी जिनमें एक गाडी स्कार्पियों जिसका नं0 एच0 आर0 70 डी0 4177 था बाकी दो बोलेरो गाडियों पर कोई नम्बर नही था। गाडियों में से उपरोक्त श्रीकान्त वगैरा उतरे जिनके हाथों में कटटा बन्दूक व राईफल जैसे हथियार थे और आते ही हमारे घर में घुस गये और एक दम से फायरिंग करनी शुरू कर दी। हम घबरा गये और जब हमने ऐतराज किया तो उपरोक्त श्रीकान्त वगैरा ने मेरे व मेरे पूरे परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की और मेरे लडके साहिब को हथियारों के बल पर घर से अपने कब्जे में ले लिया और सभी ने जोर से कहा कि अगर किसी ने शोर किया व ऐतराज किया तो गोलियों से भून देंगे तो श्रीकान्त, अनिल, मन्नू, मोनू, सन्नी व उनके साथ अन्य 10—12 व्यक्तियों ने ताबडतोड फायरिंग शुरु कर दी। हमने जैसे तैसे कमरों में घुसकर अपनी जान बचाई और उसके बाद इन सब लोगों ने हमारे घर में लूटपाट की और घर में रखे लाखों रूप्ये के सोने चांदी के जेवरात व घर में रखे मु0 45,000/— रूप्ये भी लूट लिये और हम सबको आतंकित करते हुए घर में बंधक बना लिया। हमारा घर गाव से थोडा बाहर है। कुछ ही देर बाद हमारी चीख पुकार व गोलियों की आवाज सुनकर गाव के

223-A

लोग आ गये जिस वजह से उपरोक्त श्रीकान्त वगैरा ने मेरे व मेरी लडकियों के उपर जान से मारने की नीयत से फायर किये लेकिन हम दीवार की आड लेकर बच गये। गाव मे उपरोक्त लोगो ने आतंक का माहौल बना दिया और हथियारों की फायरिंग की वजह से गाव के लोग आतंकित हो गये मेरे बेटे साहिब को अपने साथ अपहरण करके ले गये। उपरोक्त श्रीकान्त वगैरा को मैं पहले से ही जानता हू क्योकि ये पडौसी गाव मरोडा व पिंनगवा के रहने वाले है और जो अन्य 10—12 आदमी थे उनको मैं सामने आने पर पहचान सकता हूं। जाते समय सभी ने हमें धमकी दी कि कही कोई रिपोर्ट की तो तुम्हें व तुम्हारे पूरे परिवार को जान से खत्म कर देंगे। इस वजह से हमने रिपोर्ट ना की वहां पर पहुचे कुछ लडको ने मौका वारदात की वीडियों बना ली और वो वीडियो वायरल हो गयी और मैं अब हिम्मत करके बराये रिपोर्ट आपके पास आया हू।

बाद में हमें पता चला कि उपरोक्त श्रीकान्त वगैरा बजरंग दल संगठन से जुडे हुए है और इन लोगो ने अपने बचाव करने के लिए मेरे लडके के खिलाफ एक झूठा व मनघडंत मुकदमा नं0 149 दिनांक 23.04.2022 थाना फिरोजपुर झिरका में दर्ज करा दिया जिसका हमें पता नही चल पाया और इस मुकदमे में मेरे लडके को बिना किसी तफतीश व तसदीक के गिरफतार करके अदालत में पेश कर दिया जो इस समय जेल में बन्द है।

अतः जनाब से मेरी गुजारिश है कि उपरोक्त बदमाशों के खिलाफ जेरेधारा 342/365/395/397/307/452/506 भा0 द0 सं0 व आर्मस एक्ट बाबत मुकदमा दर्ज करके सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की जावे। आपकी अति कृपा होगी।

प्रार्थी L.T.I होशियार

दिनांकः— 25/04/2022

होशियार पुत्र प्यार खान निवासी गाव शेखपुर थाना फिरोजपुर झिरका जिला नूह

मोबाईल नं0 9306034471

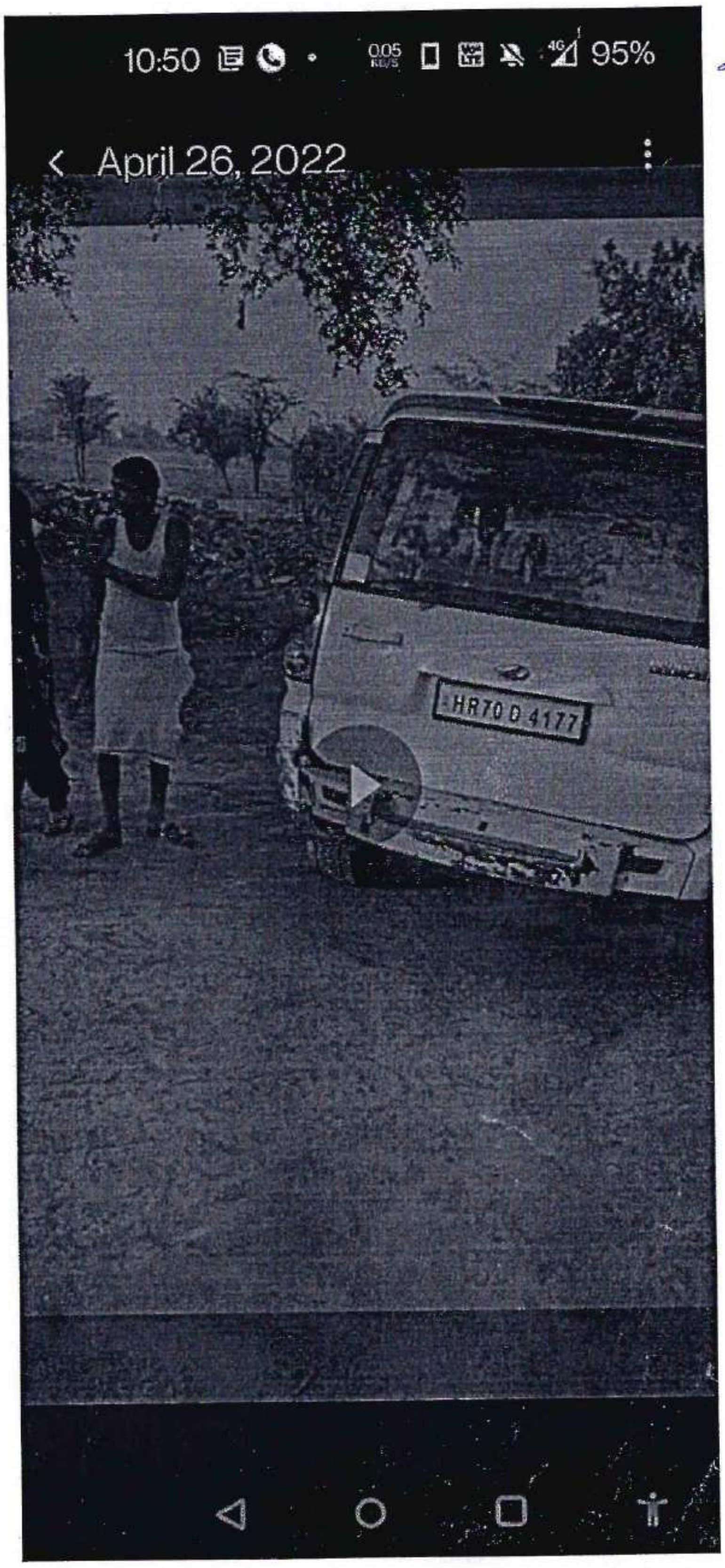
10:50
95%
April 26, 2022
HR70 D 4177

3:07 228 4G Hon'ble Speaker

Aslam Khan
4 h ·

Azad Bol · Follow
5 h ·

गोरखनाथ मंदिर के गार्ड पर घास काटने की दराती' से हमला करने वाले #मुर्तुज़ा' को 'आतंकी' करार देकर #फांसी की सज़ा सुनाई गई है! दूसरी तर... See more

2 · 2 shares

Like · Comment · Share

Home · Friends · Watch · Marketplace · Notifications · Menu

226

मेवात : जानिए कौन है मोनू मानेसर जिसपर लगा है 22 साल के वारिस की हत्या का आरोप

सत्यम् तिवारी | 01 Feb 2023

अपराध भारत राजनीति

देश में गौ रक्षा के नाम पर हिंसा और हत्या की घटनाएं 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद से बढ़ी हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच के आंकड़े के मुताबिक 2015 से 2018 तक इन हमलों में 44 लोगों की हत्या हुई है, जिनमें से 36 मुसलमान थे।

227

गोवंश ला रही गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, संदिग्ध परिस्थिति में युवक की मौत

परिजनों ने गोरक्षा दल के सदस्यों पर लगाया हत्या का आरोप

नूंह | नूंह जिले के तावडू खंड में भिवाड़ी-तावडू मार्ग पर गोवंश ला रही एक कार शनिवार सुबह 4 बजे खोरी कलां गांव के पास एक टेंपो से टकरा गई। दुर्घटना के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में कार चालक की मौत हो गई। जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक के परिजनों ने गोरक्षा दल के सदस्यों पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं, पुलिस इसे सड़क दुर्घटना बता रही है। शनिवार को क्षेत्र के लोगों को जैसे ही घटना के बारे में पता चला राजकीय शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज नलहड़ में भारी संख्या में भीड़ जमा हो गई। इसके बाद पुलिस बल भी मौके पहुंचा और शांति बनाने की अपील की। इसके बाद क्षेत्र के लोग गोरक्षा दल के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर नलहड़ मेडिकल कॉलेज परिसर में ही बैठ गए। सदर थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने बताया कि खोरी कलां चौकी के अंतर्गत अतीत का मोड़ के पास टाटा एस

टेंपो एवं सेंट्रो गाड़ी की भिड़ंत हो गई। सेंट्रो में वारिस गांव हुसैनपुर, शौकीन गांव आंकड़ा व नफीस गांव रनियाकी सवार थे। सड़क हादसे में तीनों चोटिल हो गए, जिनमें से वारिस निवासी हुसैनपुर ने हादसे में लगी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। वहीं, पुलिस की बातों से मृतक के परिजन संतुष्ट नहीं हैं। परिजनों का कहना है कि गोरक्षा दल के सदस्यों ने तीनों की पिटाई की है और इसी पिटाई की वजह से वारिस की जान गई है। इस घटना से क्षेत्र के लोगों में गोरक्षा दल के खिलाफ भारी रोष है।

228

विवाहित युवक की रहस्यमय ढंग से मौत, परिवार ने गौरक्षक दल पर हत्या का आरोप लगाया

नूंह। जिला के तावडू सदर थाना क्षेत्र के खोरी में दो वाहनों की टक्कर में एक युवक के रहस्मय तरीके से मौत होने का समाचार प्राप्त हुआ है। विवाहित युवक की रहस्मय ढंग से मौत होने से शनिवार को शहीद हसन खां मेवाती राजकीय मेडिकल कॉलेज नल्हड(नूंह) में पीड़ित के परिजनों व अन्य लोगों ने खूब शोर मचाया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि मृतक को कथिततौर से बजरंग दल के लोगों ने मारा है जबकि पुलिस प्रशासन की माने तो सडक दुर्घटना में युवक की मौत हुई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह तावडू सदर थाना क्षेत्र खोरी में एक सेंटरो कार व टाटा गाडी की आपस में टक्कर हो गई, पुलिस ने दोनों गाडियों के घायलों को अस्पताल में पहुंचाया जिसमें नल्हड मेडिकल कॉलेज में एक विवाहित युवक वारिस उम्र करीब 22 साल निवासी हुसैनपुर की ईलाज के दौरान मौत हो गई। पीड़ित परिवार की माने तो कथित बजरंग दल के लोगों ने वारिस को मारा पीटा और गंभीर चोट पहुंचाकर हत्या की हैं। घटना की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और मेडिकल कॉलेज में पीड़ित परिवार व अन्य ग्रामीणों की हुजूम लग गया।

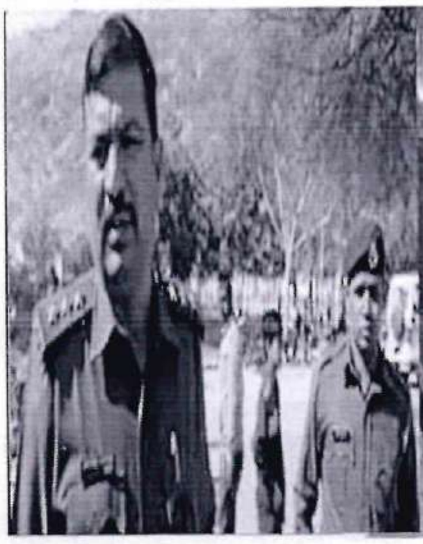

पुलिस ने भी सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल तैनात कर दिया। पीड़ित परिजनों ने बताया कि वारिस अपने दो अन्य साथियों के साथ जा रहा था लेकिन बजरंग दल के लोगों ने उनको पकड़ कर मारा पीटा और वारिस की हत्या कर दी है। खबर लिखे जाने तक तावडू सदर पुलिस ने सडक दुर्घटना का मुकदमा दर्ज कर लिया हैं और पीड़ित पक्ष की शिकायत लेकर आगे जांच कर रही है।

इस बारे में तावडू सदर थाना प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार ने शनिवार सांय बताया कि सदर थाना क्षेत्र में एक सेंटरों कार व टाटा गाडी में आज सुबह टक्कर हुई है, सेंटरो कार में सवार वारिस निवासी गांव हुसैनपुर व उसके दो साथियों व दूसरे वाहन के चालक को सडक दुर्घटना में चोटे आई है। सडक दुर्घटना का मुकदमा दर्ज कर पीड़ित पक्ष की भी शिकायत लेकर आगे कार्रवाई की जा रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने माना कि सेंटरो कार में एक गाय भी बरामद हुई हैं।

2:33 289 4G

Irshad Hussain Meo
1h ·

तारिफ भूतका is with Irshad Hussain Meo. · Follow
4h ·

अब मोनू मानेसर का आर्म्स लाइसेंस रद्द करने की तैयारी

पटौदी थाने में दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में हो रही कार्रवाई

DCP मानेसर ने पकड़ा गिरफ्तारी के लिए भी लगी है टीम
भिवानी में बोलेरो कार में जले हुए कंकाल मिलने के मामले में भी भरतपुर पुलिस कर रही तलाश

मोनू मानेसर

पुलिस की धक्कामुक्की से गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत

अस्पताल में भर्ती महिला की पत्नी

मां ने लगाया आरोप

लोकेश की गिरफ्तारी के लिए पलवल पुलिस भी एक्टिव

बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने SDM को सौंपा ज्ञापन

Write a comment...

Home Friends Watch Marketplace Notifications Menu

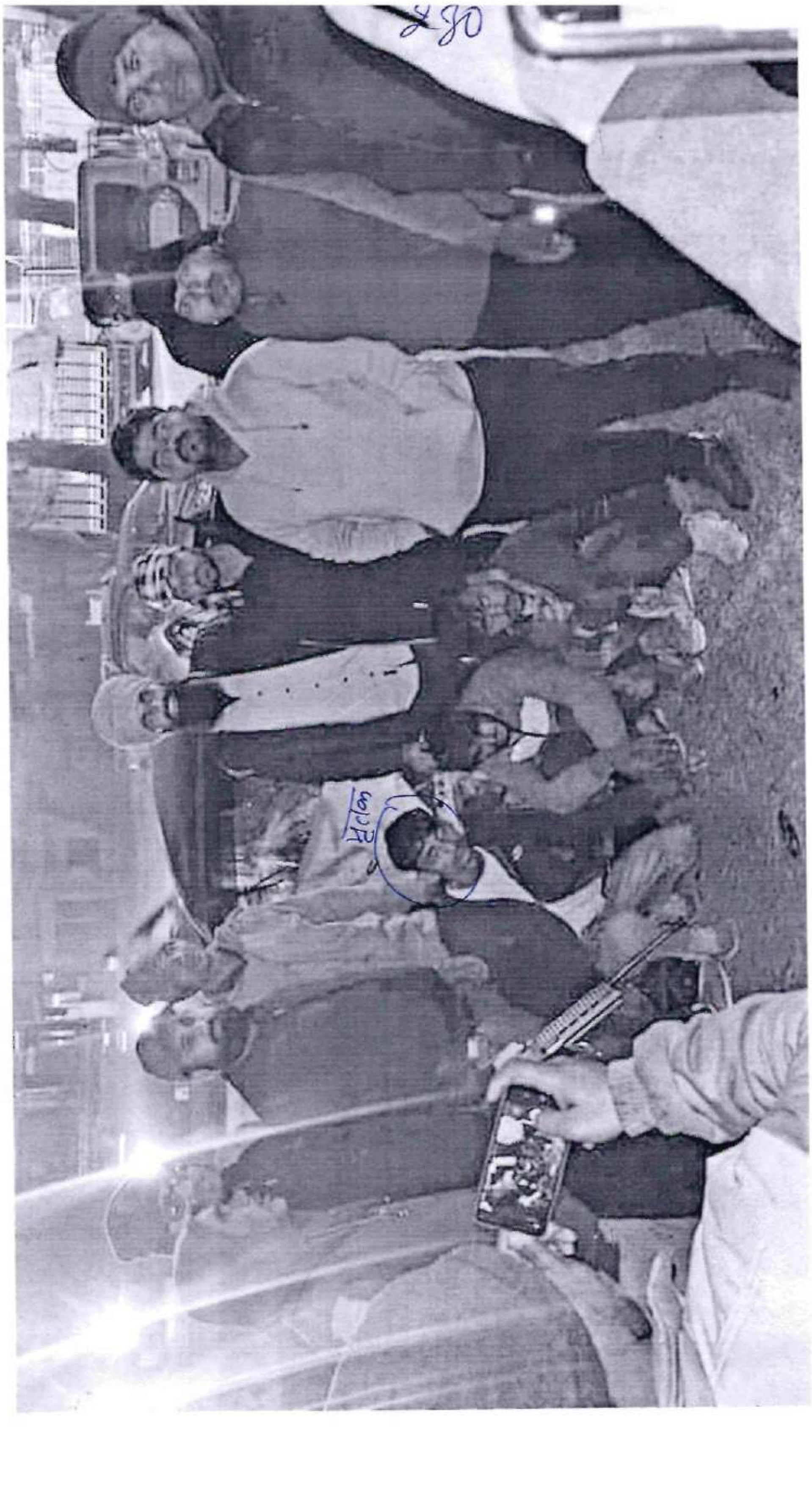

232

श्री भारत भूषण बतरा(रोहतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 19.02.2023 को 50 हजार सरकारी कमर्चारियों ने ओ.पी.एस. लागू करवाने के लिए प्रदर्शन किया था और ये प्रदर्शन बिल्कुल शांतिपूर्वक था लेकिन कर्मचारियों पर लाठीचार्ज किया गया, वॉटर कैनन का प्रयोग किया गया तथा आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इससे कुछ कर्मचारियों को चोटें भी आईं। उपाध्यक्ष महोदय, इससे तो यही लगता है कि कर्मचारियों की डिमांड के आगे सरकार बिल्कुल बहरी हो गई है। उपाध्यक्ष महोदय, ओ.पी.एस. के बारे में एक सीनियर आई.ए.एस. आफिसर ने एक ट्वीट भी किया है कि जीवन की संध्या में कर्मचारियों को बाजार के सहारे छोड़ना, क्या नैतिक है ? पैंशन फण्ड को सुरक्षित करना चाहिए कि हर कर्मचारी को रिटायरमैंट पर पुरानी पैंशन योजना मुताबिक पैंशन मिले। उपाध्यक्ष महोदय, ये बात सरकार का एक उच्च अधिकारी कह रहा है कि ओ.पी.एस. को लागू किया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, एन.पी.एस. स्कीम बीजेपी राज के अन्दर आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में शुरू हुई थी और यह ठीक बात है कि उसके बाद इसको कांग्रेस सरकार ने भी अडॉप्ट किया परन्तु टाइम के साथ एक टैस्टिड एक्सपीरियंस यह हुआ कि एन.पी.एस. स्कीम ठीक नहीं है और चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ऐलान भी कर चुके हैं कि परिवर्तन कुदरत का नियम है और हम पहली कलम से अनाउंस करेंगे कि ओ.पी.एस. लागू हो गई।(शोर एवं व्यवधान)

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत सिंह चौटाला): माननीय सदस्य जी, आप यह बताएं कि इसे लागू किसने किया था।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: उप मुख्यमंत्री जी, आप इसे पढ़कर आएं फिर पूछें कि इसे लागू किसने किया था। जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तब यह एन.पी.एस. लागू हुई थी बाद में इसे कांग्रेस सरकार ने भी अडॉप्ट किया। यह एक तरह से तजुर्बा है। अगर यह कर्मचारियों के हित में नहीं है तो हमने कह

दिया कि इसे वापस लो। इसी तरह से राजस्थान में एन.पी.एस. श्रीमती वसुंधरा जी ने लागू किया था और कांग्रेस ने इसे वापस ले लिया। हिमाचल में इसे हमारी कांग्रेस सरकार ने लागू किया था लेकिन अब वापस ले लिया, छतीसगढ़ में वापस ले लिया। इसी तरह पंजाब में आम आदमी पार्टी के मान साहब ने वापस ले लिया। यह एक तरह से तजुर्बा है। कर्मचारी के हित की बात सोचनी चाहिए अगर कर्मचारी कहते हैं कि एन.पी.एस. हमारे हित में नहीं है तो सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए।

श्री दुष्यंत सिंह चौटालाः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एन.पी.एस. की बात की तब मैंने सिर्फ इतना पूछा कि इसे लागू किसने किया ?(शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतराः उपाध्यक्ष महोदय, एन.पी.एस. को वर्ष 2004 में सैन्ट्रल गवर्नमैंट ने लागू किया उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने इसको अडॉप्ट किया।

श्री दुष्यंत सिंह चौटालाः उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की बात पर आ रहा हूं कि श्री मनमोहन सिंह जी ने देश में लागू की, मगर इसमें स्टेट्स का परैरोगेटिव था कि स्टेट्स में कौन–कौन कब अडॉप्ट करेंगे। हरियाणा में इसे आपकी सरकार ने अडॉप्ट किया। आज यह कह रहे हो कि बदल देंगे। हमारी सरकार ने अधिकारियों की तीन सदस्यीय कमेटी चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में गठित की है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने इसे लागू करके बड़ी भारी गलती कर दी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उप मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि आप इस गलती को सुधारो, आप यहां किसलिए बैठे हो अब इसे सुधारो। आप मेरी गलती निकाल रहे है अब आप इसे सुधार लीजिए मैं फिर भी आपका धन्यवाद कर दूंगा। बातें करना बहुत आसान होता है।

श्री भारत भूषण बतराः उपाध्यक्ष महोदय, 30–35 साल नौकरी करने के बाद सरकारी कर्मचारी अपने आपको ठगा सा महसूस करता है। No social security is left. It is a question of the survival of the government servant also. वह नौकरी करता है और उसके बाद उसको क्या मिलता है इसके बारे में सरकारी कर्मचारी बेहतर तरीके से बता सकते हैं। एन.पी.एस. में हरेक इम्पलॉय की 10 परसैंट डिडक्शन होती है और 14 परसैंट सरकार देती है पर ओ.पी.एस. के अंदर कोई पैसा किसी हालत में नहीं कटता है। सबसे बड़ी खासियत यही है कि उसमें कोई पैसा नहीं कटता है। एन.पी.एस. में कोई फिक्स पैंशन की गारंटी नहीं है। इसमें 60 परसैंट अमाउंट मैचोरिटी पर मिलता है और आज तक जो 40 परसैंट पैसा है वह शेयर मार्किट में लगा हुआ है। अडानी का हम सभी ने हाल देख लिया। अब सरकार और किसी और कम्पनी में पैसा इनवैस्ट कर देगी। जिस प्रकार से इकोनॉमी धड़ाम हुई है वैसे ही बेचारा इम्पलॉय भी धड़ाम हो जायेगा। एन.पी.एस. में फैमिली पैंशन का प्रावधान भी नहीं है। वैसे आप भी एग्री करेंगे कि ओ.पी.एस. लागू होनी चाहिए। 25 परसैंट अमाउंट जो है वह एन.पी.एस. के अकाउंट से इम्पलॉय को कोई दिक्कत आये तो वह विद्ड्रॉ कर सकता है पर जो गवर्नमैंट का शेयर है उसमें से एक पैसा भी नहीं निकाल सकता। यह भी बड़ी मुश्किल से एक्सैपशनल सरकमस्टांसिज में होता है। अब मैं ओ.पी.एस. के फायदों के बारे में बताता हूं। उसके फायदे ही फायदे हैं। Not even a single penny gets deducted from the salary of the employees, guaranteed fixed

pension on retirement and no investment is needed. किसी के लिए कोई मैनडेटरी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने एन.पी.एस. के अंदर मैडीकल रिम्बर्समैंट काट दी। मेरी सरकार से यही रिक्वैस्ट है कि इतना जुल्म तो नहीं किया जाना चाहिए कि बेचारा कर्मचारी रिटायर होने पर उसके ईलाज के पैसे भी न दें। ओ.पी.एस. के अंदर मैडीकल रिम्बर्समैंट का प्रॉविजन है। मेरी यह मांग है कि फैमिली पैंशन का भी प्रॉविजन होना चाहिए। अगर पैंशनर की डैथ हो जाती है तो उसकी विडो को पैंशन का बैनीफिट मिलना चाहिए।

राव चिरंजीव (रिवाड़ी): डिप्टी स्पीकर सर, आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने के लिए मौका दिया सबसे पहले तो इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विकास। मेरा यह कहना है कि इसको बदल देना चाहिए और इसको होना चाहिए अपनों का साथ, अपनों का विकास। पिछले 8 सालों के दौरान हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था की जो हालत है वह बहुत ज्यादा खराब हो गई है। कल इस बारे में मेरा सवाल भी लगा था। मैंने पूछा था कि पिछले आठ सालों में क्या कानून व्यवस्था प्रदेश के अंदर खराब हुई है? उसका जवाब तो नहीं में ही आना था। मैं यह बताना चाहूंगा कि वर्ष 2015 में जहां 1000 रेप हुए थे अब वर्ष 2022 के अंदर 2000 रेप हुए। इस प्रकार से 100 परसैंट की बढ़ोतरी हुई फिर भी सरकार कह रही है कि इस तरह से नहीं बढ़े हैं। अभी तक हर रोज 25 हीनियस क्राईम इस साल के

अंदर हर रोज हुए हैं। इसी प्रकार से 7 रेप, दो मर्डर भी रोज हुए हैं फिर भी सरकार कह रही है कि हरियाणा में कानून व्यवस्था खराब नहीं हुई है। खैर हो सकता है कि सरकार को ये हीनियस क्राईम न दिखते हों। मैंने मॉब लिंचिंग के बारे में ऊपर एक बात और पूछी थी। सरकार की तरफ से जवाब आया कि मॉब लिंचिंग के लिए कोई लॉ नहीं है। मैं सरकार से यही प्रार्थना करूंगा कि वह मॉब लिंचिंग के लिए जरूर कोई लॉ बनाया जाये क्योंकि इस तरह की घटनायें आये दिन प्रदेश के अंदर हो रही हैं सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। सरकार को अपना विकास ही नहीं बल्कि प्रदेश के विकास के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। सरकार ने हर जगह अपने फाईव स्टार ऑफिसिज बना लिए हैं। लोगों के लिए सरकार ने कहा था कि वर्ष 2022 तक हर किसी को पक्का मकान देंगे। वह पक्का मकान सरकार अब तक नहीं दे पाई है। इस बारे में भी स्थिति स्पष्ट की जाये। हमारे रिवाड़ी के अंदर जो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। हो सकता है कि सरकार को इंदिरा गांधी जी के नाम से कुछ तकलीफ हो। अगर आर.एस.एस. के किसी नेता के नाम पर उस यूनिवर्सिटी का नाम होता तो हो सकता है कि उसका कुछ भला हो जाता। मैं सरकार से कहूंगा कि इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री रही हैं अगर उनके नाम पर कोई यूनिवर्सिटी बनी है तो उसके ऊपर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि रिवाड़ी के अंदर एक ही इकलौती यूनिवर्सिटी है। गुरुग्राम के अंदर सरकार की एक यूनिवर्सिटी चल रही है उसकी बिल्डिंग

तक नहीं है। अभी पिछले दिनों मुझे सैनिक स्कूल, गोठरा जाने का मौका मिला। बड़े शर्म की बात है इस सरकार का नारा है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ लेकिन वहां पर बेटियों के लिए हॉस्टल ही नहीं है। वहां पर लड़कियों को लड़कों के हॉस्टल में रहना पड़ रहा है। वहां पर लड़कियों का हॉस्टल बनाने की घोषणा वर्ष 2010 के अंदर हुई थी। इस प्रकार से वर्ष 2012 में वहां पर लड़कियों का हॉस्टल बन जाना चाहिए था लेकिन वर्ष 2023 में 11 साल बाद सरकार द्वारा लड़कियों के हॉस्टल को एक दूसरी बिल्डिंग के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। वहां पर कोई भी सुविधा नहीं है। स्पोर्टस के ऑडिटोरियम नहीं हैं, हॉर्स राइडिंग की व्यवस्था भी नहीं है तथा वहां पर लड़कियों के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस तरफ सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि मसानी बैराज को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जायेगा। मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि रेवाड़ी, बावल और धारूहेड़ा का कैमिकल युक्त पानी वहां पर डाला जा रहा है और रेवाड़ी की जनता वही कैमिकल युक्त पानी पीने को मजबूर हो रही है। रेवाड़ी में पीने के लायक पानी नहीं बचा है। कल महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया था कि प्रदेश के लोगों को 55 लीटर पानी प्रतिदिन मुहैया करवाया जायेगा लेकिन रेवाड़ी की जनता प्यासी मर रही है। अब मैं रेवाड़ी के बस स्टैंड के बारे में अपनी बात रखना चाहता हूं। रेवाड़ी में जाम की सबसे बड़ी समस्या इसलिए है कि हमारा रेवाड़ी का बस स्टैंड नहीं बन रहा है। पिछले सत्र में भी मुझे कहा गया था कि रेवाड़ी का बस स्टैंड बन जायेगा लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन

करना चाहूंगा कि रेवाड़ी का बस स्टैंड जल्दी बनवाया जाये ताकि लोगों को इस सुविधा का लाभ मिल सके। हमारे माननीय साथी श्री सत्य प्रकाश जरावता जी ने कहा था कि 2 करोड़ 77 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से कासन और मानेसर गांवों के लोगों को जमीन अधिग्रहण के मुआवजे के तौर पर मिल रहे हैं लेकिन उससे वे खुश नहीं हैं इसलिए उनको 9 करोड़ रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से 1810 एकड़ जमीन का मुआवजा दिया जाये। इसी प्रकार से धारूहेड़ा में बिजली के तार बहुत नीचे लटक गये हैं जिनके बारे में मैंने पहले भी हाउस में आवाज उठाई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उन तारों को जल्दी से जल्दी ठीक किया जाये ताकि वहां पर कोई दुर्घटना न हो। आप सभी जानते हैं कि गुरूग्राम वर्ल्ड मैप पर एक मैट्रोपोलिटन सिटी है। पिछले 9 सालों में नोएडा और दिल्ली में तो मैट्रो का विस्तार हुआ है लेकिन गुरूग्राम में एक पिलर भी नहीं बना है। इस प्रकार मुझे लगता है कि दक्षिण हरियाणा के साथ भेदभाव हो रहा है इसलिए इसको बंद करने की जरूरत है क्योंकि हमारा दक्षिण हरियाणा वैसे ही बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है इसलिए उस ओर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सरकार ने यह कहा था कि रेवाड़ी में माजरा सोराज गांव में मेडिकल कॉलेज बनेगा लेकिन आज तक उस पर कोई काम नहीं हो पाया है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में एक बहुत बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। आज हरियाणा बेरोजगारी में देश में नम्बर 1 पर है। सरकार ने कौशल रोजगार निगम के रूप में जो भर्ती सिस्टम शुरू किया है यह कहीं न कहीं ठेकेदारी सिस्टम को बढ़ाने का काम किया है। यहां पर उप–मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं और इनको 75 प्रतिशत नौकरियां हरियाणा के युवाओं को देने का जो बिल लेकर आना था वह नहीं लाये हैं। हम देख रहे हैं कि आज भी फैक्ट्रियों में हरियाणा से बाहर के लोग नौकरियों पर लग रहे हैं इसलिए जल्दी से जल्दी

हरियाणा के युवाओं को 75 प्रतिशत नौकरियां देने का बिल विधान सभा से यथाशीघ्र पास करवाया जाये। धन्यवाद।

श्री नयन पाल रावत(पृथला): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्यकाल पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले शासनकाल में पृथला के लिए स्किल डिवैल्पमैंट यूनिवर्सिटी देने का एक सराहनीय कार्य किया था। इसके लिए हमारे दुधौला गांव के लोगों ने 85 एकड़ जमीन 1 रूपया प्रति एकड़ के हिसाब से डोनेट की थी। यह यूनिवर्सिटी कम्पलीट हो गई है और उसमें कुछ कोर्सिज शुरू होने हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उस गांव के बच्चों को उस यूनिवर्सिटी में नौकरियों में ग्रुप–सी, ग्रुप–डी और एडमिशन्स में रिजर्वेशन दिया जाये। इसके अतिरिक्त हमारा एक गोल्ड फील्ड प्राइवेट हॉस्पिटल था जो कोरोना काल में बंद हो गया था और सरकार ने उसको टेकओवर कर लिया था तथा उसमें लगभग 100 बैड का हॉस्पिटल बनाया है। अब वह हॉस्पिटल चालू होने की प्रक्रिया में है तथा उसमें कुछ डॉक्टर्स की भर्ती हो रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उसकी भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाये। जब वह प्राइवेट हॉस्पिटल चालू था तो उसमें लगभग 165 कर्मचारी लगे हुए थे जो आज सड़क पर हैं। अब उनकी उम्र अधिक हो गई है तथा उनकी संख्या लगभग 100 रह गई है इसलिए उनको भी इसमें समायोजित किया जाये। मेरे विधान सभा क्षेत्र के 104 गांव हैं और वह ग्रामीण क्षेत्र है जिसमें छोटे–छोटे पशुपालक रहते हैं इसलिए मेरी वहां पर एक वैटरनरी यूनिवर्सिटी खोलने की मांग है ताकि उन पशुपालकों को सुविधा मिल सके। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले साल तिगांव की रैली में हमारी सड़कों के लिए 100 करोड़ रुपये देने की मंजूरी दी थी। उसमें से अब

25 करोड़ रुपये सड़कों की मुरम्मत के लिए हमें दे दिये गये हैं तथा बाकी पैसा भी यथाशीघ्र जारी किया जाये। धन्यवाद।

श्री सोमबीर सांगवान (दादरी) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। मैं दो–तीन चीजें आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि वर्ष 2016 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दादरी को जिला बनाया था। उसके बाद पिछले सत्र में दादरी, पलवल और एक जिला और था उसमें मैडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की गई थी। हमने उस मैडिकल कॉलेज के लिए गांव छपार में 350 एकड़ लैंड फ्री ऑफ कोस्ट उपलब्ध करवाई है लेकिन उस पर सरकार ने अभी तक कोई काम शुरू नहीं किया है जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां मैडिकल कॉलेज की घोषणा दो साल पहले की थी जिसकी क्लासें लग रही हैं लेकिन अभी तक कोई बिल्डिंग नहीं बनी है और वहां कोई नई शुरूआत भी अभी तक नहीं हुई है। इसी तरह से कई साल पहले रोहतक रोड पर एक ऑवर ब्रिज बनाने के लिए 29 करोड़ रुपया मंजूर हुआ था लेकिन अभी तक उस पर काम शुरू नहीं हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरी मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है कि उस ऑवर ब्रिज को बनाने की घोषणा भी की गई है और उसका पैसा भी मंजूर हो गया है लेकिन उसके बाद भी अधिकारियों की नगलीजेंसी के करण, उनकी ढिलाई के कारण वह काम अभी तक पैंडिंग है। उसी तरह दादरी में सीवरेज लाईन बिछाने के लिए 107 करोड़ रुपया मंजूर किया गया है जिसमें 56 करोड़ रुपया सीवरेज लाईन के लिए मिल भी गया है लेकिन उस पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। मेरी आप से गुजारिश है कि पैसा आने के बाद भी वह काम पैंडिंग है। माननीय मंत्री जी भी यहां बैठे हुए हैं उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ा सा दादरी हल्के की तरफ भी ध्यान दें। जो पैसा आया हुआ है कम से कम उसका तो सदुपयोग हो । नैना चौटाला जी ने जो दादरी

होस्पिटल में अल्ट्रासाउंड मशीन की बात की है वह मशीन पिछले 5–7 साल से होस्पिटल में आई हुई है लेकिन डॉक्टर न होने के कारण वह यूं ही रखी हुई हैं। वहां डॉक्टर्ज उपलब्ध करवाने के लिए मैंने कई बार मुख्यमंत्री जी को भी लिखकर दिया हुआ है। वह गरीब व पिछड़ा हुआ इलाका है और वहां नजदीक कोई मैडिकल सुविधा भी नहीं है इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए वहां पर डॉक्टर्ज की एप्वायंटमैंट की जाए। वैसे तो पूरे हरियाण प्रदेश के अन्दर डॉक्टर्ज की कमी है। कम से कम उस क्षेत्र के हिसाब से वहां कुछ डॉक्टर्ज तो एप्वायंट जरूर हो जाएं या फिर कोई टैम्परेरी व्यवस्था हो जाए ताकि समस्या का समाधान हो जाए। इसी तरह से मेरे हल्के की तीन–चार चीजें और हैं जो पैंडिंग हैं। हमारे वहां एक नये बस स्टैंड की आवश्यकता है क्योंकि वहां जो पुराना बस स्टैंड है वह शहर के अन्दर आ गया है जिससे वहां चारों तरफ जाम की स्थिति बनी रहती है। मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं अगर उस बस स्टैंड को बाहर शिफ्ट कर दिया जाए तो वहां जाम की स्थिति से निजात मिल सकती है। इसी तरह से हमारे वहां सी.सी.आई. (सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया) की 204 एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है उसका सदुपयोग करके वहां कोई कॉमर्शियल सैक्टर डिवैल्प करके उस जमीन का सुधार किया जाए क्योंकि उस जगह की चारों तरफ बढ़िया कनैक्टिविटी होने के कारण दादरी में गुरूग्राम की तर्ज पर अच्छी सुविधा देकर दादरी को बेहतरीन जिला बनाया जा सकता है और वहां सैक्रेटेरियेट डिवैल्प किया जाए। मैडिकल कॉलेज व जिन स्कूल्ज में स्टाफ की कमी है उनमें तुरंत प्रभाव से स्टाफ एप्वायंट करके वहां सुधार किया जाए। मैं आपके माध्यम से दो–तीन बातें और बताना चाहता हूं। बिजली मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं मैं उनके नोटिस में भी लाना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में पिछले 6 महीने से बिजली के बिल नहीं आ रहे हैं। उसके बाद लोगों के बिजली के बिल ज्यादा हो जाएंगे फिर वे बिल को भर नहीं पाएंगे और वे डिफाल्टर

हो जाएंगे। अतः मैं बिजली मंत्री जी से रिक्वैस्ट करूंगा कि इसकी व्यवस्था जरूर की जाए। हमारे क्षेत्र के 42 गांवों के बारिश के पानी की निकासी के समाधान की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी लेकिन अब तक वह काम शुरू नहीं हुआ है। मेरे क्षेत्र के ज्यादातर काम तो हो गये हैं लेकिन कुछ कामों का पैसा भी आ गया है लेकिन काम शुरू नहीं हुए हैं इसलिए मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं जितना जल्दी हो सके इन कामों को किया जाए क्योंकि आगे आने वाले समय में बारिश का मौसम आने वाला है। अतः सीवरेज की, पीने के पानी की और रेन वाटर की जो समस्या है अगर उसमें अभी से काम शुरू होगा तभी इस समस्या का समाधान होगा। पिछले दो साल से मैंने तो हर बार कहा है कि हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा मैडल जीतने वाला हमारा हरियाणा प्रदेश है और उसमें बहुत बड़ी भागीदारी हमारे चरखी दादरी व भिवानी जिले के खिलाड़ियों की है। नैशनल और इंटरनैशनल खिलाड़ी बहन गीता–बबीता चाहे रैसलिंग में हो, हवासिंह कोच चाहे बॉक्सिंग में हो, लीला राम, दयानन्द जैसे कितने उच्च कोटि के पहलवान वहां हुए हैं। उस इलाके में खेलों के लिए बेहतर सिस्टम है। अगर सरकार वहां एक स्पोर्टस यूनिवर्सिटी और दे दे तो ज्यादा से ज्यादा मैडल जीतने में चरखी दादरी व भिवानी जिले का बहुत बड़ा योगदान मिल सकता है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एक उपहार के रूप में या यह कह सकते हैं कि बेहतरीन व्यवस्था के लिए, खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की जो इस प्रकार की पॉलिसी है कि हमारे हरियाणा के बच्चे ज्यादा से ज्यादा मैडल जीतें तो अगर दादरी जिले के अन्दर एक स्पोर्टस यूनिवर्सिटी मिल जाए तो बच्चों का बहुत भला होगा। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए आपका तहेदिल से आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री असीम गोयल(अम्बाला शहर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जीरो आवर पर अपने हल्के की कुछ बातों को रखने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय, जो होटल्ज हैं, मैरिज पैलेसिज हैं या बैंक्वेट हाल हैं, इनको वाटर रिसोर्सिज डिपार्टमैंट, पोल्यूशन डिपार्टमैंट तथा कारपोरेशन की तरफ से गारबेज टैक्स के संदर्भ में एन.जी.टी. का संदर्भ लेकर नोटिसिज दिए जा रहे हैं। अतः मेरा सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जो होटल्ज, मैरिज पैलेसिज और बैंक्वेट हाल एन.जी.टी. के नार्म्ज को मैच नहीं कर पाते हैं तो ऐसी अवस्था में इनको राहत देने के लिए सरकार की तरफ से कोई कामन पालिसी बनानी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, हजारों लोगों की आजीविकायें, इन पर डिपैंड करती हैं। इनको जो ये नोटिसिज जारी हुए हैं, के संदर्भ में मैंने इन डिपार्टमैंट्स के हैड्ज से भी बात की है। अतः सदन के माध्यम से मैं पुनः निवेदन करता हूँ कि निश्चित तौर पर होटल्ज, मैरिज पैलेसिज और बैंक्वेट हाल के लिए कामन पॉलिसी बनाई जाये। अब मैं दूसरे विषय पर आता हूँ। अम्बाला के अंदर वाटर लैवल बहुत उंचा है। यदि कंस्ट्रक्शन के लिए तीन फुट भी डिगिंग की जाती है तो भी नीचे से पानी निकलना शुरू हो जाता है। यहां पर सैक्टर्ज के अंदर जो डी.एस.एस. हैं, उनके लिए यह प्रावधान अवेलेबल है कि वे बेसमैंट बना सकते हैं लेकिन अम्बाला की ऐसी स्थिति नहीं है कि वहां पर बेसमैंट का निर्माण किया जा सके। उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा जनहित का मुद्दा है। चूंकि यहां पर बेसमैंट नहीं बन सकती है तो ऐसी अवस्था में सरकार को डी.एस.एस. पर एक अतिरिक्त फ्लोर बनाने की अनुमति दी जाये चाहे इसके लिए सरकार अलग से फीस क्यों न लगा दे। लाखों लोगों की जीविका भी इससे जुड़ी हुई है। अतः सरकार को इस तरह ध्यान देने की जरूरत है। जहां तक अम्बाला की बात है, विभिन्न सैक्टरों के हजारों लोग इस समस्या से त्रस्त हैं।

अगर सरकार की तरफ से इस संदर्भ में पॉलिसी बनाई जायेगी तो इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां एक स्टेडियम है। मैंने इस स्टेडियम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से स्विमिंग पुल बनाने की मांग की थी जिसको पूरा कर दिया गया है और अब इस स्टेडियम में स्विमिंग पुल के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है। इसके साथ ही साथ मेरा सरकार से यह भी अनुरोध है कि यहां पर सिंथेटिक ट्रैक तथा हाकी का टर्फ भी जल्द से जल्द लगाने का काम किया जाये। जिस प्रकार शाहबाद की बच्चियों ने अपनी लगन व मेहनत से पूरे विश्व में हरियाणा का परचम लहराने का काम किया है, वैसे ही उनसे प्रेरणा लेकर हमारे यहां की बच्चे भी इस खेल में उतरना चाहते हैं, अतः सिंथेटिक ट्रैक और हाकी का टर्फ जल्द से जल्द लगाने का काम किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अम्बाला शहर में आई.एम.टी. बनाने की घोषणा की हुई है और इसके लिए हमने 1200 एकड़ भूमि को ई–भूमि पर चढ़वाने का काम भी कर दिया है और यह पोर्टल अभी हाल ही में बंद हुआ है। अतः मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि अम्बाला शहर में आई.एम.टी. को भी जल्द से जल्द मूर्त रूप देने का काम किया जाये। ई–भूमि पर जिन लोगो ने अपनी जमीन की पेशकश की है उनसे नैगोशिएशन करके इस संदर्भ में आगे बढ़ने का काम किया जाये। अब मैं वीटा प्लांट के विषय पर आता हूँ। अम्बाला के अंदर हरियाणा का सबसे पुराना वीटा प्लांट है। आदरणीय मंत्री जी सदन में मौजूद हैं, उन्होंने कह रखा है कि जिस दिन भी यहां ई–भूमि पोर्टल पर जमीन की सभी प्रकार की फोरमैलेटिज पूरी हो जायेंगी तो एक उन्नत किस्म का नई टैक्नोलोजी से युक्त वीटा का प्लांट जिसमें 5 लाख लीटर दूध रोजाना कैटर किया जा सकेगा, ऐसे प्लांट को अम्बाला में स्थापित करने का काम किया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, जमीन के रेट दिन–प्रतिदिन बढ़ते जा रहे है। छह महीने पहले जो रेट था वह

आज और ज्यादा बढ़ गया है। हमने इच्छुक किसान साथियों से ई–भूमि पोर्टल पर इसके लिए निविदाएं डलवा दी हैं। अतः इस तरफ भी सरकार को जल्द से जल्द कदम उठाने की जरूरत है। अब मैं तीसरे विषय पर बात करना चाहूंगा। अम्बाला शहर में 150 साल पुरानी अंग्रेजों के जमाने की एक पुरानी जेल है जोकि आज के समय में रिहायशी क्षेत्र के बीचों बीच आ गई है। इस जेल में 700 कैदियों को रखने की क्षमता है लेकिन बावजूद इसके यहां पर क्षमता से अधिक कैदियों को रखा जाता है। लोगों की सेफ्टी के ध्यानार्थ, मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस जेल को अम्बाला शहर के बाहर शिफ्ट करने का काम किया जाये। इसके लिए भी हमने ई–भूमि पोर्टल पर इच्छुक किसान साथियों से 145 एकड़ जमीन डलवाने का काम किया है। अंत में मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए पुनः अनुरोध करना चाहूंगा कि ई–भूमि के तीनों काम अर्थात आई.एम.टी., उच्च क्षमता का वीटा प्लांट तथा जेल को शिफ्ट करने के काम को सरकार जल्द से जल्द मूर्त रूप देने का काम करे। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री राम करण काला: उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का समय तो नहीं मिल पाया है अतः आपसे निवदेन है कि मेरी लिखित स्पीच को प्रोसिडिंग्ज का पार्ट बनाया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है।

***श्री राम करण काला:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री

———————————————

***चेयर के आदेशानुसार उपरोक्त लिखित स्पीच को प्रोसिडिंग्ज का पार्ट बनाया गया।**

जी तथा माननीय उप–मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि शाहबाद हल्के में बस स्टैंड के सामने अंडरपास बनाए जाने की अति आवश्यकता है। मैंने पहले सैशन में भी इसके लिए आवाज उठाई थी एवं पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी शाहबाद में बस स्टैंड के सामने रूके भी थे। अभी शाहबाद हल्के के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से इसके लिए मांग की थी। शाहबाद में बस स्टैंड के सामने से एन.एच.ए.आई का रोड जिस पर दोनों तरफ रेलिंग लगी हुई है, सड़क को पार करने के लिए ओवर ब्रिज जोकि लोहे का है और जिस पर सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता है। बुजुर्ग व्यक्ति उस पर चढ़ने में असमर्थ हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग उस सड़क को नीचे से क्रास करते हैं। कईं बार बड़े दुखःद हादसे भी हो जाते हैं। पूरे शाहबाद हलके की पुरजोर मांग है कि शाहबाद बस स्टैंड के सामने अंडरपास जरूर बनना चाहिए। शाहबाद की सी.एच.सी में डाक्टरों की कमी है जिसमें मुख्य रूप से लेडी डाक्टर, बच्चों के डाक्टर, अल्ट्रासाउंड की मशीन एवं अन्य स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भारी कमी है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध है कि शाहबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टरों की कमी एव अन्य संसाधनों की पूर्ति जल्द से जल्द करवाई जाये। ई–टैंडरिंग के मामले में मेरा सुझाव है कि ग्राम पंचायत के विकास के लिए केन्द्र सरकार से मिलने वाली ग्रांट को टैंडर से तथा ग्राम पंचायत की आय ग्राम विकास के कार्यों के लिए निर्वाचित ग्राम पंचायत एवं सरपंच के द्वारा ही खर्च किया जाना चाहिए तथा राज्य सरकार से मिलने वाली विकास कार्यों की ग्रांट का कम से कम दस लाख रूपये तक खर्च करने की क्षमता सरपंच एवं ग्राम पंचायत को मिलनी चाहिए जिसके चलते सरपंच अपनी ग्राम पंचायत का विकास करवा सकें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सैशन में पिछली बार आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय उप–मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया

था कि पीने के पानी के लिए जो ट्यूबवैल हैं, उनका रखरखाव पूरी तरह से जन स्वास्थ्य विभाग को ही दिया जाये एवं उन ट्यूबवैलों पर आपरेटर रखने का अधिकार भी जन स्वास्थ्य विभाग को ही दिया जाना चाहिए। मैं जानना चाहूंगा कि सरकार ने इस संदर्भ में क्या जरूरी कदम उठाये हैं। भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों को उनकी फसल का मूल्य बहुत देरी से मिलता है जिससे किसानों को अपना खर्च चलाने में बहुत मुश्किल होती है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी व माननीय उप–मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस योजना के तहत किसान को उसकी फसल का मूल्य जल्द से जल्द मिलना चाहिए। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय उप–मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जो फंड मुख्यमंत्री किसान खेत सड़क मार्ग योजना, हरियाणा के तहत जारी किया गया था, किसी कारण से सरकार के द्वारा वह फंड वापस ले लिया गया है और हमने पूरे हल्के में किसानों को बता दिया था कि उनके यह रास्ते मंजूर हो गए लेकिन अब उनके लिए फंड वापिस लेने के कारण उन कार्यों के टैंडर नहीं हो रहे हैं। अतः अनुरोध है कि वह फंड जल्द से जल्द जारी करने का कष्ट करें ताकि किसानों से किए गए वायदों को पूरा किया जा सके। ग्राम पंचायत में किसी महत्वपूर्ण जगह से जैसे कि शमशान घाट या धर्मशाला या किसी गुरूद्वारे के सामने से बिजली की तारों को शिफ्ट करने के कार्य में बिजली विभाग द्वारा बहुत बड़ी राशि का एस्टीमेट बनाया जाता है जोकि ग्राम पंचायत के द्वारा बिजली विभाग को जमा कराना होता है। आपसे अनुरोध है कि सार्वजनिक कार्य के लिए जिसमें पंचायत में ही पैसा जमा कराना हो उसके लिए बिजली विभाग द्वारा कम से कम एस्टीमेट बनवाया जाए। कुछ सरकारी विभागों में चतुर्थ श्रेणी के कच्चे कर्मियों को अभी तक हरियाणा कौशल रोजगार

निगम के माध्यम से नहीं लगाया गया है। कृपया इस दिशा में संज्ञान लेकर जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।

बैठक का स्थगन

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब सदन की कार्यवाही दोपहर भोज के लिए

*01.30 बजे

1 घंटे के लिए *स्थगित की जाती है।

(तत्पश्चात् सदन दोपहर 2.30 बजे तक के लिए स्थगित हुआ।)

(जब सदन समवेत हुआ तो अध्यक्ष महोदय ने सदन की अध्यक्षता की।)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मुझे श्री वरूण चौधरी, विधायक तथा दो अन्य विधायकों सर्वश्री भारत भूषण बतरा तथा आफताब अहमद से अल्प अवधि सूचना संख्या 1 राज्य में स्टिल्ट प्लस चार मंजिला घरों के निर्माण के विरोध से संबंधित प्राप्त हुई जिसे मैंने ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 50 में परिवर्तित करके स्वीकार कर लिया है।

इसी विषय पर ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 42 जो कि श्री नीरज शर्मा, विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण मैंने इन्हें ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 50 के साथ जोड़ दिया है। श्री नीरज शर्मा, विधायक भी चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

अब श्री वरूण चौधरी, विधायक प्रथम हस्ताक्षरी होने के नाते अपनी सूचना पढ़ें।

श्री वरूण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं तथा श्री भारत भूषण बतरा, विधायक श्री आफताब अहमद, विधायक इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि प्रदेश में हरियाणा बिल्डिंग कोड को बार–बार

संशोधित कर स्टिल्ट प्लस चार मंजिला घरों को बनाने की अनुमति दी गई है, जिसका विभिन्न निवासी कल्याण संघो एवं निवासियों द्वारा भारी विरोध किया जा रहा है। यह नीति निर्माता के पक्ष में तथा निवासियों के विपक्ष में बनाई गई है। सड़क, जल–निकासी, सीवरेज, बिजली, पानी की आपूर्ति, पाठशाला, अस्पताल आदि सुधार के बिना चार मंजिलों की अनुमति अनुचित है। आबादी बढ़ने एवं ऊँचे भवनों के कारण यह पार्किंग की समस्या मौजूदा बुनियादी ढांचे पर बोझ, आस–पास के घरों को नुकसान, सूरज की रोशनी को अवरूद्ध एवं हवा के बहाव को रोकने का कार्य कर रही है। इस नीति के कारण जनता में भारी रोष है क्योंकि यह पूरी तरह से उपस्थित भू–निर्माण को बर्बाद कर देगा। अतः सरकार इस विषय पर अपना वक्तव्य दे।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 42
स्वीकृत अल्प अवधि चर्चा संख्या 1 परिवर्तित ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 50 के साथ सलंग्न

ध्यानाकर्षण सचूना संख्या 42 के द्वारा श्री नीरज शर्मा, विधायक हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सैक्टरों में स्टिल्ट प्लस चार मंजिला की अनुमति बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सैक्टरों में स्टिल्ट प्लस चार मंजिला मकान बनवाने की अनुमति जारी की है, जिसके कारण सैक्टर वासियों में काफी रोष है क्योंकि उनका कहना है कि अनुमति से पहले सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर ध्यान देना चाहिए। इसका बड़ा कारण इस नीति के बनने के बाद पुराने सेक्टरों में शुरू हुए चार मंजिला भवनों के निर्माण की वजह से पुराने घरों में आ रही दरारें और अन्य कारण हैं। हवाएं धूप, पार्किंग तथा सीवरेज की समस्या पैदा होने लगी है। इस पर विस्तृत चर्चा की जाए।

वक्तव्य–

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल): अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्र तलों की रजिस्ट्री, रिहायशी प्लाटों के तीन तलों तक का प्रचलन हरियाणा के शहरों में 2009 के आस–पास तेज हुआ, जब इसके बारे में नीति निर्धारित की गई तथा अधिनियम में भी संशोधन किया गया।

बाद में जब दिल्ली में चार तलों के निर्माण तथा ऐसे तलों की रजिस्ट्री ने 2014 में काफी जोर पकड़ा, तब प्राकृतिक रूप से हरियाणा के शहरों में भी चार तलों की रजिस्ट्री को अनुमोदित करने हेतु आवाज उठने लगी।

परिणामस्वरूप, 2017–2018 के मध्य जन–साधारण की मांग चार तलों की रजिस्ट्री के लिए काफी तेज हो गई थी। जन–साधारण की इस मांग को ध्यान में रखते हुए पहली बार 21.11.2018 को नीतिगत निर्णय के अधीन चार तलों की रजिस्ट्री को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। चार मंजिलों के पंजीकरण की अनुमति देने का नीतिगत निर्णय पूरे राज्य में लागू किया गया तथा डिवैल्परों /कॉलोनाईजरों एवं एच.एस.वी.पी. द्वारा निर्मित रिहायशी भूखंडों को भी इसमें शामिल किया गया है।

अब तक हरियाणा के विभिन्न शहरों के लाइसेंसों में लगभग 6500 मामलों में चौथी मंजिल के निर्माण/पंजीकरण के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें से अधिकांश भूखंडों पर निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और इनमें से कई में मंजिलों का पंजीकरण भी पूरा हो चुका है। इसके अलावा, लगभग 12,000 भूखंडों के नक्शे एच.एस.वी.पी. विभाग द्वारा स्टिल्ट + 4 तलों के लिए स्वीकृत किए गए हैं।

इस समय मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर सेवाओं को तत्काल उन्नत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पार्किंग की समस्या को कम करने के लिए स्टिल्ट प्लस चार मंजिलों के निर्माण के मामले में स्टिल्ट के निर्माण का प्रावधान अनिवार्य है। हालांकि भूतल कवरेज बढ़ाने के लिए, सैटबैक कम कर दिए गए हैं, लेकिन पर्याप्त रोशनी और हवा के लिए न्यूनतम सैटबैक रखे गए हैं। एच.एस.वी.पी. द्वारा स्टिल्ट प्लस चार मंजिलों के निर्माण की निगरानी के लिए आसपास के प्लॉट धारकों की जानकारी के लिए एक तंत्र विकसित किया गया है। भूखंडों के निर्माण के कारण किसी भी नुकसान की शिकायत होने पर, अधिकारियों की एक समिति निर्माणाधीन स्थलों का दौरा करेगी और क्षति का आंकलन करेगी। समिति की संतुष्टि के अनुसार क्षतिग्रस्त भवन की मरम्मत के बाद ही आगे के निर्माण की अनुमति दी जाएगी।

इस तरह के मांग के उपर फैसला लेते हुए कई बातों का ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक है। सारे विश्व में शहरों के सघन विकास (compact development) को विशेष बल दिया जा रहा है जिससे कि कम इलाके में लंबवत विकास (vertical development) करके ज्यादा लोगों को मकान मुहैया कराया जा सके तथा उनके सुविधाओं का भी स्थानीय स्तर पर ही ध्यान रखा जा सके।

ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हम कोई आकस्मिक निर्णय ले लें तथा बाद में फिर लोगों का मत सामने आए कि बंद करने का निर्णय इन स्थितियों में या इन शहरों में उचित नहीं था और इस विषय पर वापस मंथन शुरू हो जाए। इस प्रकार, एक व्यापक निर्णय पर पहुंचने से पहले सभी उपयुक्त कारकों पर विचार करना महत्वपूर्ण है और सरकार जनता से प्राप्त सभी प्रमाणों और

प्रतिक्रियाओं पर विचार करते हुए नीति की जांच और संशोधन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

श्री वरूण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी मान रहे हैं कि इस नीति में कमियां हैं और इसकी समीक्षा की जाएगी । माननीय मंत्री जी खुद कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हम आकस्मिक कोई निर्णय ले लें तथा बाद में लोगों का मत सामने आये कि इन स्थितियों में इन शहरों में इसको बंद करने का निर्णय सही नहीं था । जब स्टिल्ट जमा चार मंजिल भवन नीति का प्रावधान किया गया था तो इस विषय में उसी समय विचार कर लेना चाहिए था कि यह ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है । अगर इस विषय में उस समय कोई समिति बनी हुई होती तो आज यह समस्या पैदा न होती । अध्यक्ष महोदय, आज पूरे प्रदेश में इस नीति के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चल रहा है । श्री वी.पी. मलिक, पूर्व सेनाध्यक्ष ने भी इस नीति के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवाया है । अध्यक्ष महोदय, Residents Welfare Association v/s The Union Territory of Chandigarh के केस में सुप्रीम कोर्ट की 10 जनवरी, 2023 की एक जजमैंट है । मैं इसका पैरा नं. 167 और पैरा नं. 168 पढ़कर सुनाना चाहता हूं ।

167. Before we part with the judgment, we observe that it is high time that the Legislature, the Executive and the Policy Makers at the Centre as well as at the State levels take note of the damage to the environment on account of haphazard developments and take a call to take necessary measures to ensure that the development does not damage the environment. It is necessary that a proper balance is struck between sustainable development and environmental protection. We therefore appeal to the Legislature, the Executive and the Policy Makers at the Centre as well as at the State levels to make necessary provisions for carrying out Environmental Impact Assessment studies before permitting urban development.

168. We direct the copy of this judgment to be forwarded to the Cabinet Secretary to the Union of India and the Chief Secretaries

to all the States to take note of the aforesaid observations. We hope that the Union of India as well as the State Governments will take earnest steps in that regard.

अध्यक्ष महोदय, यह बात environmental impact assessment यानि कि पर्यावरण प्रभाव आकलन जिसमें क्षेत्र के वायु मंडल, स्थल मंडल, जीवन मंडल और जल मंडल पर प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है । वह मूल्यांकन नहीं हुआ है । उस मूल्यांकन के बिना ही बार–बार हरियाणा बिल्डिंग कोड को बदला गया । इसमें क्या जल्दबाजी थी और किसको फायदा पहुंचाने की आवश्यकता थी ? आज जहां पर भी ये चार मंजिला इमारतें बनी हैं वे सब परेशान हैं । माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि इससे पार्किंग का सुधार हुआ है । अध्यक्ष महोदय, इससे तो पार्किंग की समस्या और बढ़ी है । आज आप चाहे एक समिति बनाकर 10 बजे पूरे प्रदेश में भेज दें जहां पर भी स्टिल्ट जमा चार मंजिला इमारतें बनी हैं उनकी गाड़ियां भी बाहर खड़ी होती हैं । जिस घर में पहले 4–5 सदस्य रहते थे आज अपार्टमैंट्स बनने के कारण 20 से 25 लोग उसी स्थान पर रहने लगे हैं । हमारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को न तो ठीक किया गया और न ही उसे बढ़ाया गया तो फिर समस्या का समाधान कैसे होगा ? इस निर्णय से प्रदेश की जनता बड़ी नाखुश है । माननीय मंत्री जी ने माना है कि इसमें कमियां हैं तो इसके लिए जल्द–से–जल्द समिति का गठन किया जाए और वह समिति सिर्फ एक शहर के लिए नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए बनाई जाए । मैं तो हैरान हूं कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी, 2023 को मुख्य सचिव को भी इस बारे में लिखा है तो मुझे लगता है कि इसकी कॉपी तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय को भी पहुंचाई गई होगी कि इस तरह का environmental impact assessment पहले होना चाहिए । उसके बाद ही सरकार को बिल्डिंग कोड में बदलाव के लिए कोई फैसला लेना चाहिए ।

श्री वरुण चौधरी: जारी– अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना है कि जनहित में हरियाणा बिल्डिंग कोड को जल्द से जल्द बदला जाए और ये जो 4 मंजिलों का प्रावधान है, उसको बन्द किया जाए।

....

पंजाब विधान सभा के सदस्य का अभिनंदन

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री गुरमीत सिंह विधायक, पंजाब विधान सभा, सदन की कार्यवाही देखने के लिए सदन की विशिष्ठ दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं सदन की तरफ से उनका स्वागत करता हूं।

....

श्री मनीराम गोदारा राजकीय महाविद्यालय भोडिया खेड़ा, जिला फतेहाबाद के अध्यापकगण एवं विद्यार्थियों का अभिनन्दन

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, श्री मनीराम गोदारा राजकीय महाविद्यालय, भोडिया खेड़ा के अध्यापकगण एवं विद्यार्थी सदन की कार्यवाही देखने के लिए सदन की दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं सदन की तरफ से इनका अभिनन्दन करता हूँ।

....

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री भारत भूषण बत्तरा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पर्यावरण जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इस सरकार को ऐसे फैसले लेने से पहले सोचना चाहिए था कि क्या ये टोटल जनरल हैल्थ और जनहित में है या नहीं है ? सरकार 4–4 मंजिला मकान बनाने के लिए अलाउ करती है, लेकिन उसके पास कैपेसिटी कितनी है? पानी की कैपेसिटी वही है, सीवरेज की कैपेसिटी वही है, रोड्ज उतनी ही विड्द की हैं और रोड्ज की विड्द बढ़ा नहीं सकते। उसके बाद जब एच.एस.वी.पी. में कंस्ट्रक्शंज होती हैं और साथ वालों को 4

मंजिला मकान बनाने के लिए अलाउ कर दिया तो साईड वाले मकानों में क्रैक्स आ जाती हैं। इसके कारण डिफिकल्टी होती है। Speaker Sir, there is a resentment in the residents so far as the Government decision to allow four floors with stilt parking has impacted the residents directly or indirectly and created issues where none existed. While the infrastructure is not equipped to handle this increased load, the decision has led to high-rises in plotted sectors, impacting services, locking out sunlight and depriving residents of clean air as rampant constructions goes on. अगर एक मकान के साथ में 4 मंजिला मकान बन जाता है तो दूसरे मकान में न तो हवा आती है और न ही रोशनी आती है। एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें धूप की भी बड़ी जरूरी होती है। अध्यक्ष महोदय, इसमें एक छोटा– से उदाहरण के तौर पर रोहतक का सैक्टर–1 ही ले लें। यह सैक्टर सन् 1986–87 में बना था और उसके बाद जितना भी डाउन दा अर्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर है, वह बहुत पुराना हो चुका है। उसी के हिसाब से आगे डिवैल्पमैंट होगी। अगर आप उसको 4 फ्लोर करके 4 गुणा आबादी बढाएंगे तो उसके लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर चेंज करें। इसके लिए आप या तो सीवरेज की नयी पाइप लाईंज डालें और पानी की सप्लाई के लिए नयी पाइप लाईंज डालें। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि air and sun लाईफ का पार्ट है। ये चीजें लोगों को जीवन के लिए मिलनी बहुत जरूरी हैं। ये लोगों की सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं। इससे सिर्फ बिल्डर्ज को ही फायदा मिल रहा है और किसी को फायदा नहीं मिल रहा है। The issue of water shortage, increasing traffic, choked sewerage, increased load on the existing infrastructure and environmental pollution caused by construction of four floors. अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा

कि आपने तो पंचकुला के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मंजूर करवा लिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी से ऑर्डर भी करवा लिये हैं। इसके अलावा बाकी शहरों का क्या हाल होगा ?

श्री अध्यक्षः बत्तरा जी, अभी इस संबंध में ऑर्डर नहीं हुए हैं।

श्री भारत भूषण बत्तराः अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि इस संबंध में ऑर्डर होने चाहिएं। आप पंचकुला के लिए एक मैट्रोपोलिटन सिटी की कल्पना करते हैं। आप भी इस बात के लिए महसूस करते हैं और हम सभी माननीय विधायकगण भी महसूस करते हैं कि मल्टी लैवल बिल्डिंग्ज बनाने के लिए बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर तो पैदा करें। चूंकि हमारे शहरों में 50 साल पुरानी पाइप लाईंज डली हुई हैं। सरकार से ये ही नहीं संभल रही हैं। सीवरेज की समस्या प्रदेश की बहुत बड़ी समस्या है। पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। रोड्ज की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि ये तीनों सुविधाएं सरकार लोगों को उपलब्ध करवा दे तो वे खुश हो जाएंगे और यह बात कहेंगे कि सरकार बहुत अच्छी है, परन्तु सरकार लोगों को ये सुविधाएं नहीं दे पा रही है। इसके अलावा मैं कोट करना चाहूंगा कि–

> "Retd. General, Shri V.P. Malik has put words of thanks to the Hon'ble Speaker, Shri Gian Chand Gupta ji for the steps you have taken in this regard. He said that "I have seen the statement given by Hon'ble Speaker, Shri Gian Chand Gupta. I am happy that he took the matter to the Chief Minister, Haryana and he agreed to stop S+4 activity but I believe in seeing action on ground. So, I would wait for written orders and its effect on the ground."

अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि आपके यहां इतनी elite families रहती हैं आपने PMDA (Panchkula Metropolitan Development Authority) के लिए तो यह ऑर्डर करवा लिया है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि वे लोग रिक्वैस्ट कर रहे हैं कि सभी शहरों का ऑर्डर करवाईये एक शहर का नहीं। अगर मुख्यमंत्री सदन में होते तो हम उनसे यह बात पूछते कि बिल्डिंग बाई लॉज रोज–रोज क्यों चेंज करते रहते हो इसकी क्या जरूरत है? अब आपने वर्ष 2022 में एक नोटिफिकेशन करके मल्टी स्टोरी का ऑर्डर कर दिया और some times in some floors there is unlimited heights. कहीं–कहीं तो 16.5 हो गया है। फ्लोर एरिया रेशो (एफ.ए.आर.) बढ़ाने के लिए सभी चीजों को ध्यान में रखना बड़ा जरूरी होता है। मैं एक मिनट का छोटा सा उदाहरण दूंगा। मैं वर्ष 2009 से वर्ष 2014 में विधायक था। फ्लोर एरिया रेशो (एफ.ए.आर.) बढ़ाने के लिए मैंने बहुत जोर लगाया और जब इलैक्शन नजदीक आया तो हुड्डा साहब ने इसके लिए एक मीटिंग बुलाई जिसमें मिस्टर श्री ढिल्लो, श्री टी.सी. गुप्ता और श्री खंडेलवाल जैसे अधिकारी शामिल थे। मैंने उनको कवर्ड एरिया का जिक्र किया जिस तरह से आपने इस टाइम 100 मीटर के ऊपर 75 परसैंट अलाउ कर दिया है। जैसे आपने 75 परसैंट का 250 मीटर तक कर दिया है। सभी ऑफिसर एक दम चौंक पड़े कि हम किसी भी हालत में यह रिक्वैस्ट एक्सीड नहीं करेंगे। इस बात के लिए फैसिलिटीज होनी चाहिए और इस बात के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए और सीवरेज सिस्टम को बर्दाशत करने के लिए पानी भी होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यही है कि वहां पर सब कुछ होना चाहिए। अगर सब कुछ प्रदान करोगे और सारे शहरों में नये सीवरेज सिस्टम डाल दोगे तब तो इस बात को ठीक माना जायेगा। आज कल लोगों को रहने की प्रॉब्लम है। इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि प्रोपर्टी महंगी होती है लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं।

परिवार बढ़ रहे हैं। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर सारे ठीक कीजिए। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा तब तक इस ऑर्डर को रोका जाना चाहिए। यह मेरी रिक्वैस्ट है।

Shri Aftab Ahmed: Sir, I think all my concerns have been covered by both the Members, Shri Varun Chaudhary Ji and Shri B.B. Batra Ji. Kindly allow other Member to speak.

श्री नीरज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जब किसी भी शहर का मास्टर प्लान बनता है तो उस मास्टर में जो सबसे मूलभूत संरचना हम लोग रखते हैं वह जनसंख्या की रखते हैं और उसमें समय–समय पर बदलाव भी करते हैं। मास्टर प्लान में जब भी कोई बदलाव होता है तो उसमें एक लाइन पहले लिखी जाती है कि ये वर्ष 2021 का था अब हम वर्ष 2025 का मास्टर प्लान बना रहे हैं या वर्ष 2031 का मास्टर प्लान बना रहे हैं या वर्ष 2041 का मास्टर प्लान बना रहे हैं और इसकी अनुमानित जनसंख्या इतनी होगी क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी इसके हिसाब से हम मास्टर प्लान में चेंज कर रहे हैं। जब हम मास्टर प्लान में चेंज करते हैं तो हम हर सैक्टर के अंदर पी.पी.ए. निर्धारित करते हैं कि इस सैक्टर के अंदर पापुलेशन पर एकड़ इतनी रहेगी। जब इसके नक्शे पास होते हैं तो यह बात डिसाइड होती है कि यह 2 बी.एच.के. का बनेगा या 3 बी.एच.के. का बनेगा या 4 बी.एच.के. का बनेगा। उसके बाद उस पापुलेशन के हिसाब से बिजली, पानी और सीवरेज की सारी बात आ जाती है। हमारे कहने का मकसद एक ही है कि जो मंत्री जी ने जवाब में भी कहा है कि चौथी मंजिल के लिए 2018 में रजिस्ट्रियों की मांग भी उठी थी और सरकार ने उस मांग की एवज में दिनांक 21.11.2018 को रजिस्ट्रियां खोल भी दी थी। सरकार को पता था कि वह इल्लीगल कार्य हो रहा है। मेरा इसमें यही कहना है कि कानून व्यवस्था के हिसाब से उस इल्लीगल कार्य पर

एक्शन लेते और इस बात का पता करते कि इसमें किन अधिकारियों ने चार मंजिला इमारत बनाने की इजाजत दे दी। सरकार गरीब आदमी के 50 गज के मकान के लिए तो बुलडोजर लेकर पहुंच जाती है। सरकार ने रजिस्ट्री की परमीशन दे दी। अध्यक्ष महोदय, सैनिक कॉलोनी का यह मामला है और इसमें चौथी मंजिल में अड़ोसी पड़ोसी के ऊपर छत गिर गई थी क्योंकि जो पुराने सैक्टर्ज बने हुए हैं, उनमें प्रोपर तरीके से खुदाई तो कर नहीं रहे हैं, earth mover लगाते हैं क्योंकि मकान पुराना है जिसके कारण अगले के मकान में नुकसान हो रहा है। दूसरा सरकार ने स्टिल्ट प्लस चार की पॉलिसी बना दी। हमारे फरीदाबाद में हाउसिंग बोर्ड है उसमें तकरीबन सैक्टर 7—10 में 150 जगह नक्शे पास करवा लिये गए आज आप मौके पर जाकर चैक करवा लो, वहां पर पूरा भ्रष्टाचार का अड्डा या ऐसे कहें कि राजनीतिक संरक्षण का अड्डा बन गया है। उनमें से एक जगह पर भी पार्किंग नहीं हो रही है और वहां पर सब दुकानें खोलकर के बैठे हुए हैं। जिन बेचारों ने अथॉराइज्ड मार्केट में दुकान ली हैं, उनका क्या कसूर है ? उन्होंने संबंधित दुकानें सरकार से ही खरीदी हैं, बाहर से नहीं खरीदीं हैं और पैसा भी सरकार को ही दिया है। अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा आपसे सिर्फ यही कहना है कि सरकार जो नए सैक्टर डिवैल्प कर रही है उसमें आपके पास बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, आप इसको जरूर लागू करें, लेकिन पुराने सैक्टरों में इसे लागू करने से पहले चाहे वहां की आर.डब्ल्यू.एज. से पूछे, चाहे वहां का सर्वे करवाएं और लोगों से राय—शुमारी भी लें और अगर उस सैक्टर के कम से कम 80 प्रतिशत लोग राजी हैं तो इसे लागू करो। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस चीज से शायद आप भी सहमत हैं कि यह बात पंचकुला में भी हो गयी है। पूरे हरियाणा में अभी इस बात के ऊपर क्लैरिटी नहीं है। स्पीकर सर, हम कॉलोनियों में तो कह देते हैं कि पानी के मीटर के कनैक्शन नहीं हैं, सीवरेज के

कनैक्शन नहीं हैं लेकिन सैक्टर 55 के अन्दर एक भी सिंगल घर ऐसा नहीं है जो पानी का बिल न दे रहा हो, सीवरेज का बिल न दे रहा हो। आये दिन सैक्टर 55 के लोग सड़कें तक जाम कर रहे हैं और कल को अगर आपकी ये स्टिल्ट प्लस 4 मंजिल की पॉलिसी आ जाएगी तो जो मौजूदा लोग सैक्टर 55 में रह रहे हैं, वे अभी पीने के पानी के लिए त्राहिमाम–त्राहिमाम कर रहे हैं तो जब यह पॉलिसी लागू हो जाएगी तब बाकी जनता क्या करेगी ? ये मैं आपके माध्यम से सरकार को जरूर कहना चाहूंगा। धन्यवाद।

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि फ्लोर वाइज रजिस्ट्री वर्ष 2018 में शुरू हुई लेकिन ये वर्ष 2009–10 में शुरू हुई थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा।(शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा जो बातें कही गयी हैं उनका जवाब दे रहा हूं। इसलिए माननीय सदस्य बतरा जी को बीच में नहीं बोलना चाहिए। जब माननीय सदस्य ने अपनी बात रखी थी तब मैंने उनके बीच में नहीं बोला था। इसलिए माननीय सदस्य मुझे अपनी बात रखने दें। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि रजिस्ट्री वर्ष 2009 में शुरू हुई थी और पहले घर एक यूनिट माना जाता था, उस समय फ्लोर वाइज रजिस्ट्री नहीं होती थी। कांग्रेस पार्टी की सरकार में ही यह फ्लोर वाइज रजिस्ट्री शुरू हुई थी। उसके बाद वर्ष 2017–18 में दिल्ली में चौथी मंजिल बनानी अलाऊ हुई। अध्यक्ष महोदय, जब दिल्ली में चौथी मंजिल बनानी अलाऊ हुई, उसके बाद ही यह आवाज हरियाणा प्रदेश में भी उठी थी। तब यह फैसला हुआ था कि दिल्ली में चार मंजिल अलाऊ हैं और हमारे यहां के लोगों की डिमांड है तो फिर चौथी मंजिल बनाने की रजिस्ट्री

शुरू कर दी गई। कई सदस्य कहते हैं कि इसके लिए न तो पानी है, न बिजली है और न ही सड़क है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि जब अर्बन प्लानिंग होती है तब बाकायदा उसका डिजाइन देखा जाता है। अब जो एफ.ए.आर. दिया गया है, जिसमें चौथी मंजिल की परमिशन दी गई है उसके प्रोवीजन में सड़क है, सीवर भी है और वाटर सप्लाई भी है। यह डिजाइनर की मर्जी के बगैर प्लानिंग में हो ही नहीं सकता। उनका बिल्डिंग कोड है इसमें यह प्रोवीजन है कि हमारा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्टक्चर है उसमें सड़क, पानी, बिजली ले सकता है। अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि पिछली सरकार में बहुत सारी लाइनें खींच–खींचकर हजारों एकड़ जमीन में कॉलोनियां काट दी गईं, वहां पर न तो सीवर है और न ही सड़कें हैं। वहां का ई.डी.सी. का पैसा दूसरे शहर में लगा दिया गया। आज भी फरीदाबाद का सैक्टर 55, और गुरुग्राम में स्लम बना हुआ है। इसकी वजह यही है कि कागजों में तो सैक्टर बसा दिये गये जबकि मौके पर कुछ नहीं बनाया गया। ई.डी.सी. का पैसा ले लिया गया और उसे डायवर्ट कर दिया गया जिसके कारण ये सारी समस्याएं पैदा हो गई हैं। वहां पर न तो 24 मीटर की सड़क है और न ही उसके लिए कोई जमीन एक्वायर की गई है। यह समस्या बनी हुई है लेकिन हम धीरे–धीरे करके इसको सुधार रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे दुनिया के बड़े–बड़े शहरों में सिंगापुर, हॉन्गकॉग, न्यूयार्क तथा लंदन हैं और वहां हमारे एफ.ए.आर. से दो गुना, तीन गुना, चार गुना तक एफ.ए.आर. अलाउड है यह वर्टिकल में अलाउड है, लेकिन वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी देना पड़ता है। हमारे यहां पर 1 लाख गाड़ियों की पार्किंग का प्रावधान स्टिल्ट पॉलिसी प्रोवीजन की वजह से अलग से उपलब्ध किया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि किसी आदमी ने प्लॉट खरीदा तब उसने देखा था कि यहां इतना एफ.ए.आर. अलाउड है और मेरे पड़ोस

में चार मंजिल का घर नहीं बनेगा। उसको दिक्कत हो सकती है तो इसमें हम यह नहीं कहते कि उसने एकदम से चार मंजिल क्यों बना ली ? लेकिन जो बिल्डिंग बाईलाज और कोड हैं, उनके हिसाब से सैटबैक भी छोड़ना पड़ता है। आगे–पीछे, दाएं–बाएं भी जगह छोड़नी पड़ती है और पार्किंग का प्रोवीजन भी छोड़ना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, जो बिल्डिंग बाईलाज या पॉलिसिज हैं, ये कोई परमानेंट चीज नहीं होती। इनके ऊपर वक्त–वक्त पर विचार करते रहते हैं और इसे जरूरत के अनुसार बदलते भी रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज जो नई मांग माननीय सदस्य ने उठाई है, हम उस पर एडामैंट नहीं है कि उनकी बात नहीं सुनेंगे। हम उनकी इस बात पर भी ध्यान देंगे कि जो अच्छे टाउन प्लानर हैं, अर्बन टाउन प्लानर हैं, जो अच्छे–अच्छे सिटीजन हैं, उनसे सलाह लेकर के आगे की पॉलिसी में विचार करके सुधार किया जा सकता है कि किस तरह से किस सैक्टर में क्या जरूरतें हैं। एक सैक्टर स्पैसिफिक ऐसा भी हो सकता है जिसमें सिंगल स्टोरी बिल्डिंग अलाऊ कर दी जाये। अभी भी बहुत सारे सैक्टर्ज ऐसे हैं जिनमें सैक्टर के बीच में 20 एकड़ जमीन है उसमें 20 मंजिल की अनुमति दे रखी है। इससे प्लॉट वाले को समस्या हो जाती है। इस प्रकार से समस्यायें हैं। इस कारण से हर जगह की पॉलिसी को बदलते रहते हैं। हमारी सरकार जनसाधारण को सुविधा देने के लिए कृतसंकल्प है। विपक्ष के साथियों ने आज जो विषय उठाया है इस पर भी विचार करने के लिए सरकार तैयार है। जहां–जहां इस विषय से जुड़े हुए लोग हैं जिनको इसकी जानकारी है वे सभी जगहों की स्टडी करके हमारे अनुरूप रिकमण्डेशन देंगे। हम यह भी नहीं चाहते कि हमारी सरकार लोगों को अच्छा घर न दें। हमें स्लम को बनने से भी रोकना

है। कच्ची कालोनी कटने से भी रोकना है। हम यही चाहते हैं कि हम जनता को ऐसी सुविधाएं दें जिससे आम जनता को फायदा हो और किसी को कोई दिक्कत न हो। हमारी सरकार यह काम करने के लिए तैयार है।

श्री वरूण चौधरी : स्पीकर सर, मंत्री जी बता दें कि क्या कोई एनवॉयरनमैंट इम्पैक्ट असैसमैंट करवाई थी।

श्री जय प्रकाश दलाल : स्पीकर सर, जब शुरू में कालोनी का मास्टर प्लॉन बनता है तब एनवॉयरनमैंट असैसमैंट होती है। (विघ्न) जब पूरा सैक्टर बसाया जाता है तब देखा जाता है कि इससे एनवॉयरनमैंट पर क्या इम्पैक्ट आयेगा, कितने आदमी रहेंगे, हवा में क्या इम्पैक्ट आयेगा। हमने कोई डैंसिटी नहीं बढ़ाई। ओवरऑल गुरूग्राम शहर की डैंसिटी वही है। वहां पर उतने ही आदमी रहेंगे।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, जब एक मकान की जगह चार मकान बन जायेंगे तो डैंसिटी तो अपने आप बढ़ जायेगी।

श्री जय प्रकाश दलाल : स्पीकर सर, सारे शहर की आबादी उतनी ही रखी जायेगी।

श्री वरूण चौधरी : स्पीकर सर, मंत्री जी कह रहे हैं कि घनत्व नहीं बढ़ा। मेरा यही कहना है कि घनत्व तो बढ़ गया।

श्री जय प्रकाश दलाल : स्पीकर सर, इसमें मेरा यही कहना है कि पहले जब घर बनता था तो उसकी एक रजिस्ट्री होती थी। रजिस्ट्रियां अलग–अलग नहीं होती थी। कांग्रेस के समय में उसकी तीन रजिस्ट्रियां

अलाऊ हो गई। अब हमारे टाईम में तीन रजिस्ट्रियों की बजाये चार रजिस्ट्रियां अलाऊ हो गई।

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर सर, मंत्री जी इस बात का जवाब दे दें कि क्या इन्होंने एनवॉयरनमैंट इम्पैक्ट असैसमैंट करवाई है या नहीं करवाई है?

श्री जय प्रकाश दलाल : स्पीकर सर, एनवॉयरनमैंट इम्पैक्ट असैसमैंट की जरूरत मास्टर प्लॉन के समय होती है इसलिए यह तो वही बता सकते हैं जिन्होंने मास्टर प्लॉन बनाया था। इसके बारे में उनसे ही पूछ लिया जाये। जहां तक मास्टर प्लॉन का सम्बन्ध है वह कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में बना था।

श्री अध्यक्ष : ऐसा नहीं है। मंत्री जी मेरी बात सुनिए। मास्टर प्लॉन को आपने चेंज किया है। जिस एक्सपर्ट कमेटी की बात आप आ कर रहे हैं अगर यही एक्सपर्ट कमेटी पहले बनाकर के इसके ऊपर डिसीजन लिया गया होता तो शायद आज यह दिक्कत न आती। अब मुझे लगता है कि यह वास्तविक दिक्कत है क्योंकि मैं खुद इससे प्रभावित हूं। सरकार को इस मामले में जल्दी से जल्दी कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है कि हम इस मामले में विचार करने के लिए तैयार हैं। हमें किसी चीज पर रिजिड नहीं हैं। इस मामले में एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बनाकर उसकी राय लेकर के सभी स्टेक होल्डर्स से पूछ कर कोई न कोई उचित निर्णय लेंगे।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, इस मामले में जो कमेटी बनानी है उसको जल्दी से जल्दी बनायें और उसको अपनी रिपोर्ट देने के लिए टाईम बाउंड कर दें।

श्री जय प्रकाश दलाल : स्पीकर सर, हम तीन महीने में कमेटी बनाकर उसकी राय लेंगे।

श्री भारत भूषण बतरा : स्पीकर सर, इस मामले में विचार करने के लिए जल्दी से जल्दी एक्सपर्ट कमेटी बने। मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी इस हाऊस के अंदर यह एश्योरैंस दें कि till the expert Committee Report comes इसको अबेयैंस में रखा जाये।

श्री जय प्रकाश दलाल : स्पीकर सर, अगर किसी ने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी होगी तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं?

श्री भारत भूषण बतरा : स्पीकर सर, मेरा तो यही कहना है कि जो सरकार ने लाईसैंस दे दिये हैं वे तो ठीक हैं लेकिन आगे सरकार लाईसैंस देना बंद कर दे।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, आप आगे नक्शे पास मत करें। कम से कम यह तो आप कर ही सकते हैं।

श्री जय प्रकाश दलाल : स्पीकर सर, आज के दिन जो कानून है हमें उसी को फोलो करना होता है।

श्री नीरज शर्माः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे सैक्टर–55 का नाम लिया है कि वहां के कुछ ड्यूज बकाया रहते हैं। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि सैक्टर–55, एच.एस.वी.पी. का सैक्टर है और मेरे सैक्टर–55 के निवासी

जो–जो चीज इस्तेमाल करते हैं उसका एक–एक पैसा जमा करवाते हैं इसलिए सरकार का भी यह दायित्व बनता है कि वहां के निवासियों को पानी, सीवरेज तथा सड़कों की सभी सुविधायें मुहैया करवाई जायें।

....

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भ तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा पुनरारम्भ होती है। जो नाम मेरे पास बोलने के लिए आये हैं मैं उनके नाम बता देता हूं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के 15 सदस्यों के नाम आए हुए हैं, जननायक जनता पार्टी के 3 सदस्यों के नाम आए हुए हैं तथा कांग्रेस पार्टी के कुल 10 सदस्यों के नाम बोलने के लिए मेरे पास आए हुए हैं। इस प्रकार से कुल 28 विधायकों को अभी बोलना है। इसलिए हमें समय का ध्यान रखना है। अभी तक हमने जो समय कैलकुलेट किया है उसके अनुसार 197 मिनट बोल चुके हैं और 163 मिनट हमारे पास बकाया हैं। इस प्रकार से लगभग 3 घंटे का समय है और उसी में ये सभी सदस्य कम्पलीट हो जाने चाहिएं। ये सभी नाम आज नहीं आ पायेंगे क्योंकि 4.30 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी को इस अभिभाषण पर हुइ चर्चा का जवाब देना है इसलिए इसमें लगभग हमारे पास डेढ़ घंटा बचा हुआ है और उसमें जो भी होगा उसको हम ले लेंगे। अब मैं यह सूची पढ़ देता हूं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के श्री हरविन्द्र कल्याण, श्री लक्ष्मण सिंह यादव, श्री रामकुमार कश्यप, श्री जगदीश नायर, श्री नरेन्द्र गुप्ता, श्री भव्य बिश्नोई, श्री विनोद भ्याणा, श्री प्रवीन डागर, श्रीमती सीमा त्रिखा, श्री प्रमोद विज, श्री महीपाल ढांडा, श्री सत्यप्रकाश जरावता, श्रीमती निर्मल रानी, श्री बिश्म्बर सिंह तथा श्री दुड़ा राम जी हैं। इसी प्रकार से जननायक जनता पार्टी के श्री रामकुमार गौतम,

श्री अमरजीत ढांडा तथा श्री जोगी राम सिहाग। इसी प्रकार से कांग्रेस के श्रीमती किरण चौधरी, श्री इंदुराज, श्रीमती शैली, श्री मेवा सिंह, श्री शीशपाल सिंह, श्री नीरज शर्मा, श्री बलबीर सिंह, श्रीमती रेनुबाला, श्री धर्मसिंह छोक्कर तथा श्री प्रदीप चौधरी शामिल हैं। अब श्री हरविन्द्र कल्याण अपनी बात रखें।

श्री हरविन्द्र कल्याण(घरौंडा): अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं जिसमें सरकार की एक दूरगामी सोच और उसके साथ–साथ एक सुधारीकरण और विकास के प्रति सरकार की दृढ़ता दिखाई देती है। अध्यक्ष महोदय, पिछले 8 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने सुशासन की दिशा में अनेकों कदम उठाये हैं और मैं इसी को सबसे अहम मानता हूं तथा अभिभाषण में भी इसको प्रमुखता से दर्शाया गया है। अध्यक्ष महोदय, सुधारों के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि सुधार वास्तव में बहुत बड़ी चुनौती होते हैं। सुधार करना इतना आसान नहीं होता है और जहां तक मेरा आज तक का अनुभव है मैंने यह देखा है कि खास तौर से राजनीतिक लोग आम तौर पर सुधारों को बहुत बड़े लेवल पर करने से अपने आपको पीछे रखते हैं क्योंकि कहीं न कहीं एक डर होता है कि जब सुधार की प्रक्रिया शुरू करेंगे तो उसमें व्यवस्था एक बार हिलती है तथा उससे लोगों को दिक्कत होती है जिसके कारण कहीं न कहीं लोगों का विरोध भी झेलना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि हम सभी राजनीतिक लोगों का एक स्वभाव भी होता है कि नाराज तो किसी को करना ही नहीं है। कई बार लोग कोई बात बोलते हैं तो हम बिना सोचे समझे उनकी बात को हां बोल देते हैं। क्या ठीक है और क्या गलत है हम यह सभी कुछ जानते हैं लेकिन हम उनको नाराज नहीं करना चाहते इसलिए हम उनको हां कर देते हैं क्योंकि वोट बैंक की चिन्ता हमेशा रहती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने पिछले 8 वर्षों में बहुत से सुधार के कार्यों

को आगे बढ़ाया है। हरियाणा प्रदेश की जनता इसकी गवाह है कि किस तरीके से आज पोने तीन करोड़ की आबादी वाले हरियाणा प्रदेश के अन्दर मजबूत व्यवस्थाएं खड़ी हुई हैं। इस सदन को भी इस बारे में विचार करना पड़ेगा कि 145 करोड़ की आबादी वाले देश में पोने तीन करोड़ की आबादी वाला हरियाणा प्रदेश है तो क्या इसमें लचर व्यवस्थाओं से काम चल सकता है? इसमें सुधारीकरण की जरूरत है या नहीं है इस संबंध में हमारे अन्दर एक गम्भीरता जरूर आनी चाहिए। मैं समझता हूं कि उसके लिए हमारी सरकार ने टैक्नॉलोजी का भरपूर प्रयोग किया है। स्पीकर सर, टैक्नॉलोजी एक ऐसा हथियार है जिससे पारदर्शिता बढ़ती है। वहीं हमारे संसाधन सही तरीके से इस्तेमाल हों ताकि समाज की जरूरतों को सही तरीके से पूरा कर सकें। साथ ही साथ जब हम मैनुअली काम करते हैं तो भेदभाव बहुत हो जाता है जोकि एक स्वभाव भी होता है लेकिन टैक्नॉलोजी कभी भेदभाव नहीं करती जिससे सभी पात्र लोगों को सीधा व पूरा लाभ मिलता है। यही काम भारतीय जनता पार्टी की श्री मनोहर लाल जी की सरकार पिछले आठ वर्षों से कर रही है। साथ ही साथ मैं कई बार इसके ऊपर सोचता हूं कि जब मैं छोटा था तो हमारे यहां एक छोटा आयशर ट्रैक्टर हुआ करता था और वह आयशर ट्रैक्टर हैंडल के साथ स्टार्ट करना पड़ता था। मैं भी उसको स्टार्ट किया करता था लेकिन कई बार उसका हैंडल घुमाते हुए बैक मार जाया करता था जिससे ट्रैक्टर स्टार्ट होने की बजाए हाथ भी टूट जाया करता था। यह जो प्रक्रिया चली हुई है उससे मैं समझता हूं कि बहुत जगह हम देखते हैं कि राजनीतिक दल यू टर्न लेते हैं और उनको वह यू टर्न इसलिए लेना पड़ता है कि एक समय वह किसी प्रक्रिया का साथ देते हैं और जब लोगों की भावना दूसरी तरफ होती है तो वे उस भावना के साथ जुड़कर उस मुद्दे पर यू टर्न ले लेते हैं ऐसा भी हमने पिछले दिनों में काफी देखा है। इसी कारण से सुधार वास्तव

में बहुत मुश्किल है, इनकी इम्पलीमैंटेशन बहुत मुश्किल है और हम लोगों को आज अपना माईंडसैट बदलने की भी जरूरत है। हम सभी ने कोरोना काल का मुश्किल दौर भी देखा है जिसमें विकास की गति भी कम हुई है लेकिन श्री मनोहर लाल जी ने उन कठिन हालात के अन्दर भी बड़ी मजबूती से इन सुधार कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया है। कल मुझे अच्छा लगा कि एक विपक्षी साथी ने सरकार के कुछ कामों की सराहना की। वह करनी चाहिए बल्कि कामों की ही नहीं प्रयासों की भी सराहना करनी चाहिए। मैं अपनी बात को ज्यादा लम्बा न करते हुए केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि यहां पर हमारे विपक्षी साथी और सभी जिम्मेवार साथी बैठे हुए हैं उनको सचिन तेंदुलकर की तरह बैटिंग नहीं करनी चाहिए। सचिन तेंदुलकर सज्जे हाथ से भी चौका मारता है और खब्बे हाथ से भी चौका मारता है। आज भी यहां पर दो विषय आए हैं जिनमें एक विषय ओ.पी.एस. का भी आया। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने यह माना है कि उनसे गलती हुई है। मैं यहां केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि 10 साल तक उनकी सरकार रही, 10 साल में उन्होंने ओ.पी.एस. को लागू किया? उन्होंने 18 अगस्त को वह नोटिफिकेशन की और उसके बाद जितने साल भी उनकी सरकार रही उन्हें अपनी भूल का अहसास नहीं हुआ। आज वे राजनीति करते हैं। मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, 5 मिनट में क्या बोला जाएगा।

श्री अध्यक्ष : जो आप बोल सकती हैं वह बोलिये।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह तो ज्यादती है।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, यह समय सब के लिए एक जैसा है।

श्रीमती किरण चोधरी : अध्यक्ष महोदय, आप कम से कम बोलने का समय 10 मिनट तो कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, यह समय सब के लिए एक जैसा है।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोलने वाली तो मैं पहली सदस्या हूं।

श्री अध्यक्ष : बी.जे.पी. की तरफ से बोलने वाले भी ये पहले ही स्पीकर थे।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने उनको और बोलने से मना थोड़ी किया है।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, वे भी 5 मिनट ही बोले हैं। आप भी 5 मिनट ही बोल लीजिए।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, 5 मिनट में तो कुछ भी कवर नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, मैं किसी के साथ discrimination या किसी के साथ favouritism तो करता नहीं हूं।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह तो ज्यादती है।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, यह ज्यादती नहीं है, न्याय है। 5 मिनट सब को मिलेंगी तो सब के साथ न्याय होगा।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इस राज्यपाल के अभिभाषण में बहुत उंची उड़ान जरूर भरी है। जिस तरह से डिजनीलैंड के अन्दर माया व्यापी सपने दिखाए जाते हैं इस राज्यपाल के अभिभाषण में भी उन माया व्यापी सपनों का जाल बुनने की कोशिश की गई है जबकि सत्य यह है कि जो चीजें राज्यपाल के अभिभाषण में बोली गई हैं उसमें से धरातल पर कुछ भी नहीं है, सारा उसके

विपरीत है। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि देश की स्वतंत्रता की 75 वीं एनीवर्सरी है इसलिए इसको अमृत काल बताया गया है। इसी अमृत काल के अन्दर तीन कृषि कानून लाए गये। इसी अमृत काल में उन किसानों के ऊपर बड़ी बर्बर तरीके से लाठियां बरसाई गई। इसी अमृत काल के अन्दर उनको आतंकी कहा गया। उनकी मौत के ऊपर मजाक उड़ाया गया। इसी अमृत काल के अन्दर हमारे कर्मचारियों के ऊपर किस तरह से पानी की बौछारें की गई, मिर्च के गोले दागे गये जिन्होंने उम्र भर अपने घुटने रगड़कर सरकार की सेवा की है। उन्होंने सरकार की मदद की लेकिन आज आपने उनको बिल्कुल बेघर करके बैठा दिया है। उनके बुढ़ापे का सहारा भी आपने खत्म कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण के पैरा 6 में सरकार ने अपनी बहुत जबरदस्त पीठ थप–थपाई है लेकिन मेरे को यहां कुछ नजर नहीं आता है क्योंकि जो बात कही गई थी कि हम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) लेकर आएंगे लेकिन आज तक उसका कोई जिक्र नहीं है। चाहे छोटे व्यापारी हों, एम.एस.एम.ई. के लोग हों या बेरोजगार बच्चे हों उनका यहां पर कोई जिक्र नहीं है, कोई उनके सामने आशा नहीं है। मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगी कि–''मुतमइन हैं वो मुझे दे के उम्मीदों के चिराग, तिफ्ल ए मकतब हूं, खिलौनों से बहल जाऊंगा।'' ऐसे में बहलने वाले हरियाणा के लोग नहीं हैं। जैसे हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने इण्डियन एक्सप्रेस में उल्लेख किया है कि– this is a silent strike on the poor. This is what is happening unfortunately. अध्यक्ष महोदय, हर तरीके से आपने देखा है कि यहां पर कितने स्कैम हुए हैं। मैं उन स्कैम के नाम नहीं गिनाउंगी क्योंकि आप समय नहीं दोगे लेकिन सच्चाई यह है कि आज एग्रीकल्चर की बाते करें तो पाले की वजह से फसलों का नुकसान हो गया है लेकिन गिरदावरी नहीं हो रही है जिससे हमारे किसान त्राहि–त्राहि कर रहे हैं। जब वे यूरिया खाद के कट्टे लेने के लिए लाईनों में खड़े होते हैं तो

उनको जिंक या कुछ और थोपा जाता है। सारा का सारा काम इस तरह से हो रहा है। पाले के मुआवजा के लिए श्रुति चौधरी जी ने अपने समय में इसको आपदा के अन्दर डलवाया था और केन्द्र सरकार में कानून बनवाया था। उस समय उन्होंने पूरे अहीरवाल के 36 करोड़ रुपये बंटवाए थे। उस समय नारनौल और अटेली हल्के में पाला पड़ा था। आज अगर पाले की वजह से नुकसान हुई फसल की गिरदावरी करवाई जाएगी तो यह कहा जाएगा कि 50 प्रतिशत से नीचे गिरदावरी करवाई जाए ताकि बेचारे उन किसानों को पूरा का पूरा मुआवजा न मिल पाए। अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं एक बात और बताना चाहती हूं कि अब पी. पी.पी. नाम से एक पहचान पत्र बनाया जा रहा है। सरकार टैक्नॉलोजी की बात करती है, यह बहुत अच्छी बात है कि टैक्नॉलोजी को आगे लेकर आएं लेकिन जो धरातल के ऊपर हमारे गांव के लोग हैं वे अभी अशिक्षित हैं। उनको इस बात का मालूम नहीं है। अभी मुझे बताया गया है कि श्रुति चौधरी लोहारू के गांव मंडौली का दौरा कर रही थी। वहां एक बुजुर्ग उसके पास आया जिसकी आंखों के अन्दर आठ–आठ आंसू थे। उस बुजुर्ग ने सामने बैठकर कहा कि बेटी कतई मारे गये, तो श्रुति ने उससे पूछा कि ताऊ क्या बात हो गई। वह कहने लगा कि यूं बोलैं सैं कि आधार कार्ड व पैन कार्ड ऊपर करना सै तो मैंने तो दोनों जोड़ दिये लेकिन मेरा तो किमैं बना कोना। इस तरह के हालात गांवों के अन्दर हो रहे हैं। जिन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए वे मुआवजे से वंचित हैं। (विघ्न)

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, लोहारू की बात की गई है।(विघ्न)

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, आप इनको बोल लेने दें, उसके बाद आप बोल लेना।

श्रीमती किरण चोधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंडौला की बात कर रही हूं। वर्ष 2017–18 के अन्दर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मेरे इलाके के अन्दर 172

घर चयनित हुए थे जिनके मापदंड भी पूरे थे लेकिन तब से लेकर आज तक केवल 9 घर बनाए गये हैं। जगह–जगह पानी की त्राहि–त्राहि हो रही है कहीं भी पानी नहीं है। हमारे इंडैंट का पानी खत्म कर दिया गया है। हमारे इलाके में एक तरह से बर्बादी हो रही है। वहां पीने के पानी के लिए 500–500 रुपये का टैंकर आता है। वहां लोग बर्बाद हो रहे हैं। आपने मुझे अपनी सारी बात तो कहने नहीं दी हैं लेकिन अंत में मैं एक बात जरूर कहूंगी कि–

'' तुम्हारे पैर के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं इन बेपनाह अंधेरों को सुबह कह नहीं सकता, मैं इन नजारों का अंधा चश्मदीद नहीं।''

धन्यवाद।

श्री राम कुमार गौत्तम (नारनौल): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। मैं माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के क्रमांक नं 1 से लेकर 127 तक सभी प्वायंट्स की बहुत ज्यादा प्रशंसा करता हूँ। सरकार द्वारा बहुत बढ़िया काम किए जा रहे हैं, समय के अभाव के कारण मैं सारी बातें सदन के पटल पर नहीं रख सकता। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात जरूर सदन को बताना चाहता हूँ, जिसका मैं बहुत कायल भी हूँ। पहले एक समय ऐसा भी था, जब लोग यह चाहते थे कि किस विधायक के साथ मित्रता करूं या किस मंत्री के यहां जाऊं ताकि वह अपना बच्चा सरकारी नौकरी पर लगवा सके। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी ने बहुत बढ़िया व्यवस्था की है और आज प्रदेश में बच्चे मैरिट के आधार पर लगने लगे हैं। आज ना जाने कितने गरीब घरों के बच्चे जो मेरे नोटिस में भी हैं वे मैरिट के आधार पर बड़े–बड़े पदों पर लगे हैं, यह

इसी सरकार में संभव हुआ है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ करता था। (इस समय मेजें थपथपाई गईं) अध्यक्ष महोदय, पहले बच्चे बसों, रेलों आदि में बदमाशी करते फिरते थे लेकिन आज बच्चे तरह–तरह कोचिंग सैंटरों में दाखिला लेकर एग्जाम की तैयारी करते हैं। इस सरकार ने दूसरा जो सराहनीय काम किया है वह इल्लीगल कॉलोनियों के संबंध में है। पहले टाऊन एण्ड कंट्री प्लानिंग विभाग और दूसरे संबंधित लोग खूब बे–हिसाब से पैसे कमाते थे लेकिन इस सरकार ने इस संबंध में ऐतिहासिक फैसला लेकर अनेकों हजारों गरीब परिवारों का भला किया है। मैं इस संबंध में सरकार की भूरि–भूरि प्रशंसा करता हूँ। (इस समय मेजें थपथपाई गईं) हरियाणा विधान सभा में विधायक के पी.ए. की सैलरी पहले 15 हजार रुपये प्रति महीना थी, जिसे बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रति महीना कर दी है। मैं इस बात की तहेदिल से तारीफ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी इसको अब 20 हजार रूपये प्रति महीना से बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रति महीना करेंगे। इससे गरीब परिवारों का बहुत ज्यादा भला होगा। इसी तरह से ड्राईवर की सैलरी भी 20 हजार रुपये प्रति महीना कर दी गई। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी से यह फैसला करवाने में आपने भी मेरा पूरा साथ दिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और आपने मुझे बताया था कि आपकी दोनों बातें स्वीकार कर ली गई हैं। सरकार ने यह बहुत ही अच्छा काम किया है, मैं इसके लिये तहेदिल से तारीफ करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी की सरकार में चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने ऐसा नहीं है कि काम नहीं किये, काम बहुत किये थे। हुड्डा साहब ने सड़कों के संबंध में रोहतक में काम किया लेकिन जब रोहतक की सीमा समाप्त हुई और भिवानी जिला शुरू हुआ तो काम रोक दिया। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने हिसार से अम्बाला तक की सड़क बनाई है, इसके लिये हम सभी सरकार का बहुत भारी

शुक्र गुजार हैं। इस प्रकार के काम केवल इसी सरकार में संभव हो पाये हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की सरकार ने चण्डीगढ़ एम.एल.एज हॉस्टल में 'नेता जी सुभाष चन्द्र बोस' के नाम से एक गजब का पार्क बनाया है। अध्यक्ष महोदय, इस पार्क को बनाने के लिये आपका, माननीय उपाध्यक्ष महोदय का अहम रोल रहा है। जब पंजाब व हरियाणा के विधायकगण या अन्य गणमान्य व्यक्ति आते–जाते हैं तो उस पार्क को देखकर बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकार की कुछ बातों में जहां कमियां रही हैं, उनको भी मैं आपके माध्यम से सदन के पटल पर रखना चाहता हूँ। अभी लोक सेवा आयोग में 600 पदों का विज्ञापन निकला था उनमें से सिर्फ 50 पद ही भरे गये हैं। उन 50 बच्चों में से 20 बच्चे तो दूसरे राज्यों से हैं। इससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि वो भी अपने ही देश के निवासी हैं लेकिन 550 बच्चे सिलैक्ट नहीं हुए, यह आंकड़ा काफी परेशानी करने वाला है, इसलिए इस सिस्टम में गंभीरता पूर्वक सुधार करने की आवश्यकता है। इसमें 45 प्रतिशत कोटा रिजर्व कैटेगरी के लिये और 50 प्रतिशत कोटा सामान्य कैटेगरी के बच्चों को बुलाने के लिये रखा गया है, इस सिस्टम को ठीक करना चाहिये। पास बच्चों में से दोगुना या तीन गुना बच्चे आयेंगे तो रिक्त पद भरे जायेंगे क्योंकि आज हमारे प्रदेश के बच्चे दर–दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो रहे हैं। इस प्रकार से आज के दिन लोक सेवा आयोग में बहुत ज्यादा सुधार की आवश्यकता है। इसी प्रकार से आरोही मॉडल स्कूलों में नियुक्त अध्यापकों को यह विश्वास दिया गया था कि पांच वर्षों की सेवाएं होने के बाद उनकी नौकरी स्थाई कर देंगे लेकिन वे बेचारे आज भी कच्चे ही हैं और उनको लगे हुए भी कई–कई साल हो गये हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे इलाके में बरसात से फसलों का बहुत भारी नुकसान होता है, इसका स्थाई तौर पर समाधान होना चाहिये क्योंकि हर साल बेचारे गरीब किसान भाइयों की बहुत

फसलें खराब हो जाती हैं। (घंटी) अध्यक्ष महोदय, आज भी मेरी बहुत–सी बातें कहनी रह जाएंगी, इसलिए आप मुझे बोलने के लिए फिर समय दे देना । इस समय माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय श्री दुष्यन्त चौटाला सदन में उपस्थित नहीं है । माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय श्री दुष्यन्त चौटाला और उनके पिता नारनौंद में आये थे । उस समय उन्होंने कहा था कि अब हम नारनौंद में रैगुलरली आया करेंगे और नारनौंद हल्के को सम्भालेंगे लेकिन अब उनको वहां पर गये हुए कई महीने हो गये हैं । जिस समय माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय श्री दुष्यन्त चौटाला ने लोक सभा का चुनाव लड़ा था तो हिसार लोकसभा क्षेत्र में नारनौंद पहली ऐसी कांस्टीच्युएंशी थी जहां से उनकी जीत हुई थी । इस बार विधानसभा के चुनावों में जजपा हिसार जिले की कई कांस्टीच्युएंशीज में हार गई लेकिन नारनौंद कांस्टीच्युएंशी में जीती है । अतः मेरा उनसे कहना है कि वे नारनौंद हल्के के काम करें । वे अब वहां के बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं । वहां की सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं । इससे वहां पर बहुत भारी नुकसान हो रहा है । वहां की जीन्द–हांसी, जींद–सफीदों, हांसी–भिवानी आदि बहुत–सी इम्पोर्टैंट सड़कें टूटी पड़ी हैं । उन सड़कों को ठीक किया जाना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है गौतम जी, आपका समय पूरा हो गया है, इसलिए अब आप अपनी सीट पर बैठिये । अब माननीय सदस्य श्री लक्ष्मण सिंह यादव बोलेंगे ।

श्री लक्ष्मण सिंह यादव (कोसली) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं । मैं अपनी बात दो लाइनों से शुरू करता हूं –

अभिभाषण पर विचार जरूरी है,
सदन में भाषा संस्कार जरूरी है
विरोध के लिए विरोध करना ठीक नहीं,
विरोध करें किन्तु मर्यादा का आधार जरूरी है ।

हमारी सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के लिए अनेक काम किये हैं । हमने पहले की सरकारें भी देखी हैं और हम वर्तमान सरकार को भी देख रहे हैं । पहले भाई–भतीजावाद और क्षेत्रवाद बहुत हावी था । आज न तो भाई–भतीजावाद है और न क्षेत्रवाद है बल्कि आज सिर्फ 'सबका साथ सबका विकास' की बात चल रही है । इसके अलावा आज प्रदेश में 'हरियाणा एक हरियाणवी एक' की बात चल रही है । आज एच.सी.एस. भर्ती का परिणाम आया है । उसमें कहीं क्षेत्रवाद नजर नहीं आता है । हमने पहले की सरकारें भी देखी थी । पिछले 10 साल में रेवाड़ी का केवल एक लड़का एच.सी.एस. बना था लेकिन आज उस क्षेत्र से अपनी मेहनत के बल पर 4 एच.सी.एस. निकले हैं । उसमें से 3 एच.सी.एस. तो अकेले मेरे हल्के से ही हैं । यह एक अच्छी व्यवस्था का परिणाम है । पहले रेवाड़ी से जो एच.सी.एस. बना था वह भी एक नेता का रिश्तेदार था वरना वह भी एच.सी.एस. नहीं बन पाता । (विघ्न)

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र से इस बार एक भी एच.सी.एस. नहीं बना तो हम इससे क्या समझें ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अपने क्षेत्र के बच्चों को अच्छा पढ़ायें और उनका ट्यूशन लगवायें तो वे भी अपने आप अधिकारी बन जाएंगे । (शोर एवं व्यवधान) वे अब मेरा समय खराब न करें । जिस बाजरे की फसल को पहले कभी खरीदा नहीं जाता था, माननीय मुख्य मंत्री महोदय का भला हो कि उनकी वजह से पिछले 3 साल से मेरे क्षेत्र का सारा बाजरा खरीदा जा रहा है । मैं माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की भी सराहना करना चाहूंगा कि उन्होंने वर्ष 2023 को मोटा अनाज खाने के लिए प्रेरित करने हेतु घोषित किया है । सरकार ने जहां बाजरे का एम.एस.पी. बढ़ाने का काम किया वहीं बाजरे का एक–एक दाना खरीदने का भी काम किया गया । इसके लिए मैं माननीय मुख्य

मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगा । आज प्रदेश में पढ़ी–लिखी पंचायतें हैं । वे पंचायतें निरन्तर आगे बढ़ रही हैं । मैं कहना चाहूंगा कि सरकार सरपंचों की बातों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उनकी ताकत बढ़ाने का भी काम करे । सरकार ने आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड तैयार करवाया है । पहले रिकॉर्ड का पता ही नहीं चलता था और लोग पटवारियों के पीछे चक्कर काटते रहते थे । आज केवल एक क्लिक से जमीन का ऑनलाइन रिकॉर्ड मिल जाता है । हमारी सरकार ने खिलाड़ियों को भी सर्वाधिक पुरस्कार राशि दी है । हमारी सरकार ने अंतर–जिला परिषद, ग्राम दर्शन पोर्टल बनाया है । सरकार ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, सूक्ष्म सिंचाई योजना, तालाबों का जीर्णोद्धार और हर खेत स्वस्थ खेत यानि हमने जमीन का हैल्थ कार्ड बनाने का भी काम किया है । कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं है जो एम.एस.पी. पर 14 फसलों की खरीद कर रहा हो । पूरे देश में अकेली हमारी सरकार ऐसी है जो 14 फसलों को एम.एस.पी. पर खरीद रही है । हमारी सरकार ने ऋणों का एकमुश्त निपटान, ई–ऑफिस, नागरिक संसाधन सूचना विभाग, हरियाणा कौशल निगम और प्लेवे स्कूल की शुरूआत की है । यह व्यवस्था भी आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। आज हमारी सरकार द्वारा जगह– जगह पर खेल नर्सरीज खोली जा रही हैं। कॉमन पात्रता परीक्षा भी ली जा रही है। वरना पहले बारी–बारी सबके फॉर्मज भरवाये जाते थे, लेकिन उनकी परीक्षाएं नहीं करवायी जाती थी। आज हमारी सरकार कॉमन पात्रता परीक्षा ले रही है। इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहूंगा कि 'सुक्ष्म युवा योजना' के साथ–साथ आज हमारी सरकार धरातल पर जाकर काम कर रही है। इस प्रकार मेरी सरकार अंत्योदय की योजना को साकार करने का काम कर रही है। इसके अतिरिक्त मैं एक ही बात कहना चाहूंगा। हमारे वहां पर बालदन और दड़ौली में वैटरनरी कॉलेज बनाने की डिमांड वर्षों से चली आ रही है और वहां पर जमीन

भी उपलब्ध है। इसलिए सरकार यह काम भी करवाने का काम करें। हमारे कोसली का बस स्टैंड डाउन एरिया में है जिसके कारण वहां पर पानी भर जाता है। मैं समझता हूं कि सरकार उसको भी तोड़कर दोबारा से बनवाने का काम करे।

श्री चिरंजीव राव: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के घर के बाहर की सड़क भी नहीं बनी हुई है, इसलिए वे उसकी भी मांग रख दें।

श्री लक्ष्मण सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि यह माननीय सदस्य की जिम्मेवारी है। मेरे घर के बाहर की सड़क चमाचम कर रही है। इसलिए माननीय सदस्य को वहां पर चलकर देखना चाहिए।

श्री चिरंजीव राव: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के घर के बाहर वाली सड़क की बात कर रहा हूं।

श्री लक्ष्मण सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि बाहर तो पता नहीं क्या– क्या है? यह माननीय सदस्य की भी जिम्मेवारी है। क्या माननीय सदस्य ने कभी उस मुद्दे को उठाया है?

श्री चिरंजीव राव: अध्यक्ष महोदय, मैंने उस मुद्दे को आज ही उठाया है।

श्री लक्ष्मण सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपनी बात को यह कहकर समाप्त कहना चाहूंगा कि–

हमने अपनी नीतियों को आकार दिया है, अंतिम पायदान को आधार दिया है।

लूट और झूठ की राजनीति को खत्म करके जनता के सपनों को साकार किया है।

जय हिन्द। जय भारत।

श्री इंदूराज (बड़ौदा): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं

आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कानून एवं व्यवस्था सुधारने के की बात की गयी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पिछले दिनों लंबे टाईम के बाद बड़ी मुश्किल से हरियाणा सरकार ने पुरूष कांस्टेबल की भर्ती निकाली थी। जोकि कई महीनों से माननीय कोर्ट में लटकी हुई हैं। सरकार अपनी ही बनाई नीति को कोर्ट में सही साबित नहीं कर पायी। भर्ती में जिन युवाओं का चयन हुआ था, वे कई महीनों से ज्वाइनिंग के इंतजार में बैठे हुए हैं। हरियाणा प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था का दिवालिया पिटा हुआ है। ऐसे में हरियाणा प्रदेश में नए पुलिस वालों की जरूरत है, लेकिन सरकार उस भर्ती को पूरी नहीं कर पा रही है। अगर महिलाओं की बात करें और खिलाड़ियों की बात करें तो पिछले दिनों पूरे देश ने देखा कि पूरी दुनिया में हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन करने वाली हरियाणा प्रदेश की बेटियां जंतर–मंतर पर धरना दे रही थीं। उन्होंने एक सांसद पर शोषण के आरोप लगाए। इतना ही नहीं वो बाहुबली सांसद हरियाणा प्रदेश की बेटियों को रोज मीडिया के जरिए धमकी दे रहा था। लेकिन पूरा हरियाणा प्रदेश यह देखकर हैरान था कि बी.जे.पी.–जे.जे.पी. की सरकार उस सांसद के खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोली। अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे सदन की भावना से आपको परिचित करवाना चाहता हूं कि उस सांसद को हरियाणा प्रदेश का सदन चेतावनी दे कि हमारी बेटियों की तरफ नजर उठाने की हिम्मत न करें। लेकिन हमारी सरकार उससे इतना क्यों डरी हुई है ? इसके बारे में पता नहीं क्या बात है? इस सरकार ने खिलाड़ियों से तो मानो दुश्मनी लगा रखी है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री हुड्डा जी की सरकार ने खेल नीति लागू की थी तो उसमें हर विभाग में खेल कोटे का 3 प्रतिशत आरक्षण लागू किया था। लेकिन हरियाणा प्रदेश की बी.जे.पी.–जे.जे.पी. सरकार ने केवल 3 विभागों में ही 3 प्रतिशत कोटा छोड़कर बाकी विभागों में से

खेल कोटा ही खत्म कर दिया। क्या यह सरकार युवाओं को खिलाड़ी के स्थान पर नशेड़ी बनाना चाहती है? कांग्रेस सरकार की 'पदक लाओ–पद पाओ' खेल नीति से 750 प्लस खिलाड़ियों को नियुक्तियां मिली थी। लेकिन अब खिलाड़ियों से बड़े पदों पर नियुक्ति का अधिकार ही छीन लिया गया है। इस मोर्चे पर ये सरकार नाकाम है। सरकार किसानों को एम.एस.पी., खराबे का मुआवजा, वक्त पर खाद–बीज, युवा को रोजगार, बुजुर्गों को पैंशन, बच्चों को वजीफा, व्यापारी को राहत, नागरिक की सुरक्षा, स्कूल में टीचर्ज, दफ्तर में कर्मचारी, अस्पताल में डॉक्टर्ज, यहां तक की मरीज को जरूरत पड़ने पर दवाई और ऑक्सीजन भी नहीं दे पायी। यहीं बी.जे.पी. और जे.जे.पी. के 8 साल का रिपोर्ट कार्ड है। अध्यक्ष महोदय, आपने देखा कि कोविड–19 के समय पर ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी थी, लेकिन हॉस्पिटल्ज में ऑक्सीजन भी नहीं मिली। वर्ष 2014 से पहले हरियाणा प्रदेश प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, रोजगार सृजन, खिलाड़ियों, किसानों, बुजुर्गों के सम्मान, खुशहाली और विकास में तमाम राज्यों के मुकाबले पहले पायदान पर था। लेकिन इस सरकार ने 8 साल में हरियाणा प्रदेश को बेरोजगारी, अपराध, नशा, भ्रष्टाचार, किसानों पर अत्याचार, खिलाड़ियों से भेदभाव और बदहाली में पहले नंबर पर पहुचा दिया है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में आलम यह है कि आज बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक मौजूदा सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। अभी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों आदमपुर के चुनाव में इस बात की बड़ी सुर्खियां बनी थी कि बच्चों को भी अपने स्कूलों को बचाने के लिए धरने पर बैठना पड़ा था। अध्यक्ष महोदय, युवाओं को भर्ती घोटाले के खिलाफ, रोजगार की मांग के लिए, खिलाड़ियों के खेल कोटा बचाने के लिए, किसानों को कभी एम.एस.पी., कभी मुआवजा तो कभी तीन कृषि कानूनों के खिलाफ, व्यापारियों को जी.एस.टी., लॉकडाउन की अव्यवहारिक पाबंदी

के खिलाफ, राहत पैकेज की मांग को लेकर, मजदूरों और कच्चे कर्मचारियों का रोजगार छीनने के खिलाफ, कर्मचारियों को कभी पुरानी पैंशन स्कीम लागू को लेकर, महिला और आम नागरिक को सुरक्षा की मांग को लेकर बार–बार सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ा है। (घंटी) अभी हमारे कर्मचारी पुरानी पैंशन की मांग कर रहे थे कि उन पर लाठियां बरसाई गई और जींद में सरपंचों पर लाठीचार्ज भी करवाया गया। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 परसैंट कोटा देने की बात कही गई थी लेकिन बड़ा दुख होता है कि सरकार द्वारा आज हरियाणा प्रदेश में महिलाओं पर भी लाठियां बरसाने का काम किया जा रहा है इसलिए मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी महिलाओं पर लाठी चार्ज करने के लिए निंदनीय प्रस्ताव लेकर आयें। इस सरकार की उपलब्धि जनता के गले की फांस साबित हुई है। उदाहरण के लिए जिस परिवार के पहचान पत्र को सरकार उपलब्धि बता रही है, उसने बुढ़ापा पैंशन काटने का काम किया और पिछड़े वर्गों का आरक्षण खत्म करने के अलावा कोई काम नहीं किया।

श्री राम कुमार कश्यप (इन्द्री): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका दिल की गहराईयों से धन्यवाद करता हूं। महामहिम ने अपने अभिभाषण में सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं और उपलब्धियों का उल्लेख किया है। इनमें चाहे निरोगी हरियाणा स्कीम की बात हो या फिर चिरायु योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बनाने की बात हो, चाहे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात हो, चाहे कृषि और बागवानी को बढावा देने के लिए इसमें बजट को 4 गुणा बढ़ाने की बात हो या फिर पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत और बी.सी.ए. वर्ग को 8 प्रतिशत आरक्षण देने की बात हो। इन सभी योजनाओं

के कारण हरियाणा में हर क्षेत्र में विकास हुआ है और सभी वर्गों को इन योजनाओं का बहुत लाभ हुआ है। अतः मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं इसी संदर्भ में मेरे हल्के की कुछ समस्याएं हैं जिनका उल्लेख करना जरूरी समझूंगा। मेरे हल्के में गीढ से धापू तक 3 किलोमीटर का रास्ता है। यह हरियाणा को पंजाब से जोड़ने का काम करता है। तीन साल पहले यमुना पर कोई पुल नहीं था और पुल बनने के बाद इंटर स्टेट सड़क बन गई है। जिसके कारण आवागमन के साधन बढ़ गये हैं जिससे सड़क की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है और सड़क के नाम पर गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जब हरियाणा और यू.पी. को यह रोड जोड़ने का काम करती है तो इसको निश्चित तौर पर जल्दी से जल्दी बनाने का काम किया जाये। दूसरा मेरे हल्के में लहसुन की खेती होती है इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि लहसुन की खेती को और बढ़ावा दिया जाये ताकि किसानों का उत्पादन बढ़ सके और उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सके। इसके लिए लहसुन अनुसंधान केन्द्र खोलने का काम किया जाये। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हरियाणा में पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए केश कला बोर्ड और माटी कला बोर्ड बनाया गया था परन्तु दो साल से इसका पुनर्गठन नहीं हुआ है इसलिए इन दोनों बोर्डों का गठन किया जाये ताकि पिछड़े वर्गों को इससे फायदा हो सके। इसके बाद मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हरियाणा में 150 लाख के करीब आर.एम.पी. डॉक्टर काम कर रहे हैं। इन्होंने करोना काल में भी लोगों के घर–घर जाकर प्राथमिक उपचार देने का काम किया था और उनको जागृत करने का भी काम किया था। अध्यक्ष महोदय, ये डॉक्टर्ज थोड़े से पैसों में गरीबों का इलाज कर देते हैं परन्तु इनको हर समय छापा पड़ने का डर सताता

रहता है जिसके कारण ये हर समय टैंशन में रहते हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि सरकार इनको ट्रेनिंग देकर प्राथमिक उपचार की अनुमति देगी तो ये डॉक्टर्ज बहुत अच्छी तरह से और फ्री माइंड होकर गरीब जनता का भला कर पायेंगे। इसके अतिरिक्त मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं पर ई–टैंडरिंग लाने का जो काम किया है यह काम में पारदर्शिता लाने के लिए किया गया है। मैं समझता हूं कि इससे भ्रष्टाचार से छुटकारा मिलेगा परन्तु मैं यह भी कहूंगा कि फिर भी अगर इसमें कहीं पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों की कोई समस्या है तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मिल बैठकर इस समस्या का समाधान करें। मैंने यह बात कहनी थी। आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्रीमती शैली(नारायणगढ़): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूं। अध्यक्ष महोदय, मैंने महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण सुना जिसमें सरकार ने महामहिम राज्यपाल के माध्यम से अपनी नाकामियों को छुपाया है। अध्यक्ष महोदय, सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। आज प्रदेश की जनता के सामने समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। प्रदेश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, महंगाई तथा अत्याचार चरम पर है। अध्यक्ष महोदय, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग उठाने वाले लोगों पर सरकार लाठियां बरसा रही है। सरकार द्वारा पहले किसानों पर, फिर नौजवानों पर और उसके बाद पंचकुला के अन्दर कर्मचारियों और जीन्द में पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि जिनमें महिला भी शामिल थीं पर लाठियां बरसाई गईं। अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी झेल रहा है। सरकारी विभागों में करीब 2 लाख पद खाली पड़े हैं तथा तमाम गड़बड़ घोटाले और पेपर लीक के बीच जो इक्का–दुक्की भर्तियां होती हैं

उनमें भी हरियाणा की बजाय अन्य राज्य के लोगों का चयन हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के तमाम वर्गों के साथ आज कर्मचारी सड़क पर हैं। अगर कांग्रेस शासित राज्य अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दे सकते हैं तो हरियाणा सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती? अध्यक्ष महोदय, आज सरकार बड़े बड़े वादे करती है, बड़े–बड़े नारे देती है, 'बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ' लेकिन आज हमारी बेटियों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। अगर हमारी बेटियां मंत्रियों के घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं तो कहां पर सुरक्षित होंगी ? अध्यक्ष महोदय, करनाल के अन्दर हमारी विधान सभा कमेटी गई थी तब वहां पर हमारी बेटियों ने कमेटी के सामने बताया। जब स्कूल तथा कॉलेजों में हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं तो कहां पर सुरक्षित होंगी ? अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि ऐसा करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि आगे आने वाले समय में लोग ऐसा करने से पहले 10 बार सोंचे।**(इस समय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)** उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे किसानों की क्या हालत है बीजेपी सरकार ने चुनाव से पहले किसानों की आय दोगुनी करने का वायदा किया था लेकिन आज हमारे किसानों को किस तरह से सड़कों पर धरने पर बैठना पड़ रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के अन्दर बार–बार अपनी नारायणगढ़ मिल की मांग उठाती हूं कि आज भी हमारे किसानों की 100 करोड़ रुपये के करीब पेमैंट बकाया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगी कि किसानों को उनकी बकाया पेमैंट जल्दी की जाए। उपाध्यक्ष महोदय, आज सड़कों की हालत क्या हो चुकी है ? आज पूरे हरियाणा की सड़कें टूटी पड़ी हैं। सदन में पहले तो मेरे सारे भाई सरकार की तारीफ करेंगे फिर बताएंगे कि हमारी सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। अगर सरकार इतना अच्छा काम ही कर रही है तो फिर चारों तरफ जो धरने–प्रदर्शन हो रहे हैं, ये क्यों किये जा रहे

हैं ? अगर सरकार इतना अच्छा काम करती तो ये लोग सड़कों पर क्यों बैठते। आज जनता गरीबी से त्रस्त हो चुकी है। उपाध्यक्ष महोदय, जब से हमारा देश आजाद हुआ है क्या आपने कभी आटे के ऊपर जी.एस.टी. देखी है लेकिन आज आटे पर भी जी.एस.टी. लगाई जा रही है और आटे को 20–25 रुपये किलो बेचा जा रहा है, गरीब आदमी अपना गुजारा कैसे करेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगी सरकार को महंगाई की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। आज स्कूलों के अन्दर टीचर्स नहीं है। हॉस्पिटलों के अन्दर डॉक्टर्स नहीं हैं और हमारे बच्चे नौकरी के लिए दूसरे देशों में जा रहे हैं तो कहां से डॉक्टर आएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार हमारे प्रदेश के बच्चों को यहीं पर रोजगार दे। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं बुढ़ापा पैंशन पर बात करना चाहूंगी कि सरकार ने वादा किया था कि हम बुजुर्गों को 5100 रुपये पैंशन देंगे, आज उस वादे का क्या हुआ ? लोगों को पहले जो पैंशन मिलती थी वह भी काट ली गई। आज लोगों के राशन कार्ड काटे गये हैं, पैंशन काटी गई है। उपाध्यक्ष महोदय, आप गांवों में जाकर के देखें वहां ऐसे–ऐसे गरीब लोग, मेरी बहनें तथा बुजुर्ग लोग हैं जो कहते हैं कि हमारी पैंशन काट ली गई है। उनकी आय ज्यादा दिखाकर पैंशन काटी गई है। इस बात को सरकार ने भी माना है कि इसमें कुछ कमियां पाई गई हैं। इसलिए इन कमियों को जल्दी दूर किया जाए (घंटी) और जिनकी पैंशन काटी गई है उनकी पैंशन वापस से शुरू की जाए और जिनके राशन कार्ड काटे हैं उनके राशन कार्ड भी बनाए जाएं। उपाध्यक्ष महोदय, अंबाला से लेकर के काला अम्ब तक एक सड़क निकाली गई है उसमें मेरे हल्के के कुछ गांव आते हैं उनको बहुत कम मुआवजा दिया गया है अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि हमारे किसान आए दिन वहां धरने पर बैठते हैं और मांग करते हैं कि हमारा

मुआवजा बढ़ाया जाए।(घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात रखने के लिए दो मिनट का समय और दिया जाए।

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्या, आपके बोलने का समय पूरा हो चुका है आप अपनी बाकी समस्याएं लिखकर के दे दीजिए वे रिकॉर्ड में आ जाएंगी।

श्री जगदीश नायर (होडल) : उपाध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे महामहिम गवर्नर महोदय जी के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया सबसे पहले मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं इसके समर्थन में बोलना चाहूंगा। सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, सिंचाई और सड़क इत्यादि के क्षेत्र में सराहनीय काम किया गया है। शिक्षा के मामले में हर विधान सभा क्षेत्र में जो कॉलेज खोलने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्य किया वह बहुत ही सराहनीय है। हैल्थ डिपार्टमैंट के तहत मैडीकल कॉलेज जिलेवाईज खोलने की घोषणा की गई। इसी प्रकार से हमारे विधान सभा क्षेत्रों के हॉस्पिटल्ज की दशा को सुधारने का सरकार ने जो कार्य किया वह भी बहुत ही सराहनीय है। रोजगार में पारदर्शिता लाकर नौकरियां देने का काम किया गया। प्रदेश में 24 घंटे बिजली देने के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए सरकार ने 5682 गांवों में आज 24 घंटे बिजली देने का काम किया है। हमारी सरकार की यह भी एक अनोखी मिसाल है। हर घर जल–नल योजना के तहत पानी की पाईप लाईन बिछाकर लोगों को पानी देने के लिए जो काम सरकार कर रही है वह भी काबिलेतारीफ है। हमारी सरकार के समय हरियाणा प्रदेश में जो सड़कों का जाल बिछाया गया है वह किसी से भी छिपा नहीं है। मैं

मानता हूं कि बरसात के बाद सड़कें टूट जाती हैं लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र की सड़कों को ठीक करने के लिए 25–25 करोड़ रूपये की राशि दी है लेकिन इसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी कहते हैं कि कुछ और राशि सड़कों के नैटवर्क को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए दी जायेगी। मैं इसके लिए अपनी सरकार का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। उपाध्यक्ष जी, मैं इस मंच के माध्यम से अपनी सरकार से एक अनुरोध और करना चाहूंगा कि हमारे जो सरपंच धरने पर बैठे हैं वे हमारे छोटे भाई हैं। उनके साथ सलाह–मश्विरा करके सरकार उनके साथ समझौता करे। सफाई कर्मचारी पार्ट टाईम स्वीपर बेचारे लम्बे समय से 1996 के बाद से आज तक पक्के नहीं हुए। मेरी सरकार से यही प्रार्थना है कि हमारी सरकार इस मामले में भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। मेरी सरकार से प्रार्थना है होडल में क्लर्क मेरे से भी मिले थे। वे भी बेचारे धरने पर बैठे थे। उनकी भी तनख्वाह का कोई विषय था। मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार उनके मामले पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करे। इसके बाद मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात कहना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र की बृज चौरासी कोस की परिक्रमा है। यह एक बहुत ही अहम मुद्दा है। 100 गांवों की पंचायत मेरे विधान सभा क्षेत्र में हुई थी। वहां पर एक नया इशू और आ गया कि भारत सरकार ने बृज चौरासी कोस की परिक्रमा के विकास के लिए 9 हजार करोड़ रूपये दिये थे लेकिन इसमें से हमारे हरियाणा का दायरा कम करके यू.पी. का दायरा बढ़ा दिया गया है। मेरा

आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उस दायरे को ज्यों की त्यों रखा जाये। इसी प्रकार से मेरी यह मांग है कि होडल और हसनपुर में एक बाई–पास की जरूरत है इसलिए इन दोनों जगहों पर नये बाई–पास बनाये जायें। बहडोली से रामगढ़, हसनपुर से बिडूकी, रामगढ़ से बिडूकी, बाहोली से रामगढ़, नवलगढ़ से काचीखेड़ा, बोराका से नवलगढ़ रोड, बोराका से बिछोर रोड और खामी से बिडुकी रोड ये कच्चे रोड हैं इसलिए इन रोडों पर काम करने की जरूरत है। इसके लिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं। वैसे सरकार ने मेरे विधान सभा क्षेत्र में 500 करोड़ रूपये दिया है यदि मैं वह लिस्ट पढ़ूं तो बहुत समय लग जायेगा। मैं अपनी सरकार से मांग करता हूं कि पिंगौर ड्रेन पर तीन नये पुल बनाये जायें। बंचारी–गोच्छी ड्रेन पर माता शक्ति मंदिर के पास नया पुल बनाया जाये। बेंगलतू गांव में साईफन पर एक नया पुल बनाया जाये। खामी में एक गर्ल्स कॉलेज खोला जाये और सौंध में उच्च विद्यालय को 10 प्लस टू स्कूल का दर्जा दिया जाये। दिघौट में 10 प्लस टू स्कूल बनाया जाये। सराय गांव में आई.टी.आई. की जमीन हमारे पास पड़ी है। वहां पर आई.टी.आई. की बहुत सख्त जरूरत है। इसी प्रकार से हसनपुर में एक नर्सिंग कॉलेज की जरूरत है। यमुना नदी के पास मेरे विधान सभा क्षेत्र के लगभग 6–7 गांव पड़ते हैं वहां पर यमुना नदी में हॉल्ट लगाये जाने की बहुत सख्त जरूरत है क्योंकि जब यमुना नदी में बाढ़ आती है तो इन सभी गांवों में अफरा तफरी मच जाती है इसलिए वहां पर यमुना नदी में हॉल्ट लगाकर इनको सुरक्षा प्रदान करने की जरूरत है। उपाध्यक्ष

महोदय, हमारे कांग्रेस के साथी श्री इंदुराज जी ने माननीय मंत्री जी श्री संदीप सिंह के बारे में कुछ टिप्पणी की थी। मैं हमारे कांग्रेस के साथियों को बताना चाहता हूं ***

श्री इंदुराजः उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो बात कही थी वह सदन के सदस्य तथा मंत्री जी के बारे में कही थी। माननीय सदस्य उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं इसलिए इन बातों को रिकॉर्ड से निकलवा दिया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य श्री जगदीश नायर जी ने उन व्यक्तियों का जिक्र किया है जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं इसलिए वह रिकॉर्ड से निकाल दिया जाये। अब श्री अमरजीत ढांडा जी अपनी बात रखेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अमरजीत ढांडा(जुलाना): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में 127 बिंदुओं पर फोकस किया गया है जो कि 36 बिरादरी के लिए लाभदायक हैं उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। हमारे विपक्ष के साथी कह रहे थे कि सरकार कह रही थी कि वर्ष 2022 में किसान की आय दोगुनी कर देंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि आज 4500 से 5000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से जीरी बिक रही है तो वह किसान की ही तो बिकी है। इसी प्रकार से विपक्ष के साथी सड़कों के

*** चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड से निकाल दिया गया।**

बारे में कह रहे थे कि सड़कें टूटी हुई हैं तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि नैशनल हाईवे 152–डी ऐसा हाईवे बना है जिसके कारण हम जीन्द से 2 घंटे में चण्डीगढ़ पहुंच जाते हैं। गोहाना से जीन्द का जो रोड बना है वह मेरे विधान सभा क्षेत्र जुलाना से हो कर गुजरता है और वह भी बहुत अच्छा रोड बना है। जीन्द के बारे में जिस प्रकार से हमारे साथी डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा जी बता रहे थे मैं भी बताना चाहूंगा कि आज जीन्द के अन्दर से 8 एन.एच. निकल रहे हैं जिससे लोगों को फायदा हो रहा है। इनमें मुख्य रूप से हांसी से अम्बाला रोड है वह जीन्द से होकर गुजरता है। रोहतक से जीन्द रोड भी बना है वह भी मेरे विधान सभा क्षेत्र जुलाना से होकर गुजरता है। इसके अलावा जुलाना विधान सभा क्षेत्र की गांव से गांव को जोड़ने वाली 62 सड़कें ऐसी थी जो आज तक नहीं बनी थी वे सड़कें आज बन रही हैं। पहले जुलाना हल्का विपक्ष में रहता था इसलिए जुलाना हल्के की सड़कों को नहीं बनाया जाता था। जुलाना के चारों तरफ जीन्द, महम, रोहतक, गोहाना और बरोदा हल्के लगते हैं इसलिए जहां पर जुलाना हल्के की सीमा शुरू होती थी वहीं पर हमारी सड़कें बननी बंद हो जाती थी। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में सड़कें बन रही हैं उसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। जहां तक किसान की बात है तो मेरे हल्के में बाढ़ की बहुत मार रहती थी लेकिन सरकार ने 300 करोड़ रुपये की लागत से पाइप लाइन बिछा कर बाढ़ के पानी की निकासी का उचित प्रबंध कर दिया है जिससे 36 बिरादरी खुश है। अब मेरे हल्के जुलाना में बाढ़ का प्रकोप समाप्त हो गया है तथा किसानों को अब बाढ़ से नुकसान नहीं होता है। बाढ़ का प्रकोप समाप्त होने के कारण आज जुलाना में किसानों के खेतों में 90–90 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जीरी का उत्पादन हो रहा है तथा किसान खुशहाल हो रहे हैं। खेतों में पानी न भरने के कारण आज गेहूं की फसल भी बहुत अच्छी लगी हुई है। उपाध्यक्ष

महोदय, अब मैं मेरे हल्के के खेल स्टेडियमों के बारे में अपनी बात रखना चाहूंगा। मेरे हल्के में जुलाना, हथवाला तथा बुआना में खेल स्टेडियम बन रहे हैं जिनका कुछ काम पैंडिंग है और उस पैंडिंग वर्क के ऐस्टीमेट्स मुख्यालय पर आए हुए हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उनको यथाशीघ्र पूरा किया जाये तथा वहां तक पहुंचने के लिए रास्ते का भी इंतजाम किया जाये। इसी प्रकार से मेरे हल्के में एक रामराय गांव है जहां पर बच्चे तीर्थ स्थल के तालाब में तैराकी करते हैं इसलिए वहां पर एक स्विमिंग पूल बनाने के लिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं ताकि बच्चों को तैराकी करने की सुविधा मिल सके। अतः निवेदन है कि बजट से स्विमिंग पूल के लिए पैसा देने का काम किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, जुलाना में 72 गांव हैं, जिसमें से 38 गांव ऐसे हैं जहां पर फ्लड की बहुत ज्यादा मार पड़ती थी। यहां पर 34 गांव ऐसे है जहां पर नीचे का पानी अच्छा नहीं है। आदरणीय भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के समय में यहां पर बिरोही माइनर, करेला माइनर तथा रामकली सब माइनर के लिए तीन प्रपोजल चले हुए थे लेकिन पता नहीं किन कारणों की वजह से यह प्रपोजल अधूरे ही रह गए। अतः मैं सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तथा माननीय उप–मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि इन तीनो माइनरों से संबंधित स्कीम को दोबारा से शुरू किया जाये और इन तीनों माइनर के लिए बजट से पैसा देने का काम किया जाये। इससे किसान भी खुश हो जायेंगे और उनकी डबल आमदनी भी हो जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, सदन में माननीय मंत्री जे.पी. दलाल जी बैठे हुए हैं जिनके पास मार्केटिंग बोर्ड भी है, मैं उनके ध्यान में लाना चाहूंगा कि मेरे हल्के में मार्किट बोर्ड की तीन चार बड़ी सड़कें बनी हैं और 10 साल की समयावधि के होते हुए इनकी तो अब डी.एल.पी. भी खत्म हो गई है। इन सड़कों के नाम कुछ इस प्रकार से है जैसे फतेहगढ़ से लिजवाना कलां, देशखेड़ा से देवरढ़, नीडाना से ललित खेड़ा, रामकली

से करसोला, देवरड़ से मालवी वाया कमाच खेड़ा, शामलों खुर्द से रधाना, खरेंटी से उगालन, सुंदरपुर से सिवाहा, ढिगाना से नंदगढ और रामराय खेड़ा से रामगढ़ तक। ये सड़कें पहले अच्छी थी लेकिन बड़ा रोड बनाने की वजह से अब ये टूट चुकी हैं अतः इनको दोबारा से बनाने का काम किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, जुलाना हल्के में एक गतौली गांव है। वहां पर डिप्टी सी.एम. साहब, महिला कालेज की घोषणा करके आये थे। मेरा सदन के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है यह कालेज मेरे इलाके मे देने की कृपा कर दी जाये। एक मेरा अनुरोध यह है कि सरपंचों की पावर 2 लाख रूपये से बढ़ाकर 20 लाख रूपये तक बढ़ाने का काम किया जाये।

श्री मेवा सिंह(लाडवा): उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने सदन में महामहिम राज्यपाल महोदय से बहुत लंबे–चौड़े भाषण के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों का गुणगान कराने का काम किया है। सरकार की तरफ से बड़े लुभावने नारे दिए गए जैसे शासन कम–सुशासन ज्यादा, हरियाणा एक–हरियाणवी एक और सबका साथ–सबका विकास। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा के लोग अपने सपनों को साकार करने के लिए बड़ी आशा के साथ आपकी तरफ देख रहे हैं लेकिन सरकार द्वारा जो बड़ी–बड़ी बातें की जाती हैं, उनका असर धरातल पर कहीं नजर नहीं आता है। किसान कल्याण की बात की गई। आखिरकार किसान के लिए सरकार ने किया ही क्या है ? सरकार ने 2024 तक आमदनी दोगुनी करने का वायदा किया था लेकिन सरकार ने तो लागत को दोगुनी करने का काम किया है। आठ साल के अंदर सरकार ने महज पांच रूपये गन्ने का रेट बढ़ाने का काम किया जबकि कांग्रेस की सरकार में चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने 193 रूपये तक भी गन्ने का रेट बढ़ाने का काम किया था। आज आलू के किसान के क्या हालात हो गए है, यह हम सब जानते हैं। मेरे हल्के में पिपली सब्जी मंडी आती है जोकि आलू की

बहुत बड़ी मंडी है। वहां पर आलू एक रूपया पर किलो के हिसाब से बिक रहा है। आज सरकार ने किसान की यह हालत कर दी है। राज्यपाल अभिभाषण में सिंचाई और जल संरक्षण की बात कही गई। उपाध्यक्ष जी, हमारे इलाके में दादुपूर नलवी नहर की सबसे बड़ी जरूरत थी। मैं सदन के माध्यम से एलान करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी और इस सरकार का नाम काले अक्षरों में लिखा जायेगा जिसने एक खुदी–खुदाई नहर को काटने का काम किया। हमारा लाड़वा, थानेसर और यमुनानगर जिला एक तरह से डार्क जोन में आता है और यहां के लिए यह नहर किसी जीवन दायिनी से कम नहीं थी लेकिन सरकार ने इस नहर को जिस तरह से काटने का काम किया है, इसके लिए जनता इस सरकार को माफ नहीं करेगी। ग्रामीण विकास और पंचायत की बात करें तो पिछले दो साल तक तो सरकार ने पंचायतों के चुनाव तक नहीं करवाये थे और अब चुनाव करवाये भी हैं तो सरपंचों के हाथ बांध दिए गए हैं। तीन महीने से हर ब्लॉक में ताले लगा–लगाकर सरपंच, सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। अगर ऐसा ही करना था तो सरकार को पंचायत के चुनाव कराने की क्या जरूरत थी ? जब पिछले दो साल से पंचायत के अभाव में जे.ईज. काम कर रहे थे तो आगे भी जे.ई से काम करवा लेते ? सरकार जे.ईज. पर तो विश्वास करती है लेकिन चुने हुए प्रतिनिधियों पर सरकार को कोई विश्वास नहीं है। अगर ऐसा ही करना था तो सरकार ने पंचायत चुनाव करवाकर आखिरकार लोगों को इस तरह से चुनावों में लुटवाने की क्या जरूरत थी ? क्यों लोगों को चुनाव में धकेला गया ? मेरी सरकार से मांग है कि सरपंचों पर विश्वास करते हुए उनकी 2 लाख रूपये की पावर को बढ़ाते हुए 25 लाख रूपये तक बढ़ाने का काम किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पंचायती राज सिस्टम में सरपंच, ब्लॉक समिति का मैम्बर, जिला परिषद का वाइस चेयरमैन तथा जिला परिषद के चेयरमैन जैसे पदों पर काम करके यहां एम.एल.ए. बनकर आया हूँ और

मैं जमीनी स्तर की भी पूरी जानकारी रखता हूँ। जे.ई. के पास असैसमैंट और एस्टिमेट्स की पावर होती है तो ऐसी सूरत में इसका फायदा उठाकर वे सरपंच को मजबूर करने का भी काम करते हैं। अगर कोई सरपंच ईमानदारी से काम करता है तो ऐसी स्थिति में जे.ई. उसकी असेसमैंट पूरी नहीं करता है। अगर सरपंच 10 लाख रूपये ईमानदारी के साथ विकास कार्यों पर खर्च करने की कोशिश करता है तो जे.ई. उसकी असैसमैंट 8 लाख रूपये कर देता है। अगर जे.ई. की सेवा–पानी होती रहती है तो असैसेमैंट को 12 लाख रूपये भी कर देता है। ऐसी परिस्थिति में इस तरह की व्यवस्था पर नकेल कसने की आवश्यकता है। यूं कहें कि सरकार को सरपंच की बजाय टैक्निकल विंग पर नकेल कसने की ज्यादा जरूरत है और सरपंचों पर विश्वास करते हुए उनकी फाइनेंशियल पावर्स को बढ़ाने का काम किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पिपली हल्के में बस स्टैंड के प्रस्तावित निर्माण की बात कही गई है लेकिन पिछले 8 साल से माननीय मुख्यमंत्री की अनाउसमेंट में यह कार्य शामिल होने के बाद भी आज तक यहां पर एक ईंट तक भी लगाने का काम नहीं किया गया है और जैसी परिस्थिति चल रही है, उससे ऐसा लगता है कि आगे के दो साल में भी हमारे बस स्टैंड का कार्य प्रस्तावित ही रहेगा। सरकार द्वारा व्यायामशालाओं की बात कही गई और इसकी एवज में हजारों एकड पंचायत की जमीन को बर्बाद करने का काम किया गया और इस जमीन की चारदीवारी करके एक तरह से जमीन को घेर तो लिया गया लेकिन यहां पर न तो कहीं ग्राउंडमैंन है और न ही कहीं कोई कोच वगैरह है बल्कि यहां पर भेड़ें, बकरियां और आवारा बच्चे बैठे रहते है और ये आवारा बच्चे यहां बैठकर दारू, सिगरेट और बीडी पीते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सरस्वती नदी की बात की गई। आज कुरूक्षेत्र में पूरी सरस्वती नदी पर लोगों का कब्जा हो चुका है। लोगों ने कहीं चारदीवारियां कर ली हैं तो कहीं छोटे–छोटे

पुल बना लिए हैं और जिसके कारण आधा कुरूक्षेत्र, ज्यादा बरसात की अवस्था में डूब जाता है और यही नहीं कईं गांवों की पांच–सात हजार एकड़ फसल बर्बाद तक भी हो जाती है। मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि सरस्वती की निशानदेही करके, इसकी खुदाई करने का काम किया जाये। सरकार, विकास की बात करती है लेकिन आज अस्पतालों में डाक्टर्स नहीं हैं, पैरामैडिकल स्टॉफ नहीं है, स्कूलों में मास्टर नहीं हैं और न ही स्कूलों में लैक्चैरर हैं लेकिन केवल कागजों पर विकास दिखाकर जनता को ठगने का काम किया जा रहा है। क्या यही विकास है ? तहसीलों में तहसीलदार नहीं है, ब्लॉकों में बी.डी.ओ. नहीं है। यही नहीं एक बी.डी.ओ. और तहसीलदार को तीन–तीन, चार–चार चार्ज तक दे दिए जाते हैं। पंचायतों में सैक्रेटरी नहीं हैं, बिजली दफतरो में जे.ई. नहीं है और ए. एल.एम. नहीं है। प्रदेश की सड़कों की बुरी हालत हो गई है और इस बारे में विपक्ष के और सत्ता पक्ष के सभी एम.एल.ए. बारी बारी से मुद्दा भी उठा रहे है लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। (घंटी) मेरे हल्के में अभी दो सड़कें बनी उमरी से दौलतपुर और बबैल से मंगोली जाटान यारा तक। तीन महीने में इन सड़कों का बहुत बुरा हो चुका है। अतः सदन के माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है कि इन सडकों की क्वालिटी को चैक करवाने का काम किया जाये और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाये। कानून एवं व्यवस्था के हालत क्या हैं ? केन्द्र की समाजिक प्रगति रिपोर्ट कहती है कि नागरिक सुरक्षा में हरियाणा सबसे निचले पायदान पर है।

श्री उपाध्यक्षः मेवा सिंह जी, आपके बोलने का समय समाप्त हो गया है। आप प्लीज बैठिए।

श्री नरेन्द्र गुप्ता (फरीदाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने महामहिम द्वारा दिए गए अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया। महामहिम जी ने सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार से वर्णन किया है। उसका मैं अपनी तरफ से समर्थन करता हूँ। हरियाणा में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा परिवार पहचान पत्र की परिकल्पना की गई थी और इसके बाद इसका जमीन पर वास्तविक रूप से कार्यान्वयन करने का काम भी किया गया। समाज में जो व्यक्ति बहुत विकट परिस्थितियों में रहते हैं, उन्हें स्वास्थ्य के लिए चिरायु योजना के तहत 46.7 लाख से अधिक चिरायु कार्ड वितरित किए गए। यह वास्तव में हरियाणा सरकार की एक बहुत बड़ी पहल है और मैं तहे दिल से इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का शुक्रिया करता हूँ। निश्चित रूप से जो गरीब व्यक्ति हमारे समाज में रहते हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से तथा शिक्षा की दृष्टि से, उनको इस तरह की चीजों का घर बैठे बहुत बड़ा फायदा होगा। परिवार पहचान पत्र का प्राथमिक उद्देश्य, प्रत्येक लाभार्थी को उसके घर तक सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। चाहे वह विधवा पैंशन हो, बुढ़ापा पैंशन हो या फिर कोई और योजना हो, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से यह फायदा लाभार्थी को घर बैठे-बैठे मिल जाया करेगा। जहां तक चिरायु कार्ड की बात है, आधार कार्ड से चिरायु कार्ड को लिंक करने का काम किया गया और जब मुझे पात्र लोगों को खुद अपने हाथों से चिरायु कार्ड देने का मौका मिला तो पाया कि लाभार्थियों के चेहरे पर कुछ अलग ही चमक थी और यह चमक देखते ही बनती थी। निश्चित तौर पर जो गरीब व्यक्ति हैं, उनके जीवन में विभिन्न स्तरों पर किस तरह से सुधार लाया जा सके, इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह एक बहुत ही अनूठा कार्य किया है और इसके लिए मैं एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारी सरकार,

भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टोलरेंस की सोच रखती है और सरकार के भ्रष्टाचार विरोधी मिशन को आगे बढ़ाते हुए सी.एम. फलाईंग स्क्वॉयड ने वर्ष 2022 में 1303 छापे मारे और इस प्रकार 456 एफ.आई.आर. दर्ज की गई तथा 555 लोगों को अरैस्ट करने का काम भी किया गया। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए यह बहुत ही अच्छी पहल हैं। ऐसा करने से जो लोग खाद्य पद्धाथों में मिलावट करने का काम करते थे, अवैध खनन करते थे, बिजली की चोरी करते थे, ऐसे लोगों को इस तरह के छापों से निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा सबक देने का काम, हरियाणा सरकार के द्वारा किया जा रहा है और इस प्रकार समाज में गलत काम करने वालों को, गलत काम करने से पहले कईं बार सोचना पड़ेगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की स्थापना अपने आप में एक अच्छी पहल है। जो कर्मचारी कांट्रैक्ट पर लगे होते थे उनका पी.एफ. व ई.एस.आई. का पैसा कांट्रैक्टर जमा नहीं करते थे और न ही उनको समय पर सैलरी देते थे लेकिन हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनने के बाद, अब उन्हें सही समय पर सैलरी मिल रही है और रेगुलर पी.एफ. और ई.एस.आई. का उनका पैसा जमा भी हो रहा है। मुझे लगता है कि जो एक लाख से ज्यादा कर्मचारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड में इंरोल्ड हुए हैं, उसमें उनको बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में शिक्षित नागरिकों का चुनाव करके बहुत अच्छी पहल की है। यदि शिक्षित लोग पंचायत या समाज में काम करेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छी डिवैल्पमैंट गांवों में देखने को मिलेगी। आज बहुत ही अच्छी सोच के साथ गांवों व शहरों में डिवैल्पमैंट के अनेकों काम हो रहे हैं। सरकार ने राजस्व रिकॉर्ड को आनलाइन करके बहुत ही अच्छा काम किया है। पहले हमारे किसान भाइयों और भू–मालिकों को लैंड म्यूटेशन के लिये पटवारियों के चक्कर काटने पड़ते थे।

आज प्रदेश को इन सबसे मुक्ति मिली है। मैं इसके लिये भी सरकार का तहेदिल से धन्यवाद करता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, डिवैल्पमैंट एक कंटीन्यू प्रक्रिया होती है और विपक्ष के माननीय साथी अभी कह रहे थे कि यदि सब कुछ ठीक–ठाक है तो माननीय विधायक अपने क्षेत्र की डिवैल्पमैंट की बातें सदन के पटल पर क्यों रख रहे हैं? डिवैल्पमैंट रूकने वाली प्रक्रिया नहीं होती है और हमारी सबकी जिम्मेवारी बनती है कि सभी अपने–अपने विधान सभा क्षेत्रों की समस्याएं व डिवैल्पमैंट की बातें सदन के पटल पर रखें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समय के अभाव के कारण पूरी बातें सदन के पटल पर नहीं रख सकता। मैं भारत वर्ष के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को भी इस समय याद करता हूँ जिन्होंने हमारे फरीदाबाद के दोनों तरफ हाईवे बनाये हैं। दिल्ली से बम्बई जाने के लिये जो दूरी 24 घंटे में पूरी होती थी, अब वह दूरी 12 घंटे में पूरी करने के लिए कुछ रोड तक का निर्माण शुरू कर दिया है। हमारे दिल्ली से दौसा तक सड़क का उद्‌घाटन भी हो चुका है। अब मात्र तीन घंटे में जयपुर पहुँचा जा सकता है। यह हमारे लिये एक सपने की तरह ही है, मैं खुद पौने तीन घंटे में जयपुर पहुँच गया था। उपाध्यक्ष महोदय, इस समय माननीय उप मुख्यमंत्री सदन में उपस्थित नहीं है लेकिन मैंने आपके माध्यम से यह डिमाण्ड पहले भी रखी थी और अब भी रख रहा हूँ कि जो हमारा गुडईयर चौक, एन.एच–2 पर है, उस पर कोई कट नहीं दिया गया है। इससे मेरे शहर के सैक्टर्ज 7, 8, 4 आदि बहुत से क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों को दूर–दूर जाकर बल्लभगढ़ में जाम की स्थिति में फंसना पड़ता है, इसलिए इस संबंधित हाईवे पर जरूर से जरूर एक कट बनवाया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका बहुत–बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।

श्री शीशपाल सिंह केहरवाला (कालांवाली) (अ.ज.): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अगर माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को देखूं तो एक बात से अपनी बात शुरू करना चाहूंगा।

'एक जख्म ही नहीं, यहां तो सारा वजूद ही जख्मी है,
दर्द भी हैरान है, उठू तो कहां से उठू।'

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को पढ़ने के बाद कृषि, एजुकेशन, बेरोजगारी आदि कोई भी क्षेत्र हो, समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से शुरू किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, इस समय माननीय शिक्षा मंत्री सदन में उपस्थित हैं। मेरे से पहले सदन में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। जो शिक्षा और रोजगार की बात हुई, सरकार कह रही है कि हमने इन दोनों क्षेत्रों में बहुत ज्यादा काम किए हैं। सरकार ने यदि शिक्षा के क्षेत्र में काम किए हैं तो मेरे हाथ में शिक्षा से संबंधित जो रिजल्ट की कॉपी है, वह नहीं होती। सरकार ने यदि टैक्निकल शिक्षा पर काम किया होता तो टैक्निकल एजुकेशन के लैक्चरार्स की लिस्ट ऐसी नहीं होती। हम इस लिस्ट को देखेंगे तो पायेंगे कि जो जनरल कैटेगरी के 157 बच्चे सिलैक्ट हुए हैं उनमें से बिहार राज्य से 19, उत्तर प्रदेश राज्य से 47, मध्य प्रदेश राज्य से 9, उत्तराखंड राज्य से 8 हैं, गाजियाबाद, सिक्किम, कानुपर आदि से बच्चे लगे हैं। इस प्रकार से टोटल मिलाकर 103 बच्चे दूसरे राज्यों से सिलैक्ट हुए हैं। यदि किसी भी माननीय सदस्य को इस संबंध में कोई शक है तो मेरे पास इसकी एक लिस्ट है, वे ले सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि ये बच्चे हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं? मेरा रोजगार के विषय के बारे में कहना है कि सरकार कहती है कि रोजगार के क्षेत्र में हमारा 75 प्रतिशत हिस्सा होना चाहिये।

जब 157 बच्चों में से 103 बच्चे दूसरे राज्यों से सिलैक्ट होते हैं, क्या हमारे हरियाणा के बच्चों में इतनी काबिलियत नहीं है कि वे इन पदों पर भर्ती हो सके? क्या हरियाणा का युवा जनरल कैटेगरी में मैरिट में नहीं आ सकता था?

शिक्षा (श्री कंवर पाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूँ कि मैरिट का तरीका क्या होता है? मैरिट के आधार पर हमारे प्रदेश के बच्चे भी दूसरे प्रदेशों में नौकरी पर लगते हैं। माननीय विधायक सरकार को समझा दें कि मैरिट का कौन सा तरीका अपनाना चाहिए।

श्री भारत भूषण बतराः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है।

श्री उपाध्यक्षः बतरा साहब, प्लीज आप बैठ जाइये। आपका बोलने का समय नहीं है। शीश पाल जी आप अपनी बात कंटीन्यू रखें।

श्री शीशपाल सिंह केहरवाला : उपाध्यक्ष महोदय, यह कंट्राडिक्टरी बात है । हमें माननीय शिक्षा मंत्री जी बतायें कि कहां पर कमी रही है जिस कारण हमारे बच्चे मैरिट में नहीं आ पाये । क्या हरियाणा केवल थर्ड और फॉर्थ क्लास की नौकरियों के लिए बना है ? सरकार बड़ी–बड़ी बातें करती है । सरकार सुशासन की बात करती है । मैं पूछता हूं कि सरकार किस सुशासन की बात करती है ? जनता पी.पी.पी. से परेशान हो रही है और जनता बी.पी.एल. कार्ड कटने से परेशान हो रही है । सरकार कहती है कि हमने अंत्योदय का बहुत अच्छा काम किया है । ऋण के लिए सरकार के पास कुल 68,257 आवेदन आये हैं जिसमें से 60,347 आवेदकों को बैंकों ने लिया है । केवल 17,466 आवेदकों को सरकार से लाभ प्राप्त हुआ है । अतः रिजल्ट केवल 25 प्रतिशत है । पास होने के लिए भी 33 परसैंट अंकों की जरूरत पड़ती है । इसमें सरकार फेल है और सरकार कहती है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है । सरकार कहती है कि हमने कानून व्यवस्था में सुधार किया है जबकि अनेक साथियों ने बताया है कि प्रदेश में महिला अपराध

27 परसैंट बढ़कर हम देश में अव्वल स्थान पर पहुंच चुके हैं । सरकार हरियाणा के 1 नंबर पर होने की बात करती है लेकिन प्रदेश अपराध में 1 नंबर पर आ चुका है । गोली चाहे पंजाब, हरियाणा या किसी अन्य प्रदेश में चलती है लेकिन .... (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर मैं एक मिनट बोलना चाहूंगा क्योंकि आज विपक्ष के कई मैम्बर यह मामला उठा चुके हैं । मेरे पास इससे संबंधित सारा डाटा उपलब्ध है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री शीशपाल सिंह केहरवाला : उपाध्यक्ष महोदय, इससे मेरे बोलने का समय कम हो जाएगा ।

श्री उपाध्यक्ष : शीशपाल जी, माननीय मंत्री जी के जवाब देने में आपका समय नहीं जुड़ेगा । आपको अपना पूरा समय दिया जाएगा ।

श्री कंवर पाल : उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के शासन के 10 साल में मर्डर के केस 42 परसैंट बढ़े जबकि हमारी सरकार के शासन के 7 साल में 0.5 परसैंट केस बढ़े । (शोर एवं व्यवधान) विपक्ष के शासन के 10 साल में अटैम्प्ट टू मर्डर के केस 54 परसैंट बढ़े लेकिन हमारी सरकार के शासन के 7 साल में 18.6 परसैंट केस बढ़े । (शोर एवं व्यवधान) विपक्ष के शासन के 10 साल में रेप के केस 136 परसैंट बढ़े और हमारी सरकार के शासन के 7 साल में 83.9 परसैंट केस बढ़े । (शोर एवं व्यवधान) विपक्ष के शासन के 10 साल में अपहरण के केस 812 परसैंट बढ़े जबकि हमारी सरकार के शासन के 7 साल में 12.9 परसैंट केस बढ़े । (शोर एवं व्यवधान) मेरे पास सरकार का रिकॉर्ड है । विपक्ष के शासन के 10 साल में फिरौती के लिए अपहरण के केस 114 परसैंट बढ़े जबकि हमारी सरकार के शासन के 7 साल में 42.1 परसैंट केस बढ़े । (शोर एवं व्यवधान) विपक्ष के शासन के 10 साल में गवर्नमैंट सर्वेन्ट पर हमले के केस 48 परसैंट बढ़े जबकि हमारी

सरकार के शासन के 7 साल में –22.6 परसैंट केस बढ़े । (शोर एवं व्यवधान) विपक्ष के शासन के 10 साल में एस.सी./एस.टी. पर जुल्म के केस 349 परसैंट बढ़े लेकिन हमारी सरकार के शासन के 7 साल में 82.9 परसैंट केस बढ़े । (शोर एवं व्यवधान) विपक्ष के शासन के 10 साल में चोरी के केस 190 परसैंट बढ़े जबकि हमारी सरकार के शासन के 7 साल में 27 परसैंट केस बढ़े । (शोर एवं व्यवधान) विपक्ष के शासन के 10 साल में स्नैचिंग के केस 153 परसैंट बढ़े । (शोर एवं व्यवधान) इसके बावजूद विपक्ष के साथी कानून–व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं । मेरा कहना है कि विपक्ष अपने समय का डाटा उठाकर देखे । (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अभी माननीय सदस्य ने कानून–व्यवस्था पर जो सवाल खड़ा किया था माननीय मंत्री जी ने उसका जवाब दिया है । उन्होंने यह जवाब ऑन रिकॉर्ड दिया है । (शोर एवं व्यवधान) यह कोई बहस का विषय नहीं है । माननीय मंत्री जी ने केवल आंकड़ें बताये हैं ।

श्री शीशपाल सिंह केहरवाला : उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश सरकार मोदी सरकार की रिपोर्ट पेश करके काम करना चाहती है तो मैं एक बात और कहना चाहता हूं । अगर सरकार रिपोर्ट की ही बात करती है तो मैं सदन में एक और रिपोर्ट देता हूं । अगर हम मानव अधिकार हनन के मामलों की बात करें तो इस मामले में वर्ष 2016–22 तक कुल 18,659 शिकायतें आई हैं । इनमें से 4367 शिकायतें तो अकेले पुलिस के खिलाफ हैं । आप समझ लीजिए कि लगभग 45 परसैंट शिकायतें पुलिस के खिलाफ हैं । अतः सरकार किस प्रकार के सुशासन की बात कर रही है ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको जो आंकड़ें बता रहा हूं आप इसे बेशक चैक करवा लें । (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : शीशपाल जी, आपका समय पूरा हो गया है । अतः अब आप अपनी सीट पर बैठें । (शोर एवं व्यवधान)

श्री आफताब अहमद : उपाध्यक्ष महोदय, आप माननीय सदस्य को अपनी बात कहने दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष : आफताब जी, माननीय सदस्य के 5 मिनट्स पूरे हो गये हैं, इसलिए मैंने उनको बैठने के लिए कहा है । अब माननीय सदस्य श्री विनोद भ्याना बोलेंगे ।

श्री विनोद भ्याणा (हांसी): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा जब सदन के पटल पर भाषण पढ़ा जा रहा था तो उससे साफ जाहिर हो रहा था कि यह मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार गरीब, किसान, युवा, कमेरा और व्यापारी हितैषी है। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश साधु–संतों व पीर–फकीरों का प्रदेश है। इस प्रदेश की मिट्टी से गीता के उपदेशों की सुगंध आती है और यह मिट्टी हमें समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए प्रेरित करती है। उसी कड़ी में प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी भी गरीब कल्याण में अंत्योदय पर लगे हुए हैं और एक हद तक हमारी सरकार ने अंत्योदय पर काम करते हुए सफलता भी प्राप्त की है। वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि–

अयम निज परोवेती गणना लघु चेतासाम,
उदार चिताम तू वसुधैव कुटुंबकम।

यानि कि माननीय मुख्यमंत्री जी मेरा और पराया की नीति पर काम नहीं करते। बल्कि संपूर्ण प्रदेश की जनता के लिये 'हरियाणा एक हरियाणवी एक' की नीति पर काम करते हुए प्रदेश में सार्थक कदम उठा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी

सरकार ने नारा दिया था कि 'सबको छत'। उसी कड़ी में 28,572 लाभार्थियों को मकान निर्माण के लिए 482 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर अपनी कथनी और करनी का एक समान होने का प्रमाण दिया है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पी.एम.ए.वाई) के तहत 29,711 मकानों की तुलना में 28,837 मकानों को स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें से 21,932 मकानों का निर्माण भी पूरा कर लिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार चिकित्सा पर भी काम कर रही है। उसी कड़ी में प्रदेश के प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी जिसके तहत भिवानी, जींद, यमुनानगर तथा नारनौल में सरकारी मेडिकल कॉलेज, नल्हड़ जिला मेवात में डेंटल कॉलेज, फरीदाबाद, रेवाड़ी, कैथल, कुरूक्षेत्र और पंचकूला में नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है।

श्री आफताब अहमदः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय सदस्य से कहना है कि जो मेडिकल कॉलेज/नर्सिंग कॉलेज बने हुए हैं, उनकी सुध तो ले लें।

श्री उपाध्यक्षः आफताब जी, प्लीज, आप बैठ जाएं। माननीय सदस्य की बात सुन लें।

श्री विनोद भ्याणाः उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार श्री मनोहर जी के नेतृत्व में उद्योग जगत को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। उसी कड़ी में हरियाणा प्रदेश ने व्यापार सुधार कार्य योजना 2020 के मूल्यांकन में भाग लेने वाले 37 राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों की 2022 में जारी इज–ऑफ डूइंग बिजनैस रैंकिंग में टॉप अचीवर का दर्जा हासिल किया है। वहीं खरखौदा में 3300 एकड़ पर लगने वाला मारुति सुजुकी का प्लांट हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए एक आस–रोजगार की नई किरण लेकर आया है। वहीं हमारी सरकार आधारभूत

संरचना को मजबूत बनाने के लिए काम कर रही है और उसी कड़ी में रेल लाइन, ग्रीन–फील्ड नेशनल हाईवे एवं प्रदेश के हिसार शहर में हवाई अड्डा स्थापित किया जा रहा है। वहीं केन्द्र सरकार के साथ–साथ प्रदेश सरकार भी किसान और खेती के उत्थान के लिए वचनबद्ध है। हमारी सरकार ने जहां किसानों को समृद्ध बनाने के लिए अनेक किसान कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर लागू की हैं। वहीं किसान की आय को दौगुनी करने के लिए पशुपालन और डेयरी को बढावा दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, युवा प्रदेश के विकास का आधार होते हैं। हमारी सरकार ने युवाओं को बिना खर्ची–पर्ची के रोजगार प्रदान करते हुए–एकल पंजीकरण के माध्यम से सरकारी नौकरियों में बार–बार आवेदन करने से युवाओं को छुटकारा दिलाने का काम किया है। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि–

सपनों को मिलेगी अब उड़ान दूर नहीं,
खुद के बलबूते मिलेगी पहचान दूर नहीं,
चिराग खिल उठे हैं ज्ञान की ज्योति से,
अब बिना खर्ची–पर्ची रोजगार दूर नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में दो दिन से देख रहा हूं कि किस कदर विपक्ष मुद्दा विहीन निराधार बातें कर अपनी राजनीति चमकाने के लिए सदन का समय खराब कर रहा है। आज प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की सबका–साथ, सबका विकास की नीति के चलते ईमानदार सोच की हरियाणा प्रदेश का जन– जन सराहना कर रहा है क्योंकि–

हम दिल में खुशी ईमान भी रखते हैं
प्रदेश के लोगों का मान भी रखते हैं
फूलों के साथ कांटे भी कबूल हैं हमें
आम–खास कोई नहीं सबको समान रखते हैं।

श्री जयवीर सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मेरे हल्के की बात की है, इसलिए मुझे भी अपनी बात रखने के लिए समय दिया जाए।

श्री उपाध्यक्षः जयवीर जी, प्लीज, आप बैठ जाएं।

श्री विनोद भ्याणाः उपाध्यक्ष महोदय, मैं अंत में आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने अपने हल्के की कुछ डिमांड्स रखना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र हांसी के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय– अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पोर्ट्स में भाग लेकर अपने क्षेत्र का नाम रोशन करने का काम किया है। चाहे वह कॉमनवैल्थ गेम्ज हों या एशियन गेम्ज हों। इनमें मेरे हल्के के खिलाड़ियों ने न केवल भाग लिया है बल्कि देश व प्रदेश को पदक दिलाने का काम भी किया है। मेरे हांसी शहर में खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए कोई खेल स्टेडियम दिया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसी के साथ–साथ एक बात सी.एम. साहब से नम्रतापूर्वक कहूंगा कि सरपंचों के साथ बातचीत करके संबंधित मुद्दे का कोई हल निकाला जाए। धन्यवाद।

श्रीमती शकुंतला खटकः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहिए कि खिलाड़ियों के साथ क्या हो रहा है ? उस बात का भी जवाब दे दें।

श्री जोगी राम सिहाग (बरवाला): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए समय दिया, मैं इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पहले पैरा पर 14वीं हरियाणा विधान सभा के चौथे बजट सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आजादी के 75वें वर्ष में हमारे महान राष्ट्र के अमृत काल में हरियाणा विधान सभा का यह पहला सत्र है, इसलिए इस सत्र का महत्व और भी बढ़ जाता है और आप सभी से उच्च स्तर की

प्रतिबद्धता व्यक्त करने की अपेक्षा की जाती है। हम से पूरे सदन से हरियाणा प्रदेश की जनता यह आशा रखती है कि हम सदन के अंदर सभ्य भाषा का प्रयोग और मर्यादित शब्दों का प्रयोग करे, यह हमारे प्रदेश की जनता हम सबसे चाहती है। मैं हरियाणा सरकार और भारत सरकार के जो अच्छे काम हैं, उनको भी गिनाना चाहूंगा। भारत सरकार ने आयुष्मान योजना लागू की है, जिसकी कल्पना करना ही बहुत बड़ी बात है कि 5 लाख रुपये की सहायता हर परिवार को दी जाती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उससे भी आगे बढ़कर एक चिरायु योजना लागू की है। जिसके कारण हरियाणा प्रदेश में जो पहले आयुष्मान योजना के तहत कार्ड बनाये गये थे उसमें 29 लाख परिवारों को लाभ दिया गया था लेकिन अब चिरायु योजना के तहत इसमें 46.70 लाख परिवार शामिल हुए हैं। हमारे लिये यह बहुत अच्छी बात है। यह पूरे हिन्दुस्तान के लिए उदाहरण भी है। ये हमारी अच्छी बातें हैं। मुझे लगता है कि इसके अंदर और भी बहुत सारी अच्छी बातें होंगी लेकिन यहां पर सदन में बार–बार सड़कों का जिक्र आता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की सरकार ने निसंदेह अच्छी सड़कें बनाई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हैं लेकिन प्रदेश की सरकार ने हो सकता है कि अच्छी सड़कें बनाई हों। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसमें यह कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की सरकार ने जो सड़कें बनाई हैं, उसके साथ एक बिन्दु भी लगाया है और वह बिन्दु टोल के रूप में है। मैं हिसार का उदाहरण देना चाहूंगा। हिसार शहर से बाहर कोई भी व्यक्ति बगैर टोल दिये, किसी भी दिशा में निकलकर दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा इसलिए सरकार को इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो कहूंगा मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि मेरी बात सरकार के पक्ष में जाएगी या सरकार के विरोध में जाएगी । मैं सबकी बातें कहूंगा। कल जो घटना घटित हुई है, उसके बारे में मैं

बताना चाहता हूं। मैंने परसों तलवंडी को रास्ता देने का मामला उठाया था लेकिन आप लोगों ने उठाने नहीं दिया और कल ही उस पर एक कमेटी गठित की गई है। मैं सरकार को भी आगाह करना चाहता हूं कि यदि अगर कमेटी ने लीपापोती की और उसने कोई रास्ता नहीं निकाला तो हम संघर्ष करने से पीछे नहीं हटेंगे और वह रास्ता हमें जल्द से जल्द मिलना चाहिए। यह मैं सरकार से आग्रह भी करता हूं और चुनौती भी देता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत से साथियों ने पिछले दिनों चुनकर आई पंचायतों और सरपंचों को लेकर जिक्र किया था, किसी ने उनको कहा कि वो चोर हैं, वो लुटेरे हो सकते हैं, किसी ने कुछ कहा और किसी ने उनको ईमानदार भी कहा। हमारे बहुत से साथी सरपंचों ने बीच में ये शब्द भी कहे कि हम दो–दो लाख रुपये ऐसे नहीं लगाकर आये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि उनके कहने का भाव क्या था, क्या यह बात इनको पता है। उनके भाव का गलत अर्थ निकाला गया। उनके कहने का भाव यह था कि हमारे गांव के विकास के लिए पैसे खर्च करके विकास कैसे किया जाये इसलिए उन्होंने सरपंच बनने की कोशिश की है। उनके कहने का भाव यह था, न कि भ्रष्टाचार करने के लिए उन्होंने दो लाख रुपये लगाये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि यह चुनाव करवाने पर सरकार का पैसा क्यों खर्च किया गया? यह बात हमारे एक साथी ने भी कही थी। अगर उनको दो लाख रुपये खर्च करने तक की लिमिट है तो मत करिये दो लाख रुपये की लिमिट। चाहे इसकी 50 हजार रुपये की ही लिमिट कर दीजिए लेकिन उनको खर्च करने की पावर दें और अगर ऐसा नहीं करते तो फिर इतना क्यों खर्चा किया गया? जो इतनी बड़ी पंचायतें चुनी गई हैं जो ये सरपंच बनकर आये हैं, ये 20 लाख रुपये की मांग करने के लिए नहीं, 10 लाख रुपये की मांग करने के लिए नहीं, 25 लाख रुपये की मांग करने के लिए

नहीं और ये 30 लाख रुपये की मांग नहीं कर रहे हैं बल्कि ये गांवों का विकास करने के लिए मांग कर रहे हैं। (घंटी) मैं इससे भी आगे बढ़कर यह कहना चाहता हूं कि गांव के अंदर कोई भी पैसा लगे वह सरपंच की परमिशन के बगैर नहीं लगाना चाहिए और यह कानून भी कहता है कि सरपंच की परमिशन के बगैर पैसा नहीं लगना चाहिए। आप लगाकर के दिखा दीजिए।(शोर एवं व्यवधान)उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश का एकमात्र दूरदर्शन केन्द्र जो हिसार में स्थित है उसको चंडीगढ़ में शिफ्ट क्यों किया जा रहा है इसका कारण बताया जाए ? वहां पर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर उसे चंडीगढ़ में शिफ्ट क्यों किया जा रहा है ? हमारे प्रदेश के कलाकर अपनी प्रजैंटेशन कैसे दे पाएंगे ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः मंत्री जी, आप बोलिए।

श्री देवेन्द्र सिंह बबलीः उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य ने मेरे विभाग से संबंधित प्रश्न किया है और सदन में भी बार–बार सरपंचों की पावर से संबंधित प्रश्न उठाया जा रहा है और कल से मैं भी सदन में देख रहा हूं कि सभी सम्मानित सदस्यों ने सरपंचों की बात को यहां पर रखने का प्रयास किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि यह पूरा मामला हमारे भी संज्ञान में है। पंचायतों व जिला परिषद से हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं हम इन चुने हुए सभी प्रतिनिधियों का सम्मान करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार पहली सरकार है जिसने सरपंचों के मान–सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। हमारी सरकार ने गांव में यह एक नई परम्परा स्थापित की है कि गांव में जा कर शपथ समारोह करके सरपंचों को शपथ दिलाने का काम किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद जिला वार जा कर संवाद प्रोग्राम करके हमने सभी सरपंचों से सुझाव लेने का काम किया। सरकार ने सिर्फ एक फैसला गांव हित के लिए, डिवैल्पमैंट

के लिए, जनहित के लिए तथा प्रदेश हित के लिए लिया है कि जो काम पहले मैनुअली होता था, कोटेशन बेस पर होता था अब सरकार ने उसे ई–टेंडरिंग के माध्यम से करने का काम किया है और जो पहले 5–10 लाख रुपये तक की फाइलें अप्रूवल के लिए चंडीगढ़ आती थीं उन फाइलों को हमने गांव लैवल पर, ब्लॉक लैवल पर तथा जिला लैवल पर ही करने का काम किया है। उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ और सिर्फ जो कोटेशन से काम था हमको उसने ई–टेंडरिंग के माध्यम से करने का काम किया है। हमारे जे.ई. उसका एस्टीमेट्स बनाएंगे और ब्लॉक लैवल पर एस.डी.ओ. उसकी अप्रूवल देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, ब्लॉक लैवल की और गांव लैवल की एडिमिनिस्ट्रेटिव पावर हमारे सरपंचों के पास ही हैं। वे ही प्रस्ताव डालेंगे और वे ही टैंडर लगवाएंगे तथा वे ही एल–वन को काम अलॉट करेंगे और वे ही उसका पैसा जारी करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, पी.आर.आई. के पैसे के अलावा गांव की डिवैल्पमैंट के लिए जो पैसा प्रदेश सरकार से लेना है, मैं सभी सम्मानित सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि आप अपने–अपने सरपंचों से मीटिंग करें। संवाद प्रोग्राम में हमें सुझाव मिला था कि छोटे कामों में समय ज्यादा लगता है इसलिए हमने उस टेंडर प्रणाली को 21 दिन से घटाकर 7 दिन करने का काम किया है। इसलिए आप सरंपचों को एक बार बुलाकर समझाने का काम करें, टैंडर लगवाने का काम करें। हमारा जितना पैसा पंचायती राज के लिए गांव में गया है वह लग नहीं पा रहा है। अबकी बार भी हमारा बजट खर्च नहीं हो पा रहा है। (शोर एवं व्यवधान) विधायक जी, आप मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। मेरा सभी सम्मानित सदस्यों से सदन में अनुरोध है कि आप सभी अपने–अपने सरपंचों से मिलें और उनको बुलाएं और उनको कहें कि इसको इम्पलीमैंट करें। जहां समस्या आती है हम उसको इम्प्रूव करेंगे। उनके साथ बैठेंगे लेकिन यह कह देना कि इसको 20 लाख रुपये कर दो यह ठीक नहीं है। 20 लाख रुपये क्यों हुआ

था उसके बारे में मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। पहले काम मैनुअल होते थे उसकी अकाउन्टिबिलिटी नहीं थी। आज हमारे पास 11 हजार से ज्यादा शिकायतें आयी हैं उनमें हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ भी हैं। हम इस व्यवस्था को सिस्टम में लाना चाहते हैं इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि यह प्रणाली प्रदेश के, जनहित के लिए है इसमें आप सभी सहयोग करें और इसे सरपंचों के कंधों पर रखकर राजनीति न करें। धन्यवाद।

श्री नीरज शर्मा(फरीदाबाद एन.आई.टी.): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि मैंने सर्वप्रथम पी.पी.पी. को लेकर वर्ष 2021 में प्रश्न लगाया था। आज पी.पी.पी. को पता नहीं क्या–क्या नाम दिया गया है। अब यह पी.पी.पी. पैरवी, प्रणाम, पैसा बन गया है। उपाध्यक्ष महोदय, यहां मेरे जितने साथी बैठे हैं इन सबके दरवाजे पर सुबह कोई न कोई पैरवी करने के लिए आता है कि साहब मेरे साथ यह हो गया। फिर वह सरकारी दफ्तरों में प्रणाम करेगा। दलालों को पैसा पकड़ायेगा और अपना काम करेगा। उपाध्यक्ष महोदय, उस समय भी इस प्रश्न पर 27 मिनट तक बहस चली थी तब कई साथी नाराज भी हुए थे कि हमारे प्रश्न रह गए। 4 साल का बच्चा क्या कमाई कर सकता है ? ये चीजें तो एक छोटे से छोटे सॉफ्टवेयर में आ सकती थी। उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा दुख होता है जब एक आदमी को अपने हाथ से ऐसी एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है कि साहब मैं जीवित हूं मुझे जिंदा डिक्लेयर कर दीजिए। यह सभी कुछ पिक्चरों में तो देखने में अच्छा लगता है कि मुसद्दी लाल के हसीन सपने लेकिन हकीकत में यह देखना अच्छा नहीं लगता। दूसरी बात मैं प्राईवेट अस्पतालों और स्कूलों की लूट के बारे में कहना चाहूंगा। भारत सरकार का कानून भी है कि अगर

किसी का परिजन बीमार हो जाये तो हर आदमी चाहता है कि उसका अच्छे से अच्छा इलाज करवाया जाये। कभी–कभी इलाज के दौरान उसकी मुत्यु भी हो जाती है। जो व्यक्ति परिवार का मुखिया होता है उसको पता नहीं होता कि लेन–देन कहां है और कहां नहीं जबकि यह कानून है भारत सरकार का और इसकी पालना कराना स्टेट गवर्नमैंट का कर्त्तव्य है। कोई भी अस्पताल मृतक की डैडबॉडी को होल्ड नहीं कर सकता लेकिन प्राईवेट अस्पताल वाले मृतक के परिजनों को ऐसे तरसाते हैं कि उन्हें अंत में जेवर तक बेचकर डैडबॉडी लेकर जानी पड़ती है क्योंकि जवान मौत भी होती है तो आदमी कहता है कि जल्दी से जल्दी संस्कार कर दिया जाये। इसके विषय में सरकार सख्त से सख्त कदम उठाये। तीसरी बात मैं सफाई कर्मचारियों के बारे में कहना चाहता हूं। जो हमारे सीवरेज कर्मचारी हैं जो सीवरेज के अंदर घुसकर सीवरेज साफ करते हैं उसका पूरा मैन्युअल और सिस्टम है इसलिए जब तक उसकी पालना न हो तब तक कोई सरकारी या प्राईवेट सफाई कर्मचारी सीवरेज में न जाये उसके बावजूद भी अगर कोई उसको बुलाये तो उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। किसी भी सफाई कर्मचारी की मृत्यु सीवरेज के अंदर जाने से नहीं होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा प्राईवेट स्कूलों के अंदर कोरोना में सब जुट गये, पिट गये, नौकरी व रोजगार चले गए। बच्चे शैक्षणिक सत्र के बीच में प्राईवेट स्कूल को छोड़कर सरकारी स्कूल में शिफ्ट नहीं कर सकते थे। एग्जाम की डेट आती है तो मासूम बच्चों को टॉर्चर किया जाता है कि आपने फीस जमा नहीं की इसलिए आपको एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। इसमें बच्चे की गलती नहीं है मां–बाप की गलती है। औकात नहीं थी कि उसको प्राईवेट स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया जाये। राईट टू एजुकेशन एक्ट में यह कानून भी है कि बच्चे को एग्जाम में बैठने से कोई रोक नहीं सकता। कोई उसको मना नहीं कर सकता। उसकी सख्ती

से पालना कराई जाये। उपाध्यक्ष महोदय, यहां सभी लोग अपने निगम की बात कर रहे थे। आऊसोर्सिंग पॉलिसी टू में 2017 में जो आदमी काम कर रहा था। आज 6 साल हो गये हैं लेकिन उसके चार आने नहीं बढ़े हैं। क्या उसके घर में महंगाई की मार नहीं आई? क्या उसको पैसे की बढ़ोतरी नहीं चाहिए? उनकी भी तनख्वाहों के पैसे बढ़ाये जायें। अमृतकाल की बड़ी बात हो रही है। हमारे यहां दो तालाबों का उद्घाटन हुआ। कसम से पाली गांव के तालाबों की मिट्टी चोरी हो गई। कहां ठेकेदार है और कौन सा महकमा है? माईक पर हम भी भाषण देकर आये थे कि ढूंढो, ढूंढ रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिल रहा है। मैं आपको पाली गांव का उदाहरण बता रहा हूं। इसके अलावा हमारे यहां नगला और सरूपपुर गांव में काफी इण्डस्ट्रीज लग चुकी है। कोई भी एरिया खाली नहीं है। मेरा आज इस बारे में क्वैश्चन भी लगा था। जैसे आप रैजीडैंशियल कॉलोनियां पक्की कर रहे हैं उनके ऊपर भी हर घड़ी तलवार लटकी पड़ी है। कभी पॉल्यूशन डिपार्टमैंट की और कभी किसी और डिपार्टमैंट की। वे टैक्स भी दे रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि उनकी भी कोई नीति बनाकर के उनको भी रेगुलराईज किया जाये। सरकार को रेवेन्यू भी मिले और उनके ऊपर लटकने वाली तलवार भी खत्म हो। उपाध्यक्ष महोदय, ये अडानी और अम्बानी जी पूरा देश लूट रहे हैं हरियाणा को तो बचा लो। अडानी के बारे में मैंने बताया था कि एक–एक दिन में 27–27 करोड़ रूपये का नुक्सान हो रहा है क्योंकि 12 रूपये प्रति यूनिट तक बिजली खरीद रहे हैं। हुड्डा साहब 2.94 रूपये की व्यवस्था कर गये थे। वर्तमान सरकार से यह व्यवस्था सम्भाली नहीं गई। उन्होंने 25 साल का कांट्रैक्ट बनाया था।

बिजली मंत्री (श्री रणजीत सिंह) : उपाध्यक्ष जी, ये जो कह रहे हैं यह अडानी का समझौता उसी वक्त हुआ था जब हुड्डा साहब की सरकार थी। यह समझौता अब का नहीं है बल्कि यह समझौता पहले का है।

श्री नीरज शर्मा : उपाध्यक्ष जी, मेरे यहां अम्बानी की टोल रोड है। वहां पर टोल का पूरा पैसा दिया जा रहा है। बल्लभगढ़ से पाली की तरफ चलें या भाखड़ी की तरफ चलें, यहां की एक कमेटी बना दी जाये, वह वहां पर दौरा कर ले और वह कमेटी ही बता दे कि वह रोड टोल देने लायक है या नहीं है। जो चोर की सजा है वह नीरज शर्मा की सजा है। मेरा यही कहना है कि इतना न लुटवाया जाये। इसके अलावा हमारा यहां एकमात्र बादशाह खान नामक अस्पताल है। जब शहर की आबादी कुछ लाख में थी उसके बाद बार–बार ट्रॉमा सैंटर की आवाज उठती है हमारे यहां एक ट्रॉमा सैंटर बनाया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास मुद्दे बहुत हैं मेरा तो आप पढ़ा हुआ ही मान लेना। मुझे एक रामायण की चौपाई को बोलने का समय दे दें। उपाध्यक्ष महोदय, समस्यायें इतनी हैं खास तौर से भ्रष्टाचार की। मैं भ्रष्टाचारियों पर एक बात बताना चाहता हूं। जब रावण को देखा तो विभीषण जी बड़े अधीर हुए। लंका काण्ड की चौपाई है :–

रावनु रथी बिरथ रघुबीरा। देखि बिभीषन भयउ अधीरा।।
अधिक प्रीति मन भा संदेहा। बंदि चरन कह सहित सनेहा।।
नाथ न रथ नहि तन पद त्राना। केहि बिधि जितब बीर बलवाना।।
सुनहु सखा कह कृपानिधाना। जेहिं जय होइ सो स्यंदन आना।।
सौरज धीरज तेहि रथ चाका। सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका।।
जय हिन्द। जय भारत। राम राम।

श्री उपाध्यक्ष : नीरज जी, अब आप बैठिए।

श्री नीरज शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मेरी कुछ बातें और कहने से रह गयी हैं। यदि आपकी इजाजत हो तो मैं इनको लिखित रूप में सदन के पटल पर रख देता हूं। आप इनको प्रोसीडिंग्स का पार्ट बनवा देना।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है नीरज जी, आप अपनी लिखित स्पीच दे दें। उसको प्रोसीडिंग्स का पार्ट बना दिया जायेगा।

***श्री नीरज शर्मा :** धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित रूप से कहना चाहता हूं कि –

***चेयर के आदेशानुसार उपरोक्त लिखित स्पीच को प्रोसीडिंग्स का पार्ट बनाया गया।**

22/2/2023

22-2-23

430

मेरे द्वारा फरीदाबाद के गांव मुजेंडी पंचायत में हुए करोडो रू के गबन के मामल की शिकायत की गई थी। गबन के मामले में बीडीपीओ पूजा पर एफआईआर नं 92 दिनांक 26.03.2021 के तहत मामला दर्ज किया गया था और यह एक मामला नही है इनके रहते हुए कई पंचायतों में करोडो रू का धोटाला हुआ है मामला दर्ज होने के उपरांत से ही बीडीपीओ पूजा फरार चल रही थी। माननीय न्यायलय का साहरा लेकर बीडीपीओ पूजा अग्रीम जमानत पर बाहर आ गई है लेकिन कई वर्ष पर बीत जाने के बावजूद कोई ठोस कार्यवाही नही की गई है जिससे की ऐसा प्रतीत होता है की जांच को दबाने की तैयारी की जा रही है मेरे द्वारा लिखित में इसकी शिकायत उच्च अधिकार प्राप्त समिति जो मनोहर लाल जी ने बनाई है उसको की गई उसका कोई जवाब तक नही दिया जाता है। कैसे रोक लगेगी भष्टाचार पर।

22/2/23

- फरीदाबाद में एक मात्र बादशाह खान हस्पताल है जिसमें काफी सुविधाओ का अभाव है ज्यादातर मरीजो को यह से स्थानातंरित कर दिया जाता है। जिन गरीबो परिवार के बच्चों की डिलवरी हस्पताल में होती है उनसे सुविधा शुल्क की मांग की जाती है। सुविधा शुल्क लेकर गरीबो को लूटा जा रहा है। इसके अतिरिक्त आपको बताना चाहूंगा कि फरीदाबाद की आबादी लगभग 50 लाख के आस पास है लेकिन सुविधाओ का अभाव है। इसलिए लोगो की मांग है कि बादशाह खान हस्पताल में एक ट्रामा सेंटर खोला जांए।
- आपके सज्ञांन मे लाना चहता हूँ कि <u>The Toy association of India</u> का मागं पत्र मुझे प्राप्त हुआ था। इसी संदर्भ मे दिनांक 15/02/2020 को दिल्ली स्थित निक्को होटल में <u>The Toy association of India</u> के सभी अधिकारिगण/सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्‌यम मांत्रलय भारत सरकार की तरफ से निदेशक श्री विजय कुमार जी एंव हरियाणा राज्य औद्योंगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम (HSIIDC) के अधिकारी मौजूद रहे। इसके उपरान्त उक्त अधिकारियों को सरकारी कालेज खेडी गुजरान के साथ लगती पंचायत की जमीन दिखाई गई, जिसपर सबकी सहमति बनी थी। आपकी अध्यक्षता में दिनांक 02/07/2020 को शाम 07:00 बजे मुख्यमंत्री निवास चण्डीगढ प

मीटिंग हुई। जिसमें मानीनय श्री राजेश खुल्लर जी,आई.ए.एस., श्री ए.के. सिंह जी,आई.ए.एस, मुख्य रूप से उपस्थित रहे। जिसमें आपके द्वारा सैद्धांतिक तौर पर TOY CITY/IMT बनाने की सहमति दी थी। विभिन्न मीटिंगो के दौरान मैं चण्डीगढ में श्री अनुराग जी, श्री राजेश खुल्लर जी, श्री एस.एस. फुलिया जी, एंव माननीय मंत्री महोदय से व्यक्तिगतौर पर मिलकर प्रोजेक्ट को चालू करने बारे अनुरोध किया। अब अतिरिक्त परिवहन आयुक्त हरियाणा के पत्र कमांक 47377 दिनांक 20.10.20 के द्वारा सूचना प्राप्त हुई है की परिवहन विभाग उक्त जमीन देने को तैयार नही है। श्रीमान जी, देश के प्रधानमंत्री जी ने भी खिलौना उघोग और उससे जुडने वाले रोजगार के बारे में कहा है, इसलिए मेरा आपसे अग्रह है कि एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए ताकि जो भी रूकावटे इस प्रोजेक्ट के तहत आ रही है उनको दूर करके इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द शुरू किया जाए।

- आपको बताना चाहता हूँ कि आयुष विभाग में मेरी विधानसभा एन.आई.टी 86 फरीदाबाद अंतर्गत आने वाले बल्लभगढ सोहना रोड पर स्थिति गांव खेडी–गुजरान की लगभग 8 एकंड जमीन हरियाणा सरकार के द्वारा आयुष मंत्रालय को National institute of unani medicine for non communicable diseases की स्थापना एंव इसके साथ–2 120 बेड का हस्पताल खोलने के लिए दी गई है। इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आयुष मंत्रालय को कई बार डी.ओ लेटर भी लिखा, लेकिन आजतक तक कोई कार्य शुरू नही हुआ है। भारत सरकार में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल का पुनः विरतार हुआ है जिसमें माननीय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, को आयुष मंत्रालय का पदभार दिया गया है जिसने मैने व्यक्तिगत मिलकर उपरोक्त प्रोंजेक्ट को जल्द

20/2/23

से जल्द शुरू करने का अनुरोध किया है। लेकिन आज तक कोई कार्य शुरू नही हुआ। मेरी सरकार से मांग है कि इसपर तुंरत प्रभाव से सज्ञांन लेकर उपरोक्त प्रोजेक्ट को शुरू करवांए या फिर विभाग से बात करके आयुष विभाग से सम्बन्धित स्वास्थ्य सुविधा शुरू करने का कष्ट करे ताकि फरीदाबाद के लाखो लोगो को इसका लाभ मिल सके।

- मेरी विधानसभा एनआईटी–86 के अंतर्गत गांव कोट, सिरौही, फतेहपुर तगा, टीकरी खेड़ा, धौज, मादलपुर, कुरैशीपुर, ऑलमपुर, खोरी जमालपुर, मांगर, सिलाखड़ी व अन्य गांव पड़ते है जिनके विकास कार्य अतिरिक्त उपायुक्त, फरीदाबाद के पत्र क्रमांक 2641 दिनांक 2.09.2019 के तहत प्रबंधक निदेशक ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड चंडीगढ़ में काफी समय से लंबित पड़े हुए थे जोकि आचार सहिंता लगने के कारण लम्बित रह गए थे। उक्त विकास कार्यो की फाईल निदेशक पंचायत विभाग, प्रधान सचिव पंचायत, और माननीय उप मुख्यमंत्री से अनुमोदित होकर श्री सतीश कुमार ओ.एस.डी. जी के पास लम्बित पडी थी।

इस मामले बारे मेरे द्धारा विधानसभा में प्रश्न संख्या 734 लगया गया था जिसपर जवाब दिया गया की 102 कार्यो के प्राकलन पंचायती राज सस्थाओं के माध्यम से उनके स्वंय के धन/स्त्र्रोतो से निष्पादित कराने के निर्देश के साथ दिनांक 06.04.2021 को वापिस भेज दिए गए।

श्रीमान जी आपको बताना चाहूंगा की पंचायतो के पास अपना कोई ऐसा फंड नही होता तथा 24 फरवरी 2021 से पंचायते भंग पडी है तथा विधानसभा में पुनः प्रश्न सख्ंया 17 पूछा गया की 2019 से 30.05.2022 तक एचआरडीएफ स्कीम के तहत हरियाणा में कितना और एनआईटी विधानसभा में कितना फंड

22/12/23

अलाट किया तो उसपर सरकार द्धारा जवाब दिया गया कि हरियाणा में 146.35 करोड रू अलाट किए गए, लेकिन बडे दुख के साथ कहना पड रहा है कि एनआईटी विधानसभा में एक रूपया भी 2.5 वर्षो में नही दिया गया। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि गांवों में लंबित पड़े विभिन्न विकास कार्यों को जल्द से जल्द शुरू करवाने का कष्ट करे।

- मेरी विधानसभा के गांव डबुआ की 47.56 एकड भूमि तथा गांव बाजरी की 32.42 एकड भूमि वर्ष 1994 में नगर निगम में सम्मिलित हुई थी। जिसकी किमत आज की तारिख में 3 करोड रू प्रति एकड के लगभग है लेकिन बडे दुख के साथ कहना पड रहा है कि गांव वाले आज भी विकास के कार्यो के तरस रहे है, ना ही गावों में मुख्य रास्ता का निर्माण हुआ है ना ही सीवर लाईन एंव पानी का लाईन डाली गई है। मेरी सरकार से मांग है कि दोनो गांवो का सर्वे करवाकर गांव के लम्बित विकास कार्य करवाए जांए।

- मेरी विधानसभा के वार्ड–9 में गरमीयों के समय पानी की काफी समस्या रहती है जिसके चलते लोगो को जाम तक लगाना पडता है इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि मेरी विधानसभा के वार्ड–9 नगंला गांव की सरकारी जमीन पर एक नया पानी का बूस्टर बनाया जाए।

- मेरी विधानसभा से होकर बल्लभगढ सोहना रोड निकलती है जोकि बल्लभगढ से होकर सोहना गुडगांव राजस्थान को जाती है इस सडक पर अक्सर जाम की समस्या बनी रहती है गोछि चौक पर, सरूरपुर चौक पर, पाली चौक पर, नगंला चौक पर लोगो को कई–2 धंटे जाम की समस्या से जुझना पडता है इसलिए

28/8/23

मरी सरकार से मांग है कि उपरोक्त स्थानो पर पुलो का निर्माण करवाया जाए ताकि लोगो को जाम की समस्या से निजात मिले।

मेरी विधानसभा के गांव धौज में क्रेशर जोन है जोकि सरकार द्वारा ही शुरू किया गया था अब उसको चलाया नहीं जा सकता, सरकार उनके बारे में भी कुछ सोचे।

22/2/23

➢ **प्रदेश में हुए घोटालों का विवरण निम्न प्रकार से है:–**

1. धान खरीद में घोटाला
2. गेंहू व सरसों खरीद एवं चने की तुलाई में घोटाला
3. राईस मिलों द्वारा चावल में किया गया घोटाला।
4. लॉकडाउन के दौरान हुआ शराब घोटाला।
5. लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में रजिस्ट्री घोटाला
6. ट्रांस्फर घोटाला
7. किलोमीटर घोटाला
8. छात्रवृति घोटाला
9. फसल बीमा योजना के प्रीमियम में घोटाला
10. सरकारी नौकरियों की भर्ती में पैसों का लेनदेन।
11. हरियाणा में आयुष्मान भारत योजना में घोटाला।
12. हरियाणा में प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाला।
13. अम्बाला में अन्तर्राष्ट्रीय फुटबाल स्टेडियम में 46 करोड़ रूपये का घोटाला।
14. अम्बाला में होम्योपैथिक मेडिकल कालेज की नींव पडते ही करोड़ों का घोटाला।
15. हरियाणा राज्य फार्मेसी कांउसिल में घोटाला।
16. हरियाणा बिजली वितरण निगम में 50 करोड़ रूपये का घोटाला
17. दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में रिटायर्ड फौजियों और अन्य कर्मचारियों के पी. एफ. में 6.31 करोड़ रूपये का घोटाला।
18. पंचायतों के चुनाव 2 साल तक न करवाकर ग्रामीण विकास के कार्यों में घोटाले हुए।

22/2/23

19. नगर निगमो, परिषदों व पालिकाओं में हो रहे भ्रष्टाचार के मामलों ने सारी सीमाऐं लांघ दी हैं।
20. देह शामलात की 500 एकड़ भूमि को बेचने का फर्जीवाड़ा।

उपरोक्त घोटालों में सरकार द्वारा दोषियों व भ्रष्टाचार में संलिप्त उच्च स्तर के लोगों के विरूद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। केवल लिपापोती में लगी है।

INDEX

क्र	विषय	पेज
1	प्रदेश में फैला भ्रष्टाचार एवं घोटाले	2
2	परिवार पहचान पत्र	4
3	अंत्योदय परिवार उत्थान योजना बारे	6
4	शिक्षा व्यवस्था	8
5	कृषि एवं किसान	10
6	कानून व्यवस्था	12
7	बेरोजगारी	15
8	आबकारी एवं कराधान	17
9	ई–टेंडरिंग व रिकॉल	18

22/8/23

प्रदेश में फैला भ्रष्टाचार एवं घोटाले

- प्रदेश में भ्रष्टाचार और घोटालों की बाढ़ आई हुई है प्रतिदिन एक भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है। हरियाणा राज्य सतर्कता ब्यूरो ने इस वर्ष रिश्वत लेने के हजारों मामले दर्ज किए है। औसतन हर महीने भ्रष्टाचार के आरोप में 15 लोक सेवकों की गिरफ्तारियां हो रही है।
- वर्तमान में प्रदेश का ऐसा कोई विभाग नहीं बचा है जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला न हो। पिछले 7–8 सालों में प्रदेश के कई नगर निगमो, परिषदों व पालिकाओं में भ्रष्टाचार सारी सीमाऐं लांघ चुका है।
- प्रदेश की गठबंधन सरकार में लगभग 20 से ज्यादा बड़े ऐसे घोटाले कुछ समय पहले हुए हैं जो सरकार के ध्यान में भी लाए जा चुके हैं परंतु जिनकी जांच अभी तक सरकार द्वारा नहीं करवा पाई है। सिर्फ जांच के नाम पर सरकार लिपापोती कर रही है।
- सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के दावे तो करती है लेकिन जीरो टॉलरेंस का कहीं नामोनिशान तक नहीं है।
- प्रदेश में घोटाले पर घोटाले होना अब एक आम बात सी हो गई है। किसी भी विभाग में आज आम नागरिक के लिए बिना सुविधा शुल्क काम करवा मुश्किल हो गया है।

- सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) लोगों के लिए सुविधा की बजाए पेरशानी का कारण बन गया है। परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में लोगों की आय के गलत आंकडे दिखाए गए हैं जिसके कारण उनके लिए अब यह पत्र–परेशान पत्र बन कर रह गया है।
- वर्तमान में प्रदेश से लगभग 14 लाख शिकायतें दर्ज हुई हैं जिसमें से 11 लाख 23 हजार शिकायते तो केवल आय से संबंधित गड़बड़ियों बारे दर्ज हुई हैं। आय गलत होने की वजह से लगभग 9 लाख 60 हजार लोगों के नाम बीपीएल कार्ड की सूची से काट दिए गए हैं।
- बीपीएल गरीब परिवार के लोगों का आरोप है कि विभाग द्वारा बीपीएल कार्ड सूची से नाम काटने के दो कारण बताए जा रहे हैं जिनमें पहला कारण जिनकी

२२/२/२३

अच्छे पढ़े–लिखे लाखों युवाओं को कौशल रोजगार निगम में रोजगार से वंचित रखा जा रहा है।

- प्रदेश के पढ़े–लिखे युवाओं में सरकार के प्रति गहरा रोष व्याप्त है जो अच्छी शिक्षा के बावजूद भी कौशल रोजगार निगम द्वारा रोजगार नहीं दिया जा रहा।

आबकारी एवं कराधान

- महोदय, कोरोना महामारी के दौरान व लॉकडाउन के समय प्रदेश में बहुत बड़े स्तर पर शराब के कई घोटाले हुए थे जिसकी जांच के लिए एक एस.ई.टी भी खरखौदा के मामले में गठित की गई थी।
- परंतु बड़ी हैरानी की बात है कि अभी तक उस एस.ई.टी. की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई हैं जिससे प्रदेश की जनता को पता चल सके कि इस शराब घोटाले में जांच के दौरान कौन–कौन दोषी पाए गए तथा दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई। सरकार सदन को भी अवगत करवाए कि शराब घोटाले की जांच के लिए अन्य जिलों में की गई जांच कमेटी की रिपोर्ट का स्टेटस क्या है।

22/2/23

- बढ़ती बेरोजगारी की स्थिति को देखते हुए माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक मामले में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को **'पीड़ित संघ'** की संज्ञा दी है।
- पिछले सालों में जितनी सरकारी नौकरियां निकली हैं वे सब भ्रष्टाचार और धांधलियों की भेंट चढ़ गई हैं। प्रदेश में बेरोजगारी चिंता का विषय है।
- प्रदेश में सरकार द्वारा एक कौशल रोजगार निगम स्थापित किया गया है जिसके माध्यम से विभिन्न विभागों के लिए भर्तियां की जा रही हैं जिसका अपने आप में कोई औचित्य नहीं दिखाई देता क्योंकि पहले ही प्रदेश में 65 सरकारी रोजगार कार्यालय कार्यरत हैं जिनके माध्यम से उक्त भर्तियां की जा सकती थी।
- यह कौशल रोजगार निगम लिमिटेड कम्पनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत है। कौशल रोजगार निगम के माध्यम से ठेका प्रथा के अनुसार भर्ती किए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया में उम्मीदवारों की पात्रता का आंकलन कैंसे किया जाता है इसके बारे में कोई स्पष्ट तौर पर नहीं बताया गया है और न ही उम्मीदवारों के चयन के लिए समान अवसर व आरक्षण का प्रावधान बारे कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है।
- इस कौशल रोजगार निगम में केवल अनुभव प्रमाण पत्र वालों को ही नौकरी का अवसर दिया गया हैं जबकि

22/2/23

- वास्तव में ये राजस्थान के रहने वाले थे तथा मुस्लिम समाज से संबंधित थे परंतु कथित तौर पर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इनकी हत्या गौ–रक्षकों द्वारा की गई बताई है जिसकी वजह से प्रदेश में खास तौर से मेवात क्षेत्र में भय का वातावरण बना हुआ है तथा कानून व्यवस्था पर भी एक प्रश्न चिन्ह है, जिस पर सरकार द्वारा उचित कार्यवाही की जानी चाहिए थी।

बेरोजगारी

- आज प्रदेश में पिछले कई सालों से बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। वर्तमान में सी.एम.आई.ई की ताजा रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में बेरोजगारी दर 21.7 प्रतिशत आंकी गई है जो देश में कई सालों से पहले स्थान पर हैं।
- इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस प्रदेश की बेरोजगारी दर पूरे देश में पहले स्थान पर हो उस प्रदेश के युवा कितनी बड़ी बेरोजगारी की मार झेल रहे होंगे और उनकी मानसिक दशा क्या होगी।
- प्रदेश के सरकारी विभागों में काफी समय से लगभग 2 लाख पद खाली पड़े है परंतु इन खाली पदों को नियमित रूप से भरने में सरकार की कोई रूचि नहीं दिख रही। इसके विपरीत प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवा नौकरी पाने की कतार में खड़े हैं।

थी अब शिक्षण संस्थानों में भी बेटियों अपने आप को असुरक्षित समझाने लगी हैं।

- वर्ष 2022 में प्रदेश के स्कूलों में लड़कियों के साथ यौन शोषण के 6 बड़े गम्भीर मामले सामने आए हैं जिनमें शिक्षकों व कर्मचारियों पर आरोप लगे हैं। यदि इस प्रकार के मामले शिक्षण संस्थानों में नहीं रूकेंगे, तो बेटियां कैसे पढ़ पाएंगी। माता–पिता अपने बच्चों को शिक्षण संस्थानों में घर की तरह सुरक्षित समझकर भेजते हैं।
- पिछले कुछ समय से शिक्षण संस्थानों में यौन उत्पीड़न के मामलों पर बेटियों की सुरक्षा को लेकर गम्भीर सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में हांसी के एक गांव के सरकारी स्कूल में चपरासी द्वारा छठी कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है तथा अनेक मामले प्रदेश के अन्य जिलों के सरकारी शिक्षण संस्थानों में घटित हुए हैं। सरकार का नारा बेटी बचाओं–बेटी पढ़ाओं ढकोसला बनकर गया है।
- पिछले दिनों भिवानी जिले में दो व्यक्ति जिनके नाम जुनैद व नासीर एक गाड़ी में जिन्दे जले हुए पाए गए हैं तथा जिसमें हरियाणा पुलिस द्वारा तत्काल एफआईआर दर्ज करके उचित कार्यवाही न करने की वजह से लोगों में काफी रोष है।

22/2/23

- प्रदेश के पुलिस विभाग में लगभग 20 हजार पद रिक्त पड़े हैं जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार की कोई रूचि नहीं है।
- पिछले कुछ समय से प्रदेश के खेल विभाग के खिलाड़ियों के साथ अपराधिक घटनाओं के कारण उनमें काफी निराशा और परेशानी है जिससे खिलाड़ियों के मनोबल पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।
- हाल ही में प्रदेश की एक महिला खिलाड़ी कोच के साथ दुराचार/दुर्व्यवहार का मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है जिस पर सरकार द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है जिसके कारण खिलाड़ियों में बहुत निराशा है।
- यह सर्वविदित है कि पिछले कुछ सालों से सरकार की खेल प्रोत्साहन नीति के कारण प्रदेश के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है और मैडल भी हासिल किए है।
- सरकार द्वारा खेल विभाग से संबंधित अपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने और उन्हें न्याय देने के बारे में सरकार क्या कदम उठा रही है इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए।
- आज प्रदेश की सरकारी शिक्षण संस्थानों में लगातार छात्राओं के साथ यौन शोषण के मामले बढ़ रहे हैं। बेटियां अपने आप को बाहर तो सुरक्षित नहीं समझती ही

22/2/23

रूप में या तो मामूली राशि दी गई या कोई मुआवजा नहीं दिया है।

- बीमा कम्पनियों ने हरियाणा से लगभग 40 हजार करोड़ रूपये से अधिक का भारी मुनाफा कमाया है। सरकार के संरक्षण में बीमा कम्पनियां पैसा कमा रही हैं और किसान खाली हाथ रह जाते है।

कानून व्यवस्था

- प्रदेश में बढ़ते अपराधों के कारण आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। आज दिन–दिहाड़े गोलीबारी, हत्या, बलात्कार व अन्य अपराधों के मामले निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि प्रतिदिन लगभग 3 हत्याऐं, 4 बलात्कार तथा हर तीसरे दिन 1 गैंगरेप तथा 6 अपहरण के मामले घटित हो रहे हैं।
- इसके साथ–साथ प्रदेश में आए दिन व्यापारियों से लूटपाट, फिरौती तथा हत्याओं की घटनाऐं भी लगातार बढ़ रही हैं। इन घटनाओं ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है।
- प्रदेश में महिला सुरक्षा की बात करें तो इस संबंध में सरकार के सभी दावे खोखले नजर आ रहे हैं। प्रदेश में चाहे महिलाएं हो या युवा लडकियां या फिर छोटी बच्चियां, कोई भी सुरक्षित नहीं है। महिलाओं के साथ होने वाले अपराध के आंकड़े पेरशान करने वाले हैं।

24/8/23

- एक ओर तो इस वर्ष सरकार द्वारा शुगर मिलों द्वारा लिए जा रहे गन्ने की कीमतें अभी तक निर्धारित नहीं की जबकि दूसरी ओर इस वर्ष हारवेस्टर से गन्ने की फसल की कटाई पर वजन में बिना किसी औचित्य के कटौती 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दी गई है जबकि पड़ोसी राज्य की शुगर मिलों में यह कटौती केवल 3 प्रतिशत है।
- इस वर्ष जनवरी तथा फरवरी माह में प्रदेश के किसान पाला और शीत लहर से प्रभावित सब्जियों और सरसों की फसल को भारी नुकसान हुआ है।
- अभी हाल ही में कृषि विभाग द्वारा एक सांकेतिक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें प्रदेश के भिवानी, महेन्द्रगढ, हिसार व चरखी दादरी इत्यादि जिलों में सरसों की फसल को पाला पड़ने की वजह से भारी नुकसान हुआ है।
- भिवानी जिले में लगभग 3.65 लाख एकड़ में सरसों की फसल थी जिसमें से लगभग 2.50 लाख एकड़ लगभग 70 प्रतिशत सरसों की फसल को नुकसान हुआ है।
- महेन्द्रगढ़ में लगभग 87 हजार हेक्टयर में सरसों की फसल को नुकसान हुआ है। अभी तक सरकार द्वारा इस नुकसान के लिए स्पेशल गिरदावरी के आदेश नहीं दिए हैं जिससे प्रदेश के किसान धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं।
- वर्ष 2020 खरीफ फसल को हुए नुक़सान के मुआवजे को लेकर कई स्थानों पर किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। किसानों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि बीमा कम्पनियों द्वारा पिछले कई सीजन से मुआवजे के

पूंजीपतियों के तो कर्ज माफ कर रही है लेकिन किसान जो पूरे देश का पालन–पोषण करता है उसके ऋण माफ करने की जब बात आती है तो सरकार देश की अर्थ व्यवस्था खराब होने का ढोंग रचती हैं।

- किसानों के कर्ज में दबने का मुख्य कारण फसलों पर बढ़ती लागत व फसलों का उचित भाव नहीं मिलना है। जब खराब मानसून या प्राकृतिक आपदा आती है, तो किसान ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाता है और सरकार उसके नुकसान की लागत मूल्य को ध्यान में रख भरपाई नहीं करती जिससे उसका कर्ज ओर भी बढ़ जाता है।
- वर्तमान सरकार ने वर्ष 2016 में किसानों की 2022 तक आय दोगुनी करने का वादा किया था लेकिन आय दोगुनी होना तो दूर, फसलों पर लागत और किसान पर कर्ज दोगुना हो गया है।
- प्रदेश की लगभग सभी चीनी मिलों में गन्ने की पिराई नवम्बर माह में शुरू हो चुकी है जबकि हरियाणा सरकार द्वारा इस वर्ष 2022–23 के लिए गन्ने की कीमतें निर्धारित नहीं की गई हैं।
- पिछले वर्ष सरकार द्वारा अगेती गन्ने की फसल की कीमत 362 रू. प्रति क्विंटल तथा पछेती गन्ने की फसल की कीमत 355 रू. प्रति क्विंटल निर्धारित की गई थी। आज की परिस्थितियों में डीजल, खाद, दवाईयां, बीज आदि के साथ–साथ गन्ने की छिलाई, लदाई, ढुलाई आदि में बेतहाशा वृद्धि के कारण गन्ने की फसल पर लागत बढ़ने के कारण किसान इस वर्ष 425 रू. प्रति क्विंटल की मांग कर रहे हैं।

22/2/23

- प्रदेश के लगभग सभी जिलों में अध्यापकों की कमी के कारण स्कूलों में बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं परंतु नूहं जिले के स्कूलों में हालात बहुत ही चिंताजनक हैं।
- अधिकारिक आंकड़ों के अनुसार नूहं जिले के 17 प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनमें 1501 छात्र हैं लेकिन वहां एक भी शिक्षक नहीं है। एक स्कूल में तो 411 छात्रों को केवल एक शिक्षक ही पढ़ाता है।
- हकीकत में 54.3 छात्रों के लिए एक जेबीटी शिक्षक नियुक्त है जबकि 30/32 छात्रों के लिए एक शिक्षक नियुक्ति निर्धारित मानदड़ों के विरूद्ध है।
- प्राथमिक विद्यालय स्तर पर मानदड़ों को पूरा करने के लिए जिले में 2058 जेबीटी शिक्षकों की आवश्यकता है। प्राप्त सूचना के अनुसार नूहं जिले में 59 मिडल स्कूलों में 6914 छात्र हैं लेकिन एक भी शिक्षक नहीं हैं व 11 मिडल स्कूलों में 2590 छात्र हैं वहां केवल एक–एक शिक्षक है। 21 माध्यमिक/वरिष्ठ स्कूल हैं जिनमें 3091 छात्र हैं लेकिन एक भी शिक्षक नहीं है। ये आंकड़े नूहं जिले में स्कूली शिक्षा बारे बहुत ही चिंताजनक हैं।

कृषि एवं किसान

- आज हरियाणा प्रदेश के किसान कर्ज की मार झेल रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार हरियाणा के प्रत्येक किसान पर आज 1 लाख 82 हजार का कर्ज है जो देश में चौथे स्थान पर है।
- वर्ष 2019, 2020 व 2021 यानि तीन वर्षों में 712 खेती से जुड़े लोगों ने आत्महत्याऐं की हैं। सरकार बड़े–बड़े

अवस्था के लिए एंबुलेंस को पहले सूचित करने जैसे नियमों का पालन करना होता है।

- इन गरीब परिवारों के उत्थान की तो बात करती है लेकिन हकीकत में इन परिवारों के प्रति सरकार गम्भीर दिखाई नहीं देती।

शिक्षा व्यवस्था

- आज प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था और उसकी गुणवत्ता लगातार गिरती जा रही है। स्कूलों का समायोजन और शिक्षकों की कमी ने प्रदेश के बच्चों का भविष्य अंधकारमय बना दिया है।
- सरकार ने अभी हाल ही में 105 सरकारी स्कूल समायोजन के नाम बंद कर दिए हैं जिसके कारण प्रदेश में समूचे तौर पर 4802 स्कूलों की कमी हो गई है।
- वर्तमान शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो गई है कि आज स्कूल की कई कक्षाऐं एक ही कमरे में चल रही हैं, बच्चों के पास बैठने के लिए डेस्क नहीं हैं व शौचालय की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है।
- सरकार की ऑनलाईन तबादला प्रक्रिया के कारण प्रदेश में लगभग 117 ऐसे सरकारी माध्यमिक विद्यालय है जिनमें कोई शिक्षक नहीं हैं।।
- रेशनेलाईजेशन के नाम पर अध्यापकों के पद समाप्त किए जा रहे है। वैसे भी सरकारी स्कूलों में हजारों की संख्या में अध्यापकों के पद खाली हैं जिसके कारण शिक्षा का स्तर निंरतर गिरता जा रहा है।

की है। दिहाड़ीदार मजदूरों द्वारा आत्महत्याऐं करना बहुत ही चिंता का विषय है और ये मामले लगातर बढ़ रहे हैं।

- पिछले कई सालों से सीवर सफाई के दौरान जहरीली गैसों से दम घुटने के कारण बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारियों की मौत हुई है।
- वर्ष 2017 से दिसम्बर 2022 तक लगभग 51 मौतें हो चुकी है। वर्ष 2021 में जहां 5 मौतें हुई थी, वर्ष 2022 में 13 मौतें हो चुकी हैं।
- प्रदेश में लगातार सफाईकर्मियों के जान जोखिम में डालने और समुचित सुरक्षा के इंतजामों पर सवाल उठते रहे हैं। प्रदेश में नियमित, कॉन्ट्रैक्ट, आउटसोर्स के माध्यम से काम कर रहे उन सफाई कर्मियों के बारे में प्रदेश सरकार के पास कोई डाटा उपलब्ध नहीं है।
- मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट 2013 के तहत किसी भी व्यक्ति को निर्धारित सुरक्षा नियमों के बिना सीवर में भेजना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
- किसी विषम परिस्थिति में सफाईकर्मी को सीवर के अंदर भेजा जाता है तो इसके लिए 27 तरह के नियमों का पालन करना होता है। प्रदेश में कई मामले सामने आ चुके हैं जहां न तो सरकारी और न ही निजी एजेंसियां इन नियमों का पालन करती हैं।
- सीवर में अंदर घुसने के लिए इंजीनियर की इजाजत होनी चाहिए और पास में ही एंबुलेंस होनी चाहिए ताकि दुर्घटना की स्थिति में जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके। सीवर टैंक की सफाई के दौरान विशेष सूट, ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क, गम शूज, सेफ्टी बेल्ट व आपातकाल की

22/2/23

अंत्योदय परिवार उत्थान योजना बारे

- सरकार ''मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना'' के अन्तर्गत 3.35 लाख परिवारों की पहचान करने की चर्चा है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय एक लाख रू. से कम बताई गई है।
- इस योजना के अन्तर्गत पशुपालन एवं डेयरी कामकाज को बढ़ावा देने के लिए 68,257 आवेदकों से आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 60,347 आवेदन बैंकों को भेजे गए हैं जबकि केवल 904 आवेदन ही प्रक्रियाधीन (Under Action) हैं। उपरोक्त आंकड़ों से अनुमान लगाया जा सकता है कि सरकार इन परिवारों के उत्थान के प्रति कितनी गम्भीर है।
- वर्ष 2015 से 2021 तक पिछले 7 वर्षों के दौरान प्रदेश में दिहाड़ीदार मजदूरों द्वारा लगभग 2956 आत्महत्याऐं की गई हैं।
- यह सर्वविदित है कि ये मजदूर दैनिक परिश्रम करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। विशेषज्ञों की रिपोर्ट के अनुसार इन मजदूरों द्वारा आत्महत्या करने के पीछे रोजगार न मिलना, अचानक रोजगार छिन जाना, गरीबी, कर्ज व महंगाई जैसे अनेक कारण बताए जा रहे हैं।
- प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र जैसे सोनीपत, पानीपत, गुरूग्राम, फरीदाबाद व बहादुरगढ़ इत्यादि शहरों में बड़ी संख्या में दिहाड़ीदार मजदूर प्रभावित हुए हैं। वर्ष 2021 में लगभग 535 दैनिक दिहाड़ीदार मजदूरों ने आत्महत्याएं

आय 1 लाख 80 हजार से ज्यादा है और दूसरा कारण जिनके बिजली के बिल 9 हजार रू. से अधिक है।

- सरकार बताए कि जब बीपीएल कार्ड धारकों के लिए परिवार पहचान पत्र में 1.80 लाख आय का आधार रखा गया है तो बिजली के सालाना बिल की राशि 9 हजार रू. का आधार बनाने का क्या औचित्य है।
- हकीकत में आज गरीब लोगों पर महंगाई की मार इस कदर पड़ी है कि आमदनी अठनी–खर्चा रूपया हो गया है लेकिन सरकार गरीब आदमी की आमदनी के पहलु को नजर अंदाज करते हुए केवल खर्चे को आधार मानकर बीपीएल कार्ड धारकों के नाम काटने बहाना बना लिया है जिससे स्पष्ट कि वर्तमान सरकार गरीब विरोधी सरकार है।
- परिवार पहचान पत्र में न केवल बीपीएल कार्ड धारकों को परेशान होना पड़ा है बल्कि बुजुर्गों, विधवाओं व विकलांगो की पेंशन भी धड़ड़ेले से काटी जा रही हैं। आज प्रदेश के बुजुर्गों में भी भारी रोष है।
- उदाहरण के तौर पर करनाल जिले के गांव जलमाना निवासी एक दिव्यांग दंपति की 6 बेटियां हैं। उनकी पहले पेंशन काटी गई और फिर राशन कार्ड भी काट दिया गया है विभाग द्वारा की गई इस गलती को ठीक करवाने के लिए यह दंपति लगातार दफ्तरों के चक्कर काटने पर मजबूर हैं।
- प्रदेश में इस प्रकार के सैंकड़ों उदाहरण सामने आए हैं जिनमें विभाग ने तथ्यों की जानकारी के बिना उनकी पेंशन तथा राशन कार्ड काट दिए गए हैं।

ई–टेंडरिंग व रिकॉल

- महोदय, प्रदेश की पंचायतों के चुनाव पिछले वर्ष अक्तूबर–नवम्बर, 2022 में सम्पन्न हुए हैं जिसके बाद से सरकार द्वारा एक निर्णय लिया गया कि 2 लाख रूपये तक के विकास कार्य सरपंच पंचायत के स्तर पर कर सकेंगे और उससे उपर की राशि के विकास कार्य सरकार द्वारा ई–टेंडरिंग के माध्यम से होंगे।
- सरकार के इस निर्णय को लेकर प्रदेश के सरपंच निरंतर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ सरकार ने सरपंचों को अपने पद से हटाने के लिए राईट–टू–रिकॉल की शक्तियां का जो अलोकतांत्रिक प्रावधान किया है उसको लेकर सरपंचों में सरकार के प्रति भारी रोष व्याप्त है।
- सरपंचों का कहना है कि दोनों उक्त निर्णयों से पंचायत के अधिकारों का हनन हुआ है और भ्रष्टाचार के लिए एक नया दरवाजा खोल दिया है।
- सरंपचों द्वारा निरंतर किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों के बावजूद भी सरकार द्वारा इन मामलों में अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है।

22/2/23

18

श्री महीपाल ढांडा(पानीपत ग्रामीण): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। यहां पर एक बात हमारे विपक्ष के लगभग सभी सदस्य बोलते जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब सत्ता में आई थी तो इन्होंने कहा था कि हम किसान की आय को दोगुनी करेंगे लेकिन आज किसानों की आय कहां

दोगुनी हुई है। ऐसा जुमला हर बार छोड़ा जा रहा है। मैं आज एक–एक कांग्रेसी साथी को चैलेंज करके कह रहा हूं कि वे एक–एक फसल का रेट बताना शुरू कर दें कि वर्ष 2013–14 में आपकी सरकार ने किसानों को उनकी फसलों का क्या रेट दिया था? वर्ष 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो इन्होंने किसानों को क्या दिया? 60 साल बनाम 8 साल का मैं पूरा विवरण सदन के पटल पर रखूंगा। मैं बिना तथ्य के सदन में कभी नहीं बोलता हूं। मैं जीरी के बारे में विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूं कि जब वर्ष 2013–14 में इनकी सरकार थी तो सरकार ने मोटे धान का क्या रेट दिया था? (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि ये आमदनी के साथ–साथ कृषि के बढ़े हुए खर्चों के बारे में भी बता दें कि कृषि में खर्चे कितने बढ़ गये हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः मलिक साहब, आप इतने सीनियर मैम्बर हैं और बैठ जाइये। माननीय सदस्य को अपनी बात कह लेने दीजिए। आपको अलाऊ नहीं किया गया है इसलिए आप बैठ जाइये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री महीपाल ढांडाः उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिसकी आंख न हों और आंखों से अंधा हो उसको तो समझाने में दिक्कत आती है मगर जो अकल से अंधा हो उसको समझाने का क्या कोई सूत्र है? उसको समझाने का एक ही सूत्र है और वह है दस्तावेज। मैं हमारे कांग्रेस के साथियों से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस ने देश में 60 साल तक राज किया और 60 साल में ये मोटे धान का रेट 1310/– और 1345/– रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से दे पाए। अब ये लोग हमें कहते हैं कि तुमने क्या किया तो मैं बताना चाहूंगा कि 8 साल में हमारी सरकार ने धान का रेट 2040/– और 2060/– रुपये प्रति क्विंटल

कर दिया है। ये उसकी तुलना करके देख लें। 60 साल में 1310 और 1345/– रुपये और 8 साल में हमने 2040/– और 2060/– रुपये प्रति क्विंटल का रेट दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि आप सुन लें और जब आपकी बोलने की बारी आए तो उस समय जवाब दे देना। इस तरह से हाउस नहीं चल सकता है। यह कोई अच्छी बात नहीं है। आप सभी सुन लें।

श्री महीपाल ढांडाः उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इनको पता नहीं है क्योंकि खेतीबाड़ी से इनका कोई सम्बन्ध नहीं है। पता नहीं ये सभी लोग कहां–कहां से पढ़ कर आये हैं? मैं दस्तावेज के आधार पर बोल रहा हूं। ज्वार का रेट वर्ष 2013–14 में 1500/– रुपये प्रति क्विंटल था और जो कह रहे हैं कि किसान की आय दोगुनी करो दोगुनी करो मैं उनको बता दूं कि आज 8 साल के बाद ज्वार का भाव बढ़ कर 2990/– रुपये प्रति क्विंटल किया है और इतने भाव में सरकार द्वारा एक–एक दाना खरीदा जा रहा है। बताओ कि रेट दोगुने किये हैं या नहीं किये हैं, ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। इनकी कांग्रेस की सरकार ने 1250 रुपये के हिसाब से भी बाजरे का एक दाना भी खरीदा हो तो आप रिकॉर्ड निकलवा लीजिए। हमारी सरकार आज 2350 रुपये के हिसाब से सारा का सारा बाजरा खरीद रही है। आजकल मोटे अनाज की बात भी हो रही है। कांग्रेस की सरकार में राखी का दाम 1310 रुपये था लेकिन आज 3578 रुपये है। आप हिसाब लगायें कि कितना गुणा बढ़ा है? कांग्रेस के साथी कह रहे हैं कि किसान की आय दुगुनी करो लेकिन हमारी सरकार तो दुगुनी से भी आगे दे रही है और किसान की फसल का एक–एक दाना खरीदा गया है। हम हरड़ की खेती किया करते थे क्योंकि हमारे खेत में पानी कम होता था इसलिए हरड़ की खेती

करते थे। जब हम हरड़ की खेती करते थे तो कांग्रेस के समय में हमें कहीं मंडी उपलब्ध नहीं हुई और मंडी उपलब्ध न होने की वजह से किसान ने हरड़ की फसल को बोना छोड़ दिया है। इनके समय में हरड़ का दाम 4300 रुपये प्रति क्विंटल था लेकिन कहीं मंडी नहीं थी, कोई खरीदने वाला नहीं था। आपके माध्यम से मैं कांग्रेस के साथियों को कहना चाहूंगा कि वे हरड़ की खेती करें, हमारी सरकार उसको खरीदेगी। ये कह रहे हैं कि किसान की आय दुगुनी कहां है। मैं कहता हूं कि ये कौन सी क्लास में पढ़कर आए हैं। इनको कुछ दिखाई ही नहीं देता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मूंग दाल की बात कर रहा हूं कि कांग्रेस के राज में मूंग दाल का भाव 4500 रुपये प्रति क्विंटल था लेकिन इन्होंने मूंग दाल का एक दाना भी नहीं खरीदा। हमारी सरकार मूंग दाल को 7755 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद रही है। आप ये बताइये कि यह दुगुना है या नहीं है। हमारी सरकार हर किसान का एक–एक दाना खरीद रही है और ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, यहां कपास की बात की गई है। कांग्रेस के राज में कपास कभी नहीं खरीदी गई। इनके समय में कपास का 3700 रुपये प्रति क्विंटल का दाम था उसके बाद जब हमारी सरकार आई तो हमारी सरकार 6380 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कपास का एक–एक तिनका खरीद रही है। उसी तरह से सन फलावर की बात की गई कांग्रेस राज में कभी भी सन फलावर नहीं खरीदा गया। ये किसानों का उल्लू बनाते रहे। इन्होंने भोले–भाले किसानों को बहकाने का काम किया है। ये पता नहीं ये किस यूनिवर्सिटी में पढ़कर आए हैं। ये कांग्रेस के सारे सदस्य झूठ बोलने में माहिर हैं। इनका जो भी सदस्य खड़ा होता है वही एम.एस.पी. की बात करता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अगर आप लोग अपने मैंबर को बुलवाना चाहते हैं तो आपके ही एक मैंबर का समय खत्म हो जाएगा।(शोर एवं व्यवधान) आप किसी दूसरे मैंबर

का समय लेना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन आपके मैंबर कहते हैं कि हम अपना समय नहीं देंगे।(शोर एवं व्यवधान) आप किसी दूसरे मैंबर को अपना समय दे सकते हैं।

श्री महीपाल ढ़ांडा : उपाध्यक्ष महोदय, ये मेरे बोलते हुए बीच में विघ्न इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इनकी पोल पट्टी खुल रही है। आज हमारी सरकार में सात साल में गेंहू का रेट 1400 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है और 8 साल में आज 2125 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। इस प्रकार से गेहूं में लगभग 815 रुपये का दाम बढ़ाया गया है क्या ये इनको नजर नहीं आया? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनके समय में जौं का रेट 980 रुपये प्रति क्विंटल था लेकिन मैं इनको बता रहा हूं कि हमारी सरकार ने जौं को 1735 रुपये क्विंटल के हिसाब से खरीदा है। हमारी सरकार जौं की फसल का एक–एक दाना खरीद रही है। उपाध्यक्ष महादय, चने की फसल के बारे में बात हुई है। कांग्रेस के समय में चने का 3100 रुपये प्रति क्विंटल रेट था जिसमें एक दाना भी नहीं खरीदा गया लेकिन हमारी सरकार ने 5335 रुपये के हिसाब से चने का एक–एक दाना खरीदा है। आज किसान की चने की फसल का एक–एक दाना खरीदा जा रहा है। इसी तरह से कांग्रेस राज में मसूर की दाल का एक भी दाना नहीं खरीदा गया। उस समय इन्होंनें किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए मंडी तक नहीं दी जिससे किसानों ने मसूर की फसल को बोना ही बंद कर दिया। इन्होंने मसूर का एक दाना नहीं खरीदा। दिल्ली से ही 2950 रुपये एम.एस.पी. घोषित कर देते थे। आज हमारी सरकार 6000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मसूर का एक–एक दाना मंडी में खरीद रही है। ये लोग किसान का उल्लू बनाने का काम कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) इनके समय में इन लोगों ने कभी सरसों को खरीदने तक का काम नहीं किया था। (शोर एवं व्यवधान) इन्होंने 3050 रूपये प्रति क्विंटल सरसों का एम.

एस.पी. घोषित किया था लेकिन इनकी सरकार ने सरसों का एक दाना तक खरीदने का काम नहीं किया था। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो हमारी सरकार ने 5450 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सरसों खरीदने का काम किया था। ये लोग मंड़ियों में जाकर देखें तो इनको पता चल जायेगा कि आज वहां पर सरसों 8000 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदी जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, झूठ के पैर नहीं होते हैं और कांग्रेस के लोगों ने जो झूठ बोलने में पी. एच.डी. की हुई है, इससे जनता इन लोगों की इस हिसाब से घिसाई करेगी कि ये लोग जनता में जाकर बोलने के लायक तक नहीं रह पायेंगे। मैं आज सदन के माध्यम से हरियाणा के भोले–भाले किसान से निवेदन करता हूँ कि चाहे काले चोर की बहकाई में आ जाना लेकिन इन कांग्रेस पार्टी के लोगों की बहकाई में मत आना। इन कांग्रेस के लोगों ने जनता को बर्बाद करने का काम किया है। (शोर एवं व्यवधान) मैं फिर सदन के माध्यम से अपने किसान भाइयों से अपील करता हूँ कि उनकी भलाई के लिए अब तक जो कुछ भी किया गया है, वह केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया है। अतः इन कांग्रेस के लोगों से बचकर रहने की जरूरत है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलबीर सिंह (इसराना) (एस.सी.): उपाध्यक्ष महोदय, कल एक 'सड़क बचाओ संघर्ष समिति' हमारे कई एम.एल.एज. से मिली थी। उस समिति ने हमारे समक्ष जो बाते रखी हैं, सबसे पहले मैं उनको सदन के सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा है कि तलवंडी राणा–बरवाला रोड बंद हो जाने से एक और इस रोड पर जिन लोगों के रोजगार उद्योग धंधे कायम हैं, वे बंद होने की कगार पर आ गए हैं। वही रोजाना स्कूल–कालेज में जाने वाले छात्र–छात्राओं, कर्मचारी व अन्य लोगों को भी अढ़ाई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। यही नहीं कई किलोमीटर घूमकर जाने से चार गुणा ज्यादा किराया भी हिसार तक जाने के लिए देना पड़

रहा है। इस रोड के बंद हो जाने से छात्र, कर्मचारी, गरीब, मजदूर व ग्रामीणों का जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है और ग्रामीणों को अनेक आर्थिक और मानसिक परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। अतः मेरा सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि चूंकि इस मार्ग के बंद हो जाने से हिसार–बरवाला–उकलाना और आदमपुर के लोग प्रभावित हो रहे हैं, वही चंडीगढ़ से हिसार तक आने जाने वाले रोजाना के यात्रियों के लिए भी इस रोड के बंद हो जाने से दूरी और भी ज्यादा बढ़ जायेगी। इस समय भी तलवंडी राणा में लगभग एक हजार महिलायें धरने पर बैठी हुई हैं तो इस रास्ते का हल कराया जाये। मैं सदन के माध्यम से सरकार से यह भी निवेदन करता हूँ कि जो सरपंच हैं, सरकार को उनके साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में बताया गया कि एक बड़ी अच्छी छलांग सरकार ने लगाई है क्योंकि पढ़े लिखे सरपंचों–पंचों को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि यह किस चीज की छलांग लगाई है? जब से पंचायत बनी है, एक भी गांव में विकास कार्य नहीं हुआ है। आज प्रदेश के सभी सरपंच, सरकार की ई–टैंडरिंग प्रणाली के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं। ई–टैंडरिंग प्रणाली जो सरकार लेकर आई है, वह बहुत गलत है। मेरा सदन के माध्यम से अनुरोध है कि जिस प्रकार चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी जब हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे और पंचायतों को काम करने का पूर्ण अधिकार था और पंचायतों को फ्री हैंड होकर काम करने का अधिकार होता था, ठीक उसी प्रकार के अधिकार, पंचायतों को देने का काम करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि सरकार को सरपंचों के साथ नहीं भिड़ना चाहिए। आज हमारे सरपंच एकजुट हैं। वे ठीक बात पर अड़े हुए हैं। अगर सरकार सरपंचों के साथ संघर्ष करेगी तो फिर आपके साथ भी वहीं होगा जिस प्रकार केन्द्र सरकार तीन काले कृषि कानून लेकर आई थी और किसानों ने डटकर इनका मुकाबला किया था

और अंत में सरकार को हार का मुंह देखना पड़ा था और किसान की जीत हुई थी। इसका नतीजा यह निकलकर आया था कि देश के प्रधानमंत्री को और दूसरे नेताओं को थक हारकार 36 बिरादरी के किसानों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी थी। ठीक वैसा ही परिणाम यहां भी देखने को मिल सकता है। अगर यह सरकार भी इसी रास्ते पर चलेगी तो इसके परिणाम ठीक नहीं होंगे। अतः मैं सरकार को आगाह करता हूँ कि सरपंचों की परीक्षा मत लो और उनके लिए ई–टैंडरिंग प्रणाली जो सरकार लेकर आई है, उसको खत्म करने का काम किया जाये। सरपंच बड़ा ही सम्मानित पद है। मैंने भी सरपंच बनकर काम किया है। (शोर एवं व्यवधान) एक माननीय सदस्य ने कहा कि हम कांग्रेसी विधायक लोगों को उल्लू बना रहे हैं। सच्चाई यह है कि जिन्होंने उल्लू बनाया है, वे अपनी कमियों को छुपा रहे हैं। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने देश के पढ़े–लिखे बेरोजगार युवाओं को बहकाया था कि हम सत्ता में आते ही हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज देश में भारतीय जनता पार्टी को राज करते हुए 9 साल हो गये हैं यानि इस वर्ष तक 18 करोड़ रोजगार देने की बात हुई। यदि देश की टोटल आबादी को 18 करोड़ से भाग करते हैं तो हर तीसरे व चौथे घर में पूरे देश और हमारे प्रदेश में भी नौकरी होनी चाहिये थी। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने देश व प्रदेश के पढ़े–लिखे बेरोजगारों का उल्लू बनाया है। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक और बहुत बड़ा झूठ बोलने का काम किया है। झूठ बोलने की प्रैक्टिस यदि किसी ने करनी है तो वह भारतीय जनता पार्टी से सीखे। (घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो मेरा बोलने का समय बाकी है। भारतीय जनता पार्टी ने देश और हरियाणा प्रदेश की जनता से झूठा वादा किया है। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः बलबीर जी, प्लीज आप बैठ जाइये। दूसरे माननीय सदस्य को बोलने का मौका दीजिए।

श्री बलबीर सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनट और बोलने का मौका दीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे क्लेरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसायटी (हरियाणा) ने मांग–पत्र दिया है कि 'लिपिक पद को कार्यसमीक्षा के आधार पर Rs. 3500/-EPL-6 वेतनमान निर्धारित किया जाये।' इस प्रकार से ग्राम पंचायत मोहयूदीनपुर थिराना (पानीपत) ने रैजोल्यूशन दिया है कि उनके गांव का नाम बदलकर ग्राम पंचायत थिराना कर दिया जाये।

श्री उपाध्यक्षः बलबीर जी, अब प्लीज बैठ जाईये। आपका माईक ऑफ कर दिया गया है, अब आपकी कोई बात रिकॉर्ड नहीं होगी।

श्री प्रवीण डागर (हथीन): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश में पिछले 8 सालों से चहुँमुखी विकास हो रहा है। प्रदेश की जनता को मूलभूत सुविधाएं मिलें, इस पर सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। मैं सरकार की सभी योजनाओं की प्रशंसा करता हूँ। श्री मनोहर लाल जी ने प्रदेश की पौने तीन करोड़ की आबादी को अपना एक परिवार समझकर 'सबका साथ–सबका विकास' की नीति के अनुसार सभी वर्गों का ध्यान रखा है। शिक्षा के क्षेत्र के बारे में चर्चा करूं तो पूरे प्रदेश के अंदर राजकीय संस्कृति मॉडल स्कूल बनाने का काम किया है। यदि कृषि के क्षेत्र में चर्चा करूं तो प्रदेश में पहले सेम की समस्या थी। इस बारे में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो उस समय श्री आफताब अहमद से भी इस समस्या के बारे में कहते थे और उस समय हुड्डा साहब से भी कहते थे कि हमारे किसानों की एक साझा समस्या है। दोबालू माईनर की

खुदाई करवा कर जो हमारे किसान भाइयों की सेम की समस्या है, उसे दूर किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य श्री आफताब अहमद से कहना चाहूंगा कि उस समय आपकी सरकार ने इस समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जब हमारी सरकार वर्ष 2019 में दोबारा से सत्ता में आई तो हमारी सरकार ने किसानों का ध्यान रखते हुए दोबालू माईनर को खुदवाने का काम किया। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सभी जिलों में मैडिकल कॉलेज खोलने का कदम सरकार ने उठाया है, वह बहुत ही सराहनीय है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे पलवल जिले में मैडिकल कॉलेज की पिछले सत्र के दौरान घोषणा हुई थी, इस बार बजट सत्र में उसको मंजूरी देते हुए उसकी जगह का चयन करते हुए जल्दी से जल्दी निर्माण करवाया जाये। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हथीन क्षेत्र में सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित मेरी कुछ मांगे हैं । (शोर एवं व्यवधान)

परिवहन मंत्री (पंडित मूल चन्द शर्मा) : .... (शोर एवं व्यवधान)

श्री आफताब अहमद : .... (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला खटक : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री पंडित मूल चन्द शर्मा ने माननीय सदस्य श्री आफताब अहमद को ठीक बात नहीं कही है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : शकुंतला जी, एक मैम्बर सदन में बोल रहे हैं । अतः मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि आप उन्हें डिस्टर्ब न करें । यह अच्छी बात नहीं है । आप प्लीज अपनी सीट पर बैठिये । (शोर एवं व्यवधान)

श्री प्रवीण डागर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी मांग है कि मेरे क्षेत्र के बहीन, मानपुर, गहलाब और जैंदापुर में पी.एच.सी. का निर्माण करवाया जाए । मेरी माननीय मुख्य

मंत्री महोदय से रिक्वैस्ट है कि दिल्ली–मुम्बई एक्सप्रैस–वे और के.एम.पी. एक्सप्रैस–वे के इंटरचेंज की गांव मंडकौला में कनैक्टिविटी दी जाए । इस की माननीय मंत्री जी ने मंजूरी दी हुई है । यह सड़क हरियाणा सरकार ने बनानी है, इसलिए इस हेतु जमीन का जल्द ही अधिग्रहण करके इसका निर्माण करवाया जाए । उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र के गांव बहीन और मानपुर के मध्य में एक डिग्री कॉलेज बनाया जाए ।

श्रीमती शकुंतला खटक : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री पंडित मूल चन्द शर्मा ने माननीय सदस्य श्री आफताब अहमद को ठीक बात नहीं कही है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : शकुंतला जी, यह कोई तरीका नहीं है । एक मैम्बर सदन में बोल रहे हैं । अतः मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि आप उन्हें डिस्टर्ब न करें । यह अच्छी बात नहीं है । आप प्लीज अपनी सीट पर बैठिये ।

श्री प्रवीण डागर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि गुरूग्राम कैनाल के पास का काफी क्षेत्र पानी के रिसाव की वजह से सेम की समस्या से पीड़ित है । वहां के किसानों की हालत दयनीय है । मेरे द्वारा सिंचाई विभाग को नहर की कंक्रीट लाइनिंग हेतु प्रस्ताव दिया गया है । मेरी मांग है कि इस बजट में गुरूग्राम कैनाल की कंक्रीट लाइनिंग हेतु बजट आवंटित किया जाए । उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में 2 सड़कें बिल्कुल खराब हैं – एक जैंदापुर से सहराला और दूसरी वह सड़क जो हथीन से मीरका होते हुए नूँह को जोड़ने का काम करती है । इनकी मरम्मत के लिए भी बजट मन्जूर किया जाए । माननीय मुख्य मंत्री महोदय और माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय ने मेरे हथीन क्षेत्र के लिए जो 25 करोड़ रुपये मन्जूर किये हैं उसके लिए मैं हथीन की जनता की ओर से उनका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं । मेरी मांग

है कि हथीन के सब–डिविजन अस्पताल जोकि 25 बैड क्षमता का है उसकी क्षमता को बढ़ाकर 100 बैडिड किया जाए । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि सरपंचों के साथ बैठकर उनकी समस्या का भी समाधान किया जाए । मैं अपनी बात एक शेर के माध्यम से खत्म करना चाहूंगा –

काम करने वालों पर ही आमजन विश्वास करेगा,
यह अभिभाषण नहीं किसी को भी निराश करेगा ।
केवल विरोध करने के लिए लिए विरोध करना ठीक नहीं,
यही हरियाणा का विकास करेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद ।

श्री धर्म सिंह छौक्कर (समालखा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं । माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सरकार के काम–काज की जो तारीफें हुई वे आप सभी के सामने हैं । इस बारे में पहले काफी डिस्कशन हो चुकी है । सरकार ने 'हरियाणा एक हरियाणवी एक' और 'सबका साथ सबका विकास' का नारा दिया था । मैं अपने क्षेत्र की बात कहूंगा कि चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल के दौरान 10 साल में जो विकास हुआ था, इस सरकार के 8 वर्ष के कार्यकाल में उतना विकास नहीं हुआ है । इस समय सदन में प्रत्येक विभाग के माननीय मंत्री जी भी बैठे हैं । मैं कहना चाहूंगा कि अगर इस कार्यकाल में प्रदेश में कोई कॉलेज, अस्पताल, सी.एच.सी., स्टेडियम, पावर हाउस, पुल या कोई पुलिया भी बनी हो तो बता दें । इसके बावजूद यह सरकार विकास की बात करती है । अब मैं अपने हल्के के विकास की कुछ बातें कहना चाहूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि यह बहुत चिन्ता का विषय है । बिजली

की चोरी को रोकना अच्छी बात है और हम इसका समर्थन भी करते हैं लेकिन बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए जाएं कि सुबह 4–5 बजे हमारी बहन–बेटी चौबारे में सो रही होती हैं, इसलिए इस समय रेड न की जाए । रेड करने के समय में थोड़ा चेंज किया जाए । इसके अलावा अगर ए.एल.एम. किसी पर जुर्माना लगा देता है तो उसकी अपील का कहीं प्रावधान ही नहीं है । उसको कहा जाता है कि आप चीफ मिनिस्टर के पास जाओ क्योंकि अब जो जुर्माना लगाया है बस लग गया । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा और इस बारे में मैंने पहले भी कहा था । इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लैवल पर अपीलेट अथॉरिटी में एस.ई. लैवल के किसी अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए । अगर किसी का बिजली का कनैक्शन भी नहीं है तो उस पर भी 1.50 लाख रुपये या 2 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से कहना है कि इसको चेंज करके एक पॉलिसी बनायी जाए। डिस्ट्रिक्ट हैडक्वॉर्टर पर एक अपील अथॉरिटी बनायी जाए क्योंकि अगर ए.एल.एम./एम.एम. ने 50,000 रुपये का जुर्माना लिख दिया तो उसको कोई काटने वाला नहीं है। जबकि हर डिपार्टमैंट में अपील का प्रावधान है। जैसे रेवैन्यू डिपार्टमैंट में तहसीलदार, एस.डी.एम., डी.सी., कमिश्नर, एफ.सी.आर. के बाद सरकार तक अपील की फाइलें जाती हैं इसलिए इसके लिए भी अपीलेट अथॉरिटी का प्रावधान करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय माइनिंग मिनिस्टर से एक बात कहना चाहूंगा और इसके बारे में मैंने पहले भी कहा था मेरे विधान सभा क्षेत्र से 32 किलोमीटर की दूरी पर यमुना नदी लगती है। अगर कोई भी किसान अपने घर की चिनाई के लिए, किसी संस्था, मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे के लिए रेत लाता है तो विभागीय ऑफिशियल्ज उसकी बुग्गी–गाड़ी को पकड़ लेते हैं। उपाध्यक्ष

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि इसके लिए एक पॉलिसी बनायी जाए कि जो किसान अपने पर्सनल यूज के अलावा बेचने के लिए ट्रक भरकर रेत ले जाता है या ट्रॉली भरकर रेत ले जाता है तो बेशक उसको पकड़ लें इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसान अपने लिए कोई चीज बनाने के लिए रेत ले जाता है तो उस पर थोड़ा–सा ध्यान रखा जाए और उसकी बुग्गी–गाड़ी को न पकड़ा जाए। इसके लिए सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न आए। मेरे हल्के के सनौली रोड पर एक टोल प्लॉजा बना हुआ है। इसके लिए लोगों ने पूरा एजिटेशन भी किया था और सरकार को डी.सी. के माध्यम से ज्ञापन भी दिया था, इसलिए सनौली ब्लॉक और बापोली ब्लॉक के लोगों का टोल टैक्स माफ किया जाए। इसमें मेरा यही कहना है। दूसरा हमारा जो समालखा का फ्लाईओवर का ब्रिज बना हुआ है। उसको आज बने हुए करीब तीन साल हो चुके हैं उसकी दोनों तरफ की रोड्ज का बहुत बुरा हाल है। नेशनल हाइवे पर बहुत ज्यादा गढ्डे खुदे पड़े हुए हैं और वहां पर हर रोज एक्सीडैंट्स होते रहते हैं। जिनके कारण बहुत नुकसान होता है। उपाध्यक्ष महोदय, इस समय माननीय उप मुख्यमंत्री जी सदन में उपस्थित नहीं हैं। चूंकि वे पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) मंत्री भी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस बात पर भी गौर फरमाया जाए क्योंकि इस नेशनल हाइवे पर से चण्डीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जे. एंड के. तक का ट्रैफिक निकलता है। इस नेशनल हाइवे पर से लोग जाते हैं, लेकिन उन गढ्डों के कारण सरकार की बदनामी होती है। इसमें मेरा कहना यह है कि इसका भी प्रॉयरिटी पर ध्यान रखा जाए। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि इसी सरकार के समय में वर्ष 2018 में समालखा में सी.एम. साहब ने एक सी.एम. अनाउंसमैंट की थी। मेरे विधान सभा क्षेत्र की जो कॉलोनीज

हैं, उनको म्यूनिसिपल लिमिट में एक्सटैंड करने का प्रावधान था, लेकिन उन बातों को आज 5 साल हो चुके हैं। जब हम संबंधित अधिकारियों से पूछने के लिए जाते हैं तो वे कहते हैं कि सर्वे हो गया है और ये कॉलोनीज म्युनिसिपल लिमिट में एक्सटैंड हो जाएंगी। लेकिन अभी तक उनका सर्वे नहीं हुआ है। जो गांव का एरिया है और शहर का एरिया है, वह तो कमेटी में है, लेकिन वहां पर डिवैल्पमैंट बिल्कुल नहीं हो रही है। इस प्रकार वे न तो गांव के रहे और न ही शहर के रहे। इनकी म्युनिसिपल लिमिट एक्सटैंड करने की सी.एम. साहब की घोषणा है, इसलिए उसको तुरंत लागू किया जाए। इसको इम्पलीमैंट किया जाए। हमारी 16–17 कॉलोनीज पॉलिसी के अनुसार नॉर्म्ज पूरे करती हैं, उन कॉलोनीज को नियमित किया जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में सनौली से वाया बापोली समालखा स्टेट हाइवे है। यहां पर एक नेशनल हाइवे है और यह पानीपत से मुज्जफरनगर होते हुए आगे तक जाता है, लेकिन संबंधित स्टेट हाईवे पर पुल नहीं है। वहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है और वहां पर एक चौक भी है। इसको चालू हुए 6 महीने का समय हो चुका है, लेकिन इस दौरान कम से कम 8 एक्सीडैंट्स हो चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष: धर्म सिंह जी, प्लीज, अब आप बैठ जाएं। आपके बोलने का समय पूरा हो चुका है। अब माननीय सदस्य श्री दुड़ा राम जी अपनी बात रखेंगे।

श्री धर्म सिंह छौक्कर: उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा चुकलाना गांव है और उसकी लगभग 50,000 की आबादी है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि इस गांव की पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में बदला जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धर्म सिंह जी, अगर इसके अलावा आपकी कोई बात रह गयी है तो उसके बारे में लिखित में दे देंगे तो उसको प्रोसिडिंग्ज का पार्ट बनवा देंगे।

श्री दुड़ा राम (फतेहाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल अपने हल्के की कुछ दिक्कतों के बारे में ही बात करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले विधान सभा सैशन के दौरान भी यह बात उठायी थी कि फहेहाबाद जिला हैडक्वार्टर पर कोई भी कॉलेज नहीं है। मैंने इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी प्रार्थना की थी और उन्होंने लिखकर भी भेजा है। फतेहाबाद के पास मताना गांव है वहां पर पहले जे.बी.टी. का कॉलेज था, लेकिन वह बन्द हो चुका है। वह बिल्डिंग भी सरकार की ही बनायी हुई है और वह 10 एकड़ जमीन है। मेरी इस बारे में आज भी माननीय मंत्री पंडित मूलचन्द शर्मा जी से बात हुई है कि वहां पर बिल्डिंग बनी हुई है और जिला हैडक्वॉटर पर कॉलेज नहीं है। मेरी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि आने वाले मार्च के महीने के बाद वहां पर क्लॉसिज लगवाएं ताकि बच्चों को कोई दिक्कत न हो। वहां पर जगह भी दे रखी है और बिल्डिंग बनी हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि इस बात पर पूरी गौर की जाए।

श्री उपाध्यक्ष: शिक्षा मंत्री जी, यह बिल्डिंग मताना गांव में बनी हुई है।

श्री दुड़ा राम: उपाध्यक्ष महोदय, यह कॉलेज वाला विभाग माननीय मंत्री पंडित मूलचन्द शर्मा जी के पास है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप इस काम को करवा दें। इस संबंध में मुझसे भी लोग मिलने के लिए आये थे, इसलिए मैंने भी साथ में सिफारिश कर दी है।

श्री दुड़ा राम: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी की वहां पर रिश्तेदारी भी है। माननीय शिक्षा मंत्री जी और माननीय परिवहन मंत्री जी भी सदन में बैठे हुए हैं, इसलिए इस काम को दोनों माननीय मंत्री जी मिलकर करवा दें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: उपाध्यक्ष महोदय, क्या इन्होंने एक भी स्कूल बनवाया है?

श्री दुड़ा राम: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय नेता प्रतिपक्ष को कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी स्कूल्ज भी बनवा रहे हैं। **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।)** अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं किसानों के खेतों में बनने वाले खालों की बात करना चाहूंगा। मैं खास करके हिसार, सिरसा और भिवानी जिले की बात करूंगा। इस बारे में सरकार ने 20 साल की पॉलिसी बनाई हुई है। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है उस पॉलिसी को कम करके 10 साल किया जाये ताकि वहां के किसानों को इसकी सुविधा मिल सके। इसके अलावा मैं खास करके फतेहाबाद शहर की बात करूं क्योंकि अब फतेहाबाद को जिला बना दिया गया है यह पहले सब–डिवीजन हुआ करता था। अगर मैं वहां पर पानी की निकासी और सीवरेज को लेकर बात करूं तो वहां पानी की निकासी और सीवरेज के लिए नया सर्वे करवाकर कोई नई व्यवस्था लागू करने का काम किया जाये। अगर मैं भूना नगर पालिका की बात करूं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहले इसका जिक्र किया था, पहले वहां पर पंचायत हुआ करती थी और आज वहां पर नगर पालिका बन गई है। इसमें कुछ एरिया ऐसा बच गया है, मेरे कहने का मतलब यही है कि वहां के लोगों के वोट नगर पालिका में आ गये हैं। नगर पालिका के एरिया से जो कॉलोनियां बाहर पड़ती हैं और रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार जो रास्ते छोड़े गये हैं, उन रास्तों को न तो वहां की नगरपालिका बनाने का काम करती है और न ही वहां पर पंचायत है। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि चाहे इन रास्तों को नगर पालिका बनाये या पंचायत बनाये लेकिन वहां के लोगों को सहूलियत दी जाये क्योंकि इससे लोगों को काफी दिक्कत होती है। इसके अलावा मैं भूना में बहुत सालों से बाईपास की मांग करता आ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना

है कि भूना में बाईपास बनवाया जाये। इसी तरीके से फतेहाबाद के बाहर तो सड़कें बना दी गई हैं लेकिन फतेहाबाद के गांवों धनगर से दरियापुर तक एक मिनी बाईपास जा रहा है, उसको भी चौड़ा बनाने का काम किया जाये क्योंकि वहां पर बस–स्टैंड भी बन चुका है। इसके अलावा मैं ज्यादा न कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा क्योंकि टाइम कम है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं। मेरी मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि सरपंचों की जहां तक बात है तो आपस में बैठकर जो भी बीच का रास्ता निकलता हो तो वह निकालना चाहिए ताकि हमें कोई दिक्कत न आये। इसके अलावा फतेहाबाद और हिसार जिला के एरिया में लोग ढाणियां में रहते हैं। वहां पर खेतों में जो बिजली दी जा रही है और किसानों ने अपने खेतों में ट्यूबवैल भी लगा रखे हैं, उनको 8 घंटे बिजली मिलती है। गांव के हिसाब से जितना बिल आता है, उसी हिसाब से वे बिल भी पूरा भरते हैं इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि उनको 24 घंटे बिजली देने का काम किया जाये। चाहे इसके लिए गांव से अलग लाईन देकर जोड़ा जाये या और किसी दूसरे तरीके से लाईन को जोड़ा जाये। जहां पर लाईट नहीं लगी हुई है उन किसानों को आप लाईट देने का कष्ट करें क्योंकि खास करके तीन चार जिलों में लगभग–लगभग लोग ढाणियां में रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोलने के लिए श्री प्रदीप चौधरी जी रहते हैं। मैं उनको यह भी कहूंगा कि वे भी बोल लें। 6 सदस्य जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वे नहीं बोल पाये हैं। जब बजट का सत्र आयेगा उसमें ये वाला टाईम एडजस्ट करके हम उनको बोलने के लिए डबल टाईम दे देंगे।

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, हमारा नम्बर नहीं आया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आफताब जी, सभी को बोलने का टाईम दिया गया है। कोई बोलने से नहीं रहा है। (शोर एवं व्यवधान) मेरे पास लिस्ट है। जो नहीं बोले हैं, उनको भी बुलवाएंगे। 6 लोग तो बी.जे.पी. के भी हैं जो बोलने से रह गए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, हम यहां बैठे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बताओ कौन नहीं बोला। आप बोले हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, हम नहीं बोले हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मुझे गवर्नस एड्रैस और जीरो ऑवर पर भी बोलने का टाइम नहीं मिला है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मेरे पास आपकी पार्टी की तरफ से आपका नाम नहीं आया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम नहीं बोला गया।

श्री अध्यक्ष : आफताब जी, ठीक है आपको भी बोलने के लिए डबल टाईम दे देंगे। प्रदीप जी, आपने बोलना है तो बोल लो।

श्री प्रदीप चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आज अमृत काल की जो बात कही जा रही है लेकिन वही आज प्रदेश में चाहे मंहगाई हो, चाहे बेरोजगारी बढ़ती हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे आई.डी. प्रूफ की बात हो, पैंशन कटने की बात हो, चाहे राशन कार्ड कटने की बात हो, चाहे किसान, कर्मचारियों, सरपंचों को लेकर प्रदर्शन करने के लिए जो हाहाकार मचा हुआ है, वहां पर आज कहीं न कहीं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। सरकार द्वारा कालका और पिंजौर जैसे शहरों में या गांवों में बिजली देने की बात कही जाती है कि हम इनको 24 घंटे बिजली दे रहे हैं

लेकिन कहीं न कहीं बिजली पूरी नहीं मिल पा रही है और बिजली न मिलने के कारण पानी पर भी असर पड़ता है और पीने के पानी को लेकर वहां पर इतना बुरा हाल है कि सर्दियों में भी 15–15 मिनट तक पानी के लिए इंतजार करना पड़ता है। आपने भी अखबारों या मीडिया के माध्यम से देखा और सुना होगा कि वहां पर पीने के पानी को लेकर इतना हाहाकार मचा हुआ है। आज सफाई व्यवस्था में स्वच्छता अभियान की बात की जाती है। कालका–पिंजौर नगर पालिका सबसे पुरानी रही है और नगर निगम में भी रही है अब नगर परिषद बनी है लेकिन वहां आज तक कहीं भी डम्पिंग ग्राउंड का कोई समाधान नहीं हो सका। कूड़े को कभी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में डाल देते हैं, कभी पिंजौर गार्डन के आगे डाल देते हैं, कभी मल्लाह मोड़ के किनारे पर डाल देते हैं और कभी माजरा टगरे में डाल देते हैं। लोगों के विरोध से यह कूड़ा रामपुर सियडी में डालना शुरू कर दिया लेकिन वहां पर भी जनता ने इसका बहुत विरोध किया। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि वहां पर डम्पिंग ग्राउंड की सही व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को कूड़ा करकट से दिक्कत न आए। इस कूड़े करकट से पीने के पानी में भी बहुत दिक्कत आती है। इस पर पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों के भी बयान आए हैं कि कूड़ा करकट डालने से पीने के पानी पर भी असर पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, कालका–पिंजौर हॉस्पिटल बीमारियों के कारण मरीजों से भरा रहता है। यह बात अखबार की है, अखबार में यह खबर रोज छपती है और आज भी छपी है कि आज भी वहां बहुत ज्यादा मरीज हैं। अध्यक्ष महोदय, अधिकारियों के ये बयान आते हैं कि कूड़े करकट की वजह से कहीं न कहीं पानी पर असर पड़ता है इससे वहां पीने का पानी खराब है। अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली बार भी सदन में एक बात रखी थी कि हमारे बरवाला ब्लॉक, रायपुर रानी ब्लॉक तथा मोरनी ब्लॉक के 40–50 गांव ऐसे है जहां पर कोई डिस्पेंसरी

की व्यवस्था नहीं है इसलिए वहां डिस्पेंसरी की व्यवस्था की जाए। लेकिन इस पर हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान था कि हम वहां चिन्हित करेंगे और जहां चिन्हित करेंगे वहां डिस्पेंसरी बना देंगे। अध्यक्ष महोदय, यह कब चिन्हित किया जाएगा क्योंकि यह लोगों की डिमांड है लोग हमसे पूछते हैं? अध्यक्ष महोदय, जो 55 लीटर पानी देने की बात थी वह भी कहीं न कहीं पूरी नहीं हो पा रही। अध्यक्ष महोदय, जहां एक ओर आवारा पशुओं को लेकर आम आदमी परेशान है वहीं दूसरी और किसानों के खेतों में भी इनसे नुकसान होता है इसलिए इसका भी कोई समाधान निकाला जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, किसान एम.एस.पी. का इंतजार कर रहा है इसलिए सरकार को एम.एस.पी. लागू करनी चाहिए। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि जब भी किसानों को यूरिया और डी.ए.पी. की जरूरत होती है तो उन्हें यह समय पर नहीं मिल पाता है इसलिए इस समस्या का समाधान होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आज बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। बीजेपी की सरकार देश व प्रदेश में दो बार से रही है। हमारे दो बड़े कारखाने थे जिनमें एक ए.सी.सी. सीमेंट फैक्ट्री थी वह बंद हो गई। उसके बाद एच.एम.टी. फैक्ट्री बंद हो गई। अब हमारे आई.टी.आई, बिटना के जो कर्मचारी 10—12 साल से काम कर रहे थे, उनको एक महीने का नोटिस देकर निकाला जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, 7 ए लगा दी गई मेरी आपके माध्यम से सरकार से अपील है कि इस 7 ए को खत्म किया जाए क्योंकि उसको लेकर के छोटे—मोटे धन्धे हैं वे बन्द पड़े हैं। इसके साथ—साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो सरपंचों के अधिकार हैं उनको न छीना जाए। लोगों ने उनको चुनकर भेजा है लेकिन आज उनको संघर्ष करना पड़ रहा है। आज उन पर जो लाठीचार्ज की घटना हुई है, वह निंदनीय है। अध्यक्ष महोदय, स्कूलों के एजुसेट चौकीदार 24 घंटे की ड्यूटी करते हैं लेकिन इस महंगाई के दौर में उनको आज जो 7 हजार रुपये की तनख्वाह

मिलती है इसको लेकर वे परेशान हैं इसलिए उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए। अध्यक्ष महोदय, चाहे आर.यू.बी. हो या आर.ओ.बी. हो, इसको लेकर बड़ी दिक्कतें है। अध्यक्ष महोदय, पिंजौर में हमारी चाणक्यपुर कॉलोनी हैं वहां आप भी गए हैं उसका रास्ता बन्द किये जाने का प्रयास किया जाता है। प्रभावशाली लोग ऐसे काम वहां कर रहे हैं। इसी तरह रायपुर रानी ब्लॉक में मैंने पहले भी कई बार डिमांड रखी है कि वहां पर फायर ब्रिगेड का स्टेशन नहीं है इसलिए वहां पर फायर ब्रिगड का स्टेशन खोला जाए और वहां फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की जाए। अध्यक्ष महोदय, जहां तक सड़कों की बात है आज प्रदेश में सड़कों की हालत बहुत खराब है। कल मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से अपनी यहां की सड़कों की बात की तो उन्होंने कहा कि मैंने इनकी पहले दो बार जांच करा ली जबकि हमें नहीं पता कि इनकी पहले कब जांच हुई ? लेकिन उप मुख्यमंत्री महोदय ने पहले ही कह दिया कि वहां पर एक मोरनी कौन्टिनैंटल रिजॉर्ट है उसका मैं पता करूंगा कि वह क्या चीज है और उसके आगे हम सरकारी सड़क नहीं बनाएंगे, यह खबर अखबार में छपी है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी जिस होटल की बात कर रहे वह तो ऑन रोड है वहां पर सड़क कहां जाएगी ? आज 'अमर उजाला' में खबर छपी है कि सरकारी खर्चे से हम रिजोर्ट तक सड़क नहीं बनवा सकते। जबकि ऐसा कोई मसला नहीं, ऐसा कोई रिजॉर्ट नहीं जहां कोई सड़क बनानी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह गुजारिश करूंगा कि आपने विधान सभा से जो कमेटी भेजने का निर्णय लिया है मैं उसका धन्यवाद करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करूंगा कि यह कमेटी जल्द से जल्द वहां जाए। मैंने आपको कहा है कि वहां लोगों को बहुत दिक्कत है, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि जल्द से जल्द इस कमेटी को वहां पर भेजा जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री जी महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जवाब देंगे।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो माननीय राज्यपाल जी का जिन्होंने 20 फरवरी, 2023 को इस सदन में सरकार की उपलब्धियों, नीतियों और भावी कार्यक्रमों के बारे में एक बहुत ही सारगर्भित व मायनेपूर्ण अभिभाषण दिया, उसके लिए समूचे मैं सदन की ओर से उनका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण में प्रदेश सरकार द्वारा विगत वर्ष में राज्य में जो विकास के एतिहासिक कार्य हुए, अंत्योदय को हासिल करने के लिए हमने जितने प्रकार की योजनायें बनाई, प्रदेश की अवसरंचना में भी जो विकास के काम हुए या भविष्य के विकास का जो हमारा विजन है उसके ऊपर उन्होंने विस्तार से प्रकाश डाला। इस अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों ने निश्चित रूप से इसकी आलोचना भी की है, कुछ सुझाव भी दिये हैं और कहीं–कहीं दबी जुबान में विपक्ष के कुछ हमारे मित्रों ने उसको सार्थक भी कहा है। कुल मिलाकर मेरा यही कहना है कि आलोचना हो कोई बात नहीं। स्वस्थ आलोचना का मैं हमेशा समर्थक रहा हूं क्योंकि विपक्ष का एक मुख्य काम होता है सरकार के कामों की स्वस्थ आलोचना करना। अगर आगे बढ़ने के लिए कोई कमी रह गई है तो उसके बारे में बताना। जहां तक इस विषय का मामला है इसके लिए मैं जरूर स्वागत करूंगा लेकिन बहुत चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही एक अलग अंदाज में और अलग शब्दों में कही जाती हैं। चालाकीपूर्ण व्यवहार भी बताया जाता है और कहीं न कहीं ऊंचे सपने और ऊंची उडान देखने की बात भी उनकी रहती है। जब वह जोर–शोर से बोलते हैं तो उस बोलने में कभी–कभी उनको लगता है कि इसका हमारा जो उद्देश्य है जनता जो देख रही है वो परपज पूरा होता है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि –

वे बोले इतना कि कल अखबार में छप गये,
वे बोले इतना कि कल अखबार में छप गये,
वक्त गुजरा तो आज रद्दी में बिक गये।

कुल मिलाकर मेरा यही कहना है कि जो अखबार में छपने के लिए बोले हैं वे रद्दी में बिके हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी यह कहना है कि –

कुछ देर खामोशी है, फिर शोर आयेगा,
आपका वक्त है, हमारा दौर आयेगा।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि –

रद्दी तक तोली जाती है तराजू में,
रद्दी तक तोली जाती है, तराजू में बिकने से पहले,
तुम्हें कोई परख रहा है तो इसमें बुरा क्या है?

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, क्वैश्चन ऑवर और जीरो ऑवर की तरह आप एक शेयर का ऑवर और फिक्स कर दें। (विघ्न) मतलब वे गवर्नर एड्रैस के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे हैं। लोगों के स्टाईल को कि वे कैसे बोल रहे हैं उसकी कैसे प्रेजैंटेशन है। वे तो अपने–अपने संस्कारों और अपनी एजुकेशन के हिसाब से बोल रहे हैं। ये गवर्नर एड्रैस के धन्यवाद प्रस्ताव का पार्ट नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, ये धन्यवाद अभिभाषण के दौरान आपस में हंसी मजाक है। आप इसको सीरियसली न लें।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष जी, हंसी मजाक नहीं है हरियाणा में तो लोग चारों तरफ त्राहि–त्राहि कर रहे हैं इसलिए यहां पर हंसी मजाक न किया जाये।

श्री अध्यक्ष : ठीक है कादियान जी, अब आप बैठ जायें।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष जी, आप मेरी बात भी सुनें। मेरा यह कहना है कि –

चर्चे हैं आसमानों पर तुम्हारी बर्बादी के,
अगर नहीं समझोगे तो मिट जाओगे,
तुम्हारी दास्तां भी नहीं होगी दास्तानों में। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, अब आप बोल लिये। अब मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि बीच में डिस्टर्ब न करना। (विघ्न) मैं आपसे यही कह रहा हूं कि be in order. (विघ्न) कादियान जी, देखिए दो दिन तक आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यहां पर हुई पूरी चर्चा को सुना है। अब आप जरा एक घंटा उनको भी सुन लीजिए ।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, माहौल को हल्का करने के लिए इस प्रकार की शायरी भी जरूरी है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से शायरी करके सदन का समय खराब हो रहा है। मुख्यमंत्री जी को जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि जिम्मेदारियां मेरी भी हैं और मैं बिना जिम्मेदारी के नहीं बोलता हूं। इनका जो काम था इन्होंने किया है इसलिए अब इनको सुनना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, दो दिन तक आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी चर्चा को सुना है इसलिए अब सभी सदस्यों को इनका जवाब सुनना चाहिए।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कई सुझाव आए हैं और मैंने पहले भी कहा है कि जो अच्छे सुझाव आयेंगे उन पर हम काम करेंगे। इसी प्रकार से कुछ डिमांड्ज भी रखी गई हैं जिनको

हमारे सभी अधिकारियों ने नोट किया है। इन डिमांड्ज के बारे में मेरा कहना यह है कि इनमें से जो डिमांड्ज जिस समय पूरी करने की होंगी उस समय बता दिया जायेगा कि यह डिमांड इस समय पूरी करने की है। यह एक लगातार चलने वाला सिस्टम है। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि कोई बात मंत्री ने कमिटमैंट कर दी तो वह अगले ही दिन हो जायेगी। कठिनाइयां पहले की सरकारों के सामने भी आती थी और आज भी जब कठिनाई आती हैं तो बताई जाती हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी की बात से मैं सहमत हूं कि कई बार मंत्रियों को घोषणा करनी पड़ जाती हैं। बहुत सारे सदस्यों ने यहां सदन में कहा है कि 8 साल पहले मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की थी तो इस बारे में मेरा तो एक ही निवेदन है कि आप अपनी–अपनी घोषणाओं को पूरा करवा लीजिए।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैंने तो बताया है कि कठिनाइयां सभी के समय में होती हैं। हुड्डा साहब के समय में भी रही हैं और हमारे समय में भी हैं और आगे भी रहेंगी। यह एक लगातार चलने वाला प्रोसैस है। विपक्ष का काम कहने का है और कहना चाहिए। हो सकता है हममें कोई सुस्ती आई हो तो हम सजग हो जायेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैंने बता दिया है कि जितनी भी डिमांड्ज हैं उनको नोट कर लिया गया है इसलिए अगर सभी का मैं यहां पर जवाब देने लगा तो जवाब पूरा नहीं हो पायेगा। इस चर्चा के दौरान कुछ प्रश्न भी खड़े हुए हैं और कुछ शंकाएं भी हुई हैं जिनमें से कुछ का उत्तर मैं अभी दूंगा और कुछ का उत्तर कल बजट स्पीच में भी आ जायेगा। बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जो पिछले साल के बारे में कहे जाते हैं और उनके समाधान के लिए ही बजट होता है क्योंकि अगले साल के बजट में उसमें कुछ न कुछ करने के लिए बजट मिल जाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय ई–टैंडरिंग का है जो हमारे बहुत से

साथियों ने उठाया है इसलिए मैं इस पर चर्चा जरूर करना चाहूंगा। इस बारे में मेरा कहना यह है कि व्यवस्थाएं तो बहुत पहले से चल रही हैं लेकिन समय–समय पर व्यवस्था परिवर्तन किसी अच्छे उद्देश्य को लेकर होता है। न केवल प्रदेश में बल्कि देश में भी देश की आजादी के बाद हम लगातार देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं तथा पढ़ भी रहे हैं कि भ्रष्टाचार नाम की एक बीमारी है जो बहुत नीचे तक घर की हुई है। मैंने इसमें कभी भी किसी का बचाव नहीं किया है। मैंने अपने भाषण में भी कहा है कि इसमें नेता भी सम्मिलित होते हैं, अधिकारी भी सम्मिलित होते हैं, कर्मचारी भी सम्मिलित होते हैं तथा कुछ जनता के लोग भी जो वैस्टिड इंट्रस्ट वाले होते हैं वे भी कुछ न कुछ करके लाभ उठाते हैं। ये चीजें कई बार तो म्युचअल अंडरस्टैंडिंग से भी होती हैं और इससे पब्लिक का और पब्लिक एक्सचैकर का नुकसान होता है। अपनी जेब भरने के लिए बहुत से लोग प्रयत्न करते हैं लेकिन सरकार का प्रयास वही माना जायेगा कि व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए उसको कैसे कंट्रोल किया जाये तथा कैसे उसको जीरो लेवल पर लाया जाये। अब प्रश्न यह है कि जीरो लेवल पर आया या नहीं आया, कितना नीचे आया या नहीं आया यह विचार हो सकता है लेकिन इस सारे मामले में हम लोगों ने यह जो सिस्टम खड़ा किया है इसमें पहली बात यह कही जा रही है कि गांवों का जो पैसा है वह गांवों में नहीं भेजा जा रहा है। इस बारे में मेरा कहना यह है कि अभी लगातार हम इस बारे में प्रयत्न कर रहे हैं। ग्राम पंचायतों और अर्बन लोकल बॉडीज के जितने भी अधिकार हैं वे हमने धीरे–धीरे करके मोटे तौर पर सारे अधिकार उनको दे दिये हैं। सरकार का काम मुख्य रूप से उनको बजट उपलब्ध करवाना है। बजट के बारे में सभी को पता है कि एक निश्चित हैड में निश्चित बजट है। हम अपनी डिस्क्रिशनरी पॉवर पर जितना बजट रखते हैं वह साल के अंत में जहां जितनी जरूरत होती है वहां पर डिमांड के हिसाब से खर्च

हो जाता है। लेकिन गांवों तथा अर्बन लोकल बॉडीज के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन तथा सैंट्रल फाइनेंस कमीशन से भी फंड मिलता है। इसके अतिरिक्त अब तो उनको बिजली के बिलों पर भी 2 प्रतिशत पैसा मिलता है। इसी तरह से पंचायतों तथा जिला परिषदों को स्टैम्प ड्यूटी का भी 2 प्रतिशत पैसा मिलता है। इसके अतिरिक्त उनकी अपनी आमदनी भी होती है। कहीं पर ठेके की आमदनी होती है तथा कहीं पर लीज पर दी हुई जमीन की आमदनी होती है। अब उसमें जी.पी.डी.पी.(ग्राम पंचायत डिवल्पमैंट प्लान) के माध्यम से केन्द्र सरकार की तरफ से भी एक पोर्टल बनाया गया है जिसके तहत हर पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद् साल के अपने बजट के हिसाब से उन कामों की एक लिस्ट बना कर पोर्टल पर डाल देंगी। उसमें उनके साधनों से जितना काम हो सकता है वह करवायें उसके बाद हमारे पास कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें एच.आर.डी.एफ. है तथा अभी हमने आर.आई.डी.एफ.(रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डिवल्पमैंट फंड) का प्रावधान किया है। इसी प्रकार ग्राम विकास मंत्रालय का अपना एक बजट होता है। वह बजट बड़े कामों के लिए जब जहां जरूरत होती है वहां दिया जाता है। हमने जिला परिषदों को पर्याप्त फंड उपलब्ध करवाए हैं। पंचायतें अभी बनी है इसलिए इनका लास्ट क्वार्टर का जो पैसा बचा हुआ था वह 1100 करोड़ रुपये अनाउंस करके भेजा है। वह पैसा एस.एन.ए. अकाउंट बनाकर उसमें भेजा है। वह सारा पैसा उस एस.एन.ए. अकाउंट में रहेगा। वे जितना काम करवाते जाएं उतना पैसा उसमें से निकालते जाएं लेकिन ये जो प्रथा है कि पैसा हमारे हाथ में आ जाए और हम उसकी पावर अपने हाथ में रखें, पेमेंट करें तो अपने हाथ से करें और उसमें जिस मर्जी ठेकेदार से काम करवाएं। इस सिस्टम में बहुत सी गड़बड़ है। हमने इसको स्टेट लैवल पर भी लागू किया है और एक अलग से इंजीनियर वर्क्स पोर्टल भी बना दिया है कि इंजीनियर का कोई भी काम होगा वह उस पोर्टल के माध्यम से

होगा। इसके अलावा किसी की मर्जी नहीं है कि वे किसी ठेकेदार को बुलाकर उसको काम दे दे। उसमें कॉम्पीटीशन है। एल–1 में जो आएगा, एल–2 में जो आएगा उसमें 5 प्रतिशत का डिफरैंस होगा तो उससे नैगोशियेशन की जाएगी। कम पैसे में क्वालिटी को ठीक रखते हुए वह काम करवाया जाएगा। हमने दो लाख रुपये तक के काम के लिए तो यह कहा है कि आप जिसको मर्जी बुलाकर काम करवाओ, किसी भी ठेकेदार से करवाओ। गांव में छोटे–बड़े बहुत से काम ऐसे होते हैं जो दो लाख से कम होते हैं। जब से हमने यह व्यवस्था बनाई है आज की डेट में भी 2890 काम दो लाख से नीचे हैं जिनको सरपंचों ने करवाने शुरू कर दिये हैं। कुछ काम चढ़ भी रहे हैं, कुछ काम कर भी रहे हैं। आज की डेट में 3254 पंचायते हैं उन्होंने अपने प्रस्ताव भी पारित कर दिये हैं और काम भी चढ़ा दिये हैं। दो लाख से पांच लाख तक के पैसे निश्चित रूप से ई–टैंडरिंग के माध्यम से ही जाएंगे उसके भी 3297 काम पोर्टल पर डल चुके हैं जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल पंचायत करेगी, उनको पंचायत पास करेगी और बाद में जो एस्टीमेट्स बगैरह बनने हैं वे जे.ई. व एस.डी.ओ. लैवल पर बनेंगे और फिर वे उसको पोर्टल पर डालेंगे। बाद में हमें टैंडर भी वही देंगे। टैंडर डालने में अब ओपन हो गया है जिसमें कोई भी आदमी आकर टैंडर ले सकता है। आज की डेट में ग्रामीण काम को करने के लिए 600 से ऊपर कॉन्ट्रैक्टर्ज ने अपने आप को रजिस्टर्ड कर लिया है। हमने इसको खुला कर दिया है। इसमें हमने शर्तें बहुत कम लगाई हैं। छोटे काम के लिए बहुत कम शर्तों के आधार पर कॉन्ट्रैक्टर्ज अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इसमें प्रचार यह किया गया है कि इसमें जे.ई., एस.डी.ओ. जिस मर्जी को टैंडर देंगे लेकिन मैं कहता हूं कि इसमें किसी की मर्जी नहीं चलेगी। इसमें न जे.ई., एस.डी.ओ. की मर्जी चलेगी और न सरपंचों की मर्जी चलेगी। जो छोटे काम हैं उनमें जो ठीक क्वालिटी का काम करेगा और ठीक रेट

तय करेगा उसको सब मिलकर वहां सरपंच भी होगा, वहां जे.ई., एस.डी.ओ. भी होगा और उनका ग्राम सचिव भी होगा तथा बी.डी.पी.ओ. भी होगा सभी मिलकर टैंडर देंगे। बड़े कामों में उसका लैवल थोड़ा बढ़ जाएगा। इस लैवल के हिसाब से एक पूरा ट्रांसपेरेंट्स प्रारूप बना दिया है और उस ट्रांसपेरेंट्स प्रारूप पर काम करने से किसी को कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ अगर है तो वह यह कि दबी जुबान में बहुत लोग आकर कहते हैं कि पंचायतों का चुनाव लड़ने पर इतना पैसा खर्च कर दिया जी। अगर हमको पता होता कि ये सिस्टम बनना है तो हम इतना पैसा क्यों खर्च करते? अब इसको आप इम्प्लाईड सैंस समझ लें। इम्प्लाईड सैंस क्या है क्योंकि हमने पंचायतों के चुनाव लड़ने पर ज्यादा पैसा खर्च किया है इसलिए हमें पैसा निकालने का ज्यादा अधिकार दिया जाए। क्षमा करना । हम ये एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और हम यह लड़ाई अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। हमारे भविष्य में आने वाली पीढ़ियां ऐसी न हो कि जनता का पैसा लिया जाए और वह कुछ जेबों में जाए। वह हम नहीं जाने देंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, जब पंचायत इलेक्टिड बाडी है तो सरकार को उस पर विश्वास तो करना चाहिए लेकिन सरकार तो पहले ही ऐसा मानकर चल रही है कि अगर उनको अख्तियार दिए जायेंगे तो पैसा यहां चला जायेगा या वहां चला जायेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इस संदर्भ में अपना ही एक उदाहरण देकर बताना चाहूंगा कि मैं रोहतक पंचायत समिति का इलेक्टिड चेयरमैन होता था और उस समय हमारी सरकार भी थी। मैंने मेरे एक सहपाठी को अपने यहां बी.डी.ओ. लगवा लिया और जब इस संदर्भ में प्रस्ताव बनकर आया तो प्रस्ताव में लिख दिया गया कि सारी फाइनेंशियल पावर बी.डी.ओ. को दी जाती है। अब जिस प्रकार सरकार कह रही है कि जे.ईज. या कोई और फाइनेंशियल पावर का प्रयोग करेगा, मैं यह उदाहरण उसी संदर्भ को लेकर दे रहा हूँ। जब मैंने उस

प्रस्ताव को पढ़ा तो मैं सब समझ गया। हालांकि बी.डी.ओ. मेरा सहपाठी था लेकिन मैंने कुछ न कहकर सिर्फ बी.डी.ओ. को अपने पास बुलाया और कहा कि बी.डी.ओ. साहब आप एक प्रस्ताव और बनाओ और उसमें लिखो कि आज के बाद बी.डी.ओ. की जीप में एक लीटर पैट्रोल भी मेरे दस्तखत हुए बिना नहीं डलेगा। मेरा मकसद यही था कि बी.डी.ओ. पर कंट्रोल रहे। इस उदाहरण से मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार को इलेक्टिड बाडी पंचायत पर विश्वास करना चाहिए और जे.ईज. वगैरह पर कंट्रोल रखना चाहिए। पंचायत का मतलब सिर्फ एक सरपंच से नहीं लेना चाहिए बल्कि पंचायत पूर्ण रूप से एक इलेक्टिड बाडी होती है। हम भी इलेक्टिड हैं और आप भी इलेक्टिड हैं तो सरकार को इलेक्टिड बाडी पर विश्वास खराब करके काम नहीं करना चाहिए और केवल यही नहीं सोचना कि बिना ई–टैंडरिंग के केवल मात्र घोटाले ही होंगे क्योंकि सरकार ने जो पोर्टल बनाये हैं, कभी कोई पोर्टल नहीं चलता, चलता भी है तो गलत डाटा पेश करता है। चाहे परिवार पहचान पत्र की बात हो या और कोई दूसरी बात हो, इस वक्त इन पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है बल्कि जरूरत यह है कि पंचायतों को उनके अधिकार से वंचित न रखा जाये।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, हर विषय पर चर्चा करने की जरूरत है। मैं भी इलेक्टिड हूँ और इलेक्टिड बाडी पंचायतों पर पूर्ण विश्वास करता हूँ और यह बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। मैं इलेक्टिड रिप्रेजेंटेटिव हूँ और प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ। हुड्डा साहब, आप भी 9–10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो पिछले साल सरकार ने 1 लाख 77 हजार करोड़ रूपये का बजट पारित किया था, क्या यह सारा पैसा केवल मेरे साइन से खर्च हुआ था। ?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, पास तो कैबिनेट से ही होता है ?

श्री मनोहर लालः ठीक बात। जिस प्रकार यहां कैबिनेट से पास होता है ठीक उसी प्रकार वहां पंचायत से पास होगा। 2 लाख रूपये की लिमिट से नीचे का कोई भी छोटा–बड़ा काम पंचायत से ही पास होगा और पंचायत जिस काम को कहेगी केवल वही काम होगा और दूसरा कोई काम नहीं होगा। ग्राम सचिव का काम होगा, उस काम को अकाउंट फोर करना अर्थात सारे मैटर को जस्टिफाई तरीके से देखना। यही नहीं हमने यह भी छूट देने का काम किया है कि अगर कोई काम कराना है तो जिस मर्जी कांट्रैक्टर से बिना ई–टैंडरिंग के भी करा सकते हैं हालांकि हमने कोटेशन लेने का प्रावधान जरूर किया है और कोटेशन के बिना तो शायद पंचायत काम न करा पायें लेकिन कोटेशन कितने आदमियों ने दी है, दो ने दी हैं या चार ने दी हैं, इस सबके प्रावधान के बाद काम करवाने का अधिकार दिया गया है लेकिन इसमें जो प्रमुख बात है, वह यह है कि सरकार ने 2 लाख की लिमिट से नीचे के काम कराने के पूरे राइट पंचायत को दिए हैं और इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है। चाहे कांट्रैक्टर को बुलाओ, चाहे पंचायत से प्रस्ताव पास करके पेमेंट कर दो, सरकार की इस तरह की बातों पर कोई रोक टोक नहीं है लेकिन यदि 2 लाख से लेकर 25 लाख तक का काम होगा, तो वह केवल ई–टैंडरिंग से ही होगा और किसी भी सूरत में कैश में पैसों के लेन देने से यह काम नहीं होंगे। वैसे अगर देखें तो सरकार को भी यह अधिकार नहीं है कि वह सरकारी खजाने से 2 लाख रूपये निकलवाकर किसी से कोई काम करवा ले। यही नहीं सरकार के किसी मंत्री तक को भी यह अधिकार नहीं है कि वह सरकारी खजाने से 2 लाख रूपये निकलवाकर किसी से कोई काम करवा ले लेकिन पंचायतों को यह अधिकार दिया गया है और इसके लिए हमने आज की डेट में सारे बजट का भी प्रावधान किया हुआ है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, आज की डेट में पी.डब्ल्यू.डी. में सारा काम ई–टैंडरिंग से होता है तो क्या मुख्यमंत्री जी यह कह सकते हैं कि वहां पर करप्शन खत्म हो गया है ?

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, हां खत्म हो गया है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, अगर भ्रष्टाचार वहां पर खत्म हो गया है तो फिर ठीक है लगे रहो।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि भ्रष्टाचार पर काफी लगाम लगी है।(शोर एवं व्यवधान) एक बार सुनिए तो मैं क्या कह रहा हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मेवा सिंहः अध्यक्ष महोदय, कोई लगाम नहीं लगी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार पर कोई लगाम नहीं लगी है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, आप इनको बिठाइये। जब सदन का नेता अपना बयान दे रहा होता है तो इस तरह उसको इंट्रप्ट नहीं किया जा सकता।

श्री अध्यक्षः मेवा सिंह जी और मलिक साहब आप लोग अपनी सीटों पर बैठ जाये और सदन के नेता रिप्लाई दे रहे हैं, अतः आपको उनकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं हर बार लिहाज करता रहा हूँ। जब सदन के नेता अपना रिप्लाई दे रहे हों तो उस वक्त केवल नेता प्रतिपक्ष ही बोल सकता है। इस तरह से दूसरे सदस्य हस्तक्षेप नहीं कर सकते है। पहले भी जब मैं अपना रिप्लाई देता था तो दूसरे सदस्यों द्वारा इंट्रप्ट किया जाता था लेकिन मैंने हर बार

इन लोगों की लिहाज करने का काम किया लेकिन अब ऐसा कोई लिहाज नहीं होगी। विपक्ष के सदस्यों को सदन की मर्यादा बनाकर रखने की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष: मेवा सिंह जी, आप अपनी सीट पर बैठिए।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, विषय पर पुनः आते हुए मैं कहना चाहूंगा कि यदि सिस्टम में कोई गलत बात है तो सरकार को बताया जाये कि सिस्टम में यह बात गलत है और ऐसी बातें होनी भी चाहिए। अब मैं हमारे समय में भी जो गड़बड़ हुई हैं, उनके बारे में सदन को बताना चाहूंगा। (शोर एवं व्यवधान) सुनिए, क्या हुआ पिछले सालों में। हमें भी कई बार बहुत सी बातें बाद में ध्यान में आती है और तुरंत ध्यान में नहीं आती हैं। मान लो 100 करोड़ का टैंडर हुआ। हो सकता हो कि उस समय वह काम 125 करोड़ का हो लेकिन मिल–मिलाकर किसी आदमी ने 100 करोड़ का टैंडर ले लिया और चूंकि नियम यह है कि जो एल–1 होगा, वह टैंडर ले जायेगा। बाद में उसी टैंडर को स्कॉप ऑफ वर्क ज्यादा दिखाकर या एनहांसमैंट दिखाकर, टैंडर को बढ़ा लिया जाता था। इस प्रकार 100 करोड़ रूपये के टैंडर के काम को 125–150 करोड़ रूपये तक अपने आप बढ़ाकर ले जाने का खेल खेला जाता था। अब आगे सुनो। अब हमने तय कर दिया है कि सबसे पहले तो एस्केलेशन क्लाज लगाया जायेगा, क्योंकि आज रेट किसी एक चीज का कुछ है, छह महीने बाद काम की लागत 5 परसेंट 10 परसेंट बढ़ भी सकती है और बढ़ना स्वाभाविक भी है क्योंकि मार्किट रेट के उपर ही सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अगर हम एस्केलेशन क्लॉज नहीं लगायेंगे तो पहला ही टैंडर अपने आप 10 परसेंट मानकर के रेट शायद 10 परसेंट बढ़ा दिया जायेगा। अतः इस तरह की बातों को ध्यान में रखकर हमने निर्णय लिया है कि एस्केलेशन क्लाज लगायेंगे। ऐसा होता था कि अगर टैंडर मान लो छह महीने की बजाय

एक साल या डेढ साल आगे चला जाता था तो ई.एम.सी. छोड़कर भाग जाया करते थे कि क्या हुआ 2 परसेंट पैसा ही तो है, छोड़ो ना, क्यों काम करूं क्योंकि घाटा हो जायेगा लेकिन अब हमने यह किया कि तीन महीने से पहले जितने भी टैंडर्ज में 10 परसेंट से ज्यादा एस्केलैशन हुई थी और अभी उन पर काम चल रहा है, उनकी सबकी पैमैंट रोक दी है। सभी विभागों के लगभग 500 टैंडर्ज ऐसे थे, चाहे वे एच.एस.वी.पी., एच.एस.आई.आई.डी.सी., पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एण्ड आर.), यू.एल.बी. या पंचायत विभाग आदि के हों।

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि डी.एन.आई.टी. में 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य की बात मान ली है लेकिन जो काम हो गये हैं उसमें आज कुछ निकालेंगे तो अगला–पिछला बहुत कुछ निकल कर सामने आ जायेगा। अभी जो काम चल रहे हैं, हमने केवल उनकी पैमैंट रोकी है। अध्यक्ष महोदय, हमने 10 परसेंट से नीचे के टेंडर्ज की एस्केलैशन तो अलाउ कर दी है। यदि 10 परसेंट से ऊपर एस्केलैशन किसी भी कारण से हुई है तो उसकी जांच सेक्रेटरी लैवल पर होगी। यदि वे इस संबंध में सैटिस्फाइड हैं तो ठीक है। मान लो 10 परसेंट की जगह 12, 15 या 20 परसेंट हो गया तो उसको वहां क्लीयर करेंगे। यदि इसके ऊपर सैटिस्फाइड नहीं है तो हमने मिनिस्टर्ज की कमेटी बनाई हुई है उसको वहां एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यदि एक्सप्लेन करने के बाद ठीक नहीं पाया जाता तो संबंधित अधिकारी या संबंधित ठेकेदार जिसका भी दोष होगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम उनको खाली छोड़ देंगे। अध्यक्ष महोदय, 25 लाख रुपये से ऊपर तक के भी काम होते हैं। उसके लिये ऊपर के अधिकारी हैं। उसकी

इंवॉल्वमैंट इंजीनियरिंग वर्कस में एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल की रहेगी लेकिन टैक्निकल एप्रूवल कोई सरपंच, चेयरमैन या हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। टैक्निकल एप्रूवल टैक्निकल आदमी को ही करनी पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि पंचायतों ने अपना काम करना शुरू कर दिया है । भ्रष्टाचार की लड़ाई हम सबको मिल करके लड़नी पड़ेगी। मेरा निवेदन है कि इस लड़ाई के अंदर विपक्ष के साथी भी हमारा जरूर साथ देंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारे एक माननीय साथी ने क्वालिटी को लेकर एक बात उठाई थी। उसके सन्दर्भ में मेरा यह कहना है कि हमने कुछ महीने पहले एक अलग से क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी बनाई है। शायद उसकी नोटिफिकेशन वगैरह हो गई होगी, अगर नहीं हुई तो कुछ दिनों में हो जायेगी। जो भी चलते हुए काम हैं उन सब में क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी जाकर चैक करेगी, उसके सर्टिफिकेट के बाद ही पेमैंट होगी अन्यथा उसकी पेमैंट नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य श्री कुलदीप वत्स ने परिवार पहचान पत्र में खामियों के बारे में एक बहुत गंभीर मुद्दा उठाया था। मैंने उसका उत्तर जो देना था, वह दे दिया है। उन्होंने इस बारे में एक प्रश्नों का बंडल दिया था, उसका सारा जवाब दे दिया है। यदि श्री कुलदीप जी इस समय सदन में उपस्थित नहीं है तो मैं यह बंडल नेता प्रतिपक्ष को दे देता हूँ, नहीं तो अध्यक्ष महोदय आपको दे देता हूँ, उनको दे दिया जाये।

(इस समय माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उपरोक्त प्रश्न—उत्तर का एक बंडल माननीय अध्यक्ष महोदय को दिया गया।)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने किसके बारे में कहा था?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य ने 'परिवार पहचान पत्र' में जो खामियां हैं उसको लेकर कुछ कहा था।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, इसमें बड़ी अजीब–अजीब शिकायत की चीजें निकली हैं। इसमें इंकम टैक्स पेयर की शिकायत भी आई हुई है। गवर्नमैंट इम्पलाईज की शिकायत भी आई हुई है। कुछ ग्रीवेंसिज जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई हैं, वे भी आई हुई हैं। उसको हम लगातार मॉनीटर करके सॉल्व कर रहे हैं। उसमें अभी लगभग 50 परसेंट चीजें बाकी हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई हैं। उनको भी सॉल्व जरूर करेंगे। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री राम कुमार गौत्तम ने संस्कृत पद का विषय उठाया था। माननीय सदस्य के विषय उठाने के बाद कल ही विज्ञापन निकला है। अध्यक्ष महोदय, अध्यापकों की भर्ती का विज्ञापन संयोग से यह पहले से ही तैयार किया हुआ था और विज्ञापन कल ही निकला है। उस विज्ञापन के अनुसार टी.जी.टी. संस्कृत अध्यापक के 714 पद हैं। टोटल टी.जी.टी. के 7471 पदों का विज्ञापन निकला है। मेवात कैडर की अलग से 1252 पदों का विज्ञापन निकला है। उसमें 100 पद ऊर्दू अध्यापक के भी हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य श्री नीरज शर्मा जी ने एक विषय उठाया था लेकिन उसमें अलग–अलग तरह की कंट्राडिक्शन थी, इन्होंने कहा कि हमारे यहां तहसील बनाई जाये क्योंकि हम बहुत ज्यादा रेवेन्यू देते हैं। जब हम रेवेन्यू देते हैं तो हमारे यहां तहसील होनी चाहिये और साथ में यह कह दिया कि हमारे यहां कूड़ा घर स्थापित ना किया जाये। अगर माननीय सदस्य तहसील की मांग करते हैं तो उनको यह मांग नहीं करनी चाहिए कि हम अपने क्षेत्र में कूड़ाघर नहीं बनने देंगे । कूड़े की व्यवस्था ऐसी है कि यह हर घर से निकलता है और इसे हम ही पैदा कर रहे हैं । उसको हम ही इकट्ठा करेंगे, हम ही उसका ट्रीटमैंट करेंगे और हम ही उसको कहीं–न–कहीं उपयोग भी करेंगे । Waste is wealth now. Waste is energy now. हम नई टैक्निक के आधार पर उसका उपयोग कर रहे हैं । यह transitional phase है और इसमें कुछ प्लांट्स लग गये हैं, कुछ लग रहे हैं ।

हाँ, जब तक ये प्लांट्स नहीं लगेंगे तब तक यह कहीं–न–कहीं पर इकट्ठा होगा। इस पर एन.जी.टी. की नजर है खासकर एन.सी.आर. पर । अगर एन.सी.आर. में ये व्यवस्थाएं कहीं कमजोर पाई जाती हैं तो वे हम पर जुर्माना भी लगाते हैं । (विघ्न)

श्री नीरज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने सदन में मेरा नाम लिया है ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कल कूड़े से संबंधित बात कही थी, इसलिए मैंने इनका नाम लिया है । (शोर एवं व्यवधान) माननीय सदस्य कह दें कि मैंने यह बात नहीं कही या मैंने यह विषय नहीं उठाया । (शोर एवं व्यवधान) माननीय सदस्य श्री नीरज शर्मा केवल यह बता दें कि क्या इन्होंने सदन में कल यह विषय नहीं उठाया था । माननीय सदस्य ने सदन में यह विषय उठाया था, इसीलिए मैंने उसका जवाब दिया है ।

श्री नीरज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह क्या बात है कि एस.टी.पी. लगेगा तो मेरे ही हल्के में लगेगा । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : नीरज जी, जहां कूड़ा होगा एस.टी.पी. तो वहीं लगेगा ।

श्री नीरज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, वह एस.टी.पी. दूसरी जगह से शिफ्ट होकर मेरे हल्के में लगाया जा रहा है । मेरा कहना है कि वह एस.टी.पी. पहले जिस स्थान के लिए निर्धारित था अब भी वहीं लगाया जाए । वहां पर उसके लगाने का विरोध हो रहा है, इसलिए उसे वहां से शिफ्ट किया जा रहा है ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, एक विषय एजुसैट चौकीदारों का आया था । मैं बताना चाहता हूं कि यह विषय हमारे ध्यान में है क्योंकि एजुसैट चौकीदार पहले पार्ट टाइम यानि 4–4 घण्टे के लिए नियुक्त थे । अब हमने इनको फुल टाइम के लिए अप्वॉयंट कर दिया है । इनका वेतन पहले केवल 7000 रुपये था।

अब हम इनको हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शिफ्ट कर रहे हैं और इसके लिए हमने इनसे ऐप्लीकेशंज ले ली हैं । इसके अतिरिक्त हम इनको हरियाणा कौशल रोजगर निगम के अधीन लाकर लैवल–1 की न्यूनतम मानदेय 14,000 रुपये जरूर देंगे । अब इनको एजुसैट चौकीदार नहीं कहा जाएगा । एजुसैट चौकीदार की बजाय इनको मल्टी पर्पज वर्कर कहा जाएगा । अब इनसे चौकीदार के अलावा स्कूल के अन्य कार्य भी करवाये जाएंगे । एक विषय खिलाड़ियों के कोटे का आया है । इसमें शायद कंफ्यूजन हो गया है कि हम खिलाड़ियों को केवल 4 विभागों में ग्रूप–सी की 3 परसैंट पोस्टें देंगे । ऐसा नहीं है । (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, नोटिफिकेशन में यही है ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं बताता हूं कि नोटिफिकेशन में क्या है । ग्रूप–सी की जितनी नौकरियां होंगी और जो भी ग्रुप–सी की नौकरियां पिछले साल दी गई हैं उसके अनुपात में जनवरी में ही उसकी 3 परसैंट पोस्ट्स ऐडवरटाइज की जाएंगी । उनको 4 विभागों में नियुक्तियां इसलिए दी जाएंगी ताकि जो खिलाड़ी अपनी योग्यता के आधार पर नौकरी पा रहा है उसकी पहली योग्यता खेल की है, इसलिए सरकार उसकी विधा का उपयोग या तो गृह विभाग में हो सकता है या खेल विभाग में हो सकता है क्योंकि वहां पर खेल की गतिविधियां होती हैं । इसके अलावा हम उनका उपयोग शिक्षा विभाग में कर सकते हैं या फिर हम उनका उपयोग बिजली विभाग में कर सकते हैं क्योंकि वहां भी खूब खेल होते हैं । इसके अलावा जो विभाग खेलों में आगे बढ़ने के लिए अपनी टीमें बनाएंगे उनको प्रारंभ में तो इन्हीं में से डेपुटेशन पर खिलाड़ी कोटे से भर्ती हुए कर्मचारी देंगे । अगर किसी विभाग ने स्थाई कोच बनाने हैं या खेलों में कोई गतिविधि करनी है और वे इसकी डिमांड करेंगे तो उसकी पोस्ट सैंक्शन करके वहां पर पोस्ट्स जोड़ दी जाएंगी । आज के दिन ऐसे केवल 4 विभाग हैं

। इसमें नंबर वही रहेगा जो ग्रूप–सी के पदों का 3 परसैंट है । उस नंबर में कहीं कोई कमी नहीं आएगी । यह बात मुझे स्पष्ट करनी थी । (विघ्न) पहले कर्मचारी नौकरी में खेल के नाते से आता है और वह बिना किसी कंपीटिशन के आता है । जब हम उसको ग्रूप–सी की क्लर्क की सीट पर बिठाते हैं तो वह कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता । (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने उनके लिए बेसिक क्वालीफिकेशन तो रखी ही है । (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि बेसिक क्वालीफिकेशन में भी नौकरियों में एक कंपीटिशन है । अगर कोई कंडीडेट बेसिक क्वालिफिकेशन के साथ 33–35 परसैंट नंबर लेकर आया है तो 65–70 परसैंट नंबरों वाला जो कंडीडेट सिलैक्ट होकर आया है खेल कोटे से आया हुआ कर्मचारी उसके सामने टिक नहीं पाता है । खिलाड़ी को तो अपनी इम्पलॉयमैंट चाहिए । ऐसे में अगर हम उसकी योग्यता का ज्यादा उपयोग करेंगे तो इससे वह भी संतुष्ट रहेगा वरना वह तो बैठा यही सोचता रहेगा कि मैं तो खेल के माध्यम से सिलैक्ट हुआ था, इसलिए मुझे कुछ नहीं आता । मेरा कहना है कि ऐसे कर्मचारी हैं, इसलिए हमने यह काम सिस्टम को थोड़ा–सा सुधारने के लिए किया है । हाँ, हम उनके 3 परसैंट कोटे में से पोस्ट्स को कम नहीं करेंगे यह मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं । इसी प्रकार एक विषय कल हमारे माननीय विधायक ने एस.पी.आई. रैंकिंग के बारे में उठाया था। नीति आयोग द्वारा साल में एक बार एस.पी.आई. रैंकिंग करवायी जाती है और उस रैंकिंग में कम से कम 100 पैरामीटर्ज शामिल होते हैं। यानी एक–दो पैरामीटर्ज नहीं होते हैं क्योंकि अलग–अलग चीजों के अलग–अलग पैरामीटर्ज होते हैं। उसके बाद फिर कम्पोजिट होता है। जो कम्पोजिट होता है, उसके लिए एक एवरेज सर्कल लिया जाता है। हम अलग–अलग पैरामीटर्ज के

हिसाब से किसी पैरामीटर में 90 प्रतिशत पर भी खड़े हो जाएंगे, किसी पैरामीटर में 35 प्रतिशत पर भी खड़े हो जाएंगे, किसी पैरामीटर में 50 प्रतिशत पर भी खड़े हो जाएंगे और किसी पैरामीटर में 60 प्रतिशत पर भी खड़े हो जाएंगे। यह विषय किस माननीय सदस्य ने उठाया था, वह मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। इसको इस ढंग से देखना चाहिए कि इस कम्पोजिट में देश के 19 बड़े प्रदेश हैं और छोटे प्रदेशों का एक अलग सिस्टम है, उनकी कैटेगरी भी अलग बनती है। लेकिन इन 19 बड़े प्रदेशों में हम छठे स्थान पर हैं और हमारे से आगे तमिलनाडु, केरल, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब और कर्नाटक प्रदेश हैं। इसमें ये पांच राज्य हमारे से आगे हैं और छठा स्थान हमारा है। इसके बाद 13 प्रदेश हमारे से पीछे हैं। ये जो 13 प्रदेश हमारे से पीछे हैं मैं उनके नाम भी बताना चाहूंगा। इनमें गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ, महाराष्ट्र, राजस्थान, यू.पी., उड़ीसा, मध्यप्रदेश, असम, बिहार और झारखंड शामिल हैं। इस रैंकिंग में ये प्रदेश हमारे से पीछे हैं। इस एस.पी.आई. रैंकिंग को Statistical Progression Index भी कहते हैं। हम इस रैंकिंग में एक–दो चीजों में 35–36 प्रतिशत पर भी हैं। लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया यह सारा कम्पोजिट है। अगर कोई चीज खराब बतानी है तो अच्छी चीजों के बारे में भी बताएं। हमारा प्रदेश इसमें कई चीजों में बहुत अच्छा है। इसमें जिलानुसार भी रैंकिंग है और इस जिलानुसार रैंकिंग में 6 टीयर्ज हैं। इसमें देश भर के जिले आंके गये हैं। इसमें फर्स्ट टीयर में तो हमारे प्रदेश का कोई जिला शामिल नहीं है, लेकिन सैकिण्ड और थर्ड टीयर्ज में हमारे प्रदेश के 20 जिले शामिल हैं। इनमें से टीयर टू में 8 जिले हैं, टीयर थ्री में 12 जिले हैं, टीयर फोर में 1 जिला है और टीयर फाईव में भी 1 जिला है। यह हमारा बहुत अच्छा स्कोर है और हमें इसमें अपना संतोष व्यक्त करना चाहिए। यह बात ठीक है कि अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहिए कि हम ये हैं, हम ये हैं।

जहां पर हम नम्बर 1 पर हैं, उसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन जहां पर अभी 2,3,5,6 और 8 नम्बर पर हैं, वह भी हमको बताना ही है। इसको कैसे इम्प्रूव करना है, इसके लिए एक–एक चीज पर ध्यान करेंगे और उसको आगे ठीक करेंगे। इसके अलावा एक मंहगाई/गरीबी का विषय भी बार–बार आता है। इसमें मेरा इतना ही कहना है कि जहां तक मंहगाई का विषय है, इसके बारे में सभी अपने–अपने तरीके से बोलें, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े–लिखे को फारसी क्या? हम लोग कर्मचारियों का डी.ए. हर साल मंहगाई के आधार पर बढ़ाते हैं। इस डी.ए. को बढ़ाने का एक पैरामीटर नहीं है। इसका आंकलन सैंट्रल गवर्नमैंट की एजेंसी करती है। पता नहीं डी.ए. बढ़ाने के कितने पैरामीटर्ज हैं ? अगर इनमें से कोई एक पैरामीटर ऊपर–नीचे हो जाए तो कम से कम हमारे कर्मचारी उसको उसी समय पकड़ते हैं कि इसका पैरामीटर कम क्यों कर दिया और उसका ज्यादा क्यों कर दिया ? यह हमारे हाथ में नहीं है। हर 6 महीने बाद डी.ए. (डियरनैस अलाउंस) की किश्त जारी होती है कि वह कितने परसैंट आगे बढ़ेगा? मैं इस संबंध में 2 आंकड़ें बता रहा हूं। इसका हर 10 साल के बाद एक बेस रेट होता है और उसके हिसाब से वह अगले 10 साल तक बढ़ता रहता है। एक बेस रेट वर्ष 1996 में था, उसके बाद सन् 2006 में था। इसके बाद फिर वर्ष 2016 में आया और अब इसके बाद वर्ष 2026 में आएगा। इस सारे को मिलाकर हैंडरैड कर दिया जाता है। फिर हैंडरैड से उसकी परसैंटेज बढ़ती है। यह वर्ष 2006 में हैंडरैड था और उसके बाद हर 6 महीने में बढ़ाते रहे। अब हम वर्ष 2023 में हैं। इसकी इक्वेलैंट डेट जनवरी, 2013 है। जनवरी, 2013 के बारे में किसी को पता है या नहीं है, लेकिन मैंने जो जानकरी ली है उसमें बताया गया कि 80 प्रतिशत मंहगाई हो गयी थी। D.A. was declared 80 percent in January, 2013. अभी जनवरी

का डी.ए. तो डिक्लेयर होना है, इससे पहले 1 जुलाई का जो डी.ए. डिक्लेयर्ड था, वह 38 प्रतिशत था। अगर जनवरी में ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो यह 41 प्रतिशत हो जाएगा। यानी अब डी.ए. का रेट 41 प्रतिशत है। इसके बारे में हमारे सभी कर्मचारी बन्धु जानते हैं। हमें तो अपनी तनख्वाह रेगुलर मिलती है, लेकिन जो एक्स एम.एल.एज. हैं, उनको इसी ढंग से डी.ए. भी मिलता है। अब डी.ए. का रेट 41 प्रतिशत है। यानी 7 साल के वक्त में वर्ष 2006 से वर्ष 2013 तक 80 प्रतिशत मंहगाई थी। अब वर्ष 2016 से लेकर वर्ष 2023 तक 41 प्रतिशत मंहगाई है। It is nearly half. विपक्ष के माननीय सदस्यगण इस बात को समझ रहे हैं। इस प्रकार यह सारा मंहगाई से संबंधित विषय है। विपक्ष के माननीय सदस्यगण कह रहे हैं कि गरीब, गरीब, मंहगाई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि गरीबी को तो इन्होंने पल्ले से छोड़ा ही नहीं। यह जो मंहगाई है, उसकी मैं इनकी पार्टी के समय के वर्ष 2006 से वर्ष 2013 तक के शासनकाल से तुलना कर रहा हूं। उस समय मंहगाई 80 प्रतिशत थी।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : मुख्यमंत्री जी, अब क्या महंगाई नहीं है?

श्री मनोहर लाल : हुड्डा साहब, मैं यह कह रहा हूं कि आज जितनी महंगाई है, उसका मैं वर्ष 2006 से लेकर वर्ष 2013 तक की तुलना कर रहा हूं। आप लोगों के शासनकाल में सैंटर और स्टेट में भी 80 परसैंट महंगाई थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : मुख्यमंत्री जी, आप इसकी तुलना वर्ष 2014 से लेकर अब तक भी कर लो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : हुड्डा साहब, मैं यह भी कह रहा हूं कि वर्ष 2014 से लेकर वर्ष 2016 तक की भी बात कर लो लेकिन मैं वर्ष 2014 के आंकड़ों के बारे में बताना चाहूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : मुख्यमंत्री जी, आप यह बात बताओ कि हमारे समय में स्टेट का डीजल पर कितना वैट था और अब कितना वैट आपने कर दिया? (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : देखिये हुड्डा साहब, अगर किसी चीज का 100 रुपये का रेट है और वह 200 रुपये हो जाये तो 100 परसैंट महंगाई होगी और अगर उस चीज का रेट 200 रुपये है तो फिर उस चीज का रेट 100 रुपये हो जाये तो क्या फिर 100 परसैंट महंगाई होगी? वह 50 परसैंट ही महंगाई होगी। किस चीज पर महंगाई हो रही है। आखिर कोई एक समय था जब वर्ष 1966 में हमारा बजट शायद 2000 करोड़ या 3000 करोड़ रुपये से शुरू हुआ था। वर्ष 2022–23 का 1 लाख 77 हजार करोड़ रुपये का बजट था लेकिन यह आगे चलकर यही थोड़े ही खड़ा रहेगा। यह कई लाख करोड़ रुपये तक भी जायेगा। यह जो inflation rate है लगातार उसमें जुड़ते–जुड़ते एक सिस्टम चलता है इसलिए अब उस समय किसी चीज का रेट 100 रुपये था तो आप 100 रुपये मत गिनो। आप यह गिनो कि यह कितने परसैंट बढ़ा, इसका सिस्टम आपको लगाना पड़ेगा इसलिए उस मुकाबले में आधी महंगाई हमारे यहां पर है। महंगाई तो वही है अगर 1 रुपये बढ़ जाये तब भी महंगाई लेकिन महंगाई कितनी है और उसी हिसाब से सबकी आमदनी बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ती है तो मेरा इस विषय पर यह कहना है कि हमेशा–हमेशा एक ही रेट लगाते रहना ठीक नहीं है। हम जो अपना शोर मचाते हैं वह किसी एक चीज को लेकर लगातार मचाते रहते हैं। इसी प्रकार से गांव की गारंटी वाली बात बता दी है। कर्ज के बारे में एक बात बताई गई। अब वह आंकड़े पता नहीं कहां से लाते हैं। इन्होंने बताया कि 3 लाख 19 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है। जो आंकड़े बताये थे, उनके बारे में मैं फिर से बता रहा हूं। वर्ष 2021–22 में राज्य का जो बकाया ऋण था वह 2 लाख 23 हजार करोड़

रुपये था और उससे अगले साल में यानी वर्ष 2022—23 में भी उसमें जो 40 हजार करोड़ रुपये के ऋण की स्वीकृति हुई थी उसमें भी लगभग 30 हजार करोड़ रुपये आयेगा लेकिन इसके बदले में साथ में कुछ ऋण वापिस भी होता है इसलिए वापिस वाला आंकड़ा उतना कम भी होता है। वापिस में जो मूलधन होता है साथ में उसका ब्याज होता है वह भी वापिस होता है, यह भी लगातार हमारा वजन बढ़ रहा है। हमने वर्ष 2016—17 से लेकर वर्ष 2020—21 तक..................

(शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : मुख्यमंत्री जी, अब तो यह ऑनलाईन है। आप सी.ए.जी. की स्टेटमैंट—वन मंगवा लो।

श्री मनोहर लाल : हुड्डा जी, आप मुझे सी.ए.जी. की स्टेटमैंट—वन दे दें। मैं आपको इसका explanation करके बता दूंगा।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : मुख्यमंत्री जी, सी.ए.जी. की स्टेटमैंट—वन 2 लाख 79 हजार 976 करोड़ रुपये का कर्जा बता रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : हुड्डा साहब, आप 3 लाख 17 हजार करोड़ रुपये बता रहे हो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : मुख्यमंत्री जी, मैं आपको यह कर्जा लाईबिलिटी मिलाकर बता रहा हूं। यह तो आपने 2 लाख 36 हजार करोड़ रुपये का internal debt बता दिया लेकिन आपकी लाईबिलिटी कितनी है? मैंने सदा ही यह ब्यान दिया है कि और यह बात कही है कि कर्जा और लाईबिलिटी मिलाकर 4 लाख करोड़ रुपये के करीब पहुंच जायेगी। आप कल बजट पेश करोगे तो पता लग जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : हुड्डा साहब, मान लो मैंने किसी को 100 रुपये देना है और 110 रुपये लेना है तो मेरा 10 रुपये asset है। आप 100 रुपये गिनकर मेरे ऊपर कर्ज बता रहे हो (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : मुख्यमंत्री जी, मैं on the floor of the House यह बात कह रहा हूं कि you will cross the limit. लोन और लाईबिलिटी मिलाकर आपकी लिमिट 3.50 लाख करोड़ रुपये क्रोस हो जायेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : हुड्डा साहब, आप मुझे बताओ मैं आपको इसी हिसाब से आंकड़े से दे दूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : मुख्यमंत्री जी, अब तो सब कुछ ऑनलाईन हो गया है।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप इस बारे में व्हाईट पेपर इशू करे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : डॉ. साहब, कल जो बजट आयेगा वह व्हाईट पेपर ही है। बजट जो होता है वह व्हाईट पेपर ही होता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : मुख्यमंत्री जी, आप सी.ए.जी. की स्टेटमैंट–वन, टू, थ्री और फोर मंगवा लो। आपने किस–किस चीज पर खर्चा किया है और आपने जहां–जहां कर्ज लिया है वह भी मंगवा लो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : हुड्डा साहब, आप मुझे यह जानकारी दे दीजिए वैसे कल बजट में सारी चीजें आ जायेंगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : मुख्यमंत्री जी, आपका फाइनैंस सैक्रेटरी कौन है उसको कहो कि वह सी.ए.जी. की स्टेटमैंट–वन, टू, थ्री और फोर लेकर आये और कितना कर्जा लिया है वह भी लेकर आये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : हुड्डा साहब, मैं आपको सैक्रेटरी, फाइनैंस के आंकड़े ही बता रहा हूं। अब आप सैक्रेटरी, फाइनैंस के आंकड़े सुनने के लिए तैयार नहीं हो। आप अपनी जानकारी देने के लिए तैयार नहीं। यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : मुख्यमंत्री जी, यह मेरी जानकारी नहीं है। यह तो ओपन है। सी.ए.जी. की रिपोर्ट तो सैक्रेटरी, फाइनैंस लेकर आयेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : हुड्डा साहब, मैं यह कह रहा हूं कि सी.ए.जी. की रिपोर्ट में यह नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप सैक्रेटरी, फाइनैंस को यह कह दो कि सी.ए.जी. की स्टेटमैंट–वन, टू, थ्री और फोर ले आओ और स्टेट ने कितना–कितना कर्जा लिया है वह भी ले आओ और स्टेटमैंट–थ्री के साथ जो एनैक्श्चर है वह ले आओ, आपको पता लग जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, हमें तो इतना पता है कि जो परमिसिबल लिमिट्स हैं हमारा कर्ज उसके अन्दर है। मैं उसके आंकड़े बता रहा हूं और उसकी परमिसिबल लिमिट्स बता रहा हूं। उस लिमिट को आप झूठा कर दो तब मेरे से जवाब मांगो। अब आपके आंकड़े कहां के हैं, ये आप बतायें ?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः मुख्यमंत्री जी, ये तो आंकड़ों का खेल है, लिमिट आप बताओगे आप कहोगे यह 29 प्वाइंट कुछ प्रतिशत है। अगर असलियत में देखो तो यह 38 प्रतिशत मिलेगा।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, कल मुझे एक सज्जन ने एक आंकड़ा दिखाया जिसके ऊपर लिखा हुआ था एस.ई.सी.सी. 2011, जबकि 2011 में एस.ई.सी.सी. था ही नहीं। उसमें ये लिखा हुआ था कि बी.पी.एल. की जो लिमिट थी वह 15,000

रुपये महीने थी जबकि आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 2011 में वह लिमिट 10,000 रुपये थी। 15,000 रुपये की लिमिट तो आज हमने किया है। जिस आंकड़े के बारे में मैंने बताया है, वह सिर्फ टाइप किया हुआ है और टाइप करके कुछ बातें उसके नीचे लिखी हुई हैं। उस डॉक्यूमैंट की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, उस पर किसी के साइन नहीं है। टाइप करवाकर कहीं से भी आएगा ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मुझे पेपर्स दे दो, इनको एक बार मैं देखूंगा। मैं अभी भी इसे नकारता हूं। हां, अगर आप इसे टेबल पर रख दोगे तो मैं सारे आंकड़ों का जवाब दे दूंगा कि क्या आंकड़े हैं। आप कई बार आंकड़े लेकर के कागज दिखाते हैं और बाद में मांगा जाता है तो कहते हैं मैं नहीं दूंगा। इसमें इनको क्या संकोच है। आप एक पेपर तो दे दीजिए जिससे यह पता चल जाये कि यह कहां से निकाला गया है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः मुख्यमंत्री जी, यह स्टैटमैंट सी.ए.जी. की है और यह ऑन लाईन है।

श्री मनोहर लालः हुड्डा साहब, आप मेरे को एक बार इसे दोगे तभी तो मैं इसे देखूंगा। इसकी आप मुझे फोटो स्टेट करवाकर कापी दे दीजिए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः ठीक है मुख्यमंत्री जी, आप इसकी फोटो स्टेट कापी करवा लीजिए।

श्री मनोहर लालः ठीक है, हुड्डा साहब। मैं आपको इसका कल जवाब दूंगा। अध्यक्ष महोदय, इसकी फोटो स्टेट करवाकर हमारे सेक्रेटरी, फाइनेंस को दिलवा दीजिए। शायद इसका जवाब मेरे भाषण से पहले ही आ जाए।

(इस समय सी.ए.जी. स्टेटमैंन्ट सैक्रेटरी, फाइनेंस को दी गयी।)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः मुख्यमंत्री जी, सेक्रेटरी, फाइनेंस तो मेरा अजीज है। आपने इसे मेरे से मांगा और सेक्रेटरी, फाइनेंस को दे दिया। मुझे मेरे पेपर्स वापस दे दें।

श्री मनोहर लालः हुड्डा साहब, मैं तो इसे सेक्रेटरी, फाइनेंस को ही दूंगा। इसमें मेरा क्या रोल है ?

Shri Bhupinder Singh Hooda: Speaker Sir, I have given the papers to the Chief Minister only.

श्री मनोहर लालः हुड्डा साहब, मुझे तो यह सेक्रेटरी, फाइनेंस को ही देना है मेरा यह घर का खाता नहीं है। सरकार का एक सिस्टम है और मैं उसी सिस्टम में ही चैक करवाऊंगा।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः मुख्यमंत्री जी, खाता तो मेरे भी घर का नहीं है।

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, यह ऑफिशियल डाक्यूमैंट है ना?

श्री मनोहर लालः स्पीकर साहब, यह ऑफिशियल डाक्यूमैंट है।

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, ऑफिशियल डाक्यूमैंट को तो ऑफिसर्स ही देखेंगे।

श्री मनोहर लालः स्पीकर साहब, मैं इसकी तहकीकात करवाऊंगा कि यह असली है या नकली है, यह कहां से निकला है, किस वेबसाईट पर है, कौन से खाते का है, मैं ये सभी चीजें चैक करवाऊंगा ?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष जी, ऐसे मत करो। आप मेरी बात सुने। मैं और भी लाकर दे दूंगा। मैं ये पेपर्स पहले नहीं दे रहा था लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह मेरे को दे दीजिए तब मैंने यह दिये हैं।

श्री मनोहर लालः हुड्डा साहब, मैं इनका क्या करूंगा? मुझे इसकी कौन सी पुड़ियां बनानी हैं। मैंने इनका कुछ नहीं करना। मैं सदन के सामने घोषणा करता हूं मैं इसे सेक्रेटरी, फाइनेंस को दूंगा वे इसकी तहकीकात करेंगे और जवाब लाकर देंगे और जवाब लाकर देने के बाद मैं आपको बताऊंगा।

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, आपके उस कागज में ऐसा क्या सीक्रेट है ?

Shri Bhupinder Singh Hooda: Speaker Sir, I will never give the papers to the Finance Secretary.

श्री मनोहर लालः हुड्डा साहब, यह नहीं हो सकता, यह रिकॉर्ड पर आ गया है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः स्पीकर साहब, ये शिष्टाचार नहीं है।

श्री मनोहर लालः हुड्डा साहब, यह रिकॉर्ड पर आ गया। मैं आपके डॉक्यूमैंट को वैरीफाई कैसे करवाऊंगा ? मैं उसे सिस्टम में दूंगा।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः सीएम साहब, रिकार्ड निकालना सैक्रेटरी, फाईनैंस का काम है। इसीलिए मैं डॉक्यूमैंट देने से मना कर रहा था।

श्री मनोहर लालः हुड्डा साहब, आप मना क्यों कर रहे थे ?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः मुख्यमंत्री जी, मैं मना इसलिए कर रहा था क्योंकि जो काम सेक्रेटरी को करना है उसे सेक्रेटरी को करने दीजिए। यह पब्लिक डॉक्यूमैंट है।

श्री मनोहर लालः हुड्डा साहब, देखिए जब कोई आरोप लगाया जाता है तो वह डॉक्यूमैंट टेबल पर रखा जाता है और टेबल पर रखा नहीं जाएगा तो डॉक्यूमैंट की कोइ वैल्यू नहीं है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः मुख्यमंत्री जी, मैंने तो अपने डॉक्यूमैंट केवल फोटो कॉपी के लिए दिये थे, जबकि मेरे डॉक्यूमैंट ही ले गये।

श्री मनोहर लालः हुड्डा साहब, आपको अपना डॉक्यूमैंट मिलेगा।

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, आपको अपना डॉक्यूमैंट मिलेगा।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मुझे मेरे कागज वापस दिलवाओ।

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, आपको अपना डॉक्यूमैंट वापस मिलेगा। आपके कागज अभी आ जाएंगे।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, मेरा आपसे निवेदन है कि जब तक हुड्डा साहब के कागज वापिस न मिलें तब तक सदन को उठने न दें। अगली बात यह कि अगर आप चाहें तो जब तक जवाब न हो तब तक सदन को न उठने दें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष जी, मैं मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि इतना तो मेरे में भी दम है कि जब तक मेरे कागज वापिस नहीं होंगे मैं दरवाजा ही नहीं खुलने दूंगा। दरवाजे को लॉक कर दूंगा। मैं आपको भी नहीं जाने दूंगा।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, मेरा भी हुड्डा साहब को यही कहना है कि मैं भी जवाब देकर ही जाऊंगा। हुड्डा साहब को अपने डॉक्यूमैंट्स की इतनी चिंता है इसका मतलब इन डॉक्यूमैंट्स में अभी कुछ गम्भीरता बची हुई है। अध्यक्ष जी, हमें हुड्डा साहब की वार्तालाप में आनंद आ गया और सिस्टम के बारे में हमें भी ध्यान में आ गया। अध्यक्ष जी, हुड्डा साहब के कागज वापिस आ गये हैं इसलिए सभी को ताली बजानी चाहिए। हुड्डा साहब को मेरा यह भी कहना है कि वे अपने डॉक्यूमैंट्स को प्रॉपर्ली चैक कर लें कि जो डॉक्यूमैंट्स इन्होंने दिये थे वही हैं कहीं उनको बदल तो नहीं दिया।

(इस समय श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा द्वारा दिए गए कागज उनको वापिस दिये गये)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा जी, अब आपके कागज आ गये हैं। आप इनको चैक भी कर लें। यह भी बता दें कि क्या अब दरवाजा खुलेगा?

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, यहां पर एक विषय डॉ. अभय सिंह यादव जी और श्री सीता राम यादव जी सहित दूसरे साथियों द्वारा उठाया गया है कि प्रदेश में फसल खराब हुई है। इसमें मेरा इतना ही कहना है कि अब इससे सम्बंधित जो व्यवस्था है उसको भी हमने थोड़ा पारदर्शी किया है और फिर बात पोर्टल की आयेगी। हमने इसको भी पोर्टल पर कर दिया है। पोर्टल के क्या–क्या लाभ

होंगे वह भी मैं आप सभी को बाद में बताऊंगा। इसमें हमनें क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया है और क्षतिपूर्ति पोर्टल का नियम यह है कि जब भी कोई नुकसान होता है। (विघ्न) स्पीकर सर, आज हुड्डा साहब ने यह तो मान लिया कि जितने पोर्टल्ज की जरूरत हो उतने जरूर बनाओ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष जी, हम पोर्टल को सरकार नहीं बनने देंगे। हम तो यही चाहते हैं कि जहां पर पोर्टल की जरूरत हो उसके जरूर पोर्टल बनाये जायें लेकिन हर चीज का पोर्टल बनाना सही नहीं है। पहचान पत्र का भी पोर्टल। प्रदेश में बेरोजगारी इसी वास्ते ज्यादा फैल रही है।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, मेरा हुड्डा साहब को यही कहना है कि –

मंजिलें मिलें या न मिलें यह सब मुकद्दर की बात है।
पर हम तुम्हारी तरह कोशिश भी न करें, ये गलत बात है।।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष जी, मेरा मुख्यमंत्री जी को यह कहना है कि –

जो चांद ढूंढ रहा है उसके साथ नहीं हूं मैं,
इसलिए क्योंकि कल का सवेरा मैंने देना है।।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, मेरा हुड्डा साहब को यही कहना है कि –

सितमगर तुझसे उम्मीद–ए–वफा होगी कि नहीं होगी।
सितमगर तुमसे वफा होगी कि नहीं होगी, हमें तो देखना
यह है कि तुम जालिम कहां तक हो।।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी नजारों की बात करते हैं इसलिए मुख्यमंत्री जी को मुझे भी यह सुनाना पड़ेगा कि –

नजर नहीं नजारों की बात करते हैं।
जमीन पर चांद–सितारों की बात करते हैं।।
हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले,
भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं।।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, मेरा हुड्डा साहब को यही कहना है कि –

इन बारिशों से तेरी दोस्ती अच्छी नहीं फराज,
कच्चा तेरा मकान है, कुछ तो ख्याल कर।।

....

सदन की बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यदि सदन की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय 30 मिनट्स के लिए बढ़ा दिया जाये।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, सदन की बैठक का समय 30 मिनट्स के लिए बढ़ाया जाता है।

....

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भण तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान(पुनराम्भ)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मेरा तो कच्चा मकान है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि–

आसमान से ऊपर बादल हैं,
मुझे क्या पता था कि ये बादल
मेरे कच्चे मकान पर ही बरसेंगे।

श्री अध्यक्षः कादियान साहब, आपकी इच्छा पूरी हो गई है।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं हुड्डा साहब को कहना चाहूंगा कि–

सारी फितरत नकाबों में छिपा रखी है,
सिर्फ तस्वीर उजालों में लगा रखी है।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, इसी बात पर मुझे भी एक श़ेर याद आ गया इसलिए मैं भी सुना देता हूं–

आपको वफ़ा याद नहीं, हमें जफ़ा याद नहीं,
जिन्दगी के दो ही तराने हैं, एक आपको याद नहीं,
एक हमें याद नहीं।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि–

वह जो सामने मुश्किलों का अम्बार है,
वही तो मेरे हौंसलों का मीनार है।

अध्यक्ष महोदय, एक विषय फसलों के खराबे और क्षतिपूर्ति पोर्टल का भी आया था। उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि इसमें हमने क्या किया है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि अगर सारे काम पोर्टल से ही चल जायेंगे तो सरकार भी पोर्टल से ही चला लें। क्या हमारी जरूरत है और क्या ये अधिकारी बैठे हुए हैं इनकी जरूरत है?

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, जहां पर जरूरत है मैं उसी के बारे में बता रहा हूं। जब भी कोई नुकसान होता है तो हमने किसान को अपनी फसल के खराबे को पोर्टल पर दर्ज करने का अधिकार दिया है। पहले किसान द्वारा खराबे की जानकारी को पोर्टल पर दर्ज करने का समय 72 घंटे का था लेकिन कुछ शिकायतें हमारे पास आई थी कि यह 72 घंटे में दर्ज नहीं हो पाती हैं इसलिए हमने किसानों के लिए इसको बढ़ा कर एक सप्ताह कर दिया है। अब किसान अपने किला नम्बर के हिसाब से 7 दिन में अपनी फसल का खराबा पोर्टल पर डाल देगा कि मेरा इस फसल का इतना खराबा हुआ है। उसके बाद उसी पोर्टल पर पटवारी अपनी

रिपोर्ट देगा लेकिन उसको पता नहीं लगेगा कि किसान ने पोर्टल पर अपनी फसल के बारे में क्या डाला है। उसी पोर्टल पर कानूनगो भी अपने इलाके की फसलों के खराबे के बारे में अपनी रिपोर्ट डालेगा और उसे भी पता नहीं चलेगा कि किसान और पटवारी ने क्या लिखा है। कानूनगो के बाद तहसीलदार भी इसी प्रकार से अपनी रिपोर्ट देगा। जब इन चारों की रिपोर्ट सब्मिट हो जायेंगी उसके बाद एस.डी.एम. 25 प्रतिशत और डी.सी. 10 प्रतिशत रैंडमली उसमें से लेगा और जा कर उसका जायजा लेगा।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, सारा समय तो इसी में लग जायेगा?

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, समय लगता है तो लग जाये क्योंकि पटवारी, कानूनगो और तहसीलदारों का यही काम है, उनको करना चाहिए। अगर यह सारा काम हम एक ही आदमी को दे देंगे तो उसमें जहां भी गड़बड़ होगी वह कम होगा तो कम ही चलता जायेगा और अगर अधिक होगा तो अधिक ही चलता चला जायेगा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद फिर फसल कटती है। उसके लिए भी हमने "मेरी फसल मेरा ब्यौरा" पोर्टल बना रखा है। उसमें पोर्टल पर किसान अपना पूरा ब्यौरा देता है कि मेरी इस एकड़ में इतनी फसल हुई तथा इस एकड़ में इतनी फसल हुई है। किसान, पटवारी, कानूनगो और तहसीलदार की जो एंट्री हैं उनका मेरी फसल मेरा ब्यौरा के रिकॉर्ड के साथ मिलान होगा। यह मिलान कोई व्यक्ति नहीं करेगा बल्कि आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस के माध्यम से पोर्टल पर अपने आप आ जायेगा कि इन सभी के आंकलन में इतना अन्तर है। उससे पता चल जायेगा कि किसके खराबे के आंकलन में कितना अंतर है। उसमें लोवैस्ट और हाइयस्ट दोनों के अंतर बताये जाते हैं। हां, लोवैस्ट और हाइयस्ट पर हम जरूर विचार करेंगे कि इसमें किसने क्या गड़बड़ की है। अब

इसमें 5 जगह से एंट्रीज हुई हैं तो उसमें देखा जायेगा कि किसका आंकलन सबसे ऊपर है। इसमें भी बहुत बड़े खेल हो रहे हैं। कैसे–कैसे खेल हो रहे हैं उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। यह 3 साल पहले की बात है। हमारे पास शिकायत आई कि एक जिले की फसल का खराबा हो गया। उस समय ये सारी व्यवस्थाएं नहीं थी। उस समय केवल "मेरी फसल मेरा ब्यौरा" पोर्टल था। उसके बाद यहां से अधिकारियों ने उस खराबे को मान कर यहां से 18–19 करोड़ रुपया मुआवजे का भेज दिया। इशू करने से पहले "मेरी फसल मेरा ब्यौरा" पोर्टल पर उसका मिलान करना होता था। उस समय हमने आदेश दिये हुए थे कि इशू करने से पहले "मेरी फसल मेरा ब्यौरा" के साथ मिलान कीजिए कि किसान ने क्या बोया हुआ था और कितनी बिक्री हुई थी। जहां जिस फसल के लिए मुआवजा लिया गया वहां वह फसल बोयी ही नहीं थी। वहां बोया कुछ और नुकसान किसी और का दिखाकर मुआवजा मंजूर करवा लिया। अल्टीमेटली 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' में यह व्यवस्था थी कि अगर फसल का नुकसान नहीं होता है तो पैसे को वापिस मंगवाएंगे तो उसमें से साढ़े ग्यारह करोड़ रुपये वापिस आए थे। ये चीजें हैं। अब इसमें कौन कहां गड़बड़ करता है उसको चैक करने के लिए हमें व्यवस्थाएं तो खड़ी करनी पड़ेंगी। अगर हम इन व्यवस्थाओं को पारदर्शिता से स्वीकार करेंगे तो बहुत सुखी रहेंगे और पारदर्शिता से स्वीकार नहीं करेंगे तो कोई न कोई हमारे कपड़े फाड़ता रहेगा। इसलिए हमने यह सब व्यवस्था कर दी है। जो जनरल गिरदावरी होती है उसमें ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। हां, किसी फसल की जनरल गिरदावरी का एक टाईम तय होता है और उस टाईम के बाद वह खत्म हो जाती है। अगर उसके बाद अचानक कोई विपत्ति आ जाए जैसे ओला पड़ गया, बरसात हो गई या कुछ और नुकसान हो गया तो फिर स्पेशल गिरदावरी करवाई जाती है और स्पेशल गिरदावरी का भी टाईम बाउंड होता है कि जहां

फसल में नुकसान हुआ है वहां जाकर उसकी तीन दिन में स्पेशल गिरदावरी करनी होती है जोकि डी.सी. की देखरेख में होती है ताकि उसका बाद का नुकसान भी आंका जा सके। जो यह कहा जाता है कि आपने फसल खराबे के संबंध में अभी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी इस तरह का समाचार जहां से भी मिला है वह गलत है। पहले जो इंस्ट्रक्शन जाती होंगी उसके बारे में भी हमने सुना है। उसके संबंध में बताया जाता था कि फलां जगह 10 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान नहीं दिखाना है और कहीं 25 प्रतिशत से ज्यादा नहीं दिखाना है तथा फलां इलाके में 70 प्रतिशत नुकसान दिखा देना। पहले इस तरह की इंस्ट्रक्शन जाती रही थी लेकिन अब एक भी ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं जाएगी। अगर कोई डी.सी. यह कह दे कि इंस्ट्रक्शन नहीं आई हैं तो आप उस डी.सी. का नाम बता देना हम उससे उसका हिसाब किताब ले लेंगे। हम इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं भेजेंगे।

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो मुआवजा किसानों को दो साल से नहीं मिल रहा है उसके बारे में भी बता दीजिए।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, अगर वह सारा खराबा इस प्रोसैस में क्लीयर हो चुका है तो उसका मुआवजा तुरंत मिलेगा और जो इस प्रोसैस में क्लीयर नहीं हुआ है तो जरूर कहीं न कहीं गड़बड़ होगी। अगर कहीं कोई गड़बड़ होगी तो पता लग जाएगा। या फिर आप हमारे रेवैन्यू सैक्रेटरी को लिख कर दे देना कि कहां–कहां का मुआवजा रहता है। हम एक–एक का जवाब देंगे। इसी के साथ एक विषय स्वामित्व का आता है कि स्वामित्व से लोग बड़े परेशान हैं। हम बताना चाहते हैं कि हमने इसको वर्ष 2017 में शुरू किया था। यह हमने क्यों शुरू किया था उसके बारे में बताना चाहूंगा कि गांव का जो लाल डोरा होता है उसको बढ़ाने

की डिमांड आती थी। वह क्यों बढ़वाना चाहते थे क्योंकि लाल डोरा में कोई नियम लागू नहीं होता था। किसी को कोई जमीन बेच दी, खरीद ली उसका रिकॉर्ड तो रेवैन्यू में भी मान्य नहीं है। लाल डोरा में तो पंचायत को अधिकार है वह जो कह देगी वही फाईनल है लेकिन इसके कारण से झगड़े बहुत होते थे क्योंकि इसके अन्दर कई तरह की मिस मैनेजमैंट होती थी। हमें अल्टीमेटली कुछ लोगों ने विचार दिया कि लाल डोरा बढ़ाने की बजाए खत्म कर दो। हमने उस विषय को समझा और ध्यान में आया कि यह ठीक है। अगर पहली बार ग्राम पंचायत यह कह देगी कि फलां–फलां आदमी की इतनी जमीन है। ये इस जमीन का मालिक है और ये इस जमीन का मालिक है तो वह बात तो पंचायत की माननी पड़ेगी लेकिन उसके बाद उस जमीन की रजिस्ट्रियां करवा दी जाती है जोकि मात्र 100 रुपये में की जा रही हैं।

श्री जगबीर सिंह मलिक : मुख्यमंत्री जी, अब तो वे रजिस्ट्रियां होनी बन्द हो गई हैं।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, कोई रजिस्ट्रियां बन्द नहीं हुई हैं। अगर कहीं बन्द हुई हैं तो हमें बता दें। जो रजिस्ट्रियां लाल डोरा के अन्दर की हैं जब तक वे कम्पलीट नहीं होंगी तब तक बन्द नहीं होंगी। इसमें लाल डोरा से बाहर की नहीं है क्योंकि एक आबादी लाल डोरा और फिरनी के बीच में भी है। इसमें जो रजिस्ट्री एक बार हो चुकी है वह दोबारा नहीं होगी, अगर दोबारा होगी तो वह रेवैन्यू का जो हिसाब है उसी से होगी। पहले टाईम की जो रजिस्ट्री होती है वह 100 रुपये में होती है।

श्री जगबीर सिंह मलिक : मुख्यमंत्री जी, अब तो वे रजिस्ट्रियां होनी बन्द हो गई हैं।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, अगर कहीं बन्द हो रही हैं तो मैं उसकी जानकारी ले लूंगा। इसको हमारे अधिकारी सुन रहे हैं। मैं आज ही कह रहा हूं कि जितनी भी लाल डोरा की रजिस्ट्रियां हैं वे अपनी रजिस्ट्रियां करवा लें। अगर कोई अपनी रजिस्ट्रियां नहीं करवाएंगे तो उसके लिए हम टाईम बाउंड भी करेंगे। हो सकता है कि वे इसलिए ना करवा रहे हों कि 100 रुपये भी क्यों देना। उसके लिए हम बंधन लगाएंगे कि जो इस समय तक अपनी रजिस्ट्रियां करवा लेगा तो वह 100 रुपये में अपनी रजिस्ट्रियां करवा लेगा नहीं तो इसके बाद हम रजिस्ट्री का रेट पूरा कर देंगें। वह 100 रुपये भी इसलिए हैं क्योंकि वह पंचायत के कहने पर पहली बार अपनी रजिस्ट्रियां करवा रहा है लेकिन इसको पैंडिंग नहीं रख सकते। उसको हम टाईम बाउंड करेंगे। हो सकता है कहीं टाईम बाउंड के हिसाब से रजिस्ट्रियां बन्द कर दी हों इसलिए हम ऐसे व्यक्तियों को एक मौका और देंगे। सभी गांवों की ड्रोन मैपिंग हो चुकी है। उसमें हर एक का पता चल गया है कि किसका कितना और कहां तक प्लॉट है। उस ड्रोन मैपिंग के आधार पर ही उसकी रजिस्ट्री होनी है। जहां बन्द हो रही हैं हम उसको खुलवाएंगे और उनको एक मौका और देंगे।

श्री अध्यक्ष : मुख्यमंत्री जी, इसके अन्दर कई जगह पारिवारिक डिस्प्यूट हैं और उन डिस्प्यूट के कारण ही वे रजिस्ट्री करवा नहीं पा रहे हैं।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, अगर कहीं पारिवारिक डिस्प्यूट है तो उसकी भी हम कोई प्लानिंग बनाएंगे। हम कोई ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जिसमें उस परिवार की जमीन की डिस्प्यूटिड रजिस्ट्री करके उसको कोर्ट में या कहीं भी जमा करवा देंगे। जब फैसला होगा उसमें जिसकी होगी वह ले जाएगा।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, कई जगह इस प्रकार की प्राब्लम्स आई हैं कि आबादी देह का बंटवारा हो गया और सुप्रीम कोर्ट की डिक्री से हरेक आदमी को आनरशिप के प्लॉट्स भी मिल गए लेकिन लाल डोरा फिक्स करते हुए, इन प्लाट्स को भी अलग कर दिया गया।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं मलिक साहब को बताना चाहूंगा कि अगर ऐसे ग्रिवेंसिज होंगे, तो स्पेशली इस प्रकार के ग्रिवेंशिज को हल करने के लिए हमें पता है कि क्या करेंगे, पता है मलिक साहब हम क्या करेंगे, शायद आपको नहीं पता, हम इसके लिए भी अलग से एक और पोर्टल बना देंगे। **(इस समय सदन में हंसी के फव्वारे फूट पड़े।)** अध्यक्ष महोदय, अब मैं पूरे हाउस को लाल डोरा की व्यवस्था खत्म करने संबंधी स्वामित्व योजना के बारे में बताना चाहता हूँ। इस तरह की योजना शुरू करने वाला हरियाणा पहला राज्य था। अब तक किसी का इस तरफ ध्यान तक नहीं था और बाद में तो प्रधानमंत्री जी ने हमसे इस बारे में स्पेशली पूछा कि यह योजना क्या है। जब हमने इस योजना के बारे में उनको सारी बातें बताई तो उन्होंने अपने अधिकारियों से इस बारे में चर्चा की और अंतोतगत्वा आज यह स्वामित्व योजना देश के 8 प्रदेशों में संपूर्ण रूप से चालू हो गई है और इस तरह से वहां अब सभी जगहों पर ड्रोन मैपिंग भी हो रही है। अध्यक्ष महोदय, यह जमीनों के झगड़े बहुत टेढ़े होते हैं और इस तरह के झगड़ों को खत्म करने के लिए जब तक हम टैक्नोलोजी का सहारा नहीं लेंगे, तब तक जमीन से जुड़े झगड़े खत्म होने का नाम नहीं लेंगे। अध्यक्ष महोदय, आज भी हमें 50—50, 100—100 साल पुराने डाक्यूमैंट्स ढूंढने पड़ते हैं और समय बीतने पर किताबें गल जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं और डाक्यूमैंट्स के रिकार्ड भी नहीं मिलते हैं तो ऐसी स्थिति में सभी तरह के रिकार्ड्स को डिजिटलाइज करना आज की डेट में बहुत जरूरी हो गया है और हम इस दिशा

में भी यत्नपूर्वक सारा काम कर रहे हैं। अब मैं फिर से विषय पर आता हूँ। विषय था के.एम.पी. का कि आखिरकार यह के.एम.पी. क्या है अर्थात यह नैशनल हाइवे है, स्टेट हाइवे है या कुछ और है। अध्यक्ष महोदय, हमारा कहना है कि के.एम.पी. न तो नैशनल हाइवे है और न ही यह स्टेट हाइवे है बल्कि यह एक्सप्रैस–वे है और एक्सप्रैस–वे की अपनी एक अलग कैटेगरी होती है और इस तरह के एक्सप्रैस–वे केवल हरियाणा में ही नहीं हैं बल्कि और दूसरी जगहों पर भी हैं। नैशनल हाइवे ने एक्सप्रैस–वे बनाये हैं। एक्सप्रैस–वे का जो नियम है, वह इस तरह से तो बिल्कुल लागू नहीं होता कि उसकी सड़क के साथ–साथ लगती सारी जमीन का रेट ही ज्यादा हो जाये। जो एक्सप्रैस–वे होते हैं, उनमें लिमिट्स में कुछ एग्जिट और एंट्री प्वायंट्स होते हैं और इन्हीं के हिसाब से एक्सप्रैस–वे के साथ लगती जमीनों के भाव बढ़ते हैं और घटते हैं अर्थात जो जमीन एग्जिट प्वायंट और एंट्री प्वायंट के दायरे में आती है, उसके रेट बढ़ जाते हैं लेकिन जहां पर न तो सड़क से उतर सकते हैं और न सड़क पर चढ़ सकते तो वहां के रेट्स में कुछ ज्यादा चढ़ाव नहीं होता है । जहां तक नियमों की बात है जो नियम स्टेट हाइवे या नैशनल हाइवे के लिए नियत होते हैं, वे नियम एक्सप्रैस–वे के लिए नहीं होते हैं। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, जैसाकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि के.एम.पी. न तो स्टेट हाइवे है और न ही नैशनल हाइवे है बल्कि यह एक्सप्रैस–वे की श्रेणी में आता है तो ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि आखिरकार किसान वहां धरने पर बैठे ही क्यों? वास्तव में आपने ही एश्योरेंस दिया था कि के.एम.पी. को स्टेट हाइवे डिक्लेयर करवायेंगे।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, हमने ऐसा कोई एश्योरेंस नहीं दिया।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, आपको विषय का मूल समझने की जरूरत है। अगर हम इन द सैंस ऑफ कंपनसेशन के हिसाब से बात करें तो स्टेट हाइवे की अवस्था में कंपनसेशन, कलेक्टर रेट का डेढ गुना देना पड़ता है और नैशनल हाइवे की अवस्था में इसे दोगुना देना पड़ता है। अब मैं आगे बताता हूँ। यहां के लोग जब रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो जो रजिस्ट्रेशन अथारिटी है, वह कलेक्टर रेट से दोगुनी अर्थात डबल फीस चार्ज करती है। कहने मतलब जब लेने का समय आता है तो डबल चार्ज कर दिया जाता है तो जब देने का समय आये तो डबल क्यों नहीं दिया जाता।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, नहीं ऐसी कोई फीस नहीं ली जाती।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, अगर आप नहीं मानते तो मैं आपको इसके सबूत दे दूंगा। ये जो किसान धरने पर बैठे हैं इनकी यही तो समस्या है।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, ठीक है यदि हुड्डा साहब सबूत देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अगर कलेक्टर रेट बढ़ता है तो उसी के हिसाब से ही तो स्टाम्प ड्यूटी बढ़ती है। अगर कोई यह बात मन में लेकर बैठा है कि आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले उसका कलेक्टर रेट 20 लाख रूप्ये था तो आज वह 40 लाख रूपये कैसे हो गया तो यह तो कोई सवाल नहीं हुआ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि अगर नैशनल हाइवे के साथ जमीन एक्वायर होती है तो लैंड एक्विजीशन एक्ट के हिसाब से कंपनसेशन, कलेक्टर रेट का डबल दिया जाता है और स्टेट हाइवे के साथ जमीन एक्वायर होती है तो कंपनसेशन, कलेक्टर रेट से डेढ गुणा दिया जाता है लेकिन मान लो मैं अपनी जमीन बेच रहा हूँ और आप जमीन खरीद रहे हो तो ऐसी स्थिति में रजिस्ट्री कराते वक्त कलेक्टर रेट से डबल फीस चार्ज की जाती है और ऐसी

अवस्था में प्रश्न उठता है कि जब लेने का समय आता है तो डबल चार्ज कर दिया जाता है तो जब देने का समय आता है तो उस वक्त डबल कंपनसेशन क्यों नहीं दिया जाता?

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, यदि नेता प्रतिपक्ष की ऐसी कोई शिकायत है तो वह मुझे दे दे, निश्चित रूप से जिम्मेदारी के साथ काम करते हुए शिकायत का समाधान करने का काम किया जायेगा।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, इस तरह की तकलीफ रघुवीर सिंह कादियान के बेरी हल्के के लोगों की भी है और गीता जी के हल्के के लोगों की भी है।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, एक्सप्रैस–वे के साथ बेरी हल्का कहां से आ गया? यहां पर के.एम.पी. एक्सप्रैस–वे की बात हो रही है। यहां पर बेरी हल्का तो कहीं भी नहीं है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, बेरी हल्के का दाबोदा गांव इसके साथ लगता है और यही नहीं दुलहेड़ा और खरखौदा भी इसके साथ लगता है। यह जो आर्बिटल रेल कोरीडोर बना रहे हैं, इसके लिए भी यहां की जमीन एक्वॉयर कर रहे हैं वहां पर भी कलैक्टर रेट ही दे रहे है।

श्री मनोहर लालः जिस तरीके से और जिस प्रपोर्शन के हिसाब से कलैक्ट रेट बढ़ाकर मुआवजा दिया जाता है, उसी रेट से और उसी रेशों के हिसाब वहां स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। अगर कहीं पर कलैक्ट रेट बढ़ाकर मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है तो वहां स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। अध्यक्ष महोदय, फिर भी यदि कोई शिकायत होगी तो उसकी इंक्वॉयरी करवा देंगे। अध्यक्ष महोदय, रेलवे एक्ट के अन्तर्गत जमीन एक्वॉयर की गई है। जो हमारा रेगुलर एक्ट होता है, उसके अन्तर्गत नहीं

है। आर्बिटल रेल कॉरिडर में हमारा शेयर जरूर है लेकिन रेलवे एक्ट में ही जमीन एक्वॉयर की गई है। हमने कुछ लोगों की बात सुनी है क्योंकि वे हमारे पास आये थे और मिलकर भी गये हैं। मेरे पास भी श्री रमेश दलाल कुछ लोगों को लेकर आये थे। मैंने भी उनकी बात सुनी थी। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब भी उनकी बात सुनी है। अन्ततोगत्वा हमने एक सुझाव दिया है कि अगर कहीं पर कलैक्टर रेट बढ़ाने की गुंजाइश है तो उसका एक रास्ता है क्योंकि कई बार कलैक्टर रेट नहीं बढ़ाए गये हैं, वे बहुत पुराने रेट चलते आ रहे हैं। यदि हम कलैक्टर रेट नहीं बढ़ा पाये हैं और अगर जैनुअन लगता है कि वहां मार्किट रेट ज्यादा है तो उसका एक रास्ता है और वह कानून सम्मत है। वह रास्ता यह है कि वे आर्बिट्रेशन में जायें। अध्यक्ष महोदय, आर्बिट्रेशन में एक पक्ष सरकार का भी होता है। सरकार की तरफ से कहेंगे कि इसका मार्किट रेट ज्यादा है, इसलिए इसका रेट बढ़ा दिया जाये। हम इस प्रकार का काम करेंगे लेकिन सरकार स्वयं उसको नहीं बढ़ा पायेगी। इसके लिये कानूनी नियम है और नियम के अनुसार आर्बिट्रेशन में रेट बढ़ सकता है, इसलिए सरकार वहां उनकी मदद जरूर करेगी।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, यह एक लम्बी प्रक्रिया है।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, यदि दोनों पक्ष राजी हो जायेंगे तो कोई लम्बी प्रक्रिया नहीं है। इसका एक नियम होता है और हम नियम के हिसाब से चलेंगे। अध्यक्ष महोदय, एक मामला शिक्षा से जुड़ा हुआ आया था। शिक्षा क्षेत्र में विद्यार्थियों को दिये गये टैबलेट वापिस लेने की बात हुई थी। यह बात ठीक है कि एक संबंधित अधिकारी ने विद्यार्थियों से टैबलेट वापिस लेने का एक सर्कुलर निकाला था। जब इस बात का पता लगा तो तुरंत प्रभाव से उस सर्कुलर को वापिस ले लिया। जब इस बारे में संबंधित अधिकारी से पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि इसमें लिखा हुआ है कि यह स्कूल की प्रॉपर्टी है। अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक

है कि वह स्कूलों की प्रॉपर्टी है। जब तक बच्चा उस स्कूल में पढ़ेगा तब तक उसका उपयोग करेगा लेकिन स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट के समय उस बच्चे को टैबलेट वापिस जमा करवाना होगा। हमने इस बारे में संबंधित अधिकारी को कहा था कि इतना जल्दी टैबलेट वापिस लेने की क्या जरूरत थी। बच्चे को एग्जाम देना है और एग्जाम देकर यदि उसी बच्चे को उसी स्कूल में एडमिशन लेना है तो उसको एस.एल.सी. लेने की भी जरूरत नहीं है, इस हिसाब से उसको बाद में भी वह यूज करेगा। अध्यक्ष महोदय, यदि वह स्कूल 10वीं कक्षा तक है और उस बच्चे का 10वीं रिजल्ट आ जाये तो उससे टैबलेट वापिस मांग लो और उसके बाद उसका स्कूल का डॉक्यूमैंट दे दो। अध्यक्ष महोदय, यह चार सालों में रोटेशन के हिसाब से उन्हीं स्कूलों में काम आने वाली चीज है। अध्यक्ष महोदय, मैंने क्लीयर कर दिया है कि जो गलती हुई है उसको सुधारते हुए बच्चों से एस.एल. सी. लेने से पहले किसी भी विद्यार्थी से टैबलेट की वापसी नहीं होगी। इसमें सॉफ्टवेयर की जरूर दिक्कत है क्योंकि यह पैल स्पोस सॉफ्टवेयर कंपनी है। यह हमारे लिये नई विधा है। इसमें धीरे–धीरे नई कंपनियां आ रही हैं। पहले बहुत कम कंपनियां थी। पैल कंपनी का जो पहला टैंडर था वह 10 सब्जैक्ट्स को लेकर था। उन 10 सब्जैक्ट्स के टैंडर में लेने वाली जो कंपनी आई थी उसने 140 करोड़ रुपये का रेट कोट किया था। अध्यक्ष महोदय, जब हमारे एक्सपर्ट्स ने देखा कि यह तो बहुत ज्यादा रेट है और इतना रेट नहीं होना चाहिये तब इस संबंध में दोबारा से टैंडर किया गया और वह चीज सिर्फ 7 करोड़ रुपये में मिली। इस प्रोसैस में डिले तो होता है लेकिन आज भी 10 सब्जैक्ट्स और हैं जिनके लिये टैंडर करके पैल कंपनी का सॉफ्टवेयर लेना है। चूंकि ये नई विधाएं हैं इसलिए इसमें टाइम तो लगता है। हमारे हाथ में भी ज्यादा चीजें नहीं हैं। हम इसके लिये तैयार हैं, हम अगले 10 सब्जैक्ट्स का भी टैंडर करेंगे और जल्दी

इसको ले लेंगे। अध्यक्ष महोदय, एक विषय सी.ई.टी. (सामान्य पात्रता परीक्षा) से संबंधित था। मेरा इस संबंध में इतना ही कहना है कि जो चीजें पहले आज तक नहीं हुई वह पहली बार तो होंगी, यानि चार सालों में पहली बार सी.ई.टी. करवाने का डिसीजन लिया और इस बार पहली बार हुई है। यह हर साल होनी चाहिये, ठीक है अब हर साल होगी। इस प्रकार से सी.ई.टी. हर साल ग्रुप 'सी' और ग्रुप 'डी' का होगा। अभी तक हमारी योजना यह थी कि इसको अलग–अलग समय में करेंगे। जो बच्चे ग्रुप 'सी' में सिलेक्ट हो जायेगा बाद में उन सबको ग्रुप 'डी' की भर्ती में भी मौका मिल जायेगा। अभी एक नई योजना के बारे में हमने आपस में बैठ कर विचार किया है और इसके लिये ए.जी. साहब और एक्सपर्ट्स से सलाह–मश्विरा भी करेंगे कि सी.ई.टी. को ग्रुप 'सी' और ग्रुप 'डी' दोनों के लिए इक्ट्ठा साल में एक ही बार करेंगे। जो प्रश्न–पत्र तैयार होगा वह ग्रुप 'डी' के बराबर अर्थात् 10वीं कक्षा के समकक्ष होगा लेकिन उसमें 2 ग्रूप रहेंगे । जिन्होंने गूप–सी का फॉर्म भरा है उनको अलग से 20 या 25 क्वैश्चंस का एक ऐडिश्नल क्वैश्चन पेपर मिलेगा । उन दोनों के सैंटर्ज भी अलग–अलग होंगे । गूप–सी वालो को ऐडिश्नल पेपर को सॉल्व करने के लिए आधे घण्टे का समय एक्सट्रा दिया जाएगा । मान लीजिए गूप–सी वालो को 2 घण्टे का समय मिलेगा तो गूप–डी वालो को अढ़ाई घण्टे का समय मिलेगा और अगर गूप–सी वालो को अढ़ाई घण्टे का समय मिलेगा तो गूप–डी वालो को 3 घण्टे का समय मिलेगा ताकि उसी समय ग्रूप–सी का एक ऐडिश्नल पेपर भी हो जाए । बेसिक पेपर 10वीं वाला सबका एक रहेगा । ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रूप–सी का अलग–अलग पोस्ट्स के हिसाब से एक और पेपर होना है और ग्रूप–डी की पोस्ट्स का कोई और पेपर नहीं होना होता है । उसी हिसाब से ग्रूप–सी की सिलैक्शन के बाद उसमें जो हायर मैरिट वाले कंडीडेट्स होंगे उनको ग्रूप–डी की नौकरी

ऑटोमैटिकली मिल जाएगी । मैंने अगले साल के लिए यह घोषणा जरूर की है लेकिन इसकी टैक्निकल चीजों को देखकर हम इसे फाइनल करेंगे । (विघ्न)

राव चिरंजीव : अध्यक्ष महोदय, एक बार माननीय मुख्य मंत्री महोदय हमें एम्स के बारे में जवाब दे दें ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, एम्स का हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है ।

राव चिरंजीव : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में महामहिम राज्यपाल महोदय ने कहा है ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में महामहिम राज्यपाल महोदय ने कहा होगा लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा है । इन सभी बातों का मैंने आज ही जवाब नहीं देना है । मुझे जो महत्वपूर्ण विषय लगे मैंने केवल उन्हीं का जवाब दिया है । (विघ्न)

राव चिरंजीव : अध्यक्ष महोदय, क्या यह विषय महत्वपूर्ण नहीं है ?

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, सैशन अभी और चलना है । कुछ बातों का आज जवाब दिया जाएगा और कुछ बातों का जवाब आगे दिया जाएगा । अतः माननीय सदस्य को इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए । माननीय सदस्य को धैर्य से जवाब सुनना चाहिए । जवाब देने के लिए तो बहुत–से विषय हैं लेकिन आज मैं जितने विषयों का जवाब दे सकता हूं उतने विषयों का मैं जवाब दे रहा हूं । अब मैं 24 घण्टे बिजली देने के विषय पर जवाब दूंगा । 'मेरा गांव जगमग गांव' योजना के शुरू होने से पहले प्रदेश में बिजली की बहुत बुरी हालत थी, रिकवरी नहीं होती थी, लाइन लॉसिज बहुत ज्यादा थे आदि । हमने बहुत ही आग्रहपूर्वक इस कार्य को शुरू किया और शुरू–शुरू में तो हमें इसमें ताने भी सहने पड़े । बाद में हमें इसका लाभ हुआ और मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि पूरे प्रदेश में जो 7,255 गांव हैं उनमें से 5,694 गांवों में .... (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने केवल योजना का नाम ही बदला है । (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : नहीं, अध्यक्ष महोदय । पिछली सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं थी जिसमें गांवों में 24 घण्टे बिजली देने के लिए प्रयास किये गये हों ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, हमने यह प्रावधान किया था कि जो गांव बिजली का पूरा बिल देगा हम उसको 24 घण्टे बिजली देंगे । यह हमारी स्कीम थी । इस सरकार ने केवल उस स्कीम का नाम बदला है । (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को वर्ष 2014 का एक आंकड़ा निकालकर बताऊंगा । (विघ्न) मैं कहूंगा कि जिसको लागू करवा सको वही स्कीम होती है । जिसे आप लागू ही न करवा सको ऐसी स्कीम का क्या फायदा हुआ ? हाँ, अभी गांवों में 24 घण्टे बिजली मुहैया करवाने में छोटी–मोटी दिक्कतें जैसे ट्रिपिंग की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, ओवरलोड की हैं । किसी–किसी गांव में ऐसी शिकायतें आ सकती हैं अन्यथा हम 78 परसैंट गांवों में पूरी बिजली दे रहे हैं । अब मैं स्टिल्ट जमा 4 मंजिला भवन के निर्माण के विषय पर जवाब देना चाहता हूं । इस पर माननीय मंत्री जी ने भी विस्तार से जवाब दिया है । उन्होंने बताया है कि इसे रिव्यू करने के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है । इस बारे में उस कमेटी को लोगों से और रेजीडैंट वेलफेयर एसोसियशंज से भी बात करनी पड़ेगी क्योंकि यह डिमांड के आधार पर खुलता और बंद होता है । किन क्षेत्रों में इस नीति को लागू किया जाए हम यह निर्णय एक्सपर्ट्स की कमेटी की सिफारिशों के आधार पर ही करेंगे । विपक्ष का जैसा कहना है कि इसे जल्दी कीजिए तो इसके लिए भी हमें विश्वास दिलाने में भी थोड़ी कठिनाई आ रही थी। माननीय सदस्य श्री बी.बी. बतरा ने कहा कि तब इसे ऐबियंस (abeyance) में ले आओ । मुझे भी ऐसा ही लग रहा है । अतः आज हम यह घोषणा करते हैं कि

अब के बाद स्टिल्ट जमा 4 मंजिला भवन का तब तक कोई भी नक्शा एंटरटेन नहीं किया जाएगा जब तक हम इस बारे में कोई फैसला नहीं कर लेते हैं ।

श्री वरुण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, इस तरह की समिति यह फैसला लेने से पहले बन जाती तो और अच्छा होता।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, ये फैसला तो सरकार को लेना है और सरकार ने फैसला ले लिया कि यह अबेयैंस में है। इसको कोई बन्द नहीं किया है। इस अबेयैंस का मतलब यह है कि जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती तब तक आगे काम नहीं करेंगे। कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो हो सकता है कि उसके हिसाब से किसी जगह पर बन्द करना पड़े और किसी जगह पर न करना पड़े। यह भी हो सकता है कि सारा काम बन्द करना पड़े या सारा काम चालू रखना पड़े। इस पर नो कमिटमैंट। इसमें कमेटी की जो सिफारिश आएगी, उस पर फिर भी डिपार्टमैंट्स बैठकर सोचेंगे। यह एक बहुत बड़ा विषय है, यह छोटा विषय नहीं है। आज कुछ लोग इसके फेवर में हैं और कुछ लोग इसके विरोध में हैं। इस विषय पर जो जनहित का फैसला होगा, वही फैसला लागू करवाएंगे।

श्री अध्यक्षः माननीय मुख्यमंत्री जी, इसको थोड़ा टाईम बाउंड कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, इसमें टाईम बाउंड तो हो ही गया है कि जब तक फैसला नहीं होगा तब तक सारे काम ही बन्द हो गये हैं। यह आपके पंचकुला के लिए तो हो ही गया है कि जब तक फैसला नहीं होता तब तक काम बन्द है। हम तो चाहेंगे कि यह काम जल्दी से जल्दी हो। हम ऐसी कमेटी बनाएंगे जो इस विषय पर जल्दी से काम करे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इस विषय पर चुनावों से पहले फैसला करेंगे या बाद में करेंगे?

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूंगा कि इस विषय का चुनावों का कोई संबंध नहीं है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं इस काम को टाईम बाउंड करने के लिए कह रहा हूं।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूंगा कि यह काम टाईम बाउंड तो हो गया है। इस विषय पर जब तक कोई नया फैसला नहीं होगा तब तक आगे काम बन्द रहेगा। यह फैसला तो हो गया है। इसमें हो सकता है कि 15 दिनों के बाद फैसला हो जाए और हो सकता है कि 5 साल भी लगा दें। इसमें माननीय नेता प्रतिपक्ष को क्या दिक्कत है? जिनकी यह काम बन्द करने की मंशा थी, वह काम तो हो ही गया है। अब मैं अपने उस विषय पर आता हूं कि जिसका मुझे जुनून है। मेरा जुनून यह है कि भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। इन चीजों के बारे में मेरे पास बहुत से सुझाव भी आते हैं, लेकिन मैं कभी घबराया नहीं और कभी डरा नहीं क्योंकि मुझे इस भष्टाचार को खत्म करना ही करना है। भष्टाचार खत्म करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि जितना ह्युमन इन्टरफेस कम किया जाए, मानवीय हस्तक्षेप कम किया जाए और जितनी डिस्क्रिशनरी पॉवर्ज कम की जाएं, उतना ही भ्रष्टाचार रूकेगा।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी पोर्टल चला तो रहे हैं।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय नेता प्रतिपक्ष को कहना चाहूंगा कि मैं भी वही बात कह रहा हूं। हम जो पोर्टल चला रहे हैं उसमें

ई–गवर्ननैंस ऑनलाईन सिस्टम को महत्व दिया है और शुरू से ही दे रहे हैं। आज उसका रिजल्ट निकल रहा है। मैं एकदम यह नहीं कह रहा हूं कि वह क्लाइमैक्स पर पहुंच गया है। लेकिन उसके रिजल्ट इतने अच्छे निकल रहे हैं जिनके कारण हमें उत्साह मिल रहा है और बहुत चीजों का लाभ हो रहा है। मैं डी.बी.टी. का एक उदाहरण देकर बताना चाहूंगा कि जितने भी बेनिफिशरीज हैं उन सबके खाते में सीधा पैसा जाता है। चाहे वह बेटियों का कोई अनुदान हो, चाहे किसान की प्रॉक्योरमैंट का पैसा हो, चाहे किसी का वजीफा हो, चाहे ओल्ड एज पैंशन हो। अब ये सारी चीजें किसी के हाथ में नहीं जाती हैं बल्कि सीधी उनके खातें में जाती हैं। अगर संबंधित बेनिफिशरी अपने खाते में पैसा निकालकर किसी में बाट दें तो उसमें हमारा कोई बस नहीं है। वह संबंधित पैसों का कुछ भी करे क्योंकि वह उसका मालिक है। लेकिन अब संबंधित बेनिफिशरीज के खाते में सीधा पैसा जाता है। मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले 3 सालों में जब से डी.बी.टी. करना शुरू किया है तब से लाखों घोष्ट बेनिफिशरीज कम हुए हैं। इसके कारण साढ़े 1100 करोड़ रुपये की बचत भी हुई है। यह बचत इस डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के कारण हुई है क्योंकि पहले बीच में फर्जी चीजें थी और उनका कोई पता नहीं लगता था कि कहां से पैसा निकल गया है और वह पैसा वापिस आएगा या नहीं आएगा? पहले इसके बारे में भगवान ही जानता था। लेकिन अब अगर संबंधित पैसा बैंक में है और वह आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है तो वह पैसा वापिस आएगा। जैसा अभी मैंने एक उदाहरण बताया था कि साढ़े 1100 करोड़ रुपया वापिस आया है। अगर पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो वह खाते में जाएगा लेकिन यदि पैसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ और रूक गया तथा कोई आईडैंटिफिकेशन नहीं हुई तो वह पैसा वापिस आएगा। इसलिए हमारे लिए ये सब एक तरीके से चौकीदारे का काम कर रहे हैं। हमने इस नाते से 100 से

अधिक पोर्टल और एप बनाये हैं। यह इन्हीं पोर्टल्ज का काम है कि गरीब की बेटी की शादी का शगुन, बुजुर्ग की पैंशन, विद्यवा की पैंशन और विद्यार्थियों की छात्रवृति एक क्लिक से सीधी उनके खाते में जाती हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि बुजुर्गों की पैंशन कट भी रही है।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष को कहना चाहूंगा कि जिनकी पैंशन कट रही है, वह पोर्टल के कारण ही कट रही है। उनकी पैंशन क्यों कट रही है ? कल मैंने उसका जवाब दे दिया था। जो इन्कम टैक्स पे कर रहा है, जो गवर्नमैंट इम्पलायी है और जो पैंशनधारी हैं, हम उन पर पिछले 11 सालों से कुछ नहीं कर रहे हैं।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में भी गड़बड़ है जिसके कारण संबंधित बच्चों ने एडमिशन लेना बन्द कर दिया है। सारे बच्चे आगे की पढ़ाई छोड़कर चले गये हैं।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मैंने कल भी बताया था कि जो कमियां हैं, उनको दूर करेंगे। लेकिन पोर्टल्ज बन्द करेंगे, इसके बारे में आप लोग सपने लेना बन्द कर दें। इसके जरूर परिणाम निकलेंगे। हमने बहुत सारे दूसरे विषय सिस्टम बदलकर हल कर दिये हैं। विपक्ष के माननीय सदस्यगण पहले हर सिस्टम को गलत कहते थे। हमने पढ़ी–लिखी पंचायतें बनायी तो विपक्ष के माननीय सदस्यों ने कहा कि यह गलत है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि एम.एल.ए. तो अनपढ़ भी चुनकर आ जाते हैं, लेकिन सरपंच पढ़े–लिखे चुनकर आते हैं।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष को कहना चाहूंगा कि हमारी इस योजना पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगायी है।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यदि सदन की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय 30 मिनटस के लिए बढ़ा दिया जाये।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, सदन की बैठक का समय 30 मिनटस के लिए बढ़ाया जाता है।

————————

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भ तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपनी बात कन्कलूड कर रहा हूं। मैं यही कह रहा हूं कि पोर्टल का कमाल है कि किसानों की अपनी जमीन की फर्द एक क्लिक से उनको मिल जाती है। अब पटवारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं यह फर्द का ही कमाल है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। कोई व्यक्ति कहीं का भी देश में कहीं भी राशन लेना चाहे तो वह ले सकता है। केरल का आदमी हरियाणा में राशन ले सकता है और हरियाणा का आदमी असम में राशन ले सकता है। कहीं का आदमी कहीं भी राशन ले सकता है। यह सब पोर्टल का कमाल है इसलिए ऑनलाईन के माध्यम से हमने जितने भी काम किये हैं, इन सबको करने के बाद गरीबों के खाते खजाना के साथ जोड़ दिये हैं। अब खजाना है या गरीब का खाता है। बीच में कोई नहीं है और जो बीच में सफेद कपड़िये, धौल कपड़िये के रूप में बिचौलिये थे मैं तो यह भी कह रहा हूं कि वे अब बेरोजगार हुए हैं। विपक्ष के लोग इस बारे में डंका बजाते रहते हैं वह बेरोजगारी

इनके सिर चढ़कर बोल रही है इसलिए यह जुनून है। इस जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा। किसी शाह समुद्र से नूर निकलेगा, ऐसा मेरा दावा है। मित्रों, विषय तो बहुत है लेकिन फिर भी आपका बार–बार यह कहना है तो मैं इस बात के साथ समाप्त करता हूं कि हम लोग जमाने के हिसाब से चले, आज के जमाने में शुभचिंतक ऐसे होते जा रहे हैं, जो आपका शुभ होता है, देख चिंतित होते जा रहे हैं इसलिए आप चिंतित न हो, शुभ रहे, शुभचिंतक बनो। आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। मैं अंत में राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण के ऊपर हुई चर्चा उसका उत्तर देते हुए अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सदन को निवेदन करता हूं कि राज्यपाल महोदय का जो धन्यवाद प्रस्ताव है, इसको सर्वसम्मति से पारित करवायें। आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, देखिये, राज्यपाल महोदय का प्रस्ताव है मुख्यमंत्री जी ने रखा है मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं यह बात जरूर कहूंगा कि राज्यपाल महोदय बहुत काबिल आदमी है। मैं उनका सम्मान करता हूं लेकिन मैं इनकी दाद देता हूं कि इन्होंने उनसे झूठ दबकर बुलवाया है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

"कि राज्यपाल महोदय को एक समावेदन निम्नलिखित शब्दों में पेश किया जाएः–

''कि इस सत्र में इकट्ठे हुए हरियाणा विधान सभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय के अत्यन्त कृतज्ञ हैं जो उन्होंने 20 फरवरी, 2023 को 11.00 बजे प्रातः सदन में देने की कृपा की है।''

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।

———————

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण एवं बजट की हार्ड कॉपीज सदस्यों को देने के संबंध में अनुरोध

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, हमें कम से कम गवर्नर एड्रेस और बजट की हार्ड कॉपी दी जायें। इसमें Budget at a Glance भी है। आप ये दोनों डॉक्यूमैंट्स पूरे साल के लिए अलाउ कर दीजिए, विधान सभा का कामकाज पेपर लैस हो जाये हमें कोई दिक्कत नहीं है परन्तु हमें ये दोनों यानी गवर्नर एड्रेस और बजट की हार्ड कॉपीज दी जाये।

श्री अध्यक्ष : आफताब जी, करवा देंगे।

....

नेवा पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2022–23 के लिए अनुपूरक अनुमान (तृतीय किस्त) प्रस्तुत करना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय वित्त मंत्री वर्ष 2022–23 के लिए अनुपूरक अनुमान (तृतीय किस्त) नेवा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में नेवा पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2022–23 के लिए अनुपूरक अनुमान (तृतीय किस्त) प्रस्तुत करता हूं।

....

नेवा पोर्टल के माध्यम से प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब श्री हरविन्द्र कल्याण, विधायक, चेयरपर्सन प्राक्कलन समिति वर्ष 2022–23 के लिए अनुपूरक अनुमान (तृतीय किस्त) पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट नेवा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे।

प्राक्कलन समिति चेयरपर्सन (श्री हरविन्द्र कल्याण) श्रीमान् जी, मैं वर्ष 2022–23 के लिए अनुपूरक अनुमानों (तृतीय किस्त) पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट नेवा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करता हूं।

....

वर्ष 2022–23 के लिए अनुपूरक अनुमानों (तीसरी किस्त) की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2022–23 के लिए अनुपूरक अनुमान (तृतीय किस्त) पर चर्चा तथा मतदान होगा। पिछली प्रथानुसार और सदन का समय बचाने के लिए ऑर्डर पेपर पर रखी गई सभी डिमाण्ड्ज (संख्या 7, 12, तथा 19) एक साथ पढ़ी गई तथा मूव की गई समझी जायेंगी। माननीय सदस्यगण, किसी भी डिमाण्ड पर चर्चा हरियाणा विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 201 के तहत ही अनुपूरक अनुदानों पर बहस उन मुद्दों तक ही सीमित रहेगी जिनसे वे बनी हों और जहां तक विचाराधीन विशेष मुद्दों की व्याख्या करने या उन्हें स्पष्ट करने के लिए आवश्यक हो। उस सीमा तक मूल अनुदानों पर या उनसे संबंधित नीति पर कोई चर्चा नहीं होगी लेकिन बोलने से पहले वे अपनी डिमाण्ड का नम्बर बता दें जिस पर वे बोलना चाहते हैं।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए **171,73,21000 रूपये** से अधिक न हो, मांग संख्या 7–**राज्य सरकार द्वारा कर्जे तथा पेंशगियां** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **2,00,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या 12–**शिक्षा (उच्चतर/माध्यमिक/प्राथमिक) तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विकास** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **546,62,34,000 रूपये** से अधिक न हो, मांग संख्या 19–**सिंचाई/उद्योग और वाणिज्य/एम.एस.एम. ई. /पूर्ति तथा निपटान/विद्युत और नवीनीकरण ऊर्जा/विज्ञान और प्रौद्योगिकी** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(कोई सदस्य बोलने के लिए खड़ा नहीं हुआ।)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब विभिन्न डिमाण्ड्ज को सदन में वोटिंग के लिए रखा जायेगा।

मांग संख्या : 07

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए **171,73,21000 रूपये** से अधिक न हो, मांग संख्या 7–**राज्य सरकार द्वारा कर्जे तथा पेंशगियां** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

मांग संख्या : 12

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **2,00,000** रूपये से अधिक न हो, मांग संख्या 12–**शिक्षा (उच्चतर/माध्यमिक/प्राथमिक) तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विकास** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

मांग संख्या : 19

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए **546,62,34,000 रूपये** से अधिक न हो, मांग संख्या 19–**सिंचाई/उद्योग और वाणिज्य/एम.एस.एम.ई./पूर्ति तथा निपटान/विद्युत और नवीनीकरण ऊर्जा/विज्ञान और प्रौद्योगिकी** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

नियम 121 के अधीन प्रस्ताव(वर्ष 2023–2024 के लिए वित्तीय समितियों के गठन संबंधी)

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231, 233, 235 और 266 को निलंबित करने के लिए नियम 121 के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231, 233, 235 तथा 266 के उपबंध जहां तक कि वे :–

(i) लोक लेखा समिति,

(ii) प्राक्कलन समिति,

(iii) लोक उपक्रमों संबंधी समिति, तथा

(iv) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए समिति,

के गठन से संबंधित हैं, को वर्ष 2023–2024 के लिए निलंबित किया जाए।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं –

कि यह सदन अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा को प्राधिकृत करता है कि वह सदन में विभिन्न दलों/ग्रुपों की अनुपातिक संख्या को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2023–2024 के लिए पूर्वोक्त समितियों के सदस्यों को नामजद करें।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231, 233, 235 तथा 266 के उपबंध जहां तक कि वे :–

(i) लोक लेखा समिति,

(ii) प्राक्कलन समिति,

(iii) लोक उपक्रमों संबंधी समिति, तथा

(iv) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए समिति,

के गठन से संबंधित हैं, को वर्ष 2023–2024 के लिए निलंबित किया जाए ।

यह भी प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि यह सदन, अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा को प्राधिकृत करता है कि वह सदन में विभिन्न दलों/ग्रुपों की अनुपातिक संख्या को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2023–2024 के लिए पूर्वोक्त समितियों के सदस्यों को नामजद करें ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231, 233, 235 तथा 266 के उपबंध जहां तक कि वे:–

(i) लोक लेखा समिति,

(ii) प्राक्कलन समिति,

(iii) लोक उपक्रमों संबंधी समिति, तथा

(iv) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए समिति,

के गठन से संबंधित हैं, को वर्ष 2023–2024 के लिए निलंबित किया जाये।

यह भी प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि कि यह सदन अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा को प्राधिकृत करता है वह सदन में विभिन्न दलों/ग्रुपों की अनुपातिक संख्या को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2023–2024 के लिए पूर्वोक्त समितियों के सदस्यों को नामजद करें।

(प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।)

....

नेवा पोर्टल के माध्यम से हरियाणा पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2022 पर प्रवर समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब प्रवर समिति के चेयरपर्सन सदन में नेवा पोर्टल के माध्यम से हरियाणा पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2022 पर प्रवर समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

चेयरपर्सन, प्रवर समिति (श्री रणबीर सिंह गंगवा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नेवा पोर्टल के माध्यम से हरियाणा पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2022 पर प्रवर समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब सदन गुरुवार, दिनांक 23 फरवरी, 2023 प्रातः 11:00 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।

*06:39 बजे

(तत्पश्चात् सभा गुरुवार, दिनांक 23 फरवरी, 2023 प्रातः 11:00 बजे तक के लिए स्थगित *हुई।)